सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली

प्रकाशित :
नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। www.mea.gov.in

सामने का कवर जवाहरलाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय के जून 2011 के बाद से नये भवन को दर्शाता है।

सामने कवर के अन्दर 1947 के बाद साउथ ब्लाक, विदेश मंत्रालय की सीट को दर्शाया गया है।

अभिकल्पन एवं मुद्रण :

डाल्फिन प्रिन्टो–ग्राफिक्स
4ई/7, प्रथम तल, पाबला बिल्डिंग,
झंडेवालान विस्तार, नई दिल्ली–110055
दूरभाष : 011–23593541–42
E-mail : dolphinprinto2011@gmail.com

विषयवस्तु

	प्रस्तावना और सारांश	i-xxvi
1.	भारत के पड़ोसी देश	1
2.	दक्षिण–पूर्व एशिया और प्रशांत	22
3.	पूर्वी एशिया	37
4.	यूरेशिया	42
5.	खाड़ी तथा पश्चिम एशिया	49
6.	अफ्रीका	59
7.	यूरोप और यूरोपीय संघ	82
8.	अमेरीका	110
9.	संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन	131
10.	निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले	151
11.	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	155
12.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)	159
13.	विकास सहयोग	162
14.	निवेश तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन	166
15.	ऊर्जा सुरक्षा	168
16.	आतंकवाद का सामाना और नीति आयोजना	170
17.	प्रोटोकॉल	172
18.	कोंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं	175
19.	प्रशासन और स्थापना	184
20.	सूचना का अधिकार और मुख्य जनसूचना अधिकारी का कार्यालय	187
21.	ई–गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी	188
22.	समन्वय प्रभाग	189
23.	विदेश प्रचार तथा लोक राजनय प्रभाग	191
24.	विदेश सेवा संस्थान	194
25.	राजभाषा कार्यान्वयन नीति तथा विदेशों में हिन्दी का प्रचार–प्रसार	196
26.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	197
27.	विदेशी मामलों की भारतीय परिषद् (आई सी डब्ल्यू ए)	200
28.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	203
29.	पुस्तकालय	207
30.	वित्त और बजट	209

परिशिष्ट

परिशिष्ट I :	01 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान अन्य देशों के साथ भारत द्वारा संपन्न अथवा नवीकृत संधियां/अभिसमय/करार	211
परिशिष्ट II :	01 जनवरी–31 दिसंबर, 2014 के दौरान जारी किए गए पूर्ण क्षमता वाले दस्तावेज	224
परिशिष्ट III :	01 जनवरी, 2014–31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन दस्तावेजों एवं उन पर हुई सहमति की तारीख	225
परिशिष्ट IV :	आईटीईसी तथा एससीएएपी देशों की सूची	228
परिशिष्ट V :	आईटीईसी/एससीएएपी के सूचीबद्ध संस्थानों की सूची	231
परिशिष्ट VI :	वर्ष 2013–14 के दौरान नीति, आयोजना और अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूर्णतः वित्तपोषित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा आयोजित/प्रारंभ किए गए सम्मेलन/सेमीनार/अध्ययन परियोजनाएं	233
परिशिष्ट VII :	प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों और जारी किए गए पासपोर्टों, प्राप्त कुल विविध आवेदनों और प्रदान की गई सेवाओं की कुल संख्या, जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या और तत्काल स्कीम के तहत राजस्व, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पासपोर्ट कार्यालयों का कुल राजस्व और व्यय दर्शाने वाला विवरण	234
परिशिष्ट VIII :	31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन की कैडर संख्या	236
परिशिष्ट IX :	31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में काडर सं. (वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संगणित पदों एवं काडर आदि से परे पदों सहित)।	237
परिशिष्ट X :	01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति तथा मंत्रालय में कराई गई सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती और संबंधित आंकड़े।	238
परिशिष्ट XI :	विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भा.वि.सेवा अधिकारियों की संख्या	239
परिशिष्ट XII :	आरआईएस प्रकाशनों की सूची	240
परिशिष्ट XIII :	2014–15 में विदेश मंत्रालय का वित्तीय व्यय	241
परिशिष्ट XIV :	2014–15 में मुख्य क्षेत्रवार आबंटन (बजट अनुमान)	242
परिशिष्ट XV :	भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य	245
परिशिष्ट XVI :	लम्बित सीएजी लेखापरीक्षा पैराओं की स्थिति	244
संक्षिप्तियां		247

प्रस्तावना और सारांश

भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सार्थक संबंध पर बल देती है ताकि राष्ट्रीय आर्थिक बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और भौगोलिक एकता सहित अपने मुख्य लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ हम अपनी मुख्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक चिंताओं का समाधान कर सकें। भारत ने अपने सभी पड़ोसी और सार्क देशों के साथ अपने संपर्क को गहन बनाया है। हमने अमरीका, रूस, जापान, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ तथा इसके मुख्य सदस्य देशों, जिनमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी शामिल हैं, के साथ रणनीतिक भागीदारी के आर्थिक और राजनैतिक आधारों को सुदृढ़ और विस्तृत किया है। हमने अपने विस्तारित पड़ोस, आसियान, पश्चिमी एशिया और खाड़ी देशों के साथ सहभागिता बनाए रखा है। भारत ने विकास भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से अफ्रीका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नए मंचों को सुदृढ़ किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से आवाज उठाई और अंतर्राष्ट्रीय लोक नीति के उभरते क्षेत्रों में स्वतंत्र स्थिति बनाए रखी।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 मई, 2014 को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दक्षिण एशियाई देशों तथा मॉरीशस के नेताओं को अप्रत्याशित रूप से न्यौता भेजा जाना दक्षिण एशियाई देशों के साथ सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा सर्वसमावेशी संबंध स्थापित करने की हमारी मंशा एवं प्रतिबद्धता दर्शाती है। प्रधान मंत्री जी ने भारत पहुंचे सभी मेहमान नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने बाद में कहा कि यह न्यौता प्रत्येक सार्क देश के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदमा था।

भारत के विदेश मंत्री के रूप में 28 मई, 2014 को अपना कार्यभार ग्रहण करते हुए श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत की विदेश नीति का मूल इसकी सभ्यता तथा विरासत में है तथा यह हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रति एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि वे इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तथा चुनौतियों, जिनका हम सभी सामूहिक रूप से सामना कर रहे हैं, से निपटने के लिए विश्वभर में अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहती हैं।

अफगानिस्तान के साथ भारत की गहरी रणनीतिक साझेदारी है जिसे अक्तूबर 2011 में संपन्न रणनीतिक साझेदारी करार द्वारा और पुख्ता बनाया गया, जिसके तहत व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करजई के साथ 27 मई, 2014 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुलाकात की तब उन्होंने हेरातू स्थित हमारे दूतावास पर हुए हमले को नाकाम करने में अफगान नेशनल सिक्युरिटी फोर्स द्वारा की गई मदद के लिए अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत अफगानिस्तान के विकास एवं पुनर्निर्माण के प्रति वचनबद्ध है और वह एक समृद्ध, स्वतंत्र तथा सम्प्रभुतासंपन्न अफगानिस्तान देखना चाहता है, जहां सुलक प्रक्रिया अफगानिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के नेतृत्व में शुरू की जाए तथा अफगानिस्तान नियंत्रित हो। भारत ने 02 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापक द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के जरिए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में उसे सहायता देना जारी रखा।

भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर सुरक्षा, बुनियादी संरचना, कारोबार, विकास तथा लोगों के बीच आपसी आदान–प्रदान के क्षेत्रों में अपने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने का कार्य किया।

बांग्लादेश संसद के अध्यक्ष डॉ0 शीरिन शर्मिन चौधरी के साथ 27 मई, 2014 को अपनी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गौर किया कि भारत और बांग्लादेश की प्रगति एवं समृद्धि में दोनों का हित हैं। भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश की विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 25–27 जून, 2014 तक सद्भावना यात्रा की। इस यात्रा से भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गति मिली।

भारत ने भूटान के साथ अपने अनूठे एवं विशिष्ट संबंध को मजबूत बनाना जारी रखा जो कि कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भूटान की यात्रा से परिलक्षित होता है। 14 जून, 2014 को अपनी भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने द्विपक्षीय संबंधों को 'B2B' – भारत भूटान संबंध बताया। प्रधान मंत्री जी ने भारत में अध्ययन कर रहे भूटानी छात्रों के दी जा रही छात्रवृत्ति राशि को दुगुना करने का सुझाव दिया। प्रधान मंत्री ने यह भी घोषणा की कि भारत भूटान को एक डिजीटल पुस्तकालय स्थापित करने में सहयोग करेगा जो भूटान के युवाओं को 02 मिलियन पुस्तकें तथा पत्रिकाएं सुलभ कराएगा। इससे पहले 27

मई, 2014 को भूटान के प्रधान मंत्री श्री शेरिंग टॉग्बे के साथ अपनी मुलाकात के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने यह नोट किया कि भारत एवं भूटान के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों के साथ–साथ एक अनूठा एवं विशेष संबंध है। उन्होंने भूटान के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए दृढ़ समर्थन का भरोसा दिलाया। दोनों प्रधान मंत्रियों ने पारस्परिक सुरक्षा हितों की अभिपुष्टि की और अपने–अपने राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर घनिष्ठ सहयोग एवं समन्वय पर सहमति व्यक्त की।

भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। मालदीव के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के साथ 27 मई, 2014 को अपनी मुलाकात के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में कार्य का संकल्प लिया। प्रधान मंत्री ने नोट किया कि भारत और मालदीव इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों देशों के सुरक्षा हित एक–दूसरे से जुड़े हैं और इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष एक–दूसरे के सरोकारों के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे। प्रधान मंत्री जी ने मालदीव को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में विशेषतः तेल की खोज तथा पर्यटन एवं शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग के लिए सरकार के समर्थन की भी बात कही।

भारत ने नेपाल को एक प्रगतिशील, शांतिपूर्ण, स्थायी तथा लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरने के लिए अपना समर्थन जारी रखा है जिसमें गहन द्विपक्षीय बातचीत तथा विकास सहायता के जरिए प्रगति हासिल की जाएगी। नेपाल के प्रधान मंत्री श्री सुशील कोइराला के साथ अपनी मुलाकात के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गौर किया कि नेपाल भारत का एक पुराना तथा मूल्यों में विश्वास रखने वाला एक मित्र देश है जिसके साथ हमारा इतिहास, भूगोल तथा प्राचीन सम्यतामूलक संबंध साझे हैं। प्रधान मंत्री जी ने परियोजनाओं विशेषतः जलविद्युत परियोजनाओं को शीघ्रता के साथ लागूकरने पर बल दिया और उन्होंने भारत और नेपाल के बीच कनेक्टिविटी तथा आर्थिक अंतरसंबंधों जिनमें रेल तथा सड़क संपर्क परियोजनाएं भी शामिल हैं, को और मजबूत बनाने की अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया।

भारत पाकिस्तान के साथ सभी विवादास्पद मुद्दों को आतंक एवं हिंसात्मक माहौल में शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ 27 मई, 2014 को अपनी मुलाकात के दौरान आतंकवाद से जुड़ी अपनी चिंताओं का उल्लेख किया। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि वह अपने नियंत्रण वाली जमीन के भारत के विरुद्ध आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपनी वचनबद्धता पर कायम रहे। प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में मुंबई हमले के दोषियों पर चल रही कार्रवाई में वह तेजी लाएगा और आरोपियों पर दोष सिद्ध करके उन्हें कड़ी सजा दिलाएगा। नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने और घुसपैठ की घटनाओं के बाद भारत ने पाकिस्तान से यह भी जोर देकर कहा कि उसे नियंत्रण रेखा की पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में इस बात का भी उल्लेख किया कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नियंत्रण रेखा पर शांति एवं अमन चैन बनाए रखना जरूरी है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिन्द्रा राजपक्षे की 26–27 मई, 2014 तक भारत यात्रा के दौरान उनके और प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधान मंत्री जी ने गौर किया भारत और श्रीलंका के बीच मूल्यों पर आधारित संबंध हैं और श्रीलंका सरकार से अनुरोध किया कि वह राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया में इस प्रकार तेजी लाए ताकि एक संयुक्त श्रीलंका में तमिल समुदायों की समानता, न्याय, शांति एवं सम्मान आधारित जीवन जीने की अभिलाषा पूरी हो सके। प्रधान मंत्री ने 500 मेगावाट क्षमता वाली सामपुर कोयला विद्युत परियोजना को शीघ्र शुरू करने और दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक संपर्क बढ़ाने में रुचि दिखाई।

भारत ने चीन के साथ एक रणनीतिक आर्थिक वार्ता (SED) शुरू की है। चीन के प्रधान मंत्री श्री ली किक्याग के साथ 29 मई, 2014 को प्रधान मंत्री की टेलीफोन पर हुई बातचीत में उन्होंने चीन के साथ अपने रणनीतिक एवं सहयोगात्मक भागीदारी का पूर्णतः उपयोग करने के लिए भातर के संकल्प को दुहराया और हमारे विकास लक्ष्यों से शुरू करते हुए यहां के लोगों को लम्बे समय तक के लाभ पहुंचाने के रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी उल्लेखनीय मुद्दे से निपटने के चीनी नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों देशोंने जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय करना जारी रखा और ब्रिक्स तथा जी–20 सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर घनिष्ठ बातचीत जारी रखी।

ईरान के साथ सम्यतामूलक तथा ऐतिहासिक संबंध ही जीवंत द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद है। हमारी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं तथा ईरान की आपूर्ति क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र हमारे द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक है।

हमने म्यामांर के साथ सुरक्षा, सीमा संबंधी मुद्दों, कारोबार एवं ट्रांजिट, बिजली, बुनियादी सुविधाएं, संपर्क परियोजनाएं तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान का वचन देकर रचनात्मक तरीके से सहयोग किया है।

भारत और मॉरीशस के संबंध समय की कसौटी पर जांची परखी, विशिष्ट तथा बहुआयामी हैं। साझा इतिहास तथा संस्कृति पर आधारित यह भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है और आज दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान–प्रदान के कारण इसे प्राप्त एक नई ऊर्जा एवं इस पर ध्यान दिए जाने से इसके तहत व्यापक रूप से अलग–अलग कार्य एवं क्षेत्र शामिल हैं।

प्रधान मंत्री डा0 नवीनचंद्र रामगुलाम विश्व नेताओं में प्रथम नेता थे जिन्होंने मई 2014 में आए ऐतिहासिक चुनावी परिणाम पर प्रधान

मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए गैर–सार्क राष्ट्रों में से एकमात्र नेता के रूप में उन्होंने 25–28 मई, 2014 तक नई दिल्ली की यात्रा की। प्रधान मंत्री डा0 नवीनचंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और भारत–मॉरीशस संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा की।

मॉरीशस के प्रधान मंत्री डा0 नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ मुलाकात में प्रधान मंत्री जी ने गौर किया कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, साझी विरासत तथा लोगों के बीच आपसी रिश्तेदारी के माध्यम से जुड़ाव है। दोनों ने इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने का निर्णय लिया विशेषतः समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग तथा तालमेल को और प्रगाढ़ बनाने के लिए सहमति व्यक्त की जिसमें बुनियादी सुविधा का विकास करना भी शामिल है। उन्होंने भारतीय समुद्री रिम संघ को और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने पर भी सहमति व्यक्त की।

आसियान के साथ भारत के संबंध हमारी विदेश नीति और पुर्वोन्मुखी नीति की एक मुख्य विशेषता है। दक्षिण–पूर्व एशिया में हमारे विस्तृत पड़ोस के साथ हमारे संबंध अधिकाधिक राजनीतिक, रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग और आर्थिक कार्यकलाप के माध्यम से बढ़े हैं। आसियान–भारत संबंध एक साझी रणनीतिक प्राथमिकता है और भारत ने भारत–म्यामां–थाइलैण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान बहुमॉडल परियोजना को लागू करने में काफी प्रगति की है।

अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे– स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय आदान–प्रदान तथा द्विपक्षीय सहयोग शामिल है। राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनके शपथ ग्रहण समारोह में बधाई दी और उन्हें अमेरिका आने का न्यौता दिया। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओमाबा ने 26 जनवरी, 2015 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा की।

रूस के साथ भारत की परम्परागत भागीदारी जारी रही। रक्षा सहयोग हमारी रणनीतिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ रूस के उप प्रधान मंत्री श्री दिमित्रि रोबोजिन के साथ मुलाकात के दौरान प्रधान मंत्री ने रूस को समय की कसौटी पर जांचा–परखा तथा भरोसेमंद मित्र बताया और कहा कि वह भारत की रक्षा क्षमताओं के निर्माण में एक प्रमुख भागीदार है। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की रूस के उप प्रधान मंत्री श्री दिमित्री रोबोजिन के साथ चार घंटे तक चली बैठक के दौरान हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। रूस द्वारा निर्मित तृतीय जहाजी बेड़ा आई एन एस त्रिखण्ड भारत को सौंपा गया और विमानवाहक पोत आई एन एस विक्रमादित्य का प्रचालन शुरू किया गया। कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की पहली इकाई को अक्तूबर 2013 में पॉवरग्रिड के साथ जोड़ा गया जबकि दूसरी ईकाई का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में पूरा होने की संभावना है।

अरब स्प्रिंग (आंदोलन) की घटनाओं के उपरांत भारत इस क्षेत्र में सभी देशों के सरकारों के साथ सक्रियता से बातचीत करता रहा। हमने अपने हितों की रक्षा करते हुए चिरस्थायी तंत्रों के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया। मिस्र के मामले में हमने कार्यात्मक स्तर पर हस्तक्षेप न करने, उदार, दूरदर्शिता, की नीति अपनाईए साथ ही एक समावेशी परिवर्तनकारी रोडमैप को लागू करने का आग्रह किया। सीरिया के मामले में भारतने संयुक्त राष्ट्र समर्थित सीरिया के नेतृत्व में एक व्यापक राजनैतिक समाधान का समर्थन किया। भारत ने जिनेवा ।। में भाग लिया और मानवीय सहायता प्रदान करने तथा रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए इजराइल–फिलीस्तीनी शांति वार्ता का समर्थन किया। साथ ही एक संप्रभुता संपन्नए स्वतंत्र, व्यावहारिक, संयुक्त फिलीस्तीन राष्ट्र के लिए अपनी मांग को भी दोहराया जो इजराइल के साथ एक सुरक्षित एवं मान्यता–प्राप्त सीमाओं के भीतर रह सके तथा पूर्वी येरूसलम जिसकी राजधानी हो। अपने आर्थिक तथा ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए हमने लीबिया के साथ बातचीत की। सूडान तथा दक्षिणी सूडान में समग्र ऊर्जा हित को देखते हुए हमने विकास भागीदारी पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर–पक्षपातपूर्ण रवैये वाली नीति को जारी रखा। खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों के साथ जहां भारत के रणनीतिकए आर्थिक, ऊर्जा तथा डायस्पोरा से संबंधित हित हैं; हमारे संबंधों को नियमित राजनैतिक कारोबार तथा वाणिज्यिक आदान–प्रदान से और प्रगाढ़ बनाया गया।

पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ लोकतंत्र, कानून तथा नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित हमारे साझा मूल्य है। उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान–प्रदान के माध्यम से हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा क्षमता के बारे में स्वीकार्यता बढ़ रही है। भारत ने मध्य तथा पूर्वी यूरोप के साथ व्यापक विनियोजन, प्रगाढ़ एवं विविध संबंधों पर आधारित नीति को जारी रखा। मध्य यूरोप के अधिकांश देशों के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों से वे अवसर ही परिलक्षित होते हैं जिसकी पेशकश भारत कारोबार तथा निवेश के रूप में करता है और इन देशोंका भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में परस्पर अभिरुचि लेना और भारत की ओर से उस क्षेत्र में अपने–आपको विनियोजित करना जहां आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सहयोग की संभावनाएं हों, भी इस तथ्य को साबित करता है।

अफ्रीका को रणनीतिक महत्व दिया जाना जारी रहा, विशेषतः भारत का इसके साथ आर्थिक तथा वाणिज्यिक पहलुओं में विनियोजन के तौर पर यह जारी रहा। अफ्रीका के साथ भारत के संबंध राजनैतिक

समर्थन और दो भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस) के तहत परियोजनाओं जिनमें छात्रवृत्तियां, प्रशिक्षण, अनुदान, ऋण तथा प्राइवेट क्षेत्र निवेश शामिल हैं, को लागू किए जाने से और मजबूत हुए। आईएएफएस – ।। में घोषित नई परियोजनाओं में 05 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला (LOC), अगले तीन वर्षों में 22,000 से भी अधिक छात्रवृत्तियां और 80 से भी अधिक क्षमता निर्माण संस्थाओं की स्थापना शामिल है। भारत को उम्मीद है कि यह सहयोग अगले शिखर सम्मेलन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। भारत के लातिन अमेरिकातथा कैरिबियाई देशों के साथ अपने द्विपक्षीय कारोबारए विकास सहायता परियोजनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को नई ऊंचाई दी जिसमें हमारी ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा और इसकी उल्लेखनीय भारतीय डायस्पोरा में योगदान करने की क्षमता मौजूद है।

परमाणु हथियार रखने वाले देश के नाते निरस्त्रीकरण संबंधी मुद्दों पर भारत का पक्ष उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों और ऐसी चुनौतियों से निपटने में सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ गहरे तालमेल की हमारी परम्परा पर आधारित है। भारत वैश्विक एवं निष्पक्ष परमाणु के प्रति वचनबद्ध है। भारत बहुपक्षवाद में संयुक्त राष्ट्र के केन्द्रीय स्वरूप को महत्व देता है और वह अंतर्राष्ट्रीय लोक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने की संयुक्त राष्ट्र की सभी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत की उपस्थिति तब और मजबूत हुई जब विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों में उसे निर्वाचित किया गया। संयुक्त राष्ट्र निकायों में उसे निर्वाचित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्रवाई में भारत सेना भेजने वाला सबसे बड़ा देश बना रहा। आधुनिक राष्ट्रकुल का एक संस्थापक के प्रति दृढ़ कटिबद्ध है। भारत ने बहुपक्षीय निकायों जैसे 20 राष्ट्रों का समूह (जी–20), बहुपक्षीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक), ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) और हिंदी महासागर रिम संघ (आईओआरए) में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाना जारी रखा।

समूह–4 तथा एल–60 जैसे समूहों समान विचारों वाले देशों के साथ भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने और सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर जोर देता रहा है ताकि इसे और अधिक प्रतिनिधित्वमूलक एवं लोकतांत्रिक बनाया जा सके जिससे इसकी विश्वसनीयता एवं कारगरता बढ़े और यह समकालीन भू–राजनैतिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें।

पड़ोसी देश

अफगानिस्तानः अफगानिस्तान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करजई 27 मई, 2014 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा उनकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए। भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी ने 29 सितंबर, 2014 को अफगानिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉ0 मो0 अशरफ गनी के काबुल में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए एक भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। प्रधान मंत्री जी ने काठमाण्डू में 26 नवंबर, 2014 को सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर अफगान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित दो प्रमुख परियोजनाएं –निमरोज प्रांत में जारंज से डेलाराम तक 218 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य और चिमताला में एक सब–स्टेशन सहित पुल–ए–खुमरी से काबुल तक 220 कि0वा0 पारेषण लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। काबुल में अफगानिस्तान के नए संसद भवन और हेरात प्रांत में सलमा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। भारत अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशिया–इस्तानबुल प्रक्रिया में सक्रियता से भाग ले रहा है। इस प्रक्रिया के तहत, भारत 'कारोबार, वाणिज्य तथा निवेश अवसर' संबंधी विश्वास सृजन उपाय का नेतृत्व कर रहा है।

बांग्लादेशः दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता दोनों ओर से की गई उच्च स्तरीय यात्राएं हैं। वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में दिसंबर 2014 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, विदेश मंत्री की जून 2014 में सर्वप्रथम विदेश यात्रा के रूप में की गई ढाका यात्रा और अगरतला स्थित बांग्लादेश वीजा कार्यालय को सहायक उच्चायुक्त कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया जाना शामिल है। भारत–बांग्लादेश संबंध सही मायने में बहुआयामी हो गया है जिसके तहत व्यापक विषय क्षेत्र शामिल हैं जैसे दृ व्यापार तथा निवेश, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन, जल, विद्युत, पोत–परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, विकास सहयोग, कला एवं संस्कृति, लोगों के बीच आपसी बातचीत, मानव संसाधन विकास आदि शामिल हैं। संयुक्त परामर्शदात्री आयोग (जेसीसी) की तीसरी बैठक 20 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों की पुनरीक्षा की गई। संयुक्त परामर्शदात्री आयोग के दौरान बांग्लादेश ने नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में भारत के साथ सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भूटानः भारत और भूटान के बीच गहरे एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जो उनके बीच आपसी विश्वास और भरोसे से परिलक्षित होता है। वर्ष 2014 में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति जारी रही जिनमें जलविद्युत, परिवहन, संचार, बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और कृषि शामिल हैं। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जून, 2014 को भूटान की पहली विदेश यात्रा की। भूटान के प्रधान मंत्री श्री शेरिंग टोब्गे ने श्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 26–28 मई, 2014 तक भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नवंबर 2014 में भूटान की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2014 में नेपाल में आयोजित 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर भूटान के प्रधान मंत्री से मुलाकात की। इन यात्राओं तथा बैठकों से दोनों देशों के बची मैत्रीपूर्ण संबंध तथा सहयोग और मजबूत हुए।

भारत भूटान का सबसे बड़ा कारोबारी तथा विकास साझेदार बना रहा। तीन जल विद्युत परियोजनाएं–पुनातसांग्चू–। (1200 मे.वा.), पुनातसांग्चू ।। (1020 मे.वा.) और मांगदेछू (720 मे.वा.) का निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि वर्ष 2017–18 तक यह प्रचालित कर दिया जाएगा। अप्रैल 2014 में भारत ने भूटान के साथ चार संयुक्त उद्यम जलविद्युत परियोजनाओं और भूटान में 600 मेगा वाट वाली खोलोंग्छ जलविद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए। प्रधान मंत्री जी ने 2014 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान खोलोंग्छू जलविद्युत परियोजना के लिए आधारशिला रखी। भूटान की शाही सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013–18) के लिए वित्तीय सहायता नियमित रूप से वितरित की जा रही है।

चीनः भारत और चीन के बीच एक रणनीतिक तथा सहयोगमूलक साझेदारी है। वर्ष 2014 में द्विपक्षीय संबंधों में चहुमुखी प्रगति देखी गई। चीन के विदेश मंत्री श्री वांग ई ने 08–09 जून, 2014 तक चीन के राष्ट्रपति श्री जी जिन्पिंग के विशेष राजदूत के रूप में भारत की यात्रा की। विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने छठे भारत–चीन रणनीतिक वार्ता में भाग लेने के लिए 13–14 अप्रैल, 2014 तक बीजिंग की यात्रा की। राष्ट्रपति श्री जिन्पिंग ने 17–19 सितंबर, 2014 तक भारत की राजकीय यात्रा की। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इससे पूर्व छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर फोर्टालेजा, ब्राजील में 14 जुलाई, 2014 को चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। प्रधान मंत्री ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन बैठक के असवर पर 13 नवंबर, 2014 को नेपीताऊ में चीन के प्रधान मंत्री श्री ली किक्यांग से भी मुलाकात की। भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी ने 26–30 जून, 2014 तक चीन की आधिकारिक यात्रा की।

मालदीवः भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध है। मालदीव के साथ भारत के राजनयिक संबंधों का यह पचासवां वर्ष है। इसके अंतर्गत मजबूत आर्थिक संबंध भी मौजूद है जिसमें विकास–सहायता, ऋण श्रृंखला, आकस्मिक ऋण सुविधा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी शामिल है। भारत ने परस्पर उच्च स्तरीय यात्राओं तथा यूक्रेन से मालदीव के छात्रों को निकालने में सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करके और माले में जल–संकट के दौरान वायुसेना के विमानों तथा नौ–सेना जहाजों द्वारा पेयजल की आपूर्ति करके अपने घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखा। भारत सरकार ने हाल ही में मालदीव के लिए तेल की विशेष व्यवस्थाओं की भी घोषणा की है।

म्यामांः भारत–म्यामां के संबंध दोनों के बीच साझा इतिहासए जातिगत, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंधों पर आधारित है। भारत–म्यामां संबंध हमारी सीमाओं पर शांति एवं अमन–चैन को बढ़ावा देने के लिए एक–दूसरे के साथ सहयोग करनेए चिरस्थायी आर्थिक विकासके लक्ष्य को प्राप्त करने और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी बातचीत को बढ़ावा देने को हमारी साझी इच्छा को परिचालित करते हैं। आसियान देशों में म्यामां ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं भारत के साथ लगती है और इसलिए यह भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच जमीनी सेतु का कार्य करता है। हाल के वर्षों में भारत–म्यामां संबंधों में तेजी आई है जिसमें बुनियादी सुविधाए कनेक्टिविटी, मानव–संसाधन तथा क्षमता–निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है।

नेपालः भारत और नेपाल के बीच मैत्री तथा सहयोग का एक अनूठा रिश्ता है जिसकी विशेषता के रूप में खुली सीमाएं, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सम्यतामूलक संपर्क, आर्थिक संबंध तथा लोगों के बीच गहरे संबंधहैं जिसे अक्सर 'रोटी–बेटी का संबंध' कहा जाता है। सत्रह वर्ष के अंतराल के बाद प्रधान मंत्री की दो नेपाल यात्राएं, पहली यात्रा 03–04 अगस्तए 2014 तक और दूसरी यात्रा 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25–27 नवंबर, 2014 तक, इस बात को दर्शाती है कि भारत सरकार नेपाल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यधिक प्राथमिकता देती है। 23 वर्षों के बाद भारत–नेपालसंयुक्त आयोग को पुनः शुरू किए जाने से जब काठमाण्डू में 26–27 जुलाई, 2014 को विदेश मंत्री की सह–अध्यक्षता में इसकी तीसरी बैठक आयोजित की गई, द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े संपूर्ण मुद्दों को नया बल मिला। जी एम आर द्वारा 900 मे0वा0 क्षमतावाली अपर करनाली परियोजना के लिए सितंबर 2014 में और नवंबर 2014 में ए जे वी एस द्वारा 900 मे0वा0 क्षमता वाली अरुण–।। परियोजना विकास करारों पर साथ ही अक्तूबर 2014 में पावर ट्रेड करार पर हस्ताक्षर किए जाने तथा अगस्त 2014 में पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना में प्रगति दिखी और यह हमारे द्विपक्षीय संबंधोंमें गुणात्मक परिवर्तन के द्योतक थे। इससे पूर्व नेपाल के प्रधान मंत्री श्री सुशील कोईराला ने प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 26–28 मई, 2014 तक भारत की यात्रा की थी। नेपाल को एक प्रगतिशील, शांतिपूर्ण, स्थायी तथा जनतांत्रिक देश के रूप में परिवर्तित होते हुए भारत नेपाल का निरंतर समर्थन करता है।

पाकिस्तानः पाकिस्तान के साथ शांति एवं सहयोग पर आधारित अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने की भारत की दीर्घकालिक नीति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ को अन्य सार्क नेताओं के साथ–साथ 26 मईए 2014 को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्यौता भेजा गया। 27 मई, 2014 को आयोजित द्विपक्षीय वार्ताके दौरान प्रधान मंत्री जी ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ के समक्ष आतंकवाद से संबंधित अपनी चिंताओं को पुनः दोहराया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबरए 2014 को अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के साथ गंभीर द्विपक्षीय वार्ता करने की भारत की इच्छा को पुनः दोहराया जिसके लिए एक शांतिपूर्ण माहौल की जरुरत है। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने एक रचनात्मक तथा चिरस्थाई द्विपक्षीय बातचीत के लिए उचित माहौल तैयार करने से संबंधित पाकिस्तान की जिम्मेदारी का भी उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे में असैनिक कैदियों तथा भारतीय मछुआरों से जुड़े मामलों को

नियमित रूप से निपटाया जाता रहा।

श्रीलंकाः भारत और श्रीलंका के संबंधों को सर्वोच्च राजनैतिक स्तर पर घनिष्ठ संबंध, बढ़ते व्यापार एवं निवेश, विकास, शिक्षा, संस्कृति तथा रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हित के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक सूझ–बूझ के तौर पर देखा गया है। पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय वार्ताएं और श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए विकास सहायता परियोजनाओं को लागू करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति से दोनों देशों के बची मैत्रीपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने में सहायता मिली है।

दक्षिण–पूर्व एशिया और प्रशांत

दक्षिण–पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों के साथ भारत के संबंधों में हाल के वर्षों में एक नई गति आई है। हमारे विस्तारित पड़ोस में विशेषतः वर्ष 2014 में नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमारे विनियोजन का दायरा बढ़ने तथा और घनिष्ठ होने से पूर्वोन्मुखी नीति में भी बदलाव आया जिससे 'एक्ट ईस्ट' के नाम से एक नया आयाम जुड़ गया। हमारे संबंधों के इस नए चरण को विदेश नीति के प्रति और अधिक सक्रिय एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है जिसके तहत राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के ठोस रूपों और क्रियान्वयन की समय–सीमा पर बल दिया गया।

हमारे सम्यतामूलक संपर्क, परस्पर सद्भावना और आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोगको सुदृढ़ बनाने की इच्छा बहुआयामी तथा भविष्योन्मुखी है और इस क्षेत्र में रह रहे भारतीय मूल से लोगों के साथ संबंध को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। कई साझेदार देशों के साथ हमारे रिश्तों में एक रणनीतिक आयाम मौजूद है और क्षेत्रीय मंचों के साथ हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध तथा बहुपक्षीय विनियोजन एक–दूसरे की जरुरतों को परिपूरित करते हैं। इस क्षेत्र में अधिक आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्व की संभावना से विश्वास में बढ़ोतरी हुई है जबकि एशिया की ओर भू–राजनीतिक स्थितिके झुकाव से इस क्षेत्र में हमारी भागीदारी को एक नई गति मिली है तथा सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

हमारी उन्नत पूर्वोन्मुखी नीति/एक्ट ईस्ट नीति नब्बे के दशक के दौरान दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्रसंघ (आसियान) के लिए परिकल्पित आर्थिक पहल पर आधारित है। इसमें राजनीतिक, रणनीतिक तथा सांस्कृतिक आयाम जुड़ गये हैं और अब यह आसियान से आगे जा चुका है। इसके तहत अब सुरक्षा, कनेक्टिविटी तथा क्षेत्रीय अखण्डता को अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख विकास ईंजन के रूप में भारत इस क्षेत्र में शांति, प्रगति तथा स्थायित्व के लिए अवसर प्राप्त करना चाहता है। हमारी उन्नत पूर्वोन्मुखी नीतिने इस क्षेत्र में तथ्झा इससे आगे एक अमिट छाप छोड़ी है। कई साझेदार देशों के क्षेत्रीय दृष्टिकोण को परिपूरित किया है और हमारे रणनीतिक एजेंडा का एक अभिन्न घटक के रूप में उभरा है।

मई 2014 में नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही उच्च स्तरीय यात्राओं, सहयोग के मौजूदा संस्थागत तंत्रों को नियमित बैठकों और नए तंत्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है जिससे संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और द्विपक्षीय सहयोग में भावी रुझानों की संभावनाएं बढ़ी हैं। नई सरकार के आने के बाद सर्वप्रथम राजकीय यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की थी (सितंबर 2014) जिसकी मेजबानी भारत ने की और प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसके बदले ऑस्ट्रेलिया की यात्रा (नवंबर 2014) की जो कि प्रधान मंत्री स्तर पर 28 वर्षों के बाद की गई कोई यात्रा थी। कई क्षेत्रों में करार सम्पन्न किए गए जिनमें से प्रमुख करार असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित थे। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने वियतनाम की यात्रा (सितंबर 2014) की ओर वियतनाम के प्रधान मंत्री ने भारत की यात्रा (अक्तूबर 2014) की।

इन यात्राओं से द्विपक्षीय समझबूझ और सहयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है और हमने ऊर्जा, रक्षा तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में प्रमुख करार सम्पन्न किए हैं। प्रधान मंत्री ने नेई पी टा में आयोजित किए गए भारत–आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) (नवम्बर, 2014) में भाग लिया जहां उन्होंने सुल्तान ब्रूवेई, फिलीपीन्स के राष्ट्रपति, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों सहित अनेक नेताओं के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिजी की ऐतिहासिक यात्रा (नवम्बर, 2014) की जहां उन्होंने 14 सदस्यीय प्रशांत द्वी समुदाय के लिए भारत–प्रशांत द्वीप सहयोग (एफआईपीआईसी) के प्रथम मंच पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया तथा प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को और सुदृढ़ किया।

विदेश मंत्री (ईएएम) ने आसियान–भारत और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए नेई पी टा की यात्रा (अगस्त, 2014) की जहां उन्होंने फिलीपीन्स, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई, न्यूजीलैंड और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री ने सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की (जून, 2014) और हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए सिंगापुर की द्विपक्षीय यात्रा (अगस्त, 2014) भी की। उन्होंने वियतनाम की भी यात्रा (अगस्त, 2014) की जिसके दौरान उन्होंने क्षेत्रीय मिशन अध्यक्ष सम्मेलन (एचओएम) और आसियान–भारत विचारक दल नेटवर्क की भी अध्यक्षता की। इसके संबंध में नियमित रूप से सरकारी स्तर पर बातचीत किए जाने से इसके समन्वय तथा कार्यान्वयन में सुधार हुआ है। इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडलों के हमारी नई संसद की यात्रा से संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के आदान–प्रदान को जारी रखा गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत से दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंध प्रमुख स्तम्भ के रूप में उभरे हैं। विभिन्न प्रकार के सामान के बारे में भारत–आसियान मुक्त व्यापार

करार को कार्यान्वित किए जाने से आसियान देशों के साथ हमारा व्यापार सुविधाजनक हुआ है जिसमें रूपए के कमजोर होने के बावजूद वर्ष 2013–14 में आसियान देशों के साथ कुल 75 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार करने और वर्ष 2014–15 के प्रथम छह माह में 44 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का व्यापार करने से तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई है। प्रशांत क्षेत्र के साथ वर्ष 2013–14 में हमारा कुल व्यापार लगभग 13 बिलियन अमरीकी डालर का था जो वर्ष 2014–15 के प्रथम छह माह में 8 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का हो चुका है। सेवाओं और निवेश के संबंध में भारत–आसियान मुक्त व्यापार करार के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के साथ हमारे बढ़ते आर्थिक कार्यकलापों को और गति मिलेगी। आसियान देशों तथा भागीदारों के साथ बातचीत करने से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में वृद्धि हुई है और भारत ने इस संबंध में एक सत्र आयोजित किया। इस आरसीईपी से आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे वर्ष 2015 तक आसियान आर्थिक समुदाय का गठन करने के आसियान के अभियान के संदर्भ में प्रासंगिकता बढ़ने की परिकल्पना की गई है और हमने भारत में इसकी बैठक आयोजित की है। इसी प्रकार थाईलैंड, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हमारे द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार (एफटीए) जिनसे प्रतिस्पर्धा तथा विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, को बेहतर तालमेल के साथ नए आयाम के रूप में देखा गया है। हम सिंगापुर और मलेशिया के साथ अपने व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) की समीक्षा कर रहे हैं ताकि इन्हें और कारगर बनाया जा सके। इस क्षेत्र के आर्थिक आयाम से प्रगति तथा विकास में योगदान मिला है। इस क्षेत्र के साथ हमारे आर्थिक संबंध हमारी विकास प्राथमिकताओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र के देश प्रमुख व्यापार और निवेश भागीदारों के रूप में उभरे हैं; सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड अवसंरचना विकास में मुख्य भागीदार हैं; तथा इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, वियतनाम और ब्रूनेई संसाधन तथा ऊर्जा सुरक्षा के दीर्घकालिक, विश्वसनीय स्रोत के रूप में उभरे हैं। मेक इंडिया पहल से इस क्षेत्र के बारे में अत्यधिक रूचि उत्पन्न हुई है जो नए औद्योगिक कोरीडोर, स्मार्ट सिटी, बौद्ध सर्किट और पूर्वोत्तर में निवेश अवसर के रूप में देखी जा सकती है। इसके साथ–साथ आर्थिक सम्पर्क सुदृढ़ करने के लिए भारत के राज्यों और दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों के बीच स्पष्ट रूप से तालमेल रखा गया। इसके अतिरिक्त हमारे कारपोरेट क्षेत्र ने अपने समकक्ष क्षेत्र के साथ कारोबार सम्पर्क विकसित किए और आर्थिक संबंधों को अधिक मजबूत करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व में वृद्धि हुई है जो कि इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता की हमारी इच्छा के लिए हमारी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। कुछ क्षेत्रों के संबंध में नियमित आदान–प्रदान और बातचीत के माध्यम से सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ किया गया। हमने अपने आसियान भागीदारों विशेष रूप से वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ प्रत्यक्ष समन्वय बनाए रखा तथा मानवीय खनन कार्रवाई के लिए और एआरएफ और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक + (एडीएमएम+) तंत्र के संबंध में सह–अध्यक्ष के रूप में भागीदारी की। हमने आस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा सहयोग के बारे में कार्य संरचना तैयार की। सिंगापुर और आस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने आपसी समझबूझ तथा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए भारत की यात्रा की। हमने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों स्तर पर आतंकवाद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए अपने सुरक्षा कार्यकलापों को प्रत्यक्ष समन्वय तथा सूचना के आदान–प्रदान से और बेहतर बनाया। हमने विधि प्रवर्तन अभिकरणों और आपदा राहत संगठन (एचएडीआर) के मध्य सहयोग के लिए तंत्र की व्यवस्था की और मुख्य भागीदारों के साथ समुद्री सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा के संबंध में बातचीत की। एमएच–370 वायुयान के खो जाने पर इसके खोज अभियान में और इसी प्रकार की अन्य घटनाओं के बारे में हमारी सहायता से हमारे पड़ोसी क्षेत्र में खोज और बचाव अभियानों में अंतर–अभियान क्षमता निर्माण करने में योगदान मिला है। हमने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आदान–प्रदान को बेहतर किया है और अद्यतन विशेषज्ञता से युक्त तथा लोकप्रिय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सार्थक सहयोग से संबंधित अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए सहायता प्रदान की है। इस क्षेत्र के अनेक देशों से मंगलयान मंगल ग्रह अभियान को व्यापक समर्थन मिला है।

भारत ने सीएलएमवी (कोलम्बिया, लाओ, म्यांमार, वियतनाम) के साथ अपने कार्यकलापों का सामान्य हित के मुद्दों पर बातचीत करके और उनकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि और जल प्रबंधन, ऊर्जा तथा पारेषण लाइनों और मानव संसाधन विकास तथा क्षमता निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के बारे में उच्चतर स्तर पर सहायता प्रदान करके विस्तार किया है। कनेक्टिविटी, उद्यमिता विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी भाषा की संस्थाओं की स्थापना को नई प्राथमिकता प्रदान की गई। नए आर्थिक अवसर सृजित करने के लिए द्वितीय भारत–सीएलएमवी कारोबार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने सइम रीप, वाट फू, माई सन और प्रीह खान जैसे सांस्कृतिक विरासत स्थलों के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए सहायता की पेशकश की। भारत ने प्रीह विहार परिसर को विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करने का भी समर्थन किया और इसके पुनरूद्धार के लिए सहायता की पेशकश की।

कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संबंध में हमारी प्रत्यक्ष सहभागिता सहित संयुक्त पहल तथा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष सहयोग के माध्यम से आसियान–भारत रणनीतिक भागीदारी को और समेकित किया गया। हमारी भागीदारी को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करने और सहयोग तथा कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जकार्ता में अलग से आसियान–राजदूत ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। नालंदा विश्वविद्यालय ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की परिधि में राजगीर, बिहार अस्थाई परिसर से इतिहास अध्ययन

स्कूल तथा पारिस्थितिकी स्कूल और पर्यावरण अध्ययन में कक्षाएं शुरू कर दी हैं। सइम रीप, कम्बोडिया में परम्परागत वस्त्रों से संबंधित एमजीसी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेई पी टा में आयोजित किए गए तृतीय बीआईएमएसटीईसी शिखर सम्मेलन में ढाका में बीआईएमएसटीईसी सचिवालय की स्थापना के अभियान को और कार्यसूची के बारे में मार्गदर्शन देने की इसकी समेकित भूमिका को प्रबल आधार मिला है। क्षेत्रीय एकता को सुदृढ़ करने और आसियान तथा सार्क के मध्य सेतु के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से सभी बीआईएमएसटीसी देशों में कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक परिवहन और अवसंरचना परियोजनाओं की सूची कनेक्टिविटी कार्यसूची को अंतिम रूप देने में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है।

भारत और प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के मध्य संबंधों में भारत और प्रशांत द्वीप नेताओं के मध्य सुआ, फिजी में शिखर सम्मेलन आयोजित करके पर्याप्त सार्थक परिवर्तन किया गया है। प्रधानमंत्री ने प्रशांत द्वीप की विकास प्राथमिकताओं और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रमुख पहल की घोषणा की है। हमने प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने सहयोग कार्यकलापों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, कृषि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम, छोटे कारोबार तथा अन्य कारोबार के विकास से संबंधित छोटी विकास परियोजनाओं में सांस्थानिक सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहयोग संबंधी नई पहल के माध्यम से गति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, प्रशांत द्वीप मंच (पीआईएफ) के साथ हमारी बातचीत और वर्ष 2014 में पलाऊ आयोजित की गई उत्तर मंच संवाद भागीदार बैठक में भागीदारी के साथ नियमित बैठकों और समोआ में आयोजित एसआईडीएस सम्मेलन से इस क्षेत्र में हमारी प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई है।

इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करके इस वर्ष के दौरान हमने विदेश में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंधों पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने सिडनी में भारतीय मूल के और फिजी में नागरिक सम्मेलन में बड़े समूह से बातचीत की; विदेश मंत्री ने सिंगापुर और हनोई में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस क्षेत्र में मौजूद भारतीय मूल के व्यक्तियों जो संख्या और प्रभाव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ने इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधीनगर में आयोजित किए गए प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी), 2015 को व्यापक जन–समर्थन मिला जिसमें आस्ट्रेलिया में रहने वाले दो व्यक्तियों तथा न्यूजीलैंड में रहने वाले एक व्यक्ति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया।

संबंधों को और व्यापक बनाने तथा प्रत्यक्ष व्यक्ति–दर–व्यक्ति सम्पर्क स्थापित करने के लिए सिडनी और हनोई में नए भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, आस–पास के स्थानों पर भारत महोत्सव आयोजित किए गए और परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान–प्रदान सहित योग, आयुर्वेद और बालीवुड को प्रोत्साहित किया गया। इस क्षेत्र के कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन पीठ स्थापित की गई। विचारक दलों के मध्य सम्पर्क स्थापित किए गए और रणनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर क्षेत्रीय बातचीत को प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण में नए शैक्षिक संबंधों तथा सहयोग स्थापित किए गए और प्रशिक्षण के लिए आईटीईसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का विस्तार किया गया तथा इसे सुदृढ़ किया गया। पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लिए बौद्ध सर्किट और पूर्वोत्तर को प्रोत्साहित किया गया। युवाओं तथा विख्यात व्यक्तियों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए करार सम्पन्न किए गए। कनेक्टिविटी, कारोबार सम्पर्क और व्यक्ति–दर–व्यक्ति आदान–प्रदान को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क को प्रोत्साहित किया गया है। हमारी विदेश नीति के दृष्टिकोण में दक्षिण–पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भारत के पडोसी देशों के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पूर्व–एशिया

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) : इस अवधि में भारत और कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। दोनों राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक–दूसरे का सहयोग करना जारी रखा। डीपीआरके ने यूएनएचआरसी (2015–2017) में; वर्ष 2014 से 2018 तक की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण से संबंधित अंतर–सरकारी समिति और वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक की अवधि के लिए एशिया–प्रशांत टेली–समुदाय के महासचिव पद पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

जापान : भारत–जापान के साथ अपने शांति, समृद्धि और विकास आधारित द्विपक्षीय संबंधों का भरपूर लाभ उठा रहा है। भारत–जापान संबंधों को विस्तृत करने का कार्य जारी रखा गया और यह गतिमान विकास दोनों देशों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा बातचीत में परिलक्षित हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री श्री शिनो अबे ने भारत का प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वार्षिक शिखर बैठक के लिए 30 अगस्त से 03 सितम्बर, 2014 तक जापान की सरकारी यात्रा की। यह भारत के बाहर किसी बिल्कुल पडोसी देश की प्रथम प्रमुख द्विपक्षीय यात्रा थी। विदेश सचिव, श्रीमती सुजाता सिंह ने अपने जापानी समकक्ष के साथ उप–मंत्री स्तरीय परामर्श करने के लिए 23 से 26 अप्रैल, 2014 तक टोक्यों की यात्रा की।

मंगोलिया : भारत–मंगोलिया संबंधों को सुदृढ़ करने का कार्य जारी रखा गया। दोनों राष्ट्रों ने दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को आयोजित प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) के दौरान अपने समग्र संबंधों को और मजबूत किया। दोनों देशों ने वार्षिक सैनिक अभ्यास में भाग लिया। भारत ने सिविल, रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में मंगोलिया को विकास सहायता प्रदान करना

जारी रखा। इस अवधि में मंगोलियों के साथ आर्थिक तथा व्यापार संबंधों में प्रगति हुई। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक–दूसरे का समर्थन करना जारी रखा।

कोरिया गणराज्य (आरओके) : भारत और दक्षिण कोरिया ने राजनीतिक सहयोग, आर्थिक भागीदारी और सांस्कृतिक आदान–प्रदान में और वृद्धि करके अपनी कार्यनीतिक भागीदारी का तीव्र विस्तार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईएएस और आसियान शिखर सम्मेलन के बाद दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को राष्ट्रपति सुश्री पार्क जुइन–ही से बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए विचारों का आदान–प्रदान किया। दोनों देशों के मध्य रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और सुदृढ़ किया गया।

यूरेशिया

भारत के 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त' भागीदार के रूप में रूस ने भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है। दिसम्बर, 2014 में 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन की भारत यात्रा से रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। इस यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रेखांकित किया जिसके आधार पर आगामी वर्षों में संबंध निर्धारित होंगे। भारत ने यूक्रेन और बेलारूस के साथ अपने राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना जारी रखा। भारत के पडोसी के भाग के रूप में मध्य एशिया क्षेत्र का अपना विशेष महत्व है जिसके साथ भारत ने अपने संबंधित को व्यापक 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के तहत और प्रगाढ़ किया है। भारत ने दक्षिणी कराकोस (अर्मेनिया, अजरबेजान जार्जिया) के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना तथा व्यापक करना जारी रखा।

रूसी परिसंघ : रूस के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए नई सरकार ने कार्यभार संभालते ही रूस के साथ सम्पर्क स्थापित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील में (जुलाई, 2014) शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन से बातचीत की; इसके बाद आस्ट्रेलिया में (नवम्बर, 2014) में समूह–20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवम्बर, 2014 में आयोजित किए गए पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार में रूस के प्रधानमंत्री श्री दिमित्र मेद्वेदेव से भी बातचीत की। राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन ने दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा की जिसके दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में सार्थक विचार–विमर्श किया। इस शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप कम से कम बीस करार सम्पन्न किए गए (सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के) जिनमें दो लक्ष्य दस्तावेज अर्थात (i) द्रुझबा– दोस्ती : अगले दशक में भारत–रूस भागीदारी को सुदृढ़ करने संबंधी दृष्टिकोण और (ii) भारत गणराज्य तथा रूसी परिसंघ के मध्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में सहयोग को सुदृढ़ करने का रणनीतिक लक्ष्य शामिल किए गए।

रूस के उप–प्रधानमंत्री श्री दिमित्रि रोगोजिन ने वर्ष 2014 में तीन बार नई दिल्ली की यात्रा की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने दुशाम्बे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान और न्यूयार्क में यूएनजीए सम्मेलन के दौरान रूस के विदेश मंत्री श्री सेरजई लावरोव से बातचीत की। विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने अपने समकक्ष के साथ विदेश कार्यालय स्तरीय परामर्श करने के लिए मार्च, 2014 में मास्को की यात्रा की।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित भारत–रूस अंतर–सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी–टीडीसी) का बीसवां सत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसकी सह–अध्यक्षता रूस के उप–प्रधानमंत्री श्री दिमित्रि रोगोजिन और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने की। संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा अवसरों को प्राप्त करने के लिए 20वें आईजीसी के संबंध में तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए विभिन्न कार्य समूहों की बैठक आयोजित की गई।

वर्ष 2014 में भारत और रूस के मध्य ऊर्जा सहयोग को और सुदृढ़ किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 21वीं विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में भाग लेने के लिए 18 से 21 जून, 2014 तक रूस की यात्रा की। ओएनजीसी और रूस की कम्पनी रोज्नेफ्ट ने आर्कटिक शेल्फ में तेल और गैस की खोज के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है।

रूस की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक यात्राओं में 'वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन' को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात से एक प्रतिनिधिमंडल, वाणिज्य सचिव की यात्रा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एपीईडीए) से प्रतिनिधिमंडल तथा पर्यटन प्रतिनिधिमंडल की यात्रा शामिल हैं।

लगभग 15 वर्ष के बाद एयर इंडिया ने मास्को को अपनी हवाई यात्रा पुनः शुरू की है। इसे साथ–साथ इस वर्ष के दौरान सांस्कृतिक आदान–प्रदान, पर्यटन, अकादमिक आदान–प्रदान और व्यक्ति–दर–व्यक्ति सम्पर्क में वृद्धि हुई है।

बेलारूस : गर्मजोशी तथ प्रत्यक्ष सहयोग के माध्यम से भारत और बेलारूस के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना जारी रखा गया। भारत ने कतिपय परम्परागत शस्त्र प्रोटोकाल ट सहायता कार्यक्रम से संबंधित समझौते के तहत बेलारूस को 90 रेडियो सैट और 30 जीपीएस नेविगेशन की आपूर्ति की है तथा 25 खान अन्वेषण उपकरणों की आपूर्ति को मंजूरी प्रदान की है।

यूक्रेन : यूक्रेन में संकट के बावजूद भारत ने इस देश के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने का कार्य जारी रखा। यूक्रेन की सरकार ने जून, 2014 में भारतीय विद्यार्थियों को पूर्वी क्षेत्र के

लुगान्सक से किवी मे ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था करके किवी में भारतीय मिशन को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की। इसके बाद भारतीय मिशन ने उनके आवास तथा उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था की। भारतीय विद्यार्थियों को पूर्वी क्षेत्रों के चिकित्सा कॉलेजों से देश के अन्य शांतिपूर्ण स्थानों पर भेजने में भी यूक्रेन सरकार ने भारतीय मिशन की सहायता की।

मध्य एशिया

भारत ने मध्य एशियाई देशों (तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किरगिस्तान और तजाकिस्तान) जो भारत के पडोसी देशों में शामिल हैं, के साथ उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने तजाकिस्तान की यात्रा की, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने कजाकिस्तान में शासी बोर्ड की 47वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। तृतीय कनेक्ट सेंट्रल एशिया ट्रैक । वार्ता दुशाम्बे में अक्तूबर, 2014 में आयोजित की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (टीएपीआई) गैस पाइप लाइन की 19वीं संचालन समिति बैठक के लिए तुर्कमेनिस्तान जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ0) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने दिसम्बर, 2014 में सरकार प्रमुखों की एस.सी.ओ. परिषद की बैठक के संबंध में अस्ताना, कजाकिस्तान की यात्रा की और उन्होंने कजाक प्रधानमंत्री श्री करीम मैस्सीमॉव के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

दक्षिणी कोकासस

अर्मेनिया, अजरबेजान और जार्जिया के दक्षिणी कोकासस देशों के द्विपक्षीय संबंधों में बेहतर द्विपक्षीय समन्वय रहा। यूरोप तथा एशिया के बीच में पड़ने वाले इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित होने की संभावित क्षमता है जिससे भारतीय कारोबार को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

एक भागीदार के रूप में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के साथ प्रमुख ऊर्जा बीपी के नेतृत्व में दक्षिणी गैस कोरिडोर परियोजना के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ ने सितम्बर, 2014 में बाकू में अभूतपूर्व समारोह आयोजित किया जो जार्जिया और टर्की के माध्यम से यूरोप को अजरबेजान की गैस प्रदान करेगा।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सहयोग से संबंधित भारत–जार्जिया अंतर–सरकारी आयोग का प्रथम सत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अर्मेनिया में टेली मेडिसिन नेटवर्क स्थापित करने और अर्मेनिया के क्षेत्र में 50 विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

भारत सुरक्षा और विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए शंघाई सहयोग संगठन को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच के रूप में देखता है। दुशांबे, तजाकिस्तान में दिनांक 11–12 सितम्बर, 2014 को विभिन्न देशों के एससीओ प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया जिसमें भारत ने एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ0) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को अस्ताना, कजाकिस्तान में सरकारों की एससीओ परिषद को प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधितव किया।

खाडी, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी एशिया

इस वर्ष के दौरान खाडी क्षेत्र के देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक, परम्परागत और प्रत्यक्ष तथा बहु–आयामी मैत्री संबंधों को और सुदृढ़ किया गया। खाडी क्षेत्र विश्व में भारत के लिए पर्याप्त रूप से व्यापारिक क्षेत्र रहा है और इसके साथ वर्ष 2013–14 में 171.8 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया है। कच्चे तेल और एलएनजी का मुख्य आपूर्तिकर्ता होने के कारण यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग एक–तिहाई भाग प्रदान करता है। सऊदी अरब, इराग, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए सर्वोच्च पांच तेल स्रोत देशों में बने रहे।

भारत और खाडी क्षेत्र के देश एक–दूसरे देश में निवेश करते हैं और भारत, खाड़ी क्षेत्र के देशों से विशेष रूप से अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करने के लिए सक्रिय रहा है। खाडी क्षेत्र के देशों में लगभग 7 मिलियन भारतीय रहते हैं और इसके विकास में पर्याप्त योगदान कर रहे हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नवम्बर 2014 में कुवैत के उप–प्रधानमंत्री अब्दुल मोहसिन मेदाज अल–मेदाज और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की भारत यात्राओं, जून 2014 में विदेश मंत्री श्री युसुफ बिन अल्वाई बिन अब्दुल्ला की भारत यात्रा तथा नवम्बर, 2014 में सऊदी अरब सल्तनत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री तवाफिक फवजान अल रवैया की भारत यात्रा सहित उच्चतम स्तर पर की जाने वाली यात्राओं से और सुदृढ़ किया गया है। इस अवधि के दौरान विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की सितम्बर में बहरीन यात्रा और नवम्बर, 2014 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। खाडी क्षेत्र के देशों की शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि में हमारी बढ़ती हिस्सेदारी से भारत ने इस क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी जारी रखी है।

पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत के पडोसी क्षेत्र का एक भाग है तथा इसका अधिक महत्व है। इस क्षेत्र में लगभग 7 मिलियन भारतीय रहते हैं और जो लगभग 40 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान करते हैं। इस क्षेत्र के साथ हमारे आर्थिक तथा वाणिज्यिक कार्यकलाप लगभग 185.6 बिलियन अमरीकी डालर (2013–14) के हैं। यह क्षेत्र हमारी 60 प्रतिशत से भी अधिक तेल तथा गैस आवश्यकता का स्रोत हैं और इसलिए यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अध्यधिक महत्वपूर्ण हैं। माघरेब क्षेत्र फास्फेट तथा अन्य

उर्वरक का प्रमुख स्रोत हैं जो हमारी खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सतत शांति तथा स्थिरता हमारे रणनीतिक हित में है।

इस वर्ष के दौरान यह क्षेत्र अनिश्चितता तथा गतिरोध की स्थिति में रहा जिससे संबंधित कार्यकलापों का पूर्णतः मूल्यांकन करने में कठिनाई पैदा हुई। सीरिया, लीबिया, इजराइल, फलस्तीन, लेबनान इत्यादि देशों में जारी संघर्ष को इरान परमाणु बातचीत तथा इस क्षेत्र में आईएसआईएस के उत्थान से प्रोत्साहन मिला है। इस क्षेत्र के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के आधार पर हमने अपनी स्थिति बनाए रखी और हम ने इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने अथवा इनमें निर्धारक बनने की इच्छा नहीं की। पश्चिम एशिया में परिवर्तशील परिस्थिति की चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हमारे मुख्य आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा हितों की रक्षा करने के लिए प्रगतिमूलक बने रहे।

इस क्षेत्र में विशेष रूप से आईएसआईएस के उत्थान से पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए रणनीतिक सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। इस संबंध में हमारा विचार यह है कि आईएसआईएस चुनौती का ठोस समाधान केवल इस क्षेत्र में बढ़ते उग्रवाद तथा अतिवादी विचारधारा का समाधान करने के लिए व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही किया जा सकता है। स्थाई राज्य संस्थाओं का निर्माण करते समय राजनीतिक प्रक्रिया तथा समाधान में तालमेल करना महत्वपूर्ण था। इस मुद्दे पर अलग–अलग दृष्टिकोण के बजाए आसूचना साझा करने, आतंकवादरोधी; साइबर स्पेस सहयोग जैसे पहलुओं को शामिल करके समेकित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इराक और सीरिया में विदेशी लडाकों को जाने से रोका जा सके; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर (अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में व्यापक समझौते को शीघ्र अपनाने सहित) आतंकवाद को रोकने के लिए विधिक कार्य संरचना तैयार की जा सके; वित्तीय संसाधनों और मानवीय सहायता का पता लगाया जा सके। इराकी–सीरिया युद्ध क्षेत्र में कुछ भारतीय जिहादी लडाकों के होने की सूचना मिली थी किंतु सरकार ने प्रवास नियंत्रण, आसूचना साझा करने तथा राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क करके इसे रोकने के उपाय किए हैं।

हमने अपने आर्थिक/ऊर्जा हितों को बढ़ाने के लिए अपने संबंधों को विविध स्वरूप प्रदान करने हेतु लीबिया के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते रहे हैं। सूडान और दक्षिण सूडान में हमने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति को जारी रखा और इन दोनों देशों में अपने समग्र ऊर्जा हितों पर विचार करते हुए विकास भागीदारी पहल जारी (ओवीएल और भारतीय तेल निगम की सूडान तथा दक्षिण सूडान में लगभग 2.5 बिलियन अमरीकी डालर परिसम्पत्तियां हैं) रखी हैं। अपने आपसी लाभदायक राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए हमने अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, मौरक्को, लेबनान, जार्डन और दिजिबोटी के साथ बातचीत जारी रखी। फार्मास्युटिकल्स, आटोमोबाइल, अवसंरचना, आवास–व्यवस्था, आतिथ्य, विद्युत उत्पादन और पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा जैस नए आर्थिक क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया गया। सोमालिया के साथ हमारे समुद्री युद्धबंदियों को सुरक्षित छुड़ाने के बारे में हमारा सहयोग सीमित रहा है।

अफ्रीका

भारत के अफ्रीकी देशों के साथ गहरे और प्रगाढ़ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध हैं जो उनकी आजादी से लेकर अब तक और सुदृढ़ होते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत के आर्थिक महत्व और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सद्भावना ने भारत–अफ्रीका संबंधों के आयाम सतत रूप से विस्तृत करने में योगदान किया है।

भारत और अफ्रीका के पास द्विपक्षीय, बहु–पक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए विस्तृत राजनयिक तंत्र तथा चैनल हैं। इस प्रकार तंत्र के माध्यम से विकास सहायता, रक्षा सहयोग, अवसंरचना तथा क्षमता निर्माण पहल आगे बढ़ाई जा रही है। इनमें विभिन्न प्रकार के विषयों के संबंध में भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस), भारत–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (आरईसी) बैठक, वार्षिक भारत–अफ्रीकी व्यापार मंत्री बैठक, आईओआर–एआरसी जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से बातचीत, संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठक, विदेश कार्यालय परामर्श और अंतर–सरकारी संयुक्त आयोग शामिल हैं।

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि इन क्षेत्रों में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की झलक है। भारत ने कृषि, श्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कोयला, खजिन संसाधन, तेल और गैस तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के बारे में अफ्रीकी भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन और करार सम्पन्न किए हैं।

अगले कुछ दशकों में भारत और अफ्रीका दोनों देशों में जनसंख्या लाभांश से लाभ प्राप्त करने की संभावित क्षमता है। ऐसा इसके मद्देनजर है कि भारत क्षमता निर्माण पहल में अफ्रीका की सहायता कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत की स्वयं की अद्भुत विशेषज्ञता को आईटीईसी, छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप कार्यक्रमों, अखिल अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजना इत्यादि के माध्यम से साझा किया जा रहा है। प्रति वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग और वित्त, प्रबंधन, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, मतदान प्रक्रियाविधि इत्यादि सहित अनेक विषयों में हजारों अफ्रीकी राष्ट्रिक प्रशिक्षित किए जाते हैं।

कृषि और सिंचाई, विद्युत उत्पादन, अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन इत्यादि के लिए रियायती ऋण सीमा से भागीदारी को और सुदृढ़ किया गया है।

भारत सरकार रक्षा और सुरक्षा विशेषकर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों सहित अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ

प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रही है। भारतीय नौसेना हिन्द महासागर क्षेत्र (आईओआर) में पाइरेसी विरोधी अभियान चलाती है और इसने अफ्रीका में आईओआर राष्ट्रों के कुछ नौसेना संगठनों को प्रशिक्षण तथा प्रचालनों में सहायता भी प्रदान की है। इसने जल संबंधी सर्वेक्षण भी किए हैं और इन देशों को मानवीय सहायता भी प्रदान की है।

यूरोप

पश्चिमी यूरोप

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने वर्ष 2014 में अपनी रणनीतिक भागीदारी की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। यूरोपीय संघ भारत का बहुमूल्य रणनीतिक भागीदार है और यूरोपीय संघ तथा इसके पूर्ववर्ती देशों के साथ भारत के संबंध आधी सदी से हैं। यूरोपीय देशों के समूह के रूप में यह सामान्य बाजार से सामान्य मुद्रा के रूप में और समुदाय से संघ के रूप में उभरा है, यूरोपीय संघ के साथ भारत की साझेदारी पर्याप्त रूप से बढ़ी है जिससे अलग–अलग यूरोपीय संघ सदस्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूती तथा सुदृढ़ आधार मिला है।

शिक्षा, संस्कृति और व्यक्ति–दर–व्यक्ति संबंधों को बेहतर बनाना एक महत्वपूर्ण सतत प्राथमिकता रही है। ये संबंध जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, काफी परिपक्व हो गए हैं। हमने वर्ष 2013 में अपने द्विपक्षीय संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाई है।

यूरोपीय संसद का चुनाव दिनांक 22 से 25 मई, 2014 के दौरान हुआ था। इन चुनावों में यूरोपीय जनवादी पार्टी (ईपीपी) सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। नई यूरोपीय संसद ने लक्समबर्ग के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जीन क्लाउड जुंकेर को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना है। इटली की पूर्व विदेश मंत्री सुश्री फेडरिका मोघिरिनी को विदेश मामले और सुरक्षा नीति के नए यूरोपीय संघ उच्च प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। नए आयेाग ने दिनांक 01 नवम्बर, 2014 को पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

यूरोपीय परिषद ने पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डोनाल्ड टस्क को यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना है। यूरोपीय संसद के चुनाव के बाद संसद में संख्या के अनुसार विभिन्न राजनीतिक समूहों से 43 सदस्यों वाला भारत के साथ संबंध के बारे में एक नया प्रतिनिधिमंडल गठित किया गया है। इस नए प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष श्री जियोफ्रे वैन आर्डेन हैं।

दिनांक 14 नवम्बर, 2014 को ब्रिस्बन में समूह–20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री हेरमन वैन रोम्पू के साथ आयोजित की गई बैठक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

28 देशों के ब्लॉक के रूप में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार भगीदार है जबकि वर्ष 2013 में भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा क्षेत्रीय भागीदार था। वर्ष 2013 (जनवरी–दिसम्बर 2014) के दौरान यूरोपीय संघ 28 के साथ भारत का समग्र द्विपक्षीय व्यापार (माल और सेवाएं दोनों) 96.6 बिलियन यूरोपीय डालर (माल का द्विपक्षीय व्यापार 72.7 बिलियन यूरोपीय डालर और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 23.9 बिलियन यूरोपीय डालर) था। सेवाओं से संबंधित व्यापार वर्ष 2012 में 22.5 बिलियन यूरोपीय डालर की तुलना में वर्ष 2013 में 6.22 प्रतिशत बढ़कर 23.9 बिलियन यूरोपीय डालर हो गया है। वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ को भारतीय माल का निर्यात 36.8 बिलियन यूरोपीय डालर है जबकि यूरोपीय संघ से भारत का आयात 35.9 बिलियन यूरोपीय डालर रहा है।

वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ से भारत को 3.2 बिलियन यूरोपीय डालर मूल्य के प्रत्यक्ष विदेश निवेश के प्रवाह के साथ यूरोपीय संघ भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ 28 में भारतीय निवेश 0.4 बिलियन यूरोपीय डालर का रहा।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संयुक्त कार्य समूह का 9वां दौर दिनांक 14–15 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यूरोपीय संसद का एक प्रतिनिधिमंडल दल दिनांक 22 से 26 फरवरी, 2015 तक भारत की यात्रा करेगा।

मध्य यूरोप

भारत ने मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ अपनी सक्रिय तथा सहयोग करने वाली नीति को जारी रखा और अपनी भागीदारी को सुदृढ़ तथा गहरी करने की कार्यवाही कर रहा है। मध्य यूरोपीय क्षेत्र के साथ भारत की कार्यनीतिक भागीदारी की मुख्य विशेषता महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय आदान–प्रदान तथा द्विपक्षीय सहयोगी प्रयास है। सरकारी यात्राओं, बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार, कारोबार आदान–प्रदान, शैक्षिक आदान–प्रदान और सांस्कृतिक कार्यकलापों से इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को आगे ले जाने में सहायता मिली है। मध्य यूरोप के लिए भारत भी इसकी प्रगति तथा विकास में महत्वपूर्ण मित्र और भागीदार है। इसके साथ राजनीतिक मुद्दों के बारे में द्विपक्षीय तथा बहु–पक्षीय मंचों पर बेहतर आपसी समझबूझ रही। इस वर्ष दोनों पक्षों की ओर से आनेक उच्च स्तरीय यात्राएं की गईं। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत से राष्ट्राध्यक्ष की प्रथम यात्रा के रूप में दिनांक 12 से 14 अक्तूबर, 2014 तक नार्वे की और दिनांक 14 से 16 अक्तूबर, 2014 तक फिनलैंड की राजकीय यात्रा की। भारत की विदेश नीति में भी इस मध्य यूरोप क्षेत्र के देशों के साथ सुदृढ़ बहु–स्तरीय आयाम शामिल किए गए हैं और ये अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा मंचों पर प्रत्यक्ष रूप से मिलकर कार्य करते हैं।

अमरीकी देश

कनाडा : हाल ही के वर्षों भारत–कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में

महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिकए सुरक्षाए व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करके उच्च स्तरीय बातचीत के द्वारा और सुदृढ़ किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री स्टीफन हार्पर ने वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक की छोटी अवधि में ही दो बार भारत की यात्रा की; महासचिव श्री डेविड जॉनसन ने फरवरी–मार्च 2014 में भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री श्री स्टीफन हार्पर ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कनाडा की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया।

वर्ष 2012 में कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने ऊर्जा सुरक्षा; कृषि और खाद्य सुरक्षा; खनिज संसाधन; अवसंरचना विकास तथा समुन्नत सिविल, रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे आपसी हित के मुख्य क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य रणनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय भागीदारी को सुदृढ़ करके और मौजूदा महत्वपूर्ण कार्यकलापों में बेहतर रूप से वृद्धि करके दूरगामी संबंध स्थापित करने के लिए सार्थक प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इन्होंने नियमित बैठकों के माध्यम से अपनी भागीदारी को सुदृढ़ करने तथा दोनों विदेश मंत्रियों के मध्य वार्षिक कार्यनीतिक बातचीत की व्यवस्था करने के लिए अपनी बातचीत को बेहतर स्वरूप प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। द्विपक्षीय ऊर्जा बातचीत को भी मंत्री स्तर तक स्तरोन्नत किया गया है। प्रथम मंत्री स्तरीय ऊर्जा बातचीत अक्तूबर, 2013 में की गई।

संयुक्त राज्य

मई 2014 में भारत के आम चुनावों के बाद से संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी में वर्ष 2014 में गुणात्मक परिवर्तन हुआ और भारत–अमरीकी रणनीतिक वार्ता के चौथे दौर के लिए जुलाई, 2014 में अमरीकी उपमंत्री श्री जॉन कैरी तथा वाणिज्य मंत्री सुश्री पेन्नी प्रिज्कर की यात्राओं और अगस्त 2014 में अमरीकी रक्षा मंत्री श्री चूक हगेल की यात्रा सहित संयुक्त राज्य अमरीका के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की। इस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयार्क की यात्रा के साथ अमरीकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के आमंत्रण पर अपनी वाशिंगटन की द्विपक्षीय यात्रा के साथ दिनांक 26 से 30 सितम्बर, 2014 तक अमरीका की यात्रा की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अमरीका जाने वाले प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा में भाग लेने के लिए दिनांक 24 सितम्बर, से 2 अक्तूबर, 2014 तक अमरीका की यात्रा की।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओमाबा ने 26 जनवरीए 2015 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा की। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐसे प्रथम अमरीकी राष्ट्रपति थे जो भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वे ऐसे प्रथम अमरीकी राष्ट्रपति भी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में दो बार भारत की यात्रा की है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि दो देशों के मध्य दो शिखर स्तरीय बैठकें केवल चार माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी।

लैटिन अमरीकी तथा कैरेबियाई देश

पिछला वर्ष लैटिन अमरीकी तथा कैरेबियाई क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी के लिए बहुत ही सार्थक रहा है। वर्ष के दौरान विशिष्ट उच्च स्तरीय यात्राओं, द्विपक्षीय करार, बहु–पक्षीय तथा द्विपक्षीय कार्यकलापों को सम्पन्न करने, विकास परियोजनाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के माध्यम से भागीदारी के बढ़ते स्तर से भारत और इस क्षेत्र के मध्य द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दक्षिण अमरीकी नेताओं के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण बैठक और जुलाई, 2014 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रेसिलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक से इस पूरे क्षेत्र के साथ हमारी भागीदारी का स्तर निर्धारित हुआ है। यह प्रथम बार हुआ कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इतने अधिक दक्षिण अमरीकी नेताओं के साथ बातचीत की हो।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सितम्बर, 2014 में न्यूयार्क में यूएनजीए के दौरान लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई राज्यों के समुदाय (सीईएलएसी) क्वारटेट से बातचीत की। इस बैठक के दौरान कोस्टारिका, इक्वेडोर और एंटीगुआ तथा बारबुडा के विदेश मंत्री और क्यूबा के विदेश उपमंत्री उपस्थित रहे। इसमें अनेक सीईएलएसी समन्वयक भी उपस्थित थे। इस संबंध में भारत ने यह प्रस्ताव किया है कि भारत–सीईएलएसी व्यापार परिषद और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच, ऊर्जा मंच और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंच की बैठक वर्ष 2015 में आयोजित की जानी चाहिए।

विदेश राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष गंगवार के नेतृत्व में 7 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सद्भावना यात्रा पर दिनांक 26 अक्तूबर से 05 नवम्बर, 2014 तक अर्जेन्टीना, चिली और मैक्सिको की यात्रा की।

गुयाना के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड रबिन्द्रनाथ रामोतार ने दिनांक 07 जनवरी से 12 जनवरी, 2015 तक भारत की द्विपक्षीय यात्रा की। वे दिनांक 07 से 09 जनवरी, 2015 तक आयोजित किए गए 13वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे जहां उन्हें 'प्रवासी भारतीय सम्मान' से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ विचार–विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने वलसाद में एक चीनी उद्योग का भी दौरा किया और मुम्बई में चीनी उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ (फिक्की) ने दिनांक 15–16 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में भारत–एलएसी निवेश संगोष्ठी आयोजित की। इसमें अर्जेंटीना के विदेश उपमंत्री श्री

कारलोस बियान्को नेतृत्व में 70 सदस्यीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ने ''भागीदार देश'' के रूप में अर्जेन्टीना का प्रतिनिधित्व किया। इस संगोष्ठी में ''विशेष महत्वपूर्ण देश'' पेरू था।

वर्ष 2014 में (अप्रैल–अक्तूबर) एलएसी क्षेत्र के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार 25.4 बिलियन अमरीकी डालर था और इस क्षेत्र में हमारा संचित निवेश अनुमानित 20 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक था। हमारी ऊर्जा तथा खद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में विपुल संभावित क्षमता है। लैटिन अमरीकी क्षेत्र भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है क्योंकि वास्तविक स्थिति तथा प्रतिशत स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र से भारत को आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। एलएसी के भीतर वर्ष 2013–14 में वेनेजुएला सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला रहा जबकि द्वितीय स्थान पर कोलम्बिया उभर रहा है, मैक्सिको तथा ब्राजील क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। हमारे बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी यह क्षेत्र कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है।

प्रधानमंत्री ने जुलाई, 2014 में ब्रेसिलिया में लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई क्षेत्र के नेताओं के साथ अपनी बातचीत में संबंधित देशों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करके सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के अनुभव को साझा करने का प्रस्ताव किया था। कराकास, ब्यूनोस एयर्स, पराग्वे, उरूग्वे, जार्जटाउन, पैरामरिबो और सेंटिगो में इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

भारत दक्षिण–दक्षिण सहयोग के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने के भाग के रूप में आईटीईसी छात्रवृति कार्यक्रम, ऋण सीमा, सहायता–अनुदान और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से इस क्षेत्र के कुछ विकासशील देशों को भी सहायता प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 24 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2014 तक संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 69वें सत्र की आम बैठक में सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस आम बैठक के दौरान दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के शीघ्र सुधार तथा पुनर्गठन का जोरदार समर्थन किया ताकि इसमें वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता परिलक्षित हो सके। उन्होंने इस प्रकार के सुधारों को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 70वीं वर्षगांठ तक पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने सचेत किया कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी न बनाया गया तो इसके सामने अपनी प्रासंगिकता खोने की चुनौती होगी और विश्व को अपनी समस्या का समाधान करने की सक्षम व्यवस्था न होने के कारण सतत समस्या का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गरीबी उन्मूलन को उत्तर–2015 विकास कार्यसूची का मुख्य विषय बनाए रखा जाना चाहिए और इस ओर प्रत्येक को पूरा ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और उग्रवाद को रोकने के लिए गहन अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित व्यापक समझौते को अपनाना चाहिए। उन्होंने कुछ देशों की अपने यहां आतंकवादियों को पनाह देने अथवा अपने नीति के भाग के रूप में आतंकवाद का सहारा लेने के लिए निंदा की। उन्होंने योग के लाभ और इसकी वैश्विक अपील को ध्यान में रखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान–की–मून से भी द्विपक्षीय बातचीत की।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने दिनांक 23 सितम्बर से 02 अक्तूबर, 2014 तक यूएनजीए सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयार्क की यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय समूह के नेताओं के साथ मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया। उन्होंने यूके, चीन, सूडान, मालदीव, किरगिझ गणराज्य, नाइजीरिया, नार्वे, यूनान और इजराइल के अपने समकक्ष नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं। विदेश मंत्री दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना के संयुक्त राष्ट्र संघ स्मारक में साहसी संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सैनिकों की स्मृति में हार पहनाने वाली प्रथम गणमान्य व्यक्ति बन गई हैं।

प्रधानमंत्री के सम्बोधन से पहले भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के समूह–4 विदेश मंत्रियों ने 69वें यूएनजीए सत्र के अवसर पर दिनांक 25 सितम्बर, 2014 को न्यूयार्क में बैठक की। उन्होंने 21वीं सदी की भू–राजनीतिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करने वाली बेहतर सुरक्षा परिषद के संबंध में अपनी सतत प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए अपने इस विचार की पुष्टि की बड़ी सुरक्षा परिषद की स्थाई और अस्थाई दोनों ही प्रकार की श्रेणियों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद मुख्यालय, न्यूयार्क में भारत के स्थाई मिशन द्वारा आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। विदेश मंत्री ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इसमें अग्रणी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से चलाए जाने वाले शांति अभियानों में सर्वाधिक सैनिक योगदान करने वाले देशों में शामिल है। इस समय चलाए जा रहे 16 शांति अभियानों में से 10 शांति अभियानों में भारतीय सैनिक शामिल हैं। भारत फरवरी 2007 से लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के इतिहास में पहली बार महिलाओं की पुलिस यूनिट से योगदान कर रहा है।

प्रधानमंत्री के योग दिवस मनाए जाने के आह्वान के अनुसरण में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिनांक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए संकल्प भेजा है। इस संकल्प को

दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को 177 सह–प्रायोजक देशों की रिकार्ड संख्या ने स्वीकार किया और इस प्रकार यह अपनी तरह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकल्प है।

भारत ने सोमालिया के अपतटीय क्षेत्र में पाइरेसी से संबंधित सम्पर्क समूह की सम्पूर्ण बैठक में (सीजीपीसीएस) सक्रिय रूप से भाग लिया और अत्यधिक जोखिम क्षेत्र तथा प्राइवेट समुद्री सुरक्षा कम्पनियों के विनियमन और बोर्ड शिप पर प्राइवेट संविदा आधारित सशस्त्र सुरक्षा कार्मिकों के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया। सीजीपीसीएस की 16वीं पूर्ण बैठक दिनांक 14 मई, 2014 को न्यूयार्क में और सीजीपीसीएस की 17वीं पूर्ण बैठक दिनांक 28 अक्तूबर, 2014 को दुबई में आयोजित की गई। पाइरेट के कारण बंधक बनाए गए 7 भारतीयों नाविकों को मुक्त करा लिया गया है और अब कोई बंधक नहीं रहा है।

इस अवधि के दौरान भारत राष्ट्रमंडल बजट में चौथा सबसे ज्यादा योगदानकर्ता और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में पांचवा सबसे ज्यादा योगदानकर्ता बना रहा। वर्ष 2013–15 की अवधि के लिए पुनर्गठित राष्ट्रमंडल मंत्री कार्य समूह (सीएमएजी) का भारत सदस्य है। राष्ट्रमंडल महासचिव श्री कमलेश शर्मा ने दिनांक 1–2 दिसम्बर, 2014 को नई दिल्ली की यात्रा की और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री से मुलाकात की।

संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक आतंकवादरोधी कार्यनीति समीक्षा (जीसीटीएस) की चौथी द्विवार्षिक समीक्षा दिनांक 12–13 जून, 2014 को की गई। भारत ने जीसीटीएस से संबंधित संकल्प को अंतिम रूप देने में योगदान किया। दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विदेशी आतंकवादी लडाकों के बढ़ते खतरे से संबंधित संकल्प 2178 (2014) को स्वीकार किया जिससे विश्व का लगभग प्रत्येक देश प्रभावित है।

भारत ने दिनांक 26 से 29 मई, 2014 तक अल्जीयर्स, अल्जीरिया में आयोजित किए गए मध्यकालिक एनएएम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अगला एनएएम शिखर सम्मेलन सितम्बर 2015 में वेनेजुएला में आयोजित किया जाएगा।

लोकतंत्र संबंधी पहल के लिए अपनी सहायता को बनाए रखते हुए भारत ने दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को न्यूयार्क में आयोजित किए गए यूएनजीए के दौरान लोकतंत्र शासी परिषद के समुदाय की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया और दिनांक 10–11 अक्तूबर, 2014 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किए गए 7वें बाली लोकतंत्र मंच (बीडीएफ VII) में भाग लिया। लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के कारगर माध्यम के रूप में निधि के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र निधि में नवम्बर, 2014 तक 31.56 मिलियन अमरीकी डालर की संचित राशि का योगदान किया है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काठमाण्डू ने 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में (26–27 नवम्बर, 2014) भाग लिया। उन्होंने सार्क प्रक्रिया के संबंध में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कुछ एकपक्षीय पहल की घोषणा की। इस शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने दिनांक 23 से 25 नवम्बर, 2014 तक क्रमशः मंत्री परिषद के 36वें सत्र और स्थाई समिति के 41वें सत्र में भाग लिया।

भारत आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिविटी और ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित करने वाली कुछ क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है तथा उन्हें जारी रखता रहा है। भारत का सक्रिय, समान और गैर–पारस्परिक दृष्टिकोण सार्क की कारगरता में वृद्धि करने का परिवर्तनकारी घटक रहा है।

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

भारत ने इस वर्ष के दौरान शाश्वत और गैर–भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण और सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के बारे में अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित विभिन्न बहु–पक्षीय मंचों पर विशेष रूप से परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे, निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार के संबंध में अपनी नीतियों पर आगे बढ़ना जारी रखा है। निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ प्रत्यक्ष भागीदारी की इसकी परम्परा पर आधारित है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रथम समिति, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यूएनडीसी) निरस्त्रीकरण से संबंधित सम्मेलन (सीडी), जैविक और विषैले हथियार समझौता (बीटीडब्ल्यूसी), कतिपय परम्परागत हथियारों से संबंधित समझौता (सीसीडब्ल्यू) और छोटे तथा हल्के हथियारों से संबंधित कार्रवाई के संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम (एसएएलडब्ल्यू से संबंधित यूएनपीओए) सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ने वर्ष 2013 सत्र में छह अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष के रूप में निरस्त्रीकरण सम्मेलन की अध्यक्षता की। निरस्त्रीकरण से संबंधित सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत ने इस सम्मेलन में पर्याप्त सार्थक कार्य शुरू करने के सभी प्रयास किए और सम्मेलन के सभी सदस्य देशों के साथ व्यापक परामर्श किया। भारत ने शस्त्र व्यापार नीति (एटीटी) से संबंधित राजनयिक सम्मेलन में भी भाग लिया। भारत ने आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठकों तथा एशिया में आपसी तालमेल और आत्मविश्वास पैदा करने से संबंधित सम्मेलन (सीआईसीए) में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार मुद्दों पर विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्श किया और अपनी बातचीत को बहु–पक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था से आगे बढ़ाया। मंत्रालय ने भारत के निर्यात नियंत्रण कानूनों और अधिक विध्वंसक हथियार (डब्ल्यूएमडी) अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन में अपने उत्तरदायित्व का सफल निर्वहनकिया। निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के क्षेत्र में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों

के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखा गया।

बहु–पक्षीय आर्थिक संबंध

वैश्विक आर्थिक सुधार और सतत आर्थिक विकास से रोजगार अवसर सृजित करने की कार्यनीतियां विकसित हुई हैं और असमानता को कम करने, बहु–पक्षीय व्यापार प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन अब ब्रिक्स, समूह–20, हिन्द महासागर रिम संघ (आईओआरए) इत्यादि जैसे बहु–पक्षीय समूहों की कार्यसूची के महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं। इबोला की समस्या और यूक्रेन के आस–पास की भू–राजनीति गतिविधियों की छाया भी कुछ बहु–पक्षीय समूहों की कार्यसूची पर देखी जा सकती है। भारत ने इस प्रकार की बहु–पक्षीय बैठक में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी जारी रखी ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की ओर बढ़ा जा सके तथा कार्यसूची की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों में सार्थक योगदान किया जा सके।

दिनांक 15–16 जुलाई, 2014 को फोर्टालेजा और ब्रेसिलिया में आयोजित किया गया छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के द्वितीय दौर का अग्रदूत रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों में शंघाई में मुख्यालय स्थापित करने के साथ नए विकास बैंक की स्थापना करने के बारे में करार सम्पन्न करना और इसका प्रथम अध्यक्ष भारत से होना तथा 100 बिलियन अमरीकी डालर की प्रारंभिक राशि से आपात आरक्षित व्यवस्था (सीआरए) करने के लिए संधि सम्पन्न करना शामिल है जो ब्रिक्स देशों के बीच बहु–पक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 15–16 नवम्बर, 2014 को ब्रिस्बेन समूह–20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया जिसमें समूह–20 देशों के साथ भारत की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। ब्रिस्बेन, आस्ट्रेलिया में समूह–20 देशों के 9वें शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों के साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे अवसंरचना निवेश, रोजगार तथा रोजगार अवसर सृजन, कौशल विकास, समूह–20 देशों में पुरूष और महिला के मध्य रोजगार सहभागिता दरों में अंतर को कम करने, भेजने की लागत को कम करने, वहनीय ऊर्जा की सुलभता, ऊर्जा कुशलता, समावेशी विकास, भ्रष्टाचार समाप्त करने, वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में सुधार और बहु–पक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के मामले थे।

हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों के साथ भारत की भागीदारी को हिन्द महासागर रिम संघ (आईओआरए)– एक ऐसा अखिल हिन्द महासागर समूह जो इस हिन्द महासागर क्षेत्र में धीरे–धीरे शीर्ष संगठन के रूप में उभर रहा है, सहित सुदृढ़ करना तथा व्यापक करना जारी रखा गया। भारत ने अक्तूबर, 2014 में पर्थ में आस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित हिन्द महासागर रिम संघ की मंत्री परिषद की 14वीं बैठक में भाग लिया। मारीशस के विश्वविद्यालय में हिन्द महासागर अध्ययन के संबंध में अध्यक्ष की नियुक्ति, एक आईओआर कविता समारोह और महिला अधिकारिता कार्यशाला संबंधी भारत की पहल की व्यापक स्तर पर सराहना की गई।

दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह उल्लेख करके कि भारत की 'पूरब को देखो नीति' को 'पूरब के कार्य' में परिवर्तित कर दिया गया है, आसियान–भारत संबंधों का विशेष आयाम दिया है। दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को नई पई टा, म्यांमार में आयोजित किए गए 12वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और आसियान नेताओं ने भारत–आसियान रणनीतिक भागीदारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आसियान को भारत की पूरब के कार्यनीति का मुख्य बिन्दु बना दिया है और सभी क्षेत्रों में संबंधों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया और आसियान–भारत कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन और परियोजना वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष सुविधा स्थापित करने की घोषणा की। विदेश मंत्रीने दिनांक 09 अगस्त, 2014 को नेई पेई टा में आयोजित की गई 12वीं आसियान–भारत विदेश मंत्री बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को नेई पेई टा में 9वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया और अन्य विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान किया। इससे पहले दिनांक 10 अगस्त, 2014 को नेई पेई टा में चौथी विदेश मंत्री बैठक में विदेश मंत्री ने भाग लिया।

भारत ने आसियान और छह एफटीए भागीदारों अर्थात भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के बारे में सक्रिय रूप से बातचीत की।

नवम्बर 2013 में भारत द्वारा आयोजित 11वीं एशिया–यूरोप विदेश मंत्री बैठक (एएसईएम) के दौरान प्राप्त उलब्धि को आगे बढ़ाते हुए भारत ने एएसईएम का ध्यान 'संवाद' से 'सुपुर्दगी योग्य' पर अंतरित करने के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 2014 को हैदराबाद में हरित निर्माण कांग्रेस 2014 के भाग के रूप में ''हरित निर्माण में ऊर्जा का कुशल उपयोग'' के संबंध में एक एएसईएम गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया।

विकास सहयोग

विकास सहयोग भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण संघटक है। पिछले कुछ वर्षों में विकासशील देशों में भारत के बाह्य विकास सहायता कार्यक्रमों के क्षेत्र तथा कवरेज में पर्याप्त वृद्धि की गई है। इनमें अल्पकालिक नागरिक तथा सैनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित ऋण की सीमाएं, अनुदान सहायता, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय आधार पर सहायता, शैक्षिक छात्रवृतियां और

व्यापक स्तर के क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

अवधारणा, शुरूआत, कार्यान्वयन और चालू करने के विभिन्न स्तरों के माध्यम से भारत की विकास परियोजनाओं के कारगर निष्पादन और निगरानी के लिए विदेश मंत्रालय में जनवरी 2012 में विकास भागीदारी प्रशासन (डीपीए) की व्यवस्था की गई है।

मेजबान सरकारों की प्राथमिकता के अनुसार अवसंरचना, पन–बिजली, विद्युत पारेषण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाएं अफगानिस्तान, बंग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत के पडोसी देशों के साथ सीमा–पार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

निवेश तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन

निवेश तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन (आईटीपी) प्रभाग आर्थिक कुटनीति को बढ़ावा देता है और विदेशी निवेश, व्यापार आवर्धन कार्यकलापों तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन व हस्तांतरण से संबंधित कार्यकलापों का समर्थन करता है। यह संबंधित मंत्रालयों, चैम्बर्स ऑफ कामर्स तथा निर्यात संवर्धन परिषदों से तालमेल करके कार्य करता है और आर्थिक तथा वाणिज्यिक मुद्दों पर कार्य कर रहे मंत्रालयों को नीतिगत सूचना प्रदान करता है।

वर्ष 2014–15 में, इस प्रभाग ने हमारे मिशनों तथा केन्द्रों को निर्यातों तथा निवेशों को बढाने से संबंधित उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए 5 करोड़ रूपए वितरित किए। वर्ष 2014 में, आईटीपी प्रभाग ने मिस्र, सेशेल्स, कोरिया गणराज्य और न्यूजीलैण्ड के साथ हुए द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ताओं में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। आईटीपी प्रभाग ने नवंबर, 2014 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन वार्ता (आईसीएएन) सम्मेलन में भी भाग लिया। आईटीपी प्रभाग ने नई दिल्ली में 26–27 नवंबर, 2014 को चौथे भारत–अरब भागीदारी सम्मेलन का आयोजन करने के लिए फेडेरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) को बजटीय सहायता प्रदान की। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कामर्स ने आईटीपी प्रभाग के सहयोग से 4–5 दिसंबर, 2014 को 'कान्फरेंस ऑन अफ्रीका –ए लैण्ड ऑफ अपरचुनिटीज' की मेजबानी की।

ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग विदेश मंत्रालय में ऊर्जा से संबंधित मामलों में नोडल प्वाइंट/बिन्दु की तरह कार्य करता है। ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने संबंधित समान उद्देश्य वाले मंत्रालयों के साथ अपना निकट बातचीत जारी रखा और ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत में योगदान भी दिया।

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों की विभिन्न बैठकों में भाग लिया। इस प्रभाग ने सियोल में संपन्न क्लीन ऊर्जा पर मंत्रालय स्तरीय बैठक. अबु धाबी में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) परिषद की बैठक, मैक्सिको में ऊर्जा सक्षमता सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (आईपीईईसी) की नीति समिति की बैठक और पेरिस में कार्यकारी समिति की बैठक, आस्ट्रेलिया में जी 20 ऊर्जा सततता कार्यात्मक समूह की बैठक और अस्ताना, कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन की उच्च स्तरीय समूह की ऊर्जा क्लब की बैठक और बैकॉक, थाइलैण्ड में संपन्न एशियाई तथा प्रशान्त ऊर्जा मंच (एपीईएफ) के विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।

इस प्रभाग ने तेल तथा गैस के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए 24–25 अप्रैल, 2014 को अस्ताना, कजाकिस्तान में संपन्न 11वीं भारत–कजाकिस्तान अंतर–सरकारी आयोग (आईजीसी) और रियाद में 28 अक्तूबर, 2014 को संपन्न दूसरे भारत– सउदी ऊर्जा परामर्शों में भाग लिया।

कोंसुली, पासपोर्ट तथा वीज़ा सेवाएं

वर्ष 2014 में पासपोर्ट तथा अन्य संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन पत्रों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई थी और यह विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सर्वाधिक उल्लेखनीय नागरिक सेवा के रूप में उभरा है। मंत्रालय ने देश में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने संबंधी अपनी फ्लैगशिप पहल–पासपोर्ट सेवा परियोजना में कई मात्रात्मक तथा गुणात्मक सुधार किए हैं। नागरिक केंद्रित सेवा प्रदाय के लिए इस परियोजना को ई–गवर्नेंस हेतु वर्ष 2014–15 का राष्ट्रीय पुरस्कार (स्वर्ण) प्राप्त हुआ है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के विस्तार तथा उनकी मात्राा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पासपोर्ट की अधिक मांग संबंधी चुनौतियों का सामना करने और पासपोर्ट निर्गम प्रणाली में व्यापक सुधार परिवर्तन करने के लिए नागरिक केंद्रित आईटी समर्थित पासपोर्ट सेवा परियोजना 2012 में शुरु की गई है और देश भर में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थापना करके तथा कार्यरत बनाकर इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस परियोजना के सफल प्रचालन के ढाई वर्ष पूरे हो गए हैं। 31 दिसंबर, 2014 तक पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित 2.24 करोड़ आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की गई है और नई प्रणाली के माध्यम से 2.09 करोड़ आवेदनों के संबंध में सेवाएं प्रदान की गई हैं।

पासपोर्ट निर्गम प्रणाली को आसान, तेज तथा सुरक्षित बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं –जनता की शिकायतें की निपटान प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, 17 भाषाओं में कार्यरत राष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना करना, नियमित आधार पर पासपोर्ट पोर्टल को अद्यतन बनाना, पासपोर्ट से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए एमपासपोर्ट सेवा मोबाईल ऐप., प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय

(एमओआईए) के ईमाइग्रेट प्रणाली का पीएसपी प्रणाली के साथ एकीकरण, पासपोर्ट मेला, अदालत , एक लाख आम सेवा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन पासपोर्ट भरने संबंधी सेवा एप्लिकेशनप्लिकेशन, शिकायतों का समाधान करने के लिए, हज आवेदनों को उच्च प्राथमिकता, अपील तथा आरटीआई के मामलों का समय से निपटान करना, पासपोर्ट कार्यालयों में भौतिक अवसंरचना में सुधार करना और पासपोर्ट बुकलेटों में नई सुरक्षा विशेषताओं को प्रारंभ करना एवं ई–पासपोर्ट परियोजना में तेजी लाने के लिए एक कार्यबल/टास्कफोर्स की स्थापना करना। 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, पासपोर्ट सेवा से संबंधित 2. 24 करोड़ से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की गई है और 2.09 करोड़ से अधिक सेवाएं नई प्रणाली के जरिए प्रदान की गई हैं।

पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन के कारण, देश में पासपोर्ट सेवा प्रदानगी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देशभर में, 21 प्रतिशत पासपोर्ट 3 दिनों के अंतर जारी कर दिए जाते हैं; 47 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट 7 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाते हैं और 64 प्रतिशत 14 दिनों (पुलिस सत्यापन में लगने वाले समय को छोड़कर) के भीतर जारी कर दिए जाते हैं। तत्काल पासपोर्टों के मामले में, 28 प्रतिशत उसी दिन जारी कर दिए जाते हैं, 60 प्रतिशत एक दिन के भीतर और 84 प्रतिशत तीन दिनों के भीतर जारी कर दिए जाते हैं। यदि प्रारंभ से अंत तक की प्रदानगी प्रणाली में पुलिस सत्यापन के समय को शामिल किया जाए तो, 49 प्रतिशत पासपोर्ट एक महीने के भीतर जारी किए गए, पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के मामले में प्रथम 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश और उत्तर प्रदेश थे, जहां कुल मिलाकर आवेदनों की संख्या 51 प्रतिशत से अधिक थी।

जनवरी–दिसंबर 2014 के दौरान, भारत, मुख्यालयों और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन में 37 पासपोर्ट कार्यालयों ने 85. 07 लाख पासपोर्ट जारी किए (जिसमें 2648 राजनयिक पासपोर्ट, 17560 सरकारी पासपोर्ट, एलओसी, आईसी और वापास दिए गए प्रमाणपत्र शामिल थे) और पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाएं प्रदान की जिसमें पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र, शामिल थे, जो वर्ष 2013 में 71.33 लाख की तुलना में दृ 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी थी। इसके अलावा, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा लगभग 13.83 लाख पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। इस प्रकार, भारत सरकार ने, कुल मिलाकर, एक वर्ष में लगभग 1.01 करोड़ पासपोर्ट सेवाएं प्रदान की। यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है और यह वर्ष 2000 की तुलना में तीन गुनी है। 31 दिसंबर 2014 तक, 5,19,29,139 नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट हैं। वर्ष 2014–15 में सभी पासपोर्ट सेवाओं से अर्जित की गई कुल राजस्व 1600 करोड रूपए है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 516.82 करोड़ रूपए की धनराशि केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन को आबंटित की गई थी।

विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में तीन दिवसीय पासपोर्ट अधिकारियों का सम्मेलन (23–25 जून, 2014) का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री ने पासपोर्ट अधिकारियों से इस नागरिक–केन्द्रित भूमिका को सेवा (सेवा) के भाव से करने का आग्रह किया न कि केवल एक काम के रूप में। नागरिकों को दी गई उल्लेखनीय सेवाओं का संज्ञान लेते हुए, मंत्री ने चयनित कर्मचारियों तथा पासपोर्ट अधिकारियों को पासपोर्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए।

भारतीय मिशनों/केन्द्रों में पासर्पोट, वीज़ा, ओसीआई और पीआईओ आवेदनों के डिजिटाइजेशन के माध्यम से ''इमेज रिट्रिवल डाटाबेस का सृजन'' परियोजना चयनित मिशनों/केन्द्रों में चलाई गई। 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, लगभग 15 करोड़ पृष्ठों का डिजिटिलीकरण किया जा चुका है।

पासपोर्ट सेवाओं में संसद की गहरी रूचि की पुष्टि बड़ी संख्या में संसदीय प्रश्नों, संसदीय समितियों द्वारा जांच तथा निरीक्षण/अध्ययन दौरों द्वारा की गई। इसमें विदेश मंत्रालय और इसके कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 16 जनवरी, 2014 को पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर का राजभाषा संसदीय समिति की प्रथम उपसमिति द्वारा दौरा और गोवा, रायपुर और देहरादून के पासपोर्ट कार्यालयों के जनवरी– फरवरी, 2015 में तय दौरे शामिल हैं। 5 दिसंबर, 2014 को संपन्न विदेश मंत्रालय की परामर्शदाता समिति की वर्ष 2014 की पहली बैठक के लिए, इस बैठक का चुना गया एजेंडा ''पासपोर्ट सेवाएं'' था। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री द्वारा की गई।

विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र प्रत्येक वर्ष लगभग 4 मिलियन वीज़ा जारी करते हैं। मिशनों/केन्द्रों द्वारा वीज़ा प्रदायगी की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, जिसमें निगर्म प्रणाली का कंप्यूटरीकरण और वीज़ा सेवाओं की आउटसोर्सिंग शामिल है जिसकी शुरूआत 2006 में की गई थी। वर्तमान में 64 मिशनों/केन्द्रों में वीजा कार्यों की आउटसोर्सिंग की गई है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्दों में आईवीएफआरटी (प्रव्रजन, वीज़ा तथा विदेशी पंजीकरण एवं नज़र रखना) परियोजना वर्ष 2015 तक पूरी कर लिए जाने की आशा है। इस समय (31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार), आईवीएफआरटी योजना (बायोमैट्रिक्स के बिना) विदेश स्थित 155 भारतीय मिशनों/केन्द्रों में प्रारंभ कर दी गई है।

जनवरी से दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान, सीपीवी प्रभाग के पंजीकरण प्रकोष्ठ ने 3,83,651 व्यक्तिगत और 1,69,534 वाणिज्यिक दस्तावेज तथा 3,57,864 एजेस्टाइल्ड दस्तावेजों को एपोस्टील के सदस्य देशों में उपयोग के लिए सत्यापित किए। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में विदेश मंत्रालय की शाखा सचिवालयों के लिए 34,305 दस्तावेज सत्यापित/एपोस्ट किए गए। कोंसुली दस्तावेजों का सत्यापन भी विदशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा किया गया है।

जनवरी से दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान, भारत ने बांग्लादेश, अजरबैजान और थाइलैण्ड के साथ प्रत्यावर्तन संधि पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम तथा बांग्लादेश के साथ प्रत्यावर्तन संधि के अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान–प्रदान किए गए। इस अवधि के दौरान, भारत ने विभिन्न देशों से छह प्रत्यावर्तन अनुरोध प्राप्त किए। इसके अलावा, भारत ने स्थानीय कानूनी कार्रवाई के लिए 32 अनुरोध प्राप्त किए। साथ ही, भारत ने एक व्यक्ति का विदेश को प्रत्यावर्तन किया जबकि एक व्यक्ति को भारत प्रत्यावर्तित किया गया।

समन्वय

इस मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों और निजी संस्थाओं के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों के बीच बातचीत का समन्वयन समन्वय प्रभाग द्वारा किया गया। इस प्रभाग ने मंत्रियों, चयनीय प्रतिनिधियों और सरकारी पदाधिकारियों के सरकारी/निजी दौरों के लिए राजनयिक अनापत्ति पर कार्रवाई की। इसने विदेशी भागीदारी से भारत में सम्मेलन/ सेमिनार/ कार्यशालाओं के आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं और भारतीय भागीदारी वाली विदेशों में खेलकूद प्रतियोगिताएं, विदेशी सैन्य उड़ानों के लिए लैण्डिंग/ओवरफ्लाइंग अनापत्ति, विदेशी नैसेना के जहाजों के दौर आदि के लिए अनापत्ति की प्रक्रिया पर कार्रवाई की। इस प्रभाग ने छात्र वीज़ा को अनुसंधान वीजा में परिवर्तित करने के संबंध में गृह मंत्रालय से प्राप्त बड़ी संख्या में संदर्भों और आयकर, 1961 की यू/एस 11(i) (सी) से छूट प्राप्त करने के लिए विभिन्न न्यासों/गैर सरकारी संगठनों तथा भारत में विदेशियों द्वारा अचल संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में वित्त मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों पर भी कार्रवाई की। कुल मिलाकर, अप्रैल, 2014 से नवंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान लगभग 4316 अनापत्ति जारी किए गए।

समन्वय विभाग ने अन्य मंत्रालयों से प्राप्त प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर भी कार्रवाई की और मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से सूचना एकत्र करने के बाद इस मंत्रालय की टिप्पणी/विचार से अवगत कराया। यह प्रभाग मंत्रिमंडल सचिवालय की ई–समीक्षा वेबसाइट के अनुवीक्षण तथा अद्यतन संबंधी कार्य भी किए।

प्रशासन तथा परियोजनाएं

प्रशासनः वर्ष 2014–15 के दौरान, इस मंत्रालय ने प्रशासनिक तंत्रों को सुचारू करने के लिए निर्णय लेने का विकेन्द्रीकरण करने तथा नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं को आसान बनाने तथा उनमें सुधार करने के भी प्रयास किए। विदेश मंत्रालय की विस्तार योजना के कार्यान्वयन में प्रगति हुई है, जिसकी शुरूआत वर्ष 2008 में हुई थी और वर्ष 2011 के अंत में भारतीय विदेश सेवा 'ख' शाखा की संवर्ग समीक्षा अनुमोदित की गई। इन पहलों से इस मंत्रालय में बढ़ती कार्मिक शक्ति की आवश्यकता को बहुत हद तक पूरा करने में सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के भर्ती नियमों की समीक्षा के लिए व्यापक कार्य इस वर्ष के दौरान डीओपीटी तथा यूपीएससी से परामर्श करके प्रारंभ किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष में भारत सरकार द्वारा जकार्ता में आसियान के लिए नए मिशन खोले जाने के साथ ही भारत की वैश्विक राजनयिक उपस्थिति में और विस्तार देखने को मिली। भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन पर इस मंत्रालय द्वारा उच्च प्राथमिकता दिया जाना जारी है।

परियोजनाएंः रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, इस प्रभाग ने चांसरी/आवासों के उपयोग के लिए विदेशों में संपत्तियों के निर्माण तथा अधिग्रहण का कार्य जारी रखा। हेलसिंकी, काबुल और जगरेब में निर्मित संपत्तियों के बिक्री/खरीद करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, एक भूखण्ड बैंकॉक में अधिग्रहित की गई और एक बड़ा भूखण्ड माले में अधिग्रहित किया गया।

विदेशों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और हिन्दी का प्रचार

विदेश मंत्रालय विदेशों में हिन्दी का प्रचार प्रसार करने और मुख्यालय, विदेश स्थित मिशन/केन्द्रों और पासपोर्ट कार्यालयों में दैनिक कामकाज में इसे कार्यान्वित करने के दोहरे उद्देश्य से कार्य करता है।

विदेश मंत्रालय में अपने मिशनों और केन्द्रों की भागीदारी से विदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम है। भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन को विदेश मंत्रालय द्वारा अत्यंत उच्च प्राथमिकता दिया जाना जारी है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीसआर)

अप्रैल– नवंबर, 2014 की अवधि के दौरान, आईसीसीआर विदेशों में भारत की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यकलापों में संलग्न रहा। अपने बौद्धिक तथा शैक्षिक कार्यकलापों के भाग के रूप में, आईसीसीआर के पास भारत में इसकी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 6200 से अधिक विदेशी विद्वान भारत में 20 से अधिक राज्यों और 120 से अधिक संस्थाओं में विभिन्न विषयों में स्कूल–पश्चात की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विदेशी विद्वानों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यकलापों के अलावा, आईसीसीआर मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन की पुर्वसंध्या पर विदेश मंत्री द्वारा उन्हें कॉल करने संबंधी कार्यक्रम का आयोजन भी करता है। अनेक राज्यों में राज्यपालों/मुख्यमंत्रियों ने आईसीसीआर अध्येतावृत्ति प्राप्त की। आईसीसीआर के पास 77 पीठ है जिसमें विदेशों में विश्वविद्यालयों की भाषाओं तथा अन्य पहलुओं को शामिल किया जाता है।

आईसीसीआर ने 31 अक्तूबर से 9 नवंबर, 2014 तक मारिशस में ''भारत के अनुबंधित श्रमिकों के अगमन की 180वीं वर्षगांठ का समारोह'' और 20–27 नवंबर, 2014 तक अलजीरिया में ''दूसरा भारत–अरब सांस्कृतिक उत्सव'' का आयोजन किया।

विदेशों में आईसीसीआर के 34 पूर्णकालिक सांस्कृतिक केन्द्र और एक उपकेन्द्र ने नृत्य, संगीत, योग, हिन्दी, वार्ता और प्रदर्शनियों के माध्यम से विदेशों में भारत की उदार शक्ति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। आईसीसीआर ने विदेशों में 55 भारतीय सांस्कृतिक समूहों/कलाकारों को प्रायोजित किया जिन्होंने लगभग 80 देशों में कार्यक्रम पेश किए। इसने विभिन्न देशों में प्रदर्शनी के लिए स्वयं के संग्रह में से 24 प्रदर्शनियों को भेजा और जयपुर में 'मैत्री' नामक पहला भारत–चीन महिला कलाकारों की रेसिडेंसी का आयोजन किया। इसने आईसीसीआर के विभिन्न प्रतिष्ठित महोत्सवों सहित भारत में 47 विदेशी समूहों द्वारा मंचन का आयोजन भी किया।

आईसीसीआर ने विचारों के आदान–प्रदान के लिए विभिन्न देशों से प्रतिष्ठित महानुभावों तथा शिक्षाविदों को आमंत्रित किया। इसने कुछ विदेशी विशेषज्ञों द्वारा भारत की खोज को भी समर्थन दिया।

आईसीसीआर ने विभिन्न देशों में वितरण के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, अरबी फ्रांसीसी और स्पेनिश भाषाओं में पत्र–पत्रिकाएं भी निकाले।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए)

2014–15 के दौरान, आईसीडब्ल्यूए ने अपने सहमति के कार्यकलापों को जारी रखा और एशिया, ईयू, अफ्रीका, अमरीका और लातिन अमरीका में राजनीतिक, सुरक्षा तथा आर्थिक विकास पर अनुसंधान तथा अध्ययन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की। वैश्विक भू–रणनीतिक और भू–राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण किया गया। इनके निष्कर्षों को 6 सप्रु हाउस दस्तावेजों, 19 मुद्दा सार, और 46 दृष्टिकोणों के रूप में प्रचारित किया गया, जिन्हें आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर डाला गया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 31 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, 85 सम्मेलन/व्याख्यान/सेमिनारों का आयोजन किया गया/भारत तथा विदेशों में इस अवधि के दौरान आईसीडब्ल्यूए के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। सप्रु हाउस लेक्चर के लगातार सीरिजों में प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों जैसे चीनी प्रधान मंत्री श्री ली काकियांग, हंगरी के प्रधानमंत्री डॉ. विक्टर ओरबान, पूर्व नेपाली प्रधान मंत्री श्री पुष्प कमल दहाल ''प्रचंड'' और श्री माधव कुमार नेपाल, 68वें यूएनजीए अध्यक्ष राजदूत श्री जॉन डब्ल्यू. आशे, सेशेल्स के वित्त मंत्री और अनेक विदेशी मंत्री, स्पीकर आदि शामिल हुए। आयोजित किए गए महत्वपूर्ण सेमिनारों में शामिल हैं –दिल्ली वार्ता VI, दिल्ली में हिन्द महासागर (टीडीआईओ) पर भारत–आस्ट्रेलिया–इंडोनेशियाई त्रिपक्षीय वार्ता, आईसीडब्ल्यूए –एमजीआईएमओ (मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स) सेंट पीटरबर्ग में आरआईएसी से वार्ता और बातचीत आदि, अलमाटी में दूसरा भारत दृ मध्य एशिया वार्ता, आस्ट्रेलिया में एआईआईए–आईसीडब्ल्यूए वार्ता (कैनबरा, मेलबॉर्न और सिडनी), पांचवां भारत मंच, अकरा, डाकर, मनीपाल, कोलकाता और चंडीगढ़ में आईएएफएस–II आईसीडब्ल्यूए–अफ्रीका शैक्षिक सम्मेलन, पांचवां वार्षिक एशियाई संबंध सम्मेलन (एआरसी–वी) और जकार्ता में भारत–इंडोनेशिया वार्ता।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली (आरआईएस)

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली (आरआईएस) नई दिल्ली में अवस्थित स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस संस्थान ने इस अवधि के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें अन्य के साथ–साथ शामिल हैंः सातवां दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन, ब्रिसबेन जी 20 शिखर सम्मेलन के समक्ष मुद्दों पर सेमिनार, थिंक टैंक के आसियान–भारत नेटवर्क पर तीसरा गोलमेज (सम्मेलन) (एआईएनटीटी), आसियान–भारत प्रख्यात व्यक्तियों के व्याख्यान, 'भारत और म्यांमार के बीच संपर्क कॉरिडोर को विकास कॉरिडोर में बदलना' रिपोर्ट का लॉच, क्रॉस–बार्डर संपर्क पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आसियान–भारत पारगमन यातायात करार पर गोलमेज (सम्मेलन), भारत में रिजनरेटिव दवाएं तथा पेटेन्ट की आवश्यकता के शासन पर गोलमेज (सम्मेलन), भारत–आर्थिक संपर्क पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र, एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश तथा तौर–तरीके विकसित करने हेतु परामर्शदात्री बैठक, जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार तथा एक नए समाज के लिए परिसर, जी. पार्थसारथी और आरआईएस पर विशेष व्याख्यान, भारत संपर्क पर गोलमेज (सम्मेलन), और आसियान एकीकरण प्रक्रिया, आरसीईपी, टीपीपी और एफटीएएपी की संभावना पर पैनल चर्चा। एफआईडीसी सेमिनार सीरिज के अलावा, आरआईएस ने एक ब्रेकफास्ट सेमिनार सीरिज प्रारंभ की है। आरआईएस ने व्यापार नीति और विश्लेषण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा, विदेश मंत्रालय के आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत एक नया क्षमता निर्माण कार्यक्रम ''दक्षिण–दक्षिण सहयोग शिक्षण'' प्रारंभ किया है।

विदेश प्रचार और लोक राजनय

21 वीं शताब्दी में प्रभावशाली आउटरीच की चुनौतियों का सामना करने के लिए, जनवरी, 2014 में मंत्रालय ने एक्सपी और पीडी प्रभागों को आपस में मिलाकर एक नया प्रभाग (एक्सपीडी) बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2014 में, विदेश मंत्रालय के वाह्य प्रचार और लोक राजनय प्रभाग (एक्सपीडी) ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विभिन्न विदेश नीति संबंधी मुद्दों पर भारत सरकार की स्थिति/रूख का प्रभावशाली तरीके से बखान करना जारी रखने

के साथ–साथ यह भारत, इसकी विदेश नीति, और विश्व के साथ भारत के संपर्क के विभिन्न पहलुओं पर स्थिति बताने के लिए घरेलू तथा विदेशी श्रोताओं/दर्शकों के साथ संपर्क जारी रखा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के साथ सक्रिय संपर्क के अलावा, इस मंत्रालय ने विशेषकर डिजिटल विभिन्नताओं से अपने लोक राजनय पहल को साथ ही साथ बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों की राय को रूप देने में और ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंच बनाने में बेहतरीन प्रभाव डालने में सफल रहा है।

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई)

रिपोर्ट की गई अवधि में विदेश मंत्रालय के नए प्रशिक्षण ढ़ांचे के कार्यान्वयन की शुरूआत हुई जिसे जुलाई, 2013 में अंगीकार किया गया था। 2012 की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की संस्तुतियों से निकलकर, इस प्रशिक्षण ढ़ांचे का उद्देश्य सेवा प्रदायगी में सुधार करने के अंतिम उद्देश्य के साथ कर्तव्यों तथा कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता तथा कौशल विकसित करके कार्यात्मक अपेक्षाओं से सीधे तौर पर संगत प्रशिक्षण देना है। कैरियर के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिए जाने को अनिवार्य बनाया जाना है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के साथ, विदेश सेवा संस्थान ने भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय सामग्री तथा तरीके दोनों की समीक्षा की तथा उन्हें संशोधित किया और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए कैरियर के दौरान प्रशिक्षण के नए स्तरों को प्रारंभ किया। आईएफएस के बैच बी के लिए प्रशिक्षण को भी प्रशिक्षण में नए तत्वों को शामिल करके और अब तक शामिल नहीं की गई श्रेणियों जैसे निजी सचिव/पीपीएस/ एसपीपीएस, एमटीएस/शौफर, विदेश स्थित मिशनों में स्थानीय भर्ती स्टॉफ को शामिल करके नवीकृत किया गया और गहन बनाया गया। मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति वाले लोगों के लिए भी अभिविन्यास प्रशिक्षण पहली बार दिए गए।

प्रशिक्षण विषयों में हाल में ही सरकार के दिशानिर्देश शामिल किए गए जिनमें राज्य विशिष्टता, मेक इन इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रपत्रों तथा आवेदनों को सरल बनाने आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण सामग्री को ऑनलाइन वेबनियर मंच के माध्यम से विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में तैनात अधिकारियों/पदाधिकारियों की पहुंच तक लाया गया जिसमें दूर बैठे प्रतियोगी न केवल कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण को देख और सुन सकते हैं बल्कि अपने माइक्रोफोन के माध्यम से बोलकर और कंप्यूटर पर अपने प्रस्तुतिकरण दिखलाकर चर्चा में भाग भी ले सकते हैं। प्रशिक्षण के तरीके में एक और नया कार्य अधिकारियों के दैनिक कर्तव्यों में कम से कम बाधा सुनिश्चित करके प्रति सप्ताह अत्यंत लचीले दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षुओं द्वारा सत्र समन्वय प्रारंभ करके जिसमें किसी विशेष सत्र के लिए कोई अधिकारी अथवा अधिकारियों का समूह विस्तृत दस्तावेज तैयार करते हैं, प्रशिक्षुओं की अधिकतम भागीदारी तथा संलग्नता को सुनिश्चित किया गया। कुल मिलाकर एफएसआई ने प्रशिक्षुओं के लक्ष्य समूह से परामर्श करके और उनकी प्रतिक्रिया/जानकारी लेकर प्रशिक्षण को उनके कार्यात्मक अपेक्षाओं से संगत बनाते हुए भागीदार–केन्द्रित एप्रोच/तरीका अपनाया।

विधि एवं संधि

विधि एवं संधि प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (छठी समिति) और इसकी विभिन्न उपसमितियों में वर्तमान वर्ष की चर्चाओं में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की कानूनी सलाहकारों की 25वीं बैठक, कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (यूएनआईडीआरओआईटी), निजी अंतर्राष्ट्रीय हेग सम्मेलन (एचसीसीएच), भारत ईएफटीए व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी करार (पाठ) की दूसरी कानूनी समीक्षा/जांच; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र (यूएनसीआईटीआरएएल); समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर एईएएन क्षेत्रीय मंच का दूसरा सेमिनार (यूएनसीएलओएस), राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार न्यूयार्क के इतर समुद्री जैव विविधता के परंपरागत तथा सतत उपयोग से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए एक तदर्थ ओपन–एन्डेड अनौपचारिक कार्यात्मक समूह, XXXVII–सीईपी ऐंटार्कटिक परामर्शदात्री समिति की ग्टप्प बैठक (एटीसीएम), यूरोप मुक्त व्यापार संगठन और कनाडा के साथ बातचीत, जलदस्युता, निःशस्त्रीकरण, जल संसाधन, मानवीय कानून और मानवाधिकार के मुद्दों पर संपर्क समूह की बैठकों में सक्रियता से भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के मुख्य भाग के दौरान, एल एण्ड टी प्रभाग ने छठी समिति की चर्चाओं में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विशेष समिति के विचारार्थ मुद्दों पर ब्रीफ तैयार किए।

इस प्रभाग ने एशियाई–अफ्रीकी कानूनी परामर्शदात्री संगठन (एएएलसीओ) के वार्षिक सत्र में और मुक्त व्यापार, निवेश सुरक्षा, असैनिक परमाणु सहयोग, सामाजिक सुरक्षा और प्रत्यर्पण, परस्पर कानूनी सहायता और श्रव्य–दृश्य सह–उत्पादन से संबंधित करारों पर विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में भी भाग लिया। इसके अलावा, इस प्रभाग ने स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की वार्षिक बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेकर सिंधु जल संधि, 1960 से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए।

इस प्रभाग ने लिंक इंडियन ट्रिटिज डाटाबेस के तहत विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर समर्पित और विदेशों के साथ भारत गणराज्य की सरकार द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई संधियों/करारों/समझौता ज्ञापनों तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों वेब माड्यूल का प्रारंभ किया है और अब वे सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

इस प्रभाग ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुबंध VII के अनुच्छेद 287 और अनुच्छेद 1 के तहत बंगाल की खाड़ी में

भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा के सीमांकन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। मध्यस्थ ट्रायब्यूनल ने हेग में 7 जुलाई, 2014 को अपने पंचनिर्णय प्रदान किए। इस निर्णय के तहत, क्षेत्रीय समुद्र में भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ और 200 ना.मि. से परे महाद्वीपीय शेल्फ को अंतिम रूप दिया गया। मध्यस्थ पंचनिर्णय दोनों पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यता और अंतिम है।

इलेक्ट्रॉनिक शासन और अनौपचारिक प्रौद्योगिकी

3 जुलाई, 2014 को मंत्रालय में ई–कार्यालय का प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य कम कागज और अधिक प्रभावी कार्यालय की ओर आगे बढ़ना है। यह मंत्रालय समेकित मिशन एकाउन्टिंग साफ्टवेयर (आईएमएएस) के वेब–आधारित संस्करण विकसित करने की प्रक्रिया में है जो बेहतर वित्तीय आयोजना और व्यय प्रबंधन की ओर अग्रसर करेगा। बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों को देखते हुए, मंत्रालय ने मुख्यालय में अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों और विदेश तैनाती के लिए जा रहे अधिकारियों को साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर देना जारी रखा।

राज्य

निर्यातों तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों के साथ समन्वय पर प्रधान मंत्री के निर्देशों तथा जोर और ज्यादा विदेशी निवेश तथा विशेषज्ञता आकर्षित करने के अनुरूप, एक अलग प्रभाग दृ राज्य प्रभाग, संयुक्त सचिव की अगुवाई में दृ इस मंत्रालय में स्थापित किया गया है। यह विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के साथ–साथ भारत में विदेशी राजनयिक और व्यापार आयोगों के बीच उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रयासों को सुविधाजनक बनाना जारी रखेगा।

राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को उपर्युक्त क्षेत्रों में बाह्य संपर्कों के निर्माण तथा पोषण में जहां अपेक्षित हो, विशेषज्ञों तथा अनुभव को उनके साथ साझा करके भी उनकी सहायता की जाएगी।

राज्यों के प्रभाग के साथ प्रारंभिक बातचीत ने ऐसे सहयोग को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों से भी उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त की है। प्राप्त महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रोंः वाणिज्य, संस्कृति, संपर्क, संचार और क्षमता निर्माण में कार्य बिन्दुओं के रूप में विकसित किए जा रहे हैं।

नालंदा

इस वर्ष के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा उत्कृष्टता संस्था के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की गई। ऐतिहासिक अध्ययन के स्कूल में और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण अध्ययन स्कूल में शिक्षण कार्य 1 सितंबर, 2014 को राजगीर में पट्टे पर ली गई परिसर में 14 छात्रों और 8 संकाय सदस्यों के साथ प्रारंभ हो गया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राजगीर में एक समारोह में 19 सितंबर, 2014 को विश्वविद्यालय की कक्षा की शुरूआत का उद्घाटन किया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री, राजनीतिक नेतागण, शिक्षाविद्, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के देशों के राजनय और अन्य उपस्थित थे।

यह विश्वविद्यालय भाषा तथा साहित्य के पांच अन्य स्कूल; बौध अध्ययन, दर्शनशास्त्र और तुलनात्मक धर्म; अर्थशास्त्र और प्रबंधन; अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शांति अध्ययन; और सूचना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी खोलने की योजना बना रहा है। शैक्षिक वर्ष 2017–18 तक सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने की योजना है। यह विश्वविद्यालय लगभग 500 संकाय सदस्य/स्टॉफ रखने और लगभग 2450 छात्रों को स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान डिग्रियां प्रदान करने की योजना बना रहा है। सरकार ने वर्ष 2021–22 तक इसकी पूंजीगत तथा आवर्ती खर्चे के लिए 2727 करोड़ रूपए का आबंटन किया।

मंत्रालय इस विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर/प्रकृति मजबूत करने के लिए ईएएस तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता रहा है। कंबोडिया, लाओस, म्यामार और वियतनाम के छात्रों को छह छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सरकार के प्रस्ताव को अगस्त, 2014 में नाय पेई ताव, म्यामार में संपन्न ईएएस मंत्रीस्तरीय बैठक में मान्यता दी गई थी। अक्तूबर 2014 में, वियतनाम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां ईएएस देश बन गया। दो गैर भागीदार देश बांग्लादेश और भूटान क्रमशः सितंबर और नवंबर, 2014 में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता देश बन गए।

आस्ट्रेलिया ने पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन स्कूल में एक पीठ स्थापित करने के लिए 1 मिलियन आस्ट्रेलियन डॉलर का अनुदान दिया। जापान ने विश्वविद्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क में सुधार करने के लिए ओडीए ऋण का वायदा किया। सिंगापुर ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की स्थापना का वायदा किया। इससे पहले, चीन, थाइलैण्ड और लाओस ने विश्वविद्यालय में अंशदान दिए। जापान, चीन और कोरिया गणराज्य ने भी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षिक सहयोग का प्रस्ताव दिया।

मेसर्स विसु शिल्पा परामर्शदाता को मई 2014 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के समीप ही अवस्थित विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के निर्माण के प्रथम चरण के लिए वास्तुकार नियुक्त किया गया था। इस स्थल पर प्रारंभिक कार्य वर्ष 2014–15 के अंतिम तिमाही में प्रारंभ होने की आशा है। अनेक नए कानून अधिसूचित किए गए।

नए सरकार की पहलें

स्वच्छ भारत अभियान

मंत्रालय के साथ–साथ विदेश स्थित हमारे मिशनों तथा केन्द्रों में 'स्वच्छ भारत अभियान' के अनुपालन में अनेक कार्यकलाप चलाए गए जिनका उद्देश्य अधिकारियों के लिए स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ–साथ उन्हें वातावरण को स्वच्छ रखने में व्यक्तिगत तौर पर सक्रिय करना था। इसमें बेकार फाइलों/कागजों/फर्नीचरों आदि की छंटाई शामिल था और कार्यालय में कार्यस्थल और ट्वायलेट को स्वच्छ, दुरूस्त तथा साफ रखना था। 02 अक्तूबर, 2014 को मंत्रालय के अधिकारियों को 'स्वच्छ भारत' शपथ दिलाई गई। इसके बाद श्रमदान किया गया। 6 दिसंबर, 2014 को मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा एक बार फिर से श्रमदान किया गया। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने भी इसी प्रकार के उपाय किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके परिसर काफी स्वच्छ रहें जो विदेश स्थित हमारे मिशनों के प्रतिनिधिक स्वरूप के अनुरूप हों।

69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस को स्वीकार करना

संयुक्त राष्ट्र का 69वें सत्र ने 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त रूप से प्रायोजित करते हुए 177 देशों के रिकार्ड संख्या के साथ एजेंडा मद 124: वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति के तहत भारत द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संकल्प ए/69/एल.17 अंगीकार कर लिया।इस संकल्प से प्रत्येक वर्ष 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में उच्च स्तरीय खंड के दौरान अपने एकमात्र भाषण में सबसे पहले इसका प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने के 75 दिनों के भीतर, भारत इस संकल्प को पारित करवाने में समर्थ हो गया। यह पहली बार है कि ऐसी किसी पहल का प्रस्ताव इतने कम समय में किसी राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया गया हो और कार्यान्वित किया गया हो।

■■

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उप राष्ट्रपति, श्री हामिद अंसारी, प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्य अतिथि अमरीकी राष्ट्रपति, श्री बराक ओबामा 26 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में 66वें गणतंत्र दिवस, 2015 का अवलोकन करते हुए।

प्रधान मंत्री 12 नवंबर, 2014 को नाय पेई ताउ, म्यांमार में 12वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान नेताओं के साथ।

राष्ट्रपति 07 नवंबर, 2014 को थिम्पू, भूटान के ताशीछोडगांग में भूटान की शाही सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के दौरान।

दुशान्बे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2014

विदेश राज्य मंत्री ने किंगस्टन में जमैका के विदेश मंत्री अर्नाल्ड जे॰ निकोलसन से मुलाकात की। जमैका के भारत के उच्चायुक्त, श्री प्रताप सिंह भी 19 फरवरी, 2015 की फोटो में दिखाई दे रहे हैं।

16 फरवरी, 2015 को विदेश राज्य मंत्री, डोमीनिकन गणराज्य के विदेश मंत्री आंद्रस नवारो गारसिया, सांटो डोमिनिगो, डोमीनिकन गणराज्य में।

भारत के पड़ोसी देश

1

अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान के बीच गहन राजनीतिक भागीदारी है, जिसे अक्तूबर, 2011 में रणनीतिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर करके कार्यरूप दिया गया तथा इसके तहत राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास और शिक्षा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध सहित कई व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। यह हमारे ऐतिहासिक तथा सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है और अफगानिस्तान के पुनःनिर्माण में भारत की भूमिका द्वारा इसे सुदृढ़ किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में स्थिरता तथा आर्थिक विकास लाने के साधन के रूप में उसके पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता की है।

अफगानिस्तान के लिए भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का वायदा शामिल है। भारत का सहायता कार्यक्रम अफगानिस्तान भर में फैला है और यह आर्थिक तथा सामाजिक विकास कार्यकलापों के सम्पूर्ण क्षेत्र में फैला है। संभार तंत्रीय और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित दो प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाएं पूरी की गई हैं –निमरोज प्रांत में जरांज से देलाराम तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण और चीमताला में एक सब–स्टेशन के साथ पुल–ए–खुमरी से काबुल तक 220 किलोवाट पारेषण लाईन का निर्माण। काबुल में अफगानिस्तान के नए संसद भवन, जो बहुलता तथा लोकतंत्र में दोनों देशों की समान वचनबद्धता का प्रतीक है, का निर्माण तथा हेरात प्रांत में सलमा बांध का निर्माण सुचारू रूप से चल रहा है और इसके जल्दी ही पूरे को जाने की संभावना है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच इस अवधि के दौरान प्रमुख उच्च स्तरीय आदान–प्रदान/वार्ताएं निम्नानुसार थीं:

- राष्ट्रपति श्री हामिद करजई ने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथ–ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 26 मई, 2014 को भारत की यात्रा की।
- विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 30–31 मई, 2014 को हेरात और काबुल का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने अफगान उप विदेश मंत्री श्री इरशाद अहमदी के साथ चर्चा की और राष्ट्रपति श्री हामिद करजई, हेरात प्रांत के गवर्नर और अफगान एनएसए से मुलाकात की।
- विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 10 सितंबर, 2014 को काबुल का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने, काबुल में भारतीय दूतावास के नए चांसरी भवन का उद्घाटन करने के अलावा, अफगान राष्ट्रपति श्री हामिद करजई से मुलाकात की और अफगान विदेश मंत्री श्री ज़रार अहमद ओस्मानी से भेंट की।
- उप राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी ने नए अफगान राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद अशरफ गनी के शपथ–ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 29 सितंबर, 2014 को काबुल जानेवाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) श्री अजीत डोवल ने प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में 22 अक्तूबर, 2014 को काबुल का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान, अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री हनीफ अत्मार के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करने के अलावा उन्होंने अफगान राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद अशरफ गनी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह से मुलाकात की ।
- प्रधान मंत्री ने 26 नवंबर, 2014 को काठमांडू में सार्क सम्मेलन के अतिरिक्त समय में अफगानी राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद अशरफ गनी से मुलाकात की।
- विदेश राज्यमंत्री एमओएस (वीकेएस) जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त), ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया जो 3–4 दिसंबर, 2014 को लंदन में संपन्न हुआ था।

भारत अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशिया–इस्तांबुल प्रक्रिया के केंद्र में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। विदेश राज्यमंत्री (वी.के.एस.) ने 30–31 अक्टूबर, 2014 को बीजिंग में हार्ट आफ एशिया प्रोसेस के चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रक्रिया के तहत भारत व्यापार, वाणिज्य और निवेश अवसरों के लिए विश्वासोत्पादक उपाय की अगुवाई कर रहा है।

इस अवधि के दौरान प्रमुख व्यापार संवर्धन कार्यकलाप निम्नलिखित थेः

- फेडरेशन आफ इंडियन चेंबर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) ने काबुल में भारतीय दूतावास, टास्कफोर्स फार बिजिनेस एण्ड स्टेबिलिटी आपरेशन (टीएफबीएसओ), संयुक्त राज्य अमेरिका और एक निजी परामर्शदाता फर्म ग्लोबल नेटवर्क के सहयोग से अहमदाबाद में 15 अप्रैल, 2014 को 'अफगानिस्तान में निवेश अवसर पर रोड शो' का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सहयोग हेतु हार्ट आफ एशिया प्रोसेस के तहत परिकल्पित व्यापार, वाणिज्य तथा निवेश अवसरों (टीसीआई) संबंधी विश्वासोत्पादक उपाय के तत्वावधान में आयोजित किया गया था।
- अफगानिस्तान की निर्यात संवर्धन एजेंसी (ईपीएए) ने 18–19 जून 2014 के दौरान नई दिल्ली में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) और भारत के निर्यातक संघ (आईआईए) के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- श्री जामील हारेस, उप मंत्री, खान तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के नेतृत्व में एक अफगान प्रतिनिधिमंडल और अफगान खनन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में 8 अगस्त, 2014 को एसोचेम द्वारा आयोजित सातवें ''भारत खनन शिखर सम्मेलन–प्रौद्योगिकी आमेलन तथा स्थायित्व के मुद्दे'' में भाग लिया। अफगानी प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के खनन क्षेत्र में निवेश अवसरों पर प्रस्तुतीकरण दिया।
- काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने 25 सितंबर, 2014 को एक 'मेक इन इंडिया' अभियान का आयोजन किया जिसमें अफगानिस्तान के सबसे बड़े 80 से अधिक व्यापारियों और चेंबर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के सदस्यों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम श्री अमर सिन्हा, राजदूत के स्वागत भाषण से प्रारंभ हुआ और इसके बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रस्तुति हुई और प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण भी हुआ।
- नवी मुंबई चेंबर्स आफ कामर्स एण्ड टीएफबीएसओ, अमेरिका के सहयोग से अहमदाबाद की एक निजी परामर्शदाता कंपनी ग्लोबल नेटवर्क द्वारा 1–2 अक्टूबर, 2014 को मुंबई में 'अफगानिस्तान निवेश मंच' का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के बाद बी2बी बैठकें की गईं।
- 2–4 नवंबर, 2014 को इंटरकोंटिनेंटल होटल, काबुल में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और काबुल स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से फिक्की तथा अफगान चेंबर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसीसीआई) ने भारत उत्पाद शो का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में दोनों देशों के 43 स्टाल (28 भारतीय और 15 अफगान प्रदर्शनी) थे। भारतीय प्रदर्शनियों में फार्मास्यूटिकल उपकरण, सिंचाई मशीनरी, प्लास्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, कास्मेटिक उत्पाद, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा मशीन, आटोमोबाइल (इंजन, कलपुर्जे), औद्योगिक उत्पाद, शिक्षा तथा आथित्य क्षेत्र प्रदर्शित किए गए।
- 24 अफगानी कंपनियों ने 34वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ 2014) में भाग लिया और केसर, सूखे मेवे, कारपेट, आभूषण और हस्तकला की वस्तुओं जैसे अपने उत्पादों की प्रदर्शनी प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14–27 नवंबर, 2014 को लगाई।

बांग्लादेश

रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान 18–23 दिसंबर, 2014 के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद अब्दुल हमीद की उल्लेखनीय भारत यात्रा हुई जो 42 वर्षों के अंतराल के बाद बांग्लादेश के सेरेमोनियल राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी, क्योंकि ऐसी पिछली यात्रा दिसंबर, 1972 में हुई थी। भारत में अपने प्रवास के दौरान बाग्लादेश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता के साथ मुलाकात की। उन्होंने आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, जयपुर और कोलकाता जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की यात्राएं की। बाग्लादेश के राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच घनिष्ट द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा इसका विस्तार करने में योगदान दिया।

इस वर्ष के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच विभिन्न क्षेत्रों मे सहयोग के विस्तार और इसके बाद फरवरी, 2013 की संयुक्त परामर्शदाता आयोग की बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के माध्यम से संबंध और सुदृढ़ हुए। भारत–बांग्लादेश संबंध वास्तव में बहु–शाखीय हो गए हैं जिनमें व्यापार तथा निवेश, सुरक्षा, संपर्क, सीमा प्रबंधन, जल, विद्युत नौवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, विकास सहयोग, कला तथा संस्कृति, लोगों के आपसी आदान–प्रदान, मानव संशाधन विकास भी अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ शामिल थे। इस वर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं –दिसंबर, 2014 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, जून 2014 में विदेश मंत्री के अपने पहले विदेश दौरे के रूप में ढाका की यात्रा, उच्चायोग को सहायता पहुंचाने के लिए अगरतला में बांग्लादेश वीजा कार्यालय का उन्नयन।

दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तरीय यात्राओं से दोनों देशों के बीच द्विपेक्षीय संबंधों का मूल्याकन हुआ। मई 2014 में भारत में आम चुनाओं के पश्चात बांग्लादेश के स्पीकर डां शिरीन शर्मिन चौधरी ने प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना की ओर से नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में भाग लिया। इसके

प्रधान मंत्री 26 नवंबर, 2014 को काठमाण्डू में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. अशरफ गनी से मुलाकात करते हुए।

विदेश मंत्री ने काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करजई से मुलाकात करते हुए।

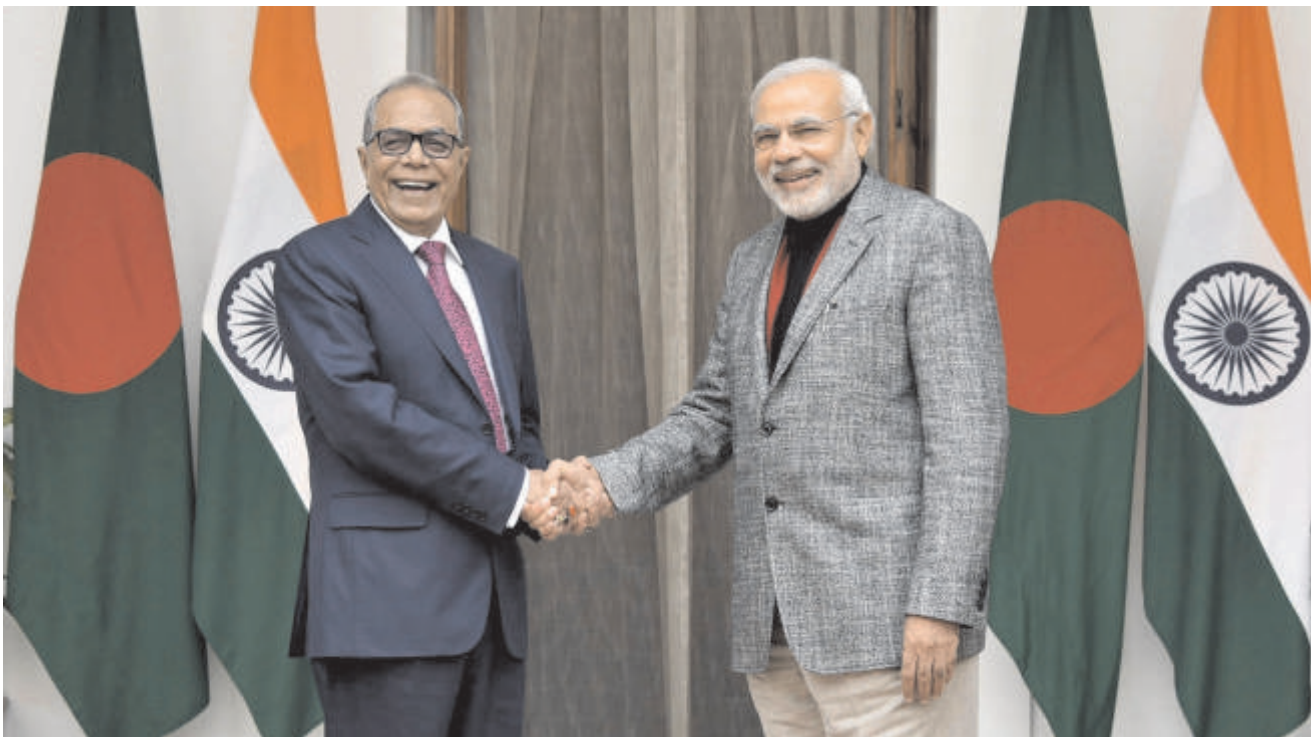

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में बांग्लादेश लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री अब्दुल हमीद से मुलाकात करते हुए।

प्रधान मंत्री 26 नवंबर, 2014 को काठमाण्डू में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश की प्रधान मंत्री सुश्री शेख हसीना से मुलाकात करते हुए।

पश्चात विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 25–27 जून, 2014 के दौरान विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली समुद्रपारीय यात्रा पर बांग्लादेश की यात्रा की। भारत –बांग्लादेश व्यापार सम्मेलन/कनक्लेव में भाग लेने के लिए 24 अगस्त 2014 को केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विदेश और प्रवासी भारतीय कार्य (राज्यमंत्री) जनरल डा॰ वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ–साथ मेघालय के मुख्यमंत्री डा. मुकुल संगमा और त्रिपुरा के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री तपन चक्रवर्ती ने बांग्लादेश की यात्रा की। श्री अनिल गोस्वामी, केंद्रीय गृह सचिव (एचएस) ने श्री डी.के. पाठक, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल के साथ–साथ एक 12 सदस्यीय अंतरमंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल के साथ 2–4 सितंबर, 2014 को बांग्लादेश का दौरा किया। श्री हर्षवर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक और दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन के 67वें सत्र में भाग लेने के लिए 08–12 सितंबर, 2014 के दौरान बांग्लादेश की यात्रा की। दो भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, एक ने सितंबर में और दूसरा नवंबर 2014 में क्रमशः आई पी यू, जिनेवा और राष्ट्रमंडल संसदीय संगठन तथा आई एम एफ के साथ बांग्लादेश संसद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बांग्लादेश का दौरा किया।

बांग्लादेश से भारत आने वाले महत्वपूर्ण दौरों में शामिल हैं– नवंबर 2014 में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणराज्य मंत्री श्री जाहिद मालेक द्वारा 07–09 नवंबर, 2014 के दौरान छठे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा, 05–07 नवंबर, 2014 के दौरान सातवें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एस ए ई एस) में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डॉ0 गौहर रिजवी की नई दिल्ली यात्रा, श्री नुरुल इस्लाम नाहिद, बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री की 30–31 अक्तूबर, 2014 के दौरान नई दिल्ली में दूसरे सार्क शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा, डॉ0 शिरीन सर्मिन चौधरी, अध्यक्ष, जातीय संसद का 29–31 अक्तूबर, 2014 के दौरान चण्डीगढ़ में संसदीय कृषि समितियों की सी पी ए कार्यशाला में भाग लेने और 16–17 अक्तूबर, 2014 के दौरान दिल्ली नीति समूह द्वारा आयोजित किए जा रहे ''विजन 2034'' नामक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा, श्री हसनुल हक इनु, सांसद, सूचना मंत्री की बांग्लादेश बौध मठ, बोधगया, बिहार में 30 अक्तूबर – 02 नवंबर, 2014 के दौरान होलीयेलो रोब्स ऑफरिंग उत्सव में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा, पांचवें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ऊर्जा मंत्रियों की 16–17 अक्तूबर, 2014 के दौरान बैठक में भाग लेने के लिए विद्युत ऊर्जा तथा खनिज संसाधन राज्यमंत्री का नई दिल्ली का दौरा, श्री असादुजमां, सांस्कृतिक कार्य मंत्री द्वारा 24–26 सितंबर, 2014 के दौरान सार्क संस्कृति मंत्रियों की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा, एयर मार्शल मोहम्मद ईनामुल बारी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, बांग्लादेश एयर फोर्स मुख्यालय का 17–20 सितंबर, 2014 के दौरान यात्रा, श्री मिकाइल सिपार, सचिव, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय की 02–04 सितंबर, 2014 की यात्रा। मेजर जनरल अजीज अहमद, महानिदेशक, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 20–24 अगस्त, 2014 की यात्रा, डाक तथा दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अब्दुल लतीफ सिद्दीकी की 07–08 अगस्त, 2014 के दौरान यात्रा शामिल थी।

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने के लिए लागू सांस्थानिक व्यवास्थाएं आवधिक रूप से की गई। संयुक्त परामर्शदाता आयोग (जेसीसी) की तीसरी बैठक 20 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में हुई जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षी की गई। जेसीसी के दौरान बांग्लादेश ने भारत के साथ नांलदा विश्वविद्यालय के संबंध में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गृह सचिव स्तरीय बातचीत का 14वां दौर 2–4 सितंबर, 2014 के दौरान ढाका में आयोजित हुआ जिसमें सुरक्षा, सहयोग, सीमा प्रबंधन, आईआईजी, तस्करी, विभिन्न द्विपक्षीय संधियों का कार्यान्वयन और वांछित व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया। इस बैठक में चिंता/सरोकार के अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सीमा गार्ड, बांग्लादेश के बीच 39वां सीमा सहयोग सम्मेलन 20–25 अगस्त, 2014 के दौरान नई दिल्ली में हुआ।

बांग्लादेश और भारत के बीच समुद संबंधी कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस) के अनुबंध VII के तहत स्थापित समुद्री सीमा के सीमांकन हेतु मध्यस्थ ट्राईब्यूनल ने 7 जुलाई, 2014 को अपना निर्णय दिया। समुद्री सीमा के समाधान हो जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दे को परस्पर समझ और सद्भावना से और अधिक निकटता से हल किया जा सकेगा। इससे बंगाल की खाड़ी के इस भाग के आर्थिक विकास के लिए रास्ता खुलेगा जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद होगा।

व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सांस्थानिक ढांचे को इस वर्ष और अधिक मजबूत किया गया। सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर इंडियन फुटवियर कंपोनेन्ट मेनूफैक्चरर एसोशिएसन (आईएफसीओएमए) और बांग्लादेश के लेदर गुड्स और फुटवियर मेनूफैक्चरर एण्ड एक्सपोर्टर एसोशिएसन के बीच ढाका में हस्ताक्षर किए गए जिसमें दोनों संगठनों के बीच बारंबार बातचीत सूचना का आदान–प्रदान और स्वस्थ व्यापार संबंध के विकास की व्यवस्था है। इस समझौता ज्ञापन से रणनीतिक गठबंधन (संयुक्त उद्यम) के विकसित होने और द्विपक्षीय विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से फुटवियर तथा कम्पोनेन्ट क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश की संभावनाओं के विकसित होने की संभावना है।

बांग्लादेश को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में वर्ष 2012–13 में 4.7 बिलियन डालर से तेज वृद्धि हुई और यह वर्ष 2013–14 में बढ़कर 6.03 बिलियन डालर हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.35 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्तमान में सार्क देशों में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। भारत बांग्लादेश अंतर–सरकारी रेल बैठक (आईजीआरएम) की बैठक 21–23 अप्रैल, 2014 को ढाका में हुई जिसमें दोनों देशों के बीच रेल सहयोग की पूर्ण समीक्षा की गई और संपर्क तथा सेवाओं में सुधार के तौर–तरीकों की भी समीक्षा की गई। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ मैत्री एक्सप्रेस द्वारा यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने, बीरोल (बांग्लादेश)–राधिकापुर (भारत), चिलाहाटी (बांग्लादेश) –हल्दीबारी (भारत) जैसे दोनों देशों के बीच के पुराने रेल संपर्कों को फिर से खोलना और अखौरा –अगरतला जैसे नए संपर्क स्थलों का निर्माण के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने भारत और बांग्लादेश के बीच भाड़ेवाले ट्रेनों के प्रचालन और कंटेनर रेल सेवाएं प्रारंभ करने की व्यावहार्यता पर भी चर्चा की।

वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को वायदा किए गए 200 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान में से 25 मिलियन अमरीकी डालर का चौथा हिस्सा बांग्लादेश पक्ष को भुगतान किया गया। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश को 175 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान सहायता का वितरण पूरा हो गया है। बांग्लादेश को 800 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला के उपयोग में सतत प्रगति प्राप्त की गई जो भारत द्वारा किसी भी देश को दी गई अकेली सबसे बड़ी ऋण श्रृंखला है। चल रही 15 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग के विकास हेतु हमारे पड़ोसी देशों के साथ संपर्क की भारत की पहल के भाग के रूप में भारत सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं में कार्य करने हेतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के अनुसंधानकर्ताओं के लिए भारत विज्ञान तथा अनुसंधान अध्येतावृत्ति (आईएसआरएफ) कार्यक्रम की शुरूआत की है। वर्ष 2015 के बाद से बांग्लादेश के अनुसंधानकर्ताओं के लिए अध्येतावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इससे 6 महीनों तक भारत की अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में अनुसंधान चलाने के लिए अधिकतम 10 बांग्लादेशी वैज्ञानिकों को मौका मिलेगा।

भारत ने भारत के फ्लैगशिप अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग कार्यक्रम, भारत तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) की स्वर्णजंयती मनाई जहां बांग्लादेश की राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थीं। वर्ष 2007 से भारत में लगभग 800 आईटीईसी विद्वानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आईटीईसी छात्रवृत्ति की संख्या वर्ष 2007 से प्रत्येक वर्ष 100 से दोगुनी होकर वर्ष 2014 में 215 हो गई है। पिछले वर्ष रिकार्ड संख्या में 185 विद्वान भारत आए थे। इसके अलावा, कोलंबों योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम के तहत लगभग 200 विद्वान वर्ष 2007 के बाद से प्रशिक्षण के लिए जा चुके हैं।

बीआईएमएसटीईसी स्थाई सचिवालय का उद्घाटन सितंबर, 2014 में ढाका में औपचारिक रूप से किया गया। भारत ने बिम्स्टेक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संबंध में बांग्लादेश को आश्वस्त किया और यह प्रक्रिया के लिए और सचिवालय को हर सहयोग देना जारी रखेगा। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक ठोस अभिविन्यास प्रदान करता है और दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है।

40वां सीमा सहयोग सम्मेलन की सह–अध्यक्षता महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, भारत और महानिदेशक बांग्लादेश बोर्डर गार्ड, बांग्लादेश द्वारा 26–29 दिसंबर, 2014 के दौरान ढाका में की गई।

हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार में सीमा हाट खोलने के साथ ही और तेजी आई है। बांग्लादेश ने श्रीनगर और त्रिपुरा में कमाल सागर में दो सीमा हाट खोलने को अनुमोदित किया। श्रीनगर (फेनी जिले में) में कार्य प्रगति पर है और इसका उद्घाटन 13 जनवरी 2015 को किया गया। त्रिपुरा–पालबस्ती और कमालपुर में दो अन्य सीमा हाट के लिए बांग्लादेश पक्ष ने सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है। मई 2013 में मेघालय सीमा के आस–पास 22 सीमा हाट का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से बांग्लादेश द्वारा 4 को अनुमोदित किया जा चुका है और काम जल्दी ही शुरू होने की आशा है। बारजेज से लेकर आशूगंज तक प्रोटोकाल रास्ते के माध्यम से और इसके बाद सड़क मार्ग से अगरतला तक –त्रिपुरा से कोलकाता 10,000 मीट्रिक टन चावल की ढुलाई 5000 मीट्रिक टन प्रत्येक के हिसाब से दो चरणों में की गई और इसे नवंबर, 2014 में पूरा किया गया।

तटीय पोतपरिवहन और किस प्रकार के जहाजों को अनुमति दी जाए, इसका मानक तय करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति गठित की गई है, जिसकी दूसरी बैठक जून, 2014 में दूसरी बार ढ़ाका में आयोजित की गई। बांग्लादेश पक्ष ने महानिदेशक, पोतपरिवहन भारत आदेश संख्या 18, वर्ष 2013 की रीवर सी वेसेल्स (आरएसवी) –IV वर्गीकरण अधिसूचना के अनुरूप वर्गीकरण तथा बीमा के लिए सहमत हुआ। बांग्लादेश ने आरएसवी –III / IV मानदंडों के प्रारंभिक अनुपालन के लिए 18 बांग्लादेशी जहाजों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी जिसके पश्चात भारतीय पोत परिवहन रजिस्टर (आईआरएस) प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करेगा। वाप्कोस कंसल्टेंट की नियुक्ति आशुगंज इनलैण्ड कन्टेनर रीवर पोर्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई। रिवर पोर्ट ने ढ़ाका में पोतपरिवहन मंत्रालय और बांग्लादेश इनलैण्ड वाटरवेज ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी (बीआईडब्ल्यूटीए) के सदस्यों को 16 जून,

2014 को एक प्रस्तुतिकरण दिया। टिप्पणियों तथा प्रतिक्रिया के आधार पर, एक संशोधित अंतिम डीपीआर तैयार की गई और 16 नवंबर, 2014 को प्रस्तुत की गई।

26–27 अक्तूबर 2014 को कोलकाता में संपन्न भारत और बांग्लादेश रेल प्रतिनिधिमंडल के बीच पिछली अंतर–रेलवे बैठक में, मैत्री एक्सप्रेस की बारंबारता प्रत्येक सप्ताह दो दिनों से बढ़ाकर तीन दिन करने का निर्णय लिया गया था। इसे जनवरी, 2015 से लागू कर दिया गया है। इस बैठक में कोलकाता–खुलना के बीच यात्री रेल सेवा और बेहतर उत्प्रवासन सुविधाओं के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। शिलांग–डावकी–सिलहट के रास्ते गुवाहाटी–ढ़ाका बस सेवा के लिए संयुक्त मार्ग सर्वेक्षण 11–13 दिसंबर, 2014 के दौरान किया गया। संयुक्त दल ने बस सेवा के लिए मार्ग की व्यवहार्यता व्यक्त की।

भारत और बांग्लादेश ने 11 अप्रैल, 2013 को बांग्लादेश में लघु विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 45.44 करोड़ रूपए (टका 58.24 करोड़ –जुलाई ओआरई) को संस्वीकृति लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में दी गई। 60 टका करोड़ की परियोजनाओं को राजशाही, खुलना और सिलहट में पहचान की गई है और ये कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गई हैं:

नियामतपुर, पोर्शा और सपाहर उपजिला, नोगांव जिला के लिए 400 गहरे नलकुपों की आपूर्ति पूरी की गई थी और इसका उद्घाटन समारोह 5 मई, 2014 को हुआ था।

कमालगंज, मौलवीबाजार में मणिपुरी सांस्कृतिक कम्पेल्स का निर्माण और उद्घाटन समारोह 3 जनवरी, 2015 को हुआ था। ढ़ाका विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग का निर्माण कार्य पूरा किया गया। दुर्गाबाड़ी मंदिर, मिमेनसिंह में तीन मंजिले डोरमिट्री भवन (साधु भवन) के (केवल भूतल) का निर्माण जनवरी, 2015 में उद्घाटन के साथ।

लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड (एल एण्ड टी) ने 24 अगस्त, 2014 को चट्टगांव के पटिया के सिकालबाहा में 225 मेगावाट कंबाइन्ड साइकल (डुएल फ्यूल) के निर्माण के लिए बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 202.22 मिलियन अमरीकी डॉलर है। यह बांग्लादेश में एल एण्ड टी द्वारा प्राप्त प्रथम इंजीनियरी, प्रापण तथा निर्माण (ईपीसी) संविदा है। एल एण्ड टी मारूबेनी कॉरपोरेशन के साथ 360 मेगावाट भेरामारा पर पहले से ही काम कर रहा है और बिबियाना में एक और 400 मेगावाट परियोजना के लिए मारूबेनी कॉरपोरेशन के साथ वार्ताएं चल रही हैं।

चिकित्सा और होम्योपैथ की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर स्वास्थ्य मंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 9 सितंबर, 2014 को हस्ताक्षर किए गए। इस क्षेत्र में सहयोग में आने वाले वर्षों में तेजी लाने की आवश्यकता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग आगे बढ़ा जब भारत ने बांग्लादेश रक्षा कार्मिकों के लिए 123 पाठ्यक्रम का प्रस्ताव दिया और बांग्लादेश पक्ष द्वारा 14 पाठ्यक्रमों का उपयोग किया गया। रिपोर्ट की गई इस अवधि के दौरान सेना और अंतर्राष्ट्रीय नौकायन/सेलिंग रेगाटा के संयुक्त अभ्यास भी आयोजित किए गए। दोनों पक्षों की ओर से राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज अध्ययन दौरा किया गया। नौसेना से नौसेना स्टॉफ की दूसरी वार्ता तथा सेना से सेना स्टॉफ की पांचवीं वार्ता क्रमशः अप्रैल तथा सितंबर 2014 में नई दिल्ली हुई।

बांग्लादेश–चीन–भारत–म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर (बीसीआईएम–ईसी) की संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) की बैठक 17–18 दिसंबर, 2014 को कोक्स बाजार में आयोजित की गई।

भारत ने भारत के फ्लैगशिप अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग कार्यक्रम, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) की स्वर्ण जयंती मनाई जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2007 से भारत में लगभग 800 आईटीईसी विद्वानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आईटीईसी छात्रवृत्ति की संख्या वर्ष 2007 में 100 प्रतिवर्ष से दोगुना करके वर्ष 2015 में 215 कर दिया गया है जिसमें से 31 दिसंबर, 2014 तक 160 का उपयोग किया जा चुका है। पिछले वर्ष, रिकार्ड (संख्या में) 185 विद्वान भारत आए। इसके अलावा, कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग योजना के तहत लगभग 200 विद्वान वर्ष 2007 से प्रशिक्षण के लिए जा चुके हैं।

04 जनवरी 2015 से, कोलकाता–ढ़ाका–कोलकाता 'मैत्री एक्सप्रेस' प्रत्येक सप्ताह एक अतिरिक्त बार चलनी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही, अब 'मैत्री एक्सप्रेस' सप्ताह में दो बार चलती है। यह व्यवस्था 4 जुलाई, 2015 तक लागू रहेगी जिसके बाद एक नयी सारणी 5 जुलाई, 2015 से लागू की जाएगी।

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित कमालगंज, मौलवीबाजार में मणिपुरी सांस्कृतिक परिसर के निर्माण का उद्घाटन समारोह 3 जनवरी, 2015 को हुआ था।

भारत सरकार के वित्तपोषण वाली अनेक अन्य परियोजनाएं वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/आगामी वित्तीय वर्ष में पूरी कर लिए जाने की आशा है।

25–30 जनवरी, 2015 के दौरान एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर को देखने के लिए बांग्लादेश एनसीसीस (बीएनसीसी) के अध्यक्ष के लिए और बीएनसीसी को 15–29 जनवरी, 2015 के दौरान गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने के लिए एक अधिकारी और 12 कैडेट (छह लड़के और छह लड़कियां) का निमंत्रण दिया गया है। भारतीय नौसेना बैण्ड गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में 24–29 जनवरी, 2015 के दौरान बांग्लादेश की यात्रा करने वाला है।

ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ डकोया एस सी बांग्लादेश को जनवरी, 2015 के प्रथम सप्ताह में स्मरणस्वरूप उपहार के तौर पर दिया गया है। बीएएफ संग्रहालय में एसी जोड़ने तथा संस्थापन के लिए एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। नई दिल्ली में वायुसेना स्टॉफ की आरंभिक वार्ता करने का प्रस्ताव फरवरी, 2015 माह में किए जाने की आशा है।

वायु सेवा स्टेशन, येलाहान्का, बेंगलुरू में 18–22 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस, रक्षा तथा नागर विमानन प्रदर्शनी, 2015 में भाग लेने के लिए बांग्लादेश वायुसेना को निमंत्रण भेजा गया है।

भूटान

भारत–भूटान संबंध परस्पर विश्वास और घनिष्ठ समझ से निरूपित हैं।

भूटानी प्रधानमंत्री श्री शेरिंग टोब्गे ने वित्त मंत्री श्री रिनजिंन दोर्जे के साथ प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 25–28 मई, 2014 के दौरान भारत की यात्रा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 27 मई को द्विपक्षीय वार्ताएं भी कीं।

प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री के साथ अपनी 15–16 जून, 2014 को भूटान की अपनी पहली विदेश यात्रा की। मई, 2014 में प्रधानमंत्री के शपथग्रहण समारोह के लिए सार्क नेताओं के भारत दौरे के बाद जल्दी ही, प्रधानमंत्री का दक्षिण एशिया के हमारे घनिष्ठ तथा मित्रवत पड़ोसियों में से एक का दौरा प्रतिकातमक था, जो हमारे निकट पड़ोसी को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री की पारो से थिंपु आने और जाने के दौरान 50 किलामीटर रास्ते के आस–पास भूटानी जनता द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश, चौथे नरेश, प्रधानमंत्री श्री शेरिंग टोब्गे और विपक्ष के नेता, डॉ. पेमा ग्याम्तशो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, 600 मेगावाट कोलोन्छु जलविद्युत परियोजना की नींव रखी, और 79 करोड़ रु॰ की भारत सरकार की सहायता वाली परियोजना, उच्चतम न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया। भूटान नरेश और प्रधानमंत्री श्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री के लिए भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री की बातचीत में नरेश, चुनी गई सरकार, विधायिका तथा न्यायपालिका शामिल थी। अपनी यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने संबंधों के अद्वितीय तथा विशेष प्रकृति को स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने भूटान को आश्वस्त किया कि भारत सरकार वर्ष 2013–18 के भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी जिसमें योजनागत सहायता 4500 करोड़ रु॰ है और आर्थिक प्रोत्साहन योजना के लिए 500 करोड़ रूपया है। प्रधानमंत्री ने कतिपय अनिवार्य खाद्य मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों से भूटान को छूट दिए जाने और नेहरू–वांग्छु छात्रवृत्ति को दोगुना करके प्रति वर्ष 2 करोड़ रु॰ करने के निर्णय के बारे में बताया और भूटान के प्रत्येक 20 जिलों को एक ई–लाईब्रेरी उपहार में दने की घोषणा की।

राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने भूटान नरेश महामहिम जिग्में खेसर नाम्गेल वांगचुक के निमंत्रण पर 7–8 नवंबर, 2014 को भूटान का राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ने नरेश, चौथे नरेश और भूटान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय अनेक मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। उन्होंने कॉन्वेंशन केन्द्र, थिंपु में 'भारत–भूटान संबंधों' पर भाषण दिया। इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ने राजदूत की छात्रवृत्ति को दोगुना करके प्रति वर्ष 2 करोड़ रूपए करने की घोषणा की। उन्होंने भूटान में भारत सरकार की सहायता वाली तीन परियोजनाएं प्रारंभ की नामतः 1) स्कूल सुधार कार्यक्रम (348.72 करोड़ रूपए) 2) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग को दो लेन का बनाना (463.657 करोड़ रूपए) और 3) जिग्में वांग्चुक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (33.7 करोड़ रूपए)। इस यात्रा के दौरान, भूटान ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से बाहर बांग्लादेश के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जो 1) रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान तथा इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, 2) रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान तथा नैशनल इनोवेशन फाउन्डेशन ऑफ इंडिया, और 3) रॉयल सिविल सर्विसेज कमिशन और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के बीच हुए।

प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर, 2014 को काठमांडू में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान भूटानी प्रधानमंत्री श्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की और द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर बातचीत की। भूटान के प्रधानमंत्री श्री शिरिंग टोब्गे 10–18 जनवरी, 2015 के दौरान भारत की सरकारी यात्रा पर आए। उनके साथ विदेश मंत्री,आर्थिक कार्य मंत्री और रॉयल भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी साथ आए। प्रधानमंत्री श्री शिरिंग टोब्गे ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, 2015 में भाग लेने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया, जहां वे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मिले। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की और नई दिल्ली में अनेक केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री शिरिंग टोब्गे ने वाराणसी और बोधगया की भी यात्रा की।

प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर, 2014 को काठमांडू में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान भूटानी प्रधानमंत्री श्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की और द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर बातचीत की। इस बैठक के दौरान प्रधान मंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री को जनवरी, 2015 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2015 में भाग लेने के लिए भारत आने का न्योता दिया।

नौवां भारत–भूटान सीमा प्रबंधन तथा सुरक्षा बैठक भूटानी गृह सचिव और सीमा प्रबंधन सचिव, गृह मंत्रालय की अगुवाई में नई दिल्ली में जून, 2014 में हुई।

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार तथा विकास भागीदार बना हुआ है। भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रूपए की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के तहत विमुक्तियां समय पर वितरित की जाती रहीं जिसके लिए प्रधान मंत्री श्री शिरिंग टोब्गे ने नवंबर, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अपनी मुलाकात के समय उन्हें धन्यवाद दिया। भारत सरकार तीन जलविद्युत परियोजनाओं नामतः पुनातसांग्छु–। (1200 मेगावाट), पुनातसांग्छु –।। (1020 मेगावाट) और मांगदेछु (720 मेगावाट) के निर्माण में भूटान की सहायता कर रही है, जिसे 2017–18 में पूरा किए जाने की प्रत्याशा है। इससे पहले, 22 अप्रैल, 2014 को , भारत ने भूटान के साथ चार संयुक्त उद्यम जलविद्युत परियोजनाओं पर अंतर–सरकारी करार और भूटान में 600 मेगावाट कोलान्छु जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए।

13वां अधिकार प्राप्त संयुक्त समूह (ईजेजी), जो भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करता है, नई दिल्ली में सितंबर, 2014 में मिला। भूटानी आर्थिक कार्य मंत्री श्री नोरबु वांग्चुक ने 13वें ईजेजी बैठक की अध्यक्षता की।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2013–18) के लिए तीसरी भारत–भूटान विकास सहायोग वार्ता सितंबर, 2014 में हुई थी। विभिन्न क्षेत्रों में 48 नई परियोजनाएं जैसे कृषि और पशुधन विकास, सड़क तथा पुल, स्वास्थ्य, शहरी विकास, संस्कृति का संरक्षण और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास आदि पर सहमति हुई थी।

एक साहित्यिक परामर्शदात्री, सियाही के सहयोग से भारत–भूटान फाउन्डेशन की पहल, माउन्टेन इकोज़ लिटरेरी फेस्टिवल का पांचवां संस्करण 21–24 मई, 2014 के दौरान थिंपु में हुआ था। दोनों देशों के साहित्यिक और राजनीतिक हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

भूटान के पांच राजनीतिक दलों के एक 12 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 13–20 दिसंबर, 2014 के दौरान भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत में बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की, संसदीय अध्यन ब्यूरो (बीपीएसटी) और भारत के निर्वाचन आयोग के साथ बातचीत की और सिंचाई, उद्योग, स्वास्थ्य तथा संचार से संबंधित विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को देखने के लिए गुजरात की यात्रा की।

शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में निकट सहयोग जारी रहे। भारत सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना में भूटानी छात्रों को स्नातकोत्तरपूर्व छात्रवृत्ति के रूप में 55 करोड़ रूपए का वायदा किया। वर्ष 2014 में, नेहरू–वांग्चुक और राजदूत छात्रवृत्तियां दोनों ही दोगुनी करके प्रतिवर्ष 2 करोड़ रूपए कर दी गई।

चीन

चीनी नेतृत्व ने भारत में नवगठित सरकार से संपर्क करने की अपनी इच्छा दर्शाई। प्रधानमंत्री श्री ली केकियांग ने 29 मई, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ दूरभाष पर बातचीत की शुरूआत की और भारत के साथ 'मजबूत संबंध' स्थापित करने की अपनी सरकार की इच्छा व्यक्त की। विदेश मंत्री श्री वांग यी ने भी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को अपना कार्यभार संभालने पर बधाई संदेश भेजा। विदेश मंत्री श्रीवांग यी, चीन के राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में 8–9 जून, 2014 को नई दिल्ली की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की नई सरकार के साथ संपर्क स्थापित करना और भारत–चीन रणनीतिक तथा सहयोगात्मक संबंध को और गति प्रदान करना था। विदेश मंत्री ने 8 जून, 2014 को विदेश मंत्री श्री वांग यी के साथ व्यापक बातचीत की। विदेश मंत्री श्री वांग यी ने राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात की और और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मिले। विदेश मंत्री की मुलाकात 9 अगस्त, 2014 को नायपेईताउ, म्यांमार में एआरएफ के अतिरिक्त समय में चीनी विदेश मंत्री श्री वांग यी के साथ हुई। उन्होंने जून, 2014 में नई दिल्ली में अपनी पिछली मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता की समीक्षा की। वे सितंबर, 2014 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अतिरिक्त समय में भी मिले।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त समय में फोर्टलिजा, ब्राजील में 14 जुलाई, 2014 को चीनी राष्ट्रपति श्री जि जिंनपिंग से मुलाकात की। बातचीत क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ–साथ द्विपक्षीय एजेंडे के सभी पहलुओं पर केन्द्रित रही। प्रधानमंत्री ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक के अतिरिक्त समय में नाय पेई ताउ में 13 नवंबर, 2014 को प्रधानमंत्री ली केकियांग से भी मुलाकात की।

श्री जि जिंनपिंग, चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति ने 17–19 सितंबर, 2014 के दौरान भारत (अहमदाबाद–नई दिल्ली) की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति श्री जि जिनपिंग ने राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत की। चीनी राष्ट्रपति श्री जि जिनपिंग की यात्रा के दौरान, कुल 16 करारों पर हस्ताक्षर किए गए जो हैं 1. चीन जनवादी गणराज्य के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से होकर भारतीय तीर्थयात्रियों की (कैलाश मानसरोवर यात्रा) के लिए नया मार्ग खोलना, 2. रेलवे में सहयोग सुदृढ़ करने पर समझौता ज्ञापन 3. रेलवे में सहयोग सुदृढ़ करने पर कार्ययोजना 4. पांच वर्षीय व्यापार तथा आर्थिक विकास योजना, 5. भारत–चीन संयुक्त आर्थिक समूह

के दसवें सत्र में सहमत कार्यवृत्त, 6. श्रव्य–दृश्य सह–उत्पादन पर करार, 7. सीमाशुल्क संबंधी मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता तथा सहयोग पर करार, 8. अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहायता पर समझौता ज्ञापन, 9. सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच आदान–प्रदान तथा सहयोग को सुदृढ़ करने पर समझौता ज्ञापन, 10. भारत गणराज्य के नेशनल बुक ट्रस्ट और चीन जनवादी गणराज्य के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस, पब्लिकेशन, रेडियो एण्ड टेलिविजन के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन, 11. औषध प्रशासन तथा सहयोग पर कार्ययोजना, 12. मुंबई तथा संघाई के बीच सहयोगी शहर स्थापित करने पर करार, 13. अहमदाबाद और गुआंग्झु के बीच सहयोगी शहर स्थापित करने पर करार, 14. गुजरात और ग्वांगडॉग के बीच सहयोगी शहर स्थापित करने पर करार, 15. महाराष्ट्र में औद्योगिक पार्क स्थापित करने में सहयोग करने पर समझौता ज्ञापन और 16. गुजरात में औद्योगिक पार्क स्थापित करने में सहयोग करने पर समझौता ज्ञापन।

चीन के उपराष्ट्रपति की पहल पर, भारत के उप–राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी ने 26–30 जून, 2014 के दौरान चीन की सरकारी यात्रा की। उप राष्ट्रपति ने अपने समकक्ष, चीन के उपराष्ट्रपति श्री ली यूआनचाउ के साथ 30 जून, 2014 को द्विपक्षीय वार्ता की और और राष्ट्रपति श्री जि जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंन 28–29 जून, 2014 को बीजिंग में 'पंचशील' की 60वीं वर्षगांठ मनाने संबंधी समारोह में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान भारत में औद्योगिक पार्क पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन, चीन से भारत को खाद्य मौसम में यारलंग जांग्बु/ब्रम्हपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल सूचना के प्रावधान के लिए कार्यान्वयन योजना और लोक अधिकारियों के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण के संचार तथा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।'भारत–चीन सांस्कृतिक संपर्क पर विश्वकोश' दोनों उपराष्ट्रपतियों की उपस्थिति में जारी किया गया।

दोनों पक्षों ने एक रणनीतिक आर्थिक डॉयलॉग (एसईडी) तंत्र की स्थापना की है। तीसरा एसईडी 18 मार्च, 2014 को बीजिंग में आयोजित किया गया। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने मैक्रो इकोनॉमिक नीति समन्वय बढ़ाने और मुद्दों तथा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विचार से द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, और आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय व वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। रेलवे अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और वित्त जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया। जेईजी की 10वीं बैठक बीजिंग में 2 सितंबर, 2014 को हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई श्रीमती निर्मला सीतारमन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वाणिज्य तथा उद्योग ने की। दोनों पक्षों ने भारतीय सूत तथा सूत यार्न पर सीमाशुल्क/ड्यूटी में कमी लाने पर चर्चा की और पंच–वर्षीय व्यापार तथा आर्थिक विकास योजना को राष्ट्रपति श्री जि जिनपिंग की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने हेतु अंतिम रूप दिया। इस यात्रा के दौरान 10वीं जेईजी की बैठक के सहमत कार्यवृत्त पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत और चीन ने सीमा सहमति के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से फेमवर्क तलाशने के लिए विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की नियुक्ति की है। अब तक सीमा के प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 17 दौर की बातचीत हो चुकी है। श्री यांग जीएची, चीनी राज्य कॉसिलर और एसआर ने 10–11 फरवरी, 2014 को तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन से 17वें दौर के लिए बातचीत करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। दोनों एसआर ने सीमा के प्रश्न के समाधान पर एक फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी रखी, जो तीन–स्तरीय प्रक्रिया का दूसरा कदम है। भारत–चीन सीमा मामले (डब्ल्यूएमसीसी) पर परामर्श तथा सहयोग के लिए कार्यतंत्र की स्थापना पर एक करार पर जनवरी, 2012 में नई दिल्ली में एसआर के 15वें दौर के दौरान हस्ताक्षर किए गए। डब्ल्यूएमसीसी की एक बैठक 17–18 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में हुई।

चीफ ऑफ द आर्मी स्टॉफ जनरल बिक्रम सिंह ने स्टॉफ समिति के प्रमुखों के अध्यक्ष की हैसियत से 2–5 जुलाई, 2014 के दौरान चीन की यात्रा की। आतंक विरोधी 'हैण्ड इन हैण्ड' पर चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूणे, भारत के निकट 17– 25 नवंबर 2014 को हुआ। विदेश सचिव ने 13–14 अप्रैल, 2014 को चीन की यात्रा की और 14 अप्रैल को उपविदेश मंत्री श्री लियु झेनमीन के साथ 6ठा भारत–चीन रणनीतिक बातचीत की। उन्होंने विदेश मंत्री श्री वांग यी से मुलाकात की और उसी दिन चीन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (सीआईआईएस) में भारत–चीन संबंध पर एक गोलमेल बातचीत में भी हिस्सा लिया। वर्ष 2006 में, दोनों देशों ने सीमा–पार नदियों (ईएलएम) पर एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र स्थापित किया। भारत–चीन ईएलएम की 8वीं बैठक जून, 2014 में नई दिल्ली में हुई। सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर भारत–चीन संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 14–18 दिसंबर, 2014 के दौरान नई दिल्ली में हुई। 7वीं भारत–चीन वित्तीय वार्ता 19 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में हुई।

भारत और चीन के बीच एक युवा प्रतिनिधिमंडल आदान–प्रदान कार्यक्रम है। 100 सदस्यीय एक चीनी युवा प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर, 2014 में भारत की यात्रा की। 100 सदस्यीय एक भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने वार्षिक युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत 25 नवंबर, 2014 से 2 दिसंबर, 2014 के दौरान चीन का दौरा किया। दोनों देशों के बीच आदान–प्रदान कार्यक्रम है जो विदेश मंत्रालय तथा चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के बीच होता है। श्री कियांग वेई, पार्टी सचिव, सीपीसी जियांझी प्रांतीय समिति ने इस कार्यक्रम के तहत नवंबर, 2014 में भारत की यात्रा की।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज चीनी विदेश मंत्री के साथ

द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए 01–02– फरवरी, 2015 को चीन की यात्रा की।

मालदीव

राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 26–27 मई, 2014 के दौरान भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ने राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और इस यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम को बताया कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंध को उच्च महत्व देता है और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में काम करने का वायदा किया। प्रधान मंत्री ने गौर किया कि दोनों देशों की साझा पहचान है कि दोनों देशों की सुरक्षा हित आपस में जुड़े हैं और सहमति जताई कि प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की चिन्ताओं के प्रति संवेदनशील रहना जारी रखेगा। इस बात पर सहमति हुई कि पेट्रोलियम, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए उपाय किए जाएं।

प्रधान मंत्री ने भी राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम से काठमांडू में 26 नवंबर, 2014 को 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त समय में मुलाकात की। प्रधान मंत्री ने सार्क सम्मेलन के दौरान मालदीव के लिए विशेष तेल व्यवस्था की घोषणा की।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने माले में अपने पारगमन ठहराव के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री सुश्री दुन्या माउमून से 3 नवंबर, 2014 को मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 24 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 वें सत्र के अतिरिक्त समय में न्यूयार्क में भी माले की विदेश मंत्री से मुलाकात की।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अजीत डोवाल ने 2–3 दिसंबर, 2014 के दौरान मालदीव की यात्रा की। वे राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम से मिले और विदेश मंत्री सुश्री दुन्या माउमून, रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री मोहम्मद नाजिम, पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल गयूम, पूर्व राष्ट्रपति श्री मोहम्मद नशीद और जम्हूरी पार्टी के नेता श्री गासीम इब्राहिम से भी मिले।

रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री मोहम्मद नाजिम ने 20–22 अक्तूबर 2014 के दौरान भारत की यात्रा की। वे विदेश मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री अरूण जेटली, तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह से मिले।

उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डा. अरविंद गुप्ता ने माले में 23 सितंबर, 2014 को संपन्न भारत, मालदीव तथा श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर त्रिपक्षीय पहल की चौथी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मालदीव में प्राचीन मस्जिदों के पुनरूद्धार के लिए अध्ययन आयोजित करने हेतु मालदीव सरकार के अनुरोध पर 14–20 अगस्त 2014 के दौरान मालदीव की यात्रा की। एएसआई प्रतिनिधिमंडल ने मालदीव सरकार के इस्लामिक मामले मंत्रालय और विरासत विभाग के अधिकारियों से चर्चा की।

तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने 08–10 मई 2014 के दौरान मालदीव की यात्रा की। वे राष्ट्रपति से मिले और रक्षा तथा सुरक्षा मंत्री श्री मोहम्मद नाजिम और रक्षा बल प्रमुख मेजर जनरल अहमद शियाम के साथ बैठकें कीं।

इस्लामिक कार्य मंत्री डॉ. मोहम्मद शाहीम अली सईद ने 10–18 अप्रैल 2014 के दौरान भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, डॉ. शाहीम ने उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी से मुलाकात की और तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉ. के रहमान खान से मिले। इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत में विभिन्न इस्लामिक शिक्षण संस्थानों के भी दौरे किए।

माले को पेयजल उपलब्ध कराने के मालदीव सरकार से 4 दिसंबर, 2014 की रात में अनुरोध प्राप्त होने के प्रत्युत्तर में, भारत सरकार ने तत्काल आधार पर पेयजल हवाई मार्ग से पहुंचाया। पहला एयर फोर्स विमान 5 दिसंबर, 2014 के दोपहर में पेयजल के बोतल के साथ माले में उतरा। इस हवाई प्रयास के साथ आईएनएस सुकन्या और आईएनएस दीपक ने भी सहायता की जिन दोनों के पास अंदर/बोर्ड पर ही अलवणीकरण संयंत्र लगा हुआ है। भारत सरकार द्वारा समय पर उपलब्ध कराई गई सहायता ने माले में एक बड़ी मानवीय त्रासदी होने से बचा लिया।

कीव में भारतीय दूतावास ने मालदीव सरकार से अनुरोध प्राप्त होने के बाद 04–05 जून, 2014 को यूक्रेन के पूर्वी भाग में लुगान्स्क से 18 मालदीवी छात्रों को बचाकर निकाला।

भारत सरकार ने 18 मई, 2014 को प्रारंभ करके माले में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल (आईजीएमएच) के नवीकरण के लिए परियोजना का वित्तपोषण किया। इस परियोजना में वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, प्रसव कक्ष, आपात कक्ष और छत, सिलिंग, अग्नि प्रणालियों तथा भवन के वायरिंग को पूरी तरह से बदलने का काम शामिल है।

मालदीव राष्ट्रीय रक्षा (एम. एन डी एफ) के लिए समग्र प्रशिक्षण केन्द्र के प्रथम चरण का निर्माण अगस्त, 2014 में प्रारंभ हुआ। भारत सरकार ने परियोजना के चरण – । के लिए 9.08 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति जताई है, जिसे अप्रैल, 2015 में पूरा कर लिए जाने की आशा है।

भारतीय तटरक्षक/कोस्ट गार्ड ने माले राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) और श्रीलंका के तटरक्षक के साथ 28–31 अक्तूबर

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मई 2014 में भूटान के प्रधान मंत्री, श्री शिरिंग टोबो की भारत यात्रा।

चीन के विदेश मंत्री, श्री वांग यी 08 जून, 2014 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ।

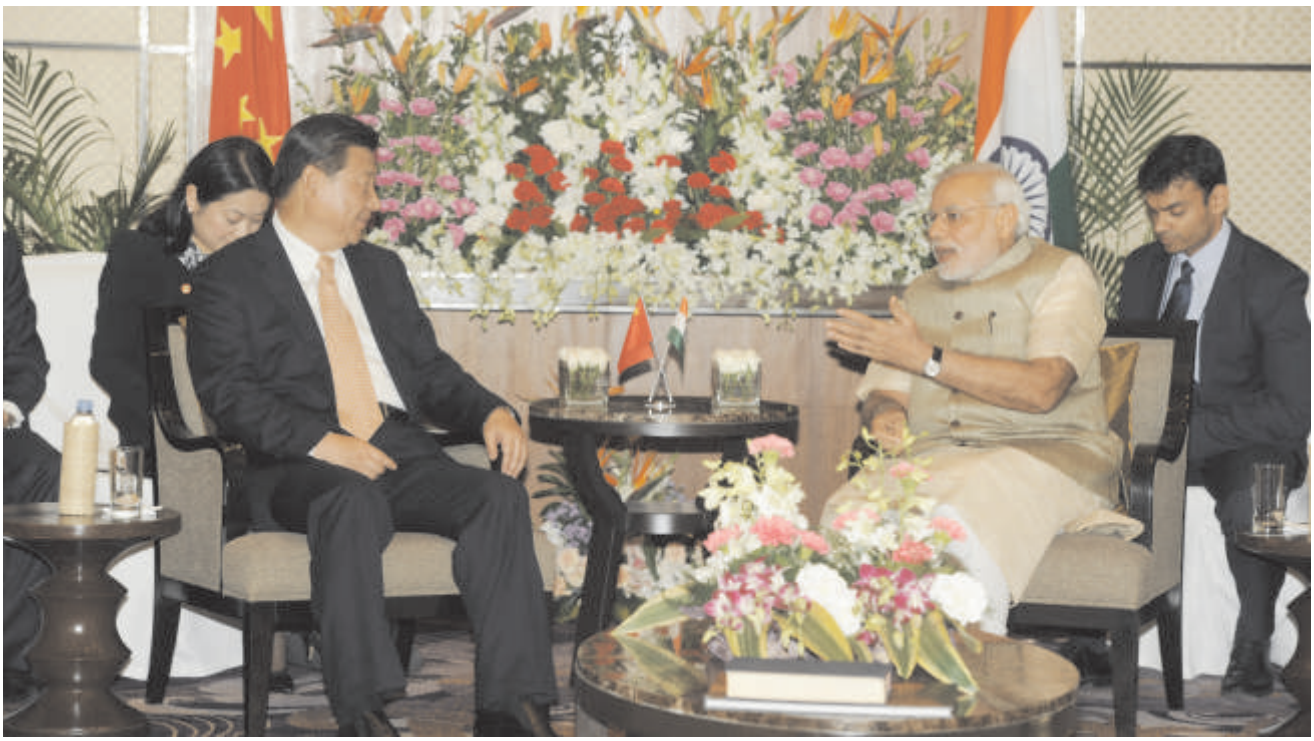

चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम, श्री जि जिनपिंग 17 सितंबर, 2014 को अहमदाबाद में प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के साथ।

प्रधान मंत्री काठमाण्डू में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति, श्री अब्दुला यामीन से मुलाकात करते हुए (26 नवंबर, 2014)।

2014 को मालदीव में ''दोस्ती–XII'' नामक संयुक्त अभ्यास का बारहवां एडिशन आयोजित किया। दो भारतीय जहाज आईसीजीएस समर और आईसीजीए राजदूत ने दोरनियर विमानों सहित अभ्यास में भाग लिया।

भारतीय सेना और एमएनडीएफ समुद्री कोर ने मालदीव में 17–30 नवंबर 2014 के दौरान 'इकुवेरीन' नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। भारतीय सेना के एक 45 सदस्यीय दल ने एमएनडीएफ मेरिनों के साथ अभ्यास में भाग लिया।

भारतीय नौसेना जहाज और हवाईजहाज द्वारा ईईजेड निगरानी मासिक आधार पर आयोजित किए गए। भारतीय नौसेना जहाजों कोस्वारी, त्रिकंड, सुकन्या, सुमेघा, काब्रा और डोर्नियर एअरक्राफ्ट ने इस अवधि के दौरान मालदीव की यात्रा की और एमडीएनएफ के साथ निगरानी में भाग लिया।

भारतीय रक्षा बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जून, 2014 और नवंबर, 2014 में मालदीव में दो चिकित्सा शिविर लगाए। 3000 से अधिक मालदीवी लोग इसमें आए और इन निःशुल्क शिविरों का लाभ उठाया, जो देश के विभिन्न स्थानों में लगाया गया था।

म्यांमार

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री स्तर के दौ दौरे हुए। पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने तीसरा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मार्च, 2014 में म्यांमार की यात्रा की और उन्होंने राष्ट्रपति श्री यू थेन सेन और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग (एनएलडी) के चेयरपरसन और विपक्ष की नेता सुश्री देव आयूंग सांन सु की के साथ चर्चाएं कीं।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11–13 नवंबर, 2014 को आसियान–भारत शिखर सम्मेलन और नौवें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए म्यांमार की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, वे राष्ट्रपति यू थेन सेन और सुश्री दाव आयुंग सान सु की से मिले।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन(इएएस) के विदेश मंत्रियों की बैठक और दूसरे आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में भाग लेने के लिए 08–11 अगस्त 2014 के दौरान म्यांमार की यात्रा की, जिसके बाद सरकारी द्विपक्षीय यात्राएं हुईं। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण विषयों पर विदेश मंत्री श्री यू व्यूना माउंग ल्वीन से चर्चा की और राष्ट्रपति श्री यू थेन सेन और म्यांमार के संघीय संसद के स्पीकर श्री थुरा यू श्वे मान से मुलाकात की।

भारत और म्यांमार के सीमावर्ती राज्यों के राजनीतिक नेताओं के बीच बातचीत हुई। शीन राज्य के मुख्य मंत्री श्री होंग गाई ने मणिपुर के वार्षिक सेंगाई महोत्सव में भाग लेने के लिए 20–23 नवंबर, 2014 को मणिपुर का दौरा 38 सदस्यीय व्यापार तथा सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के साथ की। सागाइंग क्षेत्र के मुख्य मंत्री श्री यू थेर आये और काचीन राज्य के मुख्य मंत्री श्री यू लाजोन गान साई ने नागालैण्ड के वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव में भाग लेने के लिए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस प्रतिनिधिमंडल ने असम और मेघालय की भी यात्रा की जहां उनकी बातचीत सिविल सोसायटी, शैक्षिक संस्थाओं और व्यापारियों के साथ–साथ असम तथा मेघालय के मुख्य मंत्री के साथ हुई।

उप राष्ट्रपति (1) डॉ. साई माउक खाम 19–23 जनवरी 2015 को 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकारी यात्रा पर भारत आए। उप राष्ट्रपति (1) के साथ केन्द्रीय निर्माण मंत्री श्री यू कयाव ल्वीन, उप विदेश मंत्री श्री यू थान्ट क्याव, उप स्वास्थ्य मंत्री डॉ. वीन मयांन्ट, उप संस्कृति मंत्री सुश्री डाव सांदर खाइन, परिवहन मंत्री शीन राज्य, श्री यू न्यून सांन आउंग और सामाजिक कार्य मंत्री सागाइंग प्रांत डॉ. मयांन्ट थेइन के साथ–साथ अन्य उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी आए। उनकी यात्रा के दौरान, उन्होंने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात की और उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

सांस्थानिक तंत्रों के साथ बातचीत

विदेश सचिव स्तर पर 14वां विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में 23 जुलाई, 2014 को हुआ। गृह सचिव के स्तर पर 19वां राष्ट्रीय स्तर की बैठक यांगुन में 17–19 नवंबर 2014 को हुआ। सेना कमांडर के स्तर की 5वीं क्षेत्रीय सीमा समिति की बैठक लेमाखोंग, मणिपुर में 25 जुलाई, 2014 को हुई।

संयुक्त सचिव और महानिदेशक स्तर पर भारत–म्यांमार सीमा व्यापार समिति की तीसरी बैठक 3 दिसम्बर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों की सीमा पर और सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच जिला प्रशासकों के स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की गई थीं।

भारत और म्यांमार ने सीमा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सुरक्षा सहयोग तथा सूचना के आदान–प्रदान हेतु एक कार्यढ़ांचा की व्यवस्था है।

रक्षा सहयोग

दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में समग्र द्विपक्षीय संबंधों के अनुरूप प्रगति हो रही है। भारत विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के तहत म्यांमार के थल सेना, वायु सेना और नौसेना के रक्षा कर्मिकों को प्रशिक्षण देता है।

दोनों नौसेनाओं के बीच सितंबर, 2014 में नई दिल्ली में तीसरी वार्षिक स्टॉफ वार्ता आयोजित की गई थी जिसमें प्रचालनात्मक

समुद्री प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आगे सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। फरवरी, 2014 में म्यांमार सेना द्वारा खरीदे गए 600 जेनॉन वाहनों के अतिरिक्त 400 और अधिक टाटा जनॉन वाहनों की आपूर्ति के लिए म्यांमार सेना और टाटा मोटर्स के बीच संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

विकास सहायता

भारत ने लगभग 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर तक अपनी विकास सहायता बढ़ाई। इसमें से 750 मिलियन अमरीकी डॉलर रियायती ऋण (एलओसी) के रूप में है जिसका इस्तेमाल रिफायनरियों और सड़क के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं; ट्रक एसेंबली संयंत्र की स्थापना; विद्युत पारेषण लाइनों; कृषि, दूरसंचार और रेल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। शेष राशि संपर्क संबंधी परियोजनाओं; सड़कों; पत्तनों का निर्माण; उत्कृष्टता केन्द्रों (एमआईआईटी, एसीएआरई, राईस बायोपार्क) की स्थापना; जनस्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने ; साझा सांस्कृति विरासत (आनंद मंदिर) के पुनरूद्धार एवं संरक्षण के लिए अनुदान सहायता के रूप में है।

भारत सरकार चिन स्टेट और नागा स्व प्रशासन क्षेत्र (एसएजेड) हेतु सीमा क्षेत्र विकास सहयोग परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत, प्रथम वर्ष की परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं जहां परियोजना लागत का 90 प्रतिशत सीमा मामले मंत्रालय, म्यांमार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

भारत सरकार ने सापेक्षिक तौर पर पिछड़े क्षेत्र में रह रहे समुदायों के पुनर्वास एवं समाधान के लिए म्यांमार सरकार की मदद करने की दृष्टि से राखिन स्टेट में 10 स्कूलों के निर्माण के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर भी प्रदान किया है।

भारत कोलंबो योजना की आईटीईसी, टीसीएस और आईसीसीआर की जीसीएसएस जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। इन स्लॉटों का उपयोग उत्साहवर्धक रहा है और कुछ वर्षों के दौरान इसमें उर्ध्वगामी रूझान देखने को मिली है।कुल 500 स्लाट में से नवम्बर, 2014 तक 370 स्लॉट का इस्तेमाल कर लिया गया है।

आर्थिक और वाणिज्यिक

वर्ष 2014–15 के प्रथम छमाही में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 1.184 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। म्यांमार में 46.718 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल विदेशी निवेश में से भारत का निवेश 382.4 मिलियन तक पहुंच गया।

दूसरे दौर की तटवर्ती तेल एवं गैस ब्लॉक बोली के दौरान, ओएनजीसी विदेश ने दो तटवर्ती तेल एवं गैस ब्लॉक (बी 2 एवं ईपी–3) पर विजय पाई। दूसरे दौर के अपतटीय ब्लॉकों में रिलायंस दो ब्लॉकों (एम 17 और एम 18) पर और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दो ब्लॉकों (वाईईबी और एम 4) पर विजय पाई।

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में प्रतिनिधिक कार्यालय खोलने; भारत और म्यांमार के बीच शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई सीधी नौवहन सेवा बहाली; एअर इंडिया द्वारा यांगोन और दिल्ली के बीच सीधा हवाई संपर्क की शुरूआत; तथा अगस्त 2014 में सेवाओं में भारत–आसियान मुक्त व्यापार एवं निवेश करार संपन्न करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को अनुमति प्रदान करना शामिल है।

भारतीय दूतावास ने यांगोन में 25 सितंबर, 2014 को ततमादा हाल में 'मेक इन इंडिया' का आयोजन किया। संयोग से उसी समय ''भारत–म्यांमार व्यापार और निवेश प्रदर्शनी'' का आयोजन किया गया जिसमें 100 से अधिक भारतीय कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया तथा बी 2बी बैठकें आयोजित की गईं। यांगोन के मुख्यमंत्री श्री यू मिंट स्वे तथा केन्द्रीय वाणिज्य उप मंत्री डॉ. प्वींट सैन इस कार्यक्रम में बहैसियत मुख्य अतिथि तथा सम्माननीय सदस्य के रूप में मौजूद थे। 23–24 जुलाई, 2014 को यांगोन में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स (आईसीसी), कोलकाता द्वारा "इंडिया इन्वेस्ट्रेड 2014" और बायर–सेलर मीट सहित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 55 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। सीआईआई ने 12–15 अक्तूबर, 2014 को मंडले में तीसरे इंटरप्राइजेज इंडिया शो का आयोजन किया। सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल (एसआरटीईपीसी) मुंबई ने 15–16 अक्तूबर, 2014 को यांगोन में भारतीय वस्त्र प्रदर्शनी (इंटेक्सपो) का आयोजन किया।

नेपाल

वर्ष 2014–15 में महत्वपूर्ण आंतरिक राजनीतिक गतिविधियां, अभूतपूर्व उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता और उन्नत आर्थिक व्यापार तथा सुरक्षा सहयोग चलते रहे। दो प्रधानमंत्री स्तरीय दौरों ने द्विपक्षीय संबंधों में नई जान डाल दी। प्रधान मंत्री का 3–4 अगस्त, 2014 को नेपाल के सरकारी दौरे को नेपाल सरकार और वहां की जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति श्री राम बरन यादव और प्रधान मंत्री श्री सुशील कुमार कोइराला से मुलाकात की और नेपाल के सांविधिक एसेंबली सह संसद को संबोधित किया, और ऐसा करने वाले वे पहले बाहरी विशिष्ट व्यक्ति थे। प्रधान मंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक बार फिर 25–27 नवंबर, 2014 को नेपाल की यात्रा की और 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने उन्नत लाईट हेलिकाप्टर ध्रुव को सौंपा और काठमांडू में आपात ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। प्रथम काठमांडू –दिल्ली बस सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधान मंत्री ने लुंबनी में माया देवी मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष का पौधा लगाने की भी घोषणा की। दोनों पक्षों ने सुरक्षा,व्यापार, सीमा अवसंरचना, संपर्क, पर्यटन, तथा

संस्कृति के क्षेत्र में दोनों प्रधानमंत्री स्तरीय दौरों के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों तथा करारों को अंतिम रूप दिया:

03–04 अगस्त 2014:

- पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के विचारार्थ विषय के संबंध में पत्रों का आदान प्रदान
- घेंघा नियंत्रण में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन
- दूरदर्शन एवं नेपाल टेलीवीजन के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन

25–27 नवंबर, 2014

- पनाउती में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना पर समझौता ज्ञापन
- ''पैसेंजर ट्रैफिक के रेग्यूलेशन'' हेतु मोटर व्हिकल्स करार
- पर्यटन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- नेपाल सरकार को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला पर करार
- औषधि की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- 900 गेगावाट अरुण–III जलविद्युत परियोजना के लिए परियोजना विकास करार
- अयोध्या–जनकपुर के बीच ट्विन सिटी व्यवस्था
- काठमांडू–वाराणसी के बीच ट्विन सिटी व्यवस्था
- लुम्बिनी–बोध गया के बीच ट्विन सिटी व्यवस्था

23 वर्षों के अंतराल के बाद 25–27 जुलाई,2015 को संबंधित विदेश मंत्रियों की साझी अध्यक्षता में आयोजित भारत–नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई । संयुक्त आयोग अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर सहमत या कि 1950 की शांति और मित्रता की संधि की समीक्षा, समायोजन तथा उसे अद्यतन करने की आवश्यकता थी जिसके लिए नेपाल एक विशिष्ट प्रस्ताव देगा । नेपाल–भारत संबंधों पर एक विशिष्ट व्यक्ति समूह (ईपीजी–एनआईआर) की स्थापना के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया गया । नेपाल के 9 जिलों में 2700 उथले नलकूपों कें संस्थापना के लिए नेपान–भारत मैत्री सिंचाई परियिजना के लिए भारतीय अनुदान सहायता संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

संयुक्त आयोग के स्वीकृत कार्यवृत के अनुसरण में, संबंधित सर्वेक्षण विभागों के नेतृत्व में भारत–नेपाल सीमा कार्यकारी समूह (बीडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 17–19 सितम्बर, 2014 के दौरान काठमांडू में आयोजित की गई । बीडब्ल्यू जी का यह आदेश है कि वे क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हो गए सीमा स्तंमों का रखरखाव/निर्माण आरंभ में तैयार नक्शों के अनुसार करें । तत्पश्चात भारत–नेपाल सीमा सर्वेक्षण पदाधिकारी समिति (एसओसी) की पहली बैठक 30–31 दिसम्बर, 2014 को देहरादून में आयोजित की गई । वर्ष 2014–15 के लिए फील्ड कार्य कार्यक्रम फरवरी, 2015 में आरंभ करने पर सहमति हुई ।

समीक्षाक्षीन अवधि में विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई । विद्युत व्यापार करार (पीटीए) के नाम से संदर्मित विद्युत ऊर्जा व्यापार, सीमापार पारेषण अंतर संयोजन तथा ग्रिड कनेक्टविटी पर करार पर 21 अक्टूबर, 2014 को काठमांडू में हस्ताक्षर किए गए । जीएमआर द्वारा 900 मेगावाट अपर करनाली के लिए परियोजना विकास करार पर 19 सितम्बर, 2014 को तथा एसजेवीएन द्वारा 900 मेगावाट अरूण–III पर 25 नवम्बर, 2014 को हस्ताक्षर किए गए । अठारहवें सार्क शिखर सम्मेलन की तैयारी में नेपाल सरकार के अनुरोध पर भारत ने 70 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराई । पारेषण लाइनों के उन्नयन का कार्य चल रहा है ।

5600 मेगावाट पंचेश्वर बहुप्रयोगी परियोजना हेतु पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई और उसकी दो बैठकें क्रमशः 22–23 सितम्बर, 2014 को काठमांडू में तथा 18–19 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में हुई ।

खाद्य प्रबंधन और नियंत्रण के लिए दोनों देश निकट सहयोग करते रहे । लालबकिया, बागमती और कमला नदियों के तटबंधों के निर्माण के लिए 2014 में भारत सरकार ने 22.92 करोड रूपये की सहायता प्रदान की। अभीतक वितरित कुल अनुदान सहायता 205 करोड़ रूपये है । नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में सन् कोसी नदी के ऊपरी भाग में भूस्खलन के परिणामस्वरूप दोनों देशों के सामयिक सहयोग से अगस्त, 2014 के आरंभ में बिहार में बाढ़ को टाला जा सका ।

दोनों देशों की सेनाओं के बीच प्रगाढ संबंध बराबर चलते रहे । सुरक्षा मुद्दों पर भारत–नेपाल द्विपक्षीय परामर्शी समूह (बीसीजी) की ग्यारहवीं बैठक 05–07 जुलाई, 2014 के दौरान हुई। सेना प्रमुखों के पारस्परिक दौरों से मिलिट्री संबंध और मजबूत हुए । श्रद्धापूर्ण परम्पराओं के अनुसरण में सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग द्वारा 12–15 नवम्बर, 2014 के दौरान नेपाल का दौरा उनके शुरूआती दौरों में शामिल था जहाँ उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया । सशत्र सीमा वल (एसएसबी) तथा नेपाल की सशस्त्र पुलिसबल के महानिरीक्षक के बीच दूसरी भारत–नेपाल समन्वय बैठक 06 दिसम्बर, 2014 को काठमांडू में हुई।

भारत सरकार नेपाली छात्रों को नेपाल तथा भारत में अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष 3000 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। भारत के

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर नेपाली छात्रों के अल्पावधिक पाठ्यकमों हेतु भारत नेपाल शिक्षा कार्यक्रम के प्रचालन द्वारा इन्हें और भी बढ़ा दिया गया है जैसा कि अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे में घोषणा की गई थी।

पाकिस्तान

भारत शिमला समझौता और लाहौर घोषणा के आधार पर पाकिस्तान के साथ सभी बकाया मुद्दों पर शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के लिए बचनबद्ध है । सार्थक बातचीत के लिए हिंसा और आतंक की शंका से मुक्त वातावरण होना अनिवार्य है ।

पाकिस्तान के साथ शांति और सहयोग के आधार पर संबंध सुदृढ़ करने की भारत की दीर्घावधिक नीति के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को अन्य सार्क नेताओं के साथ, 26 मई, 2014 को नई भारतीय सरकार के सहारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था । तत्पश्चात 27 मई, 2014 को द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को आतंकवाद के संबंध में भारत की चिन्ताओं से भली–भांति अवगत करा दिया गया । इस बात पर बल दिया गया कि पाकिस्तान द्वारा अपनी भूमि तथा अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों को भारत के विरूद्ध चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने की अपनी बचनबद्धता का पालन करना चाहिए । प्रधान मंत्री ने यह उम्मीद जताई कि पाकिस्तान में चल रहे मुम्बई आंतकी हमले के मुकदमें में सभी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ताकि मामले को तेजी से निपटाया तथा इसके लिए जिम्मेदार सभी के विरूद्ध दोष सिद्ध किया जा सके । यह सहमति हुई कि भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव एक दूसरे के सम्पर्क में रहेंगे और इस मामले में आगे बढ़ने के तरीके तलाशेंगे ।

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 27 मई, 2014 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच 25 अगस्त, 2014 को इस्लामाबाद में एक बैठक के आयोजन का कार्यक्रम बनाया गया । तथापि, पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा 18 अगस्त, 2014 को तथा कथित हुर्रियत नेताओं से मिलने के कारण, जिसे भारत के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप और रिश्तों को आगे ले जाने में पाकिस्तान की ईमानदारी पर प्रश्न उठे, बातचीत रद्द कर दी गई ।

संयुक्त राष्ट महासभा को 27 सितम्बर, 2014 के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ गंभीरता से द्विपक्षीय बात–चीत करने की अपनी इच्छा दोहराई और कहा कि इसके लिए आतंकवाद की छाया से मुक्त शांतिपूर्ण माहौल की आवश्यकता है । इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि कि यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह रचनात्मक तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों के लिए उचित वातावरण तैयार करे ।

सितम्बर, 2012 के रोडमैप के भाग के रूप में सहमत व्यापार समानीकरण उपाय अभी तक कार्यन्वित नहीं किए जा सके हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वाघा–अटारी सड़क मार्ग से व्यापार करने का पहला कदम अभी तक नहीं उठाया है ।

पाकिस्तान की जेलों में बंद नागरिक कैदियों तथा मछुआरों से संबंधित मामलों पर नियमित रूप से कार्रवाई होती रहीं । पाकिस्तान के कब्जे में 57 किश्तियों को मुक्त करवाने के मुद्दों पर बातचीत के लिए अधिकारियों और गुजरात से किश्तियों के मालिकों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 18–19 जुलाई, 2014 को पाकिस्तान का दौरा किया। इन किश्तियों को मुक्त करने की औपाचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। महानिदेशक, तटरक्षक तथा महानिदेशक, पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेन्सी के बीच बैठक 18–20 दिसम्बर, 2014 को नई दिल्ली में हुई । इस बैठक में मछुआरों, किश्तियों और दोनों पक्षों के बीच जानकारी के आदान–प्रदान से सबंधित मामलों पर चर्चा की गई । सरकार के प्रयासों के कारण इस वर्ष 30 नवम्बर, 2014 तक पाकिस्तान ने 6 भारतीय नागरिक कैदियों तथा 185 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है ।

श्रीलंका

राष्ट्रपति श्री महिंन्दा राजपक्षे ने 26–27 मई, 2014 को भारत का दौरा किया । राष्ट्रपति श्री महिंन्दा राजपक्षे राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से मिले तथा उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की । प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत श्रीलंका के साथ अपने सबंधों का सम्मान करता है और उन्होंने श्रीलंका सरकार से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय सामंजस्य की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें ।

प्रधानमंत्री ने 27 सितम्बर, 2014 को 69 वें संयुक्त राष्ट महासभा सत्र के अवसर पर तथा 26 नवम्बर, 2014 को काठमांडू में 18 वे सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर भी राष्ट्रपति श्री महन्द्रा राजपक्षे से भेंट की ।

श्रीलंकाई विदेश मंत्री प्रो0 जी0 एल0 पेरिस ने 09–11 जुलाई, 2014 के बीच भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मिले । दोनों पक्षों ने श्रीलंका में राजनैतिक समाधान तथा आर्थिक पुनःनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित मामलों तथा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। व्यापार और निवेश, मछुआरों के मुद्दे, शिक्षा और सांस्कृति के क्षेत्रों में विकास सहायता और सहयोग पर भी इस दृष्टिकोण से चर्चा हुई कि इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाया जा सके ।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल ने 30 नवम्बर– 02 दिसम्बर, 2014 के बीच श्रीलंका का दौरा किया तथा वार्षिक अंतराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन ''गाले डॉयलाग'' में मूल विषयक सम्बोधन दिया । उन्होंने राष्ट्रपति श्री महिन्दा राजपक्षे से भेंट की, विदेशमंत्री प्रो0 जी0एल0 पैरिस, रक्षा सचिव श्री गोटाबाया राजपक्षे तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की ।

रक्षा सचिव श्री गोटाबाया राजपक्षे 19–21 अक्तूबर, 2014 के दौरान

भारत आए। उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री अरूण जेटली से भेट की तथा राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल से मिले ।

रक्षा सचिव श्री आर के0 माथुर ने वार्षिक सुरक्षा बातचीत (एडीडी) के दूसरे चक्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व करने के लिए 09–11 अक्तूबर, 2014 के दौरान श्रीलंका का दौरा किया ।

तमिल नेशनल अलांयस (टीएनए) के एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने, अपने संसदीय समूह के नेता श्री आर0 सम्पंतन के नेतृत्व में 21–24 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली का दौरा किया । प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह से भेंट की। प्रधानमंत्री, ने श्रीलंका में सभी स्टेकहोल्डर्स से अनुरोध किया कि वे 13 संशोधन के आधार पर राजनैतिक समाधान तलाशने की दिशा में भागीदारी और पारस्परिक समायोजन की भावना से रचनात्मक तरीके से कार्य करें ।

भारत ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि संघर्ष के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित (आईडीपी) व्यक्तियों को यथा शीघ्र उनके मूलनिवास स्थान पर भेजा दिया जाए । संघर्ष से प्रभावित लोगों को अपने मकान दुबारा बनाने में सहायता देने तथा उनके लिए रोजगार के अवसरों में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी प्रातों में अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है ।

वर्ष 2008 से भारत सरकार ने श्रीलंका को 2,000 करोड़ रूपये की अनुदान सहायता तथा 7000 करोड़ रूपये की ऋण श्रृंखला की वचनबद्धता की है । भारत की विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आवास, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य व्यवसाय, उद्योग हस्तकला, संस्कृति और खेलों सहित वस्तुतः अर्थव्यवस्था की सभी विकास परियोजनाएं शामिल हैं । भारत सरकार भी संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढाने के साथ–साथ व्यापार और निवेश के अवसर सृजित करने के लिए संगठित प्रयास कर रही है ।

कुछ महत्वपूर्ण चालू परियिजनाओं में 50,000 आवासों का निर्माण (उत्तरी,पूर्वी, मध्य और उवा प्रांत), डिकोया में 150 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण, सामपुर में एक कोयला–विद्युत संयंत्र की स्थापना, जाफना, में दुरईयपा स्टेडियम की स्थापना, जाफना में एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना तथा उत्तरी प्रांत में मुख्य राजमार्ग, रेल पटरियों का पुनः निर्माण शामिल हैं ।

वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने श्रीलंका किलिनोच्ची–पल्लाई सेगमेंन्ट में मार्च, 2014 में तथा पल्लाई–जाफना में अक्तूबर, 2014 में उत्तरी रेलवे लाईन के रेलवे ट्रेक तथा सिग्नल प्रणाली, जिसके परिणामस्वरूप जाफना–कोलम्बो रेल सेवा 'याल देवी' के प्रचालन 24 वर्ष पश्चात आरंभ किए जा सके, अगस्त, 2014 मं एटच्दुवली औद्योगिक एस्टेट (उत्तरी प्रांत) और गंपाहा (पश्चिमी प्रांत) अगस्त, 2014 में, कैंडी (मध्य प्रांत) और वायाम्बा (उत्तर पश्चिमी प्रांत) में भाषा प्रयोगशालाओं सहित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की ।

श्रीलंका में युवाप्रांत के बादुला जिले में भू–स्खलन के शिकार व्यक्तियों को मानवता के आधार आपातकालीन सहायता देने के लिए भारत ने भी 25 लाख रूपये की राहत सामग्री अक्तूबर, 2014 में भिजवाई ।

भारत और श्रीलंका के व्यापार एवं निवेश सबंध मजबूत हैं तथा पिछले दशक में द्विपक्षीय व्यापार संबंध तेजी से बढ़े हैं और अनेक अग्रणी भारतीय निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने श्रीलंका में निवेश किया है और अपनी उपस्थिति दर्शाई है । श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि भारत वैश्विक रूप से श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है । दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़कर 2013–14 में 5.2 बिलियन डालर हो गया है।

श्रीलंका में आने वाले पर्यटकों में भारत एक बड़ा स्रोत बना रहा । वर्ष 2003 से अभी तक 800 मिलियन अमरीकी डालर के संचित निवेश के साथ भारत श्रीलंका में प्रमुख निवेशकों में शामिल है ।

सांस्कृतिक सहयोग के जारी कार्यक्रम (पीसीसी) में कला प्रस्तुतियों, दृश्य कलाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पुरातत्व और संस्कृतिक प्रलेखन, पुरातत्व विज्ञान, हस्तशिल्प, खेल और युवा मामलों, प्रकाशनों और व्यावसायिक आदान–प्रदान तथा मास–मीडिया जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग का स्तर बढ़ाने पर बल दिया गया है । कोलंम्बो स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय संगीत, नृत्य, हिन्दी और योगा में कक्षाओं के माध्यम से सक्रियता पूर्वक भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर रहा है । दोनों देशों से सांस्कृतिक मॅडलियां प्रतिवर्ष एक–दूसरे देश में जाती हैं ।

श्रीलंका के एक महान बौद्धवादी तथा समाज सुधारक श्री अंगारिका धर्मपाला के बारे में राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 25 अक्तूबर, 2014 को राष्ट्रपति भवन में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया ।

भारत और श्रीलेंका के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा है। भारत अब योग्य श्रीलंकाई छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के 790 स्थान प्रदान करता है जिससे न केवल नियमित स्नातकपूर्व छात्रों को फायदा हो रहा है बल्कि उच्चशोध के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्कीम तथा कोलम्बो योजना के अंतर्गत भारत प्रतिवर्ष तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनेक श्रेणियों में श्रीलंकाई नागरिकों को अल्पावधिक और मध्यम अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में लगभग 200 स्थान प्रदान करता है ।

■■

प्रधान मंत्री 11 नवंबर, 2014 को म्यांमार के राष्ट्रपति, श्री थेन सेन से मुलाकात करते हुए।

प्रधान मंत्री 12 नवंबर, 2014 को नाय पेई ताउ, म्यांमार में 12वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष तथा महासचिव, सुश्री आँग सान सू की से मुलाकात करते हुए।

प्रधान मंत्री और नेपाल के प्रधान मंत्री, श्री सुशील कोइराला भारत की सहायता से निर्मित आपात अभिघात केन्द्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन करते हुए।

प्रधान मंत्री नेपाल सरकार को ध्रुव उन्नत लाइट हैलीकॉप्टर सौंपते हुए।

प्रधान मंत्री 27 नवंबर, 2014 को 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री, श्री नवाज शरीफ के साथ।

विदेश मंत्री 16 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्री लंका के राष्ट्रपति मैथीपाल सिरिसेना वे वार्ता करती हुई

2 दक्षिण–पूर्व एशिया और प्रशांत

आस्ट्रेलिया

वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री स्तर पर दौरों के आदान–प्रदान से भारत के आस्ट्रेलिया के साथ संबंध एक नए शिखर तक पहुंच गए। दोनों देशों के बीच निश्चित परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग बढ़ाकर राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समझौतों के द्वारा संबंध बढ़ाने में दिलचस्पी बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से हो रही वृद्धि तथा संसाधनों, प्रौद्योगिकी, कौशल तथा अन्य क्षेत्रों में निकट सहयोग को संभावनाओं को भी महसूस किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जी–20 नेताओं के ब्रिसबेन में शिखर सम्मेलन तथा द्विपक्षीय दौरे के लिए 14–18 नवंबर, 2014 के दौरान आस्ट्रेलिया का दौरा किया। उन्होंने प्रधान मंत्री श्री टोनी एबट के साथ वार्ता की तथा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया (स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार किसी भारतीय प्रधान मंत्री ने ऐसा किया) उन्होंने सीनेट के अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा के सभापति तथा विपक्ष के नेता से भी भेंट की। वे राजनैतिक नेताओं, व्यवसायियों, वैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के साथ–साथ ब्रिसबेन, सिडनी और मेलबोर्न में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिले। इस दौरे के दौरान, अनेक करारों तथा समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर करार, सामाजिक सुरक्षा पर करार तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग तथा नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक के लिए अनेक समझौता ज्ञापन शामिल थे। सुरक्षा सहयोग पर एक ढांचा तैयार करने पर सहमति हुई। अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में सीईओ मंच को पुनर्जीवित करना, मेक इन इंडिया शो, 2015 की घोषणा तथा 2015 में सिडनी में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का आरंभ किया जाना शामिल थे। यह दौरा निकट द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय के लिए मील का पत्थर था।

प्रधान मंत्री श्री टोनी एबट ने नई सरकार के पहले सरकारी मेहमान के रुप में 4–5 सितंबर, 2014 को भारत का दौरा किया। प्रधान मंत्री ने उनके साथ बातचीत की जो हमारे द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य क्षेत्रों, संसाधनों, बिजली, शिक्षा, कौशल और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर केंद्रित थी। नागरिक परमाणु सहयोग पर करार, खेलों में सहयोग पर समझैता ज्ञापन, जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के नवीकरण तथा तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति से भेंट की तथा मुंबई का दौरा किया, जहां वे महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले। आस्ट्रेलियाई विद्यार्थियों के भारत भ्रमण के लिए नई कोलंबो योजना तथा रणनीतिक अनुसंधान कोष के विस्तार के लिए नई पहलें आरंभ की गईं। नागरिक परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर से भारत में आस्ट्रेलियाई यूरेनियम की बिक्री में सहायता मिलेगी, जिससे हमारी बढ़ती बिजली आवश्यकताओं के समाधान में सहायता मिलेगी। एक सुदृढ़ आर्थिक भागीदारी के निर्माण को वरीयता दी गई।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने सितंबर, 2014 में केर्न्स में आयोजित जी–20 व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आस्ट्रेलियाई आप्रवासन मंत्री श्रीस्कॉट मारीसन ने जुलाई, 2014 में भारत का दौरा किया, उद्योग मंत्री श्री इयान मैकफार्लेन नवंबर, 2014 में भारत आए तथा व्यापार मंत्री एंड्रयू रोब ने 10 से 16 जनवरी, 2015 के दौरान वाइब्रेंट गुजरात 2015 में भाग लेने के लिए गांधीनगर तथा तत्पश्चात दिल्ली, जयपुर और मुंबई का दौरा किया। आस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री श्री केविन एंड्रूज ने द्विपक्षीय विचार–विमर्श और रक्षा–सहयोग के विस्तार हेतु फरवरी, 2015 में भारत का दौरा किया।

सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा और आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री श्री पीटर वर्घीस के नेतृत्व में 21 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली में भारत–आस्ट्रेलियाई वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत हुई। नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर मई, जुलाई और सितंबर, 2014 में वार्ताओं के अनेक दौर हुए, जिसके परिणामस्वरुप सितंबर, 2014 में करार पर हस्ताक्षर किए गए तथा भारत को यूरेनियम की बिक्री शुरु करने के लिए अक्तूबर, 2014 में और आगे बातचीत की गयी। आतंकवादरोधी संयुक्त कार्यदल की 04 अगस्त, 2014 को केनबरा में बैठक हुई। कोंसुलर, पासपोर्ट और वीजा मामलों पर भारत–आस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यसमूह की चौथी बैठक अगस्त, 2014 में केनबरा में आयोजित की गयी। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर वार्ता का छठा दौर 19 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

कार्यात्मक क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यटन, जल संसाधन और कृषि में विचार–विमर्श और प्रौद्योगिकी सहयोग से द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार किया गया।

भारत और आस्ट्रेलिया ने आसियान, ए.आर.एफ, ई.ए.एस. और संबद्ध संस्थाओं की परिधि में क्षेत्रीय सहयोग का संवर्धन किया। आस्ट्रेलिया ने अक्तूबर, 2014 में पर्थ में आईओआरए के लिए मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया। आस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर पर भारत–आस्ट्रेलिया–इंडोनेशिया त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी भी की।

सीनेटर सुश्री लीसा सिंह और सुश्री माला मेहता को गुजरात में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 2015 पर प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया।

ब्रुनेई, दारूसलाम

वर्ष के दौरान ब्रुनेई दारूसलाम के साथ द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण बने रहे और आसियान में ब्रुनेई ने भारत के लिए समन्वयक देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नवंबर, 2014 में नाए पई ताव में आयोजित पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया से भेंट की तथा द्विपक्षीय विचार–विमर्श और क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर बातचीत की।

ब्रुनेई में 10–11 सितंबर, 2014 को आयोजित एशिया–प्रशांत दूर–समुदाय आईसीटी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए संचार और दूरसंचार तथा विधि और न्यायमंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्रुनेई का दौरा किया।

नए उच्चायुक्त ने 25 फरवरी, 2014 को महामहिम सुल्तान को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। महामहिम ने चिकित्सकों, शिक्षकों आदि के रुप में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय व्यावसायियों द्वारा देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए उनकी प्रशंसा की।

म्यांमा ने नाए पई ताव में आयोजित होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए ब्रुनेई के श्री दातो एरिवान के साथ 16वीं आसियान–भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की संयुक्त अध्यक्षता के लिए इंडोनेशिया और आसियान में भारत के राजदूत श्री गुरजीत सिंह ने 23–24 जून, 2014 को ब्रुनेई का दौरा किया। समुद्री सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर टेबल टाइम एक्सरसाइज पर विशेषज्ञ कार्य समूह की 9वीं एडम प्लस बैठक में भाग लेने के लिए कमांडर शशांक शर्मा ने 28–30 अक्तूबर, 2014 को ब्रुनेई का दौरा किया। नई दिल्ली में 6–7 मार्च, 2014 को आयोजित दिल्ली–डायलाग–VI में ब्रुनेई का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मामलों और व्यापार मंत्रालय के स्थायी सचिव (आसियान) श्री दातो एरिवान ने भारत का दौरा किया।

भारतीय नौसेना आपूर्ति जहाज, आईएनएस शक्ति ने 8–11 अगस्त, 2014 के दौरान ब्रुनेई का सौहार्दपूर्ण दौरा किया और इसी अवसर का महत्व बढ़ाने के लिए वाइस एडमिरल सतीश सोनी, एफओसी ईस्टर्न कमांड ने भी ब्रुनेई का दौरा किया। रायल ब्रुनेई के नेवी जहाज केपी 80 दाश्रताकवा ने अगस्त, 2014 मे भारत (मुंबई) का दौरा किया।

आसियान भारत मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम 2012–14 के अंतर्गत आसियान देशो में संपादको/वरिष्ठ पत्रकारो द्वारा मेल जोल बढ़ाने संबंधी दौरे के भाग के रुप में दिल्ली डॉयलाग VI को कवर करने के लिए ब्रुनेई से दो पत्रकारों ने 05–11 मार्च, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। आसियान भारत छात्र विचार–विमर्श कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रुनेई से 25 विद्यार्थियों ने 9–18 नवंबर, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया तथा वे आगरा, मुंबई, हैदराबाद और नई दिल्ली के शहरों में गए।

ब्रुनेई शैल पेट्रोलियम के साथ तेल की बिक्री पर एक करार पर हस्ताक्षर के लिए भारत की सरकारी क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 24–25 मई, 2014 को ब्रुनेई का दौरान किया। ब्रुनेई के डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य चिकित्सकों कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की संभावना पर बातचीत तथा रिपास हास्पिटल में अंग प्रत्यारोपण इकाई के विकास के लिए अपोलो अस्पताल के एक सीनियर वाइस प्रेसीडेंट ने 19 नवंबर, 2014 को ब्रुनेई का दौरा किया।

कंबोडिया

कंबोडिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण बने रहे और इनका प्रगाढ़ होना जारी रहा।

जल संसाधन विकास, विद्युत पारेषण लाइन, मंदिरों के पुनरुद्धार तथा संरक्षण तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में भारत ने कंबोडिया को सहायता देना जारी रखा। कंबोडिया में भारतीय अनुदान से लगभग 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल अनुमानित लागत से केमोंग स्पीयू प्रोविन्स के भूमिगत जल संसाधनों के अध्ययन तथा सीम–रीप रिवर बेसिन हेतु दो नए परियोजनाओं को 2014 में शुरु किया गया। केमोंग प्रांत में भारत कम्बोडिया फ्रेन्डशिप स्कूल का पुनविकास कार्य लगभग पूरा हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 2003 में शुरु किए गए संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य की, जो अभी चल रहा है, उच्च गुणवत्ता युक्त कार्य के रुप में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने सराहना की है।

भारतीय थल सेना से प्रतिनियुक्ति पर गए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा शांति बनाए रखने तथा डीमाईनींग मॉडयूल्स को समाप्त करने में रायल कंबोडियन आर्मड फोर्सेस के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैप्सूल के संचालन हेतु भारत–कंबोडिया रक्षा–सहयोग जारी रहा। कंबोडियाई रक्षा सेवाओं के सदस्य स्कालरशिप के अंतर्गत भारतीय रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण भी प्राप्त करते रहे।

भारत ने यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की बैठक का संकल्प रखा और फिर दिसंबर, 2014 मे प्रीह विहार के ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन समिति (आईसीसी) की संयुक्त अध्यक्षता की। विश्व धरोहर स्थल के रुप में सूचीबद्ध एक प्राचीन शिव मंदिर प्रीह विहार के प्रबंधन, संरक्षण और पुनरुद्धार से संबंधित मुद्दों पर आईसीसी ने चर्चा की।

सीमरीप में एमजीसी एशियन ट्रेडिशन टेक्सटाइल म्यूजियम के

साफ्ट लांच की अध्यक्षता 07 अप्रैल, 2014 को कंबोडियाई उप प्रधान मंत्री तथा मंत्रिपरिषद के प्रभारी मंत्री श्री सोक एम तथा सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा ने की। म्यूजियम के शासी निकाय की दूसरी बैठक सितंबर, 2014 मे सीमरीप में आयोजित की गई, जिसमें एमजीसी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

"बौद्धमहोत्सव महोत्सव" तथा रामायण उत्सव से युक्त अत्यधिक सफल भारत महोत्सव का आयोजन फरवरी, 2014 में नोमपेन्ह तथा सीमरीप में किया गया। वर्ष के दौरान नोमपेन्ह में आयोजित एक भारतीय खान–पान समारोह भारतीय सिनेमा सप्ताह तथा महिला द्वारा 'महिला पेंटिंग' प्रदर्शनी की भूरि भूरि प्रशंसा हुई।

वर्ष के दौरान भारत तथा कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में संवर्धन हुआ। वर्ष के दौरान कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउसिंल ऑफ इंडिया (टेक्सप्रोसिल) से व्यापार प्रतिनिधिमंडल, कंबोडिया इंटरनेशनल मशीनरी इंडस्ट्रियल फेयर के लिए भारत से प्रतिनिधियों, स्टोनकटिंग उद्योग के प्रतिनिधियों, कैम्बिल्ड 2014 एंड कैम्इनर्जी एक्जीबीशन के लए भारत की 70 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कंबोडिया का दौरा किया। टेक्सेशन सेमीनार मेक इन इंडिया, आईसीटी सेमिनार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन दूतावास द्वारा किया गया।

फिजी

इस क्षेत्र में प्रधान मंत्री के दौरे से भारत–फिजी द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अधिक विस्तृत और विविधीकृत वार्ताओं, विकास सहभागिता, तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी), शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान से हमारे द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ रहे।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2014 को फिजी का दौरा किया। उन्होंने प्रधान मंत्री श्री वोक बेनीमाराम से बातचीत की, नव निर्वाचित संसद को संबोधित किया तथा फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी के एक नागरिक समारोह में वक्तव्य दिया। एलबर्ट पार्क में परपरांगत तरीके से एक समारोह में उनका स्वागत किया गया तथा उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया गया, जहां वे राष्ट्रपति श्री रेहु एपेली नेलाटिकाउ से भी मिले। इस दौरान जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, उनमें सह–जनित्रण संयंत्र के लिए ऋण श्रृंखला, राजनयिकों के प्रशिक्षण हेतु सहयोग तथा दोनों राजधानियों में अपने अपने राजनयिकों के लिए भूमि के निर्धारण पर समझौता ज्ञापन शामिल थे। अन्य जिन पहलों पर घोषणाएं की गई, उनमें फिजीयन संसद के पुस्तकालय के निर्माण हेतु सहायता, फिजी नागरिकों के आगमन पर वीजा, छोटे कारोबार तथा ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का कोष, आईटीईसी (सिविल और रक्षा) तथा स्कालरशिप स्थानों पर फिजी की संख्या बढ़ाकर 125 करना, चावल, नारियल तथा डेयरी उद्योग के विकास में सहयोग बढ़ाना, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल फिजी के संवर्धन में सहायता, सौर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, गर्वनेंस, आर्थिक विकास, सरंक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक अपराधों में इसके प्रयोग सहित–सहयोग बढ़ाना और भारतीय फिल्म उद्योग को फिजी में शूटिंग करने के लिए उत्साहित करना आदि शामिल हैं।

दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग हेतु पहले मंच का आयोजन किया जिसमें 14 प्रशांत द्वीपों के नेताओं तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने तथा इस क्षेत्र के विकास हेतु भारत की वचनबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहलुओं की घोषणा की गई।

17 सितंबर, 2014 को निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें श्री वोर्क बेनीमारामा के नेतृत्व में फिजी फर्स्ट पार्टी ने 50 में से 32 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। भारत ने अमिट स्याही की आपूर्ति तथा कुछ वाहन भेंट देकर निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग दिया। ऑस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया तथा अनेक अन्य देशों की सहभागिता वाले मल्टीलेट्रल ऑब्ज़र्वर ग्रुप (एम ओ जी) के सह–अध्यक्ष के रूप में भी भारत ने सहयोग किया।

उच्चायुक्त श्री ए. गीतेश शर्मा ने 28 अगस्त, 2014 को फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति रेटु एपेली नैलाटिकाउ को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किये।

अटार्नी जनरल तथा व्यापार मंत्री श्री एज़ाज सईद कयूम ने मई 2014 में भारत का दौरा किया। फिजी में ऑनकालोजिकल तथा हृदय संबंधी इकाइयों की स्थापना हेतु बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री नील शर्मा ने जून 2014 में भारत का दौरा किया। कृषि पर स्थायी सचिव श्री रोयोट लिगैरी ने अगस्त, 2014 में भारत का दौरा किया।

विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (परियोजना) श्री राजेश के. सचदेवा के नेतृत्व में एक संपत्ति दल ने 28 – 29 अप्रैल, 2014 को सुवा का दौरा किया तथा 23 – 24 जून, 2014 को पिक–विकास साझीदारों की नाडी में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने फिजी का दौरा किया।

फिजी से भारत मूल के सात युवकों ने 28वें भारत को जानो (के. आई.पी) कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिजी के दो पत्रकारो श्री रोसी तमानी दोवीवेराता तथा श्री अविनेश गोपा ने जुलाई, 2014 में एक्स पी प्रभाग के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया। भारत पर्यटन कार्यालय, सिडनी ने अगस्त, 2014 में हिविस्कस समारोह में भाग लिया।

भारत ने फिजी में स्वास्थ्य तथा शिक्षा कार्यक्रमों एवं सामुदायिक परियोजनाओं के लिए अनुदान दिया। इसके अतिरिक्त भारत ने जुलाई, 2005 में चीनी मिलों के उन्नयन हेतु 50.4 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला तथा भारत से मशीनों के आयात के लिए 5.38 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला भी प्रदान की।

वैज्ञानिक विचारों तथा तकनीकी मानव शक्ति आदान–प्रदान के लिए फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी (एफ एन यू) के वाइस चांसलर डॉ. गणेश चंद्र ने अप्रैल, 2014 में आईआईटी कानपुर के साथ एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। सहयाद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल इण्डिया के विशेषज्ञों ने अप्रैल, अगस्त और अक्तूबर, 2014 में फिजी का दौरा किया तथा अस्थिशल्य क्रिया एवं गुर्दे के रोगों के इलाज़ किये। फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी (एफ एन यू) में भारत के अपोलो अस्पताल समूह तथा सुवा प्राइवेट अस्पताल एवं अन्यों की सहभागिता से 27 जुलाई, 2014 को फिजी सभी के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा संगोष्ठी के आयोजन की घोषणा की।

इंडोनेशिया

वर्ष 2014 में द्विपक्षीय संबंधों में अनवरतता तथा विकास की प्रवृत्ति बनी रही। इंडोनेशिया में संसदीय तथा राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2014 में संपन्न हुए तथा श्री जोको विडोडो के नेतृत्व में नई सरकार ने अक्तूबर, 2014 में कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी तथा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री जोको बिडोडो को बधाई संदेश भेजे।

पूर्वी एशियाई, शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नाए पई ताव में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो से मिले और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। इससे पूर्व नाए पई ताव में 09 अगस्त, 2014 का आयोजित 47वी आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री डॉ. मार्टी नाटाले– गावा से भेंट की।

मेघालय विधान सभा के उप सभापति श्री सानबोर शुल्लई ने 8–9 अगस्त, 2014 को इंडोनेशिया का दौरा किया और वे देवान पर्वाकिलान डेरा (डीपीडी) (संसद की क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभा) के अध्यक्ष श्री ला ओडे इडा से मिले। डीपीडी के सभापति श्री एच. इमरान गुसमान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 22–24 अगस्त, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया तथा वे लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन से मिले।

द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ना जारी रहा। एयर चीफ मार्शल अरुप राह, स्टॉफ कमेटी के चेयरमैन चीफ (सीओएससी) व भारतीय वायु सेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने 23–26 नवम्बर 2014 के दौरान इंडोनेशिया का दौरा किया। प्रचालन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में साझे हितों के मुद्दों पर तीसरी सेना स्टाफ वार्ता में चर्चा हुई और तथा दोनों सशस्त्र सेनाओं के प्रतिभागियों ने जकार्ता में 2014 जेआईडीडी में तथा पोर्ट ब्लेयर में एचएडीआर जैसे महत्वपूर्ण सेमिनारों में हिस्सा लिया। हिंदी महासागर में दोनों जलसेनाओं द्वारा दो समन्वित गश्तें की गई तथा बगावतरोधी और आतंकवादरोधी कार्यवाइयों पर विशेष सुरक्षा बल के साथ तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'गरुण शक्ति' किया गया। भारतीय नेवी और तटरक्षकों के जहाजों के आवागमन तथा इंडोनेशियाई नेवल जहाजों के अपने अपने बंदरगाहों पर आवागमन से व्यावसायिक कार्मिकों का विचार–विमर्श जारी रहा, जबकि नीति की सहक्रिया और साझा जानकारी तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने एक–दूसरे के देश में दौरे किए। इंडोनेशियाई जल सेना ने एक जहाज और एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रतिनिधित्व के साथ मिलान 2014 में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया में बहुपक्षीय नेवल अभ्यास कोमोडो के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

रक्षा मंत्रालय से इंडोनेशिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में आयोजित रक्षा एक्सपो मे भाग लिया, जबकि प्रमुख भारतीय रक्षा सरकारी क्षेत्र उद्यमों डीआरडीओ तथा ब्रहमोस सहित भारतीय रक्षा उद्योग से जुड़े 40 प्रतिभागियों ने जकार्ता मे भारत रक्षा एक्सपो 2014 में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। दोनो अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि से, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़े है। व्यापार और वाणिजिक संबंधो को संवर्धित करने के लिए भारतीय पक्ष ने विभिन्न आउट रिच क्रियाकलापों को आयोजित किया, 22 अप्रैल 2014 को जकार्ता में भारत व्यापार मंच (आई बी एफ) और कादिन इंडोनेशिया (इंडोनेशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स) के बीच संपर्क को मदद प्रदान किया। कार्यक्रम में एक विशेष प्रकाशन ''दी इंडिया– इंडोनेशिया ईकॉनोमिक इणगेजमेंटः चैलैन्जेज एण्ड दी वे फारवार्ड'' को आरंभ किया।

जकार्ता में रेल क्षेत्र में सहयोग पर एक सेमिनार 11 सितंबर, 2014 को आयोजित की गयी, जिसमें राइट्स से एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। प्रधान मंत्री की मेक इन इंडिया मुहिम भारत में आरंभ किए जाने के साथ ही 25 सितंबर, 2014 को जकार्ता में भी आरंभ की गयी। इंडोनेशिया के लोक निर्माण मंत्रालय और वापकोस के सहयोग से जलविद्युत हेतु जल संसाधन अवसंरचना का उपयोग विषय पर एक कार्यशाला 01 अक्तूबर, 2014 को आयोजित की गयी। योगियाकार्ता में आईटी प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक 27 अक्तूबर, 2014 को आयोजित की गयी। भारत से कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों ने भी दौरे किए जिनमें इंडियन टैक्सटाइल असेसरीज एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (आईटीएएमएए) का दौरा भी शामिल था, जिसमें 23–26 अप्रैल, 2014 के दौरान आयोजित 12वीं इंडोनेशिया इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड गारमेंट मशीनरी एंड असेसरीज प्रदर्शनी (इंडो इंटर टेक्स, 2014) में हिस्सा लिया। दि शुगर टेक्सनालोसिस्टम आफ इंडिया ने अपने मिशन के सहयोग से 21–22 मई, 2014 को सुराबाया में इंडिया शुगर एक्सपो का आयोजन किया। दीर्घावधिक कोयला आपूर्ति की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एनटीपीसी के एक तीन सदस्यीय दल ने 19–22 अगस्त, 2014 के दौरान इंडोनेशिया का दौरा किया। इंजीनियर्स इंडिया लि. के आमंत्रण पर इंडोनेशिया की सरकारी क्षेत्र की तेल तथा गैस कंपनी परतामिना के एक उच्चस्तरीय दल ने 26–28 अगस्त, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। सरकारी क्षेत्र के भारतीय उपक्रमों ने 5–8 नवंबर, 2014 के दौरान जकार्ता में आयोजित इंडोडिफेंस 2014 एक्सपो में भाग लिया।

जकार्ता और बाली में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की गतिविधियों

तथा भारतीय डायस्पोरा के संगठनों के माध्यम से सांस्कृतिक सहयोग का संवर्धन हुआ। नए प्रयासों, विशेषकर फिल्मों की शूटिंग से दोनों देशों के लोगों में निकटतम संबंधों को महसूस किया गया।

लाओपीडीआर

समीक्षाधीन अवधि में लाओपीडीआर के साथ भारत के संबंध धीरे–धीरे बढ़ते रहे। हमारा सहयोग मुख्य रूप से जल–प्रबंधन और सिंचाई विद्युत पारेषण, नव संसाधनों में क्षमता निर्माण, धरोहर स्मारकों के पुनरुद्धार में सांस्कृतिक सहयोग तथा स्कालरशिप के अधीन छात्रों और तकनीकी कार्मिकों के आदान–प्रदान पर केंद्रित था।

भारतीय पक्ष की ओर से श्री राजन गोहन और श्री गणेश सिंह सहित संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14–20 सितंबर, 2014 के दौरान विएनटिएन में आयोजित आसियान इंटर पार्लियामेंटरी असेंबली की 35वीं जनरल असेंबली में भाग लिया। उद्योग और वाणिज्य के लाओ वाइस मिनिस्टर श्री सोमचित इंथमिथ नई दिल्ली में 11–12 दिसंबर, 2014 को आयोजित दूसरी भारत सीएलएमवी बिजनेस कॉल्क्लेव में भाग लेने हेतु भारत आए।

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना पर विचार–विमर्श हेतु 15–16 जनवरी, 2015 को आयाजित दूसरी चीन निगोशिएटर्स बैठक में भाग लेने के लिए वित्त के लाओ वाइस मिनिस्टर श्री थिपहाकोन ने मुंबई का दौरा किया।

सांस्कृतिक संबंधों का जहां तक संबंध है, भारत महोत्सव के पश्चात विशेषकर बौद्ध रामायण महोत्सव तथा योगा आदि कार्यक्रमों के आदान–प्रदान से इन क्षेत्रों में योगदान मिला।

मलेशिया

मैत्रीपूर्ण तथा स्नेहपूर्ण रिश्तों के कारण मलेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लगातार प्रगाढ़ता और विस्तार मिला।

नाए पई ताव, म्यांमा में 12 नवंबर, 2014 को आयोजित पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधान मंत्री श्री नजीब रजाकोन से मुलाकात की तथा पारस्परिक द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहभागिता को प्रगाढ करने पर केंद्रित थी। उनकी बातचीत आर्थिक और व्यापार संबंधों तथा प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आवास पर सहयोग को सुदृढ़ करने पर केंद्रित थी।

मलेशिया के प्रधान मंत्री के विभाग में मंत्री श्री दातो श्री इदरीस जाला पेमांदु के सीईओ ने 1 अगस्त, 2014 को भारत का दौरा किया तथा प्रधान मंत्री से भेंट की। प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्री तथा मलेशियाई भारतीय कांग्रेस (एमआईसी) के अध्यक्ष श्री दातुक सेरी जी पलानीवेल ने 7–9 सितंबर, 2014 के बीच भारत का दौरा किया तथा प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और पर्यावरण एवं वन मंत्री से मुलाकात की। मलेशिया के उप शिक्षा मंत्री श्री पी. कमलनाथ ने भारत का दौरा किया तथा 9 सितंबर, 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्री से भेंट की।

भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन ने एक सेमिनार में भाग लेने के लिए 11–15 अगस्त, 2014 के दौरान मलेशिया का दौरा किया।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री माधव लाल ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के अध्यक्ष सह–प्रबंधक निदेशक श्री रवींद्र नाथ तथा महा प्रबंधक श्री मनोज लाल के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बीच, विशेषकर इलेक्ट्रानिक्स, हल्की इंजीनियरी मशीनों, वस्त्र, लकड़ी तथा लकड़ी उत्पादों और रसायन क्षेत्रों के उपक्रमों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए 5–7 नवंबर, 2014 के बीच मलेशिया का दौरा किया।

वैश्विक बंगाल व्यापार शिखर सम्मेलन–बंगाल लीड्स 2015 की तैयारियों के संबंध में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण गुप्ता ने 13–15 अक्तूबर, 2014 के दौरान कुआलालम्पुर का दौरा किया। इस शिखर सम्मेलन में 6–8 जनवरी, 2015 के दौरान कोलकाता में एक बड़े मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया।

रक्षा सहयोग कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण से रक्षा सहयोग में बढ़ोत्तरी हो रही है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक ने अगस्त, 2014 में मलेशिया का दौरा किया तथा भारत और मलेशिया के तटरक्षकों के बीच संस्थागत संपर्क पर चर्चा की। अप्रैल, 2014 में रक्षा–प्रदर्शनी (डीएएए–2014) के दौरान भारत ने आईडीएस के प्रमुख के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। रणनीतिक प्रबंधन दौरों के संबंध में दो अध्ययन दलों (एनडीसी–54 तथा एचडीएमसी–10) ने मलेशिया का दौरा किया। पांचवी मलेशिया–भारत सेना से सेना वार्ता नवंबर, 2014 में हुई।

मई, 2014 में एक भारतीय नेवी सबमेरीन प्रतिनिधिमंडल ने सेपानगर में मलेशियाई सबमेरीन बेस का दौरा किया। वायुसेनाओं ने एमयू 30 फाइटर एयरक्रू एवसचेंज, सी–130 परिवहन प्रतिनिधिमंडल एक्सचेंज तथा पीसी–7 परिवहन प्रतिनिधिमंडल एक्सचेंज सहित अनेक प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान किया। आईएनएस रणविजय अगस्त, 2014 में पहली बार पूर्वी मलेशिया के सेपानगर बंदरगाह पर पहुंचा।

श्री एन रविशंकर, सचिव, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग और दातुक डॉ. शरीफा जराह सैयद अहमद, लोकसेवा मलेशिया के उप महानिदेशक के नेतृत्व में 26–27 अगस्त, 2014 को नई दिलली में लोक प्रशासन और गवर्नेंस पर दूसरे संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक हुई।

न्यूजीलैंड

आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वयन से न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंध धीरे–धीरे आगे बढ़ते रहे।

न्यूजीलैंड में सितंबर, 2014 में आम चुनाव हुए, जिसके पश्चात

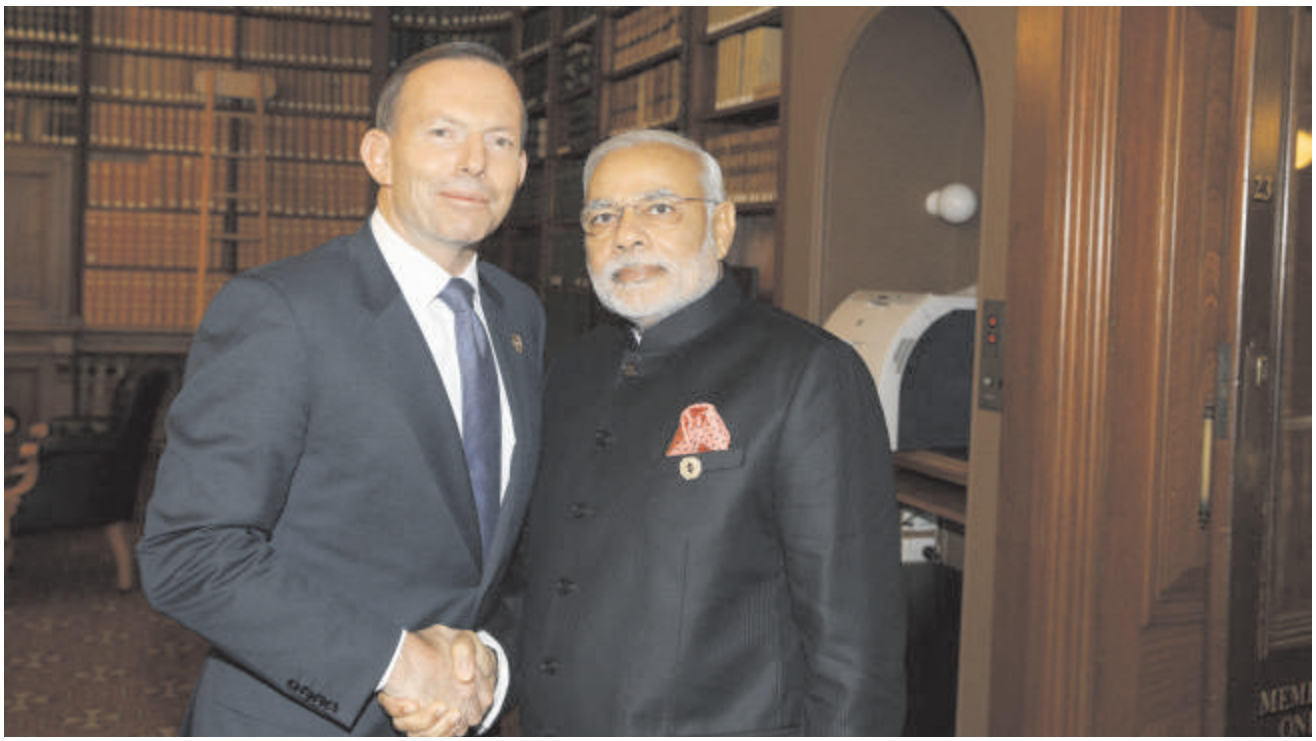

ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री, श्री टोनी एबोर्ट ने ब्रिसबेन में जी–20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए।

19 नवंबर, 2014 को अपने फिजी दौरे के दौरान प्रधान मंत्री सुवा में फिजी के प्रधान मंत्री, श्री जोसिया वी. बेनीमाराम से मिलते हुए।

प्रधान मंत्री 19 नवंबर, 2014 को सुवा में प्रशांत द्वीप के नेताओं से मिलते हुए।

नाय पेई ताउ, म्यांमार में आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर 12 नवंबर, 2014 को प्रधान मंत्री मलेशिया के प्रधान मंत्री श्री नजीब रजाक से मिलते हुए।

प्रधान मंत्री श्री जॉन की के नेतृत्व मे राष्ट्रीय सरकार सत्ता में लौटी।

न्यूजीलैंड के कुटीर उद्योग और कृषि मंत्री श्री नाथन गाई और आप्रवासन मंत्री श्री माइकल वुडहाउस के नेतृत्व में एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल ने 4–7 नवंबर, 2014 के बीच भारत का दौरा किया तथा व्यापार और उद्यम के संवर्धन और क्रिकेट विश्व कप 2015 के न्यूजीलैंड द्वारा सह–आयोजन की रूपरेखा पर कृषि मंत्री से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल में क्रिकेट से जुड़े लोग तथा खाद्य और पेय पदार्थों, कृषि व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और खेलों सहित अनेक क्षेत्रों से जुड़ी 15 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।

'सरकारों को वैज्ञानिक सलाह' पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, डॉ. आर चिदंबरम ने 28–29 अगस्त, 2014 को आकलैंड का दौरा किया और वे न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सर पीटर ग्लुकमेन से मिले।

प्रमुख व्यवसायियों के लिए वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए त्रिपुरा विधान सभा के अध्यक्ष श्री रामेंद्र चंद्र देबनाथ ने 15–18 अक्तूबर, 2014 के दौरान आकलैंड का दौरा किया तथा भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के संसद–सदस्यों तथा डायस्पोरा के सदस्यों के साथ विचार–विमर्श किया।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संगरोध बैठक 28 मई, 2014 को नई दिल्ली में हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवीं वार्षिक द्विपक्षीय आर्थिक बातचीत 13 जून, 2014 को नई दिल्ली में हुई।

दीवाली का त्यौहार मनाने के लिए न्यूजीलैंड की संसद ने 28 अक्तूबर, 2014 को एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रधान मंत्री जॉन की ने भाग लिया।

'मेक इन इंडिया' प्रयास के अनुरूप न्यूजीलैंड में 25 सितंबर, 2014 को उच्चायोग ने एक प्रमुख 'भारत व्यवसाय संगोष्ठी' का आयोजन किया। उद्यमियों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं, सीई ओज, अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों तथा न्यूजीलैंड के वरिष्ठ प्रतिनिधियों एवं भारत–न्यूजीलैंड व्यापारिक समुदायों के कुल मिलाकर लगभग 150 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा इस अवसर पर भारत के प्रधान मंत्री के संबोधन के लाइव वैबकास्ट को भी दिखाया गया।

न्यूजीलैंड के संसद सदस्य श्री कंवलजीत सिंह बख्शी को, डायस्पोरा मामलों में उनके योगदान के लिए गांधीनगर, गुजरात में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, 2015 में प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया।

पपुआ न्यू गिनी (पीएनजी)

पपुआ न्यू गिनी के साथ द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ तथा सहयोग के नए क्षेत्रों में विस्तारित होते गए।

भारत–प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग हेतु प्रथम मंच की बैठक में 19 नवंबर, 2014 को सुवा, फिजी में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी विदेश मामलों तथा अप्रवासन मंत्री श्री रिमबिंक पाटो से मिले तथा उन्होंने प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की वरीयता तथा पपुआ न्यू गिनी के साथ आर्थिक और विकास कार्यों में सहयोग और स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अवसंरचना में भारतीय सहभागिता पर चर्चा की। अन्य बातों के साथ–साथ, उन्होंने पपुआ न्यू गिनी सहित चौदह प्रशांत द्वीप देशों के नागरिकों को भारत आगमन पर वीजा, पपुआ न्यू गिनी को वार्षिक अनुदान सहायता बढ़ाकर 2,00,000 अमरीकी डॉलर करने, राजनयिकों को प्रशिक्षण, आईटीईसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, विकास परियोजनाओं में सहयोग संबंधी घोषणा की।

पीएनजी को अपने क्षमता निर्माण के प्रयासों में भारत आईटीईसी के अंतर्गत प्रशिक्षण तथा अन्य प्रयासों से सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष के दौरान, पीएनजी को भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत 30 स्थान, रक्षा संस्थानों में आईटीईसी के अंतर्गत रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु 6 स्थान, कोलंबो प्लान की तकनीकी सहयोग स्कीम के अंतर्गत 2 स्थान और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टोरल कार्यक्रमों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अंतर्गत 1 स्थान की पेशकश की गयी थी।

प्रशांत द्वीप देशों के लिए भारत के क्षेत्रीय प्रयास के अंतर्गत भारत ने पोर्ट मोर्सबी के सेंट चार्ल्स लवांग सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने सहायता अनुदान प्रदान किया। बेसरफुट कालेज ने अनेक प्रांतों और विद्युतीकरण के लिए पीएनजी महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।

पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में श्री माधव चन्द्र ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए।

पलाड में जुलाई, 2014 में आयोजित प्रशांत द्वीप मंच नेता शिखर सम्मेलन में पीएनजी राजनयिक डेनमेग टेलर को सर्वसम्मति से प्रशांत द्वीप मंच का महा सचिव नियुक्त किया गया।

फिलीपींस

भारत फिलीपींस के संबंध मित्रतापूर्ण रिश्तों, पारस्परिक लाभ तथा क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर विकसित होने जारी रहे।

नाए पई ताव में आयोजित आसियान–भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर 13 नवंबर, 2014 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति श्री बेनिगनो एस. एक्विनों से मिले। उन्होंने सहयोग के बड़े मुद्दों पर और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर बातचीत की। इससे पूर्व, नाए पई ताव में आसियान–भारत मंत्रिस्तरीय बैठक के अवसर पर 9 अगस्त, 2014 को फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव श्री अलवर्ट एफ डेल रोसारियो से भेंट की तथा द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

मंत्रिस्तरीय एवं अधिकारी स्तरीय अनेक अन्य दौरे भी हुए, जिनमें

पश्चिम बंगाल सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. शशि पांजा का 3–5 दिसंबर, 2014 तक का मनीला दौरा भी शामिल है, जो आरंभिक बाल्यावस्था विकास पर यूनीसेफ सम्मेलन में भाग लेने आए थे। जनसंख्या विकास पर एशियन फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस (एफएफपीपीडी) तथा यूएनएफपीएफ द्वारा 6–7 सितंबर, 2014 को आयोजित दसवें क्षेत्रीय महिला मंत्रियों और सांसदों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीमती विप्लव ठाकुर संसद सदस्य ने फिलीपींस का दौरा किया।

सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा ने 11वें विदेश कार्यालय विचार–विमर्श तथा पांचवीं सुरक्षा बातचीत के लिए 5–6 मार्च, 2014 को मनीला का दौरा किया।

मनीला में 20–23 अगस्त, 2014 के दौरान सद्भावना दौरे पर आईएनएस सहयात्री के सद्भावना दौरे से तथा 19–23 सितंबर, 2014 के दौरान भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस समुद्र पहरेदार के आगमन से रक्षा सहयोग सुदृढ़ होने जारी रहे। आर्मी हाई कमांड कोर्स के एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9–15 नवंबर, 2014 के दौरान फिलीपींस का दौरा किया तथा फिलीपींस नेवी के एक 5–सदस्यीय प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने 10–14 नवंबर, 2014 के बीच भारत का दौरा किया।

भारत ने 12वीं आसियान–भारत पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक तथा लेगाज्पी शहर, फिलीपींस में 17–20 मई, 2014 के दौरान आयोजित पूर्व एशिया और प्रशांत तथा दक्षिण एशिया के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ आयोग की 26वीं संयुक्त बैठक की सह अध्यक्षता की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री गिरीश शंकर अपर सचिव, पर्यटन ने किया। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तथा एटेनियो स्कूल ऑफ गवर्नेंस में भारत के 'सूचना का अधिकार अधिनियम' पर चर्चा के लिए आयोजित आसियान–भारत प्रमुख व्यक्तियों की व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत श्री यशोवर्धन आजाद, भारत के केंद्रीय सूचना आयुक्त ने 1–2 दिसंबर, 2014 को मनीला का दौरा किया।

8 भारतीय पत्रकारों ने आसियान भारत मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 28–31 अगस्त, 2014 के दौरान फिलीपींस का और फिलीपींस से 25 छात्रों ने आसियान–भारत छात्र आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 9–18 नवंबर, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया।

वैश्विक मंदी के बावजूद भारत और फिलीपींस को व्यापार–संबंध स्थिर रहे। प्रमुख भारतीय आईटी और फार्मा फमों का कार्य क्रमशः आईटी की सहायता से चल रही सेवाओं और जेनरिक्स सेक्टर में अच्छा बना रहा। फिलीपींस सरकार के पीपीपी मुख्य अवसंरचना कार्यक्रम के अंतर्गत केबु–मेक्टान एयरपोर्ट के रख–रखाव हेतु एक भारतीय कंपनी जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. ने संयुक्त कन्सोर्टियम बिड में सफलता हासिल की और जीएमआर मेगावाट जेवी ने केबु मेक्टान एयरपोर्ट के प्रचालन का कार्य 1 नवंबर, 2014 को आरंभ कर दिया। टाटा मोटर्स ने भी फिलीपींस में सात वाहन लांच करके आटो–मोबाइल सेक्टर मे एक बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने आपदा राहत वाहनों की आपूर्ति हेतु दवाओं की सिटी गवर्नमेंट के साथ 120 वाहनों की आपूर्ति के सौदे पर हस्ताक्षर किए और इन वाहनों की आरंभिक खेप 18 सितंबर, 2014 को दवाओ के मेयर को सौंप दी। एक प्रमुख डिजाइन और जीवनशैली प्रदर्शनी 'मनीला फेम' में भाग लेने के लिए एफआईईओ के नेतृत्व में 12 कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 16–19 अक्तूबर, 2014 के दौरान देश का प्रतिनिधित्व किया।

सिंगापुर

सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और दोनों देशों के बीच बारंबार हुए दौरों से सुदृढ़ हुए, जिनके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में हमारे संबंध मजबूत हुए। वर्ष 2014–15 भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की पचासवीं वर्षगांठ को चिंहित करता है।

भारत–सिंगापुर राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के महत्व को दर्शाने के लिए यादगारी कार्यक्रमों की श्रृंखला का सिंगापुर के विदेश मंत्री श्री के. शणमुगम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उद्घाटन करने हेतु विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 15–16 अगस्त, 2014 को सिंगापुर का दौरा किया।

आवास, गरीबी उपशमन और शहरी विकास मंत्री श्री वैकया नायडू ने 6–8 नवंबर, 2014 को सिंगापुर का दौरा किया।

अवसंरचना, कौशल, गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन तथा अन्य क्षेत्रों में निश्चित परियोजनाओं के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक राज्य सरकारों ने सिंगापुर के साथ संपर्क स्थापित किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने 18–22 अगस्त, 2014 के दौरान सिंगापुर का दौरा किया तथा अनेक राजनैतिक तथा कारोबारी नेताओं से मुलाकात की और सहयोग के लिए अनेक करार किए। तेलगांना के मुख्य मंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव ने एक प्रतिनिमंडल के साथ 20–23 अगस्त, 2014 के दौरान सिंगापुर का दौरा किया। राजस्थान की मुख्यमंत्री सुश्री वसुंधरा राजे ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 20–23 अगस्त, 2014 के दौरान सिंगापुर का दौरा किया और पेय–जल, शहरी विका, अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रशिक्षण पर सहमति करार किए गए। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू एक सरकारी तथा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल को कर 12–14 नवंबर, 2014 के दौरान सिंगापुर पहुंचे और नई राजधानी तथा स्मार्ट सिटीज विकसित करने पर सहमति करार हुए। राज्य सरकारों और सिंगापुर के बीच निकट संबंधों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नया स्वरूप मिला है।

नई सरकार के साथ संपर्क बनाने के लिए विदेश मंत्री और विधि मंत्री श्री के. षणमुगम ने 30 जून–5 जुलाई, 2014 के बीच भारत (नई दिल्ली, हैदराबाद और चैन्ने) का दौरा किया तथा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की। रक्षा मंत्री डॉ. नग एंग हेन ने

नाय पेई ताउ, म्यांमार में 9वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर 13 नवंबर, 2014 को फिलीपींस के राष्ट्रपति, श्री बेनिंग्नो साइमन कोजुआंग्को एक्विनो–III से हाथ मिलाते हुए प्रधान मंत्री।

नाय पेई ताउ में 12वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के अवसर पर 12 नवंबर, 2014 को सिंगापुर के प्रधान मंत्री श्री ली ह्सीन लूंग से मिलते हुए प्रधान मंत्री।

18–20 अगस्त, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। सेवानिवृत्त वरिष्ठ मंत्री श्री गोह चोकटोंग ने 7–11 सितंबर, 2014 के दौरान नई दिल्ली, हैदराबाद और भोपाल का दौरा किया तथा वे प्रधान मंत्री एवं राज्य के नेताओं से मिले। प्रधान मंत्री कार्यालय में मंत्री तथा गृह एवं व्यापार तथा उद्योग के द्वितीय मंत्री श्री एस. ईश्वरन ने 8 दिसंबर, 2014 को हैदराबाद का दौरा किया, जहां आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के मास्टर प्लान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उप–प्रधान मंत्री और वित्तमंत्री श्री थर्मन षणमुगरत्नम ने 10 दिसंबर, 2014 को भारत का दौरा किया तथा दिल्ली इकोनोमिक्स कॉन्क्लेव 2014 में एक सारगर्भित व्याख्यान दिया।

भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा सचिव के नेतृत्व में भारत–सिंगापुर रक्षा नीति वार्तालाप सितंबर, 2014 में संपन्न हुआ, जहां रक्षा सहयोग के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। वर्ष के दौरान भारत से स्टाफ–समिति के अध्यक्ष प्रमुखों एवं आर्मी स्टॉफ के चीफ, एयर स्टॉफ के चीफ तथा भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक ने सिंगापुर का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच रक्षा बलों के नियमित पारस्परिक दौरे हुए और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तथा अभ्यास भी आयोजित किए गए। इस अवधि में अभ्यास के लिए भारत की ओर से सिंगापुर के लिए सात आईएन/आसीजी जहाज भेजे गए तथा चार सिंगापुर नेवी जहाज भारत आए।

दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के दौरों का जबरदस्त आदान–प्रदान हुआ, जिसमें सीआईआई के अध्यक्ष श्री अजय श्रीराम के नेतृत्व में सीआईआई कोर ग्रुप का 27–28 नवंबर, 2014 को हुआ दौरा भी शामिल था। एस्पन इंडिया तथा आईएसएएस के बीच महत्वपूर्ण बातचीत सिंगापुर में हुई, जिसमें अधिकारी भी शामिल हुए।

द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश कार्यकलाप तेजी से जारी रहे, यद्यपि व्यापार में कुछ आवधिक कमी भी आई। तथापि, सिंगापुर के साथ द्विदिशिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ना जारी रहा, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक के एक अधिकतम स्रोत के रूप में उभर कर सामने आया। सिंगापुर में लगभग 6,000 भारतीय आर्थिक इकाइयों के पंजीकरण से जावक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी वृद्धि दिखाई दी, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक अवसरों में संतुलन उत्पन्न हुआ।

सांस्कृतिक कार्यकलापों तथा जन संपर्क का आदान–प्रदान चलता रहा। सिंगापुर में वर्षभर के वार्षिक महोत्सव में सांस्कृतिक, कलात्मक, फिल्म, साक्षरता, थिएटर आयामों तथा शैक्षिक संगोष्ठियों, कारोबारी सत्रों और जहाजों का आना–जाना जैसी गतिविधियां जारी रहीं इस समारोह से युवा वर्ग विशेष रूप से आकर्षित हुआ है, जिससे दोनों देशों के संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे।

थाईलैंड

भारत और थाईलैंड के संबंध निकट और मैत्रीपूर्ण हैं, जो सदियों पुराने सामाजिक सांस्कृतिक रिश्तों के परिचायक हैं। थाईलैंड में मई, 2014 में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद, भारत ने यह आशा दर्शाई कि थाईलैंड अपने राजनैतिक मुद्दों को सुलझा लेगा और प्रजातंत्र की भावना, कानून के राज तथा देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, जितनी जल्दी संभव हो, देश में सामान्य स्थिति बहाल कर लेगा। साथ ही, भारत अनवरत रूप से थाईलैंड से जुड़ा रहा।

नाए पई ताव में आयोजित भारत–आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर 12 नवंबर, 2014 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री जनरल प्रयूत–चान–ओ–चा के साथ पारस्परिक हित तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

म्यांमा के नाए पई ताव में 47वीं आसियान विदेश मंत्री बैठक के अवसर पर 10 अगस्त, 2014 को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज विदेशी मामलों के कार्यवाहक मंत्री और विदेशी मामलों के स्थाई सचिव श्री सिंहासक फुआंगकेटकोव से मिलीं।

चुलाचोमवलो रॉयल मिलिट्री अकादमी का 85 सदस्य प्रतिनिधिमंडल राजकुमार महा चक्री सिरिन्धोरन के नेतृत्व में 22 जुलाई, 2014 को कोलकाता आया।

'लिंग समानता और महिला सशक्तिकरणः बीजिंग+20 समीक्षा पर एशिया और प्रशांत सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला और बाल कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 19–20 नवंबर, 2014 को बैंकाक पहुंचा। मिलान में 17 अक्तूबर, 2014 को आयोजित एशिया–यूरोप बैठक (ए.एसईएम) के रखने शिखर सम्मेलन के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने प्रधानमंत्री जनरल प्रयूत चा–ओ–चा से भेंट की। गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बैंकाक में 22–26 जून, 2014 को आयोजित छठे एशियाई मंत्रिस्तरीय आपदा जोखिम कटौती सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भाग लिया। उन्होंने 27–28 नवंबर, 2014 को बैंकाक में आयोजित 'सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स इन एशिया एंड दि पेसिफिक पर आयोजित प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी भाग लिया।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा और विदेश मंत्रालय में स्थाई सचिव श्री सिंहासक फुआंगकेटकोव ने नई दिल्ली में 8 सितंबर, 2014 को आयोजित तीसरी भारत–थाईलैंड विदेश कार्य परामर्शदात्री समिति की संयुक्त अध्यक्षता की तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं पारस्परिक हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

रायल थाई सशस्त्र बलों के रक्षा प्रमुख जनरल तनासक पतिमा–परागोर्न ने 28–30 जून, 2014 के भारत के सरकारी दौरे के दौरान एक थाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। जनरल तनासक ने रक्षा मंत्री और वित्र मंत्री श्री अरुण जेटली से भेंट की तथा चेयरमेन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तथा थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह से मुलाकात की।

द्विपक्षीय उच्च स्तरीय रक्षा बातचीत की तीसरी बैठक 9 मई, 2014 को नई दिल्ली में हुई। थाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एयर चीफ मार्शल सोंगताम चोक्कनापिटाग, रक्षा उप स्थाई सचिव ने तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री शंकर अग्रवाल, विशेष सचिव, रक्षा मंत्रालय ने किया। समुद्री डकैती, गश्ती चोरी तथा शस्त्रों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विचार हेतुए इंडियन नेवी तथा द रायल थाई नेवी ने अंडमान समुद्र में क्रमशः 1–8 अप्रैल और 18–26 नवंबर, 2014 के दौरान समन्वित गश्त का क्रमशः 18वां तथा 19वां चक्र आयोजित किया। भारतीय नेवी के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाडर्न के भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) घड़ियाल, आईएनएस सुजाता, आईएनएस सुदर्शिनी और आईसीजीएस वरुण 21–24 अप्रैल, 2014 के दौरान फुकेट बंदरगाह पर पहुंचे। रायल थाइर एयरफोर्स (आरटीएएफ) के प्रचालनों के असिस्टेंट चीफ ऑफ दि एयर स्टाफ एयर मार्शल सुत्तीपोंग इनसिंयोंग ने नई दिल्ली में 9–11 सितंबर, 2014 के दौरान आयोजित 5वीं द्विपक्षीय एयर स्टाफ वार्ता के लिए थाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी पर भारत–थाईलैंड संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक तथा त्रिपक्षीय परिवहन लिंकेज परियोजना की 7वीं कार्यबल बैठक 29–30 सितंबर, 2014 को बैंकाक में हुई। वीजा और कोंसुलर मामलों पर द्विपक्षीय तदर्थ कार्यकारी समूह की चौथी बैठक 2 सितंबर, 2014 को बैंकाक में हुई। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्यकारी समूह की 9वीं बैठक 11–12 दिसंबर, 2014 को चियांग आई में हुई।

भारत सरकार के निमंत्रण पर एक 10–सदस्यीय थाई भाषा मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने 31 मई से 7 जून, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। भारतीय पत्रकारों के एक 9–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आसियान–भारत मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 5–8 अगस्त, 2014 तक बैंकाक का दौरा किया।

थाईलैंड के साथ भारत का व्यापार स्थिर रहा। एफटीए को कार्यक्षेत्र में विस्तार करने पर 9 दिसंबर, 2014 को आयोजित व्यापार मामलों पर भारत–थाईलैंड संयुक्त समिति की दूसरी बैठक में विचार–विमर्श किया गया। दिनांक 25 सितंबर, 2014 को लांच की गयी 'मेक इन इंडिया' मुहिम के समसमय दूतावास ने एक व्यापारिक कार्यक्रम आयोजित किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक दलों के आदान–प्रदान से मजबूत सांस्कृतिक संबंध बने रहे। इनमें सुश्री रामिन्दर तारा सिंह खुराना के नेतृत्व में ओडिसी नृत्य समूह, श्री गिरीश प्रधान के नेतृत्व में फ्यूसियन बैंड समूह तथा श्री शाम्बिक घोष के नेतृत्व में दिरमोसेक डांस कंपनी द्वारा अप्रैल–नवंबर, 2014 के दौरान थाईलैंड में आयोजित कार्यक्रम शामिल थे।

वियतनाम

इस अवधि में भारत–वियतनाम के संबंध उच्च स्तरीय दौरों के आदान–प्रदान तथा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सहभागिता के और प्रगाढ़ होने से अत्यधिक मित्रतापूर्ण तथा स्नेहपूर्ण बने रहे।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 14–17 सितंबर, 2014 के दौरान वियतनाम का राजकीय दौरा किया तथा इस दौरान वे राष्ट्रपति, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के महासचिव और प्रधान मंत्री से मिले तथा उन्होंने हनोई और हो–ची–मिन्ह शहर का दौरा किया। मुख्य करारों पर हस्ताक्षर किए गए तथा दोनों देशों एवं उनके लोगों के बीच संबंधों की घनिष्ठता पर बल दिया गया। इससे पूर्व, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 25–26 अगस्त, 2014 को वियतनाम का दौरा किया जिस दौरान उन्होंने उप–प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री श्री फाम बिन मिन्ह के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की तथा राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से भेंट की। अपने इस दौरे के दौरान, उन्होंने उप प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री श्री फाम बिन मिन्ह के साथ मिलकर आसियान इंडिया नेटवर्क ऑन थिंकटैंक्स (एआईएनटीटी) के तीसरे राउंडटेबल का उद्घाटन किया। उन्होंने क्षेत्र के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की तथा क्षेत्र के 16 भारतीय मिशन प्रमुखों से भी मिलीं।

वियतनाम के प्रधान मंत्री श्री न्गुयेन तान डंग ने 27–28 अक्तूबर, 2014 को भारत का राजकीय दौरा किया तथा इस दौरान उनके साथ एक बड़ा व्यवासियक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें अनेक प्रमुख सरकारी उद्यमों के सीईओ भी शामिल थे। भारत के प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री श्री न्गुयेन टान डंग से वार्ता की तथा श्री डंग ने राष्ट्रपति एवं प्रधान मंत्री से भी भेंट की। सीआईआई को समन्वयन से एक प्रमुख व्यसायिक कार्यक्रम भी किया। वर्ष के दौरान हुए उच्चस्तरीय दौरों के दौरान बिजली, संस्कृति युवा मामलों, पशु स्वास्थ्य, रक्षा, क्षमता निर्माण सूचना और प्रसारण आदि पर 14 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

अंतर संसदीय संघ की 132वीं सभा के लिए लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन 28 मार्च से 1 अप्रैल, 2015 के दौरान हनोई, वियतनाम का दौरा करेंगी।

वियतनाम और भारत के बीच नई दिल्ली में 16–17 अप्रैल, 2014 को आयोजित छठे एफओसी तथा तीसरे रणनीतिक वार्तालाप में भाग लेने के लिए वियतनामी उप विदेश मंत्री श्री फाम कुआंग विन्ह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधमंडल भारत आया। विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम (डीवीपी) के अंतर्गत वियतनाम के फुओ प्रोविन्स के पार्टी सचिव, श्री होंग वान मैक के नेतृत्व में एक वियतनामी प्रतिनिधिमंडल 23–31 जनवरी, 2015 के दौरान भारत का दौरा करेंगे।

भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने उच्चस्तरीय रक्षा संबंधों के एक भाग के रुप में 17–20 दिसंबर, 2014 के दौरान वियतनाम का दौरा किया। वियमनाम के उप रक्षा मंत्री, ले. जनरल न्गुयेन ची बिन्ह ने रक्षा सचिव के साथ सुरक्षा वार्ता के लिए 16 जनवरी, 2015 को दिल्ली का दौरा किया। द्विपक्षीय रक्षा संबंध रक्षा हार्डवेयर सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत और गहन होते जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित 100 मिलियन डॉलर की ऋण–श्रृंखला का इस्तेमाल नौसेना पोतों की बिक्री के लिए किया जाएगा। दोनों पक्षों की ओर से रक्षा संबंधी अनेक संगोष्ठियां आयोजित की गयी तथा कुछ भारतीय जल सेना युद्धपोतों आईएनएस शिवालिक (अगस्त, 2014) तथा तटरक्षक जहाज 'समुद्र पहरेदार' (अक्तूबर, 2014) ने वियतनाम की बंदरगाहों पर चक्कर

लगाया। दोनों ओर से अनेक उच्च स्तरीय रक्षा दौरों से संबंध और सुदृढ़ हुए।

हनोई में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ए.डी.एम.एम.) प्लस के सहकारी ढांचे के अंतर्गत 18 जून, 2014 को आयोजित एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) ऑन ह्यूमैनीटेरियन माइन एक्शन की पहली बैइक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती स्मिता नागराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वियतनाम का दौरा किया।

व्यापार और संबंधित मुद्दों पर भारत–वियतनाम संयुक्त उप आयोग की दूसरी बैठक के लिए भारत सरकार के वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 19–20 जनवरी, 2015 को हनोई और हो ची मिन्ह नगर, वियतनाम का दौरा किया।

वियतनाम अकादमी ऑफ सोशल साइंसेज (वीएएसएस) के अध्यक्ष प्रो. गुयेन एक्सुआन थांग ने आसियान–भारत विशिष्ट व्यक्ति व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत 11–14 अगस्त, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। हो ची मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पालिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष प्रो. टा नागोक टान ने 19–23 अक्तूबर, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समीक्षाधीन अवधि में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और यह 2015 के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी पार कर गया। दोनों पक्ष 2020 तक 15 बिलियन अमरीकी डॉलर के संशोधित व्यापार लक्ष्य पर सहमत हो गए हैं। राजमार्गों तथा ऊर्जा संयंत्रों की प्रमुख परियोजनाओं के अलावा वियतनाम में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल अनुमानित निवेश से भारत की लगभग 100 परियोजनाएं चल रही हैं। हनोई में भारतीय दूतावास तथा हो ची मिन्ह शहर में महा कोंसलावास ने, भारत के साथ व्यापार करने के बारे में अनेक व्यापार संवर्धन कार्यक्रम, संगोष्ठियां आयोजित कीं तथा देश के अनेक भागों में 'मेक इन इंडिया' मुहिम भी चलाई। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वियतनाम को रियायती निबंधनों और शर्तों पर अनेक ऋण श्रृंखलाओं की पेशकश की है।

पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) तथा अन्य स्कालरशिप कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला बड़ा देश रहा है। दिल्ली/मुंबई–बैंकाक–हो ची मिन्ह सिटी के बीच नवंबर, 2014 से जेट एयरवेज द्वारा आरंभ कोड शेयर उड़ानों के साथ जनता के आपस में आदान–प्रदान तथा सांस्कृतिक सहयोग को एक बढ़ावा मिला।

प्रशांत द्वीप समूह

प्रधान मत्री के फिजी दौरे के दौरान 19 नवंबर, 2014 को सुवा, फिजी में प्रशांत द्वीपों के नेताओं के साथ आयोजित प्रथम शिखर बैठक के परिणामस्वरूप प्रशांत द्वीपों के साथ भारत के संबंधों को एक प्रमुख उछाल मिला। प्रशांत नेताओं के साथ अयोजित बैठक एक जबरदस्त सफलता थी न केवल इसलिए कि यह इस प्रकार की पहली बैठक थी बल्कि इसलिए भी कि इससे भारत के साथ निकट संबंधों के संकेत मिले।

भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के प्रथम मंच के आयोजन से 14 प्रशांत द्वीपीय देशों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया दिखाई दी है। इसमें किरीबाती (श्री अनोट टोंग) तथा नोरू (श्री बैरन दिवावेसी वाका) के राष्ट्रपतियों; तुवालू के गवर्नर जनरल (श्री इटालेली लाकोबा); फिजी (रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) फ्रेक बेनीमारामा) समोआ (श्री तुइलेपा आइनो सेलेलोमालीलेगेई) टोंगा (श्री तु इवाकानो) नियू (श्री टोक तलागी), कुक आइलैंड (श्री हैनरी पुणे) के प्रधान मंत्री; पीएनजी (री रिमबिंक पाटो); वनुआटु (श्री मेलटेक साटो किलमान लिवटीवान) और मार्शल आइलैंड्स (श्री एन्टोन टोनी देबरम) के विदेश मंत्री और पलाऊ (श्री ग्रेगोरियो नगिरमांग) के स्वास्थ्य मंत्री। (सोलोमन आइलैंड के राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष चुनावों की वजह से इसमें भाग नहीं ले सके, जबकि फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ मार्कोनोसिया के राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण इसमें भाग नहीं ले पाए)। फिजी में सोलोमन आइलैंड के उच्चायुक्त (श्री पैटर्सन ओटी) तथा फिजी में मार्कोनेसिया के राजदूत (श्री गेरसन जेक्सन) ने अपने नेताओं का प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/मंत्री 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उपस्थित हुए।

एफआईपीआईसी से प्रशांत द्वीप देशों को पारस्परिक हित के मुद्दों पर सीधी चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधान मंत्री ने जलवायु परिवर्तन तथा विकास संबंधी उनकी चिंताओं से सहमति जताई और कहा कि इस क्षेत्र के साथ हमारा सहयोग उनकी अपनी विकास प्राथमिकताओं पर आधारित है। उन्होंने आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर तथा मानवशक्ति के आदान–प्रदान पर अधिक सहयोग देने का प्रस्ताव रखा। प्रधान मंत्री ने क्षेत्र के साथ निकट संबंध बनाने की भारत की इच्छा जताई तथा प्रशांत द्वीपों को तकनीकी सहायता प्रदान के लिए 1 मिलियन डॉलर की विशेष अनुकूलन निधि देने, ई–कनेक्टिविटी के लिए एक पैन प्रशांत द्वीप परियोजना, दूरस्थ चिकित्सा तथा दूरस्थ शिक्षा, पर्यटकों के लिए आगमन पर वीजा प्रत्येक प्रशांत द्वीप देश को अनुदान सहायता 1,25,000 डॉलर से बढ़ाकर 2,00,000 डॉलर प्रति वर्ष करने, भारत में व्यापार कार्यालय स्थापित करने में सहायता, प्रतिनियुक्ति पर आईटीईसी विशेषज्ञों को भेजने, पीआईसी से राजनयिकों को प्रशिक्षण, विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम, एस एंड टी और सौर सहयोग तथा प्रशांत नेताओं की नियमित शिखर बैठकें आयोजित करने की घोषणा की। एफआईपीआईसी की अगली बैठक 2015 में भारत में आयोजित किए जाने की आशा है।

पलाउ में 31 जुलाई–1 अगस्त, 2014 को आयोजित 26वें पेसिफिक आइलैंड फोरम (पीआईएफ) पोस्टफोरम डायलाग में भाग लेने के लिए सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आपिया, समोआ में 1–4 सितंबर, 2014 के दौरान आयोजित तीसरे यूएनएसआईडीएस सम्मेलन में एक तीन–सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया।

एफआईपीआईसी पहल की शुरूआत से प्रशांत क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों का एक नया अध्ययन शुरू हुआ है।

■■

नाए पेई ताउ, म्यांमार में 12 नवंबर, 2014 को आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर थाइलैण्ड के प्रधान मंत्री जनरल प्रयूत चान–ओ–चा से हाथ मिलाते हुए प्रधान मंत्री।

नई दिल्ली में 28 अक्तूबर, 2014 को समाजवादी गणराज्य वियतनाम के प्रधान मंत्री, श्री नग्यूयेन तान डुंग से हाथ मिलाते हुए प्रधान मंत्री।

नई दिल्ली में 28 अक्तूबर, 2014 को समाजवादी गणराज्य वियतनाम के प्रधान मंत्री श्री नग्यूयेन तान डुंग से भेंट करती हुई विदेश मंत्री

सुवा में प्रशांत द्वीप नेताओं के साथ मुलाकात करते प्रधान मंत्री।

3 पूर्वी एशिया

लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया

भारत तथा लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया (DPRK) के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग जारी रखा है। DPRK ने UNHRC (2015–2017); 2014–2018 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु अंतरसरकारी समिति; तथा 2015–2018 की अवधि के लिए एशिया प्रशांत टेली समुदाय के महासचिव के पद पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था।

जापान

वर्ष 2006 से भारत तथा जापान के संबंधों में दोनें देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 'वार्षिक शिखर सम्मेलन' के तंत्र द्वारा प्रेरित होकर हाल के वर्षों मे महत्वपूर्ण तथा गुणात्मक परिवर्तन आया है। जापान ने बदले हुए क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के संदर्भ में भारत के साथ संबंधों को विकसित करने की प्रतिबद्धता के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाना जारी रखा है। भारत–जापान सहयोग के पांच स्तंभों में राजनीतिक; रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग; व्यापक आर्थिक भागीदारी; विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी में पहल; लोगों का लोगों से आदान–प्रदान; तथा क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग शामिल है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक शिखर बैठक हेतु 30 अगस्त से 3 सितंबर 2014 तक जापान की सरकारी यात्रा की थी। यह भारत के पड़ोसी देशों से अलग उनकी पहली महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी। टोक्यो में दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के पश्चात प्रतिबंधित बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने जापान के सम्राट को आमंत्रित किया था। जापान के उप–प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री तारो आसरे, विदेश मंत्री श्री कूमियो की शीडा, रक्षा मंत्री श्री इत्सूनोरी ओनोडेरा, आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री तोशीमित्सु मोटेगी तथा भूमि, अवसंरचना, परिवहन एवं पर्यटन मंत्री श्री अकिरो ओटा ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। जापान के लोकतांत्रिक पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी तथा न न्यू कोमेटो पार्टी, प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के संयुक्त साझेदारों के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। भारत–जापान विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी हेतु टोक्यो घोषणा–पत्र पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किया था तथा 'तथ्य–पत्र (Factsheet)' साझा विकास हेतु भारत तथा जापान–भागीदारी' को जारी किया था। इस यात्रा से कई वास्तविक नतीजे निकले। आर्थिक पक्ष पर, नए भारत–जापान निवेश संवर्धन साझेदारी की शुरूआत की गई थी जिसके तहत जापान ने पांच वर्षों की अवधि के दौरान भारत में लोक–निजी निवेश में 3.5 ट्रिलियन येन निवेश करने की इच्छा जताई और साथ–साथ भारत में काम करने वाली जापानी कंपनियों की संख्या को दोगुना करने की भी इच्छा जताई थी। सहयोग के नए प्रमुख क्षेत्रों के तौर पर रक्षा उपकरणों तथा पौद्योगिकी की पहचान की गई थी। इस यात्रा के दौरान दोनों ओर से जापानी विदेश–एंड प्रयोक्ता सूची में से छः भारतीय हस्तियों को हटाए जाने पर सहमति भी बनी थी। दोनों ओर से उर्जा, एल एन जी, रेलवे, अवसंरचना, स्मार्ट शहर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा लोगों का लोगों से आदान–प्रदान को बढ़ावा देने सहित कई क्षेत्रों में उनके सहयोग एवं साझेदारी को सुढ़ृढ़ करने पर सहमति बनी थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए थेः (क) भारत–गणराज्य के रक्षा मंत्रालय तथा जापान के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग एवं विनिमय पर ज्ञापन; (ख) भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जापान के स्वास्थ्य, मजदूर एवं कल्याण मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सहयोग पर ज्ञापन; (ग) महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में भारत गणराज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा जापान के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन; (घ) सड़क तथा सड़क परिवहन क्षेत्र में भारत सरकार के सड़क यातायात तथा राजमार्ग मंत्रालय एवं जापान के भूमि, अवसंरचना, परिवहन तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच सहयोग ढांचा; (ड़) भारत सरकार के नए एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय तथा जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को–ऑपरेशन के बीच समझौता ज्ञापन; तथा (च) बनारस (भारत) तथा क्योटो (जापान) के शहरों के बीच सहयोगी शहर संबंध के संदर्भ में पुष्टि की इच्छा।

भारत तथा जापान के पास विभिन्न द्विपक्षीय करारों के कार्यान्वयन स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा के लिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तरों पर संयुक्त तंत्र है। विदेश सचिव/उप विदेश मंत्री के स्तर पर द्विपक्षीय परामर्श 25 अप्रेल, 2014 को टोक्यो में आयोजित किया गया था।

सरकार ने 9 अक्तूबर, 2014 को जापान के निवेश की सुविधा तथा फास्ट ट्रैक करने के लिए "जापान प्लस" नाम के विशेष प्रबंधन दल का गठन किया था। दसवें एशियाई तट–रक्षक प्रमुखों की बैठक के

दौरान भारतीय तट–रक्षक जलयान (ICGS) समुद्र पहरेदार तथा भारत में निर्मित प्रदूषण नियंत्रण जलयान (PCV) ने योकोहामा, जापान की यात्रा की तथा 29 सितंबर से 01 अक्तूबर, 2015 तक योकोहामा में जापानी तट–रक्षकों के साथ संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया था। जापानी आर्थिक, व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय ने 17 सितंबर, 2014 को जापानी विदेश एंड प्रयोक्ता सूची (Foreign end user list) से 6 भारतीय अंतरिक्ष तथा रक्षा हस्तियों को हटाए जाने की अधिसूचना जारी की थी। जापानी एयर सेल्फ डिफेंस के साठवी (60वी) वार्षिक आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल, अरूप साहा ने 21–24 अक्तूबर, 2014 तक जापान की यात्रा की थी। जापान में भारत उत्सव आयोजन के उद्घाटन समारोह के लिए पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद यशो नाईक ने 27–30 अक्तूबर, 2014 तक जापान की यात्रा की थी। 28 अक्तूबर 2014 को टोक्यो में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पर दूसरे भारत–जापान संयुक्त कार्य–दल का आयोजन किया गया था, जिसमें जापानी औद्योगिक टाउनशिप/जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करने में प्रगति पर चर्चा की गई थी। 29 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में शहरी विकास पर 8वें भारत–जापान संयुक्त कार्य–दल (JWG) का आयोजन किया गया था। गुवाहाटी सीवरेज परियोजना के कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा 15.62 बिलियन येन के ऋण के विस्तार के लिए टिप्पणियों के आदान–प्रदान पर 21 नवंबर, 2014 को हस्ताक्षर किया गया था। 24 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में अफ्रीका पर चौथे भारत–जापान वार्ता का आयोजन किया गया था। भारत–जापान ICT विस्तार सहयोग ढांचा के अंतर्गत 3 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में दूसरे भारत–जापान संयुक्त कार्य–दल का आयोजन किया गया था।

भारत–व्यापक सहयोग ढांचा के अंतर्गत द्वितीय भारत–जापान संयुक्त कार्य दल की बैठक 3 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत की यात्रा करने वाले जापानी विदेश मंत्री तथा वित्त सचिव के बीच आर्थिक मुद्दे पर 7वीं भारत–जापान रणनीतिक वार्ता 18 दिसंबर, 2014 को आयोजित की गई थी। महानिदेशक/संयुक्त सचिव स्तर पर 6ठी भारत–यू.एस.–जापान त्रिपक्षीय वार्ता 20 दिसंबर, 2014 को आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र कार्य पर चौथी भारत–जापान परामर्शी 20 दिसंबर, 2014 को आयोजित की गई थी। यू.एस–2 पर संयुक्त कार्य दल की उप–समिति की बैठक 22 दिसंबर, 2014 को आयोजित की गई थी। रक्षा उपस्कर और प्रौद्योगिकी सहयोग पर कार्यकारी स्तरीय परामर्श करने के लिए प्रारंभिक बैठक 23 दिसंबर, 2014 को आयोजित की गई। वाराणसी शहर और क्योटो शहर के बीच सहभागिता करार को प्रचालनात्मक बनाने के लिए सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति की प्रथम बैठक 13 जनवरी, 2015 को आयोजित की गई। भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (IIFCL) की पी पी पी अवसंरचना वित्त पोषण परियोजना हेतु जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा 50 बिलियन येन (लगभग 2620 करोड़ रुपए) के ODA ऋण हेतु आदान–प्रदान संबंधी दस्तावेज पर 16 जनवरी, 2015 को हस्ताक्षर किए गए। भारत के विदेश मंत्री एवं जापान के विदेश मंत्री के बीच 17 जनवरी, 2015 को 8वीं भारत–जापान रणनीतिक वार्ता हुई।

मंगोलिया

भारत तथा मंगोलिया के बीच एक अलग प्रकार का सभ्यता का संबंध है तथा साथ ही सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंध भी है। मित्रता एवं विश्वास ने भारत–मंगोलिया संबंधों को चिह्नित किया है, जिसे 'व्यापक भागीदारी' के रूप में बढ़ाया गया है। 27 नवंबर, 2014 को आयोजित पहले विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) के दौरान दोनों देशों के संपूर्ण संबंधों पर चर्चा की गई थी। सीमा सुरक्षा बल (भारत) तथा सीमा रक्षा हेतु सामान्य प्राधिकरण (मंगोलिया) के बीच चौथे डी जी स्तर की वार्ता में भाग लेने के लिए 15–20 दिसंबर, 2014 कार्यक्रम में मंगोलिया के सीमा रक्षा हेतु सामान्य प्राधिकरण के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल ल्हाचिनाजाव शी कि अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की थी। दोनों देश भारत तथा मंगोलिया में आयोजित वार्षिक मिलिटरी अभ्यास में नियमित तौर पर भाग लेते हैं। भारत ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के तहत शिक्षा हेतु आई टी ई सी कार्यक्रम तथा आई सी सी आर छात्रवृत्ति, वार्षिक 'मंगोलिया को मांग–अनुदान', के तहत नागरिक, रक्षा तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मंगोलिया को विकास सहायता देना जारी रखा है। नए व्यापार के कार्यान्वयन हेतु उलानबतार में राजीव गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ प्रोडक्शन एंड आर्ट के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। इस परियोजना के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है तथा अगले वर्ष तक इसे पूरा किए जाने का अनुमान है। उलानबतार, मंगोलिया में "भारत–मंगोलिया संयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी शिक्षा एवं आउटसोर्सिंग केंद्र की स्थापना हेतु भारत द्वारा दिए गए 20 मिलियन अमरीकी डालर की साफ्ट ऋण श्रृंखला को पहले ही उपयोग किए जाने पर मंगोलिया भी सहमत हो गया है। ऋण श्रृंखला करार को अगस्त 2012 से प्रभावी कर दिया गया है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करना जारी रखा है।

कोरिया गणराज्य

भारत तथा दक्षिण कोरिया राजनीतिक सहयोग, आर्थिक संबंध तथा सांस्कृतिक विनिमय को और अधिक बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी का सतत विस्तार किया है। लोगों का लोगों से संबंध तथा दोनों देशों के बीच यात्रा बढ़ाए जाने के क्रम में भारत ने 15 अप्रेल, 2014 से कोरियाई पर्यटकों हेतु आगमन पर वीजा की सुविधा का विस्तार किया है। कोरिया की राष्ट्रपति सुश्री जियून–ले की जनवरी, 2014 में भारत की सरकारी यात्रा के दौरान भारत ने कोरिया को पवित्र बोधि–वृक्ष का पौधा भेंट स्वरूप प्रदान किया था, यह पौधा सिओल पहुंच गया है और 2015 के मध्य तक एक प्रसिद्ध

मंदिर में इसे दर्शनार्थ खोला जाएगा। ICCR के महानिदेशक ने कोरिया यात्रा के दौरान 21 जुलाई, 2014 को बूसान में हांगबियोप–सा मंदिर में, कोरिया में पहली बार महात्मा गांधी की अर्धप्रतिमा का अनावरण किया था। कोरियाई राष्ट्रपति श्री पार्क जियून–ह्यू ने 22 जुलाई, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात की और आम चुनावों में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी तथा कोरिया की यात्रा के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। दोनों नेताओं ने आने वाले वर्षों में बड़ी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का स्वागत किया तथा साझेदारी में संपूर्ण प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद जताई थी। विदेश मंत्री ने नेपीताओ में 10 अगस्त, 2014 को आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) में विदेश मंत्रियों के बैठक के अंत में कोरियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की थी, जब अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर भी सहमति बनी थी कि वह अगली संयुक्त आयोग बैठक (JCM) का आयोजन करने के लिए सिओल की यात्रा करेंगी। सचिव (पूर्व) तथा कोरियाई प्रथम उप–मंत्री के नेतृत्व में 29 अगस्त, 2014 को सिओल में आयोजित चौथे भारत–कोरिया गणराज्य नीति एवं सुरक्षा वार्ता (FPSD) में द्विपक्षीय संबंधों का और अधिक विस्तार करने पर विचार–विमर्श किया गया था। इसके पश्चात JCM की तैयारी के तौर पर संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) तथा उनके कोरियाई समकक्ष के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का सिओल में आयोजन किया गया था।

पूर्वी एशिया तथा आसियान शिखर सम्मेलन के अंत में 12 नवंबर, 2014 को नेपिताई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति पार्क जिडन ह्ये ने मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए अपने विचारों का व्यापक तौर पर आदान–प्रदान किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचनाओं तथा वर्गीकृत मिलिटरी सूचना के संरक्षण (जनवरी 2014 में), रक्षा नीति वार्ता पर संस्थान (दिसंबर 2013 में सिओल में), उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान–प्रदान, मिलिटरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच नियमित आदान–प्रदान पर करारों के निष्कर्ष के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा तथा सुरक्षा संबंधों को बढ़ाया गया था। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के सचिव स्तरों के बीच सिओल में नवंबर 2014 में एक उत्पादक संयुक्त समिति बैठक का आयोजन किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा रक्षा अधिग्रहण एवं कार्यक्रम प्रशासन (DAPM) के बीच सहभागिता भी और मजबूत हो रही है।

व्यापक विषय–वस्तु– नवीकृत संबंधों की ओर नए अवसर तथा चुनौतियों के तहत 13वें कोरिया–भारत वार्ता का सह–आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कार्य हेतु सियोल मंच (SFIA) तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान हेतु भारतीय परिषद (ICRIE) के द्वारा 07–08 नवंबर, 2014 को सियोल में किया गया था। इस वार्ता ने अग्रणी नीति बनाने वालों, शिक्षाविदों, रक्षा तथा सुरक्षा विश्लेषकों एवं कॉर्पोरेट लीडरों को एक मंच पर ला दिया है। रक्षा उत्पादन; सिविल परमाणु उर्जा; ICT तथा अंतरिक्ष अनुसंधान; तथा भारत एवं कोरिया से SME जैसे क्षेत्रों में सहयोग को संवर्धित किए जाने हेतु इस मंच द्वारा कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं।

द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गुणात्मक प्रोत्साहन देने के लिए तथा प्रधानमंत्री के 'मेक–इन इंडिया पहल के विषय से कोरियाई उद्योग को अवगत कराने के लिए भारतीय दूतावास ने अब तक के सबसे बड़े व्यावसायिक सिंपोजियम 'भारतःअवसंरचना एवं विनिर्माण का नया भविष्य का 29 अगस्त, 2014 को आयोजन किया था। सचिव (पूर्व) ने मुख्य संबोधन किया था। अन्य जाने–माने वक्ताओं में DMIC के CEO तथा गुजरात राज्य के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने अन्य के साथ मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट कार्ड, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत में विनिर्माण सुविधा की स्थापना कराने के लिए कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग प्रोत्साहित करने के लिए 17–20 अक्तूबर, 2014 के दौरान दक्षिणी कोरिया की यात्रा की थी। इन्होंने अग्रीणी कोरियाई उद्योग घरानों के CEO से मुलाकात की थी।

कोरिया व्यापार–निवेश संवर्धन एजेंसी (KOTRA) राजस्थान में अब तक के पहले कोरियाई औद्योगिक पार्क की स्थापना किए जाने पर कार्य कर रहा है। पुणे के निकट महाराष्ट्र में 1.8 मिलियन टन क्षमता तथा 700 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के निवेश से पौस्को (POSCO) के कोल्ड रोल्ड स्टील मिल का कार्य समाप्त होने के करीब है।

2013 में द्विपक्षीय व्यापार की राशि 17.57 बिलियन हो गई थी। भारत कोरिया का 15वां सबसे बड़ा व्यापार सहभागी है। कोरिया की ह्यूंदई मोटर्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एल जी, इत्यादि जैसी प्रमुख कंपनियां, जिन्होंने जून–2014 तक भारत में 3.49 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है, उनकी योजना इस निवेश को आगे और बढ़ाने की है। कोरिया में महिंद्रा एंड महिंद्रा (सांगयोंग मोटर्स), आदित्य बिरला समूह(नोर्वोलस लि.), तथा टाटा (टाटा डेबू वाणिज्यिक वेहिकल्स) के नेतृत्व में भारत का FDI (प्रत्यक्ष विदेश निवेश) 3 बिलियन अमरीकी डालर के करीब है।

कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के साथ विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 29 दिसंबर, 2014 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) की सह–अध्यक्षता करने के लिए 28–30 दिसंबर, 2014 को सियोल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति मैडम पार्क गुवेन हाई से मुलाकात की और व्यापार, उद्योग एवं उर्जा मंत्री, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठकें की। द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने तथा इसे और प्रभावशाली बनाने के वास्ते एक शेड मैप तैयार करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार–विमर्श करने की दृष्टि से दोनों मंत्रियों के लिए यह बैठक अवसर दायनी साबित हुई। द्विपक्षीय आर्थिक, रक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि 2015 की प्रथम तिमाही के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग, रक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कोरिया गणराज्य की यात्रा कर सकते हैं।

■■

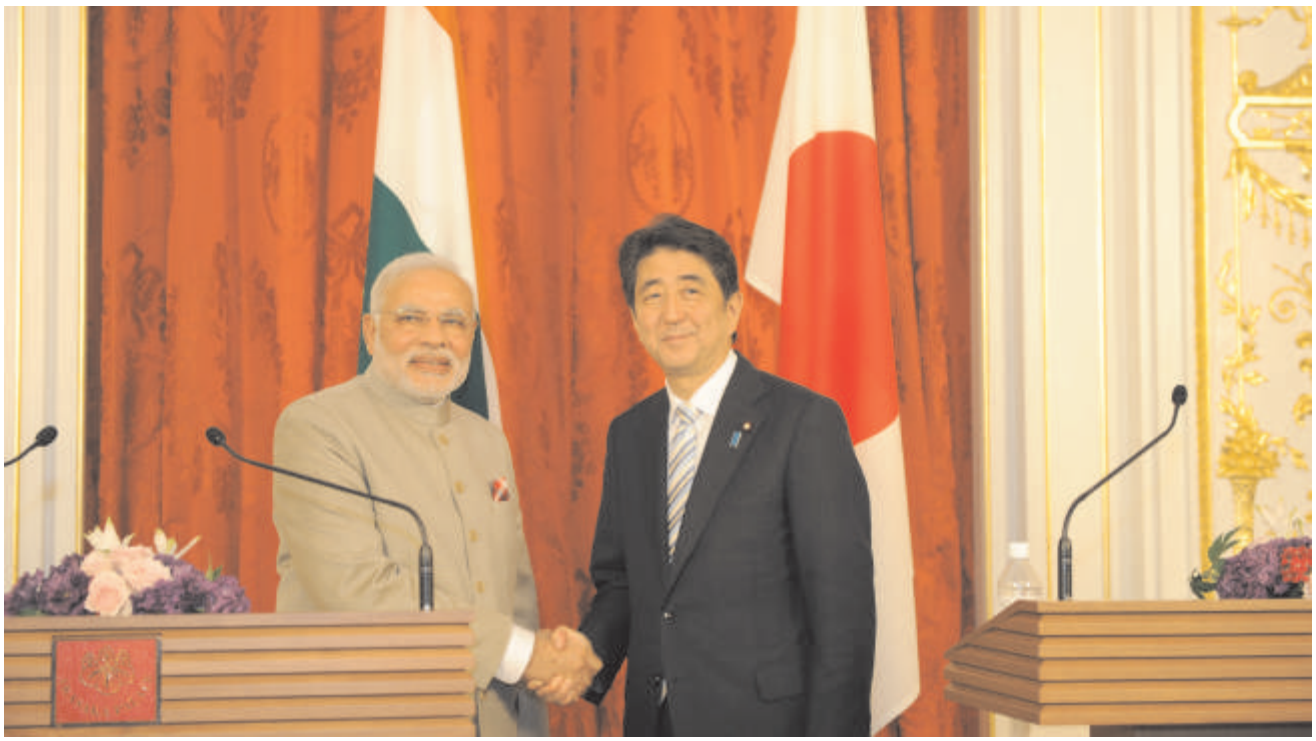

टाक्यो में 01 सितंबर, 2014 को संयुक्त प्रेस वार्तालाप के दौरान जापान के प्रधान मंत्री, श्री शिंजो अबे के साथ प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी।

नाय पेई ताउ, म्यांमार में 12 नवम्बर, 2014 को 12वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के अवसर पर कोरिया गणराज्य की राष्ट्रपति सुश्री पार्क ग्यून–हई से हाथ मिलाते हुए प्रधान मंत्री।

विदेश मंत्री का कोरिया गणराज्य का दौरा –सियोल में 29 दिसंबर, 2014 को कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री, श्री युन ब्यूंग से भेंट करती हुईं विदेश मंत्री।

4 यूरेशिया

रूसी परिसंघ

भारत तथा रूस, लगभग छः दशकों के परस्पर विश्वास तथा भरोसे के आधार पर बने दीर्घावधिक मित्रता साझा करते हैं। इन वर्षों के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न स्तरों पर सक्रिय वार्ता को जारी रखा है। वर्ष 2000 में हस्ताक्षरित सामरिक भागीदारी घोषणापत्र के तहत भारत के प्रधानमंत्री तथा रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर बैठकों की प्रणाली को संस्थापित कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति श्री ब्लादीमीर पुतिन ने 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10–11 दिसंबर, 2014 तक भारत की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंत में 16 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा, ब्राजील तथा 15–16 नवंबर, 2014 को ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया में जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति श्री ब्लादीमीर पुतिन से मिले थे।

15वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा था। दोनों देश उनके सामरिक साझेदारी के विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त स्वरूप पर बल देते हैं। इस शिखर सम्मेलन ने सामरिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम परिणाम पस्तुत किया है तथा कम से कम 20 द्विपक्षीय दस्तावेजों एवं वाणिज्यिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें परमाणु, रक्षा, उर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा निवेश क्षेत्रों पर करार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने अगले दशक तक हमारे द्विपक्षीय सहयोग के महत्वाकांक्षी दृष्टि प्रदान किया है। 'द्रूसवा–दोस्ती' नाम का संयुक्त दस्तावेज जारी किया, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग 'विस्तृत–आधार' (broad-basing') की बात की गई है तथा यह इन संबंधों को नए गुणात्मक स्तर पर ले जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए अपना समर्थन दिया है तथा दोनों देशों ने दोनों के समान अधिकार वाले क्षेत्रों में संयुक्त रूप से आतंकवाद से लड़ने का शपथ लिया है।

सामरिक परमाणु सहयोग पर एक पृथक दृष्टि का उच्चारण किया गया जो सामग्री की प्रौद्योगिकी तथा स्थानीयकरण (localistation) के स्थानांतरण की वृद्धि के साथ अगले दो दशकों में कम से कम 12 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की बात कही गई है।

रूस, भारत का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सहभागी है, इसके बावजूद भारत ने अपने रक्षा स्रोतो का विविधिकरण किया है। नेताओं ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत हमारी रक्षा परियोजनाओं को समकालीक बनाने के तरीकों की खोज की है। अप्रेल 2014 में न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (NPCIL) ने सामान्य ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किए थे तथा रूसी कंपनी एटॉमस्ट्रोएक्सपोर्ट के साथ कुडनकुलम परमाणु उर्जा संयत्र की इकाई 3 तथा 4 के लिए एकीकरण समझौता किया था। विदेश सचिव श्रीमति सुजाता सिंह ने रूस के प्रथम उप विदेश मंत्री श्री ब्लादीमीर तितोव तथा उप विदेश मंत्री श्री आईगोर मोरगुलोव के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के आयोजन हेतु अप्रेल 2014 में मास्कों की यात्रा की थी। दो मंत्रालयों के बीच निरस्त्रीकरण, अप्रसार तथा निर्यात नियंत्रण (मास्को, अप्रेल, 2014); शंघाई सहयोग संगठन (SCO) (मास्को, सितंबर, 2014); तथा रूस–भारत–चीन (RCI) (मास्को, सितंबर, 2014) पर विदेश कार्यालय परामर्श संपन्न हुआ था।

अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय, श्री अनुज कुमार बिश्नोई ने मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर तीसरे मास्को सम्मेलन में भाग लिया था; उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा उप–सलाहकार श्री नेहचल संधू ने 18–21 जून, 2014 तक कजाम में सुरक्षा मामलों पर आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय उच्च रैंकिग कार्मिक बैठक में भाग लिया था। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री आर.पी.सिंह ने मई 2014 में मास्को में आयोजित ब्रिक्स सदस्य देशों की एंटी–ड्रग्स बैठक में भाग लिया था।

रूसी उप प्रधानमंत्री श्री डिमित्री रोगोजीन ने 18 जून, 2014 को भारत की यात्रा की थी तथा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। उस समय के पदासीन रक्षा मंत्री श्री अरूण जेटली तथा सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया था।

पूर्व मुख्य न्यायाधीस श्री आर.एम.लोधा ने 18–21 जून, 2014 को चौथे सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय विधि मंच में भाग लिया था; महालेखा नियंत्रक श्री शशिकांत शर्मा ने एशियाई तथा यूरेशियाई लेखापरीक्षकों की बैठक में भाग लेने के लिए सितंबर 2014 में, रूस

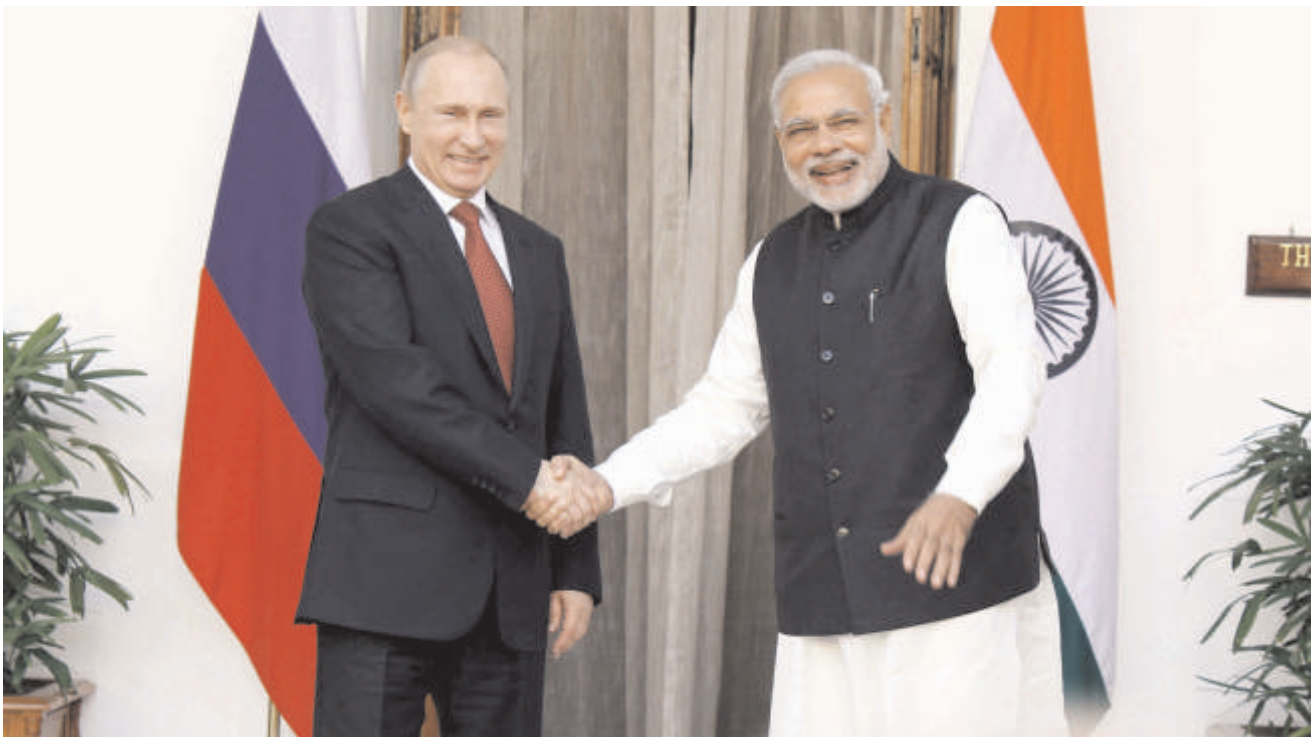

रुस संघ के राष्ट्रपति का भारत में सरकारी दौरा (10–11 दिसंबर, 2014) रुस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम ब्लादिमीर पुतिन से 11 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में हाथ मिलाते हुए प्रधान मंत्री।

रुस संघ सरकार के उप प्रधानमंत्री महामहिम श्री दामित्री ओ. रोगोजिन से 18 जून, 2014 को नई दिल्ली में भेंट करती हुईं विदेश मंत्री।

की यात्रा की थी। दोनों देशों के बीच उर्जा सहयोग के विकास के लिए विकास लगातार जारी है। पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21वें विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस(WPC) में भाग लेने के लिए 18–21 जून, 2014 तक रूस की यात्रा की थी तथा इस कांग्रेस में भारतीय दीर्घा का उद्घाटन किया था। इन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर वार्ता करने के लिए रूसी उर्जा मंत्री श्री एलेक्जेंडर नोवाक से भी मुलाकात की थी। पहले मई 2014 में, आर्कटिक शेल्फ में तेल तथा गैस अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग हेतु ONGC तथा रूस के रोजनेफ्ट ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। एयर इंडिया ने लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद 18 जुलाई, 2014 से मास्को के लिए उड़ाने शुरू की।

इस वर्ष के दौरान शुरू की गई विशिष्ट परियोजनाओं में प्रगति, वार्ता तथा सहयोग के लिए रक्षा सहयोग जारी रखा गया है। 7वें भारत–रूसी उच्च स्तरीय मॉनीटरिंग (HLMC) बैठक का आयोजन जून 2014 को नई दिल्ली में किया गया; 14वें मिलिटरी प्रौद्योगिकी सहयोग (MTC) कार्य दल की बैठक का आयोजन सितंबर 2014 को नई दिल्ली में किया गया; 14वें द साल्स (SALS) कार्य दल बैठक का आयोजन अक्तूबर 2014 में नई दिल्ली में किया गया था। प्रधानमंत्री ने रूस में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को जून 2014 में राष्ट्र को समर्पित किया था। दोनों देशों की नौसेना, वायु–सेना तथा थल–सेना ने रूस में संयुक्त मिलिटरी अभ्यास किया था–इंद्र नेवी 2014 (जुलाई), आविया इंद्र 2014 (अगस्त) तथा थल–सेना अभ्यास के लिए इंद्र आर्मी 2014(सितंबर)। NCC प्रतिनिधिमंडल ने वार्षिक 'युवा विमय कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए अगस्त, 2014 में रूस की यात्रा की थी।

24–26 सितंबर, 2014 तक मास्को में आयोजित 'भारत शो' प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में वाणिज्य सचिव ने भाग लिया था, जिसे लगभग 100 भारतीय कंपनियों की भागीदारी से आयोजित किया गया था, इसमें मुख्य तौर पर फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा, वस्त्र तथा कपड़ा क्षेत्र की कंपनिया शामिल थीं। द्विवार्षिक 'वाइब्रेंट गुजरात–2015' के प्रचार के लिए सितंबर 2014 में गुजरात के एक प्रतिनिधिमंडल ने मास्को तथा सैंट पीटर्सबर्ग की यात्रा की थी। कृषि तथा परिष्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने सितंबर 2014 में मास्को में आयोजित विश्व फूड एक्सपो में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। गोवा पर्यटन तथा भारत पर्यटन सहित 18 कंपनियों के पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सितंबर 2014 में मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला में भाग लिया था।

सांस्कृतिक, पर्यटन, शैक्षिक आदान–प्रदान तथा लोगों का लोगों से संपर्क लगातार उपरिगामी प्रवाह का साक्षा है। ICCR द्वारा प्रायोजित पंजाबी लोक–नृत्य तथा संगीत दल ने अक्तूबर 2014 में मास्को, कालुगा, कुर्सक तथा तारूसा शहरों की यात्रा की थी।

सितंबर 2014 में दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के अंत में, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने रूसी विदेश मंत्री श्री गर्गेई लावसेव से मुलाकात की थी। भारत ने SCO शिखर सम्मेलन बैठक के समक्ष SCO सदस्यता का अपना अनुरोध प्रस्तुत किया था।

रूसी उप प्रधानमंत्री (DPM) श्री दमित्री रागोजीन तथा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 5 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में व्यापार, आर्थित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक सहयोग (IRIGC-TEC) पर भारत–रूस अंतर्सरकारी समिति की सह–अध्यक्षता की थी। DPM श्री दमित्री रोगोजीन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात किया था। संबंधित क्षेत्रों में सहयोग एवं अवसर के आकलन हेतु व्यापार तथा आर्थिक सहयोग; निवेश; आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक सहयोग; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति एवं पर्यटन; खनन पर उप–समूह; नागरिक उड्डयन, बैंकिंग, उर्वरक पर कार्य–दलों ने समिति की बैठक से पूर्व मुलाकात की।

आर्थिक, संस्कृति, शिक्षा, इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए रूस के विभिन्न क्षेत्रों तक मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी पहुंच दर्ज की है, इसके लिए वे रूस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के लिए उन क्षेत्रों की यात्रा तथा उनके साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से संपर्क बना रहे हैं। दूतावास ने मास्को में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

दोनों देशों के आर्थिक आकार तथा क्षमताओं की तुलना में भारत तथा रूस के बीच का द्विपक्षीय संबंध साधारण है। 2013 में द्विपक्षीय व्यापार की राशि 10 बिलियन अमरीकी डालर थी। (रूस से आयातः 8 बिलियन अमरीकी डालर; रूस को निर्यात 2 बिलियन अमरीकी डालर)।

बेलारूस

भारत–बेलारूस का द्विपक्षीय संबंध पारंपरिक तौर पर गर्मजोशी एवं सौहार्दपूर्म है। बेलारूस ने 2014–18 की अवधि के लिए "अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतर–सरकारी समिति" के चुनावों के लिए भारत की उम्मीदवारी को अपना समर्थन दिया था। मनी लांडरिंग तथा आतंकवाद के वित्त–पोषण से संबंधित सूचना के आदान प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन पर यूरेशियाई दल के प्लेनेरी सत्र के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जो मनी लांडरिंग तथा आतंकवाद के वित्त–पोषण का विरोध करते हैं। सात अन्य देशों के साथ–साथ भारत तथा बेलारूस इसके सदस्य हैं। युद्ध में बचे हुए विस्फोटकों की अनापत्ति हेतु (ERWS) बेलारूस की सहायता के अंतर्गत भारत ने बेलारूस को 90 रेडियो सेट तथा 30 GPS नेवीगेटर की आपूर्ति की और 25 माईन डिटेक्टर की मंजूरी दी।

वर्ष 2012 में 498.575 मिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में 2013 में यह 35.312 मिलियन डालर रहा। भारत को उर्वरकों की बिक्री में कमी तथा भारत से आयात में कमी के कारण द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट हुई। भारतीय दूतावास ने बेलारूस में श्री सोमनाथ रॉय के नेतृत्व में ICCR द्वारा प्रायोजित 5 सदसियों के संगीत समूह 'घटम' सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

यूक्रेन

यूक्रेन में जो आंतरिक संकट 2013 के अंत में शुरू हुआ था, वह 2014 में भी जारी है। इस वर्ष की शुरूआत में जिस अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली थी उसे शीघ्र ही विश्व की प्रमुख शक्तियों ने मान्यता दे दी तथा उसके पश्चात मई 2014 में नए राष्ट्रपति श्री पेट्रो पोरोशेंको के चयन से वहां की राजनीतिक स्थिति को स्थिर बनाने में सहायता मिली थी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को बधाई संदेश भेजा था।

यूक्रेन के पूर्वी भाग में सुरक्षा की खराब होती स्थिति तब और खराब हो गई जब जुलाई 2014 में रूस के सीमावर्ती क्षेत्र में मलेशियाई यात्री उड़ान को मार गिराया गया तथा इसके सभी 298 यात्री मारे गए। भारत ने इस जेट को मार गिराए जाने की निंदा की तथा पीड़ितों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की।

पूर्वी यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती स्थिति के बीच, कीव स्थित भारतीय दूतावास ने यूक्रेन सरकार के सक्रिय सहयोग से जून 2014 में लगभग 1000 भारतीय छात्रों (तथा इनमें से कुछ सार्क देशों के) को लुंगास्क से कीव उन्हें दो ट्रेनों की व्यवस्था करके सफलतापूर्वक वापस लाए। दूतवास ने कीव में उनके रहने की व्यवस्था की और भारत तक की यात्रा की भी व्यवस्था की।

दूतावास ने कीव में कुछ संस्थानों में हिंदी शिक्षण हेतु सुविधा प्रदान किए जाने का समर्थन किया। दूतावास ने भारतीय फिल्मों को यूक्रेन में दिखाए जाने के लिए वहां की राष्ट्रीय टेलीविजन कंपनी के साथ एक करार पर भी हस्ताक्षर किए थे।

दक्षिण कॉकाशस

भारत ने दक्षिणी कॉकाशस में अर्मेनिया, जॉर्जिया तथा अजरबेजान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना जारी रखा है। ये देश यूरोप तथा एशिया के बीच क्रॉसरोड़ पर स्थित हैं तथा ये इस क्षेत्र तथा यूरोप से आगे जमीनी संपर्क तथा उर्जा परिवहन/पारेषण लाइनों का महत्तवपूर्ण भाग भी हैं। यहां व्यापार, पर्यटन, शिक्षा तथा संस्कृति को बढ़ाए जाने के लिए दोनों ओर से कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

आर्मेनिया

आर्मेनिया में टेलीमेडिसन नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारत ने 24 जून, 2014 को येरेवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री श्री होविक अब्राहमयान की उपस्थिति में 29 अगस्त, 2014 को, वेऑट्स द्जोर में 50 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए समझोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अर्मेनिया का यह दूसरा क्षेत्र होगा जहां भारत से यह सुविधा प्राप्त की गई है। मई 2014 में मुंबई में आयोजित फार्मास्यूटिकल्स प्रदर्शनी IPHEX 2014 में अर्मेनिया की 14 कंपनियों ने भाग लिया था।

येरेवान स्टेट लिंग्यूस्टिक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाया जाना जारी है तथा यूनिवर्सिटी में 30 मई, 2014 को विश्व हिंदी दिवस–2014 का आयोजन किया गया था। मिशन ने येरेवान में विभिन्न सासंकृतिक कार्यकलापों को भी बढ़ावा दिया है तथा "मेक इन इंडिया" का प्रस्तुतीकरण भी शुरू किया है।

वर्ष 2013 में द्विपक्षीय व्यापार 67 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ा, जिसमें से अर्मेनिया से भारत में आयात 1.45 मिलियन अमरीरी डालर था। भारत से अर्मेनिया निर्यात किए जाने वाले मुख्य मदों में फ्रोजन बोवाइन मीट शामिल है।

अजरबेजान

यूरोप को जार्जिया तथा तुर्की के रास्ते से अजेरी गैस प्रदान किए जाने की परियोजना "दक्षिणी गैस कॉरीडोर" की भूमि खोदने के समारोह का आयोजन 30 सितंबर, 2014 को बाकू में किया गया था। ONGC विदेश लि. (OVL) के एक भागीदार के रूप में भारत पैट्रोलियम (BP) के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय कांसोर्टियम के द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन ने 'मेक इन इंडिया' परियोजना की शुरूआत के साथ ही 25 सितंबर 2014 को व्यवसाय सप्ताह का भी आयोजन किया था। संगीत नाटक अकादमी के 20 सदस्यों के दल ने शेकी सिटी में "सिल्क वे" अंतर्राष्ट्रीय संगीत उत्सव में भारतीय संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया था।

2013 में, 1.098 बिलियन अमरीरी डालर के अजेरी निर्यात तथा 49. 7 मिलियन अमरीकी डालर के भारतीय निर्यात के साथ अजरबेजान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1.148 बिलियन अमरीरी डालर था।

जार्जिया

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक सहयोग पर भारत–जार्जिया अंतर–सरकारी आयोग (IGC)

का पहला सत्र 29 अप्रेल, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री दीनकर खुल्लर, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय ने किया था तथा जॉर्जिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के उप–विदेश मंत्री श्री डेविट जालागानिया ने किया था। इस विचार–विमर्श का केंद्र–बिंदु दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश, उर्जा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कोंसुली मुद्दे, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा फार्मास्यूटिकल्स, तथा कृषि होगा। जॉर्जिया की ओर से भारतीय कंपनियों द्वारा जॉर्जिया के कृषि, उर्जा, स्टील तथा तेल अन्वेषण के क्षेत्रों में किए गए निवेश को नोट किया गया है। इस सत्र में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई मजबूत प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया गया था। दोनों ओर से विशेष तौर पर फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि तथा पर्यटन में सहयोग को बढ़ाने की क्षमता को नोट किया गया।

IGC सत्र के पश्चात FICCI में व्यापार मंच आयोजित किया गया, जहां दोनों देशों में मौजूद व्यापार एवं निवेश के अवसरों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया था। परस्पर लाभ के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक हितों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर परिसंघ तथा जॉर्जियाई वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मध्य एशिया

कनेक्ट मध्य एशिया पॉलिसी में दिए गए उद्देश्यों के अनुसरण में, भारत ने मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना जारी रखा है। व्यापार प्रतिनिधिमंडलो की यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा रक्षा लेन–देन के द्वारा उच्च स्तर पर परस्पर बातचीत हुई थी। तीसरा ट्रैक–II भारत–मध्य एशिया वार्ता 10 अक्तूबर, 2014 को दुशांबे में आयोजित किया गया था। इस वार्ता में लगभग 75 देशों के लोगों ने भाग लिया था, जिसमें अलग प्रकार से तटस्थ तुर्कमेनिस्तान की सहभागिता भी शामिल है। मंत्रालय के भारतीय प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक (ITEC) योजना के तहत लगभग 420 छात्रवृत्ति तथा ICCR के तहत 100 छात्रवृत्ति वर्ष 2014–15 के लिए मध्य एशिया को आबंटित किया था। इन देशों ने इन छात्रवृत्तियों की काफी सराहना की है तथा मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण में उन्हें सहयोग दिया है।

मध्य एशियाई क्षेत्र में मुख्य दलों के साथ मध्य एशिया वार्ता के द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र के तहत मंत्रालय ने मई तथा जून 2014 में नई दिल्ली में यू.एस. के साथ वार्ता आयोजित की थी।

कजाकिस्तान

भारत तथा कजाकिस्तान के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक संबंध पर अंतर–सरकारी आयोग की ग्यारहवीं बैठक 20–30 अप्रैल, 2014 को अस्टाना में आयोजित किया गया था। भारत की ओर से आयल एंड गैस मंत्रालय के सचिव श्री सौरभ चंद्रा ने इसका नेतृत्व किया था तथा कजाकिस्तान की ओर से वहां के आयल एंड गैस उप–मंत्री श्री मैगजम मिर्जालीएव माराटोविक ने नेतृत्व किया था। IGC बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई थी तथा व्यापार, वाणिज्य, उर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कोंसुली मामले, संपर्क, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, खनन, वस्त्र, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के और अधिक क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया गया था।

तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने अस्टाना में 02–05 मई, 2014 तक आयोजित 47वें गवर्नरों की बार्षिक बोर्ड बैठक में भाग लेने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

05–08 नवंबर, 2014 को अलमाटी में आयोजित "वर्ल्ड फूड एक्सपो' में एसोचेम के 45 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था।

विदेश राज्य मंत्री (VKS) ने 15 दिसंबर 2014 को अस्ताना में आयोजित शंघाई को–आपरेशन आर्गेनाइजेशन (SCO) सरकार प्रमुखों की बैठक के अवसर पर कजाक प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।

किर्गिज गणराज्य

भारत तथा किर्गिज गणराज्य के बीच राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था स्थापित करने का करार 23 अप्रेल, 2014 से लागू किया गया था।

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली से मेजर जनरल अनुराग के नेतृत्व में 16 सदस्यों के दल ने 11–16 मई, 2014 तक किर्गिज की यात्रा की। उन्होंने वहां के उप–रक्षा मंत्री तथा उप–विदेश मंत्री से मुलाकात की थी।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने UNGA के 69वें सत्र के अवसर पर 24 सितंबर, 2014 को न्यूयार्क में किर्गिज विदेश मंत्री श्री एलनि अब्दीलदाएव के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित की थी।

ICCR द्वारा प्रायोजित 10 सदस्यों के भांगडा नृत्य दल "भोला पंछी" ने 18 अक्तूबर, 2014 को बिश्केक में तथा 19 अक्तूबर, 2014 को कारा–बाल्टा में अपना प्रस्तुतीकरण दिया था। मिशन ने बिश्केक में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था।

रक्षा मंत्री तथा सचिव (रक्षा R & D) के डॉ. अविनाश चंदर के नेतृत्व में पांच सदस्यों के DRDO प्रतिनिधिमंडल ने भारत–किर्गिज द्विपक्षीय सहयोग पर विचार–विमर्श करने के लिए तथा बिश्केक एवं तूया आशु में हाई आल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर का मॉनीटर करने के

लिए 25–28 अक्तूबर, 2014 तक किर्गिज गणराज्य की यात्रा की थी।

तजाकिस्तान

भारत तथा तजाकिस्तान एक समान इतिहास साझा करते हैं, जिसने मजबूत द्विपक्षीय संबंध स्थापित किया है। विदेश कार्यालय परामर्श, आतंकवाद के विरोध, व्यापार तथा रक्षा पर कई परामर्शी तंत्र स्थापित हैं।

विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने द्वितीय विदेश कार्यालय परामर्शी के लिए 07–09 मई 2014 तक दुशांबे की यात्रा की थी और अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपतिश्री ईमोमाली रहमान से मुलाकात किया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 10–12 सितंबर, 2014 तक दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) प्रमुखों के परिषद में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

भारत, तजाकिस्तान तथा अन्य मध्य एशियाई देशों के लगभग 75 विद्वानों ने 10 अक्तूबर, 2014 को दुशांबे में आयोजित थर्ड ट्रैक–II भारत–मध्य एशिया वार्ता में भाग लिया था। भारत तथा मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढाए जाने के लिए विद्वानों ने सिफारिशें कीं तथा सुझाव दिए थे। इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA), नई दिल्ली तथा एकेडेमी ऑफ साइंसेज, तजाकिस्तान गणराज्य द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

तुर्कमेनिस्तान

TAPI (तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत गैर पाइपलाईन परियोजना) के 26वें तकनीकी कार्य दल का आयोजन 06–07 जुलाई, 2014 तक अश्गाबात में किया गया था और इसके ठीक बाद 08 जुलाई, 2014 को संचालन समिति बैठक (SCM) का आयोजन किया गया था। संचालन समिति बैठक (SCM) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, श्री सौरभ चन्द्र ने किया।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 14वें हेड्स ऑफ स्टेट समिट ऑफ दे SCO के अवसर पर 12 सितंबर, 2014 को दुशांबे, ताजकिस्तान में तुर्कमेन राष्ट्रपति श्री गुरबांगुली बर्डीमुहामेडोव के साथ द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया था।

लोक संगीत एवं नृत्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव तथा 'भारत में तुर्कमान संस्कृति के दिन' में भाग लेने के लिए 30 सदस्यों के तुर्कमान सासंकृतिक दल ने 12–18 अक्तूबर, 2014 तक भारत (नई दिल्ली तथा जयपुर) की यात्रा की थी।

TAPI के 19वें संचालन समिति की बैठक 19–20 नवंबर, 2014 को अश्गाबात में आयोजित की गई थी। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

लगभग 849 भारतीय नागरिक तुर्कमेनिस्तान में रहते हैं, इसमें से अधिकतर तेल तथा गैस और निर्माण के क्षेत्र में अर्ध–कुशल कामगार हैं। इनमें तेल तथा गैस के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर तथा तकनीशियन भी हैं। ये भारतीय या तो विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं अथवा भारतीय कंपनी (पंपोस निर्माण प्रा. लि.) द्वारा सीधे नियुक्त किए गए हैं, जो तुर्कमेनिस्तान में फ्रेंच कंपनी के लिए निर्माण श्रमिक उपलब्ध करवा रहे हैं।

उजबेकिस्तान

भारत के सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने ताशकंद की यात्रा की तथा समरकंद में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) कार्यकारी परिषद के 99वें सत्र में पर्यटन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था।

21 दिसंबर, 2014 को उजबेक संसदीय चुनावों का आयोजन किया था तथा 31 दिसंबर, 2014 को परिणामों की घोषणा की गई थी। उजबेक चुनाव आयोग के द्वारा उजबेक चुनावों में पर्यवेक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए राजनय, राजनीति, अकादमिक तथा मीडिया के क्षेत्र के जाने–माने भारतीयों को आमंत्रित किया गया था। उजबेक प्रेसीडेंसियल चुनावों के लिए 29 मार्च, 2015 को निर्धारित किया गया है।

2013 में द्विपक्षीय व्यापार की राशि 259.6 मिलियन अमरीकी डालर थी। इस वर्ष के दौरान एसोशिएटेड चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एस्सोचैम), केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स तथा कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (CHEMEXCIL) तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) के प्रतिनिधिमंडलों ने ताशकंद की यात्रा की थी।

■■

तजाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री इमोमाली रहमोन के साथ दुशान्बे में भेंट करती हुईं विदेश मंत्री।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति श्री वलादीमीर पुतिन के साथ प्रधान मंत्री की द्विपक्षीय बैठक।

खाड़ी तथा पश्चिमी एशिया

5

खाड़ी देश

सभ्यता संबंधों के आधार पर भारत के खाड़ी देशों के साथ पारस्परिक तौर पर घनिष्ट संबंध हैं तथा लोगों का लोगों से वायब्रैंट संबंध है। मित्रता के संबंधों को राजनीतिक, व्यापार तथा वाणिज्यिक स्तर पर यात्राओं के नियमित आदान–प्रदान द्वारा और सुदृढ़ किया गया है। खाड़ी क्षेत्र विश्व में भारत का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र बन गया है और 2013–14 में द्विपक्षीय व्यापार 171.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। खाड़ी क्षेत्र भारत को कच्चे तेल और एल एन जी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है तथा भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 60 प्रतिशत वहां से आता है। भारत के मुख्य पांच तेल प्रदाता देशों में से चार खाड़ी क्षेत्र के देश– सऊदी अरब, इराक, कुवैत तथा यू ए ई हैं। खाड़ी देशों में लगभग 7 मिलियन भारतीय रहते हैं जो अपने मेजबान देशों के विकास में योगदान दे रहे हैं।

बहरीन

बहरीन अधिराज्य के साथ हमारे मित्रवत तथा बहुआयामी संबंध हैं, जो भारतीय प्रवासियों का मनपसंद गंतव्य स्थान बना हुआ है जिसे निरंतर उच्च–स्तरीय राजनीतिक यात्राओं से आगे और मजबूत किया जा रहा है। विदेश तथा प्रवासी भारतीय मामले मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 06–07 सितंबर 2014 को बहरीन अधिराज्य की यात्रा की। उन्होंने प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र (OIFC) द्वारा आयोजित भारतीय डायस्पोरा संपर्क बैठक के उद्घाटन में भाग लिया तथा शीर्ष बहरीनी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय निर्वासित समुदाय द्वारा आयोजित ओणम समारोह में भी इन्होंने भाग लिया था। यात्रा के दौरान, OIFC ने बहरीन आर्थिक विकास बोर्ड तथा बहरीन भारतीय सोसायटी के साथ दो करारों पर हस्ताक्षर किए थे।

22 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली भारत–बहरीन उच्च संयुक्त समिति की पहली बैठक के लिए बहरीन अधिराज्य के विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अहमद बिन मोहम्मद अल खलीफा भारत की यात्रा करेंगे।

भारत तथा बहरीन के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर 20 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (खाड़ी) तथा बहरीन का नेतृत्व अरब एवं अफ्रो–एशियाई कार्य तथा संगठन, विदेश मंत्रालय हेतु सहायक अवर सचिव डॉ. राणाबिंत ईस बिन दुआईज अल खलीफा ने किया था।

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भल्ला महानिदेशक (रक्षा आसूचना एजेंसी) ने 17–19 नवम्बर 2014 को बहरीन की आधिकारिक यात्रा की थी तथा बहरीनी सशस्त्र बल के सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अदमद अल खलीफा से मुलाकात की थी।

ईरान

भारत के "आर्थिक एवं सुरक्षा क्षेत्र" की भागीदारी में ईरान एक महत्वपूर्ण देश है। भारत उर्जा संसाधन का बड़ा एवं विकासशील खरीददार है, तथा ईरान एक बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है इसलिए भविष्य में निकट उर्जा सहयोग संबंध के निर्माण का अच्छा आधार होगा।

ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों में लगातार विस्तार हो रहा है। अप्रेल–सितंबर 2014 की अवधि के लिए भारत–ईरान व्यापार 7.35 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के द्विपक्षीय व्यापार में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत से चैंवर्स ऑफ कॉमर्स (FICCI, ASSOCHAM, CII) ने ईरान के साथ विनिमय को बनाए रखना जारी है।

भारत ने चाहबहार पोर्ट के विकास में हमारी भागीदारी पर ईरान के साथ भारत के विचार–विमर्श में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अक्तूबर, 2014 में, पोर्ट परियोजना में भागीदारी के लिए अनापत्ति पर कैबिनेट से सहमति जताई है तथा समझौता ज्ञापन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए और विचार–विमर्श जारी है।

भारत ने 8–14 अगस्त 2014 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण पारगमन गलियारे (INSTC) के आस–पास एक सफल ट्रायल–रन का आयोजन किया जिसमें बांदर अब्बास–अस्तारा और बांदर अब्बास–अमीराबाद मार्ग शामिल है।

चाहबहार और INSTC में हमारी भागीदारी का उद्देश्य अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के लैंड–लॉग्ड देशों के साथ संपर्क बढ़ाना है।

इस अवधि के दौरान भारत और ईरान के बीच प्रमुख उच्च स्तरीय आदान–प्रदान/वार्ता में निम्नलिखित शामिल हैं:–

श्री सतीश मेहता, महानिदेशक, ICCR ने 24 जुलाई 2014 को तेहरान की यात्रा की और ईरानी सांस्कृतिक विरासत हस्त–कला

तथा पर्यटन संगठन (ICHHTO) के प्रमुख श्री मसूद सुल्तानीफर से मुलाकात की। ICCR तथा ICHHTO के बीच भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संपर्क और सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री सतीश मेहता ने श्री इब्राहिम रहीमपुर ईरान के उप–विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

डॉ. अब्बास अखौंदी, ईरान इस्लामिक गणराज्य के सड़क एवं विकास मंत्री ने सार्क शिखर सम्मेलन के 18वें सत्र के अवसर पर नवंबर 2014 में भारत की यात्रा की। श्री अखौंदी ने जहाजरानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गडकरी से 25 नवंबर, 2014 को मुलाकात की और रेलवे मंत्री श्री प्रभु से 28 नवंबर, 2014 को मुलाकात की।

इराक

इराक के साथ ऐतिहासिक, घनिष्ठ तथा बहुआयामी संबंध हैं। इराक कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है इसलिए हमारी उर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

बसरा के लिए सीवरेज सिस्टम के पुनर्निर्माण मै. मोकुल–श्रीराम JV को 235 मिलियन अमरीकी डालर, की संविदा; नसिरीयाह पावर के निर्माण हेतु BGR एनजी EPC द्वारा 246 मिलियन अमरीरी डालर की संविदा; आकाज विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए मै. लैंको इंफ्राटेक द्वारा 81 मिलियन अमरीकी डालर की संविदा तथा बसरा में होटल के पुनर्निर्माण हेतु मै. शापूर्जी पोलौंजी को 85 मिलियन अमरीकी डालर की संविदा सहित कई भारतीय कंपनियों को इराक में ई पी सी संविदाएं प्रदान की गई हैं।

क्षमता निर्माण की शर्तों के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सहयोग(ITEC) के तहत भारत द्वारा इराक को 80 स्लाट; 'सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना' (CEP) तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के द्वारा आयोजित 'सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 55 स्लाट प्रदान किए गए हैं।

जून 2014 की शुरूआत में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड एल शाम द्वारा अचानक आक्रमण करके उत्तरी तथा पश्चिमी इराक के कई शहरों पर कब्जा करने के कारण वहां की कमजोर सुरक्षा स्थिति भारत की चिंता का मुख्य कारण था। सरकार की चिंता का मुख्य कारण इराक में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा थी। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित तौर पर भारत पहुंचाए जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे, विशेष तौर पर संकट ग्रस्त क्षेत्र से उन्हें निकालने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की गई थी। 1 दिसंबर, 2014 तक 7000 भारतीय नागरिकों को वापसी में सहायता प्रदान किया गया था, जिसमें से 6000 को हवाई टिकट भी प्रदान किए गए थे।

इजराइल

गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 05–07 नवंबर, 2014 तक इजराइल की यात्रा की थी। इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतानयाहू सहित इजरायली नेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया था। गृह मंत्री की यात्रा का उद्देश्य होमलैंड क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग को और आगे बढ़ाना था। इन बैठकों के दौरान गृह मंत्री ने 'मेक इन इंडिया' की नई औद्योगिक नीति उपायों का लाभ उठाने के लिए इजरायली उद्योगों को भी आमंत्रित किया था।

होम लैंड सुरक्षा पर भारत–इजराइल संयुक्त संचालन समिति का उद्घाटन बैठक 21–23 सितंबर 2014 को इजराइल में आयोजित किया गया था। भारत तथा इजराइल के बीच फरवरी 2014 में होमलैंड एवं लोक सुरक्षा मुद्दे में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए करार में किए गए प्रावधानों के अनुसार होमलैड सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के समन्वय के लिए संचालन समिति का गठन किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में चार कार्य दलों को गठित किए जाने पर दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव श्री राजीव गउवा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

तेलअवीव में 20–22 मई, 2014 में आयोजित प्रथम इजराइली इनोवेशन कांफ्रेंस, एमआईएक्स iii में भारत ने सबसे बड़ा कंट्री पैवेलियन लगाया था। भारतीय पैवेलियन में निजी कंपनियों, छोटे एवं मध्यम उद्यमों, सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों, व्यापार संवर्धन विभागों तथा वैंचर कैपिटल फर्मों सहित 35 से अधिक भारतीय कंपनियां शामिल हुई थीं। इन पैवेलियनों को भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा कर्नाटक, केरल, गुजरात, एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से वित्त पोषण प्राप्त हुआ था।

दूतावास ने भारतीय यहूदी समुदाय के सहयोग से 14 अक्तूबर, 2014 को येरूहाम में द्वितीय भारतीय यहूदी राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया था। इस आयोजन में समृद्ध भारतीय यहूदी विरासत को दर्शाया गया था तथा इसमें सभी चारों भारतीय यहूदी समुदायों– बेने इजराइली, कोचीनी, बगदादी तथा बेने मेनाशे से लगभग 3500 लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली थी।

रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य दल की ग्यारहवीं बैठक का आयोजन 30 जून, 2014 को इजराइल में किया गया था। इस बैठक का आयोजन सौहार्दपूर्ण तथा खुले वातावरण में किया गया था, तथा इसमें परस्पर हित के कई शीर्षकों पर विचार–विमर्श किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री आर. के. माथुर ने किया था तथा इजराइल का नेतृत्व इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डैन हरेल ने किया था।

इजराइल के कृषि मंत्री श्री याईर शमीर ने "बाईब्रेंट गुजरात सम्मिट 2015" में भाग लेने के लिए जनवरी 2015 में इजराइली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इस अवसर पर, श्री याईर शमीर ने गुजरात में प्रधानमंत्री, कृषि राज्य मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने वर्ष 2015–18 के लिए कृषि

सहयोग परियोजना के तीसरे चरण के कार्यान्वयन हेतु करार पर हस्ताक्षर किए थे।

जॉर्डन

मृत सागर (Dead Sea) में 07–08 नवंबर, 2014 को आयोजित नवीकरणीय उर्जा पर संसदीय कार्रवाई में सांसदों एवं विधायकों के 8 सदस्यों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। संबंधित देशों की उर्जा नीतियों पर आधारित इस आयोजन को जलवायु संसद तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

आठ वर्षों से अधिक के अंतराल के पश्चात, 01 अप्रैल 2014 को अम्मान में भारत तथा जॉर्डन के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव(पूर्व) श्री अनिल वाधवा ने किया था जबकि जॉर्डन का नेतृत्व जॉर्डन हशमीते अधिराज्य के विदेश कार्य एवं एक्सपैट्रीएट्स मंत्रालय के महासचिव श्री मोहम्मद तैसीर बानी यासीन ने किया था। दोनों ओर से द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण गैमुट (gamut) पर रचनात्मक विचार–विमर्श किया गया था, जिसमें विशेष तौर पर राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक, उर्जा एवं संस्कृति तथा लंबित मुद्दों की भी समीक्षा की गई थी। श्री अनिल वाधवा, सचिव(पूर्व) ने 22–23 जुलाई, 2014 को दोबारा अम्मान की यात्रा की थी। इस बार इस यात्रा का प्रयोजन इराक में घटे घटनाओं पर नजर रखने के लिए तथा इस क्षेत्र में उसकी विफलता और साथ–साथ इराक में फंसे भारतीय नागरिकों के संबंध में था।

व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में, इसके पड़ोसी क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रतिकूलता एवं संघर्षों के बावजूद हमारे द्विमार्गी व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगस्त 2014 की स्थिति के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार 1.09 बिलियन अमरीकी डालर है जो अधिकतर भारत के पक्ष में है। भारतीय निर्यात संगठन संघ (FIEO) संयुक्त उप–निदेशक के नेतृत्व में 16 सदस्यों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 26–28 मई, 2014 तक अम्मान की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से FIEO तथा ACC ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। FEIO के तहत 36 भारतीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए 60 सदस्यों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 22–25 सितंबर, 2014 तक आयोजित "इंटरबिल्ड फेयर–2014" में भाग लिया था। जॉर्डन के प्रधानमंत्री श्री अब्दुल्ला एनसौर ने भारतीय राजदूत श्री अनिल त्रिगुनायत के साथ "भारतीय पैवोलियन" का उद्घाटन किया था।

27 अक्तूबर, 2014 को भारत सरकार की ओर से न्यूयार्क स्थित हमारे मिशन ने जनवरी 2014 में कुवैत सम्मेलन में वचन दिए गए अनुसार निधियों में से जॉर्डन के लिए इमरजेंसी रेसपोंस फंड के लिए न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र को 0.5 मिलियन अमरीकी डालर का चैक सुपुर्द किया था।

ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अलहराहशेह के नेतृत्व में शाही जॉर्डनियन राष्ट्रीय रक्षा कालेज से 14 सदस्यों के सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल ने 14–17 अप्रेल, 2014 तक भारत की यात्रा की थी।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के आमंत्रण पर जाहा सांस्कृतिक केंद्र, ग्रेटर अम्मान म्यूनिसिपलिटी के 12 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने 21–23 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित "वर्ल्ड परकशन फेस्टिवल" में भाग लिया था।

भारतीय प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत जॉर्डनियन उम्मीदवारों के लिए वर्ष 2014 में निर्धारित सभी 20 स्लाटों का जॉर्डन ने उपयोग कर लिया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली जॉर्डनियन छात्रों को पांच वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव दिया है। भारत द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण अवसरों का जॉर्डनियन नागरिकों ने अच्छा प्रयोग किया है।

कुवैत

भारत तथा कुवैत के बीच निकट, बहुआयामी तथा मित्रवत संबंधों को इस वर्ष के दौरान और प्रगाढ़ किया गया था। कुवैत के उप–प्रधानमंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री डॉ. अब्दुलमोहसिन मोदाज अल–मेदाज ने 26–27 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित चौथे भारत अरब साझेदारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी।

विदेश कार्यालय परामर्श के दूसरे दौर (11 सितंबर, 2014), श्रम रोजगार एवं मानव शक्ति विकास पर संयुक्त कार्य दल की चौथी बैठक, (16 जून, 2014) तथा हाइड्रोकार्बन पर संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक (24–25 जून, 2014) सहित संस्थागत तंत्र के मौजूदा ढांचा के तहत द्विपक्षीय बैठकों का आयोजिन कुवैत में किया गया था।

CMD BPCL श्री एस. वरदराजन के नेतृत्व में 6 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के साथ कच्चे तेल की वार्षिक खरीद संविदा पर हस्ताक्षर के लिए 27 अप्रैल, 2014 को कुवैत की यात्रा की थी। CMD, ONGC श्री डी. के. सर्राफ ने भारतीय तेल क्षेत्र में कुवैती निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए 17–18 जुलाई, 2014 को कुवैत की यात्रा की थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से CII ने 22–24 सितंबर, 2014 तक कुवैत में "भारत पैवेलियन" का आयोजन किया था।

लार्सन एंड ट्रबो, शापूरजी पलोंजी, डोडसाल, पुंज लॉयड, सिंपलेक्स, एफकॉन्स सहित कुछ अग्रणी भारतीय कंपनियों को इस वर्ष के दौरान 3 बिलियन अमरीकी डालर की EPC संविदाएं प्रदान की गई थी।

CSIR तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14–16 अप्रेल, 2014 तक कुवैत की यात्रा की थी। कुवैत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटीफिक रिसर्च (KISR) तथा अर्थ सिस्टम साइंस आर्गेनाइजेशन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच 16

अक्तूबर, 2014 को द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस वर्ष के दौरान INS मैसूर ने इराक के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की आकस्मिक योजना के भाग के तौर पर कुवैत की तीन यात्राएं की थी।

सुश्री सोनम कालरा के नेतृत्व में ICCR द्वारा प्रायोजित फ्यूजन दल ने (सूफी गोस्पेल परियोजना) सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरणों के लिए 16–17 सितंबर, 2014 तक कुवैत की यात्रा की थी।

लेबनान

राजनीतिक अस्थिरता के कारण, लेबनान की सरकार, मार्च 2013 से लंबित तेल तथा गैस उत्खनन को दोबारा शुरू करने तथा लगातार खराब होती सुरक्षा स्थिति से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक तथा अवसंरचनात्मक समस्याओं से जूझने एवं सीरिया तथा इराक (फिलीस्तीनी शरणार्थियों सहित) से शरणार्थियों के आगमन से जो लेबनान की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत है सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहा है।

भारतीय निर्यात संगठन संघ (FIEO) के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने मई 2014 में लेबनान की यात्रा की थी तथा सईदा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए थे। मिशन ने स्थानीय प्रदर्शनियों में भारतीय दूतावास द्वारा प्रायोजित स्टॉल में भारतीय हस्तशिल्प तथा चाय प्रोमोशनल आयोजनों को आयोजित किया तथा अकेले भारतीय भाजार में भी भारतीय खाद्य उत्सव एवं नृत्य, संगीत व प्रदर्शनियों (भारत में इस्लामिक वास्तुशिल्प तथा साडियों के फोटोग्राफ्स) के विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन केवल बेरूत ही नहीं बल्कि सईदा, टायर और त्रिपोली में भी किए थे, ये आयोजन उस दौरान भी किए गए, जब अर्सल क्षेत्र में त्रिपोली तथा उसके आसपास ISIS/अलनुसरा फ्रंट के आतंकी और लेबनान की सेने के बीच संघर्ष जारी था।

भारत तथा लेबनान के बीच सांस्कृतिक विनिमय करार कार्यक्रम के तहत ICCR द्वारा प्रायोजित सूफी गोस्पेल परियोजना की मेजबानी लेबनान ने की थी, जिसकी वर्ष 2000 में अभिपुष्टि की गई थी। सूरजकुंड मेला–2015 में लेबनान के भाग लेने के लिए सहमत होने से लेबनान तथा भारत के बीच व्यापार एवं संस्कृति दोनों ही क्षेत्रों में संबंध और अधिक मजबूत होने का अनुमान है।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में भारतीय सैन्य दल लगातार प्रभावी तौर पर कार्य चालन के इसके क्षेत्र में तनावों से जूझ रहा है, जिसमें गोलन हाईट्स तथा शीबा फार्म शामिल हैं। UNIFIL में ब्रिगेडियर तरूणदीप कुमार की उप बल कमांडर के तौर पर नियुक्ति के द्वारा वहां भारत की उपस्थिति को संवर्धित किया गया है।

ओमान

भारत तथा ओमान के बीच पारंपरिक तौर पर मजबूत आर्थिक तथा राजनीतिक संबंधों को इस वर्ष के दौरान और अधिक मजबूत किया गया था। पूर्व विदेश मंत्री श्री ई. अहमद ने श्री अनिल बाधवा, सचिव (पूर्व) के साथ 03–05 मई, 2014 तक ओमान की यात्रा की थी।

विदेश कार्य के लिए उत्तरदायी मंत्री, श्री युसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला ने भारत की नई सरकार को बधाई देने के लिए विशेष दूत के रूप में 3 जून, 2014 को भारत की यात्रा की थी। 01 अप्रेल, 2014 को पेट्रोनेट फाउंडेशन डे के तौर पर चिह्नित करने के लिए भारत में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कुवैत के तेल तथा गैस मंत्री श्री मोहम्मद अल रूम्ही आमंत्रित किए गए थे।

ओमानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, डॉ. अली बिन मासूद बिल अली अल सुनैदी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय व्यापारिक तथा सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य एवं उद्योग राज्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री के साथ 29 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त आयोग के 7वें चरण की बैठक की थी। 7वें JMD की बैठक के अवसर पर फिक्की (FICCI) तथा ओमान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री (OCCI) के साथ 8वीं संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) का आयोजन किया गया था।

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से एक प्रतिनिधिमंडल ने 25–27 अगस्त, 2014 तक ओमान की यात्रा की थी। दक्षिणी नौसेना कमाण्ड से भारतीय नौसेना प्रशिक्षण स्काड्रन के तीन जलयानों INS तीर, INS सुजाता तथा INS तरंगिनी ने 06–09 अक्तूबर, 2014 तक मस्कट के सुल्तान कबूस बंदरगाह की सद्भावना यात्रा की थी। ओमान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव, मेजर जनरल सलमान खुशूब ने 26–28 नवंबर, 2014 तक भारत की यात्रा की थी, उन्होंने द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड परामर्शों के लिए भारत के उप राष्ट्री सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से एक प्रतिनिधिमंडल ने 17–24 जनवरी, 2015 तक भारत की यात्रा की थी।

राजनयिक मामलों हेतु ओमान के विदेश मंत्रालय में अवर सचिव श्री अहमद यूसुफ अल–हारथ्री ने नई दिल्ली में आयोजित 10वीं भारत–ओमान रणनीतिक परामर्शी दल की बैठक के लिए 03 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली की यात्रा की थी।

सचिव (उर्वरक) ने 27–30 अप्रेल, 2014 तक ओमान में तीन सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर ओमानी तेल तथा गैस मंत्री के साथ विचार–विमर्श किया था। ओमान के निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाली कई भारतीय कंपनियों को कई बड़ी परियोजनाएं प्रदान की गई थी। भारतीय दूतावास ने 12 नवंबर, 2014 को भारत में निवेश संवर्धन पर केंद्रित भारत बिजनेस सेमिनार तथा 14 सितंबर, 2014 को ICCR द्वारा प्रायोजित सूफी संगीत कान्सर्ट का आयोजन किया था।

फिलीस्तीन

इजराइल तथा फिलीस्तीन के बीच अंतिम स्टेटस वार्ता 21 जुलाई, 2013 को शुरू हुई और बिना किसी नतीजे के 29 अप्रेल, 2014 को

समाप्त हुई थी। भारत ने बातचीत दोबारा शुरू किए जाने का स्वागत किया था।

02 जून, 2014 को, राष्ट्रपति श्री महमूद अब्बास ने जनमत के साथ पद–ग्रहण किया तथा परिवर्तन काल के दौरान नए राष्ट्रपति तथा संसद के लिए चुनावों का संचालन आयोजित करने का दायित्व उठाया। इस सरकार में 17 मंत्री हैं। 23 अप्रेल, 2014 को फतह–हमास समन्वय के करार के अनुसार सरकार बनाई गई थी। भारत सरकार ने इस सहयोगात्मक सहकार के गठन का स्वागत किया था। यह वेस्ट बैंक तथ गाजा के बीच समन्वय प्रयासों को भारत द्वारा दिए गए समर्थन के लिए था, जो मजबूत फिलीस्तीन राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण था।

08 जुलाई, 2014 को, इजराइल ने गाजा के खिलाफ आपरेशन प्रोटेक्टिव एज (protective edge) शुरू कर दिया था। यह आपरेशन 50 दिनों तक चला तथा इसमें 2200 से अधिक फिलीस्तीनियों की जान गई थी। भारत ने गाजा में तेजी से बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी, विशेष तौर पर महिलाओं एवं बच्चों पर हिंसा तथा घरों व अवसंरचना के विस्तृत नुकसान पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। 26 अगस्त, 2014 को मिश्र ने युद्ध समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की थी। भारत ने फिलीस्तीन तथा इजराइल के बीच सीज फायर का स्वागत किया था तथा सभी से अपील की थी कि मौजूदा सीजफायर को बनाए रखने के लिए अधिकतम सहनशीलता दिखाएं तथा ऐसी कार्रवाई से बचें जिससे हिंसा होने की संभावना हो और फिलीस्तीनी मुद्दे पर व्यापक संकल्प की दिशा में कार्य करें। भारत अपनी बात पर तटस्थ है कि गाजा का अवरोध पूरी तरह समाप्त किया जाए और मानवीय आपूर्तियों एवं अत्यावश्यक सामग्रियों को बिना बाधा के आने–जाने की अनुमति दी जाए।

12 अक्तूबर, 2014 को मिश्र, नार्वे तथा फिलीस्तीन ने गाजा के पुनर्निमाण के लिए फिलीस्तीन पर काइरो सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी की थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रदाताओं ने अपेक्षित 4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 5.4 बिलियन अमरीकी डालर देने का वचन दिया था। इस सम्मेलन में 75 से अधिक देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था तथा 4 मिलियन अमरीकी डालर देने का वचन भी दिया था। श्री संदीप कुमार, संयुक्त सचिव (पश्चिमी एशिया तथा उत्तर अफ्रीका), विदेश मंत्रालय ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका संयुक्त रूप से फिलीस्तीन में विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहे हैं। एक परियोजना (स्पोर्टस केंद्र, रामल्लाह) को फिलीस्तीनी जनता के लिए सुपर्द किया था। दो परियोजनाएं (विशेष आवश्यकताओं के साथ लोगों के पुनर्वास के लिए नेबलस केंद्र तथा गाजा में अलकुद्स अस्पताल का पुनर्वास) समाप्ति के निकट है। सितंबर 2014 में, इब्सा (IBSA) ने 1 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से गाजा में अट्टा हबीब मेडिकल सेंटर के पुनर्निमाण का अनुमोदन किया था।

19 मई, 2014 को भारत के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत तथा फिलीस्तीन के बीच 11 सितंबर, 2012 को हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार दो स्कूलों– जवाहरलाल नेहरू सेकेण्डरी स्कूल फॉर गर्ल्स, असेर अल समालियाह तथा अबुदीस में जवाहरलाल नेहरू सेकेण्डरी स्कूल फॉर बायज के निर्माण तथा साज–सज्जा के लिए फिलीस्तीन के शिक्षा मंत्रालय में भवनों हेतु महानिदेशक, श्री फवाज मुजाहिद को 1.80 मिलियन डालर की राशि में से 7,00,000 अमरीकी डालर का चैक सौंपा था। परियोजना संचालन समिति की पहली बैठक 12–13 नवंबर, 2014 को रामल्लाह में आयोजित की गई थी।

सऊदी अरब

भारत तथा सऊदी अरब के बीच शताब्दियों पुराना आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक संबंध है, जो इस वर्ष भी लगातार बढ़ता रहा है। दोनों देशों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग के पहचान किए गए क्षेत्रों में लगातार प्रगति की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शहजादा सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सौद, उप–प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री, सऊदी अरब अधिराज्य के साथ ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया में 15–16 नवंबर, 2014 को आयोजित जी–20 के अवसर पर मुलाकात की थी।

श्री सम पित्रोदा, प्रधानमंत्री के सलाहकार ने "नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड इट्स रोल इन नेशनल डेवलपमेंट" नामक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 24–25 अप्रेल, 2014 को रियाद की यात्रा की थी। पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 27–29 अप्रेल, 2014 को सऊदी अरब की यात्रा की थी तथा सऊदी हज मंत्री के साथ भारतीय हज यात्रियों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभाग) श्री धर्मेंद्र प्रधान ने द्वितीय मंत्री–स्तर द्विपक्षीय उर्जा परामर्शों हेतु 27–29 अक्तूबर, 2014 तक सऊदी अरब की यात्रा की थी।

श्री तौफीक फौजान अल रबियाह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, सऊदी अरब अधिराज्य ने 26–27 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सहयोग से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) द्वारा आयोजित चौथे भारत–अरब साझेदारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी।

सऊदी अरब के विदेश व्यापार उप मंत्री डॉ. अब्दुल्ला ए. अल ओबैद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 14–15 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित भारत सऊदी अरब संयुक्त आयोग बैठक के दसवें सत्र के सहमत परिणामों के कार्यान्वयन की बैठक की समीक्षा हेतु भारत की यात्रा की थी।

EEPC भारत के तहत पावर तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों से भारत की 25 कंपनियों ने 26–28 मई, 2014 को आयोजित 'सऊदी उर्जा प्रदर्शनी– 2014' में भाग लिया था। ITPO APEDA तथा भारतीय चाय बोर्ड के संरक्षण के तहत 52 भारतीय कंपनियों ने सऊदी एग्रो फूड एक्जीबिशन में भाग लेने के लिए 7–10 सितंबर, 2014 तक

विदेश मंत्री ने 01 अक्तूबर, 2014 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 69वें सत्र के दौरान इस्राइली विदेश मंत्री श्री एवीग्डोर लीबरमैन से मुलाकात की।

प्रधान मंत्री ने 16 नवंबर, 2014 को जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिसबेन में सऊदी अरब के शहजादे शेख सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सौद से मुलाकात की।

रियाद की यात्रा की थी।

दो भारतीय नौसेना जलयानों INS तीर तथा INS सुजाता ने, 20–23 अक्तूबर, 2014 तक जुबैल बंदरगाह की सद्भावना यात्रा की थी।

हज 2014 के दौरान 135, 914 भारतीयों ने हज यात्रा करने के लिए सऊदी अधिराज्य की यात्रा की थी।

कतर

भारत तथा कतर के बीच बहु आयामी संबंध इस वर्ष के दौरान और अधिक प्रगाढ़ हुए थे। श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व) तथा श्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मुतिब अल रूमाइही, कतर के सहायक विदेश मंत्री के नेतृत्व में द्वितीय भारत–कतर विदेश कार्यालय परामर्शी का आयोजन 5 जून, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग का संपूर्ण गैमुट सहित परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल किया गया था।

03–05 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच की 19वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर जस्टिस श्री के.जी बालकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत ने डॉ. अली बिन समीख अल मारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कतर से मुलाकात की तथा परस्पर हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया था, जिसमें विशेष तौर पर कतर में काम करने वाले भारतीय कामगारों के कल्याण पर विशेष बल दिया गया था। भारतीय तट–रक्षक जलयान 'विजित' ने 20–23 दिसंबर, 2014 तक दोहा की यात्रा की थी। रक्षा सहयोग पर करार के तहत स्थापित भारत–कतर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की चौथी बैठक का आयोजन 06 जनवरी, 2015 को किया गया था।

प्रधानमंत्री द्वारा 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू किए जाने को चिह्नित करने के लिए दोहा स्थित भारतीय राजदूतावास ने 25 सितंबर, 2014 को तीन व्यापारिक तथा निवेश बैठकों का आयोजन किया था। जनवरी 2015 में गांधीनगर में आयोजित किए जाने वाले 'वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन' का प्रचार करने के लिए 03–05 सितंबर, 2014 तक गुजरात राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने कतर की यात्रा की थी। एस्सोचैम (ASSOCHAM) परियोजना कतर में 45 भारतीय कंपनियों की भागीदारी का समन्वय किया था, जो मई 2014 में दोहा में अवसंरचनात्मक क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी थी।

जाने–माने फोटोग्राफर, कला इतिहासकार तथा फिल्म निर्माता बिनॉय बहल द्वारा इस्लामी स्मारको पर फोटोग्राफी प्रदर्शनी जिसे ICCR द्वारा भेजा गया था, इसे कल्चरल विलेज के सहयोग से दूतावास द्वारा 21 सितंबर से 18 अक्तूबर, 2014 तक कटारा में आयोजित किया गया था।

सीरिया

सीरियाई जनता की तर्कसंगत अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने सभी से आह्वान किया है कि वे सीरियाई संघर्ष को समाप्त करें ताकि वहां समावेशी राजनीतिक वार्ता का महौल बनाया जाए जिससे वहां की स्थिति का व्यापक राजनीतिक हल मिल सके। भारत इस बात पर कायम है कि इस संघर्ष को कोई सैन्य समाधान नहीं है तथा सीरिया में बाहर से किसी सैन्य हस्तक्षेप से बचना चाहिए। भारत, राजनीतिक समाधान के माध्यम से जारी सीरियाई संकट को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक सहयोग (ITEC) तथा ICCR छात्रवृत्ति के तहत भारत ने इस वर्ष भी सीरिया को सहयोग देना जारी रखा है।

संयुक्त अरब अमीरात

भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच पारंपरिक तौर पर घनिष्ठ तथा मित्रवत संबंधों को 10–12 नवंबर, 2014 तक विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की यात्रा से और अधिक मजबूत किया गया था। इस यात्रा के दौरान, इन्होंने यू ए ई के उप–प्रधानमंत्री तथा आंतरिक मामले मंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नाहयन तथा विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयन के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया था।

17–18 मार्च, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित भारत–यू ए ई संयुक्त आयोग की ग्यारहवीं बैठक की सह–अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा यू ए ई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयन ने की थी।

सुरक्षा मामलों पर द्वितीय संयुक्त समिति बैठक तथा संयुक्त रक्षा समिति सहयोग की 7वीं बैठक क्रमशः 11 दिसंबर तथा 16 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

भारतीय नौसेना प्रशिक्षण जलयानों– INS तीर, INS तरंगिनी तथा INS सुजाता के बेड़े ने 11–14 अक्तूबर, 2014 को दुबई की सद्भावना यात्रा की थी। यू ए ई के सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांड स्टाफ कालेज के 21 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने मई 2014 में भारत की यात्रा की थी तथा यू ए ई के विदेश मंत्रालय तथा डी पी वर्ल्ड द्वारा अक्तूबर 2014 में दुबई में आयोजित मेरीटाईम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था।

भारतीय राज्य सरकारों तथा यू ए ई में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच बेहतर संपर्क तथा समन्वय स्थापित करने के क्रम में भारतीय दूतावास ने 13 सितंबर, 2014 को "वर्किंग टुगेदरः इमप्रूविंग सर्विस डेलीवरी" शीर्षक के भारतीय राज्य सरकारों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया था। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल, इन छः राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भारतीय एसोशिएशनों तथा सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ इस आयोजन में भाग लिया था। इस आयोजन के दौरान यू ए ई में रहने वाले भारतीय निर्वासितों के लिए दिशा–निर्देश भी जारी किए गए थे।

दुबई स्थित दूतावास तथा महाकोंसुल ने अमीरात, भारत तथा अन्य

खाड़ी देशों से अग्रणी बिजनेस मैन को शामिल करके 'मेक इन इंडिया' अभियान का आयोजन किया था। द्विपक्षीय निवेश संरक्षण तथा संवर्धन करारों (BIPPA) एवं कस्टम सहयोग पर करारों का दोनों देशों ने समर्थन किया है।

ICCR की समकालीन पेंटिग प्रदर्शनी 'केरल ग्रीन'–सार्क देशों से कलाकारों के कार्य का संकलन तथा भारतीय कलाकारों के समूह की प्रदर्शनी का आयोजन सितंबर 2014 में किया गया था।

यमन

मारीब, यमन में भेल के 400 मेगावाट सौर उर्जा बिजली संयंत्र की प्रगति पर विचार–विमर्श करने के लिए 20 अप्रेल, 2014 को यमन गणराज्य के बिजली मंत्री श्री सालेह सुमाई ने 9 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल का भारत में नेतृत्व किया था। यमन में 60 मेगावाट के सौर उर्जा बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। मारीब में 400 मेगावाट गैस पावर परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में भेल (BHEL) के निदेशक श्री अतुल सोबती ने यमन में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। गैमन इंडिया लि. तथा यमन गणराज्य के बिजली तथा उर्जा मंत्रालय के बीच 61.5 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से पारेषण लाईन खड़ा करने के लिए पावर स्टेशन लगाने हेतु अप्रैल 2014 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

श्री अब्दुलकादर अली हेलाल, साना के मेयर सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के संघीय ढांचे तथा विकेंद्रीकरण के आयामों की शिक्षा के लिए 04–10 मई, 2014 तक भारत की यात्रा की थी। श्री अहमद नासर अहमद, सूचना उप–मंत्री, यमन गणराज्य ने 20–24 अगस्त, 2014 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित मीडिया सिंपोजियम में भाग लिया था।

योजना एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, महिला विभाग की महानिदेशक श्रीमती ईमान अब्दुल्ला अली अल हमामी सहित दो सदस्यों के यमनी प्रतिनिधिमंडल ने 17–19 सितंबर, 2014 को महिला सशक्तीकरण एवं गरीबी उन्मूलन पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन (IORA) कार्यशाला में भाग लेने के लिए 16–19 सितंबर, 2014 तक भारत की यात्रा की थी। श्री मोहम्मद महमूद अब्दो अल जंडाने ने 'हिंद महासागर वार्ता' शीर्षक के ट्रैक 1.5 में भाग लेने के लिए 05–07 सितंबर, 2014 तक एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत की यात्रा की थी।

यमनी वित्त मंत्रालय में बजट क्षेत्र के लिए उप–मंत्री श्री अमीन अब्दुलजब्बार सुल्तान अल–मोहम्मदी के नेतृत्व में एक यमनी प्रतिनिधिमंडल ने PPP मॉडल की शिक्षा के लिए 13–15 जनवरी, 2015 तक भारत की यात्रा की थी। भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए यमनी सुप्रीम राष्ट्रीय प्राधिकरण से 14 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने 19–21 जनवरी, 2015 तक भारत की यात्रा की थी।

यमनी फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से भारतीय दूतावास ने 28 अक्तूबर, 2014 को "मेक इन इंडिया" का आयोजन किया।

विशेष कुवैत प्रकोष्ठ (SKC)

खाड़ी युद्ध (1990–91) से वापस लौटने वालों के मुआवजों के दावों का निपटान करने के लिए विशेष कुवैत प्रकेष्ठ (SKC) का गठन किया गया था। सभी वैध दावों का निपटान कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा समिति (UNCC) ने अपने दावा विवरण कार्य को बंद कर दिया है तथा उनकी ओर से किसी भारतीय दावेदार का कोई दावा शेष नहीं है। यह प्रकोष्ठ लगातार दावेदारों के जारी कोर्ट मामलों, VVIP/VIP संदर्भों तथा प्रश्नों का निपटान कर रहा है। यह प्रकोष्ठ सूचना आयुक्तों के लिए RTI प्रश्नों/अपीलों को भी निपटा रहा है।

अरब लीग

दिसंबर 2013 में 2014–15 के लिए अलब लीग तथा भारत के बीच अरब–भारतीय सहयोग मंच के सहयोग ज्ञापन (MOC) तथा कार्यकारी कार्यक्रम (EP) पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात 20–24 अगस्त, 2014 तक नई दिल्ली में मीडिया सिंपोजियम का आयोजन किया गया था, जिसमें अरब के वरिष्ठ पत्रकार अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत करते हुए देखे गए थे।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)

69वें UNGA सत्र के अवसर पर न्यूयार्क में 26 सितंबर, 2014 को 8वें भारत–खाड़ी सहयोग परिषद राजनीतिक वार्ता का आयोजन किया गया था। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने खाडी सहयोग के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी तथा GCC मंत्रालयी त्रोईका बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था।

7–9 जनवरी, 2015 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित 13वें प्रवासी भारतीय दिवस में खाडी देशों से प्रवासी भारतीयों की बड़ी भागीदारी थी। श्री अशरफ पाला–राकुन्नुम्मल तथा श्री शाह भरत कुमार जयंती लाल, यू ए ई तथा श्री राजमल एम पारख, ओमान उन 15 प्रवासी भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया था।

सुप्रीम काउंसिल के सदस्य तथा रस–अल–खमात के शासक एच. एच. शेख सौद बिन सद्र बिन मोहम्मद अलकासिमी तथा यू ए ई के इकोनॉमी मंत्रालय के विदेश व्यापार क्षेत्र के उप–मंत्री तथा अवर सचिव श्री अब्दुल्ला अहमद अल सालेह ने गांधीनगर, गुजरात में 11–13 जनवरी, 2015 को आयोजित 7वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मिट में भाग लिया था।

द कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने अपने फ्लैगशिप इंटरनेशनल इनवेस्टर्स मीट–वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ उनके सहयोग से द पार्टनरशिप सम्मिट का आयोजन जयपुर, राजस्थान में 15–17 जनवरी, 2015 तक किया था। कुवैत के

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा उप–प्रधानमंत्री श्री अब्दुलमोहसिन मेदाज अल मेदाज, यू ए ई के इकोनॉमी मंत्रालय के विदेश व्यापार क्षेत्र में उप–मंत्री तथा अवर सचिव श्री अब्दुल्ला अहमद अल सालेह, कतर के इकोनॉमी एवं कॉमर्स मंत्रालय में अवर सचिव श्री सुल्तान बिन राशिद अल–खातेर तथा ओमान के निवेश एवं निर्यात विकास हेतु लोक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सलीम नासेर अल इस्माइली ने भागीदारी शिकर सम्मेलन में भाग लिया था।

हज

हज भारत द्वारा विदेश में आयोजित सबसे बड़ा कार्यकलाप है, जिसमें लगभग 1,75,000 हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा करते हैं।

हज 2014 पर भारत–सऊदी अरब द्विपक्षीय करार पर 09 फरवरी 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार को हज 2014, भारत के लिए कोटा के नाम से निर्दिष्ट किया गया था। कुल 1,36,020 सीटों के आबंटन से भारत के लिए संपूर्ण सीटों में से 20 प्रतिशत की कटौती थी। इसे भारतीय हज समिति (HCOI), को 100, 020 सीटों तथा निजी टूर ऑपरेटरों (PTOs) को 36,000 सीटों के बीच विभाजित किया गया था।

भारतीय हज समिति के साथ समन्वय से भारत सरकार हज यात्रियों की इन माध्यमों से सहायता करती है– (i) मक्का, मदीना तथा जेद्दा में आवास के प्रावधानों तथा अन्य संभार तंत्रों से सहयोग, (ii) हज के दौरान, हाजियों की सहायता के लिए डॉक्टरों, पैरामैडिक्स, समन्वयकों, सहायक हज अधिकारियों तथा हज सहायकों की प्रतिनियुक्ति; (iii) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण जो बदले में हज के लिए सऊदी अरब के लिए प्रस्थान से पूर्व हज यात्रियों को प्रशिक्षण देते हैं; (iv) मक्का, मीना, अराफात, मुजदालिफा तथा मदीना के पवित्र स्थानों पर हाजियों के लिए अस्थायी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों की स्थापना, एम्बुलेंस प्रदान करना तथा दवाइयों की आपूर्ति करना एवं (v) भारत में निर्धारित 21 बिंदुओं से जेद्दा तक तथा वहां से वापसी के लिए वायु यात्रा की सुविधा प्रदान करना।

श्री आरिफ बेग, पूर्व वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में दो सदस्यों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुविधाओं के पूर्व जांच के लिए 29 सितंबर, 2014 से 20 अक्तूबर, 2014 तक सऊदी अरब की यात्रा की थी।

हज 2014 के दौरान हाजियों को सहायता देने के लिए 541 डॉक्टरों, पैरामैडिक्स, समन्वयाकें, सहायक हज अधिकारियों तथा हज सहायाकों को प्रतिनियुक्ति पर सउदी अरब भेजा गया था।

हज 2014 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। भारतीय हज यात्रियों का अंतिम बैच 12 नवंबर, 2014 को घर वापस लौटा था। भारतीय हज समिति के माध्यम से कुल 99,966 हज यात्रियों ने यात्रा की, जबकि 36,000 लोगों ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से हज यात्रा की थी।

वार्षिक हज समीक्षा सम्मेलन 10 जनवरी, 2015 को आयोजित किया गया था। हज 2015 की तैयारियों के लिए सुझावों/सुधारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में विदेश मंत्रालय, भारत के राजदूत, सऊदी अरब, महाकोंसुल/उप–महाकोंसुल, सी जी आई, जेद्दा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय हज समिति तथा एयर इंडिया के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

जनवरी 2015 से, हज–2015 की कार्य–योजना को कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें दवाइयों की खरीद तथा डिस्पैच, जेद्दा एयरपोर्ट पर अस्थाई डिस्पेंसरी/अस्पताल खोलना, भारतीय हज यात्रियों के लिए अस्थायी टेंट लगाना, हज यात्रियों के लिए किराए पर आवास लेने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाएगा।

हज मंत्रालय, सऊदी अरब अधिराज्य के साथ बैठकों के लिए तथा 2015 के लिए द्विपक्षीय हज करार पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए फरवरी 2015 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सऊदी अरब की यात्रा करने का अनुमान है।

545 प्रतिनियुक्ति पदों के चयन(समन्वयकों, सहायक हज अधिकारी, हज सहायक, डाक्टरों, नर्सों तथा पैरामेडिक्स) की प्रक्रिया जनवरी 2015 से शुरू की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदनों का अनुरोध करते हुए प्रेस रीलिज जारी की जाएगी।

हज 2015 में भारतीय हज यात्रियों के पंजीकरण के लिए भारतीय हज समिति द्वारा फरवरी/मार्च 2015 से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसी प्रकार, 2015 के हज कोटा आबंटन हेतु निजी टूर ऑपरेटरों के पंजीकरण की कार्य–योजना शुरू की जाएगी।

■■

विदेश मंत्री ने 11 नवंबर, 2014 को अबुधाबी में यू ए ई के उप प्रधान मंत्री शेख सैफ बिन जायद से मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने अपनी ओमान यात्रा के दौरान, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्य आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हेतु ओमान सुल्तान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलवी बिन अबदुल्लाह से मुलाकात की।

अफ्रीका

6

अल्जिरिया

भारत ने अल्जिरिया को 480,000 अमरीकी डॉलर मूल्य की एफ एम डी (पैट तथा मुंह रोग) एक संयोजक टीके की एक मिलियन खुराके देश में एफ एम डी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए भेंट की। टीकों को अल्जिरियाई कृषि मंत्रालय को 13 नवंबर, 2014 को सुपुर्द की गई।

वर्ष 2014 की पहली छमाही में अल्जिरिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने 995 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहूँचा। भारत से अल्जिरिया को 635 मिलियन अमरिकी डॉलर का निर्यात रहा और अल्जिरिया से भारत में 360 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात रहा था।

भारत–अरब द्वितीय सांस्कृतिक महोत्सव अल्जायरस में 20–27 नवंबर, 2014 तक आयोजित हुआ था। महोत्सव का उद्घाटन संयुक्त रुप से अल्जिरिया के संस्कृति मंत्री, अरब लिग के उप महासचिव, महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा भारतीय राजदूत द्वारा किया गया। भारतीय चित्र प्रदर्शनी तथा भारतीय कलाकृति कौशल और देवनागरी सुलेखन की प्रदर्शनी का भी साथ–साथ उद्घाटन हुआ। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय सिनेमाघर में चार बॉलीवुड फिल्मों को दिखाया गया। महोत्सव अल्जिरिया के सात अन्य मुख्य शहरों और नगरों में फैला था। मेजबान अल्जिरिया के अतिरिक्त मिस्र, इराक, लेबनान, मॉरीतानिया, ओमान, फिलीस्तीन, सोमालिया, सुडान तथा ट्यूनीशिया ने महोत्सव में भाग लिया।

अंगोला

भारत और अंगोला के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक रहे हैं। हालांकि, अंगोला भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए मुख्य स्रोत रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों का विस्तार हो रहा है। अंगोला के उच्चतम शिक्षा के राज्य सचिव, श्री अंटोनियो मिगूल एण्ड्रे ने 27–28 अक्तूबर, 2014 तक भारत का दौरा किया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर (फिक्की) के परिसंघ से एक प्रतिनिधिमंडल ने लुआण्डा का 26–27 मई, 2014 तक दौरा किया। भारत के ऐक्जिम बैंक के माध्यम से प्रदान की गई दो ऋण श्रृंखलाओं वस्तुतः 30 तथा 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के तहत अंगोला में एक औद्योगिक पार्क परियोजना तथा एक वस्त परियोजना स्थापित करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है। भारत का अंगोला को निर्यात और निवेश में बढ़ोतरी हुई है। द्विपक्षीय व्यापार असाधारण रुप से 2006–2007 के दौरान मात्र 446.60 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2013–14 में 6528.34 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है जिसमें अंगोला का भारत को मुख्य रूपसे 5992.31 मिलियन अमरीकी डॉलर तेल का निर्यात रहा है। समग्र रुप में अप्रैल से अगस्त 2014 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार कुल 2270.93 अमरीकी डॉलर रहा। भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में ट्रैक्टर तथा परिवहन वाहन, कृषि संबंधी मशीनें तथा उपकरण, खाद्य तथा मांस उत्पाद, औषधियां तथा सौंदर्य उत्पाद, चाय, चावल (बासमती), तेजाब और पेय, चमड़े, कागज / लकड़ी उत्पाद आदि हैं।

बेनीन

भारत–अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 09–11 मार्च, 2014 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें सी आई आई – एक्जिम बैंक की बैठक में बेनीन से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था।

बेनीन के राष्ट्रपति श्री बोनी याची ने 15 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की भारत सरकार की ऋण श्रृंखला से भारतीय कंपनी मैसर्स एनजेलिक इंटरनेशनल द्वारा बनाई मई माह में ट्रैक्टर सज्जीकरण संयंत्र का उद्घाटन 19 दिसंबर, 2014 को किया। राष्ट्रपति श्री बोनी याची ने संयंत्र को राष्ट्र के लिए एक अच्छे उपहार के रूप में बताया।

श्रीमती लामातू नासिरो, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधिश के नेतृत्व में चार सदस्यीय बेनीन प्रतिधिनिमंडल ने विश्व न्यायिक संस्थानों के प्रमुखों के 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 08 –18 दिसंबर, 2014 तक लखनऊ का दौरा किया।

बोत्सवाना

भारत और बोत्सवाना मैत्रीपूर्ण संबंधों को साझा करते हैं जो कि इस वर्ष पारस्परिक सहयोग और दौरों के आदान–प्रदान से संबंधित द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर के माध्यम से घनिष्ठ हुए हैं। पारस्परिक सहयोग तथा भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा बोत्सवाना के गैर–बैंक वित्तीय संस्थान विनियामक प्राधिकरण (एन बी एफ आई आर ए) के बीच तकनीकी सहयोग से संबंधित मई

2014 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। भारतीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों का बोत्सवाना रक्षा बलों के साथ उसमें कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए मिलाप से संबंधित एक और समझौता करार हस्ताक्षरित हुआ। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर 2014 में बोत्सवाना का दौरा किया और मेजबान देश में युवाओं के बीच स्व–उद्यम विकसित करने के लिए बोत्सवाना में इन्क्यूबेटर केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थानीय उद्योग प्राधिकरण (एल ई ए) के साथ बैठकें कीं और इसे प्रभावी बनाने के लिए दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ।

बोत्सवाना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सक्रिय रुप से लाभान्वित हुआ है। भारत द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, सी वी रमन फेलोशीप, भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन मंच (आई ए एफ एस) भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आइटेक) के तत्वाधान में लगभग 200 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। ज्यादातर भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है और कुछ बोत्सवाना द्वारा स्वयं आंशिक/पूर्ण रूप से वित्तपोषित है।

बुरुण्डी

भारत और बुरुण्डी के बीच मजबूत मित्रता है। 2014 में भारत सरकार ने फरवरी 2014 में हुई भीषण बारिश से उत्पन्न क्षति के लिए आपदा राहत के रूप में बुरुण्डी सरकार के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर की नगद सहायता के लिए घोषणा की थी। आई ए एफ एस –1 के तहत प्रतिबद्ध एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वी टी सी) को पूरा किया गयाए संचालित किया गया तथा प्रशिक्षण के पश्चात बुरुण्डी प्राधिकारियों को सौंप दिया गया। आई ए एफ एस –1 में प्रतिबद्धता के तहत भारत–अफ्रीका शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का पैन–अफ्रीकी संस्थान (आई ए आई ई पी ए) जो स्थापित किया जाना है, संभवतः 2015 के प्रारंभ में उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। आइटेक के तहत बुरुण्डी को तीस स्लॉट आबंटित किया गया है। पैन–अफ्रीका ई–नेटवर्क परियोजना संतोषजनक परिचालित है।

कैमरुन

नई दिल्ली में 09–11 मार्च, 2014 तक आयोजित भारत–अफ्रीका परियोजना भागीदार पर 10वें सी आई आई –ऐक्जिम बैंक सभा में कैमरुन से एक छह सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

केप वर्डे

केप वर्डे अपनी राजनीतिक स्थिरता, कूटनीतिक स्थिति तथा निवेश अनुकूल नियमों तथा संस्थानों के कारण आर्थिक संभावनाओं को दर्शाता है। वर्ष 2014–15 के लिए केप वर्डे को आइटेक के तहत 20 स्लॉट आबंटित किया गया था। यह बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन करता है और अक्तूबर 2014 में न्यूयार्क में 2015–2017 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद चुनावों के लिए भारत के पक्ष में मतदान किया। एम एफ ए केप वर्डे ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रशिक्षण से संबंधित एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्देश्य व्यापारिक व्यक्तियों को विदेशी देशों के साथ कैसे व्यापार किया जाए, के संबंध में सूचित करना था।

आइवरी के प्रधान मंत्री श्री डेनियल काबलन डंकन के निमंत्रण पर 13 भारतीय कंपनियों को शामिल करते हुए एक भारतीय व्यापार तथा निवेश प्रतिनिधिमंडल ने 07–09 दिसंबर, 2014 तक आबिदजान का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने आइवेरी के कई मंत्रालयों से बातचीत किया और प्रधान मंत्री श्री डेनियल डंकन से भी मुलाकात की।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य (कार)

कार में निरंतर हिंसा तथा नाजुक सुरक्षा स्थिति के कारण सभी भारतीय कामगारों का भारत वापसी की वजह से भारत सरकार द्वारा समर्थित 24 मिलियन अमरीकी डॉलर ऋण श्रृंखला की लागत से बनगुई में 400 एम टी/प्रतिदिन सीमेंट संयंत्र के निर्माण और चालू कराने का कार्य 2014 में बंद हो गया था। 2013–14 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 8.64 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

चाड

नई दिल्ली में 09–11 मार्च, 2014 तक आयोजित भारत–अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 10वें सी आई आई –ऐक्जिम बैंक सभा में चाड से एक दो सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

कोमोरोस

दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और अफ्रीकी देशों में क्षमता निर्माण पर हमारे फोकस के भाग के रूप में कोमोरोस आइटेक तथा आई ए एफ एस छात्रवृत्तियों के तहत भारतीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरंतर लाभार्थी रहा है। 2014–15 में बुरुण्डी को तीस आइटेक स्लॉट्स प्रदान किए गए हैं। पैन–अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजना का कोमोरोस भी लाभार्थी है। मोरोनी में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कोमोरोस सरकार को भारत सरकार की 41.6 मिलियन अमरीकी डॉलर की दी जाने वाली रियायत ऋण श्रृंखला का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत ने कोमोरियाई पक्ष द्वारा चयनित किए जाने वाले परियोजना के लिए भी 35 मिलियन अमरीकी डॉलर का सुलभ ऋण उपलब्ध कराया था।

कोत दीव्वार (सी आई)

भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री श्री डेनियल काबलन डंकन ने कोर्ट कोत दीव्वार के व्यापार तथा

उद्योग और खान मंत्रियों के साथ 03–07 नवंबर, 2014 तक नई दिल्ली का दौरा किया। सी आई आई तथा फिक्की के साथ बातचीत के अतिरिक्त वे विदेश मंत्री से मिले। चूंकि कोर्ट डी आइवरी में शांति और स्थिरता बहाल हो गई है, भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक संभावनाओं के साथ–साथ कृषि, खनन, उत्पादन, अवसंरचना, सूक्ष्म वित्त आदि में भी निवेश संभावनाओं को तलाशने के लिए दौरा करना शुरू कर दिया है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

जुलाई 2014 में भारत सरकार ने कसाई पाश्चात्य प्रांत में स्थित 64 मेगावाट कटेनडे जलविद्युत ऊर्जा परियोजना को पूरा करने के लिए 82 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण श्रृंखला प्रदान किया। वास्तविक ऋण श्रृंखला 168 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए था। परियोजना प्रगति पर है और मार्च 2016 तक पूरा होने की संभावना है। 42 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला परियोजना काकोबोला (9.3 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है और 2015 में पूरा होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2011–2012 में 15.29 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। देश में अब तक के सबसे बड़े संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्रवाई के तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 5,300 भारतीय बल, सैनिक पर्यवेक्षक और पुलिस कार्मिक कार्य कर रहे हैं।

जीबूति

जीबूति के साथ भारत का संबंध हमेशा गरमजोशी व मैत्रीपूर्ण रहा है। जीबूति अफ्रीका में आतंक के विरुद्ध लड़ाई और अदेन की खाड़ी में जलदस्युता विरोधी कार्रवाई का केन्द्र बन गया है। जलदस्युता विरोधी कार्रवाई में लगी हुई भारतीय नाविक जहाजें आवधिक रूप में साम्भारिक सहयोग तथा आपूर्ति के लिए जीबूति बंदरगाह पर ठहरती है।

संयुक्त अरब अमीरात आधारित भारतीय निवेश निरंतर समान रूप से बढ़ रहा है विशेषकर साम्भारिकी में।

अली सबिह सीमेंट संयंत्र को आर्थिक रुप से व्यावहारिक बनाने के लिए इसे उन्नयन करने हेतु 15.13 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक अतिरिक्त ऋण श्रृंखला सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित हुआ था।

जीबूति को आइटेक के तहत पैंतीस स्लॉट और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से 11 छात्रवृत्तियां आबंटित की गई। अभी तक, 10 आइटेक तथा 09 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद छात्रवृत्तियों का उपयोग हुआ है।

मिस्र

वर्ष के दौरान उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमों के बावजूद भारत–मिस्र संबंध सौहार्दपूर्ण तथा सर्गरम रहे हैं जिसने 96.91 प्रतिशत के भारी वैध मतों से श्री अबदेल फतह अल सिसी को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते देखा है। मिस्र के मंत्रीमंडल का पुनः गठन हुआ। प्रधान मंत्री श्री इब्राहिम माहलेब को रखा गया और श्री रुमेह शौकरी को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया।

वैश्विक मंदी के बावजूद, भारत का मिस्र को 2.56 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात तथा 2.39 मिलियन अमरीकी डॉलर के आयात के साथ, 2009–10 में 3.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2013–14 में बढ़ते हुए 4.95 बिलियन अमरीकी डॉलर होकर 60 प्रतिशत तक बढ़ा है जिसने इटली के बाद मिस्र के लिए निर्यात में बड़े गंतव्य के रूप में भारत को दूसरे अन्य आयातों में स्रोत केरूप में 11वें स्थान पर बना दिया है। 50 से अधिक भारतीय कंपनियां कुल 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश के साथ भारत के आर्थिक संबंधों की बिन्दु बनी हुई है। भारत ने मिस्र के लोगों को आइटेक तथा सी वी रमन फेलोशिप के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देना जारी रखा है जिससे इन कार्यक्रमों से लगभग 112 अभ्यर्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक आदान–प्रदानों में शामिल हैः केमएक्सील द्वारा ''16वें आर बी एस एम'' पर मिस्र के प्रतिनिधिमंडल का दौरा और भागीदारी (28–29 जनवरी, 2014), ''भारत इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आई ई एस एस 2014, 22–24 जनवरी, 2014)'', 10वां सी आई आई –एक्जिम बैंक सभा (09–11 मार्च, 2014)'', ''भारत में गेहूं/फार्माएक्सल प्रतिनिधिमंडल (फार्माकोनेक्स,कायरो, 01–03 अप्रैल, 2014)''। नागर विमानन मंत्रालय, भारत और मिस्र नागर विमानन प्राधिकरण ने विमानन क्षेत्र में सहयोग पर 27 अगस्त, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राष्ट्रपति चुनने से संबंधित चुनावों के पर्यवेक्षण हेतु 25–29 मई, 2014 तक काहिरा का दौरा किया। काहिरा में 12 अक्तूबर, 2014 को गाजा पुनर्निर्माण से संबंधित आयोजित कोहिरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त सचिव (वाना) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही भारत ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 04 मिलियन अमरीकी डॉलर के योगदान की घोषणा की।

रक्षा पक्ष में संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक में पारस्परिक सहमति के अनुसार भारत से कुल पांच प्रतिनिधिमंडलों ने मिस्र का दौरा किया। समान रूप से मिस्र से पांच प्रतिनिधिमंडलों ने भारत विभिन्न सैनिक ठिकानों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, भारत से डी आर डी ओ की एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने डी आर डी ओ के महानिदेशक, श्री अनिवाश चंद्र की अध्यक्षता में 07–09 नवंबर, 2014तक मिस्र का दौरा किया।

सांस्कृतिक पहलू पर 'इंडिया बाई दी नील' (आई बी एस) सांस्कृतिक महोत्सव का दूसरा संस्करण मिस्र में 30 मार्च–20 अप्रैल, 2014 तक आयोजित हुआ था और उसमें संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, सूचना मंत्री, सामाजिक सुदृढ़ता मंत्री और उच्च

स्तरीय कई हस्तियों ने भाग लिया। महोत्सव कार्यक्रम में 'बॉलीवुड डान्स कार्यशाला, बॉलीवुड प्रेम कहानी–ए–संगीतमय, साड़ी प्रदर्शन, नगाड़ा कार्यशाला, कथक नृत्य वाचन, भारतीय फिल्म उत्सव, भारतीय खाद्य उत्सव, श्री जावेद अख्तर तथा श्रीमती शबाना आजमी के साथ संवादसत्र और श्री सुधीर तेलंग द्वारा कार्टून प्रदर्शनी शामिल हैं। सुश्री सोनम कालरा और उनके समूह ने 20–27 सितंबर, 2014 तक मिस्र में धार्मिक गान और सूफी संगीत हेतु 7वें अंतर्राष्ट्रीय 'सभा' महोत्सव में भाग लिया। संस्कृति मंत्री डॉ0 गबेर असफोर और अरब लिग के पूर्व महासचिव श्री अमरे मौसाने राजदूत श्री पी ए नजारेश की पुस्तक 'गांधी आउटस्टैंडिंग लीडरशिप' का अरबी रुपांतरण का 18 सितंबर, 2014 को लोकार्पण किया।

इसके अतिरिक्त, 400 विभिन्न स्कूलों से 4,000 मिस्र के स्कूली बच्चों ने 13–15 अक्तूबर, 2014 तक काहिरा तथा गिजा में चार अलग–अलग स्थानों पर आयोजित 20वीं 'ग्लिपसेस ऑफ इंडिया' चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। यह पहल 'भविष्य के मिस्रवासियों से भारत–संपर्क' को बेहतर सुनिश्चित करता है।

भारतीय वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक बढ़ावों के लिए मिन्या (20–21 अक्तूबर, 2014) तथा सूएज (16–17 नवंबर, 2014) तक 'इंडिया डेज' मनाया गया। 'इंडिया डेज' कार्यक्रमों में शामिल थे– 'ग्लिपसेस ऑफ इंडिया' चित्रकारी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मौलाना आजाद भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा भारतीय प्रदर्शनी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की खुबियों को दर्शाता स्थानीय वाणिज्य चैम्बर्स के साथ संवाद, स्थानीय प्राधिकारियों सहित राज्यपालों के साथ बैठक के साथ–साथ उस क्षेत्र के भारतीय कंपनियों/परियोजनाओं का दौरा। यह वाजिब और सफल आउटरीच मॉडल पसंद किया गया और सराहा गया।

इक्वेटोरियल गिनी

इक्वेटोरियल गिनी के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। आई ए एफ एस प्रक्रिया के तहत ग्रामीण विकास के लिए भू–सूचना संयंत्र केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत द्वारा दिया गया प्रस्ताव इक्वेटोरियल गिनी की सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य किया। भारत ने ए यू कार्यकारी परिषद के 25वें सामान्य सत्र में जो कि मालाबो में 23–24 जून, 2014 तक आयोजित हुआ था, में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

इरीट्रिया

इरीट्रिया में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वी टी सी) स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत से एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने 15–19 अक्तूबर, 2014 तक इरीट्रिया का दौरा किया।

इरीट्रिया में शीघ्र ही व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए दल ने इरीट्रिया के शिक्षा मंत्री तथा इरीट्रिया के व्यावसायिक प्रशिक्षण के महानिदेशक से मुलाकात की और रुपात्मक (मोडालिटी) पर चर्चा किया।

इरीट्रिया के मुख्य न्यायाधीश, श्री मेन केरिओस, ने लखनऊ में 10–16 दिसंबर, 2014 तक आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 15वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

अवधि के दौरान 01 इरीट्रियाई राष्ट्रिक को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्ति दी गई और 03 इरीट्रियाई राष्ट्रिकों ने आइटेक कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सुविधा का लाभ उठाया।

इथोपिया

उन्होंने एकरुपता कायम रखते हुए भारत का इथोपिया के साथ संबंधों के सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक, वाणिज्य, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहा है। भारत इथोपिया के अति महत्वपूर्ण और वांछित व्यापार, निवेश तथा विकास भागीदारी में से है। भारत का व्यापारिक मंच जो कि भारत का राजदूतावास, अदिस अबाबा के तत्वाधान में प्रचालित है, के 9वें वर्षगांठ का उत्सव अक्तूबर 2014 में मनाया गया और इसमें इथोपिया के प्रधान मंत्री श्री हेलेमारियम देसालेगन ने भाग लिया। यह इथोपिया के प्रधान मंत्री का किसी विदेशी व्यापारिक समुदाय के साथ पहला सार्वजनिक मुलाकात थी। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश ने अपने बढ़ोतरी प्रवृत्ति को कायम रखा है।

इथोपिया के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में द्विपक्षीय व्यापार, 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार करने की संभावना है। भारतीय कंपनियों के शीर्ष तीन विदेशी निवेशकों के रूप में रहने की अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखा है। चूंकि नई भारतीय बहुअंतर्राष्ट्रियों ने इथोपिया में अपने व्यापारिक हितों को स्थापित किया है।

भारतीय ऐक्जिम बैंक के 640 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण श्रृंखला के तहत तीन चीनी कारखानों में से दो को इथोपिया में बनाया जा रहा है और तीसरे कारखाने का चरण–। पूरा होने के करीब है। 25 सितंबर, 2014 को अदिस अबाबामें मेक इन इंडिया अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया गया। इथोपिया के साथ भारतीय कंपनियों और निर्यातकों के संपर्क को मेलों, प्रदर्शनियों तथा क्रेता–बिक्रेता बैठकों के आयोजन का प्रबंध करते हुए प्रोत्साहित किया गया।

भारत का इथोपिया को क्षमता निर्माण सहयोग लगभग 100 आइटेक स्लॉटों तथा 53 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद छात्रवृत्तियों के माध्यम से जारी है। आई ए एफ एस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 04 विद्वान भारत आए। अफ्रीकी अनुसंधानकर्ताओं के लिए सी वी रमन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के तहत, 06 इथोपियाई व्यक्तियों को शिक्षावृत्ति दी गई। अफ्रीकी संघ के चार तथा यू एन इकॉनामिक कमीशन फोर अफ्रीका (यू एन ई सी ए) के तीन प्रतिभागियों को आइटेक पाठ्यक्रम के लिए

भी भेजा गया। अफ्रीकी देशों के लिए भारत द्वारा दी जा रही ई–नेटवर्क कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में रिकॉर्ड 800 इथोपियाई छात्रों ने नामांकन भरें।

अभी तक का पहला भारत–इथोपियाई फिल्म महोत्सव अदिस अबाबा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। भारत का राजदूतावास द्वारा प्रायोजित पुरस्कारों के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्देशित इथोपियाई लघु फिल्मों और भारतीय फिल्मों को दिखाया गया।

इथोपिया के लोगों के लिए अब तक का पहला मुफ्त नेत्र सुरक्षा शिविर राजदूतावास में 13 दिसंबर, 2014 को आयोजित किया गया। विविध भारतीय समुदाय की मौजूदगी को मजबूत करने तथा रुचि बढ़ाने के लिए राजदूतावास द्वाराअपने संरक्षण में एक भारतीय चिकित्सा व्यावसायिक मंच और एक भारत शिक्षा मंच स्थापित किया गया।

गेबोन

गेबोन के राष्ट्रपति, श्री अली बोंगो ओनदीम्बा ने अक्तूबर 2014 में भारत का निजी दौरा किया। गेबोन की प्रसारण सुविधा को उन्नत तथा पुनर्वास करने हेतु भारत सरकार ने 67.19 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला प्रदान की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2011–12 में 193.26 मिलियन अमरीकी डॉलर तेजी से बढ़कर 2013–14 में 921.09 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

घाना

30 अप्रैल–14 मई, 2014 तक अक्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला केन्द्र के ए टी ए जी परिसर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद से छह सदस्यीय दल ने घाना में अक्रा में हमारे मिशन और स्थानीय भागीदार एड टू आर्टिशन, घाना (ए टी ए जी) के सहयोग से 'डिजाइनिंग दी डिफेरेंस' नाम से तीसरा अंतर्देश बास्केट्री कार्यशाला तथा प्रदर्शनी आयोजित किया। अक्रा में 28–30 मई, 2014 तक आयोजित पश्चिम अफ्रीकी खनन तथा ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी के 11वें संस्करण, वामपोक/वामपेक्स दृ 2014 के आयोजन में भारत 'भागीदार देश' था। प्रदर्शनी में इंडिया पेवेलियन में 28 भारतीय कंपनियां प्रदर्शनी लगाने वाले के रूप में थे जो भारतीय उद्यम परिसंघ द्वारा इक्टठा लाए गए थे। इंडिया अफ्रीका एक साझा भविष्य कार्यक्रम तथा विदेश मंत्रालय द्वारा समर्थित, के तत्वाधान में आइडिया वर्क्स डिजाइन एण्ड स्ट्रेटेजी प्राइवेट लिमिटेड (भारत) द्वारा इंडो–अफ्रीका व्यापार गठबंधन प्रतियोगिता, 2014 के पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया जो कि 10 जून, 2014 को घाना इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन में आयोजित हुआ। 19 अगस्त, 2014 को राष्ट्रपति श्री जॉन जरामनी महामा ने मध्य क्षेत्र में कोमेण्डा चीनी कारखाने में कार्य शुरू करने के लिए सोज काटा परियोजना 35 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऐक्जिम बैंक के ऋण श्रृंखला द्वारा वित्त पोषित है। घाना सरकार परियोजना के लिए अतिरिक्त 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्त पोषण उपलब्ध करा रही है। चीनी कारखाना पूरा होने पर स्थानीय लोगों को वस्तुतः सीधे तौर पर 1300 और सहायक व्यवसान के रूप में 5000 से अधिक को नौकरियां उपलब्ध कराएगा। अपने सम्बोधन के दौरान राष्ट्रपति श्री जॉन जमायनी महामा ने परियोजना के लिए नियमित कच्चे माल का उत्पादन सुनिश्चित करने से संबंधित सिंचाई सुविधा सहित गन्नेके पौधरोपण विकसित करने के लिए भारत सरकार से दी जाने वाली द्वितीय अतिरिक्त 24.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की घोषणा की। नई दिल्ली में 03–04 सितंबर, 2014 तक फिक्की द्वारा आयोजित ''दक्षिण से दक्षिण एच आई वी/एड्स स्वास्थ्य सभा'' में एक पांच सदस्यी घाना के प्रतिनिधिमंडल जिसमें घाना एड्स/एस टी आई नियंत्रक कार्यक्रम (एन ए सी पी), स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक शामिल थे, ने भाग लिया। 'मेक इन इंडिया' अभियान को शुरू करने के लिए घाना के उप राष्ट्रपति द्वारा निजी क्षेत्र विकास से संबंधित राज्य मंत्री के साथ 03–06 नवंबर, 2014 तक भारतका दौरा किया गया। उन्होंने हमारे उप राष्ट्रपति तथा भारतीय उद्योग के प्रमुखों से मुलाकात किया।

जयपुर में 15–17 जनवरी, 2015 तक आयोजित सी आई आई भागीदारी शिखर सम्मेलन में घाना के व्यापार एवं उद्योग मंत्री डॉ0 इकवोव स्पीओ गरबराह ने 09 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल के साथ भाग लिया।

गिनिया एवं लाइबेरिया

दोनों ही देश इबोला वाइरस के उत्पन्न होने से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने बीमारी से निपटने के लिए गिनिया और लाइबेरिया प्रत्येक को 50,000 अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय सहायता प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने डब्ल्यू एच ओ को 500,000 अमरीकी डॉलर की नगद सहायता, इबोला के लिए यू एन ट्रस्ट फण्ड में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान और पश्चिम अफ्रीका के प्रभावित देशों में ई वी डी से निपटने के लिए बचाव गियर खरीदने के लिए अतिरिक्त 02 मिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्ध कराया।

गिनी बिसाऊ

गिनी बिसाऊ में चुनाव सम्पन्न हुए और नई सरकार ने शपथ ली। भारत सरकार पुनर्निर्माण और सहयोग प्रक्रिया के लिए नई सरकार के साथ संपर्क में है। गिनी बिसाऊ में ग्रामीण विद्युतिकरण परियोजना के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर और कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए 05 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला भारत ने पुनः चालू कर दिया है। न्यूयार्क में अक्तूबर 2014 में 2014–15 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनावों में गिनी बिसाऊ ने भारत के पक्ष में मतदान किया। भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस) और आइटेक क्षमता निर्माण

कार्यक्रमों के तहत भारत ने क्षमता वृद्धि सहयोग निरंतर इस देश को उपलब्ध कराना जारी रखा है। वर्ष 2014–15 के दौरान देश को आइटेक कार्यक्रम के तहत 30 प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किए गए हैं।

कीनिया

भारत – कीनिया के संबंधों में विस्तार जारी है और भारत कीनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। वर्ष के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 04 बिलियन अमरीकी डॉलर के पार पहुंचा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यू एन ई ए) के मंत्री स्तरीय भाग के उद्घाटन सत्र में भारतीय प्रतिनिधिनमंडल की अगुवाई/नेतृत्व करने के लिए पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्त, सूचना एवं प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25–28 जून, 2014 तक नैरोबी का दौरा किया। यू एन ई ए के दौरान मंत्री ने एक दर्जन से अधिक पर्यावरण मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठकें कीं जिनमें कीनिया, मंगोलिया, यू एस ए, ईरान, जर्मनी, यू के, बांग्लादेश, मिस्र, श्रीलंका आदि शामिल थे। उन्होंने कीनिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।

राष्ट्रमण्डल सचिवालय द्वारा कीनिया के स्वतंत्र निर्वाचक तथा सीमा आयोग के सहयोग से आयोजित राष्ट्रमण्डल निर्वाचक नेटवर्क के तीसरे द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के निर्वाचन आयुक्त, श्री एच एस ब्रह्मा, चुनाव आयोग के महानिदेशक के साथ जून 2014 में नैरोबी का दौरा किया। आई ई बी सी के अध्यक्ष के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने दिसंबर 2014 में 03 सप्ताहों के लिए भारत में आई ई बी सी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 10 पूर्ण रूप से भुगतानवाली स्लॉटोंको बढ़ाने का निर्णय लिया।

कर्नाटक सरकार के वन, पर्यावरण व पारिस्थितिकी मंत्री, श्री रामानाथ राय ने अपर मुख्य सचिव, श्री मदन गोपाल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य वन्यजीव वार्डेन, श्री विनय लुथरा के साथ कीनिया में 20–26 अगस्त, 2014 तक एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने कीनिया सरकार के पर्यावरणव वन, सचिव से मुलाकात की और इस क्षे9 में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को तलाशा।

भारत के नौसेना प्रमुख, एडमिरल आर के धवन ने 02–06 नवंबर, 2014 तक कीनिया का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने कीनिया के नौसेना प्रमुख से मुलाकात किया और द्विपक्षीय सहयोग तथा जलदस्युता विरोधी सहयोग कार्यक्रम की समीक्षा की। कीनिया के नौसेना प्रमुख ने पूर्वी अफ्रीका क्षे9 में सामना की जा रही समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में भारतीय नौसेना प्रमुख को अवगत कराया। नौसेना प्रमुख ने कीनिया के रक्षा मंत्री से भी बातचीत की और द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर चर्चा की। कीनिया के सद्भावना यात्रा पर पश्चिमी बेड़े के भारतीय नौसेना के जहाज दीपक, तलवार तथा मुंबई ने मोमबासा का दौरा किया। भारतीय नौसैनिक जलसर्वेक्षण जहाज आई एन एस जमुना ने 14 सितंबर, 2014 तक कीनिया का दौरा किया और मण्डा खाड़ी के क्षेत्र में कीनिया नौसेना के साथ संयुक्त जलसर्वेक्षण के दूसरे चरण को पूरा किया। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एन डी सी) के एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन यात्रा पर 11–17 मई, 2014 तक कीनिया का दौरा किया। एन डी सी दल ने विदेा मामलों के कीनिया के प्रधान सचिव और न्यागमन व योजना तथा आंतरिक व समन्वय के प्रधान सचिवों से मुलाकात किया और अन्य कीनिया के मंत्रालयों और कीनिया के एन डी सी से भी विवरण प्राप्त किया।

भारतीय रिजर्व बैंक के निमंत्रण पर देश के विदेशी विनिमय रिजर्व को सुरक्षित कैसे संभाले से संबंधित तथ्यों के साझेदारी और प्रशिक्षण के लिए कीनिया के सेंट्रल बैंक के छह अधिकारियों ने मई 2014 में भारत का दौरा किया।

कृषि के क्षेत्र में भारत–यू एस–अफ्रीका त्रिकोणीय ढांचागत सहयोग के तहत राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर द्वारा 15 सितंबर –16 दिसंबर, 2014 तक आयोजित तृतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कीनिया के 15 कृषिधारक अधिकारियों ने भाग लिया।

विदेश मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा कोचिन में 05–07 सितंबर, 2014 तक संयुक्त रूप से आयोजित हिंदी महासागर वार्ता में कीनिया के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय से एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में 17–19 सितंबर, 2014 तक संयुक्त रूप से आयोजित महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पर हिंदी महासागर परिधि संघ कार्यशाला में कीनिया के डिवोलूशन मंत्रालय से दो वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया।

अवधि के दौरान कीनिया में भारतीय फर्मों ने कई व्यापार प्रचार कार्यक्रमों में भाग लिया। इसमें 27–29 अप्रैल, 2014 तक आयोजित कीनिया ऑटो कॉनपोनेण्ट शो, 02–04 मई, 2014 तक नैरोबी में आयोजित 17वां बिल्डक्सपो अफ्रीका 2014, 02–04 जून, 2014 तक नैरोबी में आयोजित केनपलास्ट 2014 प्लास्टिक मशीन तथा सामग्री प्रदर्शनी शामिल हैं।

कीनिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कीनिया सर्वोच्च न्यायलय से एक प्रतिनिधिमंडल और अन्य छह न्यायाधीश (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिशों आदि के साथ अध्ययन–सह–चर्चा दौरे पर) 08–14 जनवरी, 2015 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दौरा करेंगे।

द्विपक्षीय परामर्श के अनुवर्ती में भारत के चुनाव आयोग ने पूर्ण रूप से वित्त पोषित 03–16 दिसंबर, 2014 तक नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व चुनाव प्रबंधन संस्थान में कीनिया के सीमा आयोग तथा स्वतंत्र निर्वाचक के 10 निर्वाचक अधिकारियों के लिए एक ''विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम'' आयोजित किया।

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा 10 नवंबर से 09 दिसंबर, 2014 तक विदेशी संसदीय अधिकारियों के लिए संचालित 30वें संसदीय इंटरशीप कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए कीनिया के छह अधिकारी भारत आएं।

आई ए एफ एस–।। के तहत चेन्नई में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान में 19 नवंबर–12 दिसंबर, 2014 तक आयोजित ''पवन टरबाइन प्रौद्योगिकी तथा उपकरण'' पर 12वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कीनिया के ऊर्जा व पेट्रोलियम मंत्रालय के 04 अधिकारियों ने भाग लिया।

कीनिया की संसद के डेलिगेटेड लेजिसलेशन पर चयनित समिति का एक 07 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जनवरी 2015 में लोक सभा का दौरा करेगा। अविध के दौरान उच्च शिक्षा के लिए 28 कीनियाई राष्ट्रिकों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद छात्रवृत्तियां प्रदान की गई और आइटेक कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का 36 कीनियाई राष्ट्रिकों ने लाभ उठाया।

लिसोथो

लिसोथो का नेतृत्व भारत के प्रति झुकाव रखता है और अफ्रीका में भारत की भूमिका के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। लिसोथोने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत की उम्मीदवारी को निरंतर समर्थन दिया है और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने संबंधी हमारी आकांक्षाओं को भी पूरी तरह समर्थन दिया है।

जून 2001 से लिसोथो में स्थित भारतीय सेना प्रशिक्षण दल ने लिसोथो रक्षा बलों के व्यावसायिककरण करने में आगे और प्रगति किया है। 86.99 मिलियन रुपए के अनुदान के तहत लेरोथेली पोलिटेक्नीक में भारत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नत शिक्षा के लिए भारत–लिसोथो केन्द्र स्थापित किया गया है। युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लिसोथो में भारत सरकार द्वारा समर्थित 4.7 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण श्रृंखला के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आइटेक) के तहत लिसोथो को 70 स्लॉटें आबंटित की गईं जिसमें से अभी तक 43 का उपयोग हुआ है।

वित्त वर्ष 2014–15 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) ने लिसोथो को कुल 18 स्लॉटें आबंटित की गई और सभी 18 का उपयोग किया गया।

वर्ष 2013–14 के लिए भारत तथा लिसोथो के बीच द्विपक्षीय व्यापार 33.52 मिलियन अमरीकी डॉलर था जो क्षमताओं के काफी नीचे था। लिसोथो से भारतीय आयात की मुख्य चीजें हैं– रूई, पतले मोटे जानवर के बाल, घोड़े के बाल और बुनी हुई वस्त्र तथा वस्त्र सामग्री जबकि भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएं हैं– औषधियां, कपास, यांत्रिक आदि। वित्तीय वर्ष 2014–15 में आइटेक के तहत, लिसोथो को 60 स्लॉटें आबंटित की गईं।

अप्रैल से सितंबर 2014 की अवधि के लिए भारत और लिसोथो के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.53 मिलियन अमरीकी डॉलर था जिसमें भारत का लिसोथो को 17.68 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात और 0.85 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात शामिल है।

लाइबेरिया

भारत ने लाइबेरिया को 15 बसें उपहार स्वरूप दिया जो कि राष्ट्रपति श्रीमती एलेन जॉनसन सरलीफ की मौजूदगी में लाइबेरिया के वित्त मंत्री श्री अगस्टीन केफे गाफोन द्वारा 11 दिसंबर, 2014 को औपचारिक रूप से प्राप्त किया गया।

लिबिया

लिबिया अति अस्थिरता, आतंकवाद तथा इस्लामिक अतिवाद के साये में रहा। वहां नाजुक संस्थागत तथा सुरक्षा कमियां रहीं। यह सीमा पार हथियारों की तस्करी, धनशोधन और माली, नाइजर, नाइजीरिया, सीरिया तथा इराक में आई एस आई एस को धन प्रवाह के लिए अड्डा भी बन गया था। त्रिपोली तथा बेंगाजी में सरकारी बलों और इस्लामिकों के बीच जुलाई 2014के मध्य में आतंकी लड़ाई ने व्यापकता पकड़ी। अल–कायदा समर्थित संसार अल–शरिया ने बेत्दाजी को 'इस्लामिक प्रदेश' घोषित कर दिया। दोनों सरकारें और संसद अपने स्थान पर कायम रहे। ज्यादातर राजनयिक मिशन (यू एन, यू एस, मुख्य ई यू अरब मिशन) बंद हो गए या पड़ोसी देशोंमें अस्थायी तौर पर स्थानांतरित कर दिए गए। अक्तूबर 2014के प्रारंभ में भारतीय राजदूतावास को जरबा में (ट्यूनीशिया सीमा पर) स्थानांतरित किया गया, लेकिन लीबिया में बचे भारतीय राष्ट्रिकों को सहायता प्रदान करता रहा।

विविध उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्रों के लगभग 80 भागीदारी वाले फर्मों का (वर्तमान समय में सबसे बड़ी भारतीय भागीदारी और टी आई एफ 2014 में भाग लेने वाले आठ देशों में से विदेशी देशों की प्रतिभागिता में सबसे बड़ा) आई टी पी ओ के नेतृत्व में 'इंडिया पेविलियन' जिसने फरवरी 2011 के क्रांति के तीन वर्षों के बाद अफ्रीका के एक सबसे पुराने मेले में भारत की वापसी को दर्शाया, अप्रैल 2014 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 06 अप्रैल, 2014 को B2B संपर्क तथा बी एस एम के लिए एक 'भारत दिवस' कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

'नए लीबिया' में व्यापारिक संभावनाओं की तलाश के लिए 16 सदस्यीय सी ओ आई, सी ओ ई नेतृत्व वाली प्रतिनिधिमंडल ने 05–07 अप्रैल, 2014 तक त्रिपोली का दौरा किया।

2008–09 में लीबिया में शुरू की गई पैन–अफ्रीकी ई–नेटवर्क पहल जो कि वर्तमान में फरवरी 2011 की क्रांति के फलस्वरूप रुक गया था, को वापस शुरू करने संबंधी प्रयासों के भाग के रूप में टी सी आई एल समूह के महाप्रबंधक ने 11–14 मई, 2014 तक लीबिया का दौरा किया।

लिफा (एल आई एफ ए) के पुनर्जागरण को मनाने के लिए 24 मई, 2014 को आयोजित लीबिया भारत मैत्री संघ (लिफा) के पुनः शुरुआत बैठक के उद्घाटन में लगभग 30 पंजीकृत सदस्यों (लीबिया तथा भारतीय दोनों) ने भाग लिया। प्रथम वर्ष के दौरान लिफा को दिशा–निर्देश देने के लिए पांच सदस्यीय (लीबिया तथा भारतीय पक्ष के प्रत्येक दो और लीबियाई अध्यक्ष) एक संचालन समिति का भी गठन किया गया।

आंतरिक मंत्रालय में प्रशिक्षण विभाग के सहायक निदेशक के नेतृत्व में एक पुलिस प्रतिनिधिमंडल द्वारा अन्य चीजों के साथ राजनयिक सुरक्षा तथा पुलिस प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को तलाशने तथा चर्चा के लिए 05–09 जून, 2014 तक भारत का दौरा किया गया।

अगस्त 2014 में त्रिपोली, बेंग्हाजी तथा लीबिया के अन्य भाग में सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर 6500 भारतीयों में से 3284 को लीबिया से बाहर निकलने में सहयोग किया गया। इनमें से 1210 को पूरी तरह भारत सरकार के सहयोग (हवाई टिकट या विशेष यान या विशेष फेरी के लिए) से निकाला गया और 2014 को भारत सरकार द्वारा पूर्ण सुविधा द्वारा। शेष भारतीयों ने राजदूतावास के नियमित सलाहों के बावजूद, व्यवसाय सुरक्षा, लंबित वित्तीय कर्ज आदि कारणों के कारण छोड़ने से इनकार कर दिया।

हिंसा में वृद्धि और बिगड़ते सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनजर 19–21 दिसंबर 2014 के बीच भारत वापसी के लिए 71 और भारतीयों को सहायता प्रदान की गई जिससे जुलाई 2014 से सहायता प्राप्त भारतीयों की कुल संख्या 3371 हो गई। इनमें से 1281 सरकार के पूर्ण सहयोग से वापस लौटे जबकि 2090 को पूरा सहयोग सुविधा उपलब्ध कराया गया। अभी भी लीबिया में लगभग 2700 भारतीय हैं जिन्होंने भारत का राजदूतावास द्वारा जारी की गई सलाहों के बावजूद वापस रुकने और अपने व्यवसाय को जारी रखने का निर्णय लिया।

मेडागास्कर

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के भाग के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मेडागास्कर में भारत का फोसस, आइटेक कार्यक्रम, भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस) तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद छात्रवृत्तियों के तहत प्रदान की जाने वाली पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर है। 2014–15 के दौरान आइटेकके तहत मेडागास्कर को 100 स्लॉटें आबंटित की गई हैं। मेडागास्कर पैन–अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजना का लाभार्थी है जिसे 2016 तक बढ़ाया गया है। इमैलाका विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रदान की जाने वाली टेली–शिक्षा परियोजना के शुरुआत से अब तक 228 छात्रों को लाभ हुआ है। स्थानीय क्लीनिक के सहयोग से टेली–मेडीसिन सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं और 2010 से भारत के शीर्ष अस्पतालों में मालागेसी मरीजों को मुफ्त परामर्श और निदान दिया जा रहा है। समग्र रूप में, परियोजना के शुरुआत से अब तक 108 टेली–मेडीसिन परामर्श किया जा चुका है और परियोजना के टेली–मेडीसिन सुविधा का प्रयोग करते हुए बारह मरीजों का भारत में ईलाज हो चुका है।

अपोलो अस्पताल समूह से एक चिकित्सा प्रतिनिधिमंडल ने मेडागास्कर का दौरा किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित मालागेसी लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मई 2014 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

मुंबई में मई 2014में फार्मा तथा स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 25 मालागेसी प्रतनिधियों जिसमें सरकारी अधिकारी, आयातकर्ता, मीडिया आदि शामिल थे, ने भाग लिया।

विदेश मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में आयोजित युवा पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो युवा पत्रकारों ने भाग लिया।

इसके इतिहास में पहली बार चार भारतीय नौसैनिक जहाजों आई एन एस, मुंबई, आई एन एस, तलवार, आई एन एस, तेग तथा आई एन एस, दीपक ने अक्तूबर 2014 में मेडागास्कर का दौरा किया। भारतीय नौसैनिक कार्मिकों ने मानवीय गतिविधियों को अंजाम दिया और आपदा नियंत्रण तथा अग्निशमन और जल दस्युता विरोधी क्षेत्रों में मालागेसी नौसैनिक कार्मिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया।

मालावी

भारत–मालावी संबंध मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ रहे हैं। कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम (सी टी ए पी) के तहत मलावियों के किट नियंत्रण में प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत किट प्रबंधन केन्द्र (एन आई सी पी एम) से एक तीन सदस्यीय प्रतनिधिमंडल ने 27 जुलाई से 03 अगस्त, 2014 तक मलावी का दौरा किया। सी टी ए पी के तहत केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी आई आर ओ टी) से अन्य तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 17–20 नवंबर, 2014 तक मलावी का दौरा किया। 2014–15 के दौरान आइटेक कार्यक्रम के तहत मलावी की 60 स्लॉटें प्रदान की गई हैं।

माली

वर्ष के दौरान बहुत कम द्विपक्षीय संपर्क रहा। माली द्वारा अपने राष्ट्रीय अखण्डता और लोकतांत्रिक शासन के प्रति विद्रोही टूआरेग और सशस्त्र इस्लामिक कट्टरपंथियों से उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र में चुनौतियों का समाना करना पड़ रहा है। अपनी तरफ से भारत ने राष्ट्रीय अखण्डता को सुरक्षित रखने संबंधी प्रयासों और माली के अवसरंचनात्मक विकास के बढ़ावे को समर्थन दिया है। देश के पास एक नया प्रधान मंत्री श्री मौस्सा मारा और विदेश मामलों, अफ्रीकी एकीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए मंत्री श्री अबडोलय डिओप थे। माली में संयुक्त राष्ट्र का बहुआयामी एकीकृत स्थिरता मिशन से संबंधित अधिदेश, जो कि माली में राजनीतिक प्रक्रिया को

समर्थित करने और सुरक्षा संबंधी कई कार्य करने से संबंधित सुरक्षा परिषद के अप्रैल 2013 में एक संकल्प द्वारा स्थापित था, को इस संशोधन के साथ 30 जून, 2015 तक बढ़ाया गया था कि अब यह सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्थिरता के लिए नागरिकों का बचाव, राष्ट्रीय राजनीतिक वार्ता को समर्थित तथा समाधान करने संबंधी कार्यों पर केन्द्रित रहेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) से एक 11 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 16–18 जुलाई, 2014 तक बमाको का दौरा किया। माली के उद्योग तथा निवेश संवर्धन मंत्री श्री मुस्तफा बेन बरका ने दिल्ली में 03–07 नवंबर, 2014 तक भारत आर्थिक शिखर सम्मेलनमें भाग लिया।

अक्तूबर 2014 के उत्तरार्ध में में माली ने घातक इबोला वायरस बीमारी का संक्षिप्त अनुभव किया। नवंबर/दिसंबर 2014 में बमाको में एक अन्य समूह द्वारा अनुभव किया गया। माली के प्राधिकरणों ने डब्ल्यू एच ओ और अन्य एजेंसियों के सहयोग से संक्रमण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया और इस प्रयास के लिए बहुताय प्रशंसा प्राप्त किया।

मॉरीतानिया

जून 2014 में राष्ट्रपति श्री मोहम्मद अलद अबदेल अजीज भारी बहुमत से पुनः निर्वाचित हुए। उन्होंने कुल किए गए मतदान में से 82: मत प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्वारा बड़ा अधिदेश/जनमत प्राप्त होने पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता और न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने का वादा किया। देश के पास अगस्त 2014 में नए प्रधान मंत्री श्री याहमा उलद हदेमाइन थे जिन्होंने श्री मौलय उदल मोमम्मद लघादक को प्रतिस्थापित किया था। अगस्त 2014 में भारत सरकार ने सौर–डीजल उन्नत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए मॉरीतानिया को 65.68 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक ऋण श्रृंखला को अनुमोदित किया। यह विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पूर्व में 21.8 मिलियन अमरीकी डॉलर के दिए गए अनुदान के अतिरिक्त है जो कि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणोंमें है।

मॉरीशस

भारत और मॉरीशस के बीच संबंध समय परिक्षित विशेष और बहु–मुखी हैं। साझे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लगाव से जुडा यह भागीदारी काफी बढ़ा है और आज गतिविधियों और आयामों के विविध मान व्यापक स्तर पर एक नई ऊर्जा के साथ संजोए हुए हैं और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान–प्रदान को बढ़ावा दिया है। व्यक्तिगत तौर पर मई 2014 में ऐतिहासिक चुनाव परिणाम पर प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सर्वप्रथम बधाई देने वाले विश्व के नेताओं में से प्रधान मंत्री डॉ0 नवीनचंद्र रामगुलाम भी थे।

नई सरकार में शपथ ग्रहण में साक्षी बनने वाले और गैर–सार्क राष्ट्रों के नेताओं में आमंत्रित नेता के रूप में उन्होंने 25–28 मई, 2014 तक नई दिल्ली का दौरा किया। प्रधान मंत्री डॉ0 नवीनचंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात किया और भारत–मॉरीशस संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा किया।

मॉरीशस के राष्ट्रपति श्री राजकेसवूर पुरमाग ने अखिल भारतीय बुद्धिजीवी सम्मेलन 2014 में मुख्य अतिथि के रूप में 02–10 जून, 2014 तक बैंगलुरु तथा मैसूर का दौरा किया।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के आगमन के 180वें वर्षगांठ के राष्ट्रीय उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 01–03 नवंबर, 2014तक मॉरीशस का दौरा किया। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति श्री राजकेसवूर पुरमाग, प्रधान मंत्री डॉ0 नवीनचंद्र रामगुलाम, उप प्रधान मंत्री डॉ0 ए आर बीबेजॉन, विदेश मंत्री अरविन बुलेल और नेता प्रतिपक्ष श्री प्रविन्द जुगनाथ से द्विपक्षीय बैठकें कीं। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ0 एम चुन्नी द्वारा उन्हें दोपहर भोजन संबंधी बैठक पर भी बुलाया गया। दौरे के दौरान विदेश मंत्री ने पांच सार्वजनिक कार्यक्रमों को सम्बोधित किया और आई ओ आर ए चार्टर पर हस्ताक्षर किया।

हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त ई ई जेड निगरानी और गश्त के अतिरिक्त मॉरीशियाई प्राधिकारियों को बाहरी द्वीप सहयोग उपलब्ध कराने के लिए भारतीय नौसेना का पश्चिमी बेड़ा, आई एन एस त्रिशुल और आई एन एस सुकन्या ने मॉरीशस का दौरा किया। तैनाती के दौरान बेड़े के कार्मिकों ने मॉरीशस पुलिस बल/राष्ट्रीय तटरक्षक कार्मिकों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया और राष्ट्रीय तटरक्षक कार्मिकों के साथ कई परोपकार और मैत्रीपूर्ण खेलों को संचालित किया। जहाजों की यात्रा ने व्यापक लोक इच्छा को भी बढ़ाया और 5000 से अधिक जनमानस ने जहाजों का दौरा किया क्योंकि वे पोर्ट लुई बंदरगाह पर ठहरे हुए थे।

मॉरीशियाई जल सर्वेक्षण इकाई स्थापित करने हेतु मॉरीशस में तैनात भारतीय जल सर्वेक्षण दल ने पोर्ट लुई बंदरगाह और इसके अभिगम भू–सर्वेक्षकों तथा अन्य भागीदारों का प्रशिक्षण से संबंधित व्यापक जल सर्वेक्षण किया और समुद्री सीमा के सीमांकन के लिए आंकड़े को दर्शाया। भारतीय जल सर्वेक्षण विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई मॉरीशियाई समुद्र के 150 समुद्री चार्टों को नवंबर 2014 में मॉरीशस की सरकार को सुपुर्द कर दिया गया।

भारत मॉरीशस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान भारत ने 1000.8 मिलियन अमरीकी डॉलर का सामान मॉरीशस को निर्यात किया और 20.79 मिलियन अमरीकी डॉलर का सामान मॉरीशस से आयात किया।

भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू करने के उपलक्ष्य में भारतीय मिशन ने 25 सितंबर, 2014 को एक व्यापारिक गोलमेज आयोजित किया था। मॉरीशस के उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री श्री सिडर सय्यद हसन को मुख्य अतिथि

विदेश मंत्री ने 02 नवंबरए 2014 को पोर्ट लुई में मॉरीशस के राष्ट्रपति श्री कैलाश पुरयाग से मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने 02 नवंबर, 2014 को पोर्ट लुई में मॉरीशस के प्रधान मंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से मुलाकात की।

विदेश मंत्री 02 नवंबर, 2014 को मॉरीशस में अप्रवासी दिवस के 108वें स्मरणोत्सव को सम्बोधित करती हुईं।

दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री को नेल्सन मंडेला का पोट्रेट भेंट करती हुईं।

के रूप में आमंत्रित किया गया था। 50 से भी अधिक मॉरीशस के व्यापारिक नेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और लोक तथा निजी क्षेत्र के भारतीय कंपनियों के प्रमुख अभियान के शुरुआत (लॉच सेरेमनी) के साक्षी बने और यह मॉरीशस प्रसार निगम द्वारा सीधा प्रसारित किया गया।

दस तेज अवरोधक नावों की आपूर्ति हेतु संविदा को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए गोवा शिपयार्ड (पोत कारखाना) लिमिटेड से एक प्रतिनिधिमंडल ने 31 मार्च–04 अप्रैल, 2014 तक मॉरीशस का दौरा किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लिमिटेड द्वारा मॉरीशस सरकार को एक वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (जलीय तीव्र हमलाकारक यान) देने और उसके डिजाइन, निर्माण के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर करने तथा तकनीकी चर्चा हेतु गोवा शिपयार्ड से एक अन्य प्रतनिधिमंडल ने 04–07 मई, 2014 तक मॉरीशस का दौरा किया।

राजदूत श्री सतीश मेहता, भारतीया सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक ने 11–14 मई, 2014 तक मॉरीशस का दौरा किया। दौरे के दौरान महात्मा गांधी संस्थान ने संस्कृत तथा भारतीय दर्शनशास्त्र में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पीठ स्थापित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) से दो सदस्यीय प्रतनिधिमंडल ने ई–प्रीजन सॉफ्टवेयर समूह के उद्घाटन के लिए 20–23 मई, 2014 तक मॉरीशस का दौरा किया जो कि मॉरीशस सरकार के लिए एन आई सी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

27 अगस्त, 2014 को राजदूत श्री किशन राणा (सेवानिवृत्त) ने मॉरीशस इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमैसी, विदेश मंत्रालय में छोटे देश कुटनीति और विदेश मंत्रालय सुधारों पर कुछ व्याख्यान दिए।

सामरिक पड़ोस अध्ययन यात्रा के भाग के रूप में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से रियर एडमिरल आर गायकवाड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 25–27 अगस्त, 2014 तक मॉरीशस की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति श्री राजकेसवूर परमाग, उप प्रधान मंत्री श्री ए के बच्चू, विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव और आई ओ आर ए के महासचिव से मुलाकात किया। प्रसार भारती के सी ई ओ श्री जवाहर सिरकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 31–03 सितंबर, 2014 तक मॉरीशस का दौरा किया। प्रसार भारती और मॉरीशस प्रसारण निगम के बीच प्रसारण सामग्री का साझा करना, सह–उत्पादन तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित कई सांस्कृतिक समूहों ने, जिसमें सुश्री पुरवा धनश्री के नेतृत्व में भरतनाट्यम समूह (अप्रैल 2014), श्री मोरु सपेरा के नेतृत्व में राजस्थानी संगीत एवं नृत्य समूह (मई 2014), सुश्री सोनम कालरा के नेतृत्व में श्सूफी संतवाणी परियोजनाश फ्यूजन समूह (अक्तूबर 2014) तथा डॉ0 पुष्पा प्रसाद के नेतृत्व में भोजपुरी लोक संगीत और नृत्य (नवंबर 2014) शामिल है, ने मॉरीशस में प्रस्तुतियां दी।

मॉरीशस के निर्वाचक आयुक्त, श्री इरफान ए रहमान ने वाराणसी तथा कोलकाता में आखिरी चरण के मतदान और गिनती प्रक्रिया सहित ई वी एम के वैक अप पेपर ट्रेल के अध्ययन हेतु आम चुनाव के दौरान 10–18 मई, 2014 तक भारत का दौरा किया।

श्री लोरमस बंधु, मॉरीशस के स्वास्थ्य एवं उत्तम जीवन के मंत्री ने अपने राष्ट्रीय ई–स्वास्थ्य परियोजना पर 20–29 सितंबरए 2014 तक भारत में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मंत्री श्री लोरमस बंधु ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ0 हर्षवर्धन और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री श्री रवि शंकर के साथ बैठकें भी कीं। भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के दौरे के अतिरिक्त कई आधिकारिक स्तर की बैठकें भी हुईं।

मोरक्को

भारत और मोरक्को के बीच संबंध ऐतिहासिक तथा सौहार्दपूर्ण रहा है। मोरकको ने अगस्त 2014 में नई दिल्ली में अरब स्टेट्स मीडिया सिपपोजियम के प्रथम भारत अरब लीग में भाग लिया। 07 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम भारत–अबर लीग वरिष्ठ अधिकारियों (एस ओ एम) की बैठक में भी मोरक्को के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। वैश्विक आतंकवादरोधी मंच (जी सी टी एफ) के समन्वय समिति की 5वीं बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आतंकवादरोधी) श्री विनय मोहन क्वात्रा ने 02–03 अप्रैल, 2014 तक मोरक्को की यात्रा की।

2014 की प्रथम छमाही में भारत और मोरक्को के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने 622.8 मिलियन अमरीकी डॉलर को छुआ। भारत से मोरक्को को 241.2 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात रहा और मोरक्को से भारत में 381.6 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात रहा।

मोजाम्बिक

मोजाम्बिक के उप शिक्षा मंत्री श्री अरलिन्डो चिलण्नडो ने विदेश मंत्रालयव सहयोग और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भारत में अध्ययन कर रहे मोजाम्बिक छात्रों से मिलने और नई दिल्ली स्थित मोजाम्बिक मिशन के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए 06–15 जून, 2014 तक भारत का दौरा किया।

विदेश मंत्रालय व सहयोग के मंत्री श्री ओलडेमीरो बलोई ने 23–30 नवंबर, 2014 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत किया और तेल गैस के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों (पी एस यू ए) के प्रतिनिधियों से भी बातचीत किया और विश्व कार्य मामले की

भारतीय परिषद में मोजाम्बिक विदेश नीति के परिदृश्य पर व्याख्यान दिया।

सेल एवं आई सी वी एल के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें संयुक्त सचिव (इस्ताप मंत्रालय), सी एम डी (आर आई एम एल), सी एम डी (एन डी एम सी) और सी ई ओ (आई वी सी एल) शामिल हैं, ने 23–25 जून, 2014 तक मोजाम्बिक का दौरा किया और अन्य आधिकारिक व्यस्तताओं के बीच खनिज संसाधन मंत्री के साथ बैठक की। 08 अक्तूबर, 2014 को सेल, सी आई एल, आर आई एन एलए एन डी एम सी तथा एन टी पी सी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल कोल वेनचर प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल) आफ इंडिया ने 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के लागत से बेंगा कोयला खादान और टेटे के पश्चिम प्रांत में अन्य दो कोयला परियोजनाओं में रीओ टिन्टों के 65: अंश अर्जित किया।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित भारत सरकार और मोजाम्बिक के बीच 23 अप्रैल, 2014 को मपूतो में एक समझौता ज्ञापन पर मोजाम्बिक राज्य प्रशासन मंत्री और भारत के उच्चायुक्त द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

15 जुलाई, 2014 को राष्ट्रपति श्री अरमान्डो गुबुजा ने औपचारिकरूप से 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारत सरकार की ऋण श्रृंखला के तहत मालूआने में (मपूतो से 60 कि.मी.) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क में विकिसत प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार केन्द्र (अप्रैल–अगस्त 2014) में द्विपक्षीय व्यापार 819.64 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा जिसमें 728.39 मिलियनका भारतीय निर्यात और मोजाम्बिक से 91.25 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात शामिल है।

आइटेक, आई ए एफ एस तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कार्यक्रमों द्वारा मोजाम्बिक में क्षमता निर्माण सहयोग जारी है। 2014–15 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद छात्रवृत्ति के तहत, 41 मोजाम्बिक छात्र, आइटेक कार्यक्रम के तहत 10 अधिकारियों और आई ए एफ एस–।। के तहत 04 अधिकारियों को भारत भेजा गया।

मार्च 2014 में, भारतीय कंपनी एस्सार ने मोजाम्बिक सरकार से बेरा बंदरगाह पर मोजाम्बिक राज्य रेलवे और पोर्ट कंपनी, सी एफ एम के सहयोग से कोयला टर्मिनल के बनाने और चलाने के लिए दीर्घामी समय के लिए रियायत प्राप्त किया। एसोचैम (एएसएसओ सीएचएएम) के तत्वाधान में 45 भारतीय कंपनियों ने 25–31 अगस्तए 2014 तक मपूतो अंतर्राष्ट्रीय मेले (एफएसीआईएम) के 50वें संस्करण में भाग लिया।

विदेश मंत्री के निमंत्रण पर विदेश मंत्री श्री ओलडेमीरो बलोई ने 23–29 नवंबरए 2014 तक भारत का दौरा किया। 29 नवंबर 2014 को विदेश मंत्री श्री ओलडेमीरो बलोई ने द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा सामरिक हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा किया। दौरे के दौरान विदेश मंत्री श्री ओलडेमीरो बलोई ने तेल और गैस के क्षेत्र में भारत–मोजाम्बिक सहयोग से संबंधित हमारे पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

आई एन एस तेगए एक स्टिल्थ फ्रीगेट ने मोजाम्बिक के नामपुला प्रांत में नकाला बंदरगाह पर 17–20 नवंबर, 2014 तक सद्भावना दौरा किया। जहाज अपने साथ 200 अभ्यास आधारित राईफल्स भी ले गया था जिसे मोजाम्बिक सरकार के प्रतिनिधियों को भारत सरकार की ओर से उपहार के रूप में सुपुर्द किया गया।

नामीबिया

नामीबिया विश्वविद्यालय के ओंगवेदिवा परिसर में स्थित इंडिया विंगए भवन जिसने खनन इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के दो संकायों को समाहित कर रखा है, का आधिकारिक तौर पर 03 जूनए 2014 को यू एन एम के ओंगवेदिवा परिसर में सम्पन्न एक समारोह में उद्घाटन किया गया। भवन का उद्घाटन डॉ0 सैम नूजोमाए नामीबिया के संस्थापक अध्यक्ष द्वारा किया गया जो कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी है। उद्घाटन समारोह में नामीबिया सरकार और उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण हस्तियों ने भाग लिया। भवन का निर्माण नामीबिया सरकार को भारत सरकार द्वारा 12.13 मिलियन अमरीकी डॉलर के दिए गए अनुदान से हुआ है।

नाइजर

नाइजर को भारत सरकार द्वारा 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की दी जा रही ऋण श्रृंखला से वित्त पोषित ग्रामीण और अर्ध शहरी समुदाय के लिए पेय जल से संबंधित परियोजना के लिए वामकोस को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त करने हेतु अप्रैल 2014 में नाइजर सरकार के जलीय व स्वच्छता मंत्रालय और वापकोस लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) के बीच करार पर हस्ताक्षर हुआ।

एम एफ ए के महासचिव, श्री इब्राहिम सानी अबानी ने सी ई एन–एम ए डी के महासचिव के रूप में 20–21 अगस्त, 2014 तक नई दिल्ली में आयोजित तृतीय अफ्रीकी क्षेत्रीय समुदाय की बैठक में भाग लिया। 2014–15 में आइटेक कार्यक्रम के तहत नाइजर को आबंटित किए गए 135 स्लॉटों में से अभी तक कुल 100 स्लॉटों का भी उपयोग किया। दो नाइजररियाई छात्रों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्तियों का प्रयोग किया और एक नाइजीरियाई विद्वान ने भारत में पोस्ट–डोक्टोरल अनुसंधान करने के लिए अफ्रीकी अनुसंधानकर्ताओं को दी जाने वाली सी वी रमन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति का उपयोग किया। पैन–अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजना के टेली–एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा) भाग के तहतए 248 नाइजररियाई छात्रों ने अमिटी विश्वविद्यालय में नामांकन कराया जबकि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 24 छात्रों ने मद्रास

विश्वविद्यालय में नामांकन कराया।

नाइजर के निजी क्षेत्र के वाणिज्य एवं संवर्धन मंत्री श्री अल्मा क्यूमास ने भागीदारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए 15–17 जनवरी, 2015 तक जयपुर का दौरा किया। 2014–15 में नाइजर आइटेक के कुल 122 स्लॉटों का उपयोग कर चुका है।

नाइजीरिया

अबूजा में हमारे मिशन ने 31 मार्च दृ 06 अप्रैलए 2014 तक अभी तक का पहला भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया था जिसका उद्घाटन नाइजीरिया की प्रथम महिला, श्रीमती डेम पेशन्स जोनाथन द्वारा किया गया था। सप्ताह भर के महोत्सव के दौरान, सिल्वर बर्ड सिनेमा परिसर में चर्चित हिंदी फिल्मों को दिखाया गया।

भारतीय कंपनी मैसर्स स्किपर के निमंत्रण पर कानो राज्य के राज्यपाल श्री मोहम्मद राबीयू क्वानकवासो के नेतृत्व में एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 19–22 अप्रैल, 2014 तक भारत का दौरा किया। 22 मई, 2014 को अफ्रीकी विकास बैंक बैठक के साथ ही ऐक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के के. सी. एम. डी. और नाइजीरिया के वित्त मंत्री ने नाइजीरिया के इनूग, कादूना और किगाली, रवाण्डा के रिवर स्टेट के तीन विद्युत परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के लिए हस्ताक्षर किए। एल बी एम में भारतीय पीठ को जारी रखने से संबंधित 19 सितंबर, 2014 को लागोस में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लागोस बिजनेस स्कूल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

दूसरे संयुक्त रक्षा सहयोग समिति बैठकों के लिए संयुक्त सचिव (पी आईसी), रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतनिधिमंडल ने 06–09 मई, 2014 तक नाइजीरिया का दौरा किया। उन्होंने रक्षा मंत्री ले जे अलियू मोहम्मद गुसाउ और रक्षा स्टाफ के प्रमुखए एयर चीफ मार्शल अलेक्स साबुनुदु बदेह से मुलाकात की। मैसर्स पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के एम डी व अध्यक्ष श्री दीपक अमिताभ के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतनिधिमंडल ने 20–24 जुलाई, 2014 तक अबूजा का दौरा किया। दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने नाइजीरिया के विद्युत मंत्री प्रो0 चिनेजू ओ नेबो और विद्युत के क्षेत्र में अन्य नाइजीरियाई धारकों से बैठकें कीं। ब्रीगे डी विक्टर राजामनी के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय भारतीय सेना के प्रतनिधिमंडलने 11–14 अगस्त, 2014 तक नाइजीरिया का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अपने प्रतिपक्षके साथ मुलाकात किया और नाइजीरिया सेना के प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा किया। भारतीय वायुसेना और हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड (एच ए एल) के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक सात सदस्यीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने 22–26 सितंबर, 2014 तक नाइजीरिया का दौरा किया। उन्होंने प्रशिक्षणए मरम्मत और रक्षा उपकरणों के रख–रखाव आदि से संबंधित नाइजीरिया वायुसेना के साथ बातचीत किया।

एक 11 सदस्यीय नाइजीरियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 22–26 जून, 2014 तक भारतका दौरा किया और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात किया। संग्रहालय से संबंधित नाइजीरियाई संसदीय समिति से एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 06–07 अगस्त, 2014 को भारत का दौरा। नाइजीरिया के आयोग, व्यापार एवं निवेश मंत्री श्री ओलूसेगन अगंगा ने एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 10–13 सितंबर 2014 तक भातर का दौरा किया। नाइजीरिया के मंत्री ने सी आई आई द्वारा आयोजित एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी सम्बोधित किया। नाइजीरियाई रक्षा अकादम, कादूना से दो प्रक्षिक्षकों और तीन कैडेटों के रूप में 07–17 जुलाई, 2014 तक भारतीय नौसेना अकादमीए इझीमाला (केरल) का दौरा किया। नाइजीरिया रक्षा अकादमी कदूना से दो अधिकारियों और चार कैडेटों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों संस्थानों के बीच व्युतक्रम दौरे के रूप में एन डी एए खड़गवासला का 15–21 अक्तूबर, 2014 तक दौरा किया।

नाइजीरिया को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सम्भावित आपूर्ति करने के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बैंगलुरु से एक दो सदस्यीय दल ने 10 से 14 दिसंबर, 2014 तक लागोस का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, बी ई एल दल ने लागोस के राज्यपाल से भी मुलाकात किया और ई वी एम के प्रयोग पर प्रस्तुति दी। रक्षा सहयोग आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत एन डी एए खड़गवासला से एक 05 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 21–23 नवंबर, 2014 तक नाइजीरिया का दौरा किया। दोनों देशों के स्टाफ कॉलेजों के बीच दौरों का आदान–प्रदान के भाग के रूप में डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ कॉलेजए वेलिगृंटन (भारत) से कमांडेन्ट अजय जनजोना की नेतृत्व में एक 03 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 15–20 दिसंबरए 2014 तक नाइजीरिया का दौरा किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जन्मशती मनाने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, श्री ओलूसगन ओवासजो ने 16–17 नवंबरए 2014 तक भारत का दौरा किया। नाइजीरिया–भारत तकनीकी मंच स्थापित करने और आई टी हल, कुशल श्रमशक्ति के विकास से संबंधित भारत के साथ संभावित सहयोग के लिए नाइजीरियाई संघीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (एनआईटीडीए) से एक 06 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतनिधिमंडल ने 09–12 दिसंबर, 2014 तक भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने नासकोम, इनफोसिस तथा कोगनिजार के साथ बैठकें कीं।

नाइजीरिया रक्षा अकादमी, कदूना जो कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित किया गया था, के स्वर्ण जयंती समारोह को मनाने के लिए

16 जनवरी, 2015 को भारतीय उच्चायोग के परिसर में एक रात्रिभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में नाइजीरिया के सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों (सेवार्त एवं सेवानिवृत्त दोनों) सहित रक्षा मंत्री और सीनेट के अध्यक्ष ने भाग लिया। सितंबर 2014 में नाइजीरिया रक्षा अकादमी, कदूना ने भी अपने स्वर्ण जयंती समारोह को आयोजित किया था जिसमें नाइजीरिया की तरफ से नियंत्रण पर तीन वरिष्ठ सेवानिवृत्त भारतीय अधिकारियों द्वारा उसमें भाग लिया गया।

कांगो गणराज्य (आर ओ सी)

भारत सरकार द्वारा समर्थित 70 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण श्रृंखला परियोजना से किया जाने वाला ग्रामीण विद्यतीकरण परियोजना का कार्य प्रगति पर है। 2014 में भारत सरकार दो और ऋण श्रृंखलाओं को अनुमोदित किया (i) राजधानी ब्राज़ाविले और पॉन्टे नोइरे में परिवहन प्रणाली के विकास के लिए 89.9 मिलियन अमरीकी डॉलर और (ii) आर ओ सी में ग्रीन फिल्ड 600 टी पी डी घुमाऊ भट्टी आधारित सीमेंट कारखाना परियोजना के लिए 55 मिलियन अमरीकी डालर। 2013–14 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 306.53 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

रवाण्डा

इस वर्ष सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में भारत–रवाण्डा के संबंध आगे बढ़े हैं। भारत–अफ्रीका मंच में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति श्री पौल कगामे ने 03–05 नवंबर, 2014 तक भारत का दौरा किया। अपने यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात किया।

जून 2014 में नयाबोरोगो जलविद्युत परियोजना की प्रगति को देखने के लिए भारी उद्योग विभाग के सचिव, डॉ0 सुतानू बेहुरिया ने किगाली का दौरा किया। दौरे के दौरान सचिव ने रवाण्डा के अवसंरचना मंत्री प्रो0 सिलास लवाकादम्बा से मुलाकात किया।

ऐक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला से विकसित 28 मेगावाट के नमाबोरोगो जलविद्युत परियोजना ने ग्रीड को बिजली की आपूर्ति शुरू कर दिया है।

आई ए एफ एस–। के तहत प्रतिबद्ध एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वी टी सी) पूरा होने के उच्च स्तर पर है और 2015 के अंत तक तैयार होने की संभावना है।

रवाण्डा की सरकार ने पैन–ईस्ट अफ्रीकी सामुदायिक कृषि बीज उत्पादन सह प्रस्तुति केन्द्र को स्थापित करने के लिए जमीन को चिह्नित कर लिया है जो कि आई ए एफ एस–।। के दौरान रवाण्डा में स्थापित किया जा रहा है। परियोजना को आगे ले जाने के लिए एक भारतीय विशेषज्ञ दल ने नवंबर 2014 में किगाली का दौरा किया।

आई ए एफ एस–।। के दौरान किगाली में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एफ टी एल) स्थापित करना प्रस्तावित है। आवश्यक करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत सरकार द्वारा अपेक्षित उपकरणों का प्रापण किया जा रहा है।

भाग लेने के लिए फिक्की और ऐक्जिम बैंक के एक 20 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 19–23 मई, 2014 तक रवाण्डा का दौरा किया। इसके साथ हीए ऐक्जिम बैंक ने फिक्की के भागीदारी के साथ 22 मई, 2014 को रवाण्डा में ''परियोजना के विकास और वित्तपोषण में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना'' विषय के तहत भारत–अफ्रीका भागीदारी दिवस को आयोजित किया था।

सीआईआई के एक 12 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 14–17 सितंबर, 2014 तक रवाण्डा का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने किगाली में विश्व निर्यात विकास मंच में भी भाग लिया।

देश में व्यापारिक संभावनाओं को तलाशने और भारत सरकार के रियायती ऋण श्रृंखला के तहत विकसित की जा रही नमाबोंरोगो जलविद्युत परियोजना की प्रगति देखने के लिए ऐक्जिम बैंक से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 02–08 नवंबर, 2014 रवाण्डा का दौरा किया।

आइटेक–स्कैप के तहत रवाण्डा को 30 स्लॉटें आबंटित की गई हैं। 29 स्लॉटों का पहले ही उपयोग हो चुका है। स्नातक, पूर्व–स्नातक तथा पीएच डी कार्यक्रमों के लिए 12 रवाण्डा के लोगों ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्तियों का उपयोग किया है। सी वी रमन शिक्षावृत्ति पर 02 रवाण्डा के व्यक्तियों ने भारत की यात्रा भी किया। इसके अतिरिक्त आईएएफएस के तहत रवाण्डा को चार छोटे अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आबंटित किए गए हैं।

ग्रामीण रवाण्डा में 35 स्कूलों का सौर विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है और कार्यान्वित है। परियोजना भारत सरकार की ओर से सहायता अनुदान था।

पैन अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजनाए विशेषकर टेली–मेडिसीन भाग, सफलतापूर्वक प्रचालित है।

साओ टोमेव प्रिंसिपे

दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। साओ टोमे व प्रिंसिपे सरकार द्वारा पैन–अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजना का कार्यान्वयन आराम से बढ़ रहा है।

सेनेगल

भारत और सेनेगल उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों का उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने सेनेगल में चावल स्व पर्याप्तता कार्यक्रम के लिए लिफ्ट सिंचाई के प्रथम चरण के लिए 62.95 मिलियन डॉलर की एक ऋण श्रृंखला अनुमोदित किया है। भारत सरकार ने सेनेगल सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के दूसरे चरण के लिए 27.5 मिलियन अमरीकी डॉलर मात्स्यिकी विकास परियोजना के दूसरे चरण के लिए 19 मिलियन अमरीकी डॉलर और आधुनिक

कसाईखाना, मांस प्रसंस्करण, ठण्डा भण्डारण, प्रतिदान तथा मसाला संयंत्र और बाजार स्थापित करने के लिए 41.96 मिलियन अमरीकी डॉलर पहले ही दे दिया है। सेनेगल के संबंध में कुल विकासात्मक सहयोग लगभग 300 अमरीकी डॉलर है।

अक्तूबर 2014 में 2015–17 के लिए न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनावों में सेनेगल ने भारत के पक्ष में मतदान किया। सेनेगल उपग्रह आधारित पैन अफ्रीका ई–नेटवर्क परियोजना के लिए मुख्य केन्द्र होने के नाते, यहां से सभी अफ्रीकी राष्ट्रों को टेली मेडिसीन तथा टेली ऐजुकेशन कार्यक्रमों का प्रसारण जारी है। पेशेन्ट एण्ड लोकेशन की सुविधा के लिए उपकरण पहले से ही कार्यरत और प्रचालित है। परियोजना को आगे दो वर्ष की अवधि 13 जुलाई, 2016 तक बढ़ाया गया है।

भारत ने सेनेगल को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण से संबंधित अवसरों को उपलब्ध कराना जारी रखा है और आइटेक कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014–15 के लिए देश को 30 स्लॉटें आबंटित की गई हैं। इस क्षमता निर्माणके अतिरिक्त, भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन तथा सी वी रमन छात्रवृत्तियों के तहत भी सहयोग प्रदान किया जाता है। तकनीकी कौशल विकास के लिए रक्षा कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण के लिए भी भारत के पास सहयोगात्मक अवसर है। सेनेगल की सरकार नए शहर दिमनीयादिओ में एक फिल्म सिटी विसकित करने के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। डकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले भारतीय कंपनियां भाग लेती रही हैं और फेडेरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट और गेनाइजेशन (भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ) एफ आई डी ए के 2014 के संस्करण में भी संभवतः भाग लेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यापार, सांस्कृतिक तथा वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल का दौरा बढ़ा है। वर्ष 2013–14 का द्विपक्षीय व्यापार 580.087 मिलियन डालर रहा।

सेशल्स

1976 से राजनयिक संबंधों की शुरुआत से भारत–सेशल्स के संबंध घनिष्ठ हुए हैं। वर्ष के दौरान सेशल्स के साथ द्विपक्षीय संपर्क आगे विस्तारित हो गए जिसमें रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग से लेकर विकास भागीदारी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम समाहित है। कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत वाले बड़े भारतीय बहुल जनसंख्या के लिए समुदाय संबंधि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, लिए गए कई पहलों ने भी अवधि को यादगार बढ़ाया। लोगों का लोगों से संपर्क को सुविधाजनक बनाने के अतिरिक्त, आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंधों, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच सम्पर्कता को सुधारने पर फोकस था।

द्विपक्षीय राष्ट्रों के व्यापक अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) के निगरानी करने संबंधी अपने मिशन के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक पोत आई एन एस त्रिशुल ने 29 अप्रैल से 07 मई, 2014 तक सेशल्स का दौरा किया। छह महीने बाद निर्धारित समुद्री गश्त यात्रा के लिए आई एन एस सुकन्या, 23 अक्तूबर, 2014 को विक्टोरिया बंदरगाह पर पहुंचा जिसके दौरान उसने अपने अगले गंतव्य के लिए 04 नवंबर, 2014 तक सेशल्स द्वीपपुंज के दक्षिणी पानी में ई ई जेड निगरानी किया।

भारत और सेशल्स ने हवाई सेवाओं से संबंधित द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एयर सेशल्स ने दिसंबर, 2014 के प्रथम सप्ताह से भारत के लिए सीधे उड़ान सेवाएं शुरू कर दिए जिससे दोनों देशों के बीच लोगों का लोगों से संपर्क के अध्याय में एक नए दौर की शुरुआत हुई है।

अवधि का मुख्य आकर्षण सेशल्स की समुद्री सीमा जिसमें 1.3 मिलियन वर्ग किमी का एक व्यापक ई ई जेड शामिल है कि निगरानी और गश्त समक्षता को बढ़ानेके लिए सेशल्स को 07 नवंबर, 2014 को भारतीय नौसैनिक पोत, आई एन एस तरासा को उपहारस्वरूप भेंट करना रहा। भारतीय नौसेना के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धवन ने सेशल्स के राष्ट्रपति श्री जेम्स अलिक्स मिशेल की मौजूदगी में औपचारिक रूप से सुपुर्द करने संबंधी समारोह में भाग लेने के लिए 06–07 नवंबर, 2014 तक सेशल्स का दौरा किया। सेशल्स के तटरक्षक बेड़े में शामिल होने पर पोत को दोबारा ''पी एस कौसटेन्ट'' का नाम दिया गया। 2006 में पी एस टोपाज के बाद सेशल्स को उपहारस्वरूप भेंट दिया जाने वाला यह दूसरा भारतीय नौसैनिक पोत है।

आई एन एस तरासा की सुपुर्दगी और नौसेना प्रमुख के दौरेसे संयोग रखते हुए पश्चिमी बेड़े के तीन भारतीय नौसैनिक पोत, आई एन एस दीपक, आई एन एस मुंबई तथा आई एन एस तलवार ने 06–09 नवंबर, 2014 तक विक्टोरिया बंदरगाह पहुंचे। जहाजों को जनता के लिए खोले जाने पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र में भारतीय नौसेना बैण्ड द्वारा सार्वजनिक प्रस्तुति और तीनों जहाजों के कार्मिकों द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं परोपकार्य कार्य करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त किया।

द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग के भाग के रूप में सेशल्स पीपल्स डिफेंस फोर्सेज (एस पी डी एफ) के लिए आइटेक के तहत भारत में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। सैन्य सलाहकार, समुद्री सुरक्षा सलाहकार, चिकित्सा सलाहकार तथा नौसेना सलाहकार (तकनीकी) के रूप में आइटेक के प्रतिनियुक्तिाओं को एस पी डी एफ के साथ तैनात किया गया। सेशल्स सरकार के अनुरोध के प्रति उत्तर में मई 2014 में भारत सरकार द्वारा एस पी डी एफ को दो सैनिक वाहनों को दिया गया।

सिएरा लियोन

20 नवंबर, 2014 को फ्रीटाउन में भारत के मानद कौंसुल ने ईबोला वायरस बीमारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा दान में दी

गई दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों (50,000 अमरीकी डॉलर मूल्य का) को राष्ट्रपति श्री अरनेस्ट बाई कोरोमा को औपचारिक रूप से सौंपा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने डब्ल्यू एच ओ को 500,000 अमरीकी डॉलर की नगद सहायता उपलब्ध कराया, ईबोला के लिए यू एन ट्रस्ट फण्ड को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान दिया और पश्चिम अफ्रीका के प्रभावित देशों में ई वी बी से निपटने के लिए संरक्षणात्मक बचाब गियर खरीदने के लिए अतिरिक्त 02 मिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्ध कराए।

सोमालिया

यह मूल्यांकित किया गया कि वर्ष के दौरान क्षेत्र में विभिन्न विरोधों के बावजूद, सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन मिशन के सहयोग से सोमालिया सशस्त्र बलों द्वारा अल शबाब के विरुद्ध लड़ाई में प्रगति किया और सोमालिया ''कार्य में सकारात्मक दृष्टिकोण'' बनाये रखा। हालांकि, वर्ष के अंत में देश की स्थिरता को प्रभावित करने वाले राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के बीच राजनैतिक बंटवारा हुआ।

कीनिया के लिए भारत के उच्चायुक्त और साथ ही सोमालिया के लिए अधिमान्य भारत के राजदूत ने 22–25 अगस्त, 2014 तक सोमालिया का दौरा किया और अलग–अलग सोमाली मंत्रियों के समूहों से मुलाकात किया। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। सोमालिया के विदेश मंत्रालय व निवेश संवर्धन के स्थाई सचिव श्री अब्दुलाही दूल ने विदेश मंत्रालय एवं ऑबजर्वर रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा संयुक्त रूप से कोचिन में 05–07 सितंबर, 2014 तक आयोजित हिंदी महासागर वार्ता में भाग लिया।

एम वी डायर साहसिक कार्य दल के सात भारतीय सदस्यों जिन्हें सोमाली जलदस्युओं द्वारा सितंबर 2010 से बंधक बनाया गया था, को जलदस्युओं द्वारा 30 अक्तूबर 2014 को मुक्त किया गया। वे 02 नवंबर, 2014 को मुंबई पहुंचे।

अवधि के दौरान 12 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्तियों का उपयोग हुआ।

दक्षिण अफ्रीका

भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत होने के साथ–साथ रंगभेद के खिलाफ हमारे ए एन सी आधारित आंदोलन के लिए सैद्धांतिक और नियमित सहयोग/समर्थन के ऐतिहासिक संपर्कों तथा संबंधों पर आधारित है। 1994 के बाद राजनीतिक संबंध काफी अच्छी तरह विकसित हुए हैं जैसा कि उच्च स्तरीय कई महत्वपूर्ण दौरों में प्रदर्शित हुआ है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक–दूसरों की दृष्टिकोण को सम्मान/समर्थन भी करते हैं जो कि ब्रिक्स तथा ईब्सा ढांचे के माध्यम से और सुदृढ़ हुआ है। वर्ष के दौरान भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच नियमित तौर पर उच्च स्तरीय दौरों का आदान–प्रदान हुआ है।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, 2014 को प्रचारित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 07–14 जून, 2014 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री आर एम लोढ़ा ने ''आपराधिक न्याय प्रणाली में कानूनी सहयोग की पहुंचपर संयुक्त राष्ट्र की सिद्धांत और दिशा–निर्देश'' पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23–27 जून, 2014 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गर्वनर, श्री हारुन आर खान ने भारतीय विदेश विनिमय व्यापारी संघ के 9वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12–15 अप्रैल, 2014 तक केप टाउन का दौरा किया।

पूर्व सांसद एवं भारतीय संसदीय समूह के आजीवन सदस्य श्री यशवंत राव गदाख ने अध्ययन यात्रा के लिए 25–28 अप्रैल, 2014 तक केप टाउन का दौरा किया।

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से एक 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एन डी सी के कमानडेंट, उप एडमिरल सुनिल लाम्बा के नेतृत्व में 11–18 मई, 2014 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया गया।

इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लोकेश चन्द्र के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय मैग्नीज संस्थान के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27–30 मई, 2014 तक केप टाउन का दौरा किया।

आंध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने 30 सितंबर से 03 अक्तूबर, 2014 तक केप टाउन का दौरा किया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री श्री यू टी खादर फरीद ने दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान विषय पर आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 30 सितंबर, 2014 तक केप टाउन का दौरा किया। गुजरात विधान सभा के उपाध्यक्ष ने कैमरुन में सी पी ए की बैठक में भाग लेने के बाद सम्मेलन उपरांत यात्रा के लिए 13–15 अक्तूबर, 2015 तक केप टाउन का दौरा किया।

प्रधान मंत्री द्वारा 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में शुरू की गई ''मेक इन इंडिया'' अभियान पर जोहान्सबर्ग में इस मिशन द्वारा 25 सितंबर, 2014 को एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका में स्थित अग्रणीय व्यापारिक समूहों के सी ई ओ के सदस्यों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रांतीय सरकारों के अधिकारियो, भारत व्यापार मंच के सदस्यों और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के समूहों ने भाग लिया। भारत को एक आकर्षक उत्पादक केन्द्र बनाने से संबंधित सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों और अभियान से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों पर एक प्रस्तुति बनाई गई थी। प्रधान मंत्री के भाषण का वीडियों फाइल और औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचारात्मक क्लिप भी दिखाई गई। दक्षिण अफ्रीका

कंपनियों का औद्योगिक कॉरिडोर तथा रक्षा में निर्माण एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में भाग लेने से संबंधित संभावनाओं को रेखांकित किया गया। प्रस्तुति के बाद एक चर्चा हुई जहां दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों और अन्य प्रतिसाहित होने की बात कही।

दक्षिण अफ्रीका में एक भारत उत्सव–2014 का आयोजन प्रिटोरिया में भारत का उच्चायोग और दक्षिण अफ्रीका के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा हमारे राजनीतिक संबंधों के 20 वर्ष और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत वापसी के 100 वर्ष के भी स्मरणोत्सव को मनाने के लिए जुलाई–अगस्त 2014 के दौरान संयुक्त रूप से किया गया।

उत्सव के लिए मीडिया लांच भारत का महाकोंसुलावास, जोहान्सबर्ग में 16 जुलाई, 2014 को किया गया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से इसे कला एवं संस्कृति उप मंत्री सुश्री रिजॉस मबुदाहसी हदर तथा भारत की ओर से उच्चायुक्त द्वारा संबोधित किया गया। उत्सव के लोगो का अनावरण मीडिया लांच के दौरान किया गया। लगभग 50–60 पत्रकारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। उत्सव के भाग के रूप में कॉन्सटीट्यूशन हॉल, जोहान्सबर्ग में 18 जुलाई, 2014 को गांधी–मंडेला पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और वह अगस्त 2014के मध्य तक चला। इसके बाद, प्रदर्शनी को केप टाउन में 29 अगस्त, 2014 को उद्घाटन किया गया। उत्सव के भाग के रूप में भारत का उच्चायोग ने प्रिटोरिया तथा लेनासिया (जोहान्सबर्ग) में क्रमशः 09–10 अगस्त, 2014 को एक पार्टी तथा नियाजी नियाजी भाइयों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक कव्वाली का आयोजन किया। ब्लोमफनटीन, पीटरमारीजबर्ग, केप टाउन में क्रमशः 04, 06 तथा 08 अगस्त, 2014 को कथक नृत्य समूह (संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से संगीत नाटक अकादमी से) की प्रस्तुतियां हुईं। मारेस (लिसोथो), प्रिटोरिया तथा सोवेटो (जोहान्सबर्ग) में क्रमशः 10,11 तथा 13 अगस्त, 2014 को मीडिया नृत्य समूह (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) की प्रस्तुतियां हुईं।

19 जुलाई, 2014 को गांधी–मंडेला युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें भारत से 10–15 कबूली बच्चों और दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न स्कूलों से लगभग 200 छात्रों ने भाग लिया। 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में महात्मा गांधी की वापसी के 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत का उच्चायोग ने जोहान्सबर्ग से बाहर टालस्टॉय फार्म, के स्थान पर आयोजित किया गया जिसे 1910 में महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। इस कार्यक्रम ने बस्ति को एक 'यादों के बगीचे' के रूप में गांधी जी की जीवन शैली को पल्लवति और बढ़ाने के पुनर्जागरण के औपचारिक ढांचे की शुरुआत की। कार्यक्रम में दक्षिणी अफ्रीकी भारतीय समुदाय के कई लोगों ने भाग लिया गया जिसमें एक अग्रणीय रंगभेद कार्यकर्ता सुश्री मनीषी सीता, गोटिंग प्रांत के सड़क एवं परिवहन के एम ई सी श्री इस्माइल ताई, पूर्व फेडरल मंत्री, श्री इसोप पहाद, अफ्रीकी राष्ट्रीय काग्रेस के पार्षद एवं अग्रणी सदस्य सुश्री प्रेमा नायडू, महात्मा गांधी तथा नेल्सन मंडेला के पारिवारिक सदस्य दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि तथा भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्य शामिल थे। भारत की ओर से समूह को उच्चायुक्त ने सम्बोधित किया। जोहान्सबर्ग में नेल्सन मंडेला फाउण्डेशन पर 24 जुलाई, 2014 को गांधी–मंडेला दीवार का उद्घाटन किया।

रूट्स टू रुट्स (पथ से जड़ों तक) द्वारा भारतीय सीनेमा पर प्रदर्शनी और 'भारत के स्मारको' पर श्री काशीनाथ दास के वास्तविक पानी केरंगा की एक प्रदर्शनी का प्रिटोरिया के प्रतिष्ठित नेशनल म्यूजियम ऑफ कल्चरल हिस्ट्री (सांस्कृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय) में 31 जुलाई, 2014 को उच्चायुक्त द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी प्रिटोरिया में 13 अगस्त, 2014 तक चली। इसके बाद दो प्रदर्शनियां रिचर्ड बे में चलाई गई जहां वे 29 अगस्त, 2014 से 30 सितंबर, 2014 तक प्रदर्शित की गई।

भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पर एक 'भारतीय फिल्म महोत्सव' का उद्घाटन उच्चायुक्त द्वारा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहान्सबर्ग में 03 अगस्त, 2014 को किया गया। जोहान्सबर्ग तथा डरबन में विभिन्न फिल्मों को दिखाया गया।

सुश्री पूर्वा धनश्री के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित नृत्य समूह ने तमिल नववर्ष उत्सव के दौरान प्रस्तुति देने के लिए 08–12 अप्रैल, 2014 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। दक्षिण अफ्रीका के तमिल परिसंघ के सहयोग से प्रिटोरिया, डरबन, केप टाउन तथा पोर्ट एलिजाबेथ में चार प्रस्तुतियां हुईं। सभी कार्यक्रम काफी सफल रहे। प्रभाव नोट करने योग्य था और श्रोताओं द्वारा भी अच्छी तरह ग्रहण किया गया।

दक्षिण अफ्रीका में कथक प्रस्तुतिः उच्चायोग ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित, सुश्री प्रेरणा देशपाण्डे के नेतृत्व में 04 सदस्यीय कथक नृत्य समूह के लिए रुस्टेनबर्ग (18 अक्तूबर, 2014), डरबन (19 अक्तूबर, 2014) तथा प्रिटोरिया (21 अक्तूबर, 2014) में वास्तविक प्रस्तुतियां आयोजित कीं। जोहान्सबर्ग में स्थानीय कथक नृत्य स्कूल के सहयोग से एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। सभी प्रस्तुतियों ने उत्कृष्ट ख्याति पाई।

भारत का महाकोंसुलावास, जोहान्सबर्ग ने भारत–अफ्रीका व्यापार नेटवर्क के सहयोग से जोहान्सबर्ग में 17–21 नवंबर, 2014 तक गॉर्डन इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस साइंस में एक 'भारत सप्ताह' आयोजित किया। 'मेक इन इंडिया' अभियान को रेखांकित करते हुए उत्सव में दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों को भारत में व्यापार तथा निवेश करने से संबंधित संभावनाओं को दिखाया गया। कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका में 80 भारतीय कंपनियों को शामिल करते हुए उद्योग मंच के, भारत व्यापार मंच का दक्षिण अफ्रीका के गृह मंत्र, श्री मालूसी गीगाबा के साथ बातचीत, ''चुनाव पश्च भारत में अवसरंचना और ऊर्जा में सम्भावनाओं'' पर सत्र, ''भारत ने स्वास्थ्य सेवा उद्योग में कैसे क्रांति लाई में फॉर्मेसी तथा आयुर्वेदिक क्षेत्रों में बदलाव'' पर सत्र, बॉलीवुड पर प्रदर्शनी तथा सत्र ''इसके गीत एवं

नृत्य का बनानाः बालीवुड सिनेमा को गंभीरता से लेना''। कार्यक्रम का नवाचार पहलू यह रहा कि व्यापार को मेंहदी कलाकारों के माध्यम से इसे भारतीय पर्यटन के रंगों और भारतीय भोजन, मेलों और उत्सवों का रस सांस्कृतिक संदर्भ में दिखाया गया।

भारतीय नौसैनिक पोत (आई एन एस) तेग ने आई बी एस ए एम ए आर अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए 20 अक्तूबर–10 नवंबर, 2014 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। एक चेतक हेलीकॉप्टर और दस सदस्यीय एक समुद्री कमाण्डो दल भी उसमें सवार थे। पोत पर कुल 279 कार्मिक तैनात थे, तीनों नौसेना के पोतों ने, विशेष बलों के संयुक्त कार्य, व्यापारिक रूप से इकट्ठे कार्य करने तथा सुरक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह अनुपालन करते हुए पोत के दल और विमानन बलों ने आंतरिक प्रचालनता के उच्च मानक को कायम रखा। आई एन एम तेग द्वारा 08 नवंबर, 2014 को दिए गए स्वागत कार्यक्रम में, 120 अन्य अतिथियों के साथ–साथ केप टाउन के मेयर और पश्चिमी केप टाउन के प्रांतीय सरकार से दो मंत्रियों ने भाग लिया।

जोहान्सबर्ग में पहले गुरुद्वारों का उद्घाटन 30 नवंबर, 2014 को किया गया। इस अवसर पर पड़ोसी देशों बोत्सवाना, तंजानिया, कीनिया के साथ–साथ यू के महत्वपूर्ण सिख संगत नेता शामिल थे।

अप्रैल से सितंबर, 2014 की अवधि में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.36 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जिसमें भारत का दक्षिण अफ्रीका को 3.29 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात और 3.07 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात रहा।

वित्त वर्ष 2014–15 में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत दक्षिण अफ्रीका को 100 स्लॉट आबंटित किए गए जिसमें से अभी तक 74 स्वीकृत हुए हैं।

वित्त वर्ष 2014–15 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने दक्षिण अफ्रीका को कुल 52 स्लॉट उपलब्ध कराए हैं और अभी तक 37 का उपयोग हुआ।

गांधीनगर, गुजरात में 07–09 जनवरी, 2014 तक होने वाले 13वें प्रवासी भारतीय दिवस (पी बी डी) 2015 में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री सुश्री मैटे कोआना–माशाबने ने भारत का दौरा किया। पी बी डी 2015 के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था जिसने महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के 100वीं वर्षगांठ भी शामिल था।

दक्षिण अफ्रीका में 2015 के पहले तिमाही में संयुक्त मंत्रीय आयोग (जे एम सी) की बैठक होनी संभावित है। जे एम सी के प्रस्तावित 9वें सत्र में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर सकती हैं। दौरे के दौरान क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों का सम्मेलन भी आयोजित हो सकता है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ष 2013–14 के लिए द्विपक्षीय व्यापार 11.15 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा और 2013–14 के पहले पांच महीनों (अप्रैल–अगस्त) में व्यापार 5.51 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की भारत का निर्यात 2. 97 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा और 2.54 बिलियन अमरीकी डॉलर आयात रहा।

दोनों देशों के बीच व्यापार वृद्धि के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। भारतका दक्षिण अफ्रीका को निर्यात में वाहन तथा संबंधित पूर्जे, परिवहन उपकरण, औषधी एवं भेषज, जूते–चप्पल, रंग रोगन, रसायन, वस्त्र, चावल, नग तथा आभूषण आदि शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत में आयात में सोना, कोयला, तांबे अयस्क तथा ठोस, फास्फोरिक अम्ल, मैंगनीज अयस्क, एल्युमिनियम तथा अन्य खनिज शामिल हैं।

वर्ष 2014–15 में भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के तहत दक्षिण अफ्रीका को 100 स्लॉट आबंटित किए गए।

दक्षिणी सूडान

राजनैतिक तथा मानवीय बलों का राष्ट्रपति श्री किट तथा उप राष्ट्रपति श्री रिक मयार के प्रति वफादार होने के कारण राजनैतिक सुरक्षा स्थिति नाजुक बनी रही। पूरा देश सशस्त्र लड़ाई और मानवीय झगड़ों में समाहित रहा जिसने दक्षिणी सूडानियों को पड़ोसी देशों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहयोग प्राप्त शिविरों में आश्रय लेने के लिए मजबूर किया। अप्रैल 2014 में बी ओ आर, जोनगली राज्य की राजधानी में संयुक्त राष्ट्र के शिविर में शांति स्थापित करने वाले नियुक्त दो भारतीयों को शिविर में शरणार्थियों को बचाने में हमले के दौरान मामूली चोटें आईं। संकट को दूर करने के लिए दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टियों और अन्य सहयोगी शांति वार्ता में नियमित रूप से लगे हुए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और आई जी ए जी देशों के मध्यस्थता के तहत आयोजित हुआ है। जनवरी 2014 से वार्ताओं के सात दौर हो चुके हैं और झगड़े में शामिल पार्टियों को अभी तकआम सहमति पर पहुंचना है। चल रहे वार्ताओं के अनुसरण में दक्षिणी सूडान की सरकार और विरोधी बलों ने शत्रुता खत्म करने, राष्ट्रीय एकता की परिवर्ती सरकार बनाने के लिए करार पर हस्ताक्षर कर पाए हैं।

दक्षिणी सूडानमें भारतीय कंपनी ओ वी एल और इसके सहयोगी भागीदारों के तहत आने वाले क्षेत्रों में देश के आंतरिक झगड़े ने तेल उत्पादन को पूरी तरह बंद कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील देशों के 77 के समूह के 135वें सदस्य के रूप में दक्षिणी सूडान को शामिल किया।

दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कायम रखने वाले मिशन के लेखा परीक्षा करने के लिए भारत के महालेखा परिक्षक से एक चार सदस्यीय लेखा परीक्षा दल ने श्री नीलोटपाल गोस्वामी, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में 11 अगस्त से 05 सितंबर, 2014 तक दक्षिणी सूडान का दौरा किया।

क्षमता निर्माण के क्षेत्र में जारी रखने के लिए सात दक्षिणी सूडानियों को पूर्णकालिक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, नवंबर, 2014 तक के लिए लघु अवधि के आइटेक पाठ्यक्रमों के लिए 32 दक्षिण सुडानियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

येई में गांवों में सौर विद्युतीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिणी सूडान के इक्वेटोरिया राज्य के येई प्रांत में क्षेत्रीय बेयरफूर कॉलेज (सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र के नाम से जाना जानेवाला) तिलोनिया, राजस्थान और इवेंजिलीकल प्रिबाइस्टेरियन चर्च (दक्षिणी सूडान की सरकार की ओर से) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। विदेश मंत्रालय ने भी दक्षिणी सूडान में क्षेत्रीय बेयरफूर प्रशिक्षण और व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने केलिए 500,000 अमरीकी डॉलर (2.48 करोड़ रुपए) की राशि उपलब्ध कराने के लिए बेयरफूर कॉलेज के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए।

सूडान

भारत और सूडान के बीच पारंपरिक एवं बहुमुखी संबंध वर्ष के दौरान सुदृढ़ और आगे बढ़ा है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि में लगभग 46 प्रतिशत का रिकार्ड दर्ज हुआ है (888 मिलियन से 1298 मिलियन अमरीकी डॉलर)। विचारार्थ अवधि के दौरान सूडान में लौह अयस्क, सोना खनन, इस्पात उत्पादन तथा भेषज में भारतीय निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ा है। 09 जून, 2014 को सूडानी भारतीय मैत्री संघ और दी अल नाम अल अजहारी विश्वविद्यालय (एएयू) द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय लोक मैत्री परिषद' के सहयोग से एएयू के सम्मेलन हॉल में 'भारत में लोकतंत्र' पर एक संगोष्ठी आयोजित किया गया था।

सीनेटिक रेयॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (एस आर टी ई पी सी) ने 10–11 अगस्त, 2014 तक अपने अब तक का पहला केवल भारतीय वस्त्र प्रदर्शनी (इनटेक्सपो) का आयोजन खारतुम, सूडान में किया। लगभग बीस प्रदर्शनकर्ताओं ने अपने उत्पादोंको प्रदर्शित किया और बहुतायत संख्या में आयातकों, एजेंटों और फुटकर बिक्रेताओं को आकर्षित किया। एस आर टी ई पी सी के प्रारंभिक फिडबैक के अनुसार प्रदर्शनी के दौरान लगभग 52 मिलियन रुपए का व्यापार (उसी समय ऑर्डर –1.56 करोड़ रुपए और विचाराधीन–3.60 करोड़ रुपए) सृजित हुआ। खारतूम कृषि संघ से एक प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर 2014 को भारत का दौरा किया और दिल्ली में सी आई आई द्वारा सुविधागत बी एस एम में भाग लिया।

स्वाजीलैण्ड

वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों (अप्रैल –अगस्त 2014) के लिए द्विपक्षीय व्यापार 11.85 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा जिसमें 7.80 मिलियन अमरीकी डॉलर भारतीय निर्यात रहा और स्वाजीलैण्ड से 4.05 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात रहा।

स्वाजीलैण्ड को भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले ऋण श्रृंखला के तहत 37.9 मिलियन अमरीकी डॉलरकी लागत का एक कृषि विकास परियोजना का ठेका मैसर्स एनजीलिक इंटरनेशनल लिमिटेड ऑफ इंडिया को दिया गया।

वर्ष 2014–15 में 05 स्वाजी छात्रों ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद छात्रवृत्तियां प्राप्त की, आइटेक के तहत 12 स्वाजी अधिकारियों और सी वी रमन शिक्षावृत्ति के लिए आई ए एफ एस के तहत 01 छात्र को भारत भेजा गया था।

तंजानिया

तंजानिया के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। व्यापार एवं उद्योग मंत्री डॉ0 अब्दुला किगोडा ने 04–06 नवंबर, 2014 तक नई दिल्ली में आयोजित 'भारत आर्थिक मंच' में शामिल होने के लिए तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

तंजानियाई आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2013 के दौरान कुल द्विपक्षीय व्यापार03 बिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़ों के पार गया जिसमें तंजानिया को 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का भारतसे निर्यात और तंजानिया से भारत को 700 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात रहा। भारत से मुख्य निर्यात की वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, औषधिक, लौह तथा इस्पात, इलेक्ट्रिकल बर्तन, मोटर वाहन आदि शामिल है। इस अवधि में तंजानिया से मुख्य आयात की वस्तुओंमें सोना, काजू, दालें, लकड़ी तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2013–14 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 04 बिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर रहा। वर्ष 2013 में तंजानिया में भारतीय कंपनियों द्वारा कुल निवेश 133.67 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा जिसमें इस प्रकार के निवेशों से 1890 रोजगार उत्पन्न हुए। तंजानिया में 1990 से 2013 के अंत तक सामूहिक भारतीय निवेश 1.96 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जिससे 52,000 से अधिक स्थानीय रोजगार उत्पन्न किए।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुलाई 2014 में तंजानिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मवान्जा में अपनी चौथी शाखा का उद्घाटन किया। आंध्रा बैंक के प्रतिनिधिमंडलने तंजानिया में अपनी मौजूदगी स्थापित करने संबंधी संभावनाओं के आकलन के लिए अप्रैल 2014 में तंजानिया का दौरा किया। स्थानीय सी आर डी बी बैंक ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों का फायदा उठाने के लिए व्यापारिक समुदाय को एक बैंकिंग प्लेफार्म उपलब्ध कराने हेतु अपने 'इंडिया डेस्क' को शुरू किया। बैंक ने पैसे हस्तांतरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एस बी आई तथा आई सी आई सी आई के साथ भागीदारी की है।

शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' अभियान को तंजानिया के प्रधान मंत्री श्री मीजेंगो द्वारा 17 अगस्त, 2014 को भारतीय निवेशित

इस्पात संयंत्र के विस्तार की शुरुआत की जो कि क्षमता के लिहाज से पूर्व अफ्रीका में एक बड़ा संयंत्र बना देगा।

दार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत से 11 कंपनियों का प्रतिनिधित्व रहा।

दार–ए–सलाम शहर और चलीज क्षेत्र में जल आपूर्ति वृद्धि परियोजना के लिए भारत सरकार की 178.125 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए नवंबर 2014 में शुरुआत हुई। वापकोस को पी एम सी नियुक्त किया गया और दो भारतीय कंपनियों को ठेका सौंपा गया। परियोजना पर प्रगति संतोषजनक रही है।

अरुषा में नेल्सन मंडेला–अफ्रीकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में आई सी टी संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए 1.3 मिलियन अमरीकी डॉलर के भारतीय सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाते हुए अक्तूबर 2014 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आशा है कि सी जैक शीघ्र ही कार्य करेगा।

भारत पर्यटन कार्यालय, जोहान्सबर्ग ने जून 2014 में अरुषा में आयोजित कारीषू पर्यटन एवं व्यापार मेले में दूसरी बार भाग लिया। कार्यालय ने अक्तूबर 2014 के शुरुआत में दार–ए–सलाम में प्रथम स्वाहिली अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो में भी भाग लिया।

तंजानिया द्वारा आइटेक के स्लॉटों का उपयोग ऊंचा ही रहा। नागरिक क्षेत्र में आबंटित किए गए सभी 250 स्लॉटों का उपयोग अक्तूबर 2014 तक हो चुका था। तंजानिया ने मध्य नवंबर 2014 तक रक्षा के क्षेत्र में सभी 28 स्लॉटों का भी पूरी तरह से उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, 07 आई ए एफ एस और अन्य प्रशिक्षण स्लॉटें उपयोग किए गए। उपलब्ध कराई गई भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की 24 छात्रवृत्तियों में से 20 का उपयोग हुआ।

इस अवधि के दौरान सुश्री वाणी माधव, एक ओडिसी नृत्य कलाकार ने अरुषा, दार–ए–सलाम और जंजीबार में 15–17 अगस्त, 2014 तक प्रस्तुतियां दीं। ''सोल सामवाद'' एक संगीत बैण्ड ने दार–ए–सलाम में 07 अक्तूबर,2014 में प्रस्तुति दी। श्री शेखर सेन, एक प्रतिष्ठित एकालाप कलाकार ने हिंदी दिवस के अवसर पर अगस्त में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में स्वामी विवेकानंद पर एक संगीतमय प्रहसन की प्रस्तुतिदी।

पश्चिमी बेड़े के तीन पोतों और जल सर्वेक्षण जहाज आई एन एस 'जमुना' ने दार–ए–सलाम बंदरगाहका दौरा किया।

टोगो

कपास तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत टोगोलिस कपास उद्योगके विकास के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के संबंध में एक दो सदस्यीय आई एल व एफ एस समूह प्रतिनिधिमंडल ने 06–10 मई, 2014 तक टोगो का दौरा किया।

ट्यूनीशिया

जनवरी 2014 में एक नए संविधान को अपनाने और एक टेक्नोक्रेट सरकार के बननेसे ट्यूनीशिया लोकतंत्र की ओर नियमित प्रगति कर रहा है। 26 अक्तूबर, 2014 को बहुपक्षीय आम चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित करते हुए इसने अपने इतिहास में एक मील का पत्थर जड़ दिया। लोकतंत्र के रास्ते पर एक और बड़ी सफलता रही अब तक का पहले राष्ट्रपति चुनाव को 23 नवंबर, 2014 को आयोजित करना जिसमें 27 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा।

लीबिया में जुलाई 2014 में कानून व्यवस्था भंग हो जाने से ट्यूनीशिया ने वहां से लीबिया के रास्ते हजारों भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से निकालने में सभी संभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जो अक्तूबर 2014 तक जारी रहा।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा सुश्री सोनम कालरा के नेतृत्व में एक आठ सदस्यीय सूफी विलयन वादी समूह ने 28–29 सितंबर,2014 में ट्यूनीशिया में दो कार्यक्रम आयोजित किए। डॉ0 अबदेल जलीट सलेम, जीटोना विश्वविद्यालय ट्यूनीश के पूर्व रेक्टर ने शैक्षिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मेहमान के रूप में 21–30 नवंबर तक भारत का दौरा किया।

हाल ही में वर्षों में ट्यूनीशिया भारत सरकार के आइटेक कार्यक्रमों में अधिक रुचि दिखाता रहा है। ट्यूनीशिया के लिए वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित आइटेक प्रशिक्षण के 45 स्लॉट पूरी तरह इस्तेमाल में लाए गए हैं। भारत–अफ्रीका एस एण्ड टी सहयोग प्रयास के अंतर्गत ट्यूनीशिया के तीन अनुसंधानकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों ने 2014–15 के दौरान सी वी रमन शिक्षावृत्ति कार्यक्रम में सहभागिता की।

यूगाण्डा

भारतीय व्यापारिक समुदाय की बड़ी संख्या, राजनैतिक स्थिरता तथा इस क्षेत्र में भारत की शाख को देखते हुए विशेष रूप से इस क्षेत्र में यूगाण्डा के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ बने रहे।

विदेश मंत्री श्री सैम कुरेसा वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जुलाई 2014 में भारत आए। नई सरकार के गठन के पश्चात भारत आने वाले वे पहले अफ्रीकी नेता थे। उनके साथ आई सी टी मंत्री श्री जॉन नसासीरा, निवेश राज्य मंत्री डॉ0 अजेड्रा गेबरियल तथा मत्स्य राज्य मंत्री श्री रुथ नानकाबिखा भी आए। दौरे के दौरान मंत्री श्री सैम कुरेसा ने प्रधान मंत्री से भेंट कीतथा विदेश मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने सी आई आई के साथ भी बातचीत की।

यूगाण्डा में एक खाद्य प्रसंस्करण व्यापार परिपाक केन्द्र (एफ वी बी आई सी) की स्थापना के लिए अंतर–सरकार समझौता ज्ञापन पर

उच्चायुक्त द्वारा यूगाण्डा के कृषि मंत्री के साथ जून 2014 में कम्पाला में हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात दो कार्यान्वयन एजेंसियों, नामतः आई सी आर आई एस ए टी, हैदराबाद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला (एन ए आर एल) के बीच समझौता ज्ञापन पर भी कम्पाला में हस्ताक्षर किए गए। इस केन्द्र की स्थापना भारत सरकार की अनुदान सहायता से की जा रही है।

भारतीय मिलिट्री प्रशिक्षण दल (आई एम टी टी) ने यूगाण्डा पीपुल्स डिफेन्स फोर्स (यू डी पी एफ) के मध्यम तथा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना जारी रखा।

आइटेक–स्कैप के तहत यूगाण्डा को 85 स्लॉट आबंटित किए गए। यू पी डी एफ अधिकारियों ने रक्षा कार्यक्रम प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कि डिफेन्स सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज (डी एस एस सी), वेलिंग्टन में भाग लिया। ग्रैजुएट, अंडर ग्रैजुएट तथा पी एच डी कार्यक्रमों के लिए 31 युगाण्डा के व्यक्तियों ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के छात्रवृत्तियां का उपयोग किया। सी वी रमन शिक्षावृत्ति पर 01 यूगाण्डा के व्यक्ति ने भी भारत की यात्रा की। इसके अतिरिक्त आई ए एफ एस के तहत 02 यूगाण्डा के व्यक्तियों ने लघु अवधि की कार्यक्रम सुविधा का भी उपयोग किया।

इंडिया हाउस में आइटेक दिवस के उत्सव में राष्ट्रपति ने मंत्री श्री फ्रैक तूम्बेबजे, अन्य मंत्री तथा यूगाण्डा के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। कार्यक्रम में लगभग सौ यूगाण्डा के आइटेक अलयूनी ने भाग लिया।

पैन–अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजना, विशेषकर इसका दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, संतोषजनक कार्य कर रहा है।

यूगाण्डा में सबसे बड़ी संख्या लाइसेंसधारी एफ डी आई परियोजनाओं के लिए भारत स्रोत था और 108.7 मिलियन अमरीकी डॉलर के नियोजित मूल्य के 142 परियोजनाएं थीं (जुलाई 2013 – जून 2014)। एक 12 सदस्यीय सी आई आई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 17–19 सितंबर,2014 तक यूगाण्डा का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने नई व्यापारिक भागीदारों और सरकारी अधिकारिों के साथ–साथ मंत्रियों से मुलाकात किया।

उनके देश में 67वें स्वतंतत्रता दिवस को मनाने के लिए भारत–यूगाण्डा मैत्रीपूर्ण रैली का आयोजन किया गया। यूगाण्डा में भारतीयों/पी आई ओ के 27000 से अधिक जनसंख्या है। यूगाण्डा राजस्व प्राधिकरण द्वारा एकत्रित की जाने वाली प्रत्यक्ष करों का 60 प्रतिशत भारतीय/पी आई ओ के कंपनियों द्वारा दिया जाता है। भारतीय समुदाय ने भी 'भारत दिवस' मनाया, सुश्री सुनिधि चौहानने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूगाण्डा संसद की अध्यक्ष श्रीमती रेबेक्का रुडागा थी।

जाम्बिया

राष्ट्रीय जाम्बियारक्षा कॉलेज, नई दिल्ली से उप एडमिरल और कमाडेंट श्री सुनील लाम्बा के नेतृत्व में एक 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन दौरे पर 18–23 मई, 2014 तक जाम्बिया की यात्रा किया। प्रतिनिधिमंडल ने थल सेना, वायु सेना और जाम्बिया राष्ट्रीय सेवा के कमांडरोंसे मुलाकात की। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत और जाम्बिया का लम्बा सहयोग रहा है।

सचिव (पश्चिम) ने 05–09 अगस्त, 2014 तक जाम्बिया का दौरा किया। दौरा भारत का जाम्बिया के साथ संबंधों के महत्व को दोहराने का था। विदेश मंत्रालय में बैठकों के अतिरिक्त उन्होंने 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के भारतीय ऋण श्रृंखला के तहत जाम्बिया में 650 स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने से संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठकें कीं। एक सांस्कृतिक फ्यूजन बैण्ड ने अक्तूबर 2014 में जाम्बिया का दौरा किया और लूसाका में प्रस्तुतियां दीं।

श्रीमती ऊषा उथुप के नेतृत्व में एक अन्य सांस्कृतिक समूह ने भारत–जाम्बिया के राजनयिक संबंधों की स्थापना और जाम्बिया स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए प्रस्तुति दी।

जिम्बाब्वे

भारत और जिम्बाब्वे ने इस अवधि में सौहार्दपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखा है। आई ए एफ एस–। के तहत हरारे में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और मिनिस्ट्री ऑफ स्माल एण्ड मिडियम इंटरप्राइजेज एण्ड को–ऑपरेटीव डेवलपमेंट ऑफ दी रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे के बीच 03 मार्च, 2014 को हरारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य 27 एस एम ई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना है।

हरारे में खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला (एफ टी एल) स्थापित करने से संबंधित एक करार पर 18 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षर हुआ। एफ टी एल आई ए एफ एस–।। के तहत स्थापित किया जा रहा है।

भारत और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार व वाणिज्य संबंधों के विस्तार और प्रचार की दृष्टि से एक उच्चाधिकार फिक्की प्रतिनिधिमंडल ने 28–31 मई, 2014 तक जिम्बाब्वे का दौरा किया।

भारत गणराज्य की सरकार और जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार के बीच हवाई सेवा करार 19 जून,2014 को हरारे में हस्ताक्षरित हुआ। राजदूतावास ने आई टी डी सी, नई दिल्ली के सहयोग से हरारे में 13–18 अक्तूबर, 2014 तक भारतीय खाद्य उत्सव के तृतीय संस्करण को आयोजित किया। जोहान्सबर्ग स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय ने हरारे में सनगनाई/लानगनानी वर्ल्ड टूरिज्म एक्सपो में 16–18 अक्तूबर, 2014 तक भाग लिया और बेस्ट इंटरनेशनल स्टैण्ड के साथ–साथ बेस्ट ओवर ऑल स्टैण्ड का पुरस्कार जीता।

भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के तह यथा आदेशित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 17–21 नवंबर, 2014 तक हरारे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कार्यकारी विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया। कार्यक्रम को जीम व्यापार के सहयोग से संचालित किया गया था।

भारत सरकार ने जिम्बाब्वे को 500 मीट्रिक टन चावल दान में देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। हरारे में महात्मागांधी का 42 इंच का कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के संबंध में हरारे शहर से अनुमोदन प्रतिक्षित है।

अफ्रीकी यूनीयन (संघ)

अफ्रीकी संघ के बनने से भारत नियमित रूप से इसके विभिन्न शिखर सम्मेलनों में भाग लेता रहा है। सचिव (पश्चिम) ने जनवरी 2014 में अफ्रीकी संघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अदीस अबाबा में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन के दौरान कई अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुईं।

संयुक्त सचिव (पूर्व व दक्षिणी अफ्रीका) ने जून 2014 में मालाबी में ए यू शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी यूनियन कमीशन (एयू सी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुईं।

सचिव (पश्चिम) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 20–21 अगस्त, 2014 तक इंडिया–अफ्रीका रिजनल इकोनॉमिक कम्यूनिटीज (आर ई सी) की तृतीय बैठक हुई थी। दौरे पर आए आर ई सी प्रतिनिधिमंडल ने 20 अगस्त, 2014 को विदेश राज्य मंत्री, जनरल (डॉ0) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) से मुलाकात किया और विदेश मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिवों से द्विपक्षीय वार्ता किया। आर ई सी प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के कई विभागों/मंत्रालयों/एजेंसियों से मुलाकात करने के साथ–साथ संयुक्त रूप से सहमत हुए। कार्यक्रम तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों से भी मुलाकात किया। इसमें कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, बेयरफूट कॉलेज, तिलोनिया, ऊर्जा और संसाधन संस्थान आदि शामिल हैं। कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सी आई आई) ने 20 अगस्त, 2014 की शाम को एक पारस्परिक संवादका सत्र आयोजित किया था। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल ने 21 अगस्त, 2014 को टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आई सी डब्ल्यू ए) से भी मुलाकात किया। तृतीय भारत–आर ई सी की बैठक ने भारत–अफ्रीका के संबंधों को सुदृढ़ करने का एक और प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है।

भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस)

आई ए एफ एस का तंत्र 21वीं शताब्दी में भारत और अफ्रीकी भागीदारों के बीच तीन स्तरों परः महाद्वीपीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय स्तर पर एक सुयोजित संपर्क वार्ता तथा सहयोग के लिए एक नए आर्किटेक्चर की आधारशिला रखने के उद्देश्य से बना है। प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 2000 में आयोजित हुआ था और द्वितीय 2011 में अदीस अबाबा में हुआ था।

दोनों शिखर सम्मेलनों द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं और कार्यक्रम 2014 में सफलतापूर्वक जारी रहे। तीन क्षमता निर्माण संस्थान पूरे कर लिए गए– बुरुण्डी, इथोपिया तथा रवाण्डा में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र। आई ए एफ एस–।। के तहत 2011–14 की अवधि के दौरान विचार किए गए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ पत्रकारों तथा युवा पार्लियामेंटेरियन के दौरे पूरे किए गए। विदेश मंत्रालय के सहयोग से आई सी डब्ल्यू ए तथा आई डी एस ए द्वारा अकादमिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन मंच (आई ए एफ एम) तंत्र के तहत नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ विण्ड एनर्जी, चेन्नई में 19 नवंबर से 12 दिसंबर, 2014 तक विदेश मंत्रालय द्वारा ''विण्ड टरबाइन टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लिकेशन'' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम में आठ अफ्रीकी देशों से 21 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

■■

7 यूरोप और यूरोपीय संघ

अलबेनिया

रोमानिया में भारत के राजदूत ने 05–07 अगस्त 2014 को अलबेनिया का दौरा किया और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों के मामलों पर विचार–विमर्श किया। उन्होंने अल्बानिया के चैंबर ऑफ कॉमर्स और उद्योग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने चैरिटी की सिस्टर्स (मदर टेरेसा) और तिराना में स्थित भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की।

भारत और अल्बानिया के बीच राजनयिक / सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया है और कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गयी है और निकट भविष्य में इस पर हस्ताक्षर किए जा सकते है।

नई दिल्ली में अल्बानियाई दूतावास 30 सितंबर, 2014 को अल्बानिया में वित्तीय समस्याओं के कारण बंद हुआ था ।

ऑस्ट्रिया

भारत और ऑस्ट्रिया के गहरे और प्रगाढ़ संबंध है। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ)। वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), राज्यमंत्री (वीकेएस) ने 3 सितंबर 2014 पर मोंटेनेग्रो से पारगमन पर वियना का दौरा किया। राज्यमंत्री (वीकेएस) ने वियना में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की ।

परिवहन, नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए ऑस्ट्रिया के संघीय मंत्रालय में प्रौद्योगिकी अंतरण विभाग के प्रमुख मेजि0 माइकल लेडरर ने 8 सितंबर, 2014 को भारत का दौरा किया ।

श्री थोकचोम लोकेश्वर सिंह, स्पीकर, मणिपुर विधान सभा ने, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन दौरे पश्चात 14 अक्टूबर 2014 को वियना का दौरा किया।

ऑस्ट्रिया की संसद ने पहली बार भारत के लिए सुश्री अलीव कोरून, जो ग्रीन्स पार्टी से संसद सदस्य है, के नेतृत्व में एक अलग संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की। मैत्री समूह में संसद के दोनों सदनों से 155 सदस्यों के रूप में सांसद होते हैं।

दूतावास ने दक्षिण एशियाईए तिब्बतियन और बौद्ध अध्ययन संस्थान में 'महात्मा गांधी की एक संक्षिप्त जीवनी' शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

9 अक्टूबर 2014 को वियना में वाणिज्य ऑस्ट्रिया के चैंबर के साथ सहयोग में दूतावास ने "मेंक इन इंडिया" अभियान के लिए शुभारंभ समारोह का आयोजन किया।

संस्कृति और सुविधा ख्भारत सेंटर ग्राज़, के लिए ऑस्ट्रो–इंडियन सोसाइटी ने ग्राज़ में 24 अक्टूबर 2014 को भारतीय नृत्य और संगीत– भारतीय क्षेत्र 2014 के अपने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया।

दूतावास और कारिंथिया के वाणिज्य प्रांतीय चैंबर के सहयोग से ऑस्ट्रियाई अनादि बैंक (एक भारतीय के स्वामित्व वाले ऑस्ट्रियाई बैंक) ने प्रांतीय राजधानी क्लेगनफुर्त में "कारिंथिया भारत से मिलो" शीर्षक से 20 नवम्बर, 2014 को पहली संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में डा. पीटर कैसर, कारिंथिया के राज्यपाल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। यह कार्यक्रम वाणिज्यिक संबंधों, व्यापार के अवसरों और ऑस्ट्रो–बॉलीवुड पर एक सत्र रखा गया जिस पर सुश्री गुरिंदर चड्ढा, एक भारतीय मूल के निदेशक ने मुख्य भाषण दिया।

बोस्निया और हरजेगोविना

भारत और बोस्निया और हरजेगोविना के संबंध दोस्ताना और प्रगाढ़ है। वर्ष के दौरानए निम्नलिखित आयोजन हुये जिन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया।

विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर 21–22 अप्रैल 2014 को साराजेवो में आयोजित किया गया। भारत की ओर नेतृत्व सचिव (पश्चिम) श्री दिनकर खुल्लर ने किया था जबकि बोस्निया जबकि हरजेगोविना पक्ष की ओर से नेतृत्व द्विपक्षीय संबंधों के सहायक मंत्री श्री आमेर करपेटनोविक द्वारा किया गया था।

बोस्निया और हर्जेगोविना में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुई जान–माल के नुकसान पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने श्री बकीर जेटबेगेविक, प्रेसीडेंसी के अध्यक्ष को उसका गहरा दुःख व्यक्त करते हुये मई 2014 को एक शोक संदेश भेजा। भारत सरकार ने बोस्निया और हरजेगोविना को 100,000 अमरीकी डालर की राहत सहायता दी है।

एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारत के छह पटकथा लेखक, वरिष्ठ सलाहकार और दो विशेषज्ञ स्क्रिप्ट परामर्शदाताओं सहित 15–23 अगस्त 2014 को प्रतिष्ठित 20वीं साराजेवो फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए मुंबई से आया, भारत से सबसे पहला प्रतिनिधिमंडल ।

इस साल साराजेवो में हुये तीन बड़े सांस्कृतिक और शांति कार्यक्रमों, साराजेवो शीतकालीन महोत्सव, साराजेवो शांति इवेंट, 2014 और साराजेवो फिल्म समारोह में भारत ने भाग लिया।

बुल्गारिया

संबंध पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण है। भारत के प्रति बुल्गारिया के जवान और बूढ़ों के बीच आकर्षण योग, भारतीय नृत्य, भारतीय फिल्मों और धारावाहिकों की लोकप्रियता की बहुतायत से स्पष्ट है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल अंकन के वर्ष में, दोनो देश मैत्रीपूर्ण संबंधों की मौजूदा स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुये, दोनों देशों और लोगों के बीच मौजूदा दोस्ती के रिश्तों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है।

60 वीं वर्षगांठ मनाने और परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के उप मंत्री द्वारा 26 जून, 2014 को एक विशेष पोस्ट कार्ड जारी करना बुल्गारिया में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हैं। भारत क्लब के मित्रो, सोफिया विश्वविद्यालय के भारतीय विद्या विभाग और भारतीय दूतावास ने संयुक्त रूप से सोफिया विश्वविद्यालय में राजनयिक संबंधों के 60 साल पर, उत्सव सार्वजनिक बैठक 18 नवम्बर 2014 को आयोजित की। इस कार्यक्रम के लिए अपने बधाई संदेश में बल्गेरियाई विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के क्रमिक विकास पर गहरा संतोष व्यक्त किया और बुल्गारिया और भारत के साथ संबंधों के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता पर पुष्टि की। कार्यक्रम में अच्छी सहभागिता रही और इसे अच्छी तरह से बुल्गारियाई राष्ट्रीय टीवी में कवरेज मिला था।

यह वर्ष सोफिया में भारतीय दूतावास द्वारा कई कार्यक्रमों के आयोजन का साक्षी रहा। दूतावास ने पूर्व–पश्चिम भारतविद्या फाउंडेशन के सहयोग से सोफिया विश्वविद्यालय में अप्रैल 2014 में फोटोग्राफर श्री वुल्यिान ऐंगेलोव द्वारा "पवित्र वृंदावन" शीर्षक से तस्वीरों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था ।

विश्व हिंदी दिवस 10 अप्रैल 2014 को पूर्व–पश्चिम भारत विद्या फाउंडेशन और सोफिया विश्वविद्यालय के भारतीय विद्या विभाग के सहयोग से दूतावास पर मनाया गया। राजदूत ने समारोह का उद्घाटन किया और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन किया। दो घंटे के कार्यक्रम का शीर्षक "भारत का ज्ञान" अच्छी तरह से माना गया और बल्गेरियाई कलाकार सुश्री माया ज़ालोवा कंवर ने भरतनाट्यम नृत्य किया, इंदिरा गांधी बाल विहार के बच्चों ने गीत गाये, सोफिया विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्रों ने पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित एक नाटक प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर बल्गेरियाई मीडिया द्वारा कवर किया गया था।

एक 10 सदस्यीय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित मणिपुरी लोक नृत्य और संगीत मंडली और एक 20 सदस्यीय निजी गुजराती लोक नृत्य मंडली के साथ वेलिको टर्नोवो अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव में भारत ने भाग लिया । भारत की भागीदारी त्योहार का मुख्य आकर्षण था और यह व्यापक रूप से स्थानीय मीडिया में कवर किया गया था। मणिपुरी नृत्य समूह ने वेलिको टर्नोवो, रेजग्रेड, रयूज़ एवं चेलोपेक में 19 जुलाई से 2 अगस्त 2014 तक कई प्रदर्शन प्रस्तुत किये।

30 साल के वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में, सोफिया विश्वविद्यालय के भारतीय विद्या विभाग ने ईस्ट वेस्ट भारत विद्या फाउंडेशन के सहयोग से एक ई–पत्रिका " मानस– एशिया और अफ्रीका में अध्ययन" का शुभारंभ 20 नवंबर 2014 को किया गया था। इस पत्रिका के पहले अंक का समर्पण दक्षिण एशिया की संस्कृति को किया गया था जो भारत पर केंद्रित था।

बुल्गारिया आयुर्वेद एसोसिएशन ने 30 नवम्बर, 2014 को अपनी 5 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया। एसोसिएशन ने इससे पहले आयुर्वेदिक केंद्र, सोफिया में अध्यापन के लिए किताबें उपलब्ध कराने के लिए दूतावास से अनुरोध किया था । बुल्गारिया आयुर्वेद एसोसियेशन द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार आयुष विभाग पुस्तकों की आपूर्ति करने पर सहमत हुए।

पर्यटन बल्गेरियाई अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बल्गेरियाई सरकार भारत से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्सुक है। कुछ भारतीय फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों द्वारा, जिन्होंने क्षेत्रीय साथ ही हिंदी फिल्मों के लिए स्थानों को खोजने के लिए देश का दौरा किया है, दिखाई रुचि के अनुसार शूटिंग आधारित भारतीय फिल्मों के लिए बुल्गारिया एक गंतव्य के रूप में उभर सकता है ।

वर्ष के दौरान, बुल्गारिया ने भारत सरकार से वित्त पोषित हिन्दी सीखने के लिए दो भारतीय छात्रवृत्ति योजना केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा और 5 साल बीएएमएस पाठ्यक्रम के लिए आईसीसीआर आयुश के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय के कार्यक्रम के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत अब तक 13 छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया गया है।

क्रोएशिया

द्विपक्षीय संबंधों मित्रवत और सहयोगी बने रहे और आगे की अवधि के दौरान निरंतर बातचीत के माध्यम से इसे मजबूत बनाया जाना है। विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और परस्पर लाभदायक समर्थन बना रहा था।

एक दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने, मध्य यूरोप के लिए अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एयर मार्शल डी एस खजूरिया, एयर ऑफिसर–इन–चार्ज रखरखाव भारतीय वायु सेना के नेतृत्व में वायु मुख्यालय का 10–12 सितंबर 2014 को दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल

ने अवसरों की पहचान करने और रक्षा उद्योग और व्यापार सहयोग के लिए तरीकों की तलाश करने के लिए कार्लोवैक में टीपीटी कारखाने का दौरा किया।

भारतीय दूतावास को भारत सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति पर 16 जून, 2014 को स्थानांतरित कर दिया। औपचारिक उद्घाटन 30 जुलाई 2014 को आयोजित किया गया था जिसमें ज़गरेब के मेयर श्री मिलान बांदिक मुख्य अतिथि थे ।

दूतावास ने ज़गरेब विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या के अध्ययन के लिए अपना समर्थन जारी रखा जिसमें भारतीय सांस्कृति परिषद(आईसीसीआर) में हिंदी का एक पद था जिसपर तीन साल की अवधि के लिए हिंदी का एक प्रोफेसर नियुक्त किया गया। जून 2014 में क्रोएशियाई प्रोफेसर के लिए संस्कृत में पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए एक फैलोशिप आईसीसीआर से सुरक्षित था। आईसीसीआर ने एक छह सदस्यीय कथक नृत्य समूह, चार शहरों में अर्थात ज़गरेब, वराज़दिन, क्रेपिंसके, टॉपलिक और कॉप्रिवनिका में प्रदर्शन के लिए 31 मई से 5 जून 2014 को क्रोएशिया दौरा प्रायोजित किया। जबकि आईसीसीआर ने उनके हवाई टिकटों के लिए भुगतान कियाए मिशन ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, एक स्थानीय सांस्कृतिक एसोसिएशन लोटस की मदद से उनके स्थानीय आतिथ्य, प्रदर्शन आदि के लिए इंतजाम किए। संबंधित अधिकारियों ने उनके निर्दोष प्रदर्शन की सराहना की।

4–06 जून 2014 को ज़गरेब में आयोजित पर्यटन के इंटरनेशनल फेस्टिवल में 'अतुल्य भारत' की दो फिल्मों ने पुरस्कार जीते।

दूतावास ने, क्रोएशियाई गैर सरकारी संगठनों, लोटस एसोसिएशन और महात्मा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से ज़गरेब में 27 अप्रैल से 31 मई 2014 को, 6ठे 'डेज़ ऑफ इंडियन कल्चर' का आयोजन किया जिसमें विभिन्न सेमिनार, व्याख्यान, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियां आदि आयोजित की गई। यह कार्यक्रम क्रोएशियाई लोगों को परिचित कराने के क्रम में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समर्पित किया गया। 'स्त्रैण आदिरूप की खोज में ' शीर्षक से एक महीने के लिए एक स्थानीय कलाकार द्वारा भारतीय देवी देवताओं पर कला चित्रों की प्रदर्शनी एक स्थानीय संग्रहालय में राजदूत द्वारा 29 अक्टूबर 2014 को शुरू की गयी थी। श्री अरुण प्रसाद हर द्वारा निर्देशित ''गांधी लाइव्स'' फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन 17 नवंबर, 2014 को सहिष्णुता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था।

साईप्रस

संबंध पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण है।

पहली बार, गांधी जयंती और अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 02 अक्टूबर 2014 पर साइप्रस में मनाया गया था । एक संक्षिप्त समारोह में, निकोसिया में प्रतिनिधि सभा के निकट जहां महात्मा गांधी की एक प्रतिमा स्थापित है, श्री. यिआनकिस आमिराओ जो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं के द्वारा पुष्प अर्पित किये गये और इस अवसर पर एक भाषण भी दिया ।

भारत और साइप्रस के बीच अंतरिम जे एस / डीजी स्तर विदेश कार्यालय परामर्श 11 नवम्बर 2014 को निकोसिया में आयोजित किया गया था।

चेक रिपब्लिक

संबंधों का इस साल मजबूत बनाना जारी रहा। विशेष रूप जुलाई 2014 में प्राग में एक बॉलीवुड फिल्म (बैंग बैंग) की शूटिंग के बाद लोगों का लोगों के साथ संपर्क दोनों पक्षों से पर्यटकों के प्रवाह की वृद्धि का साक्षी रहा,

आर्थिक और व्यापारिक संबंध, व्यापार और उद्योग से प्रतिनिधिमंडलों के लगातार आदान प्रदान के साथ लगातार वृद्धि की राह पर बने रहे। इस साल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:

श्री जीसी मुर्मू , प्रधान निजी सचिव गुजरात के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, वाइब्रेंट गुजरात रोड शो के लिए 07–09 सितंबर 2014 को प्राग का दौरा किया। रोड शो के दौरान 60 चेक कंपनियों ने भाग लिया और अंत में एक B2B भी था।

श्री शरद जयपुरियार, अध्यक्ष, पंहदि (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली) वाणिज्य और उद्योग चैंबर के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, व्यापार विचार विमर्श के लिए 08–10 सितंबर 2014 को प्राग का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य चेक चैंबर के साथ और उद्योग और व्यापार मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आगे सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

हैवी इंजीनियरिंग के विभाग की ओर से एक 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने श्री आर के सिंहए संयुक्त सचिव के नेतृत्व में 22–25 सितंबर 2014 को संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक के लिए प्राग का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन एचईसी, एचएमटी मशीन टूल्स, नेवेली लिग्नाइट और सिंगरेनी कोलियरीज के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने 24 सितंबर 2014 को श्री जिरी हेवलिसेक, उद्योग और व्यापार के प्रथम उप मंत्री के साथ मुलाकात की और भारत– चेक जेडब्ल्यूजी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। चेक पक्ष ने चेक कोयला समूह, विटकोबिटसी, फेरिट, स्कोडा परिवहन, स्कोडा मशीन टूल्स और चेक प्रेसिजन फोर्ज की कोयला खदानों का दौरा करने की व्यवस्था की। इस यात्रा ने खनन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया।

चेक गणराज्य रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण देशों में से एक हो गया है। एयर वारफेयर कॉलेज, सिकंदराबाद से 14 अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल नेए 3 से 7 नवंबर 2014 को "विदेश शिक्षण टूर" के भाग के रूप में चेक गणराज्य का दौरा

किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एयर वाइस मार्शल डीपी उपोत के नेतृत्व में किया गया था। एक समूह के 14 अधिकारी ब्रनो में मसारेक विश्वविद्यालय में आईसीटी सुरक्षा पर अल्पकालिक क्रिप्टोग्राफी कोर्स में भी शामिल हुये। यह पाठ्यक्रम 8 सितम्बर 2014 को शुरू किया गया और 15 फ़रवरी 2015 तक निर्धारित है।

चेक विश्वविद्यालयों के उच्च प्रतिनिधियों ने अक्टूबर और नवंबर 2014 में भारत का दौरा किया। यात्रा का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना था ।

डेनमार्क

भारत– डेनमार्क के संबंध 1995 में पुर्लिया आर्म्स ड्रोपिंग केस में शामिल डेनमार्क के नील्स हॉक उर्फकिम डेवी को भारत को प्रत्यार्पित न करने से निरंतर रूप से प्रभावित हुए है।

एस्तोनिया

प्रधानमंत्री श्री तावी रावॉस ने मिलान में एएसईएम–यूरोपीय संघ की बैठक के मौके पर 16 अक्टूबर 2014 को राज्यमंत्री (वीकेएस) के साथ एक बैठक की थी । द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर विचार–विमर्श के अलावाए भारत में हिरासत में मरीन के मुद्दे और एस्टोनिया में भारतीय दूतावास के खोलने पर भी चर्चा हुई।

केन्द्र और राज्य सरकारों से 26 वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने ई–गवर्नेंस एस्टोनिया की अकादमी द्वारा आयोजित ई–गवर्नेंस के समाधान पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेनेए 22–29 अगस्त, 2014 को एस्तोनिया का दौरा किया।

फिनलैंड

राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी 14–16 अक्टूबर, 2014 को फिनलैंड की राजकीय यात्रा पर गये। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया था जिसमें श्री पी राधाकृष्णन, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री, सांसद श्री राजीव शुक्ला, श्री अनंत कुमार हेगड़े दत्तात्रेय, डॉ किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी और श्री बाबुल सुप्रियो बराल, आईआईटी और आईआईएसईआर के वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षाविद और व्यवसायी शामिल थे। राष्ट्रपति ने फिनिश राष्ट्रपति श्री सउली निनिस्ट्रो, प्रधानमंत्री श्री अलेक्जेंडर स्टब,विदेश मंत्री डॉ. इरकी टियोमियोजा और संसद के स्पीकर श्री ईरो हेयिनोउमल से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने हेलसिंकी में एक व्यापार संगोष्ठी को भी संबोधित किया। उन्होंने रोवानिमी का दौरा किया और आर्कटिक सर्कल पार किया, सांता क्लॉस ग्राम का दौरा करने के अलावा उन्होंने अर्कतीकम संग्रहालय और आर्कटिक विज्ञान केन्द्र का दौरा भी किया। इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, सिविल परमाणु अनुसंधान, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित शैक्षिक संस्थानों के साथ और वाणिज्यिक संबद्व कुल 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

फिनलैंड के साथ विदेश कार्यालय परामर्श हेलसिंकी में 13 मई 2014 को आयोजित किया गया। भारत की ओर से नेतृत्व श्री दिनकर खुल्लर, सचिव (पश्चिम) की अध्यक्षता में किया गया था और फिनिश की ओर से श्री सेजाकों लाजावा, विदेश और सुरक्षा नीति के लिए राज्य के सचिव की अध्यक्षता में किया गया था । सचिव (पश्चिम) ने विदेश मामलों के मंत्री डॉ. इरकी टियोमियोजा को भी आंमत्रित किया। फिनलैंड और भारत के बीच सामाजिक सुरक्षा पर जो समझौता जून 2012 में हस्ताक्षरित हुआ वह 1 अगस्त 2014 से प्रभावी हुआ।

यूनान

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने न्यूयॉर्क में 25 सितंबर 2014 को 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के मार्जिन पर यूनान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री इवनगेलॉस विनिज़लोस से मुलाकात की ।

उत्तराखंड विधान सभा के स्पीकर, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, यूनान के लिए एक अध्ययन दौरे पर 15–17 अक्टूबर, 2014 को एथेंस गये।

भारत–यूनान विदेश कार्यालय परामर्श का 10वां दौर 9 मई 2014 को एथेंस में आयोजित किया गया था । भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री दिनकर खुल्लर, सचिव (पश्चिम) और यूनानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूनानी विदेश कार्यालय के महासचिव राजदूत अनास्टासियोस मितसियालिस के नेतृत्व में किया गया था।

यूनान ने यूरोपीय संघ के आवर्ती सभापतित्व 1 जनवरी 2014 को प्राप्त किया जो 01 जुलाई 2014 को इटली को सौंप दिया गया था।

दूतावास ने 27 मार्च, 2014 को एथेंस में पहले व्यापार संवर्द्धन फोरम का आयोजन किया। सम्मानित अतिथि श्री लायोनिस प्लेक्सिोटकिस (सांसद), भारत–यूनान संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष थे।

भारत में पांच स्कूलों से क्रिकेट टीमों ने यूनानी क्रिकेट फेडरेशन द्वारा 21–26 अप्रैल, 2014 को कोर्फू में आयोजित चौथे इंटरनेशनल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया । टूर्नामेंट में यूनान, भारत, दक्षिण अफ्रीका, बुल्गारिया और इंग्लैंड से कुल 10 टीमें थी, जैन इंटरनेशनल स्कूल, बंगलौर ने ट्राफी जीती।

आईटीपीओ के तत्वावधान में 7–14 सितंबर, 2014 को आयोजित 79वें थेसालोनिकी अंतरराष्ट्रीय मेले में बत्तीस भारतीय कंपनियों (एसएमई) ने भाग लिया।

संस्कृति और विकास के लिए भारत–हेलेनिक सोसायटी के सहयोग से, भारतीय दूतावास एथेंस ने यूनान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की। प्रमुख कार्यक्रम थेः जून, 2014 में दूसरा बॉलीवुड नृत्य महोत्सव, जून में थेसालोनिकी और एथेंस में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग (श्री सत्यजीत रे की याद में अप्रैल में और फिल्म लंच बॉक्स की वाणिज्यिक स्क्रीनिंग अगस्त 2014 में) और 02 अक्टूबर, 2014 को न्यूयॉर्क कॉलेज, एथेंस में गांधी जयंती मनाई गयी जहां राजदूत ने गांधीजी और उनके दर्शन पर संबोधन किया।

राजदूत द्वारा 'मेंक इन इंडिया' अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए एथेंस से एक दर्जन से अधिक व्यवसायियों और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया। एक दर्जन से अधिक प्रमुख यूनानी उद्यमियों को बैचों में 17 अक्टूबर 2014 और 24 अक्टूबर, 2014 को दूतावास में आमंत्रित किया गया था।

होली सी

एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल श्री ऑस्कर फर्नांडिस, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री के नेतृत्व में वेटिकन में 27 अप्रैल 2014 को स्वर्गीय पोप जॉन पॉल द्वितीय और पोप जॉन XXIII के केननिज़ैषण समारोह में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया। प्रतिनिधिमंडल में प्रो0 के वी थॉमस, उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और न्यायमूर्ति स्यरीयाक जोसेफ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य (एनएचआरसी) थे।

राजदूत ने 15 मई, 2014 को वेटिकन में होलीनैस पोप फ्रांसिस को क्रेडेंशियल्स प्रस्तुत किया । उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए वेटिकन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की।

दो भारतीय कैथोलिक पादरियों अर्थात धन्य पिता कुरियाकोस एलियास चवरा और धन्य बहन यूफ्रेसिया वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर पर 23 नवम्बर 2014 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए गए थे । राज्य सभा के उप स्पीकर, श्री पी जे के कुरियन ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें केरल राज्य सरकार की ओर से कई सांसद और मंत्री सम्मिलित थे।

हंगरी

संबंध करीबी हैं, अनुकूल, बहुमुखी और सारवान हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं ने द्विपक्षीय सहयोग को दृढ़ता प्रदान की है।

तीन सदस्यीय भारतीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल (28–30 अप्रैल, 2014) ने रासायनिक जैविक रेडियोधर्मी और परमाणु उपकरण, प्रशिक्षणए हवाई सीबीआरएन और प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं के क्षेत्र में सहयोग को अंतिम रूप देने के लिए हंगरी के परमाणु जैविक और रासायनिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया।

21–22 सितम्बर 2014 को पर बुडापेस्ट में एक अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसके लिए सचिव (आयुष) श्री नीलांजन सान्याल ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। जनवरी 2014 में स्थापित आयुष सूचना केंद्र, यूरोप में पहला इस तरह का केंद्र है और हंगरी में आयुष को बढ़ावा देने में कारगर है।

राजदूत और उप मंत्री श्री बेन्स रेतवारी ने 19 नवम्बर 2014 को शिक्षा आदान–प्रदान कार्यक्रम (ईईपी) पर हस्ताक्षर किए। 2014–2017 की अवधि के लिए ईईपी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को, प्रकाशनों ,शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम और वार्षिक छात्रवृत्ति की संस्थाओं के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करती है।

एक बिजनेस संगोष्ठी "मेक इन इंडिया–पीएम मोदी के विजन" का 14 अक्टूबर 2014 को दूतावास में आयोजित किया गया था । मिशन में स्वच्छ भारत अभियान 28 नवंबरए 2014 को आयोजित किया गया।

आइसलैंड

भारत के मित्रों के सहयोग से एक फिल्म समारोह 08–13 अप्रैल, 2014 को मनाया गया। त्योहार के दौरान छह हिन्दी फिल्मों की स्क्रीनिंग एक बड़ी सफलता थी ।

भारत वीक 2014 के लिए भारी प्रतिक्रिया हुई थी जो होटल हिल्टन, नोर्डिका में 10 से 16 मई 2014 को मनाया गया। इस रूप में कई वर्षों में यह दूसरा भारतीय सप्ताह था। यह केरल पर्यटन की मदद से आयोजित किया गया था जिसमें उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक मास्टरशैफ और एक आयुर्वेद चिकित्सक भेजा। सुश्री प्रगति सूद भारत से एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना ने एक नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। इस स्वागत स्मारोह में श्री गुन्नर ब्रागी स्वेनिसनए आइसलैंड के विदेश मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

आर्कटिक सर्कल सम्मेलन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2014 को हर्पा कन्वेंशन सेंटर, रेकजाविक में आयोजित किया गया था। दुनिया भर से लगभग 1400 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत के दूतावास ने इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था।

एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 नवंबर, 2014 को आइसलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। भारत ने प्रतिनिधित्व किया था और भारत पर जानकारी प्रदर्शित की गयी थी और भारतीय भोजन परोसा गया था।

लातविया

द्विपक्षीय संबंध आत्मीय और सौहार्दपूर्ण बने हुये हैं। लातविया ने जनवरी 2014 नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला और भारत में लातविया के पहले राजदूत श्री आयवर्स ग्रोज़ा ने 21 अक्टूबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति को क्रेडेंशियल्स प्रस्तुत किये ।

एक आयुर्वेद सम्मेलन 30 अप्रैल 2014 को लातविया के विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था और एक समझौता ज्ञापन पर लातविया के विश्वविद्यालय और आर्य वैद्य चिकित्साल्यम और अनुसंधान संस्थानए कोयम्बटूर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

सांस्कृतिक संबंध एक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित 10 सदस्यीय गुजराती नृत्य मंडली 'सप्तक' 20–26 जून, 2014 को यात्रा के साथ मजबूत हुये। उन्होंने रीगा से संबंधित समारोह में, जिसे 2014 के लिए यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया जा रहा है, भाग लिया और लातविया के इस तीसरे सबसे बड़े शहर में लिएपाजा में आयोजित किया जाने वाले, पहली बार आयोजित भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया।

लिथुआनिया

लिथुआनियाई और एशियाई उद्यमों व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, सरकार निकायों के साथ रचनात्मक संबंधों को स्थापित करने में मदद करने के लिए 6 जून 2014 पर विलनियस में एशियाई बिजनेस फोरम आयोजित किया गया था।

एक वार्षिक आयोजन, विलनियस में एशियाई दिन, 06–07 जून, 2014 को विनियस के मेयर द्वारा आयोजित किया गया था । विलनियस में मान्यता प्राप्त एशियाई मिशन ने कार्यक्रम में भाग लिया। कलाकारों की भागीदारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भरतनाट्यम, कथक और भारतीय संगीत प्रस्तुत किया गया।

भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत का "सुर साधना' त्योहार विलनियस में 21 नवम्बर 2014 को और 22 नवंबर, 2014 को विलनियस में आयोजित किया गया था । जाने–माने सितार वादक पंडित अशोक पाठक द्वारा उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की धुनों को तबला गुरु श्री संदीप भट्टाचार्य के साथ प्रस्तुत किया गया । श्री विश्नाथ मंगाराज उड़ीसी के प्रतिपादक के साथ अन्य लिथुआनियाई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी।

विदेश मामलों के उप मंत्री श्री मान्टयुदास बेकेसियस और कृषि उप मंत्रीए श्री साउलियस किरोनका ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मान्यता प्राप्त उनके मानद वाणिज्यदूतों से मिलने के लिएए 10–12 नवम्बर, 2014 को भारत का दौरा किया। विदेश मामलों के उप मंत्री ने सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सिंह सरना और कृषि के उप–मंत्री ने, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की।

शिक्षा और विज्ञान के उप–मंत्री ने लिथुआनिया से एक शिक्षा प्रतिनिधिमंडल के साथ 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2014 तक भारत का दौरा किया।

मैसेडोनिया

संबंध आत्मीय और दोस्ताना हैं और संबंध बढ़ रहे हैं। मैसेडोनिया ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों में भारत का समर्थन किया गया है।

भारत और मैसेडोनिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार और आर्थिक मोर्चों के संबंध में एक दूसरे की क्षमता में आपसी जागरूकता की कमी के कारण मामूली बने रहे। मकदूनियाई सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं।

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत भारत द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण छात्रवृत्ति का लाभ मैसेडोनिया ले रहा है।

भारत और मैसेडोनिया के बीच दोहरे कराधान के समझौते का बचाव 4 सितंबर 2014 को अस्तित्व में आया।

माल्टा

भारत पहले देशों में एक था जिसने माल्टा की स्वतंत्रता की पहचान की थी और 1965 में इसके साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की और दोनों देशों के बीच तभी से संबंध अनुकूल हैं। हाल ही के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन और विविधीकरण देखा है विशेष रूप से व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। 01 अप्रैल से 30 नवंबर, 2014 की अवधि के दौरान सबसे उल्लेखनीय थेः

एक छह सदस्य, सीआईआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिनिधिमंडल ने 8–10 अप्रैल, 2014 को माल्टा का दौरा किया और माल्टा उद्यम के साथ सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय स्कूलों से छात्रों और शिक्षकों के एक समूह ने 27 अप्रैल से 04 मई 2014 को माल्टा का दौरा किया। जून 2014 में, एक भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया था।

लीबिया में बिगड़ती सुरक्षा शर्तों के कारण बांघज़ी की लीबिया बंदरगाह शहर से विशेष जहाज द्वारा छोड़े गये 289 भारतीय नागरिकों को लेने के लिए एक दुर्लभ विजिट 10 अगस्त, 2014 को एयर इंडिया के एक विशेष विमान ने माल्टा से की।

मोलदोवा

संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दूतावास ने अच्छी तरह से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा।

मोंटेनेग्रो

यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य (एसएफआरवाई) के दिनों के बाद से मोंटेनेग्रो के साथ संबंध पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं जब यह एक घटक गणतंत्र था।

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने 2 सितंबर 2014 को मोंटेनेग्रो की सरकारी यात्रा की । इस यात्रा के दौरान, उन्होंने राष्ट्रपति श्री फिलिप युजानोविक, प्रधानमंत्री श्री मिलो जुकानोविक और उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री इगोर लुकसिक से मुलाकात की। मोंटेनिग्रिन गणमान्य व्यक्तियों का मुख्य ध्यान, यात्राओं और प्रस्तुतियों के संगठन के आदान–प्रदान के माध्यम से निवेश और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर था हालांकि समग्र सहयोग विशेष रूप से शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र पर भी चर्चा की गई थी। दोनों पक्षों ने गंभीरता से आर्थिक सहयोग के लिए अंतर सरकारी समिति की स्थापना की संभावना का पता लगाने पर सहमति दी।

सुश्री ततजाना बर्जानोविक एक मोंटेनिग्रिन राष्ट्रीक के चित्रों की पोडगोरिका में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन 15 अप्रैल, 2014 को किया गया था। सुश्री ततजाना बर्जानोविक ने भगवद गीता से चित्रों को चित्रित किया। इस अवसर पर मोंटेनेग्रो के राष्ट्रपति श्री फ़िलिप युजानोविक उद्घाटन समारोह के लिए उपस्थित थे।

एक छह सदस्यीय आईसीसीआर प्रायोजितए कथक नृत्य समूह ने, सुश्री रूजाता सांमन के नेतृत्व में मोंटेनेग्रो का दौरा किया और दो तटीय शहरों तिवत और बुदवा में क्रमशः 29 और 30 मई, 2014 को प्रदर्शन किया। परिवहन मंत्री श्री वैन ब्रेजोविक ने तिवत के समारोह में भाग लिया।

श्री. व्लादिमीर रादुलोविक, मोंटेनेग्रो के पॉडगोरिका निवासी को भारत गणराज्य के पहले राजदूत असाधारण और पूर्णाधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी गई है।

बॉलीवुड कार्यक्रम केआईसी बुदो टोमोविक सेंटर, पॉडगोरिका में 27–30 अक्टूबर 2014 को आयोजित किया गया था । सर्बियाई उपशीर्षक के साथ तीन भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की गयी जिसपर जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

नॉर्वे

1–30 नवम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत जारी रही।

महामहिम राजा हेराल्ड वी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नॉर्वे का 12–14 अक्टूबर, 2014 को आधिकारिक राजकीय दौरा किया। यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा थी जिसमें किसी राज्य के प्रमुख अधिकारी नॉर्वे में पहली सरकारी यात्रा पर आए। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने अन्य लोगों के साथ साथ, शाही परिवार के प्रतिनिधियों, स्टार्टिंग के राष्ट्रपति ओलेमिक थोमेसन और प्रधानमंत्री श्री साल्बर्ग से मुलाकात की। यात्रा का स्थायी उद्देश्य शिक्षाए अनुसंधान, नवाचार, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना था। राष्ट्रपति ने वीडियो लिंक के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों से, जिन्होंने वर्तमान में आर्कटिक, 'हिमाद्री' में भारत के रिसर्च स्टेशन के साथ परियोजनाओं को शुरू किया है, उनके के साथ–साथ स्वालबार्ड विश्वविद्यालय केंद्र में भारतीय शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की।

यात्रा के दौरान छह सरकारी समझौते पृथ्वी विज्ञान, संस्कृति, वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के साथ–साथ कांसुली मामलों और शैक्षिक संस्थाओं के बीच आठ एमओयू किये गये।

सचिव (ए और सी) कृषि मंत्रालय, श्री आशीष बहुगुणा ने 6–11 अप्रैल, 2014 को डॉ मंडल, लाइफ साइंसेज, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के निदेशक जनरल और प्रोफेसर बंसलए संयंत्र आनुवंशिक संसाधन के राष्ट्रीय ब्यूरो के निदेशक सहित एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने कृषि और पर्यावरण अनुसंधान (Bioforsk) के लिए नार्वे संस्थान का दौरा किया और ओस्लो में नॉर्वे के कृषि और खाद्य मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया। उन्होंने स्वालबार्ड में ग्लोबल सीड वॉल्ट देखने के लिए दौरा किया।

श्री दिनकर खुल्लर, सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 23–25 अप्रैल, 2014 को ओस्लो नार्वे का दौरा किया और विदेश कार्यालय परामर्श का 6वां दौर आयोजित किया। नार्वे की ओर से श्री क्रिश्चियन सायसे, उप महा सचिव ने नेतृत्व किया था। सचिव (पश्चिम) ने श्री ओलिविंद हालेरकर, विदेशी मामलों और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रथम उप चेयर के साथ और श्री बार्ड ग्लेड पेडरसन, राज्य सचिवए विदेशी मामलों के नार्वेजियन मंत्रालय के साथ बैठकों का आयोजन किया।

श्रीमती स्नेहलता कुमारए सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय और श्रीमती नीलकमल दरबारी, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 15–16 मई 2014 को आपदा न्यूनीकरण और रिकवरी (जीएफडीआरआर) ओस्लो की ग्लोबल सुविधा के सलाहकार समूह की 15 वीं बैठक में भाग लिया।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज नेए न्यूयॉर्क में 25 सितंबर 2014 को 69 संयुक्त राष्ट्र महासभा के मार्जिन पर नार्वे के विदेश मंत्री श्री बार्गे ब्रेंडे से मुलाकात की।

श्री कैलाश सत्यार्थी, भारतीय बच्चों के अधिकारों के कार्यकर्ता, नार्वे नोबेल समिति के 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार का संयुक्त विजेता रहा था।

श्री शेख पारीथ, निदेशक, केरल पर्यटन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 11–12 नवंबर, 2014 को, केरल को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए ओस्लो रोड शो का आयोजन करने के लिए ओस्लो का दौरा किया।

पोलैंड

वर्ष 2014 भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल होने पर विशेष महत्व का रहा किया जा रहा है, और इस मील का पत्थर का जश्न मनाने के लिए आउटरीच गतिविधियों की एक बड़ी संख्या इस ऐतिहासिक वर्ष में आयोजित की गई। प्रख्यात भारतीय कलाकारों के नेतृत्व में कई सांस्कृतिक दलों ने पोलैंड में विभिन्न समारोहों में प्रदर्शन किया।

सुश्री रमा वैद्यनाथन, श्री रूपिंदर बेदी और श्री हिमांशु कनकमल डूगर और उनसे संबंधित मंडलियों ने जुलाई 2014 में पोलैंड के विभिन्न शहरों में आयोजित ब्रेव महोत्सव में भाग लिया । ट्रांसेटेनिका के निमंत्रण परए जून 2014 में गणेश–कुमारेश संगीत समूह ने पॉज़्नान में प्रदर्शन किया। सितंबर 2014 में रंगमंच अभ्यास के लिए केन्द्र द्वारा 'भारत, भारत...फैस्टीवल' आयोजित किया गया जिसमें थिएटर प्रदर्शन, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और फिल्म शो किये गये, वांडा डायनोव्सकी – उमादेवी, महात्मा गांधी की एक मित्र को समर्पित वैज्ञानिक सम्मेलन किया गया। प्रसिद्ध कलाकार सुश्री मल्लिका साराभाई और उसके ग्रुप ने इस त्योहार में प्रदर्शन किया।

लोकतंत्रों के समुदाय के स्थायी सचिवालय के निमंत्रण पर एस वाई कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने, 14 अप्रैल 2014 को

"विश्व के सबसे बड़े चुनावों का प्रबंधन– कैसे करता है भारत" शीर्षक से एक व्याख्यान दिया।

नैशनल डिफेंस कालेज से 'राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन' विषय पर अपने एक वर्ष के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में, एक 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 18–24 मई 2014 से एक अध्ययन दौरा किया।

100 से अधिक भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों, ज्यादातर एमएसएमई क्षेत्र सेए 3–6 जून, 2014 को पॉज़्नान, पोलैंड में 'इंडिया शो' में भारत की इंजीनियरिंग कौशल कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम आईटीएम पॉज़्नान, पोलैंड के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और मशीन उपकरण मेले के साथ हुई पोलैंड के प्रदर्शन और ईईपीसी और वाणिज्य और भारी उद्योग विभाग के मंत्रालय द्वारा समन्वित किया गया था। भारत को पोलैंड की सरकार द्वारा 'भागीदार देश' का दर्जा दिया गया था। अर्थव्यवस्था के लिए पोलिश उप मंत्री समारोह में मुख्य अतिथि थे। वाणिज्य और भारी उद्योग विभाग के विभाग के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया ।

7वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए एक प्रस्तावना के रूप में गांधीनगर, गुजरात में, श्री जी सी मुर्मू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 11–13 जनवरी, 2015 को सहयोग, प्रसार और गुजरात राज्य में निवेश के अवसरों और निवेश माहौल को तेज करने की दृष्टि से 04–07 सितंबर 2014 का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में कॉर्पोरेट और आईएनडीईग्एक्सटीबी, केपीएमजी और सीआईआई के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधिमंडल ने पोलिश वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों और इंडो–पोलिश वाणिज्य और उद्योग चैंबर्स की साझेदारी में आयोजित वारसॉ और व्रोकला के कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें अर्थव्यवस्था और विदेश मामलों के उप मंत्रियों और पोलैंड की सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। व्यापार और उद्योग के अग्रणी सदस्यों के साथ और शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बी 2 बी बैठकें की गयी और थिंक टैंक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के अन्य आकर्षण थे।

भारत पोलो कप 2014 में 20–21 सितंबर 2014 को वारसॉ में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना के दो अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

पोलिश उप कृषि मंत्री श्री टेडुसेज़ नेलेव्ज्क ने, पोलिश खाद्य उत्पादोंए विशेष रूप से सेब के लिए सितंबर 2014 में भारत के बाजार की खोज के सिलसिले में भारत का दौरा किया। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल से भेंट की।

वारसा में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को ''पोलैंड–भारत'' आर्थिक कूटनीति के एक प्रभावी मॉडल की ओर'' एक सेमिनार साथ संयोजन के रूप में' पोलिश संसद के महत्वपूर्ण परिसर में आयोजित किया गया था ।

नवांनगर के जाम साहेब दिगविजय सिंहजी रणजीत सिंहजी जडेजा के उपलक्ष्य में एक स्मारक गुड महाराजा, जिला अछूटा, वारसॉ में 31 अक्टूबर 2014 को अनावरण किया गया था। कार्यक्रम युद्व और शहादत और स्मृति के संरक्षण के लिए पोलिश परिषद, अछूटा जिले के मेयर द्वारा आयोजित किया गया था। समारोह में श्री एंडरेज कुनर्ट, युद्व और शहादत की स्मृति के संरक्षण के लिए मंत्री और मेयर ने भाग लिया ।

रोमानिया

द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों आत्मीय और दोस्ताना हैं।

10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, ऑल इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईए), मुंबई, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) से प्रतिनिधियों, भारत के अन्य शहरों की एसोसियेशन ने 27–30 अप्रैल, 2014 को बुखारेस्ट में आयोजित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की महासभा की बैठक में भाग लिया । प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री विजय क्लांत्रि, अध्यक्ष आईआईए ने किया था। प्रधानमंत्री श्री विक्टर पोंटा ने, वाणिज्य रोमानियाई चैंबर, अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का उद्घाटन किया।

एयर मार्शल डी एस खजूरिया के नेतृत्व में एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने 06–09 सितंबर 2014 के दौरान बुखारेस्ट का दौरा किया और स्थानीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों सहित रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया। राजदूत ने भी चर्चा में भाग लिया । एयर मार्शल खजूरिया ने मै0 ऐरोस्टारएसआरएल, बकाउ की सुविधाओं का दौरा किया जिनके साथ मिग विमानों की सर्विसिंग के लिए भारतीय वायु सेना ने एक समझौता किया है।

श्री सारीन एनकटेसु, रोमानियाई प्रधानमंत्री कार्यालय में रक्षा एवं सुरक्षा के मुद्दों के लिए रोमानियाई राज्य काउंसलर, श्री केटालिन ओल्टियानु, राज्य सचिव (उप मंत्री), अर्थव्यवस्था और कंपनियों से संबद् रक्षा उत्पादन मंत्रालय ने 23 से 29 नवंबर 2014 को भारत का दौरा किया। रोमानियाई रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, सचिव (रक्षा उत्पादन) सहित, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ बैठक की।

दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अभिवादन के संदेशों के आदान–प्रदान सहित भारत और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 65 साल चिह्नित करने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। "सांस्कृतिक मूल्य और भारत के लोकाचार" विषय पर एक पुस्तिका – भारत के दूतावास द्वारा प्रकाशित की गयी और बैठकोंए स्वागत और राष्ट्रीय दिवस की घटनाओं के दौरान स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के बीच वितरण के लिए इसे पुस्तक का प्रयोग किया जा रहा है।

"नमस्ते इंडिया'' भारत की संस्कृति की विविधता का प्रदर्शन करने वाला एक सांस्कृतिक महोत्सव दूतावास, फ्रैंकफर्ट पर्यटक कार्यालय और स्थानीय भारतीय सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा

संयुक्त रूप से 23–25 मई 2014 को गांव संग्रहालय, बुखारेस्ट में आयोजित किया गया था । अब यह एक वार्षिक आयोजन बन गया है।

एक आईसीसीआर प्रायोजित राजस्थानी लोक नृत्य समूह ने 26–28 मई 2014 को दौरा किया और इस दौरान तीन सांस्कृतिक कार्यक्रम किये।

एक पर्यटन रोड शो बुखारेस्ट दूतावास और पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट द्वारा 20 जून, 2014 को किया गया जिसमें एयर इंडिया पर्यटन कार्यालय और दूतावास द्वारा प्रस्तुतियां शामिल हैं।

भारत के दूतावास ने भारत के भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गयी पहल 'मेक इन इंडिया' पर रोमानिया के आर्थिक मंत्रालय में 26 सितम्बर 2014 को प्रस्तुती का आयोजन किया जिसमें, भारत सरकार द्वारा उठाए आगे आर्थिक उदारीकरण के उपायों और प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला। प्रमुख भारतीय व्यवसायियों और कॉमर्स के स्थानीय मंडलों से प्रतिनिधियों ने प्रस्तुति में भाग लिया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित भारत से 14 प्रसिद्ध आलंकारिक कलाकारों द्वारा "कल्पना" शीर्षक से चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन 14–20 नवम्बर , 2014 को आयोजित किया गया जिसकी मेजबानी कला संग्रहालय, प्लोइस्टि द्वारा की गयी।

सर्बिया

मार्च / मई, 2014 में क्रमशा सर्बिया और भारत के राष्ट्रीय चुनावों के बाद दोनों नई सरकारों की स्थापना के बाद संपर्कों में तेजी आई है; श्री बजे। श्री नरेंद्र मोदी और सर्बियाई प्रधानमंत्री श्री एलेक्ज़ैंडर व्युसिक ने आत्मीय संदेशों से ऐतिहासिक दोस्ती नवीनीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ विमर्श किया। मई 2014 में सर्बिया में भयावह बाढ़ के फलस्वरूप सद्भावना के एक इशारे के रूप में भारत सरकार ने 100,000 अमरीकी डालर की तत्काल वित्तीय राहत सहायता प्रदान की ।सर्बिया ने संबंधित जम्मू और कश्मीर में बाढ़ के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की।

सर्बिया ने मानवाधिकार परिषद में भारत की उम्मीदवारी का और अंतर सरकारी समिति के चुनाव में समर्थन किया और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सर्बिया की सुरक्षा के लिए 2021–22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की ग़ैर–स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष में समर्थन का पूर्व संकेत दिया।

संयुक्त आर्थिक समिति की दूसरी बैठक (जेईसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 अक्टूबर 2014 को आयोजित की गयी थी। सर्बियाई पक्ष ने भारतीय उद्योग निजीकरण की प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए और कृषि, कृषि प्रसंस्करण, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और आईसीटी के क्षेत्र में रणनीतिक समझौते में प्रवेश करने के लिए अनुरोध किया। दोनों पक्षों ने व्यापार मेलों में भागीदारी, बीआइपीए, डीटैक, पर्यटन, व्यापार, एयर सेवाओं और आईटीईसी आदि को सक्षम करने सहित मौजूदा समझौतों का लाभ लेने के लिए अनुरोध किया।

लंबित समझौतों को अंतिम रूप दिया गया जैसे कि पारंपरिक दवाओं पर समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन (कला, खेल, युवा और मास मीडिया सहित) ।

भारतीय कृषि मशीनरी कंपनियों जैसेकि टीएएफई, महिंद्रा और सोनालिका की सर्बियाई सहायक कंपनियों ने 20–26 मई, 2014 को आयेजित 81वें नोवी सेड अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले में भाग लिया। महिंद्रा ने बाढ़ पश्चात पुनर्वास के लिए ओब्रीनोवेक की नगर पालिका के लिए दो वाहनों का दान दिया

सार्वजनिक कूटनीति में भारत के दूतावास की पहल में बाहरी बस ब्रांडिंग और पत्रकारों की यात्राओं, बेलग्रेड फैशन वीक (मनीष अरोड़ा), बेलग्रेड डिजाइन वीक (सत्य शील), बेलग्रेड पुस्तक मेला, बेलग्रेड अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, और फिल्मस्ट्रीट के द्वारा 'बर्फी!' फिल्म की स्क्रीनिंग के माध्यम से अतुल्य भारत का संवर्द्धन शामिल है। आईसीसीआर शो समान रूप से सराहे गये जिसमें रूजाता सोमन का कथक, पपोन महंत के फ्यूज़न संगीत, रीता कपूर चिश्ती की सहकारी साड़ी प्रदर्शनी, टैगोर डिजिटल कला कार्य शामिल हैं। सामाजिक मीडिया के माध्यम से भारत–सर्बिया फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की गयी थी।

सर्बियाई फिल्म उद्योग ने मुंबई और गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया था; गोरान पास्कजेविक, प्रसिद्ध सर्बियाई फिल्म निर्देशक और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी के अध्यक्ष ने, पहले भारत सर्बिया. दृश्य–श्रव्य सह–निर्माण को अंतिम रूप दिया। भारतीय निर्देशक और पटकथा लेखक श्री चैतन्य तम्हानेए का प्रथम साहसिक प्रयास को "कोर्ट", को बेलग्रेड के 20 वें फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया गया और भव्य पुरस्कार "एलेक्ज़ैंडर सास पैट्रोविक" से सम्मानित किया गया था।

स्पोर्टिंग लिंक शतरंज सिमुल के लिए (प्रदर्शनी) के साथ श्री ग्रैंडमास्टर पेनताहो हरिकृष्णा की यात्रा के साथ मजबूत हुये थे। सर्बिया ने भारतीय पासपोर्ट (और अन्य) शेंगेन / ब्रिटेन और अमेरिका वीजा रखने वालों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी।

स्लोवाक गणराज्य

विदेशी और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय में राज्य सचिव श्री पीटर बुरियन, 24–26 नवंबर, 2014 को भारत की सरकारी यात्रा पर आए। राज्य सचिव ने विदेश राज्य मंत्री, जनरल (डॉ) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की थी और वाणिज्य सचिव और अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कराधान के केंद्रीय बोर्ड (सीबीडीटी) को भी बुलाया। सीबीडीटी के साथ 1986 के दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) के अनुच्छेद 24 के आवेदन को हल करने के लिए एक व्याख्यात्मक समझौता ज्ञापन पर श्री बुरियन और अध्यक्ष सीबीडीटी द्वारा हस्ताक्षर किए गए ।

वित्त मंत्रालय के निमंत्रण परए स्लोवाक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत और स्लोवाकिया के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर बातचीत करने के लिए 27–30 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली का दौरा किया।

भारत पर्यटन कार्यालय फ्रैंकफर्ट द्वारा ब्रातिस्लावा में एक पर्यटन मेले का आयोजन अक्टूबर 15, 2014 को किया गया था। भारतीय और अंग्रेजी कलाकारों द्वारा एक सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय दूतावास की भागीदारी के साथए ब्रातिस्लावा योग दिवस 8 नवम्बर 2014 पर स्लोवाक योग एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था।

स्लोवेनिया

राज्य मंत्री (वीकेएस) ने ब्लेड सामरिक फोरम के लिए स्लोवेनिया (31 अगस्त से 1 सितम्बर 2014 को) का दौरा किया। वह नेताओं के पैनल में मुख्य वक्ताओं में से एक थे। इस यात्रा के दौरानए राज्यमंत्री (वी के एस) श्री राष्ट्रपति श्री बरूत पहोर, प्रधानमंत्री निर्वाचित श्री मिरा केरार और श्री एफ एम कार्ल इरजवेक से मुलाकात की। भारत इस वर्ष के व्यापार ब्लेड सामरिक फोरम (1–2 सितम्बर 2014) का एक ध्यान केंद्रित देश रहा। "भारत और दक्षिण पूर्व यूरोप" पर पैनल चर्चा में वक्ताओं में श्री प्रकाश हिंदुजा, श्री दीप कपूरिया और स्लोवेनियाई चैंबर के वाणिज्य एवं उद्योग के अध्यक्ष श्री सामो हरिबर मिलिकशामिल थे। फिक्की और सीआईआई से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भी ब्लेड सामरिक फोरम के दौरान स्लोवेनिया का दौरा किया।

16 अक्टूबर 2014 को मिलान में एएसईएम बैठक के मौके पर राज्य मंत्री (वीकेएस)ने श्री मिरो केरार, प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

भारत से अन्य यात्राओं में उप सचिव (डीपीई) और सचिव आयुष (24–27 सितम्बर 2014) शामिल थे। सचिव आयुष ने दूतावास के कार्यालय में आयुष सूचना केंद्र का उद्घाटन किया।

शिक्षाए विज्ञान और खेल के स्लोवेनियाई मंत्रालय में राज्य सचिव ने नई दिल्ली में सीआईआई के ज्ञान एक्सपो 2014 (21–23 नवम्बर 2014) के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

प्रिमॉरस्का विश्वविद्यालय के रेक्टर नई दिल्ली में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (07–09 नवम्बर 2014) में भाग लिया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति की तीसरी संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में के 19 नवंबर 2014 को आयोजित की गयी थी । आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा की गई और पीओसी 2014–17 के तहत संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की गई।

भारत ने स्लोवेनिया में कई व्यापार मेलों में भाग लिया। 18 भारतीय कंपनियों ने 10– 15 सितंबर 2014 के दौरान सेल्जे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया।

जुबज़ाना शराब प्रतियोगिता और सस्ता जुबज़ाना इंटरनेशनल वाइन मेले में स्लोवेनिया में पहली बार भारत की चुनी हुई वाइन को पेश किया गया।

भारत ने जुबज़ाना (13–16 नवम्बर 2014) में 45वें प्राकृतिक स्वास्थ्य मेले में भाग लिया । होम्योपैथी में अनुसंधान परिषद और आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद से आयुर्वेद और होम्योपैथी सलाहकारों ने मेले में भाग लिया।

25–30 नवंबर 2014 को आयोजित 30वें स्लोवेनियाई पुस्तक मेले में पहली बार के लिए भारत ने भाग लिया।

एन आई एम एस विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधिमंडल,जयपुर ने 21 अक्टूबर 2014 को स्लोवेनिया दौरा किया और एन आई एम एस ग्रुप के सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जुबज़ाना, मारिबोर और प्रिमॉरस्का विश्वविद्यालय में बैठकों के साथ ही बायोटेक में निवेश, अक्षय ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया ।

वर्ष के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मई 2014 में शिक्षा, विज्ञान और खेल मंत्रालय; आईसीपीई; मारिबोर की नगर पालिकाय मारिबोर विश्वविद्यालय के सहयोग से, दूतावास द्वारा आयोजित किया गया गुरुदेव टैगोर वीक शामिल है । गांधी जयंती एक शांति मैसेंजर सिटी के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त साल्वेंज ग्रेडेक के स्लोवेनियाई टाउन में मनायी गयी। पुस्तक – पिता के पत्र पुत्री के नाम – स्लोवेनियाई में अनुवाद किया गया था। यह 19 नवंबर 2014 को लोकार्पित की गयी। भारत और स्लोवेनिया ने 28 नवंबर 2014 को जवाहर लाल नेहरू की 125 वीं जयंती मनाने के लिए एक संयुक्त स्टाम्प जारी किया गया था । इंडिया वीक (01–5 दिसंबर 2014 तक) जुबज़ाना में 29 नगर पालिका पुस्तकालयों में आयोजित किया गया । कार्यक्रिमों की एक संख्या में पुस्तकालयों में भारत पर पुस्तकों का प्रदर्शन, भारतीय फिल्मों का स्क्रीनिंग, विचार संगोष्ठियां और राउंड टेबल सहित कई आयोजन किये गये।

वर्ष के दौरान स्लोवेनिया में दो भारतीय फिल्मों और वाणिज्यिक शूट किये गये। वर्ष के दौरान स्लोवेनिया में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग फिल्म समारोहों में की गई। 17–21 जून 2014 को चार भारतीय फिल्में खुले इसोला फिल्म महोत्सव में 4–8 जून 2014 को प्रस्तुत की गयी । ब्लेड फिल्म महोत्सव में पहली फिल्म निर्देशक रजत कपूर की 'आंखों देखी' थी जिसे खुले मन से स्वीकारा गया और सराहना की गयी। एक भारतीय फिल्म – आशा जाओर मज्हे को 12–13 नवम्बर, 2014 के दौरान 23वें जुबज़ाना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रदर्शित किया गया।

मीडिया ने भारत में 11 जुलाई, 2014 को चार स्लोवेनियाई पत्रकारों की यात्रा, एयर इंडिया के कार्यक्रम को स्टार एलायंस समारोह में शामिल होने के लिए कवर किया। सितम्बर 2014 में ब्लेड सामरिक

फोरम के दौरान तीन भारतीय पत्रकारों की स्लोवेनियाई पक्ष द्वारा की मेजबानी की गयी।

भारत और स्लोवेनिया में स्कूलों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम चल रहे हैं। इदरिजा हाई स्कूल और एमिटी इंटरनेशनल, नोएडा के बीच एक विनिमय कार्यक्रम के तहत, इदरिजा से तीन छात्रों ने भारत में (जुलाई 2013 से फरवरी 2014) 7 महीने बिताए। जुलाई, 2014 में एमिटी इंटरनेशनल से एक छात्र की मेजबानी इदरिजा हाई स्कूल द्वारा की गयी । अदानी विद्या मंदिर, अहमदाबाद से छह छात्रों की मेज़बानी जिनाजिया मारिबोर सेकेंडरी स्कूल (अप्रैल 2014) द्वारा की गयी थी। बदले में, मारिबोर से छह छात्रों ने अहमदाबाद (अक्टूबर 2014) का दौरा किया।

सात भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्यमों के संवर्धन के लिए, इंटरनेशनल सेंटर जुबज़ाना (आईसीपीईद्ध द्वारा और अर्थशास्त्र के संकाय के एक साल के एमबीए पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। उद्यमों के संवर्धन के लिए इंटरनेशनल सेंटर, जुबज़ाना (आईसीपीईद्धए ने नैशनल इंस्च्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, हैदराबाद से 47 अधिकारियों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (02–06 जून 2014), एएससीआई से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 25 महिला अधिकारियों और सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद से (01–14 दिसम्बर 2014) से आठ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम का आयोजन किया।

स्वीडन

द्विपक्षीय संबंधों के मंत्रिस्तरीय और सरकारी स्तर पर महत्वपूर्ण यात्राओं के साथ 2014–2015 के दौरान विस्तार जारी रहा।

स्वीडन की महत्वपूर्ण यात्राओं में 10–13 नवम्बर, 2014 को रियर एडमिरल जॉन थार्नक्विस्टए रॉयल स्वीडिश नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ और 23–25 नवंबर, 2014 से श्री गेब्रियल विक्सटॉम, हेल्थकेयरए लोक स्वास्थ्य और खेल के लिए मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे शामिल हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से श्री जे.पी नड्डा से 24 नवंबर 2014 को मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और स्वीडन के बीच समझौता ज्ञापन के पांच साल के उत्सव के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया। यह भारत और स्वीडन, दोनों नई सरकारों के नए मंत्रियों की पहली बैठक थी।

भारत से दौरों में डॉ अरुण मारिया, योजना आयोग के सदस्य की यात्रा शामिल है। उच्च स्तरीय आधिकारिक दौरों की संख्या में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डॉ अरबिंदो मित्रा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में जिन्होंने 22–25 अप्रैल 2014 को भारत–स्वीडन संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दौरा किया, दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डॉ0 लालकृष्ण विजय राघवन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के नेतृत्व में 22–25 अप्रैल 2014 को और 5 से7 मई 2014 को, डॉ शैलेश नायक, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में दौरा शामिल है।

चार सदस्यीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग पर भारत–स्वीडन संयुक्त कार्य समूह की चतुर्थ बैठक में भाग लेने के लिए मई 2014 26–27 स्टॉकहोम का दौरा किया।

पश्चिम बंगाल और कर्नाटक राज्यों से भी दो महत्वपूर्ण दौरों थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुब्रत मुखर्जी, मंत्री के नेतृत्व में, पश्चिम बंगाल में प्रभावित ग्रामीण आबादी के बीच सुरक्षित पानी का उपयोग–सहयोगात्मक अनुसंधान और ऊपर के लिए स्थायी आर्सेनिक शमन के तरीकों के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने 21–24 अगस्त, 2014 को स्टॉकहोम का दौरा किया। श्रीमती लालकृष्ण रत्ना प्रभा, अपर मुख्य सचिवए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार की ओर से एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 17–22 अगस्त, 2014 को दौरा किया और सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और खुदरा क्षेत्रों का अन्वेषण किया और स्वीडिश कंपनियों के लिए निवेश के अवसरों की प्रस्तुति दी।

रवींद्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार जीतने की 100 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता की एक कांस्य प्रतिमा का 7 मई 2014 पर अपसला विश्वविद्यालय में अनावरण किया गया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्कूल के सहयोग से दूतावास ने ग्रेड–एक्स में सबसे अच्छी परियोजना के लिए टैगोर पुरस्कार की स्थापना की।

आईसीसीआर की मदद से सांस्कृतिक आदान–प्रदान बनाए रखा गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने "सप्तक" एक 10 सदस्यीय गुजराती नृत्य मंडली को जून 2014 को पहली बार अम्यो और अर्नेस्कोल्डिव्सक में प्रदर्शन हेतु प्रायोजित किया यह पहला अवसर था जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा इन शहरो में ये प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। श्री सोमनाथ रॉय के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित "घातम मंडली" ने 28 सितंबर 2014 को स्टॉकहोम संगीत सम्मेलन में भाग लिया । इस समूह ने उपसला में भी प्रदर्शन किया ।

दूतावास ने भारत असीमित मंच, जो द्विपक्षीय कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है, के तहत 22–28 अप्रैल 2014 को एक सप्ताह तक समारोह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के माध्यम से भारतीय संस्कृति के अलग अलब और नए पहलुओं को एक फिल्म समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया जबकि व्यापार सम्मेलनों की एक श्रृंखला ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उभरते अवसरों को प्रस्तुत किया।

स्विट्जरलैंड

श्री मारियो मिशेल अफेंट्रागेंर, अंतर्राष्ट्रीय संधि, बर्न, विभाग के चीफ ने 1 मई 2014 को प्रवर्तन दिवस पर प्रवर्तन निदेशालय के निमंत्रण पर प्रवर्तन मामलों पर भारत–स्विस सहयोग पर प्रस्तुति के लिए भारत का दौरा किया।

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में, एक उच्च

स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 12–16 अक्टूबर 2014 को जेनेवा में आयोजित अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) विधानसभा के 131वें सत्र के लिए प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधिमंडल में प्रो पी.जे. कुरियन, उप सभापति, राज्य सभा और पांच सांसद शामिल थे। अध्यक्ष ने भारतीय समुदाय को मिलने के लिए ज्यूरिख का दौरा भी किया। इससे पहले, लोकसभा अध्यक्ष ने 4–5 सितंबर, 2014 को संसद की महिला अध्यक्षों की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए जिनेवा का दौरा किया था।

श्री शक्तिकांतादास, राजस्व सचिव ने स्विस राज्य सचिव वित्त, श्री जेक्स डे वेटेविले के साथ कर मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए 15 अक्टूबर 2014 को स्विट्जरलैंड के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया । स्विस पक्ष भारतीय अनुरोधों की जानकारी को तेज करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की और इस अवसर पर कर चोरी और धन–शोधन पर एक संयुक्त बयान जारी किया ।

इंडो–स्विस विदेश कार्यालय परामर्श की अंतरिम जेएस/डीजी स्तर दौर 18 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी चिंता के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। एक कांसुली बातचीत भी, कानूनी न्यायिक और कांसुली क्षेत्रों और संबद्व समझौतों में सहयोग के लिए चल रही चर्चाओं का जायजा लेने के लिए 17 नवंबर, 2014 को एफओसीएस के मौके पर आयोजित की गई थी।

'बेसल वर्ल्ड' में भारत की भागीदारी, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई द्वारा आयोजित की गयी थी। 27 मार्च से 03 अप्रैल 2014 को आयोजित समारोह में 50 से अधिक भारतीय निर्माताओं और हाईएंड आभूषण के निर्यातकों ने भाग लिया ।

27 मार्च से 10 अप्रैल 2014 – 1 मई इससे पहले 2014 में 21 पर परिणाम और ज्यूरिख में विदेशी (स्विस) निवेशकों के लिए भारतीय चुनाव की संभावनाओं पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, एसआईसीसी,ने विभिन्न शहरों में कई बैठकों का आयोजन 10 अप्रैल 2014 (मुंबई), से 11 अप्रैल 2014 (पुणे), 14 अप्रैल 2014 (नई दिल्ली), 23 अप्रैल 2014 (बंगलोर) और 24 अप्रैल 2014 (मंगलोर) को "यूरोप के लिए स्विट्जरलैंड–व्यापार के प्रवेश द्वार पर" किया। स्विट्जरलैंड वैश्विक उद्यम, विदेशों में स्विस फर्मों की सुविधा के लिए स्विस सरकार एजेंसी ने 'भारत के साथ कारोबार पर' एक कार्यशाला का आयोजन 24 जून, 2014 को ज्यूरिख में किया।

ज्यूरिख में 16 मई, 2014 को श्रीमती रूजाता सोमन के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा छह सदस्यीय कथक नृत्य मंडली का प्रायोजित कथक पर एक प्रदर्शन और व्याख्यान–प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

31 अक्टूबर –02 नवंबर 2014 को आयोजित ल्यूसर्न यात्रा एक्सपो 2014, में ''भारत–भारत'' एक गैस्ट विषय था जिसमें 'भारत पर्यटन, पेरिस की भागीदारी रही। कार्यशालाएं और भारतीय नृत्य, योग का प्रदर्शन, और भारतीय आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पाद, मसाले, वस्त्र, और भारतीय भोजन के स्टालों की एक्सपो में व्यवस्था की गई। लगभग 23,000 आगंतुकों ने भारतीय स्टालों का दौरा किया।

तुर्की

संबंधों जो मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हैं उन्हें सरकारी यात्राओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और सांस्कृतिक दलों के आदान–प्रदान के माध्यम से वर्ष के दौरानऔर सदृढ़ बनाया गया।

भारतीय उद्योग परिसंघ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, (सीआईआई), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और भारत पर्यटन ने इस्तांबुल का दौरा किया। इस्तांबुल के चैंबर्स ऑफ इंडिया फेडरेशन, तुर्की के व्यापारी परिसंघ के कारोबारियों और उद्योगपतियों (टीयूएसकेओएन) और एमओयूएसआईडी ने वर्ष के दौरान भारत का दौरा किया।

एक भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल एडीजी (सी एंड डब्ल्यू), मेजर जनरल शौकीन चौहान, के नेतृत्व में वाईएसएम, एसएमए वीएसएम और सिख रेजिमेंट से दो बैंड बजाने वालों ने 24–25 अप्रैल 2014 को गैलीपोली स्मरणोत्सव समारोह में भाग लिया।

श्री दिलीप पेरूलेकर, पर्यटन मंत्रीए गोवा ने 12 मई , 2014 को अपने रोड शो के लिए गोवा पर्यटन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को दोनों देशों में वाणिज्यिक आयोजनों में प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी के साथ आगे प्रोत्साहन मिला। 28 अगस्त से 2 सितम्बर 2014 के दौरान, इजमिर में 83 वें अंतरराष्ट्रीय मेले में भारत ने फोकस देश के रूप में भाग लिया। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने भारतीय उत्पादों की व्यापक रेंज का प्रदर्शन करते हुये मेले में भाग लिया।

"मेक इन इंडिया" अभियान व्यापक रूप से वाणिज्यिक स्थानीय चेम्बर्सए वाणिज्यिक संस्थानों और व्यापार समुदाय के साथ विचार विमर्श के माध्यम से प्रचारित किया गया था।

"स्वच्छ भारत" अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रतिज्ञा के साथ शुरु हुआ, यह कार्यक्रम मिशन द्वारा किया गया था।

आईटीईसी दिवस 5 नवंबर 2014 को मनाया गया था। इस आयोजन में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मामलों के मंत्रालय, विकास मंत्रालय के मंत्रालय और मिनरल रिसर्च मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत और तुर्की के बीच मध्य सत्र महानिदेशक स्तर विदेश कार्यालय परामर्श 28 नवम्बर 2014 को अंकारा में आयोजित किया गया।

सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान विविध सारणी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विदेश में पहली बार वटवृक्ष के प्रमुख सूफी और रहस्यवादी संगीत समारोह – 'रूहानियत' 17 मई 2014 को इस्तांबुल में आयोजित किया गया था।

राजदूत श्री पास्कल एलन नासरत की किताब के तुर्की संस्करण 'गांधी का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व' का प्रतिष्ठित केओसी विश्वविद्यालय में लोकार्पण किया गया था। यूनुस एम्रे फाउंडेशन से चार प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया में तुर्की भाषा पढ़ाने के लिए 3 सितंबर, 2014 को भारत आये।

यूरोपीय संघ

भारत और यूरोपीय संघ ने 2014 में अपनी सामरिक भागीदारी की 10 वीं वर्षगांठ मनाई। यूरोपीय संघ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और यूरोपीय संघ के साथ और उसके पूर्वगामियों के साथ संबंधों को आधे से अधिक सदी हो गयी है। जैसेकि यूरोपीय देशों का समूह एक आम मुद्रा से एक साझा बाजार और एक समुदाय से एक संघ के लिए बड़ा हो गया है, भारत के संबंध यूरोपीय संघ के साथ आनुपातिक रूप से सप्लीमेंट हो गये हैं, यूरोपीय संघ के व्यक्तिगत सदस्य राज्यों के साथ भारत के संबंध अनुपूरक हो गये हैं ।

शैक्षिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सतत प्राथमिकता रही है। जो रिश्ता अंतरस्थ था परिपक्वता के एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुँच गया है। 2013 को हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्वर्ण जयंती के रूप में चिह्नित किया गया है।

यूरोपीय संसद के चुनाव 22–25 मई 2014 को आयोजित किये गये। यूरोपीय पीपुल्स पार्टी (ईपीपी), चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी । नई यूरोपीय संसद ने श्री जीन क्लाड जंकर, लक्जमबर्ग के पूर्व प्रधानमंत्री को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। सुश्री फ़ेडेरिका मोगेरिनी ए इटली के पूर्व विदेश मंत्री को विदेश और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के नए उच्च प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया गया था। नए आयोग ने पांच साल की अवधि के लिए 1 नवंबर 2014 को कार्यभार ग्रहण किया।

यूरोपीयन परिषद ने श्री डोनाल्ड टस्कए पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री को यूरोपीय परिषद के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया । यूरोपीय संसद के चुनाव के बाद, भारत के साथ संबंधों के लिए एक नया प्रतिनिधिमंडल संसद में उनके संख्यात्मक शक्ति के अनुसार विभिन्न राजनीतिक समूहों से 43 सदस्यों से मिलकर गठित की गई है। नये प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष श्री है जेफ्री वान आर्डेन।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति श्री हरमन वान रम्पुये के साथ बैठक 14 नवंबर 2014 को ब्रिस्बेन में जी –20 शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय संबंधों के कायाकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

28 देशों के एक गुट के रूप में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदार है जबकि भारत 2013 में यूरोपीय संघ का 10 वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। (जनवरी–दिसंबर) 2013 के दौरान यूरोपीय संघ 28 के साथ (माल और सेवाओं दोनों में) 2013 में भारत का समग्र 966 विलियन € जबकि (द्विपक्षीय व्यापार माल € 72.70 विलियन और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार € 23.9बिलियन)। महत्वपूर्ण सेवाओं में व्यापार € 23.9 बिलियन था जिसमें 2012 की तुलना में जो 22.5 बिलियन था 2013 में जिसमें 6. 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 2013 में € 36.8 बिलियन था जबकि यूरोपीय संघ से भारत को आयात € 35.9 विलियन रहा ।

यूरोपीय संघ से भारत को 2013 में € 3.2 बिलियन के एफडीआई प्रवाह के साथ यूरोपीय संघ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सबसे बड़े स्रोतों में एक बना हुआ है। भारतीय संघ 28 में भारतीय निवेश् 2013 में € .4 बिलियन थे।

विकास सहयोग पर भारत–यूरोपीय संघ उप आयोग की पिछली बैठक 3 जून 2014 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार ने 30 अक्टूबर 2014 को अपने भारतीय समकक्षों से 2007 के बाद से वार्ताओं का जायजा लेने के लिए दिल्ली में मुलाकात की । भारत–यूरोपीय संघ मैक्रो आर्थिक वार्ता (एमईडी) और भारत–यूरोपीय संघ वित्तीय सेवा वार्ता (एफएसडी) की 7 वीं बैठक 4 जून 2014 को दिल्ली में की गयी। भारत–यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की पिछली बैठक 27 मार्च 2014 को ब्रसेल्स में आयोजित की गई थी । कोयले पर पिछला भारत–यूरोपीय संघ जेडब्ल्यूजी 10–11 सितंबर 2014 को जर्मनी में पॉट्सडैम में आयोजित किया गया है।

पर्यावरण पर संयुक्त कार्यदल की 8 वीं बैठक को 10–11 अप्रैल 2014 को ब्रसेल्स में भारतीय पक्ष की ओर से अपर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। रोजगार और सामाजिक नीति पर 7वें भारतीय–यूरोपीय संघ की संयुक्त संगोष्ठी 'कौशल विकास' पर दिल्ली में सितंबर 2014 को आयोजित की गयी थी। अगला भारत–यूरोपीय संघ सेमिनार 2015 में ब्रुसेल्स में आयोजित किया जाएगा। संगोष्ठी राष्ट्रीय खातों में गुणवत्ता मायने रखती है पर 2015 के कि भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भागीदारी देखा है जो भारत में 25–26 नवम्बर 2014 को आयोजित की गई थी।

अप्रसार और निरस्त्रीकरण वार्ता का पहला दौर 16 मई 2014 को नई

दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस वार्ता का अगला दौर 2015 में ब्रसेल्स में आयोजित किया जाएगा ।

पश्चिम यूरोप

अंडोरा

दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच पहले विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया। चर्चा 31 मार्च 2014 को एंडोरा में आयोजित की गई और दोनों पक्षों ने सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने राजनीतिक मामलों पर नियमित विचार–विमर्श जारी रखने और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए साधनों का पता लगाने के लिए पुष्टि की है।

बेल्जियम

भारत और बेल्जियम के बीच राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संबंधों में वर्ष के दौरान प्रगति दर्ज होना जारी रहा।

जनवरी–सितंबर 2014 के दौरानए बेल्जियम से भारत का आयात 6.52 बिलियन पर रहा था जबकि इसी अवधि में 2013 के दौरान 6.01 बिलियन रहा था, की तुलना में (8.5 प्रतिशत की वृद्धि)। बेल्जियम से भारत के आयात में मुख्य मद बेल्जियम से कुल आयात का 83.2 प्रतिशत बनता है जिसमें, बिना काम किये हीरे हैं।

प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं के दौरान भारत के बलिदान स्मरणोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास द्वारा बेल्जियम में विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उचित रूप से बेल्जियम के स्थानीय अधिकारियों और जनता के द्वारा मनाया गया जिसकी सराहना बेल्जियन स्थानीय प्रधिकारियों और पब्लिक द्वारा की गयी।

राज्य मंत्री (वीकेएस) ने 28 अक्टूबर 2014 को न्यूपूर्अ और य्रेस में बेल्जियम सरकार द्वारा आयोजित विश्व युद्ध 1 शताब्दी स्मरणोत्सव कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राज्यमंत्री (वीकेएस) ने यात्रा के दौरान बेल्जियम के विदेश मंत्री श्री डिडिएर रेनडर्स के साथ 27 अक्टूबर, 2014 को द्विपक्षीय बैठक की थी।इस दौरान उन्होंने बेल्जियन के राजा के साथ संक्षिप्त बातचीत की थी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग और नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 19 नवंबर, 2014 को एंटवर्प पोर्ट का दौरा किया और पत्तन प्राधिकरण के साथ बैठक की।

संयुक्त सेवा संस्थान, नई दिल्ली और फ़्लैंडर्स फील्ड्स संग्रहालय य्रेस में 24–25 अक्टूबर, 2014 के दौरान 'भारतीय और पश्चिमी मोर्चे' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। दूतावास ने 22 अक्टूबर 2014 को ब्रसेल्स में सशस्त्र बलों और सैन्य इतिहास के रॉयल संग्रहालय में विश्व युद्ध 1 के लिए भारतीय युद्ध योगदान पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

नगालैंड गायन के एक 15 सदस्यीय समूह ने ब्रसेल्स में 9 नवंबर 2014 को "शांति कॉन्सर्ट के लिए 1000 वॉयस" में प्रदर्शन किया और बेल्जियन के राजा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया जिसमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री हरमन वान रमप्ये उपस्थित रहे। उन्होंने 7 नवम्बर 2014 को सबलोन ;ब्रुसेल्स) में ऐतिहासिक नोट्रे डेम चर्च में भी प्रदर्शन दिया।

श्री पीटर डी क्रेम (विदेश व्यापार के लिए राज्य के सचिव) ने 13–18 जनवरी, 2015 1 को भारत का दौरा किया और 15 जनवरी 2015 को जहाजरानी मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी से मुलाकात की।

एयरो इंडिया बेंगलुरु में भाग लेने के लिए भारत के लिए रक्षा मंत्री की यात्रा 15–17 फ़रवरी 2015 को निर्धारित है

फ्रांस

भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंध पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं और दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट राजनीतिक समझ है। राष्ट्रपति श्री फ्रांसवां औलैंद की फ़रवरी 2013 में भारत के लिए यात्रा के बाद प्राप्त गति को मंत्रिस्तरीय यात्राओं और संस्थागत संवादों के माध्यम से 2014 में भी बनाए रखा गया है। मंत्रिस्तरीय यात्राओं के अलावा, दोनों देश आधिकारिक यात्राओं का नियमित आदान–प्रदान कर रहे थे।

श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री ने पेरिस में 11–12 जुलाई, 2014 को आयोजित 16वीं प्रमुख आर्थिक मंच आयोजन में भाग लिया। वह फिर से वियना कन्वेंशन के पक्षकारों के 10 वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21– 22 नवम्बर 2014 को और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए दलों की 26वीं बैठक में भाग लेने के लिए पेरिस के दौरे पर गये। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने सैलून इंटरनेशनल द लेग्रोआ लिमोन्ते यर (सियाल) 2014 में भाग लेने के लिए 18–21 अक्टूबर 2014 को पेरिस का दौरा किया ।

श्री लारेंट फेबियस, विदेश मामलों के लिए फ्रांसीसी मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास ने 30 जून से 1 जुलाई, 2014 को भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री से भेंट की और वित्त और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री, श्री ज्यां यवेस ली ड्रियान ने 1 दिसंबर 2014 को भारत का दौरा किया और श्री मनोहर परिकर, रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

एनएसए और फ्रांसीसी राजनयिक सलाहकार के बीच सामरिक वार्ता का 25वां दौर 30 जनवरी, 2014 को पेरिस में आयोजित किया गया। सामरिक वार्ता का 26वां दौर 09 अक्तूबर 2014 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आतंकवाद पर संयुक्त कार्य समूह की 9 वीं बैठक 20 जून 2014 को पेरिस में आयोजित की गई थी।

जनवरी–अक्टूबर 2014 के दौरान फ्रांस के साथ भारत के व्यापार में 7.68 प्रतिशत से वृद्धि हुई है जो 6.501 बिलियन यूरो की राशि

बनती है। इस अवधि के दौरान भारत के निर्यात में 14.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसकी राशि 4.285 बिलियन यूरो पहुंच गयी है। फ्रांस से आयात में 3.76 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है जिससे 2.215 बिलियन यूरो तक व्यापार हुआ जिसके परिणामस्वरूप व्यापार अधिशेष, 2.065 बिलियन यूरो तक रहा ।

फ्रांस भारत में मौजूद पहले से ही लगभग 750 बड़े फ्रांसीसी कंपनियों के साथ भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। 2012 तक फ्रांस 2.31 बिलियन के संचयी निवेश के साथ भारत में 9वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। फ्रांसीसी कंपनियों का अपने लाभ का विस्तार करने और जोखिम में विविधता लाने के क्रम में एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की ओर देखना जारी है । लगभग एक अरब यूरो के संचयी स्टॉक के साथ करीब 100 भारतीय कंपनियां फ्रांस में मौजूद शामिल हैं।

न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया लिमिटेड निगम और जैतापुर में ईपीआर परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयों के कार्यान्वयन के लिए अरेवा के बीच जनरल फ्रेमवर्क समझौते और शीघ्र कार्य समझौते के बाद दोनों पक्षों के बीच 2010 में हस्ताक्षर किए और उपरोक्त समझौतों के कार्यान्वयन के संबंध में 2014 में विचार विमर्श जारी रहा।

फ्रांस और भारत में एक दूसरे को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप देखते हैं। दोनों देश अंतरिक्ष में अपने उत्कृष्ट सहयोग की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2015 में संयुक्त स्मारक डाक टिकट लाने के लिए सहमत हो गए हैं। एक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा समझौते, एक उन्नत फ्रेंच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के तहत – स्पॉट–7 बोर्ड इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक 30 जून, 2014 को शुरू किया गया था । 7 दिसंबर 2014 को, भारत के उपग्रह जीसैट –16 का एरियान वाहन लांच –5 शुरू किया गया था।

दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं और बढ़ गये हैं। भारत–फ्रांसीसी वायु अभ्यास के पांचवें संस्करण, गरुड़ 02–13 जून 2014 को आयोजित किया गया था। 24–25 नवंबर 2014 को वार्षिक वायु सेना कर्मचारी वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और सहयोग पर सैन्य उप समितियों की वार्षिक बैठक को 26 नवम्बर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), ने 2014 में फ्रांस के लिए भारतीय कलाकारों की यात्राओं और संस्कृति और कला के क्षेत्र में छात्रों के आदान प्रदान को प्रायोजित भी किया।

दूतावास ने 2014 में अपने कार्यक्रम 'साहित्यिक कैफे' के तहत भारत और फ्रांस के प्रख्यात लेखकों के साथ जैसेकि जावेद अख्तर, पवन वर्मा, विकास स्वरूप, क्रिस्टोफ़ जेफरलॉट, लॉरेंट–एडिसिम दीक्षित, अलका पांडे, फ्रांसिसमोनियर, हेनरी प्रीवोस्ट–अलार्ड, स्वामी वीतमोहनंदा, सिद्वार्थ धनवंत संघवी, कातिया लीग्रेट मनोछाया, पूनम चावला, जियान जोसेफ बोइलोट, मोनीश गुजराल, जीन क्लाड पेरियर और शशि देशपांडे के साथ 22 पुस्तक रीडिंग, लोकार्पण और विचार विमर्श के आयोजन किये। इसके अलावा, दूतावास ने भी कोलंबिया विश्वविद्यालय और फ्रांसीसी राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ मिलकर भारतीय लेखकों पर एक 5 दिवस समारोह का आयोजन किया जिसमें 14 प्रख्यात भारतीय लेखकों को आमंत्रित किया गया। उधर, भारत–फ्रांस सहयोग से "ले कॉम्पतवार द लैंद के सहयोग के साथ दूतावास ने पेरिस में चौथे भारत पुस्तक मेले का आयोजन किया।

प्रदर्शन कला के क्षेत्र में, दूतावास ने 10 कार्यक्रमों, जैसे भारतीय डांस जैसे कि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक और संगीत के विभिन्न रूपों के गायकों / संगीतकारों के साथ आशा भोंसले, पंडित गोस्वामी, सुश्री स्मिता नागदेवी, सुश्री सुचेता गांगुली, श्री विनायक टोर्वी आदि के साथ, का आयोजन 2014 में किया। विभिन्न फिल्म समारोहों और संगठनों के सहयोग से 2014 में दूतावास में विभिन्न फिल्मों समारोहों में, कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित, भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई । बिटेल फिल्म महोत्सव में भारत 'ऑनर का देश' था, और भारत में नासिक फिल्म समारोह के साथ इसे जोड़ने का निर्णय लिया गया। स्थानीय भारत–फ्रांस सांस्कृतिक संगठनों के साथ–साथ दूतावास द्वारा योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दिया गया है। फ्रांस में व्यापक जनता तक पहुँचने के लिए, मिशन द्वारा नियमित रूप से "नुवेल द लैंद'' में आयुर्वेद पर लेख और योग का प्रकाशन किया गया है। शिकागो में धर्म की विश्व संसद (11 सितम्बर 1893) में स्वामी विवेकानंद के भाषण की सालगिरह की पूर्व संध्या पर स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का इंटरनेशनेल युनिवर्सिटी पेरिस के परिसर में 10 सितम्बर 2014 को अनावरण किया गया था।

शैक्षिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के क्रम में, दूतावास ने 2014 में लिए एक दर्जन से अधिक फ्रेंच स्कूलों और फ्रांस के लिए 16 भारतीय स्कूलों के छात्रों की पारस्परिक यात्राओं में मदद की है। आईसीसीआर के अध्यक्ष प्रो रजिनी पर्लीवाला ने सितंबर से दिसंबर 2014 के दौरान प्रतिष्ठित विज्ञान पो इन पेरिस एंड ल हार्वे में लिंग संबंधित मुद्दों पर पढ़ाया है।

भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय शैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग को 2014 के दौरान और मजबूत किया गया । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान समिति सीईएफआईपीआर, की तीसरे और चौथे बैठके अप्रैल 2014 में ब्रिटनी में आयोजित की गई और कोलकाता में नवम्बर 2014 में की गयी। पीएचडी के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए और संयुक्त रूप से डीएसटी और फ्रांसीसी दूतावास द्वारा वित्त पोषित पोस्ट डॉक्टर फैलोशिप छात्रों रमन चार्पक अप्रैल 2013 को सीईएफआईपीआर, में शुरू किया गया था। फैलोशिप छह महीने की अवधि के लिए 15 भारतीय पीएचडी छात्रों के फ्रांस जाने के लिए और फ्रेंच के लिए 15 छात्रों को भारत आने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए दिया जाता है। सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मामलों में द्विपक्षीय

प्रधान मंत्री ने 14 नवंबर, 2014 को ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, श्री हरमन वैन रोमपुए से मुलाकात की।

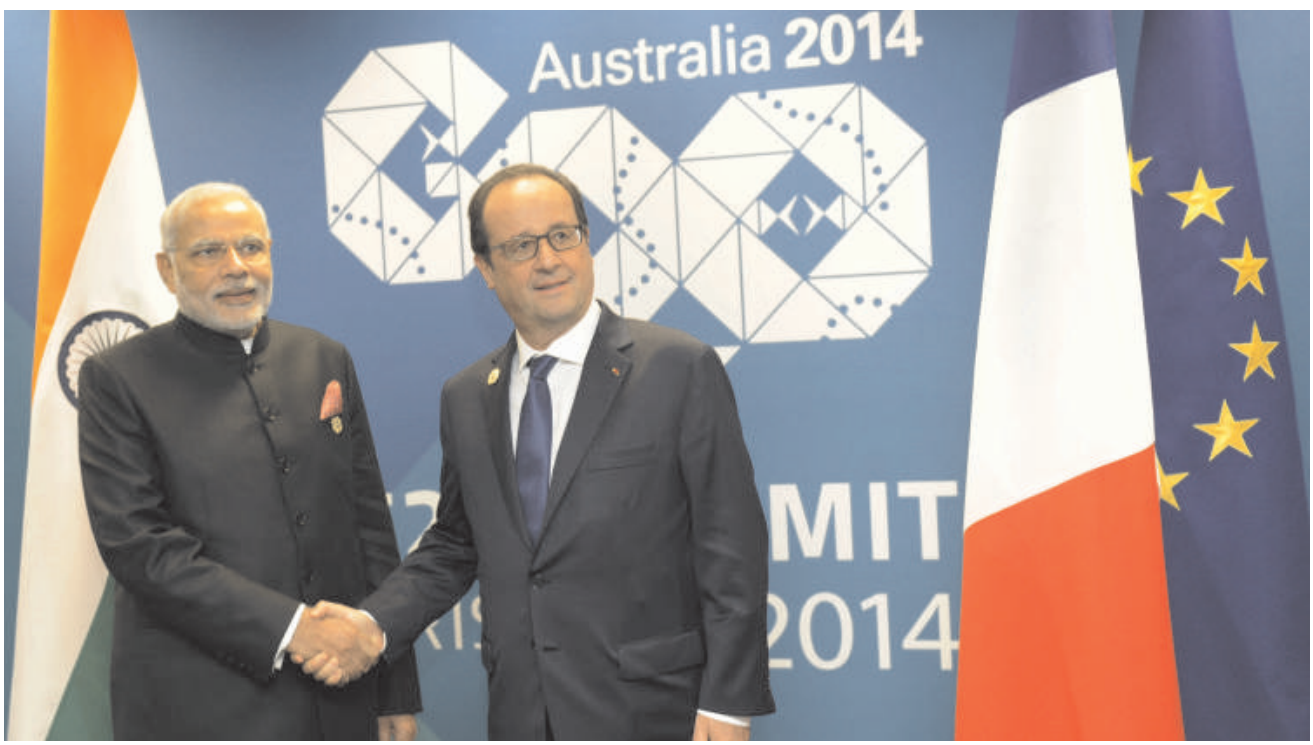

प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर, 2014 को ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया में जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांस्वा ओलौंद के साथ मुलाकात की

सहयोग पर चर्चा करने के लिए मदाम ऑन मारी देस्कोर, वैश्विक मामलों के महानिदेशक, विकास और भागीदारी, विदेश मंत्रालय के साथ 20 जनवरी 2014 को पेरिस में मुलाकात की।

24–25 नवम्बर 2014 को रेलवे मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने नई दिल्ली में 'उच्च और अर्ध उच्च गति, मल्टीमॉडल स्टेशनों, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग' पर इंडिया–फ्रेंच रेल संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

भारत पर्यटन कार्यालय, पेरिस के साथ समन्वय में मिशन ने 2014 में भारत पर्यटन कार्यालय में एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत को बढ़ावा देने का अपना काम जारी रखा। भारतीय पर्यटन कार्यालय, पेरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंच ट्रैवल मार्केट (आईएफटीएम) मेले, पेरिस में 23–26 सितम्बर 2014 को भाग लिया और उत्पादों का प्रदर्शन किया। भारत से 22 ट्रेवल और टूर ऑपरेटरों ने भाग लिया। टूर ऑपरेटरों के भारतीय संघ के साथ–साथ, भारत पर्यटन कार्यालय ने 16 से 18 सितंबर 2014 को मार्सिले, टूलूज़ और ल्योन में रोड शो आयोजित किये।

मिशन ने सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर और दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फ्रांस में भारतीय समुदाय समुदाय को आमंत्रित करके उनकी पहुंच बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। मिशन नियमित आधार पर समुदाय के साथ बातचीत भी कर रहा है।

रक्षा सहयोग के लिए भारत–फ्रांस उच्च समिति की 15 वीं बैठक 12–13 जनवरी 2015 को, पेरिस में आयोजित किया गया था । रक्षा उद्योग, प्रबंध, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर उप समिति की 16 वीं बैठक को 09–11 जनवरी, 2015 को पेरिस में आयोजित किया गया था ।

फ्रांस के विदेश मंत्री श्री आरेन फेबियस के 05–06 फरवरी 2015 को दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं। उनके विदेश मंत्री के साथ मिलने और प्रधानमंत्री से भेंट करने की संभावना है ।

आतंकवाद पर संयुक्त कार्य समूहः आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को बढ़ाने लिए आतंकवाद पर संयुक्त कार्य समूह की 10 वीं बैठक फरवरी के अंत 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

भारत–फ्रांस साइबर वार्ता का दूसरा दौर 16–17 फ़रवरी 2015 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है

जर्मनी

भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते संबंधों की गति को जारी रखा गया और आगे वर्ष के दौरान प्रगाढ़ता आयी है। दोनों पक्षों के नई सरकारों के कार्यभार संभालने के साथ ही दोनों देशों के नए नेतृत्व ने तत्काल संपर्क स्थापित किये हैं।

जर्मन विदेश मंत्री श्री फ्रैंक–वाल्टर स्टीन्मीयर ने 7–8 सितंब,र 2014 को एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया साथ ही कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, नदियों की सफाई, आदि पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक में अफगानिस्तानए इराकए ईरान और यूक्रेन सहित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। जर्मन एफएम ने शहरी मामलों के मंत्री श्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चांसलर सुश्री एंजेला मार्केल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक 16 नवंबर 2014 को ब्रिस्बेन में जी –20 शिखर सम्मेलन में की ।

प्रधानमंत्री के साथ एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल श्रीमती निर्मला सीतारमन, वाणिज्य राज्य मंत्री, का ब्राजील में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 13 जुलाई 2014 को बर्लिन में अपने रास्ते में एक रात का ठहराव था । चांसलर सुश्री एंजेला मार्केल ने 17 जुलाई 2014 को अपनी वापसी यात्रा के दौरान फ्रैंकफर्ट में अपने पारगमन पड़ाव के दौरान प्रधानमंत्री को एक टेलीफोन कॉल किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत दी।

प्रधानमंत्री ने फिर से 25–26 सितम्बर 2014 को फ्रैंकफर्ट के माध्यम से पारगमन और 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2014 को अपने रास्ते परए अमेरिका के लिए एक द्विपक्षीय यात्रा की और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद, संचार मंत्री ने एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ 15–19 सितंबर 2014 को जर्मनी का दौरा किया। उन्होंने जर्मन वाइस चांसलर और आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री श्री सिगमार गेब्रियल से मुलाकात की । यात्रा के दौरान " इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में अवसर और अभिनव " पर एक रोड शो ड्रेसडेन में, साथ ही म्यूनिख, बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में गोलमेज बैठकें आयोजित की गयी।

जर्मन विदेश कार्यालय के डा. मार्कस एडरर, राज्य सचिव ने 20 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

श्री राल्फ ब्रिनखउस, सीडीयू के एक सांसद की अध्यक्षता में एक नए भारत–जर्मनी संसदीय मैत्री समूह का गठन 18 बंडस्टेग में किया गया है। सांसदों की यात्राओं के आदान प्रदान ने पहले से ही वर्ष के दौरान रफ्तार पकड़ ली है।

पूर्वी एशिया पर बातचीत का दूसरा दौर नई दिल्ली में 7–8 अप्रैल 2014 को जर्मन विदेश कार्यालय में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक और संयुक्त सचिव (ईए), विदेश मंत्रालय के बीच आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुद्दे पर द्विपक्षीय परामर्श जर्मन विदेश कार्यालय में विशेष सचिव (आईओ और पोल) और संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मुद्दों के लिए महानिदेशक के बीच 18 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आतंकवाद

पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 15–16 मई 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

रक्षा क्षेत्र में, 7 वीं भारत–जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक 08–10 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जर्मन पक्ष की ओर से जर्मन रक्षा मंत्रालय में राज्य सचिव श्री वाल्फेंग ब्राउक्सिपे ने नेतृत्व में किया था। नेवल स्टाफ के मुख्य एडमिरल आर.के. धोवन 07–10 जुलाई, 2014 को जर्मनी की सरकारी यात्रा पर गये। द्विपक्षीय सैन्य समिति उप समूह (एमसीजी) की बैठक 10–13 नवंबर 2014 को जर्मनी में आयोजित की गई थी।

भारत हनोवर मेसी 2015 में भागीदार देश के रूप में भाग लेने के लिए जा रहा है जो अप्रैल 2015 में आयोजित किया जा रहा । हनोवर मेसी दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक मेला माना जाता है। भारत 2006 के कार्यक्रम में भागीदार देश था । 15–17 फ़रवरी 2015 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा ग्लोबल निवेश संवर्धन पर रि–इनवेस्ट 2015 बैठक और प्रदर्शनी में भागीदार के रूप में जर्मनी भाग लेगा ।

जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से पिछले कुछ वर्षों में मंदी पर रहा है। यह 2013 के दौरान यूरो 16.8 बिलियन आंका गया था। जनवरी–अक्टूबर 2014 में यह यूरो 13.44 बिलियन आंका गया था (भारत का निर्यात यूरो 06.00 बिलियन और आयात यूरो 07.44 बिलियन था)।

1991 से जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। 2013 में जर्मन एफडीआई यूएसडॉलर के दाम पर 1. 014 अरब था, और अवधि 1991–सितंबर 2014 के दौरान इसका संचयी एफडीआई यूएसडॉलर के दाम पर 7.57 बिलियन है। जर्मनी प्रौद्योगिकी ज्ञान के कई क्षेत्रों में भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत सरकार जर्मनी के साथ आर्थिक संबंधों के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए उत्सुक है, विशेष रूप से फसलोत्तर बुनियादी ढांचे, उच्च प्रौद्योगिकी, परिवहन बुनियादी सुविधाओं (रेल और बंदरगाहों सहित), व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, जल और अपशिष्ट प्रबंधन और और शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में ।

विकास सहयोग पर द्विपक्षीय परामर्श वर्ष में दो बार आयोजित हुआः पहले नई दिल्ली में मई 2014 को, उसके बाद 13–14 अक्टूबर 2014 को बॉन में । जर्मनी भारत में विभिन्न विकास सहयोग परियोजनाओं के लिए € 1.2 अरब के कुल कोष के आवंटन पर सहमत हो गया है । इन परियोजनाओं के प्रमुख क्षेत्रों में से कुछ हरित ऊर्जा कॉरिडोर, सौर संवर्धन परियोजनाओं, शहरी बुनियादी ढांचा विकास, कौशल विकास, गंगा सफाई और कृषि/खाद्य क्षेत्र में अभिनव शामिल हैं।

द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय बैठकें वर्ष के दौरान आयोजित की गई। मोटर वाहन क्षेत्र पर संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 30 सितंबर 2014 को हनोवर में आयोजित की गयी थी। व्यावसायिक शिक्षा पर संयुक्त कार्यकारी समूह की 7 वीं बैठक भारत में 9–10 अक्टूबर 2014 को आयोजित की गई थी।

2008 के द्विपक्षीय वायु सेवा की रूपरेखा पर सहमति पत्र जर्मन वाहक लुफ्थांसा द्वारा नवंबर 2014 में ए –380 विमान के प्रयोग को लागू करने के लिए संशोधन किया गया ।

श्री सिद्धार्थ बिड़ला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय फिक्की प्रतिनिधिमंडल ने 11– 13 नवंबर 2014 को बर्लिन का दौरा किया। उन्होंने जर्मन वित्त मंत्री डा वोल्फगैंग स्काबल से, आर्थिक और उर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, संघीय और विदेश कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और जर्मन उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 12 नवम्बर 2014 को 3वे भारत–जर्मनी व्यापार शिखर बैठक में भाग लिया।

इंडो–जर्मन सलाहकार समूह (आईजीसीजी) की 23 वीं बैठक में 18–20 सितंबर 2014 को एस्सेन, जर्मनी में आयोजित की गयी। आईजीसीजी भारत और जर्मनी के बीच टैक ।। संवाद के लिए एक मंच है जो सालाना मिलता है और द्विपक्षीय संबंधों के आगे मजबूत करने के लिए अपने विचार–विमर्श के आधार पर सिफारिशें करता है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) विभाग के संयुक्त सलाहकार समिति और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन (DFG) की बैठक 4 अप्रैल 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत–जर्मनी संयुक्त समिति की बैठक 20–21 नवम्बर को 2014 नई दिल्ली में आयोजित की गयी । इस अवधि के दौरान कई संस्थागत स्तर पर कई संगोष्ठियां और बातचीत की गयी।

उच्च शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 18–19 नवंबर 2014 को को नई दिल्ली में हुई।

आईसीसीआर ने वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय बर्लिन और मारबर्ग के फिलिप्स विश्वविद्यालय में दो अल्पकालिक फ्री स्थान परिचालनगत रखे। प्रो डा. अमिय पी सेन को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित हेनरिक ज़िम्मर चेयर के अगले अवलंबी के रूप में अक्टूबर 2014 से हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया संस्थान में नियुक्त किया गया था । भारत–जर्मनी के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में श्री रेनर हायरिग को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2014 का गिसेला बॉन पुरस्कार दे कर सम्मानित किया गया ।

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के छठे कोर ग्रुप की बैठक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग में 21–22 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में हुई। 70 से अधिक नीति–निर्माताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों, और व्यापार जगत के नेताओं ने इसमें भाग लिया। एनएसए श्री

अजीत डोवाल ने बैठक को संबोधित किया। यूरोप और एशिया में सुरक्षा आर्किटेक्चर पर ध्यान केंद्रित करते हुये चर्चाएँ की गयी।

जर्मन वित्त मंत्री डॉ वोल्फगैंग स्कबल 19–20 जनवरी 2015 को नई दिल्ली और मुंबई के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे । यात्रा के दौरान वोल्फगैंग स्कबल का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलना निर्धारित है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल जर्मनी के लिए यात्रा 06–08 फ़रवरी 2015 को म्यूनिख में आयोजित होने वाले 51 वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए निर्धारित है।

जर्मन सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल, श्री राल्फ ब्रिनखउस, जर्मन संसद में भारत–जर्मनी संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष के नेतृत्व में 10–19 फ़रवरी 2015 को, भारत की यात्रा पर आ रहा है।

पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और बिल्डिंग, परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन मंत्री डॉ बारबरा हेनड्रिक्स नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दूसरे इंडो–जर्मन पर्यावरण फोरम (आईजीईएफ) की बैठक में भाग लेने के लिए 27–29 जनवरी, 2015 को भारत के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। आईजीईएफ के दौरानए अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन पर दो कार्यसमूहों को सहयोग को मूर्त रूप देने के लिए स्थापित किया जाना तय है।

पर्यटन पर भारत–जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की 7 वीं बैठक 9 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में हुई। जर्मन पक्ष की ओर से नेतृत्व डॉ0 मैरियन वेबर, आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्रालय में पर्यटन नीति प्रभाग के प्रमुख ने किया था ।

उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने, मानकीकरण में सहयोग, अनुरूपता आकलन और उत्पाद सुरक्षा के लिए गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे पर भारत–जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की 2री बैठक में भाग लेने के लिए 14–16 पर जनवरी 2015 को बर्लिन का दौरा किया।

श्री फ्रांज जोसेफ मोलीटर के नेतृत्व में जर्मन संघीय स्वराष्ट्र मंत्रालय (बीएमआई) से एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल नागरिक सुरक्षा के लिए यूनिट के प्रमुख, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के लिए 21–23 जनवरी 2015 को भारत की यात्रा करेंगे।

श्री उवे बेकेमेयर, आर्थिक मामलों और ऊर्जा के जर्मन मंत्रालय में संसदीय राज्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल फ़रवरी 2015 को भारत का दौरा निर्धारित है। 13 फ़रवरी 2015 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडो–जर्मन ऊर्जा मंच (आईजीईएफ) की 6वीं बैठक में भाग लेंगे । जर्मन प्रतिनिधिमंडल 15–17 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में पहले अक्षय ऊर्जा वैश्विक निवेश संवर्धन मेले और प्रदर्शनी (फिर से निवेश) में भी भाग लेगा और इसमे जर्मनी एक भागीदार देश के रूप में भाग ले रहा है ।

जर्मन मंत्रालय में संसदीय राज्य सचिव श्री पीटर ब्लेसर, खाद्य एवं कृषि 12 फ़रवरी 2015 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कृषि पर 5वें इंडो–जर्मन संयुक्त कार्य समूह में भाग लेने के लिए भारत के लिए जर्मन कृषि कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

आयरलैंड

भारत और आयरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध अवधि के दौरान सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे।

जुलाई 2014 में कैबिनेट फेरबदल के बादए नव नियुक्त आयरिश राज्य मंत्री, शिक्षा और कौशल विभाग, कौशल और रोजगार विभाग, कौशल अनुसंधान और नवाचार के लिए विशेष जिम्मेदारी के साथ उद्यम और अभिनव विभाग ने एक एंटरप्राइज आयरलैंड व्यापार मिशन का नेतृत्व किया। मिशन के अंतर्गत सभी सात प्रमुख विश्वविद्यालयों सहित आयरलैंड के उच्च शिक्षा के पंद्रह संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान मंत्री ने साइंस गैलरी, बेंगलुरू, और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद एसजीआई और कर्नाटक सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये। नई दिल्ली में मंत्री ने आधिकारिक तौर पर क्लाउड कम्प्यूटिंग में परास्नातक कार्यक्रम के लिए आयरलैंड के नेशनल कॉलेज द्वारा पेशकश की 40 छात्रवृत्तियां शुरू की है और भारत में यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क कार्यालयों का उद्घाटन किया।

यूरोपीय मामलों और विशेष जिम्मेदारी के साथ तायोसीक(पीएम) विभाग और विदेश मामलों के आयरिश राज्य मंत्री, डेटा संरक्षण के लिए श्री दारा मर्फी मिलान ने राज्य मंत्री (वीकेएस) के साथ मुलाकात की, मिलान, इटली में एएसईएम 10 के अवसर पर, 16.17 अक्टूबर, 2014 को मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

द्विपक्षीय व्यापार का बढ़ना जारी रहा और 667 मिलियन पर पहुंच गया। दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक क्रम में न्याय और समानता मंत्री, श्री फ्रांसिस फिजराल्ड़ ने आगे के लिएए भारतीय पर्यटकों और व्यापार आगंतुकों को एक एकल वीजा पर आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच यात्रा करने की अनुमति की, 17 जून 2014 को नए 'ब्रिटिश आयरिश वीजा योजना' की घोषणा की। आयरलैंड में आईटी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों की बढ़ती संख्या ने दोनों देशों के बीच में बातचीत करने के लिए योगदान दिया है।

आयरिश कवि डब्ल्यू बी येट्स की 150 वीं वर्षगांठ पर, विदेश मंत्री, श्री चार्ली फ्लानागन ने भारत सरकार को स्व0 कवि की एक प्रतिमा भेंट की। प्रतिमा को किसी बड़े विश्वव्यापी समारोह में वर्ष के दौरान भारत में स्थापित किया जाएगा।

श्री बी एन सत्पथी, वरिष्ठ सलाहकार,के नेतृत्व में योजना आयोग से दो सदस्यीय टीम ने यूनिसेफ, यूरोस्टेट, ओईसीडी और ईएससीएपी

के एक संयुक्त प्रयास की पर दूसरी बैठक में 'सांख्यिकीय सूचना प्रणाली के प्रबंधन (एमएसआईएस 2014) में भाग लेने के लिए आयरलैंड (14.16 अप्रैल 2014) का दौरा किया। यात्रा के दौरान श्री बी एन सत्पथी ने आयरलैंड भारत व्यापार एसोसिएशन और दूतावास द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 'भारत में व्यापार के अवसर' पर अपना संबोधन भी दिया। औद्योगिक नीति और संवर्धन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभाग की ओर से एक दो सदस्यीय टीम ने डॉ मोहन चुटानी, आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में 'सेवा सांख्यिकी पर वूरबर्ग समूह' की 29 वीं बैठक में भाग लेने के लिए डबलिन (22.26 2014 अप्रैल) का दौरा किया ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित गाना बजानेवालों के समूह 'नागालैंड सिंगिंग अम्बेसडर्स' ने नवम्बर 2014 को डबलिन का दौरा किया और प्रतिष्ठित सेंट मैरी के समर्थक कैथेड्रल पर मध्य डबलिन में प्रदर्शन किया। आयरिश शिक्षा मंत्री सुश्री जेन ओ सुलिवान मुख्य अतिथि थे।

भारत पर्यटन कार्यालय, लंदन ने 24–25 जनवरी 2014 को डबलिन में वार्षिक पर्यटन प्रदर्शनी 'हॉलीडे व्लर्ड' में भाग लिया।

भारत पर्यटन कार्यालय, भारत सरकार और डबलिन में भारतीय दूतावास संयुक्त रूप से 21 जनवरी 2015 को डबलिन में "अतुल्य भारत" के बैनर तहत एक पर्यटन् शो का आयोजन कर रहा है।

यात्रा और पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों, प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं यात्रा लेखकों और सरकारी अधिकारियों सहित इसमें भाग लेने की उम्मीद कर रहे हैं।

रॉयल कॉलेज से एक दस सदस्यीय चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल, आयरलैंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था पर चर्चा के लिए 21–27 जनवरी 2015 को भारत का दौरा कर रहा है।

विदेश कार्यालय परामर्श का 6वां दौर (एफ ओ सी) 13 फ़रवरी, 2015 को डबलिन में आयोजित किया जाना तय किया जा रहा है। पिछला एफ ओ सी नई दिल्ली में 2009 में आयोजित किया गया था।

आयरिश संसद के विदेश मामलों और व्यापार (जेसीएफएटी) पर संयुक्त समिति की ओर से एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा फरवरी–मार्च 2015 को भारत का दौरा किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री पैटब्रीन, ललित गेल और सांसद और जेसीएफएटी के अध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा ।

इटली

एक सकारात्मक विकास एयर इंडिया द्वारा भारत (नई दिल्ली) और इटली (रोम और मिलान) के बीच सीधी उड़ानों के प्रारंभ के साथ 6 जून 2014 को हुई थी। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ाने दोनों देशों के बीच पर्यटकों और व्यापारियों के प्रवाह में वृद्धि की ओर अर्गसर होंगे।

2013–14 की अवधि के लिए द्विपक्षीय व्यापार यूएस डॉलर 9.4 विलियन डॉलर था जिसमें से इटली को निर्यात यूएस डॉलर 5.2 बिलियन और आयात यूएस डॉलर 4.2 बिलियन डॉलर था । वाणिज्यिक विंग सक्रिय रूप से भारत के लिए व्यापार यात्राओं की योजना के लिए इतालवी संगठनों और लोगों के व्यापार लिए प्रयास कर रहा है। इस साल के सितंबर में, एक प्रमुख इतालवी कंपनी डि मार से एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एक खोजपूर्ण यात्रा के लिए दिल्ली और मुंबई का दौरा किया। सामान्य प्रयास, भारत में व्यापार के अवसरों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने, इतालवी व्यवसायों को भारत में निवेश और निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने, दिनचर्या व्यापार करने और वाणिज्यिक और शिकायतों और विवादों की पूछताछ, बने हुये हैं।

डीआरडीओ प्रतिनिधियों सहित रक्षा प्रतिनिधिमंडलों ने इस साल नियमित बातचीत, स्वीकृति परीक्षणों और रक्षा उपकरणों और परियोजनाओं पर प्रशिक्षण के लिए इटली का दौरा किया। इटली संयुक्त उद्यम के जरिए भारत की निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्योगों संलग्न करने की मांग और रक्षा उपकरणों के निर्यात निर्यात करने का इच्छुक है, ये महसूस करते हुये कि ये न केवल रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के लिए एक बड़ा बाजार है बल्कि इसका एक भू राजनीतिक शक्ति के रूप में उद्भव है। रक्षा संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं।

दूतावास के सूचना एवं संस्कृति विंग को मजबूत बनाना और संस्कृतिए कला और शिक्षाविदों के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य के साथ कई स्थानीय सांस्कृतिक और योग संघोंए फिल्म समारोहों और विश्वविद्यालयों के आयोजकों तक पहुँचने के लिए बहुत सारे प्रयास किये हैं। यह रोम में ही नहीं लेकिन इटली के अन्य शहरों में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सफल हुये हैं। विंग ने सक्रिय रूप से बड़े प्रवासी भारतीयों के साथ सहयोग किया है और उनके समर्थन के साथ सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इतालवी शहरों पेस्तुमए ब्युसाईन और सिएना में आयोजित कार्यक्रमों की वजह से दूतावास और इटली में भारतीय समुदाय के बीच बढ़ते सहयोग ने फलदार बनाया है। 5 अक्टूबर 2014 को भारत के महावाणिज्य दूतावास, मिलान ने दूतावास परिसर में भारतीय शास्त्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम "नूर" का आयोजन किया और दशहरा और ईद–उल–ज़हा के त्योहारी सीजन अंकन के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत और सूफी भक्ति नृत्य का आयोजन किया गया।

24 अक्टूबर 2014 को रोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म 'हैदर' की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। फिल्म ने मोंडो जेन्रे (विश्व शैली) श्रेणी में "पीपुल्स च्वाइस अवार्ड' जीता । गांधी पर एक सम्मेलन 5 नवंबर 2014 को फेडेरिको द्वितीय, नपोली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का शीर्षक गांधी के संस्थागत सोच में व्यक्ति का अधिकार, विकास और धर्म' था, राजदूत द्वारा

एक व्याख्यान द्वारा शुभारंभ किया गया था ।

रोम में भारतीय दूतावास, तीन रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र संगठन में सक्रिय भूमिका निभाता है – खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और कृषि विकास के लिए इंटरनेशनल फंड (आईएफएडी)। एफएओ में भारत एफएओ परिषद और कार्यक्रम समिति का एक सदस्य है। इन समितियों की सदस्यता के माध्यम से, भारत ने महत्वपूर्ण रूप से एफएओ के कार्य एवं बजट कार्यक्रम को आकार देने के लिए योगदान दिया। जुलाई 2014 में भारत सर्वसम्मति से एफएओ के भीतर एशिया समूह के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। डब्लूएफपी में भारत कार्यकारी बोर्ड के एक सदस्य है और फरवरी 2014 में डब्ल्यूएफपी के कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो पर सूची 'बी' देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। आईएफएडी में भारतीय आईएफएडी कार्यकारी बोर्ड और इसके मूल्यांकन समिति के एक सदस्य होना जारी रहा। महानिदेशकए एफएओ ने इस साल अगस्त में भारत का दौरा किया और अन्य मंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री से मुलाकात की। आईएफएडी के प्रेजीडेंट ने भी जुलाई 2014 में भारत का दौरा किया और से वित्त मंत्री आर्थिक मामलों और कृषि विभाग के विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की।

लिश्तेंस्तेन

राजदूत ने 26 जून 2014 को वांडुज़ में अपने महल में एचएसएच प्रिंस एलॉयस, वंशानुगत राजकुमार ऑफ लिश्तेंस्तेन को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किया । यात्रा के दौरान और क्रेडेंशियल समारोह के बादए राजदूत वंशानुगत प्रिंस से मुलाकात की और विदेश मंत्री डा (सुश्री) औरेलिया फ्रिक से भी मिले।

लक्समबर्ग

भारत ने 27 नवंबर 2014 को (42 अन्य देशों के साथ) लक्ज़मबर्ग को इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण योजना के लिएसक्षम (टीवीओ, ईटीए के साथ सक्षम) किया। यह सक्षमता लक्ज़मबर्ग नागरिक को बिना भारतीय मिशन का दौरा किए ऑनलाइन भारतीय वीजा के लिए आवेदन और ऑनलाइन वीजा शुल्क का भुगतान करने के लिए सक्रिय करता है। वीजा की वैधता 30 दिनों के लिए है।

नीदरलैंड

भारत और नीदरलैंड ने बंदरगाहों, बुनियादी सुविधाओं, अंतर्देशीय जलमार्ग, कृषि, डेयरी, सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना जारी रखा। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक बने रहे हालांकि द्विपक्षीय व्यापार में इस अवधि में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। 2014 के पहले नौ महीनों के दौरान, नीदरलैंड के लिए भारत निर्यात में 34.46 प्रतिशत की कमी हुई जबकि हमारे कुल द्विपक्षीय व्यापार में 21.65 प्रतिशत की कमी हुई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भारत में नीदरलैंड से एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 2.27 बिलियन यूएसडॉलर थे। अप्रैल–सितंबर 2014 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 1,971 अरब यूएसडॉलर था। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के शीर्ष 20 व्यापारिक भागीदारों में नीदरलैंड 5 वां सबसे बड़ा देश बना रहा ।

2015 की पहली तिमाही में भारत के लिए डच प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए एक प्रस्ताव है।

भारत और नीदरलैंड के बीच अक्षय ऊर्जा सहयोग के लिए संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक हेग में 6 नवंबर 2014 को आयोजित की गयी थी।

11–13 जनवरी 2015 गांधी नगर, गुजरात में आयोजित 7 वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2015 में नीदरलैंड भागीदार देशों में से एक था । श्री साइमन स्मित, विदेश व्यापार के लिए उप मंत्री के नेतृत्व में एक 108 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

पुर्तगाल

पुर्तगाल और भारत का इतिहास और संस्कृति की समानताओं में और अंतर्राष्ट्रीय हित के कई मुद्दों पर एक आम दृष्टिकोण है। पुर्तगाल ने लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षा सहित बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन किया है।

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि से एक दल ने मार्च 2013 में हस्ताक्षर किए सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए) के आवेदन पत्र अनुमोदित करने के लिए और बातचीत करने के लिए 14–16 अप्रैल 2014 को पुर्तगाल का दौरा किया। एक बार दोनों देशों द्वारा अधिसूचित समझौते के नब्बे दिनों के भीतर लागू कर दिया जाएगा।

एक भारतीय कंपनी, आदित्य इंटरनेशनल, निवेश कार्यक्रम के तहत, तोमर की नगर पालिका में एक डिस्टिलरी और आउटलेट में 9,8 मिलियन यूरो का निवेश करेगी। एक अन्य भारतीय कंपनी, ज़ोमेटो ने अपने अभियान का शुभारंभ लिस्बन में किया।

2 अक्टूबर 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर छंपलीमॉड फाउंडेशन और राजस्थान सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जयपुर में एक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ राज्य के अत्याधुनिक कैंसर संस्थान की स्थापना करने के लिए।

पुर्तगाल में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मिशन द्वारा कई उपाय विकसित किये गये थे। दो छात्रों को विदेशों में हिंदी के संवर्धन के लिए, इस योजना के तहत आगरा के केन्द्रीय हिंदी संस्थान में अध्ययन करने के लिए, पुर्तगाल से चयन किया गया था । कला संकाय, लिस्बन विश्वविद्यालय में 30 सितंबर 2014 को दूतावास द्वारा हिंदी दिवस आयोजित किया गया था। लिस्बन विश्वविद्यालय हिंदी भाषा में एक मजबूत कोर्स है। इस अवसर पर दूतावास ने विश्वविद्यालय को हिन्दी साहित्य और भाषा पर पुस्तकों का एक

सेट प्रस्तुत किया। लिस्बन के विश्वविद्यालय के साथ सहयोग से जनवरी 2015 में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा।

सितंबर 2014 में भारत पर एक मासिक व्याख्यान श्रृंखला कला संकायए लिस्बन विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। वक्ताओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति से अंतरराष्ट्रीय मामलों को लेकर विविध विषयों पर ज्ञान साझा किया है।

25 सितंबर 2014 को लियोपोर्डो फिल्म्स ने दूतावास के सहयोग से श्री सत्यजीत रे की छह फीचर फिल्मों का पुर्तगाली सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया। । फिल्मों को 25 सितंबर 2014 से 5 नवंबर 2014 तक पोर्टो, ब्रागा, कोयमब्रा, सेतुबल और फिगुरिया डा फोज़ सहित पुर्तगाल के कई शहरों में दिखाया गया।

लिस्बन के विश्वविद्यालय के साथ सहयोग में भारतीय दूतावास जनवरी / फरवरी 2015 में भारतीय अध्ययन के लिए केंद्र का शुभारंभ करेंगे।

भारतीय दूतावास ने एआईसीईपी ;पुर्तगाल के निवेश और विदेशी व्यापार एजेंसी) के साथ सहयोग से मार्च 2015 में में एक व्यापार संगोष्ठी का आयोजन होगा।

द्विपक्षीय दौरे

- रानी मैक्सिमा (30 जून–3 जुलाई, 2014), वित्तीय समावेशन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमता में।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव (31 अगस्त – 2 सितम्बर 2014) के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल।
- डच मंत्री सुश्री लिलियने पाल्युमेन (5– 7 नवंबर, 2014) विदेश व्यापार और विकास सहयोग सड़क परिवहन, और
- (19 नवंबर 2014, राजमार्ग, जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी

मई–जून 2014 में हेग में आयोजित हॉकी विश्व कप 2014 में भारत ने भाग लिया। भारत ने इस प्रतियागिता में 9 वां स्थान प्राप्त किया।

भारत–नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में 11 जून 2014 को आयोजित किये गये। भारत की ओर से नेतृत्व श्री दिनकर खुल्लर द्वारा किया गया था, और डच पक्ष का नेतृत्व सुश्री रेनी जोन्स–बोस, महासचिव, डच एमएफ, सचिव (पश्चिम) में किया गया था ।

दूतावास ने भारत ने 13 जून 2014 को एक गोलमेज का आयोजन किया गया जिसमें व्यापार में पर्याप्त रुचि वाली चार प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया । ये चार प्रमुख कंपनियां हेनेकेन, रॉयल हेस्कनिंग, डीएचवी एफएमओ और एलन एंड ओवरी लॉ फर्म, एम्स्टर्डम थी।

हमारे शहरी विकास मंत्रालय और इंफ्रास्ट्रक्चर डच मंत्रालय और पर्यावरण के बीच पहली जेडब्ल्यूजी बैठकको 18–20 जून, 2014 को नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। जेडब्ल्यूजी के दौरान भारत की ओर शहरी नियोजन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए डच पक्ष के साथ और क्षेत्रीय योजनाए स्मार्ट सिटी के विकास, पीने का पानी, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट, ज्ञान और क्षमता निर्माण, रिवर फ्रंट विकास और बहुविध परिवहन के लिए फिर से विकास आदि पर उपयोगी विचार–विमर्श किया ।

दूतावास ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के साथ सहयोग से 23–24 जून 2014 को एम्स्टर्डम में एक परिधान क्रेता–विक्रेता से मिलने का आयोजन किया। यह पिछले 10 साल में नीदरलैंड में आयोजित पहला परिधान बीएसएम था। बीस भारतीय उत्पादकों और निर्माताओं ने बीएसएम में भाग लिया जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की शैलियों और डिजाइनों की एक विस्तृत रेंज को प्रदर्शित किया गया।

25 जून 2014 को एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था। 40 से अधिक चयनित कवियों, लेखकों और भारत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया । शाम को एक कविता सत्र का आयोजन किया गया।

5 जुलाई 2014 को आईसीसीआर प्रायोजित सांस्कृतिक मंडली गुजराती लोक नृत्य 'सप्तक' के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन गांधी सेंटर में किया गया था।

8 अक्टूबर 2014 को दूतावास ने 25 सितम्बर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा " मेक इन इंडिया" अभियान के शुभारंभ का व्यापक प्रचार करने के लिए और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की नीतिगत पहलों का प्रसार करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। लगभग 40 डच कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया।

दूतावास ने हेग में 17 अक्टूबर 2014 को डेयरी क्षेत्र में भारत–डच सहयोग पर एक आधा दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

एक इलैक्ट्रिक फॉल्क–फ्यूजन संगीत समूह ने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित '' पापों और ईस्ट इंडिया कंपनी'' श्री अंगर्ग महंत(पापों) के नेतृत्व में 28 अक्टूबर से – 2 नवंबर 2014 को नीदरलैंड का दौरा किया और एम्स्टर्डम, रॉटरडैम और हेग के शहरों में प्रदर्शन दिया।

सैन मैरिनो

भारत और सैन मैरिनो दोनों ने श्दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीटीए) और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (बीआईपीए) इस साल दोनों का अनुसमर्थन किया।

स्पेन

अवधि के दौरान भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे।

दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 28 मार्च 2014 को आयोजित किये गये थे । भारत और स्पेन ने विदेशी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष श्री करन सिंह 09.12 अप्रैल 2014 को स्पेन की सरकारी यात्रा पर आए। उन्होंने स्पेन के राजा से भेंट की और शिक्षा, संस्कृति और खेल के लिए स्पेनिश मंत्री के साथ बैठकें भी की । वाणिज्य सचिव 11.13 मई 2014 को स्पेन का दौरा किया और अपने समकक्ष के साथ वाणिज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बार्सिलोना में ग्लोबल टीबी संगोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2014 तक स्पेन का दौरा किया। उन्होंने स्पेनिश स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी बैठकें की। शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 17 से 19 नवंबर 2014 को बार्सिलोना में स्मार्ट सिटी वर्ल्ड कांग्रेस में भाग लिया।

स्पेन–इंडिया काउंसिल फाउंडेशन ने मई 2014 में तीसरे भारत नेता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन का विषय शिक्षा और शिक्षाविद था । फाउंडेशन ने 3–4 दिसंबर 2014 को स्थायी शहरों और परिवहन नेटवर्क पर पहले स्पेन–भारत फोरम का आयोजन किया। इस क्षेत्र में स्पेनिश और भारतीय दोनों कंपनियों से भाग लिया ।

2014 में भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार (जनवरी–अगस्त) 3.37 बिलियन डॉलर पर रहा था। दी गयी अवधि के दौरान भारत को स्पेन का निर्यात 1.0 बिलियन डॉलर पर रहा था और स्पेन के लिए भारत का निर्यात 2.36 बिलियन डॉलर पर रहा था। पिछले वर्ष की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार में 6.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष ने दूतावास द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, स्थानीय सरकारों और कासा ला भारत के सहयोग से आयोजित कई सांस्कृतिक गतिविधियों को देखा। प्रसिद्घ भरतनाट्यम डांसर श्रीमती अलार्म वल्ली ने इस वर्ष जनवरी में मैड्रिड और वलाडोल्डि में प्रदर्शन किया। दूतावास ने 04–08 जून 2014 को इंडिया एन कोंसिऐर्टो अपने द्विवार्षिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। श्री फकीरा खान के नेतृत्व में समूह द्वारा सुश्री रूजाता सोमन द्वारा मंगानीयार 'परंपरा और कथक' प्रदर्शन, स्पेनिश जिप्सी नृत्य के साथ प्राचीन भारतीय संगीत और नृत्य परंपराओं के संबंधों को उजागर करने की कोशिश की।

नवंबर 2014 में गायक मंडली समूह 'नगालैंड गायन अंबेस्डर' का और कोबेना में भारत और स्पेन से कलाकारों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय संगीत और जिप्सी नृत्य की स्पेनिश दर्शकों द्वारा भरपूर सराहना की गयी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, वलाडोलिड के सिटी काउंसिल और वलाडोलिड विश्वविद्यालय ने अगले पांच साल के लिए सांस्कृतिक सहयोग के लिए कासा डी ला भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत ए आर एंड पीए द्विवार्षिक आयोजन 2014 में अतिथि देश था। प्रतिष्ठित कला और विरासत की बहाली प्रबंधन महोत्सव के लिए भारतीय संस्थाओं से शैक्षिक विशेषज्ञों की मेजबानी जैसेकि आईजीएनसीए, इंटैक, अहमदाबाद नगर पालिका ने सक्रिय भाग लिया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के एक सांस्कृतिक दल ने भी आयोजन में भाग लिया।

वर्ष के दौरान स्पेन में भारत पर कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा साड़ी और कला और वास्तुकला पर एक अन्य प्रदर्शनी और आईजीएनसीए द्वारा भारतीय कथा परंपराओं को दिखाने वाली मास्क और कठपुतलियों पर एक प्रदर्शनी भी समाचारों में रही थी।

भारतीय विद्या संस्थान ने भी 01 अक्टूबर से10 दिसंबर 2014 तक भारत पर अपने शरद ऋतु पाठ्यक्रम को आयोजित किया। स्पेनिश में व्याख्यान श्रृंखला के लिए शीर्ष स्पेनिश विशेषज्ञों द्वारा किए गए जिसमें स्पेनिश लोगों और भारत के मित्रों ने उत्साह से भाग लिया।

28 जनवरी से 1 फरवरी 2014 तक के लिए आयोजित, मैड्रिड में दूतावास और पर्यटन कार्यालय पेरिस ने एफआइटीयूआर पर्यटन मेले में भाग लिया । पर्यटन कार्यालय पेरिस द्वारा स्थापित भारतीय मंडप में 18 सह–प्रदर्शक उपस्थित थे ।

29–31 जनवरी 2015 को स्पेनिश रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आएंगे। रक्षा क्षेत्र में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर वे रक्षा मंत्री के साथ वार्ता की जायेगी।

28 जनवरी – 1 फ़रवरी 2015 को पर्यटन मंत्रालय एफआइटीयूआर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले 2015 में भाग लेगा। संयुक्त आर्थिक परिषद 2 फ़रवरी 2015 को आयोजित होने वाली है।

यूनाइटेड किंगडम

दोनों पक्षों की वर्ष के दौरान उच्च स्तर की कई द्विपक्षीय यात्राएं और बातचीत हुयी हैं। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून के साथ एक–से–एक बैठक की और ऑस्ट्रेलिया में जी –20 के अवसर पर भी। विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय प्रवासीय भारतीय दिवस (आरपीबीडी) का उद्घाटन करने के लिए 16–17 अक्टूबर 2014 को ब्रिटेन का दौरा कियाय उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। राज्य मंत्री (वीकेएस) ने अफगानिस्तान पर लंदन सम्मेलन में भाग लेने 03–04 दिसम्बर 2014 से लंदन का दौरा किया। ब्रिटेन के रक्षा सचिव श्री माइकल फैलोन ने 28–29 अक्टूबर 2014 को भारत का दौरा किया । भारत की अपनी यात्रा के दौरान 25–27 अगस्त 2014 को ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री श्री निक क्लेग ने दिल्लीए मुंबई और बंगलौर का दौरा किया। उन्होंने 25 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री से भी भेंट की । यात्रा के दौरान उनके तीन ध्यान केंद्रित क्षेत्र, खुदरा, शिक्षा और एयरोस्पेस थे।

नई सरकार के आने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच पहला प्रमुख कार्य रहा जब ब्रिटेन के विदेश सचिव श्री विलियम हेग और चांसलर जॉर्ज ओसबोर्न ने संयुक्त रूप से 07–08 जुलाई 2014 को भारत का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठकें की। राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक मुद्दों और ब्रिटेन में भारतीय छात्रों से संबद्वऔर कौशल विकास से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श किया गया था ।

चांसलर और हमारे वित्त मंत्री ने आर्थिक और वित्तीय वार्ता के 7वें दौर (इएफडी) का आयोजन किया।

ब्रिटेन ने बंगलौर में एक नया तकनीक हब खोला जिसका लक्ष्य 3 साल में 1,000 बंगलौर स्र्टाट अप करना और उसे ब्रिटेन और दूसरे ब्रिटेन भारतीय व्यापार केंद्र के साथ जोड़ने जो ब्रिटेन के कारोबार के लिए सहायता प्रदान करेगा जो भारत में विकास करना चाहते हैं।

ब्रिटेन भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में है। आज की तारीख में ब्रिटेन भारत के शीर्ष 25 व्यापारिक भागीदारों की सूची में 17 वें स्थान पर है। वैश्विक आर्थिक मंदी और यूरो जोन संकट के बावजूद भारत–ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार लचीला बना हुआ है। वाणिज्य विभागए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2013–14 के दौरान दो–तरफा व्यापार यूएसडॉलर $15.82 बिलियन रहा जिसमें कि 2012–13 की तुलना में 6.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयास व्यापार में वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हैं।

भारत से ब्रिटेन को वस्तुओं का निर्यात लगभग 13.54 प्रतिशत बढ़ा है, 2012–13 में $8.61बिलियन से 2013–14 में $9.77 बिलियन और ब्रिटेन से आयात 3.94 प्रतिशत कम हुआ है जोकि 2012–13 में $6.29 बिलियन से 2013–2014 में की $6.04 बिलियन हो गया । भारत के वैश्विक व्यापार में ब्रिटेन के शेयर में भी सुधार हुआ है जो 2012–13 में 1.88 था 2013–14 में 2.7 प्रतिशत हो गया है।

आज ब्रिटेन मारीशस ओर सिंगापुर के बाद (अप्रैल 2000 से सितम्बर 2014 तक के लिए) अमेरिकी $21.60 बिलियन के संचयी इक्विटी निवेश के साथ तीसरा सबसे बड़ा आवक निवेशक है। ब्रिटेन जी –20 के बीच पहले स्थान पर है और अप्रैल 2000 सितम्बर 2014 के लिए भारत में अपने सभी निवेश का लगभग 9 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है।

2013–14 ब्रिटेन ने 3.2 बिलियन निवेश किया किसी भी अन्य जी –20 देश की तुलना में अधिक, जापान (1.7 अरब डॉलर) और अमेरिका (1 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम) ये क्रमः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं हैं।

2013–14 के वार्षिक रिपोर्ट आवक निवेश भारत में ब्रिटेन के व्यापार और निवेश द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2013–14 के दौरान यूनाइटेड किंगडम में 74 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं में 4,482 नौकरियों का सृजन किया था ।

ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपनी वार्षिक बिजनेस मिशन के हिस्से के रूप में, फिक्की का 22–25 जून 2014 के दौरान ब्रिटेन के लिए एक हाई प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल गया।

मिशन ने जहां ''भारत–ब्रिटेन आर्थिक भागीदारी बढ़ाना" पर एक गोलमेज चर्चा की मेजबानी की वहीं उच्चायुक्त ने श्री ग्रेगरी बार्कर सांसदए भारत के साथ व्यापार व्यवस्था के लिए पूर्व मंत्री का स्वागत किया । श्री. ग्रेगरी बार्कर, ने सूचित किया कि भारत ही दुनिया में एकमात्र देश रहा है जिसमें ब्रिटेन सरकार ने व्यापार व्यवस्था के लिए एक मंत्री नियुक्त किया है । यह भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर ब्रिटेन सरकार के सामरिक महत्व को दर्शाता है।

ग्लोबल इंडिया बिजनेस बैठक लिवरपूल सिटी के साथ मिलकर होरास द्वारा लिवरपूल में 22–23 जून 2014 को आयोजित की गयी थी । लिवरपूल में ग्लोबल इंडिया बिजनेस बैठक उद्यमशीलता और आर्थिक विकास को मनाने के लिए, व्यापार 2014 के इंटरनेशनल फेस्टिवल के उद्घाटन हिस्से के रूप में आयोजित की गयी थी ।

28 मई 2014 को भारत के उच्चायोग, लंदन ने वाणिज्य एवं उद्योग एशियन बिजनेस एसोसिएशन (एबीए) के लंदन चैंबर के सदस्यों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र की मेजबानी की।

2014 में भारत–ब्रिटेन आर्थिक द्विपक्षीय दौरे

भारत से ब्रिटेन के लिए

- श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री, भारत सरकार ने 17–18 नवम्बर 2014 के दौरान ब्रिटेन के लिए एक यात्रा की।
- वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, ने 27–28 अक्टूबर 2014 के दौरान एक निवेशक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए लंदन का दौरा किया।
- सचिव, विद्युत मंत्रालय, बिजली क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ तकनीकी सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 13–14 अक्टूबर 2014 को ब्रिटेन के लिए एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- श्री यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), ने 23 अप्रैल 2014 को निवेशकों और बैंकरों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र के लिए लंदन का दौरा किया।
- डॉ अरविंद मायाराम, पूर्व वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2014 को वित्तीय स्थिरता बोर्ड की पूर्ण बैठक (एफएसबी) में भाग लेने के लिए लंदन का दौरा किया।

ब्रिटेन से भारत

- सेनि0 माननीय मैथ्यू हैनकॉक, कौशल और उद्यम राज्य के पूर्व

मंत्री ने (16–17 जनवरी 2014) को प्रशिक्षण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और ब्रिटेन विशेषज्ञता में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए।

- सेनि0 माननीय ग्रेगरी बार्कर, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन विभाग में राज्य के पूर्व मंत्री और बिजनेस व्यवस्था के पूर्व मंत्री (05–10 फ़रवरी 2014)।
- सेनि0 माननीय ओलिवर लेटविन, सरकार की नीति के लिए मंत्री श्री रघुराम राजन ने, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक द्विपक्षीय बैठक के लिए 4 मार्च 2014 को मुंबई का दौरा किया।
- सेनि0 माननीय जॉर्ज ओसबोर्न, राजकोष के चांसलर (07–09 जुलाई 2014) आर्थिक और वित्तीय वार्ता (ईएफडी) के 7 वें दौर में भाग लेने के लिए।
- माननीय विलियम हेग, विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों (7–9 जुलाई 2014) के लिए पूर्व राज्य सचिव ।
- सेनि0 माननीय ओलिवर लेटविन, सरकार की नीति के लिए मंत्री, माननीय ग्रेगरी बार्कर, ऊर्जा विभाग में राज्य के पूर्व मंत्री और जलवायु परिवर्तन और भारत के साथ व्यापार व्यवस्था के लिए मंत्री श्री जो जॉनसन, डाउनिंग स्ट्रीट नीति यूनिट और सुश्री प्रीति पटेल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारतीय डायस्पोरा चैंपियन विदेश सचिव और चांसलर के साथ था ।
- सेनि0 माननीय एडवर्ड डेवी, राज्य सचिव ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन ने गुजरात ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ एक गोलमेज में भाग लेने के लिए 24–25 जुलाई 2014 के दौरान भारत का दौरा किया।
- सेनि0माननीय एडवर्ड डेवी ने दूसरी बार ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री के साथ 25–27 2014 अगस्त के दौरान भारत का दौरा किया।
- श्री शैलेश वारा, राज्य के संसदीय अवर सचिव अदालत और कानूनी सहायता मंत्री ने 1–3 सितंबर, 2014 के दौरान भारत का दौरा
- सर एडवर्ड लिस्टर, नीति और योजना के लिए लंदन के डिप्टी मेयर ने 10–14 सितंबर 2014 के दौरान भारत का दौरा किया।
- सुश्री एंड्रिया लीडसम, खजाने की आर्थिक सचिव ने औपचारिक रूप से ब्रिटेन–भारत वित्तीय सहभागिता का शुभारंभ करने के लिए, 10 अक्टूबर 2014 को भारत का दौरा किया।
- सेनि0 माननीय डॉ विंस केबल, व्यापार, अभिनव और कौशल के लिए राज्य के ब्रिटेन सचिव ने, शिक्षा, ऑटोमोटिव व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 10–15 अक्टूबर 2014 के दौरान दिल्ली, गोवा, पुणे और चेन्नई का दौरा किया।
- सेनि0 माननीय कार्वेन जोन्स, वेल्स के पहले मंत्री ने 28–30 अक्टूबर 2014 के दौरान भारत का दौरा किया । 2012 में भारत के लिए एक सफल यात्रा के बाद पहले मंत्री जोन्स ने वेल्स के प्रोफ़ाइल बढ़ाने के लिए दिल्ली और मुंबई में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- बरोनेस सुश्री संदीप वर्मा, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के लिए ब्रिटेन के राज्य के संसदीय अवर सचिव ने 12–15 नवंबर 2014 के दौरान जयपुर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- श्री ग्रेग क्लार्क, विश्वविद्यालयों, विज्ञान और यूनाइटेड किंगडम के शहरों के लिए मंत्री ने 13 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में हुई छठी भारत–ब्रिटेन शिक्षा फोरम के लिए भारत का दौरा किया। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, और श्री ग्रेग क्लार्को ने बैठक की अध्यक्षता की।
- 7वे वाइब्रेंट गुजरात, गांधी नगर में 11–13 जनवरी, 2015 को आयोजित शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन भागीदार देशों में से एक था। लार्ड इयान लिविंगस्टन, व्यापार और निवेश, अभिनव और कौशल विभाग के लिए ब्रिटेन के राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल, ने व्यापार के लिए 75 कंपनियों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक लंदन में 15–16 जनवरी 2015 को आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष की ओर से अपर सचिव (आईओ) और ब्रिटेन की ओर से नेतृत्व सारा मेकिनटोश, महानिदेशक, रक्षा और खुफिया ने किया।
- श्री अल्डरमैन एलन वायरो, लंदन सिटी के लॉर्ड मेयर ने, भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन के प्रयासों के हिस्से के रूप में 6–10 दिसंबर 2014 को भारत का दौरा किया।
- इंडिया जेटको 2015 की 10 वीं बैठक के लिए भारतीय परिसंघ के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के प्रतिनिधिमंडल के का नेतृत्व करते हुये वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 19 जनवरी 2015 को ब्रिटेन का दौरा किया और डॉ विंस केबल व्यापारए अभिनव और कौशल के लिए ब्रिटेन के राज्य सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक की ।
- सुश्री बैरोनेस डिसूजा, लॉर्ड स्पीकर, ब्रिटेन के हाउस आफ लॉर्ड्स का दौरा 16–17 फ़रवरी 2015 के लिए निर्धारित किया गया था।

वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून शिक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ विशेष संबंधों के विकास को महत्व देते हैं। लगभग 34 ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों ने भारत में कार्यालय खोला है और यहां तक कि चार महानगरों के अलावा भारत में छोटे शहरों से छात्रों से संपर्क कर रही हैं।

ब्रिटिश विश्वविद्यालयों ने उनके भारतीय समकक्षों के साथ सहयोग के स्तर में बृहद वृद्धि हुई है और नये लिंक एक नए रासायनिक जीव विज्ञान और भारत में चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना; तंत्रिका विज्ञान पर मेजर सहयोग; ऊर्जा, चिकित्सा, व्यापार और विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान भागीदारी, 2017 तक भारत में 15 मिलियन शिक्षकों के लिए अंगेजी भाषा प्रशिक्षण शामिल है ।

अप्रैल से नवंबर 2014 के दौरान डीआरडीओ और डीएसटीएल के बीच वैज्ञानिकों, कार्य समूह की बैठके, टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटरैक्टिव सत्र के आदान–प्रदान के आयोजन हुये हैं।

डीआरडीओ ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के साथ भी काम कर रहा है और सीबीआरएन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की (एमओयू फ़रवरी 2013 में हस्ताक्षर किए गए) पहले से ही भारत और ब्रिटेन द्वारा पहचान की गई है। दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार इस समझौते के तहत, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने 'प्रशिक्षक के लिए प्रशिक्षण' पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अक्टूबर 2014 में भारत का दौरा किया।

भारत–ब्रिटेन विज्ञान और नवाचार परिषद की चौथी बैठक 12 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में हुई।

बैठक के दौरान ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार नवाचार और कौशल विभाग, और न्यूटन के लिए भाभा कार्यक्रम (एक ब्रिटेन – भारत अनुसंधान और नवाचार भागीदारी) भारत सरकार के मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम सरकार के विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे ।

क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस (आरपीबीडी) का नौवां संस्करण 17–18 अक्टूबर 2014 को लंदन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के विदेश मंत्री द्वारा उद्घाटन के अवसर पर सामग्री और भागीदारी के स्तर के लिए ब्रिटेन में भारतीय डायस्पोरा के नेताओं द्वारा इसकी भरपूर सराहना की गयी थी। यह ब्रिटेन में बड़े पैमाने का पहला भारतीय डायस्पोरा कार्यक्रम था।

भारत–ब्रिटेन वित्तीय भागीदारी (आईयूएफपी)

भारत–ब्रिटेन वित्तीय भागीदारी (आईयूएफपी) का औपचारिक रूप से शुभारंभ श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री, भारत सरकार और श्री जॉर्ज ओसबोर्न, ब्रिटेन में राजकोष के चांसलर द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 7 वीं भारत–ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता, (एफईडी) के दौरान 8 जुलाई 2014 को किया गया था । आईयूएफपी, भारत और ब्रिटेन के बीच फाइनेंशियल सर्विसेज संबंध गहरा करने के लिए शुरू किया गया था। आईयूएफपी के उद्देश्यए विनियमन से उद्योग और प्रशिक्षण विकास से परस्पर शिक्षा प्रदान करना और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों और निष्पादन की पहचान करना है। श्री उदय कोटक, कार्यकारी वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा बैंक और सर जरमन ग्रिमस्टोन, स्टैंडर्ड लाइफ के अध्यक्ष और सिटी यूके जो ब्रिटेन आधारित वित्तीय और संबंधित पेशेवर सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं और आईयूएफपी के लिए सह–अध्यक्ष हैं। दोनों उद्योग नेता पेशेवरों समूहों के माध्यम से साझा हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच करेंगे जो प्रगति की रिपोर्ट देगें और अगले भारत–ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता 2015 में भारत के वित्त मंत्री और ब्रिटेन के लिए राजकोष के चांसलर कोए सिफारिशें भेजेंगे।

भारत–ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको)

10 वीं जेटको बैठक लंदन में 19 जनवरी 2015 को आयोजित हुई थी। श्रीमती निर्मला सीतारमन, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार और डा विंस केबल, व्यापार के लिए ब्रिटेन के राज्य सचिव, अभिनव और कौशल क्रमशः भारतीय और ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे। बैठकें सरकार और उद्योग दोनों "शिक्षा", 'तकनीकी सहयोग" और "स्मार्ट शहरों" पर संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में विचार विमर्श के लिए एक साथ होने की साक्षी होंगी। इन विचार–विमर्श के परिणामों को पूर्ण अधिवेशन में संबंधित कार्य समूहों के नेताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, व्यापार, नवाचार और कौशल के लिए ब्रिटेन के राज्य सचिव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जायेगी। जेटको की 10 वीं बैठक के पक्ष तर्ज पर स्मार्ट शहरों के लिए दो साइट का दौरा–मिल्टन कीन्स और विनिर्माण के लिए कैम्ब्रिज संस्थान, 20 जनवरी 2015 को जेटको प्रतिनिधिमंडल के लिए आयोजित किया गया है।

भारत–ब्रिटेन रक्षा सहयोग

दसवीं भारतीय वायु सेना–आरएएफ ईएसजी बैठक 03 फरवरी से 04 फरवरी 14 को एयर मुख्यालय (वीबी), नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । पिछले कार्यकारी संचालन समूह (ईएसजी) और रक्षा सलाहकार समूह (डीसीजी) की बैठकें दो साल के अंतराल के बाद 03–04 फरववरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 2015 के लिए अगली डीसीजी 11–12 फ़रवरी 2015 को लंदन में निर्धारित है। डीईएसजी बैठक 7–08 जनवरी 2015 को निर्धारित है।

अभ्यास कैम्ब्रियन गश्त 2014, 17–26 अक्टूबर 2014 को वेल्स में ब्रिटिश सेना द्वारा आयोजित किया गया था। कुल 119 टीमों ने इसमें भाग लिया जिसमें विदेशों से 19 टीमों ने इस गश्त में भाग लिया। 119 टीमों में से भारत सहित कुल मिलाकर केवल पांच टीमों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है।

एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2014, 11–13 दिसंबर 2014 को नौसेना अकादमी, एझिमाला, भारतीय नौसेना द्वारा केरल में आयोजित किया गया। रॉयल नेवी से तीन अधिकारियों ने इस आयोजन में भाग लिया और टीम ने कुल मिला के तीसरा स्थान प्राप्त किया।

■■

विदेश मंत्री 17 अक्तूबर, 2014 को लंदन में क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करते हुए। श्री फिल हेमंड भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं।

प्रधान मंत्री 14 नवंबर, 2014 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री श्री डेविड कैपरुन से मिलते हुए।

विदेश मंत्री 08 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली में यूनाइटेड किंगडम के विदेश तथा राष्ट्रमण्डल मामलों के विदेश मंत्री श्री विलियम हेग, एम पी से मुलाकात करते हुए।

फ्रांस के विदेश मंत्री श्री लारेंट फेबियस से नई दिल्ली में भेंट करते हुए विदेश मंत्री

8 अमेरिका

कनाडा

हाल के वर्षों में भारत–कनाडा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों के तहत उच्च स्तरीय बातचीत हुई है जिनमें राजनीतिक, सुरक्षा, व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री स्टीफन हार्पर ने वर्ष 2009 तथा 2012 की अल्पावधि में दो बार भारत की यात्रा की है; गर्वनर जनरल श्री डेविड जॉनसन ने फरवरी–मार्च 2014 में भारत की यात्रा की और प्रधान मंत्री श्री स्टीफन हार्पर ने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कनाडा आने का न्यौता दिया।

कनाडियाई प्रधान मंत्री की वर्ष 2012 में भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने रणनीतिक स्तर पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाकर और दोनों देशों के बीच परस्पर हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे– ऊर्जा सुरक्षा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, खनिज संसाधन; शिक्षा; अवसंरचना विकास और उन्नत नागरिक, रक्षा तथा आंतरिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मौजूदा महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाकर एक दूरगामी संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नियमित बैठकों के जरिए अपनी बातचीत को तेज करने और दोनों विदेश मंत्रियों के बीच वार्षिक रणनीतिक वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ता को मंत्रालय स्तरीय वार्ता में परिणत किया गया। प्रथम मंत्रालयस्तरीय ऊर्जा वार्ता दिसंबर 2013 में आयोजित की गई।

रणनीतिक वार्ता

भारत–कनाडा रणनीतिक वार्ता की दूसरी बैठक 13 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसकी सह–अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और उनके कनाडियाई समकक्ष श्री जॉन बॉयर्ड, विदेश मंत्री द्वारा की गई। दोनों पक्षों ने सम्पूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और साथ ही साझा हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। मंत्री श्री जॉन बर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री ऐड फास्ट ने संयुक्त रूप से प्रधान मंत्री से मुलाकात की।

रक्षा

मुख्य नौसेना स्टाफ एडमिरल आर के धवन ने कनाडियाई नौसेना प्रमुख द्वारा जनवरी 2014 में की गई कनाडा यात्रा के प्रतिउत्तर में 05–08 अगस्त, 2014 तक कनाडा की आधिकारिक सद्भावना यात्रा की। नौसेना स्टाफ प्रमुख ने विक्टोरिया, ओटावा तथा टोरंटो की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य कनाडा के साथ दोनों नौसेनाओं के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के अवसर तलाशना था।

परमाणु

परमाणु सहयोग करार जिस पर जून 2010 में हस्ताक्षर किए गए, को इसे लागू करने के बावत हमारी ओर से करार के लिए अपेक्षित आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लेने के बाद सितंबर 2013 में प्रचालित किया गया।

भारत–कनाडा परमाणु सहयोग करार पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 24 नवंबर, 2014 को ओटावा में आयोजित की गई। इस बैठक में परमाणु सहयोग करार तथा समुचित व्यवस्था प्रतिबद्धताएं, द्विपक्षीय उद्योग सहयोग की स्थिति के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय प्रचालनों पर चर्चा की गई। भारतीय शिष्टमंडल ने चॉक रिवर तथा डार्लिंग्टन परमाणु विद्युत स्टेशन में कनाडियाई परमाणु प्रयोगशालाओं का भी दौरा किया और टोरंटो में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की।

व्यापार तथा उद्योग

दोनों ओर से द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2012 तथा 2013 में क्रमशः 5.2 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था और जनवरी से अगस्त 2014 की अवधि के लिए यह 3.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था। स्टैटिस्टटिक्स कनाडा के अनुसार वर्ष 2013 में भारत से कनाडा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.7 बिलियन कनाडियाई डॉलर था जबकि भारत में कनाडियाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 613 मिलियन कनाडियाई डॉलर था। भारत और कनाडा द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर कार्य कर रहे हैं। सी ई पी ए की अंतिम दौर की बातचीत 11 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। तीन मुख्य मुद्दों वस्तुए सेवा तथा अस्थायी प्रवेश के लिए प्रमुख वार्ताकारों के बीच चर्चा हुई और इसके उपरांत दोनों

प्रधान मंत्री ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधान मंत्री श्री स्टीफेन हार्पर से मुलाकात करते हुए।

विदेश मंत्री और कनाडा के विदेश मंत्री श्री जॉन ब्रेड भारत–कनाडा रणनीतिक वार्ता के लिए नई दिल्ली में मुलाकात करते हुए।

पक्षों की ओर से मुख्य वार्ताकारों के बीच बैठक आयोजित की गई।

सस्काचेवन प्रांत के प्रीमियर श्री ब्रैड वॉल ने 17–23 नवंबर, 2014 तक भारत में व्यापार मिशन का नेतृत्व किया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मिशन में मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुजफ्फरनगर तथा चण्डीगढ़ में विराम शामिल थे। ऊर्जा, कृषि, खाद्य तथा नयाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए यह प्रीमियर श्री ब्रैड वॉल का भारत में दूसरा व्यापार मिशन था। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं कारोबार तथा निवेश पर बैठकें आयोजित करना, मुख्य भारतीय सरकारी तथा औद्योगिक नेताओं के साथ राष्ट्रीय तथा राज्य (गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा) स्तर पर बातचीत और परमाणु ऊर्जा आयोग तथा भारतीय दाल एवं अनाज संघ के साथ बैठकें शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री ऐड फास्ट, सुश्री केरी लिनडी फिन्डले, राष्ट्रीय राजस्व मंत्री और न्याय मंत्रालय के संसदीय सचिव, श्री बॉब डेकर्ड ने कनाडा–भारत व्यापार तथा निवेश भागीदारी को और मजबूत बनाने के लिए 12–17 अक्तूबर, 2014 तक कारोबार मिशन पर भारत के तीन शहरों की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान मंत्री श्री ऐड फास्ट ने श्रीमती निर्मला सीतारमन, वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्रीय श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्रीय श्री जितेन्द्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री; श्री वैंकेया नायडू, शहरी विकास मंत्रीय श्रीमती उमा भारती, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार मंत्रीय श्री धर्मेन्द्र प्रधान, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान कनाडियाई प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता का उपयोग करके गंगा नदी को साफ करने के लिए एक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में नवाचारी प्रौद्योगिकियों के विपणन के लिए कनाडियाई मेडिकल कंपनी नोवाडैक टेक्नोलॉजी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए और एक संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव मंगाए गए जिनसे द्विपक्षीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग और मजबूत होंगे।

ब्रिटिश कोलम्बिया के प्रीमियर सुश्री क्रिस्टी क्लार्क और उच्चतर शिक्षा मंत्री अमरीक विर्क ने 09–18 अक्तूबर, 2014 तक भारत में व्यापार मिशन का नेतृत्व किया। 70 से भी अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कारोबार मिशन के तहत भारतीय निवेशकों के साथ B2B बैठकें और सरकारी अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। इस यात्रा के दौरान ब्रिटिश कोलम्बिया और पंजाब की सरकारों ने घोषणा की कि वे उच्च स्तर शिक्षा, कौशल प्रमाणन, कृषि तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के क्षेत्रों में पंजाब तथा ब्रिटिश कोलम्बिया के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे; रिचमण्ड बेस्ड सिग्नल केम ने बेंगलोर में एक शोध एवं विकास सुविधा शुरू की जिससे कंपनी को जिसे कैंसर, ज्वलन रोग तथा केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी व्याधियों में विशेषज्ञता प्राप्त है, को अपने कैंसर से संबंधित खोजी गई औषधियों को उपयोग करने की अनुमति प्राप्त होगी; प्रधान मंत्री ने युनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली तथा चण्डीगढ़ में सनातन धर्म कॉलेज के बीच छात्रों के दोतरफा आदान–प्रदान को समर्थन तथा प्रोत्साहन देने के लिए कुल 50,000 अमरीकी डॉलर की लागत से 20 छात्रवृत्तियों के लिए वित्त पोषण की घोषणा की; आई सी–इम्पैक्ट्स ने जीएमआर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा रिलांयस इण्डस्ट्रिज के साथ दो करारों पर हस्ताक्षर की घोषणा की; साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी में भारतीय अध्ययन में एक विजिटिंग अध्ययेता कार्यक्रम शुरू करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी और इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने हाइड्रोजन तथा फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी अनुसंधान में सहयोग करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय महाकोंसुलावास, टोरंटो ने 30 अक्तूबर, 2014 को ''मेक इन इंडिया'' पहल पर एक विशेष वार्ता सत्र का आयोजन किया जिसमें कनाडियाई कंपनियों के प्रेसिडेंट तथा सी ई ओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमुखों तथा महत्वपूर्ण कारोबारी अगुवाइयों ने हिस्सा लिया। ''मेक इन इंडिया'' पहल पर एक संक्षिप्त परिचय के बाद कुछ उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों जिनमें प्रत्यक्ष निवेश नीति तथा इन क्षेत्रों में निवेश अवसर शामिल हैं, क्षेत्रों के बारे में पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। भारत सरकार के कारोबार पोर्टल www.business.gov.in जो अंतिम उपयोगता की कारोबार से जुड़ी जानकारी से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है, की भी शुरुआत की गई।

गुजरात सरकार से एक 15 सदस्यीय शिष्टमंडल जिनमें उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ने 11–13 जनवरी, 2015 तक गांधीनगर में आयोजित किया जाने वाला सातवां जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन, 2015 को बढ़ावा देने के लिए 01–04 सितंबर, 2014 तक मॉट्रियल तथा टोरंटो की यात्रा की। जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन संबंधी सत्र के अलावा वित्तीय सेवाओं, तेल एवं गैस, खनन, जीव विज्ञान, कृषि खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा, ऑटोमोटिव एवं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कारोबार तथा व्यापार के अवसर तलाशने के लिए कारोबार नेटवर्किंग सत्रों का भी आयोजन किया गया। बोर्ड ऑफ थ्रेड ऑफ मेट्रोपोलिटन, मॉट्रियल ने मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, इनोवेशन एण्ड एक्सपोर्टेशन, क्यूबेक सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मॉट्रियल में जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन पर एक प्रस्तुति दी गई जिसके बाद B2B बैठकें आयोजित की गईं।

गुजरात लघु तथा मझौले उद्यम से एक ट्रेड मिशन ने आमने–सामने व्यापार बैठकें आयोजित करके और स्थानीय चैम्बर्स तथा प्रांतीय प्राधिकारियों द्वारा आयोजित नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेकर कनाडा में व्यापार सहभागियों का पता लगाने के लिए 07–15 जून, 2014 तक टोरंटो, वाटरलू, मॉट्रियल तथा ओटावा की यात्रा की।

उद्योग क्षेत्रों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी तथा शिक्षा जैसे विषय पर ध्यान दिया गया।

परिवहन

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय से एक चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह की बैठक में शामिल होने के लिए 10–14 सितंबर, 2014 तक टोरंटो की यात्रा की। संयुक्त कार्य समूह का गठन परिवहन क्षेत्र में सहयोग करने तथा विशेषज्ञों के आदान–प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप किया गया।

खनन

खान मंत्रालय से एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने खानों को बंद करने संबंधी उपायों, पुनरुद्धार तथा पुनर्वास प्रक्रिया से संबंधित क्षमता निर्माण के प्रयोजनार्थ 27 सितंबर, 2014 से 04 अक्तूबर, 2014 तक सैडबरी, ओन्टारियो की यात्रा की। यह यात्रा भारत और ओन्टारियो के बीच संयुक्त कार्य समूह की सातवीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में थी। मिनरल टिन्योर, पेटेंट रहित खानों पर दावा, खानों के दावे को पट्टे पर देना, खान पट्टे का नवीकरण जैसे विषयों पर ओन्टारियो सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुति दी गई।

कृषि

पंजाब सरकार में कृषि तथा एन आर आई मामले मामले मंत्री सरदार जथेदार तोता सिंह ने सस्ताचेवन ऐग–वेस्ट बायो, सस्काचेवान बायोसाइंस इण्डस्ट्री एसोसिएशन की मेजबानी में कृषि जैव–विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 05–09 अक्तूबर, 2014 तक सस्कातून की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान पंजाब सरकार और इनोवेशन सस्काचेवान के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें जल सुरक्षा, दाल एवं अन्य फसलों से संबंधित संयुक्त मूल्य संवर्धन कार्यक्रम और पंजाब में सस्काचेवान विकसित जल संशोधन और अपशिष्ट जल संशोधन प्रौद्योगिकियों की जांच संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना के लिए संयुक्त उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करने की मांग की गई है।

श्री जेरी रिट्ज, कृषि तथा कृषि खाद्य मंत्री,कनाडा ने 22–24 सितंबर, 2014 तक नई दिल्ली की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्री राधा मोहन सिंह, कृषि मंत्री, श्रीमती निर्मला शांताराम, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और श्री रामविलास पासवान, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा जनवितरण मंत्री से मुलाकात की। कृषि क्षेत्र में सहयोग के अलावा श्री जेरी रिट्ज द्वारा भारतीय अधिकारियों के साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा कैनोला तेल के प्रोपाइटरी संबंधी मुद्दे पर भी चर्चा की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स (आईसीटीई) पर दूसरे भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) (की बैठक) 14 नवंबर, 2014 को टोरंटो में हुई थी। इस बैठक में आईसीटी सेक्टर में उन्नयन/इनोवेशन तथा उष्मायन/इनक्यूबेशन, अनुसंधान एवं विकास सहयोग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भागीदारी पर चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इंडस्ट्री कनाडा और इनवेस्ट कनाडा के अधिकारियों के साथ बैठक के लिए ओटावा का भी दौरा किया। कनाडा में भारतीय आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ यह प्रतिनिधिमंडल सिटीजनशीप एण्ड इमीग्रेशन कनाडा और इंप्लायमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिला और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों के लिए वीजा के मुद्दे पर चर्चा की।

डॉ. के राधाकृष्णनन, अध्यक्ष, इसरो और सचिव, अंतरिक्ष विभाग की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 सितंबर–4 अक्तूबर, 2014 के दौरान टोरंटो में 65वें अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनाटिकल कांग्रेस में भाग लिया। डॉ. के राधाकृष्णनन को इस कांग्रेस में इंटरनेशनल एस्ट्रोनाटिकल फेडरेशन द्वारा एलान डी ईमिल मेमोरियल एवार्ड दिया गया। एलान डी ईमिल मेमोरियल एवार्ड सबसे प्रतिष्ठित आईएएफ पुरस्कारों में से एक है और यह अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष चिकित्सा और अंतरिक्ष कानून के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए वर्ष 1977 से ही प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

कोंसुली

श्री कृश एलेग्जेंडर, नागरिकता तथा आप्रवासन मंत्री ने 5–10 जुलाई, 2014 के दौरान भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, और गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह से मिले। उन्होंने भारत में कैन+ कार्यक्रम की शुरूआत की जिसके परिणामस्वरूप कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए कार्यवाही ज्यादा प्रभावी ढंग से होगी और इससे अप्रवासियों का आगमन तथा एकीकरण सुविधाजनक तरीके से होगा।

संस्कृति और विरासत

कनाडा विरासत, कनाडा सरकार ने भारत और कनाडा के बीच श्रव्य–दृश्य सह–उत्पादन करार को 1 जुलाई, 2014 से लागू किए जाने की घोषणा की जिसपर फरवरी/मार्च 2014 में गवर्नर जनरल श्री डेविड जान्सटन की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार दोनों देशों के प्रोड्यूशरों को दृश्य–श्रव्य सह–उत्पादन करने के लिए अपने रचनात्मक, तकनीकी और वित्तीय संशाधनों को मिलाने की अनुमति प्रदान करेगा।

श्री विमल जुलका, सचिव ने 6–8 सितंबर, 2014 के दौरान टोरंटो

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2014 में भाग लेने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। सचिव (सू.एवं. प्रसा.) ने टेलीफिल्म कनाडा, नेशनल फिल्म बोर्ड आफ कनाडा, ओंटारियो मीडिया विकास सहयोग के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लिया और कनाडा भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सचिव (सू.एवं प्रसा.) के दौरे की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में टेलीफिल्म कनाडा, ओंटारियों मीडिया विकास सहयोग (ओएमसीडी) ने 20–24 नवंबर, 2014 के दौरान 8वें फिल्म बाजार के साथ–साथ गोवा में आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत में कनाडा के 14 प्रोड्यूशरों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। इस दौरे से भारतीय फिल्म उद्योग के साथ व्यापार संबंध विकसित करने और सह–उत्पादन के लिए एक प्रमुख प्लेयर/कर्ता और प्रमुख भागीदार के रूप में कनाडा को प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी।

सुश्री रिचा जैन के नेतृत्व में आईसीसीआर प्रायोजित एक कत्थक समूह ने 15–20 सितंबर, 2014 के दौरान कनाडा की यात्रा की। इस दल ने ओटावा, टोरंटॉ और सडबरी में मंचन किया। ओटावा में प्रदर्शन/कार्यक्रम राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया जिसमें काफी लोग आए।

अमेरिका

वर्ष 2014 में अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी में मात्रात्मक बढ़ोत्तरी हुई। मई 2014 में भारत में आम चुनावों के बाद से और भारत–अमेरिका रणनीतिक वार्ता के 5वें दौर के लिए जुलाई, 2014 में विदेश मंत्री श्री जान केरी और वाणिज्य मंत्री सुश्री पेनी पिट्ज्कर की यात्राओं सहित अगस्त 2014 में अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री चक हेगल ने यात्रा की। इसके कारण 26–30 सितंबर, 2014 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अमरीका यात्रा हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के निमंत्रण पर दोनों नेताओं के बीच पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयार्क की यात्रा के दौरान हुआ। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए और अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 24 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2014 के दौरान अमेरिका की यात्रा की।

अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत श्री मिशेल फ्रोमैन ने वाणिज्य तथा उद्योग राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के साथ मंत्रीस्तरीय व्यापार नीति की सहअध्यक्षता के लिए 24–25 नवंबर, 2014 के दौरान भारत की यात्रा की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 25–28 जून, 2014 के दौरान अमेरिका गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

अप्रैल, 2014 से (अबतक) भारत की यात्रा पर आए अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों में शामिल हैं–2–3 जुलाई, 2014 के दौरान सिनेटर जॉन मैकेन (रिपब्लिकन–अरिजोना); 18–19 अगस्त, 2014 के दौरान रिप्रजेन्टेटिव स्टीव चाबोट (रिपब्लिकन–ओहियो), और रिप्रजेन्टेटिव श्री ल्यूक मेसर (रिपब्लिकन–इंडियाना); 25–26 अगस्त, 2014 को रिप्रजेन्टेटिव श्री आरोन स्कोक (रिपब्लिकन–इलीन्वास); 7–10 अक्तूबर, 2014 के दौरान सिनेटर श्री टिमोथी केन (डेमोक्रेट–वर्जीनिया) और सिनेटर श्री अंगुस किंग (स्वतंत्र–मेन) और 16 दिसंबर, 2014 से 4 जनवरी, 2014 के दौरान कांग्रेसवोमन सुश्री तुलसी गबार्ड (डेमोक्रेट–हवाई)। दक्षिण कारोलिना के गवर्नर श्री निक्की हाले ने 13–22 नवंबर, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने 26 जनवरी, 2015 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने के लिए भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के सम्मानित अतिथि बनने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। यह इतिहास में पहली बार है कि महज चार महीनों की अवधि में दोनों देशों के बीच दो शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठकें हुईं।

प्रधानमंत्री का अमरीका दौरा

26–30 सितंबर, 2014 के दौरान प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा भारत–अमेरिका रणनीतिक भागीदारी के लिए एक सकारात्मक रुख स्थापित करने के मामले में परिवर्तनकारी प्रकृति का था और यह भविष्यदृष्टा तथा महत्वाकांक्षी भी था। प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के साथ सारणी अनुसार और प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताओं के लिए मिले, साथ ही एक निजी डिनर के साथ–साथ मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल के संयुक्त दौरे के दौरान भी मिले। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के साथ भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के अपने दृष्टिकोण को साझा किया और इस बदलाव के लिए दृढ़ता में तेजी लाने और विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग हेतु संभावनाओं की तलाश करने के बारे में बताया। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर और विकासशील देशों में सहयोग के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की संभावनाओं की भी तलाश की।

न्यूयार्क और वाशिंगटन डीसी में 30 से अधिक आधिकारिक संपर्कों में प्रधानमंत्री सफलतापूर्वक सभी प्रमुख अमरीकी साझेदारों तक पहुंचने में कामयाब रहे जिसमें अमरीकी प्रशासन कारपोरेट अमरीका, अमरीकी कांग्रेस और 3 मिलियन मजबूत भारतीय–अमरीकी समुदाय शामिल थे। यह दौरा भारत की विकासात्मक जरूरतों, वैश्विक आकांक्षाओं के पीछे सुदृढ़ भारत–अमेरिकी भागीदारी जोड़ने में कामयाब रहा और इसने स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं सहित सरकार की प्राथमिकता वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों में ठोस

प्रधान मंत्री 25 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, श्री बराक ओबामा से मुलाकात करते हुए।

विदेश मंत्री 31 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री, श्री जॉन कैरी से मुलाकात करते हुए।

परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित किया। यह दौरा उच्च प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, आतंकवाद–विरोध और रक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं की पुनः पुष्टि करने में भी सफल रहा। प्रधानमंत्री के अमरीकी दौरे के दौरान 'चलें साथ–साथ' फारवर्ड टूगेदर वी गो' के विषय पर एक दृष्टिकोण वक्तव्य और इस दृष्टिकोण को साकार रूप देने के ठोस तरीकों को प्रदर्शित करने वाला एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर और अमरीकी राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से दो ओप–एड्स का लेखन भी किया। 30 सितंबर, 2014 को अमरीकी सीनेट द्वारा भारत–अमेरिका मैत्री दिवस के रूप में निर्दिष्ट किया गया।

अमरीका चार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं नामतः परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), वास्सेनार व्यवस्था और आस्ट्रेलिया समूह में भारत के चरणबद्ध प्रवेश के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एमटीसीआर अपेक्षाओं को पूरा करता है और भारत एनएसजी में सदस्यता के लिए तैयार है। उन्होंने भारत की स्थाई सदस्यता वाले संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की। अमेरिका ने भारत के जोरदार आवाज और आईएमएफ तथा विश्वबैंक में मतदान को समर्थन देने का वायदा किया। दोनों पक्षों ने कृषि उत्पादकता, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और आपदा तैयारी सहित अनेक क्षेत्रों में विकासशील देशों में संयुक्त विकासात्मक पहलों की संभावनाएं तलाश करने संबंधी एक नए करार की घोषणा की। इसके बाद वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शी सिद्धांतों संबंधी भारत–अमरीकी वक्तव्य पर नई दिल्ली में 3 नवंबर, 2014 को हस्ताक्षर किया गया।

रणनीतिक वार्ता

उप–विदेश मंत्री श्री विलियम बर्न ने भारत–अमरीकी रणनीतिक वार्ता की तैयारी के संबंध में 9–11 जुलाई 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। भारत–अमरीकी 5वीं रणनीतिक वार्ता 31 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारतीय पक्ष के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और विदेश मंत्री श्री जॉन केरी ने अमरीकी पक्ष के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य मंत्री सुश्री पेनी प्रिट्जकर, होमलैंड सुरक्षा विभाग के अवर सचिव श्री फ्रांसिस एक्स टेलर, और विदेश विभाग में जलवायु परिवर्तन के विशेष अमरीकी राजदूत श्री टोड स्टर्न के साथ–साथ अन्य लोग शामिल थे। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक वार्ता पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग

भारत में अमरीकी राजदूत सुश्री नैन्सी पावेल सेवानिवृत्ति के पश्चात 22 मई, 2014 को भारत से चली गईं। यूएस सीडी, राजदूत (सेवानिवृत्त) डोरिस कथलीन स्टीफेंस 5 जून, 2014 को नई दिल्ली आईं। 18 सितंबर, 2014 को अमरीकी राष्ट्रपति ने श्री रिचर्ड राहुल वर्मा को भारत का नया राजदूत नामित किया। उनकी नियुक्ति की 9 दिसंबर, 2014 को अमरीकी सीनेट द्वारा पुष्टि कर दी गई।

चौथी भारत–अमरीका राजनीतिक सैन्य वार्ता नई दिल्ली में 4 दिसंबर, 2014 को हुई। भारत–अमेरिका पूर्वी एशिया परामर्श नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2014 को हुए। भारत–अमरीका–जापान त्रिपक्षीय छठे दौर की बातचीत 20 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में हुई।

उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार से संबंधित मुद्दे पर भारत–अमेरिकी उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी) के तहत चर्चा की जाती है। विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने नई दिल्ली में 20–21 नवंबर, 2014 को अमरीकी उद्योग और सुरक्षा के वाणिज्य मंत्री के साथ भारत–अमेरिका उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह की नवीं बैठक की सह–अध्यक्षता की। एचटीसीजी के तहत जैव–प्रौद्योगिकी तथा लाइप साइंस, और रक्षा तथा कार्यनीतिक व्यापार पर कार्य समूहों, जिनकी बैठक अलग से बी2बी और जी2जी खंडों के तहत हुई, के अलावा हाई–टेक विनिर्माण पर एक नए कार्य समूह की बैठक पहली बार हुई, जिसमें दोनों सरकार तथा उद्योग की संयुक्त भागीदारी हुई भारत–यू एस रणनीतिक सुरक्षा वार्ता (एस एस डी) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण, बहुआयामी निर्यात नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। अमरीका के आर्म्स कंट्रोल एण्ड इंटरनेशनल सिक्यूरिटी की अंडर सेक्रेटरी के साथ विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 20 नवंबर, 2014 को भारत–यू एस रणनीतिक सुरक्षा वार्ता की सह–अध्यक्षता की।

अध्यक्ष श्री स्ट्रोब तालबॉट के नेतृत्व में द ब्रुकिंग्स 2014 शिक्षा दौरा प्रतिनिधिमंडल ने 31 अक्तूबर से 09 नवंबर, 2014 तक भारत की यात्रा की थी। नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र तथा मानवाधिकार के लिए यू एस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा तिब्बती मामलों के लिए विशेष समन्वयक, सुश्री सारास सेवाल ने 12–17 नवंबर, 2014 तक भारत की यात्रा की। भारत सरकार ने भारत में अमरीकी सैलानी कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः 28 जून से 04 जुलाई और 13 से 20 दिसंबर, 2014 तक कांग्रेसनल स्टाफर्स शिष्टमंडल की दो अलग–अलग भारत यात्राओं की मेजबानी की।

रक्षा सहयोग

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में निरंतर विस्तार देखा गया जिसके अंतर्गत रक्षा व्यापार तथा अनूठी परियोजनाओं एवं प्रौद्योगिकियों का त्वरित मूल्यांकन एवं इस पर निर्णय लेने के लिए नवगठित रक्षा व्यापार तथा प्रौद्योगिकी पहल के जरिए सह–उत्पादन/सह–विकास को और सरल एवं कारगर बनाया गया जिससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर परिवर्तनमूलक प्रभाव पड़ेगा और भारत के रक्षा उद्योग तथा सैन्य

क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिसकी 22–23 सितंबर, 2014 को प्रथम बैठक हुई; रक्षा अध्ययन तथा संयुक्त अभ्यासों में सहयोग के लिए नई पहल जिसमें जापान के साथ तथा आर आई एम पी ए सी में त्रिपक्षीय फॉरमैट शामिल है; कार्मिक आदान–प्रदान; समुद्री सुरक्षा में सहयोग; जलदस्युतारोधी कार्रवाई आदि। दोनों पक्षों ने डी टी टी आई के अंतर्गत कार्यबल गठित किया है। अमरीकी रक्षा सेक्रेटरी, श्री चूक हेजेल ने 07–09 अगस्त, 2014 तक भारत की यात्रा की।

प्रधान मंत्री की सितंबर 2014 में अमरीका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरुप जहाजों के कानूनी रूप से निर्बाध आवाजाही तथा वाणिज्यिक कार्यकलाप की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और भारत में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए सहयोग सुनिश्चित की जा सके। भारत और अमरीका ने अमरीका–भारत रक्षा संबंध कार्यढ़ाचा, 2005 के लिए अगले दस वर्ष तक नवीकृत करने का भी निर्णय लिया।

रक्षा संबंधी 16वें भारत–अमरीका संयुक्त प्रौद्योगिकी समूह की बैठक 21–22 मई, 2014 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 13वें भारत–अमरीका रक्षा नीति समूह की की बैठक वाशिंग्टन में 28–29 सितंबर, 2014 तक आयोजित किया गया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव, श्री आर के माथुर द्वारा अमरीका की ओर से रक्षा नीति के अंडर सेक्रेटरी सुश्री क्रिस्टीन वरमुथ द्वारा किया गया।

संयुक्त राज्य अमरीका संयुक्त युद्ध बंदी/युद्ध में गुमशुदा अकाउंटिंग कमाण्ड (जे पी ए सी) सैन्य कार्रवाई में मारे गए अमरीकी सैनिकों के पार्थिव शरीर को ढूंढ़ने के लिए खोजबिन जांच मिशन संचालित करता है। इन मिशनों के अनिवार्य रूप से मानवीय स्वरूप को देखते हुए भारत में 20 अक्तूबर से 23 नवंबर, 2014 तक असम तथा नागालैण्ड में तलाशीमूलक जे पी ए सी मिशन चलाने के लिए सुविधाएं प्रदान कीं।

सुरक्षा तथा आतंकरोधी सहयोग

प्रधान मंत्री की सितंबर, 2014 की अमरीका यात्रा के दौरान भारत और अमरीका ने सूचना तथा प्रौद्योगिकी के सहयोग से आई ई डी के खतरे से निपटने के लिए और जाली मुद्रा के प्रचलन को रोकने तथा आतंकवादियों, अपराधियों तथा ऐसे लोगों जो इंटरनेट का उपयोग गैर–कानूनी प्रयोजनों के लिए करते हैं, द्वारा साइबर स्पेस के उपयोग पर रोक लगाने और आपराधिक तथा आतंकवादी गतिविधियों की जांच में सुविधा प्रदान करने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने संयुक्त एवं एकजुट प्रयासों पर बल दिया जिनमें आतंकवादियों तथा आपराधिक नेटवर्क के लिए सुरक्षित जगहों को ध्वस्त करनाए अल–कायदा, लश्कर–ए–तैयबा, जैस–ए–मोहम्मद, डी कंपनी तथा हक्कानिज जैसे नेटवर्कों के लिए सभी प्रकार के वित्तीय एवं व्यवस्थामूलक समर्थन को बाधित करना शामिल है।

भारत–अमरीका होम लैण्ड सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत अवैध निधियन, रोकड़ की तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित उप समूह की बैठक में शामिल होने के लिए एक अंतर एजेंसी शिष्टमंडल ने 22–25 अप्रैल, 2014 तक वाशिंग्टन की यात्रा की। भारत–अमरीका होम लैण्ड सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संबंधी उप समूह के तत्वाधान में सीमा प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए एक अंतर एजेंसी शिष्टमंडल ने 27–31 अक्तूबरए 2014 तक अमरीका की यात्रा की।

भारत ने होनोलुलु में 19–21 मई 2014 तक आयोजित त्रिपक्षीय भारत–अमरीका–जापान मानवीय सहायता/आपदा राहत टेबल टॉक वार्ता में हिस्सा लिया।

स्टेट डिपार्टमेंट में साइबर मुद्दे के अमरीकी समन्वयक, श्री क्रिस्टोफर पेंटर ने नई दिल्ली में 13 अक्तूबर, 2014 को अपने भारतीय प्रतिपक्षों के साथ परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की।

सिविल परमाणु सहयोग

सितंबर 2014 में यू एस के साथ प्रधान मंत्री की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सभी कार्यान्वयन मुद्दों जैसे प्रशासनिक मुद्दे, दायित्वों, तकनीकी मुद्दों तथा भारत में परमाणु पार्क की स्थापना को लाइसेंसिंग की सुविधा पर चर्चा के लिए एक संपर्क समूह स्थापित करने पर सहमति दी। सिविल परमाणु सहयोग पर भारत–अमरीका संपर्क समूह की पहली बैठक 16–17 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में हुई।

भारत–अमरीका संयुक्त वर्किंग ग्रुप ऑन ग्लोबल सेंटर फौर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनशिप (जी सी एन ई पी) की दूसरी बैठक इदाहो एनर्जी इनोवेशन लेबोरेट्री (ई आई एल), इदाहो फॉव्स में 14–15 जुलाई, 2014 को हुई।

व्यापार और आर्थिक संबंधः

2013–14 के दौरान, अमरीका में भारतीय वस्तुओं का निर्यात 39.14 बिलियन अमरीकी डॉलर तक हुआ (2012–13 में 36.16 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में) जो कि भारत के वैश्विक निर्यात का 12.45 प्रतिशत बैठता है। भारतीय आयात 22.51 बिलियन अमरीकी डॉलर तक हुआ (2012–13 में 25.20 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में) जो उसी अवधि के दौरान भारत के कुल आयात का 5 प्रतिशत बैठता है। 16.65 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है (2012–13 में 10.96 की तुलना में)। अमरीका वस्तुओं के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझीदार बन गया है। सेवा क्षेत्र में कुल व्यापार जिसके लिए पूरा आंकड़ा केवल 2011 के लिए उपलब्ध है, 54.42 बिलियन अमरीकी डॉलर था। अप्रैल 2000–सितंबर 2014 के दरमियान अमरीका से भारत में प्राप्त एफ डी आई 13.12 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया जिससे अमरीका भारत में एफ डी आई का छठा सबसे

बड़ा अंशदाता बन गया जिसमें भारत के लिए कुल एफ डी आई का लगभग 6 प्रतिशत शामिल है।

अप्रैल, 2014 में भारत और अमरीका ने मार्च, 2016 तक अगले दो वर्षों के लिए द्विपक्षीय वाणिज्यिक संवाद का विस्तार किया।

संस्थागत और संगठित यू एस निवेश को भारत में बढ़ाने के उद्देश्य से, विशेष रूप से अवसंरचनात्मक क्षेत्र में, सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत–अमरीका निवेश प्रयास के साथ ही साथ अवसंरचनात्मक सहयोग मंच स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। 17 नवंबर, 2014 को भारत–अमरीका द्वारा अवसंरचनात्मक सहयोग मंच पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 'मेक इन इंडिया' अभियान के सहयोग में, यू एस फर्म भारत के रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने तथा भारत में विश्व–स्तरीय कौशल विकसित करने में सहयोग देंगे।

सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री की यू एस यात्रा के दौरान, यू एस ने इलाहाबाद, विशाखापट्नम और वाराणसी को 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकसित करने तथा साफ पानी देने में सहयोग और 500 भारतीय शहरों की स्वच्छता में साझेदारी के लिए सहमति प्रदान की है। यह निर्णय लिया गया कि भारत–अमरीका सी ई ओ मंच को सुदृढ़ किया जाए।

8वां भारत–अमरीका व्यापार नीति मंच की बैठक 24–25 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें व्यापार एवं निवेश से संबंधित विभिन्न मुद्दे विशेषकर कृषि, सेवा, मेन्युफेक्चरिंग में निवेश संवर्धन तथा बौद्धिक संपदा के क्षेत्र पर चर्चा की गई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता 24 नवंबर, 2014 को वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर एवं डिप्टी यू एस ट्रेड रीप्रेजेन्टेटिव एम्बेसडर श्री रॉबर्ट हॉलिमेन ने की। मंत्रालयी व्यापार नीति मंच की बैठक की सह–अध्यक्षता 25 नवंबर, 2014 को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और यू एस ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव एम्बेसडर श्री माईकल प्रोमेन ने की। भारत और अमरीका ने व्यापार नीति मंच पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

विदेश मंत्रालय की सहभागिता से आर आई एस ने 12 मई, 2014 को नई दिल्ली में क्रॉस बार्डर कनेक्टिविटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें जापान, यू एस ए, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, ए डी बी, वर्ल्ड बैंक और अन्य ने भाग लिया।

अप्रैल 2014 से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत से अमरीका की उल्लेखनीय उच्च स्तरीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैः सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री विजय छिब्बर –28 अप्रैल–05 मई, 2014, नागर विमानन के महानिदेशक श्री प्रभात कुमार, 25–29 अगस्त, 2014 और सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय श्री विश्वपति त्रिवेदी, 29–30 अक्तूबर, 2014।

अप्रैल 2014 से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अमरीका द्वारा भारत में की गई उल्लेखनीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैः एक्टिंग डिपटी यू एस ट्रेड रीप्रेसेनटेटिव श्री वेंडी कटलर– 16 से 18 सितंबर, 2014 यूएस प्रेसिडेंट्स डिपटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर इंडरनेशन इकोनॉमिक्स सुश्री करोसिन एरकिंसन 11 से 13 सितंबर, 2014 यू एस आई डी एडमिनिशट्रेटर यू एस ट्रेड रीप्रेसेनटेटिव एम्बेसडर रॉबर्ट हॉलिमेन–24–25 नवंबर, 2014।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोगः

अमरीकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक श्री जॉन पी होल्ड्रेन ने 17–18 नवंबर, 2014 को आयोजित प्रथम भारत–अमरीका प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन तथा 17 नवंबर, 2014 को अमरीका–भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक के लिए अमरीकी सरकार के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। अन्यों में चेयरमैन और प्रेसिडेंट, यू एस एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक श्री फ्रेड पी हॉक्बर्ग तथा यू एस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी की निदेशक सुश्री ल्यूकेडिया आई.जैक ने प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के संबंध में नई दिल्ली की यात्रा की।

अमरीका–भारत विज्ञान और प्रोद्योगिकी संयुक्त आयोग बैठक के अंतर्गत कार्यकारी समूह विषयों में आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान स्वास्थ्य और औषध विज्ञान, उभरती हुई सामग्रियां एवं निर्माणकारी विज्ञान, जलवायु पर्यावरण और भू–विज्ञान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिला विषय शामिल थे। कृषि और पादव जैव प्रौद्यागिकी पर एक नया कार्यकारी समूह गठित करने का निर्णय लिया गया।

भारत–अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच के निकाय की 15वीं बैठक डिजिटल वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से 21 अप्रैल, 2014 को हुई। भारत–अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी एंडोवमेंट बोर्ड की 11 वीं बैठक 14 मई, 2014 को वाशिंगटन डीसी में हुई। भारत–अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी एंडोवमेंट बोर्ड की 12 वीं बैठक डिजिटल वीडियो कांफ्रैस के माध्यम से 12 दिसम्बर, 2014 को हुई।

भारत–अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी एंडोवमैंट फंड के अंतर्गत और अमरीकी भागीदारी के लिए, कुछ प्रौद्योगिकियों का सामाजिक प्रभाव के लिए वाणिज्यिकीकरण करने हेतु वर्ष 2014 में 4 पुरस्कार घोषित किए गए। डीएसटी लॉकहीड मार्टिन इंनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम, 2014 के अंतर्गत 18 युवा इंनोवेटरों और व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर, 2014 में अमरीका का दौरा किया। वहीं महिला वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और व्यवसायियों के एक 10 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में विचार व्यक्त किया।

भू–पद्वित्ति विज्ञानों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भू–पद्धति विज्ञान संगठन (ESSO), भूमि विज्ञान मंत्रालय तथा अमरीका के यूनिवर्सिटि कॉरपोरेशन फॉर एटमोस्फियरिक रिसर्च के बीच 24 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए गए। ऑपरेशनल वेव मॉडलिंग एंड एसिमिलेशन पर मांगपत्र के विवरण पर भू–पद्धति विज्ञान संगठन (ESSO), भूमि विज्ञान मंत्रालय नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

सौर सहयोग

सितम्बर, 2014 में प्रधानमंत्री के अमरीकी दौरे के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भारत अमरीका सिविल और संयुक्त कार्यकारी समूह मे अंतर्गत एक नासा–इसरो मंगल संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाए। दोनों पक्ष 2021 में लांच किए जाने वाले नासा–इसरो सिंथेटिक अपेरचर राडार (NISAR), मिशन पर सहयोग के लिए एक नए करार पर भी कार्य कर रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन ने 13–19 अप्रैल, 2014 के दौरान अमरीका का दौरा किया।

अक्टूबर, 2014 में एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मोना की, हवाई में 30 मीटर टेलीस्कोप (TMT)के भूमि पूजन में हिस्सा लिया। भारत ने टीएमटी परियोजना में एक पूर्ण भागीदार के रूप में हस्ताक्षर किए।

ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन सहयोग

सितम्बर, 2014 में प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई यूएसएक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अल्प–कार्बन और जलवायु के अनुकूल ऊर्जा अर्थ व्यवस्था मं परिवर्तन की दिशा में भारत के प्रयास को सुकर बनाने हेतु वित्तपोषण करने में 1 विलियन अमिरीकी डालर तक उपलब्ध कराएगा। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग के हेतु भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि0 और अमरीका के एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक के बीच 18 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह निर्णय लिया गया था कि स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने तथा साथ ही दोनों देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हुतु दीर्घावधिक क्षमता का निर्माण करने के लिए नये अमरीका–भारत जलवायु फेलोशिप कार्यक्रम प्रारंभ करने के उद्देश्य से एक नये स्वच्छ ऊर्जा वित्त मंच का गठन किया जाए ।

भारत और अमरीका ने नई दल्ली में 30 जुलाई, 2014 को भारत–अमरीका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक बुलाई 13–14 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में एचएफसी पर द्विपक्षीय कार्य बल की बैठक आयोजित की गई ।

नेशनल इन्स्टीच्युट ऑफ ऑशन टेक्नोलौजी (एनआईओटी) के निदेशक डॉ0 एम.ए. आत्मानन्द ने अमरीका के विदेश मंत्री श्री जॉन केरी की मेजबानी में 16–17 जून, 2014 को वाशिंग्टन डी.सी. में हमारी प्रथम ''हमारे महासागर'' इन्टरनेशनल ओशन कान्फ्रेंस में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया ।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहयोग

तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ0 हर्षवर्धन ने 25–28 जून, 20124 को अमरीका यात्रा के लिए शिष्टमंडल का नेतृत्व किया । उन्होंने वाशिंग्टन डी.सी में ग्लोबल हेल्थ फोरम की ''कॉल टू एक्शन'' बैठक में भाग लिया और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम (सीडीसी) केन्द्र । अटलांटक के साथ 26–27 जून, 20124 को बातचीत की और सैन एन्टोनियो में 28 जून 2014 अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजीशियन्स ऑफ इण्डियन आरिजिन (एएपीआई) के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया ।

सितम्बर, 2014 में प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि डेंगू, मलेरिया और क्षयरोग के सस्ते टीके विकसित करने हेतु वैक्सिन एक्शन प्रोग्राम के नये चरण की शुरूआत की जाए और एक सहौषद विकास केन्द्र की स्थापना की जाए । भारत और अमरीका कैंसर अनुसंधान और पेशेंट केयर डिलीवरी में क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यकिलाप प्रारंभ करने पर सहमत हुए ।

एक भारतीय शिष्टमंडल ने भारत में कैंसर अनुसंधान तथा एम्स के तहत राष्ट्रीय कैंसर इन्स्टीच्युट की स्थानपना पर चर्चा करने के लिए यूएस नेशनल कैंसर इन्स्टीच्युट की यात्रा की और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलौजी ने सान डियागा में 02 जून, 2014 में बायोइन्टरनेशनल में भाग लेने के लिए उच्चस्तरीय इण्डिया डेलीगेशन का नेतृत्व किया ।

तीसरी भारत–अमरीका उच्चतर शिक्षा वार्ता 17 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । इसकी सह अध्यक्षता सचिव, उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और यूएस अन्डर सेक्रटरी ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक डिप्लोमिसी एण्ड पब्लिक अफेयर्स श्री रिचार्ड स्टेंजेल ने की ।

सितम्बर, 2014 में प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भारत मं हर वर्ष 1000 अमरीकी शिक्षकों द्वारा यात्रा को सुविधा जनक बनाने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडेमिक नेटवर्कस (जीआईएएन) स्थापित किया जाए । हमारे नये एम्स राष्ट्रीय इन्स्टीच्युट और एक नया आईआई टी की स्थापाना में अमरीका सहयोग देगा ।

कोंसली सहयोग

विदेश मंत्रालय और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के बीच सुविधाओं और उन्मुक्तियों पर कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक 23 अप्रैल, 2024 को वाशिंग्टन में आयोजित की गई ।

वाशिंग्टन डीसी में 24–25 नवम्बर, 2014 को भारत और अमरीका के बीच परस्पर विधिक सहायता संबंधी अनुरोधों और प्रत्ययर्पण संबंधी परामर्श किए गए ।

भारत–अमरीका कोंसली वाता 10 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में

आयिजित की गई ।

सितम्बर, 2014 में अपनी अमरीकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने पीआईओ कार्डधारकों को जीवन पर्यन्त वीजा और अमरीकी पासपोर्ट धारकों के लिए आगमन पर 10 वर्ष का वीजा और टूरिस्ट वीजा की घोषणा की ।

लातिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देश

पिछला वर्ष लातिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों के साथ भारत द्वारा वार्ता के लिए बहुत सक्रिय दौर का रहा है। वर्ष के दौरान, ऐतिहासिक उच्च स्तरीय यात्राओं, द्विपक्षीय करार, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों, विकास परियोजनाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक संवाद होने के कारण भारत और इस क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में सहायता मिली है।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दक्षिण अमेरिकी नेताओं के साथ ऐतिहासिक बैठक और जुलाई 2014 में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रासीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक ने पूरे क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को मजबूती प्रदान की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी प्रधान मंत्री ने दक्षिण अमेरिका के इतने सारे नेताओं के साथ वार्ता की हो।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सितंबर 2014 में न्यूयार्क में यू एन जी ए के अवसर पर सीलैक क्वार्टेट (CELAC Quartet) के साथ बैठक की। कोस्टा रीका, इक्वाडोर तथा एंटिगुवा व बारबुडा के विदेश मंत्रियों तथा क्यूबा के विदेश मामलों के उप मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में काफी संख्या में सीलैक समन्वयक भी मौजूद थे। भारत ने प्रस्ताव दिया कि 2015 में भारत–सीलैक बिजनेस काउंसिल तथा सी ई ओ मंच, ऊर्जा मंच तथा एस एंड टी मंच की बैठक होनी चाहिए।

भारत अपने दक्षिण–दक्षिण सहयोग की स्थायी वचनबद्धता के हिस्से के रूप में आई टी ई सी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, ऋण श्रृंखला, सहायता अनुदान और आई टी केन्द्रों के माध्यम से इस क्षेत्र के कई विकासशील देशों को सहयोग देता है।

भारत सरकार ने जमाईका, गुयाना, सूरीनाम, गुवाटेमाला, सेंट किट्स एंड नेविस तथा ग्रेनाडा को सूखा, सोलर ट्रेफिक लाइट, स्पोर्टस स्टेडियम के लिए फ्लड लाइट, शवगृह का आधुनिकीकरण, लैब सुविधाएं तथा प्रक्रियाधीन बेलिज और जमैका में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान अनुमोदित किया है। कोस्टा रीका में आई टी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना कार्य अंतिम चरण में है।

लातिन अमेरिकी क्षेत्र धीरे–धीरे भारत को कच्चा तेल देने वाला मुख्य आपूर्तिकर्ता बन रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र से कच्चे तेल का आयात वास्तविक मायने में तथा प्रतिशतता की दृष्टि से निरंतर बढ़ रहा है। एल ए सी के अंदर, वेनेजुएला शीर्ष आपूर्तिकर्ता है और 2013–14 में कोलंबिया दूसरे स्थान पर उभरा है, जिसने मेक्सिको को तीसरे और ब्राजील को चौथे स्थान पर रख दिया है।

अर्जेंटिना

भारत और अर्जेंटिना के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध है तथा भारत और अर्जेंटिना के बीच ये संबंध सुनियोजित रूप से विकसित हो रहे हैं।

वर्तमान राष्ट्रपति सुश्री क्रिस्टीना फर्नानडीज क्रिस्टीना के तहत अर्जेंटिना सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को कार्यनीतिक स्वरूप का मानती हैं। भारत–अर्जेंटिना द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं:–

(i) भारत को अर्जेंटिना के फर्मास्युटिकल अनुबंध–II के देशों में शामिल किया गया था जिसके द्वारा सितंबर 2014 में फर्मास्युटिक्स को अंतिम रूप देने के बाद आयात के लिए अनुमति प्रदान की गई है। यह अर्जेंटिना द्वारा संशोधित असामान्य राष्ट्रपति आदेश था।

(ii) नवंबर 2014 में अर्जेंटिना से भारत में सेब, नाशपाती तथा फलों के निर्यात की अब पादप स्वच्छता वार्ता के बाद अनुमति है।

12 अप्रैल, 2014 को अर्जेंटिना के साथ 8वां विदेश कार्यालय परामर्श हुआ। श्री दिनकर खुल्लर, सचिव (पश्चिम) विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा अर्जेंटिना के विदेश सचिव, तथा श्री इडुआर्डो ज्युइन उप विदेश मंत्री ने अर्जेंटिना प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने श्री एमेडो बाउडु, अर्जेंटिना के उप–राष्ट्रपति से मुलाकात की।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लातिन अमेरिकी महाद्वीप की अपनी पहली यात्रा में 30 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 को अर्जेंटिना की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत–अर्जेंटिना संसदीय मैत्री समूह के अर्जेंटिनी प्रतिनिधियों तथा सीनेटरों, अर्जेंटिना के उप–राष्ट्रपति श्री एमेडी बाउडु तथा अर्जेंटिना मंत्रिमंडल प्रमुख (राष्ट्रपति के केबिनेट मंत्री और चाको प्रांत के राज्यपाल), श्री जॉर्ज केप्टेनिच से मुलाकात की। अर्जेंटिना के उप–राष्ट्रपति और भारत–अर्जेंटिना संसदीय मैत्री समूह ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए अगले वर्ष के शुरूआत में भारत यात्रा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की नवंबर 2014 की यात्रा शामिल है।

फिक्की (FICCI) द्वारा 15–16 अक्तूबर, 2014 को आयोजित भारत–लैक निवेश सभा (कन्क्लेव) में अर्जेंटिना सहभागी देश था। श्री कार्लोस बिएन्को, उप–विदेश मंत्री के नेतृत्व में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों जैसे श्रीमती करोलीना मोइजेज, यूजुई प्रांत, अर्जेंटिना के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सचिव तथा श्री अलिजेन्द्रों स्कीबयावी, अवर

सचिव, समन्वय, पर्यटन मंत्रालय, अर्जेंटिना सरकार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिनिधियों के 70–सदस्यीय बड़े व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल ने इस कन्क्लेव में भाग लिया।

अर्जेंटिना द्वारा की गई अन्य प्रमुख यात्राओं में श्री हरनन लेम्बर्टी, अल्मीरान्टे ब्राउन के उत्पादन सचिव, ब्यूनोस आयर्स प्रांत, की 12–22 सितंबर, 2014 को दिल्ली में क्रेता–विक्रेता सभा में सम्मिलित होने हेतु यात्रा और अर्जेंटिना के विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवीन उत्पाद मंत्री श्री लिनो ब्राफियानो की अक्तूबर 2014 के पहले सप्ताह में हैदराबाद में बायो एशिया 2015 में सम्मिलित होने हेतु यात्रा शामिल है।

10–16 मई, 2014 को ब्यूनोस आयर्स प्रांत के अल्मीरान्टे ब्राउन शहर में अल्मीरान्टे ब्राउन नगरपालिका के सहयोग से भारत सांस्कृतिक सप्ताह आयोजित किया गया। शहर के महपौर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। इस सप्ताह के दौरान भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं को समाहित करने वाले कार्यक्रम हुए।

15–17 सितंबर, 2014 को भी ज्यूजुई प्रांत में भारत सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया जहां पर अर्जेंटिना में पंजाबी–सिक्ख भारतीयों का सबसे पुराना भारतीय समुदाय है। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा संगीत का परिदृश्य, भारतीय दर्शनशास्त्र और योग पर संगोष्ठी तथा भारतीय फिल्म स्क्रीनिंग शामिल है जो अच्छी तरह सम्पन्न हुई।

इसके अतिरिक्त, 24–26 अक्तूबर, 2014 के दौरान लातिन अमेरिकी पर्यटन उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय मेला (एफ आई टी, अमेरिका लातिना) में भारत की सरकारी सहभागिता रही जिसमें पर्यटन स्टॉल और भारतीय टूर एजेंसी ने भाग लिया। 14–24 नवंबर, 2014 को ब्यूनोस आयर्स में भारत का छठा महोत्सव आयोजित किया गया। यह हाल के कुछ वर्षों का अर्जेंटिना में किसी भी देश द्वारा आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का सबसे बड़ा जमघट था। 40 से अधिक सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, पर्यटन, अकादमिक तथा गैस्ट्रोनौमी कार्यक्रम में 60,000 आगंतुकों ने भाग लिया।

अर्जेंटिन ने भारत के सभी मुद्दों जैसे विश्व व्यापार संगठन कृषि वार्ता सहित सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग, खाद्य प्रापण और वितरण मामलों पर भारत के पक्ष का मजबूती से समर्थन किया है।

बोलीविया

भारत के बोलीविया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श बैठक, श्री आर. स्वामिनाथन, विशेष सचिव, (ए एम एस एंड सी पी वी), विदेश मंत्रालय तथा श्री ज्यूआन कार्लोस अलुराल्डे तेजाडे, बोलीविया के उप विदेश मंत्री की सह–अध्यक्षता में 20 नवंबर, 2014 को ला पेज में आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान, आपसी हितों के द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की गई। विशेष सचिव (ए एम एस एंड सी पी वी) ने श्री डेविड चौक्यू ह्यूएन्का, बोलीविया के विदेश मंत्री, से भी मुलाकात की जिन्होंने सूचित किया कि राष्ट्रपति श्री इवो मोरेलिस ने निदेश दिए हैं कि भारत और बोलीविया को अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और उन्होंने बोलीविया को क्षमता निर्माण हेतु भारत के सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की।

जनवरी से सितंबर 2014 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 0.12 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया जो 2013 की उसी अवधि के दौरान 47.86 प्रतिशत की वृद्धि है। इस अवधि के दौरान भारत का निर्यात 0.11 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा आयात 0.001 बिलियन अमरीकी डॉलक का रहा। फॉर्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (PHARMEXCIL) ने 10–11 अगस्त, 2014 को सांता क्रूज में पहली बार क्रेता–विक्रेता सभा (Buyer-Seller meet) का आयोजन किया जिसमें 22 भारतीय फॉर्मास्युटिकल कंपनियों ने भाग लिया।

ब्राजील

ब्राजील के साथ भारत के बहु–आयामी द्विपक्षीय संबंध 2014 में प्रगाढ़ होना जारी रहे। 15–16 जुलाई, 2014 को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील की प्रेसीडेंट सुश्री डिल्मा रोसफ्फ के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री को ब्राजील में 16 जुलाई, 2014 को प्रेसीडेंट के अधिकारिक आवास पर सम्मानाभिवादन दिया गया। उन्होंने कृषि तथा डेयरी विज्ञान, परंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष शोध तथा अनुप्रयोग, रक्षा, साइबर सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। वे जी–20 सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों और बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर भी सहमत हुए। बैठक के दौरान क) पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग, ख) भारतीय रिमोट सेंसिंग से आंकड़ें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक ब्राजीलीय भू–स्टेशन के प्रसार में सहयोग स्थापित करते हुए प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु स्थान और ग) गतिशीलता तथा कोंसली मुद्दों पर परामर्श तंत्र की स्थापना हेतु तीन महत्वपूर्ण द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष के दौरान ऐसे अवसर आए जब भारत और ब्राजील के नेताओं ने द्विपक्षीय संदर्भ में वार्ता की। प्रधानमंत्री ने जी–20 सम्मेलन के दौरान ब्रिसबेन में नवंबर, 2014 में ब्राजीलीय प्रेसीडेंट के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री ने भी आईबीएसए, जी4 और ब्रिक्स के ढांचे के तहत सितंबर, 2014 में न्यूयॉर्क में यूएनजीए के दौरान अपने ब्राजीलय समकक्ष के साथ मुलाकात की।

ब्राजील से कई प्रतिनिधि मंडलों ने भारत की यात्रा की। डॉ. अनिल धूसा, सलाहकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 18–21

अगस्त, 2014 के दौरान ब्राजीलिया में विश्व कृषि वन्य केंद्र (आईसीआरएएफ) द्वारा आयोजित वैकल्पिक बॉयो–फ्यूल क्रॉप्स विकास हेतु कार्यक्रम की अनुवीक्षण समिति की बैठक में भाग लिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, वित्त एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के उच्च स्तरीय अधिकारिक प्रतिनिधि मंडलों ने अपने समकक्षों के साथ बैठक में भाग लेने और जी–20 बैठकों में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा की।

19 भारतीय औषधीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए फॉरमेक्सिल द्वारा प्रायोजित 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5–7 अगस्त, 2014 के दौरान साओपालो में सीपीएचआई–दक्षिण अमेरिका प्रदर्शनी में भाग लिया।

जुलाई, 2014 में प्रधानमंत्री की ब्राजील की यात्रा तथा यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की कृत कार्रवाई के रूप में श्री जी.पी. स्वामी, वैज्ञानिक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय अंतरिक्ष प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त–सितंबर, 2014 में क्यूबा, ब्राजील में राष्ट्रीय अंतरिक्ष शोध संस्थान (आईएनपीई) सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन में रिसोर्ससेट–2 डाटा डायरेक्ट रिसेपशन में भाग लिया।

2014 के पहले 10 माह में भारत और ब्राजील का समग्र व्यापार 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया तथा ब्राजील को निर्यात 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा आयात 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जिसमें भारत को 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार लाभ हुआ। वर्ष 2014 में भारत 2013 में 12वें स्थान से ब्राजील का 8वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया। लगभग 54 प्रतिशत भारतीय निर्यात मूल्य वर्धित पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि डीजल थे। भारत से प्रभुत्व निर्यात की अन्य मदें औषधि और कृषि रसायन थे जो कुल निर्यात के लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे। इन निर्यातों में दोहरे अंक पर वृद्धि हुई। विद्युत उपकरण तथा ऑटो उपस्कर उत्पादों ने इंजीनियरिंग उत्पादों का समूह तैयार किया और वे भारत के निर्यात में अन्य प्रमुख मदें थी जो कि लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अन्य महत्वपूर्ण मदों में वस्त्र उत्पाद (कपास, परिधान, उपस्कर इत्यादि) शामिल थे जो ब्राजील को भारतीय निर्यातों के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नजदीक थे।

1–15 मई, 2014 के दौरान ब्राजील के डाक विभाग द्वारा भारतीय दूतावास और भारतीय फिल्म उत्सव निदेशालय के सहयोग से दो सप्ताह एक भारतीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर भारतीय कला सिनेमा की विभिन्न भाषाओं की तेरह फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ब्राजील के डाक विभाग ने 5 मई, 2014 को भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों पर एक डाक टिकट भी जारी की।

साओपालो में भारतीय संस्कृति केंद्र (आईसीसी) ने भारतीय नृत्य स्वरूपों को शामिल करते हुए नियमित शास्त्रीय नृत्यों का आयोजन किया। आईसीसी ने विजिटिंग कलाकारों द्वारा कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जिसमें श्री राहुल आचार्य, सुश्री अरुण प्रधान और श्रीमती मारिया लोरा वालडेज द्वारा ओडिशी नृत्य प्रदर्शन तथा नीदरलैंड की सुश्री शेरोन वेजर द्वारा भरत नाट्यम प्रस्तुति शामिल थे।

आंतरिक राजनीतिक मंच पर देश में 2014 में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम देखे गए जिसमें से अक्तूबर, 2014 में प्रेसीडेंट सुश्री डिल्मा रोसफ्फ की चुनाव में जीत अत्यधिक उल्लेखनीय थी। प्रेसीडेंट सुश्री डिल्मा रोसफ्फ ने दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल जीता।

ब्राजील ने 2015 की पहली छमाही के लिए अर्जेंटीना से मर्कोसर की क्रमानुसार अध्यक्षता हासिल की।

चिली

विगत कुछ वर्षों के दौरान देखी गई नियमित वार्ताओं की गति 2014 में जारी रही जिससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। अप्रैल–सितंबर, 2014 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हो गए जिसमें से भारत का निर्यात 0.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 1.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। भारत तथा चिली के बीच श्री आर. स्वामीनाथन, विशेष सचिव (एएमएस तथा सीपीवी) और श्री एडगार्डो रिवेरो मारीन, चिली के उप–विदेश मंत्री की सह–अध्यक्षता में 31 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में भारत तथा चिली के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों का छठा दौर आयोजित किया गया। बैठक के दौरान द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

सांसदों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2–5 नवंबर, 2014 को चिली की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता राज्य सभा तथा लोक सभा के 7 संसद सदस्यों तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के तीन अधिकारियों को शामिल करते हुए श्री संतोष कुमार गंगवार, वस्त्र मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनुरूद्धार मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस प्रतिनिधिमंडल ने (i) श्री फ्रांससिको चौहान, सिनेटर तथा चिली की संसद में भारत–चिली अंतर संसदीय मित्रता समूह के अध्यक्ष, (ii) श्रीमती ईशाबेल एलेंडे, चिली की संसद की अध्यक्षता, (iii) श्री आल्डो कोरेन्जो, चिली के प्रतिनिधियों के चैम्बर अध्यक्ष, और (iv) श्रीमती लोरेटो कारवजल, चिली के प्रतिनिधियों के चैम्बर में भारत–चिली अंतर–संसदीय समूह की अध्यक्षा और श्रीमती जिमेना रिंकोन, मंत्री, चिली प्रेसीडेंसी की महासचिव के साथ बैठकें की।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक मंच पर भारत को एक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए 29 सितंबर, 2014 को सेंटीगो में एक भारतीय पर्यटन रोड शो का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

कोलंबिया

भारत–कोलंबिया के संबंध वर्ष के दौरान विकसित होना जारी रहे। विदेश कार्यालय परामर्शों का पांचवा दौर 21 नवंबर, 2014 को

बोगोटा में आयोजित किया गया। इसने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने का अवसर प्रदान किया। भारत तथा कोलंबिया के बीच इस यात्रा के दौरान खेलों के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मई, 2011 में हस्ताक्षरित दोहरा कराधान बचाव करार कोलंबिया की सरकार द्वारा संशोधन के पश्चात् 7 जुलाई, 2014 को प्रभावी हुआ।

द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों का और विस्तार होना जारी रहा। अप्रैल–सितंबर, 2014 के बीच द्विपक्षीय व्यापार 3.324 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। भारतीय निर्यात 0.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के थे।

इक्वेडर

इक्वेडर के साथ द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मजबूत होना जारी रहा। उप–विदेश मंत्री श्री लियोनार्डो अरिजगा ने 13 अगस्त, 2014 को एसएस (एएमएस तथा सीपीवी) के साथ विदेश कार्यालय परामर्शों की बैठक की सह–अध्यक्षता की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

द्विपक्षीय व्यापार भी 19.79 प्रतिशत की दर पर बढ़ना जारी रहा। अप्रैल–अगस्त, 2014 के बीच द्विपक्षीय व्यापार 0.343 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। भारतीय निर्यात 0.102 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा आयात 0.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा।

गुआना

गुआना के साथ हमारे संबंध जोशीले और मित्रवत रहे। राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड रामोटर ने 16 जुलाई, 2014 को ब्राजील में दक्षिण अमेरिका बैठक के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के ब्रिक्स–संपर्क सत्र के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक की। दोनों नेता दोनों देशों के बीच मौजूदा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर सहमत हुए। चल सिंचाई पंपों की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा गुआना को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन के साथ पूरी हुई। गुआना में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए अग्रिम राशि भी 19 मिलियिन अमेरिकी डॉलर की भारत सरकार की ऋण श्रृंखला के साथ जारी की गई।

गुआना के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड रबिन्द्रनाथ रामोटर ने 7–12 जनवरी, 2015 भारत की अधिकारिक यात्रा की। उन्होंने 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की। वे 13वें भारतीय प्रवासी दिवस जिसका 7–9 जनवरी, 2015 को गांधीनगर (गुजरात) में आयोजन किया गया था के मुख्य अतिथि भी जिसमें उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ विचार–विमर्श किए। अधिकारिक बैठकों के अलावा उन्होंने वलसाड (गुजरात) में एक चीनी फैक्ट्री का भी दौरा किया और मुम्बई में चीनी उद्योगपतियों के साथ विचार–विमर्श किए।

गुआना के अनुरोध पर भारत सड़क संपर्क परियोजना के निर्माण तथा एक समुंद्री फेरी की आपूर्ति के लिए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो ऋण श्रृंखला प्रदान करने पर भी सिद्धांततः सहमत हुआ। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत चीनी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चार विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों का भी गुआना को प्रस्ताव किया गया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के तत्वाधान में दो सांस्कृतिक समूहों ने मई तथा अक्तूबर, 2014 में जियोर्जेटाउन के राजधानी शहर सहित गुआना के विभिन्न शहरों में कई प्रस्तुतियां की।

मेक्सिको

मेक्सिको के साथ भारत की विशेष भागीदारी वर्ष के दौरान बढ़नी और विकसित होनी जारी रही। 7 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित विदेश कार्यालय परामर्शों के तीसरे दौर के पश्चात् श्री जोश एनटोनियो मेडेकुरीबरेना, मेक्सिको के विदेश मंत्री ने 20–22 अक्तूबर, 2014 को भारत की यात्रा की और विदेश मंत्री के साथ 22 अक्तूबर, 2014 को छठे संयुक्त आयोग बैठक की सह–अध्यक्षता की। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान मेक्सिको के विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री तथा जी–20 सम्मेलन के लिए भारतीय पक्ष के साथ भी बैठक की।

संयुक्त आयोग की बैठक जो कि 1984 में तंत्र की स्थापना से मंत्रालय स्तर की पहली बैठक है, की सह–अध्यक्षता विदेश मंत्री तथा मेक्सिकन विदेश मंत्री द्वारा की गई जिनके साथ मेक्सिकन उप–विदेश मंत्री और व्यापारियों के अतिरिक्त 18 सदस्यीय अंतर–मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल शामिल था। राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यापार, ऊर्जा, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा पर्यटन, कोंसुलर और सांस्कृतिक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर दोनों मंत्रियों द्वारा विचार–विमर्श किया गया। उन्होंने लेटिन अमेरिकी कैरीबन राज्यों के समुदाय (सीईएलएसी) तथा प्रशांत संबंध (पीए) के साथ जारी भारत के संबंधों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। पर्यटन तथा कृषि संबंधी संयुक्त कार्य समूह की बैठकों का 20 अक्तूबर, 2014 को जीसीएम के साथ आयोजन किया गया। एसएंडटी के संबंध में भारत–मेक्सिन संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में एसएंडटी के अभिज्ञात क्षेत्रों में 2014–16 के लिए सहयोग के एक कार्यक्रम को डीएसटी तथा सीओएनएसीवाईटी के बीच अंतिम रूप दिया गया। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष सहयोग के संबंध में इजरो तथा मेक्सिकन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच बैठक के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत तथा मेक्सिको के बीच प्रथम कोंसुलर वार्ता 17 अक्तूबर, 2014 को मेक्सिको शहर में आयोजित की गई। व्यापार तथा पर्यटन के लिए दोनों देशों के बीच प्रक्रिया को सुलभ बनाने और यात्रा को सुकर बनाने के उद्देश्य से कोंसुलर तथा वीजा मुद्दों के संबंध में विचारों का आदान–प्रदान किया गया।

दूतावास द्वारा प्रदत्त वीजा एवं कोंसुली सेवाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना 27 नवंबर, 2014 से मेक्सिकन नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल–इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (टीवीओए–ईटीए) आरंभ करना था। यह मेक्सिको के नागरिकों के लिए भारत की यात्रा करना आसान बनाएगा और द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश एवं लोगों के बीच संपर्कों में और अधिक वृद्धि करेगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार, वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य, जल संसाधन और नदी विकास और गंगा पुनुरूद्धार राज्य मंत्री तथा लोक सभा एवं राज्य सभा के विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के 7 संसद सदस्यों ने 26–29 अक्तूबर, 2014 को मेक्सिको की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने मेक्सिको की सीनेट तथा प्रतिनिधियों की संसद का दौरा किया और दोनों सदनों, सीनेट में विदेश संबंध समिति के सदस्यों तथा प्रतिनिधियों के सदन में भारत मेक्सिको मित्रता समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात की। राज्य मंत्री (संसदीय मामले) ने संसदीय स्तर पर नियमित द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ के आयोजन के लिए 2015 में भारत की यात्रा करने के लिए मेक्सिको के सांसदों को आमंत्रित किया।

भारत ने एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में मेक्सिको में आयोजित 9वें प्रशांत संबंध सम्मेलन में भाग लिया और एमएसएमई, एसएंडटी तथा आईटी के क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव किया।

भारत तथा मेक्सिको ने अपनी घरेलू प्रक्रिया पूरी की और सीमा शुल्क मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता के संबंध में करार को लागू होने की पुष्टि करते हुए नवंबर, 2014 में राजनयिक टिप्पणियों का आदान–प्रदान किया।

2013 में भारत विश्व में मेक्सिको का 16वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और एशिया प्रशांत क्षेत्र में छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था।

लगभग 40 भारतीय कंपनियों ने आईटी, औषधीय तथा ऑटो घटकों सहित मेक्सिको में अपनी उपस्थिति पहले ही स्थापित कर दी है। भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी टेक महिन्द्रा ने मई, 2014 में अमेरिकी क्षेत्र में विस्तार नीति के अपने भाग के रूप में मेक्सिको में प्रवेश की घोषणा की। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) तथा पीईएमईएक्स ने 25 सितंबर, 2014 को मेक्सिको में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा मेक्सिको में तेल के क्षेत्रों में खोज तथा विकास की बोली प्रक्रिया जो मेक्सिको में ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख सुधारों के पश्चात् निजी निवेशकों के लिए खुली हैं, में सक्रिय रूप से भाग लेने के उद्देश्य से दिसंबर, 2014 में मेक्सिको में अपने संचालन आरंभ करने के लिए सूचीबद्ध है। भारत में मेक्सिको के निवेश भी बढ़ रहे हैं।

भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ) ने 14–17 जनवरी, 2014 को गुडालाजारा में आयोजित मेक्सिको में अत्यधिक महत्वपूर्ण फैशन उद्योग आयोजन इंटरमोडा में ''भारतीय पवेलियन'' तैयार किया जिसमें एक दर्जन से अधिक भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

फरवरी में मूल रसायन, औषधी एवं कॉस्मेटिक निर्यात संवर्धन परिषद् (कैमेक्सिल) ने मेक्सिको शहर में विश्व व्यापार केंद्र में दूसरी भारतीय रसायन एवं कॉस्मेक्टिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। भारत की 47 से अधिक कंपनियों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। लगभग 200 मेक्सिकन तथा मेक्सिको के विदेश व्यापारियों ने प्रदर्शनी के 47 स्टॉल का दौरा किया।

भारतीय ऑटोमोटिव कम्पोनेंट निर्माता संघ (एसीएमए) ने भारत के ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के 13 युवा सीईओ के समूह की 24–28 मार्च, 2014 को मेक्सिको के ऑटो कम्पोनेंट बाजार में निवेश संभावनाओं को समझने तथा उनकी पहचान करने के उद्देश्य से मेक्सिको की यात्रा का आयोजन किया।

भारतीय मासाला बोर्ड ने 4 जून, 2014 को अलीमेंटारिया मेक्सिको–2014 में ''भारतीय पवेलियन'' की स्थापना की जो कि मेक्सिको शहर में होने वाली महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में से एक है।

भारतीय पर्यटन कार्यालय ने 18 सितंबर, 2014 को मेक्सिको शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका पर्यटन मेले (एफआईटीए 2014) में भारतीय पर्यटन संचालकों की भागीदारी आयोजित की।

बढ़ते हुए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा मेक्सिको में भारतीय दूतावास के सहयोग से 28–30 अगस्त, 2014 को गुडालाजारा, मेक्सिको में 26वें एक्सपो नेशियोनल फेरेटेरा के भाग के रूप में ''द इंडिया शो'' का आयोजन किया जिसमें भारत अधिकारिक भागीदार देश था। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 70 से अधिक भारतीय कंपनियों ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग वस्तुओं की प्रदर्शनी की।

भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए एक प्रमुख और महत्वपूर्ण गतिविधि के भाग के रूप में गुरूदेव टेगौर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (जीटीआईसीसी) ने विभिन्न विषयों में अपने परिसर में नियमित कक्षाएं आयोजित की।

परागुआ

भारत तथा परागुआ के बीच किसी बकाया मुद्दे के न होते हुए सौहार्दपूर्ण संबंध बने। परागुआ ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् 2015–17 के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

असनशियन में 5 दिवसीय भारतीय भोजन उत्सव का आईटीडीसी, पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजन किया गया।

पेरू

पेरू के साथ द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मित्रवत रहना जारी रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजीलिया में 16 जुलाई, 2014 को आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के साथ राष्ट्रपति श्री ओलांटा हुमाला के साथ मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने तथा विभिन्न नए क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि करने के संबंध में विचार–विमर्शों का आदान–प्रदान किया।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी भारत–पेरू संयुक्त समिति की पहली बैठक 7–8 जून, 2014 को लीमा में आयोजित की गई और सहयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहमति हुई।

20 अगस्त, 2014 को पेरू के उप–विदेश मंत्री श्री एडगर वासक्यूज ने नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव के साथ विचार–विमर्श किया। दोनों पक्ष द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार के लिए वार्ता आरंभ करने पर सहमत हुए। 15–16 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित फिक्की के भारत–एलएसी कन्क्लेव में पेरू मुख्य देश था।

जनवरी से सितंबर, 2014 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था जो 2013 की इसी अवधि में 17.34 प्रतिशत कम है। इस अवधि के दौरान भारत से पेरू को निर्यात 0. 567 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पेरू से आयात 0.233 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सिन्थेटिक एवं रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने 28–29 अप्रैल, 2014 को लीमा में प्रथम भारतीय वस्त्र एवं यान प्रदर्शना सह बीएसएम इंटेक्सपो पेरू का आयोजन किया। औषध निर्यात संवर्धन परिषद् फारमेक्सिल के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 6–8 अगस्त, 2014 को पेरू की यात्रा की। भारतीय मासाला बोर्ड ने पहली बार लीमा में 27–29 अगस्त, 2014 को आयोजित एलएसी क्षेत्र में सबसे बड़े भोजन मेले ''एक्सपो एलीमेंटारिया'' ने भाग लिया। कई भारतीय कंपनियों ने पेरू में अपने संचालनों में विस्तार करना जारी रखा।

उरुग्वे

भारत तथा उरुग्वे के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर उरुग्वे में 9–10 अप्रैल, 2014 को आयोजित किया गया तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता श्री दिनकर खुल्लर, सचिव (पश्चिम) द्वारा की गई। श्री तबेरे वार्जक्वेज ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव जीते और वे 1 मार्च, 2015 को शपथ ग्रहण करेंगे।

भारत ने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् 2015–17 के लिए उरुग्वे का उम्मीदवारी हेतु हाल के समर्थन सहित सभी बहुपक्षीय मंचों में उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

वेनेजुएला

भारत तथा वेनेजुएला सौहार्दपूर्ण संबंधों को जारी रखे हुए हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, राजनैतिक और आर्थिक मुद्दों पर विचारों की समानता है। वेनेजुएला अपने तेल, गैस, खनिज, स्वर्ण, हीरे के भंडारों के रूप में एक तेल एवं संसाधन –अमीर देश है। वेनेजुएला में सबसे बड़े सिद्ध तेल के भंडार है जो लगभग 297 बिलियन बैरल तथा विश्व में आठवां सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार (196 ट्रिलियन क्यूबिक फीट) है। वेनेजुएला ने जनवरी, 2015 से यूएनएससी की गैर स्थायी सदस्यता हासिल की है। वेनेजुएला को 2015 में अगले एनएएम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो कुल तेल आयात का लगभग 12 प्रतिशत है तथा हाईड्रोकार्बन क्षेत्र दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विगत कुछ वर्षों में वेनेजुएला हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। वेनेजुएला के बाजार में भारतीय औषधीय कंपनियों की उपस्थिति में मात्रात्मक वृद्धि हुई है। परस्पर हित के अन्य संभावित क्षेत्रों जैसे कि औषधियां, उद्योग जगत, ऑटोपार्टस, आईटी एवं दूरसंचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, डेयरी तथा पशुपालन में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में अधिक अभिरूचि है।

पिछले वर्ष के शानदार प्रत्युत्तर के साथ भारत सरकार ने वेनेजुएला को 2014–15 के लिए 16 आईटीईसी सीटों का आबंटन किया।

केंद्रीय अमेरिका

कोस्टा रिका

हाल ही में विदेश मंत्रालय ने पनामा में भारतीय दूतावास को कोस्टा रिका का संघ प्रत्यायन हस्तांतरित किया जिसने भारतीय वीजा को सुलभ बनाने तथा कोस्टा रिका के साथ भारत के संबंधों में सुधार करने में सहायता की। सेंटर –लेफ्ट पार्टीडो एकिओन सियूडडाना के राष्ट्रपति श्री लुईस गुलेरमो सोलिस ने 8 मई, 2014 को कोस्टा रिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति श्री लुईस गुलेरमो सोलिस ने भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग जारी रखने और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं का आदान करने के लिए कदम उठाने की पुनः पुष्टि की।

ईआई साल्वाडोर

मंत्रालय ने हाल ही में गुवाटेमाला में हमारे दूतावास के लिए ईआई साल्वाडोर के संगत प्रत्यायन हस्तांतरित किया है जिसने भारतीय वीजा तथा ईआई साल्वाडोर के साथ भारत के संबंधों में सुधार को सुलभ बनाया है। आईआई साल्वाडोर के साथ दूसरा विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में दिसंबर, 2014 को आयोजित किया गया। आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध मंच पर औषध निर्यात संवर्धन परिषद् (फॉरमेक्सिल) के 21 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने

अगस्त, 2014 में ईआई साल्वाडोर की यात्रा की और क्रेता दृ विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया।

ईआई साल्वाडोर के साथ दूसरा विदेश कार्यालय परामर्श 10 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान राजनैतिक, वाणिज्य और व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्त एवं तकनीकी सहयोग, शिक्षा, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन, नवाचार सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया गया। मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की गई। लेटिन अमेरिका कैरीबियन राष्ट्रों (सीईएलएसी) तथा केंद्रीय अमेरिकी समेकन प्रणाली (एसआईसीए) के साथ भारत के जारी संबंधों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया गया।

गुवाटेमाला

गुवाटेमाला के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध महत्वपूर्ण रूप से मजबूत हुए हैं। भारत तथा गुवाटेमाला के बीच प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श गुवाटेमाला में 7 अप्रैल, 2014 को आयोजित किए गए। गुवाटेमाला के विदेश मंत्री श्री कार्लोस रौल मुरालेस मोस्कोसो ने भारत की यात्रा की और 15 अक्तूबर, 2014 को विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सूखा राहत सहायता के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की जिसके लिए प्रतीक चैक गुवाटेमाला के उप–राष्ट्रपति श्री रोकसाना बालडेटी को बाद में सौंपा गया। गुवाटेमाला से आर्थिक मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 16–17 अक्तूबर, 2014 को छठे भारत–एलएसी निवेश कन्क्लेव में भागीदारी की। इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश मामलों को उप–मंत्री और साथ हाईप्रोफाइल गुवाटेमालीय व्यापारियों का समूह शामिल था। दो भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद् (पलेक्सकोंसिल) औषध निर्यात संवर्धन परिषद् (फारमेक्सिल) ने क्रमशः अप्रैल और अक्तूबर, 2014 में गुवाटेमाला की यात्रा की। उन्होंने काफी सफल क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन किया।

होन्डुरस

मंत्रालय ने हाल ही में गुवाटेमाला में हमारे दूतावास के लिए होन्डुरस के संगत प्रत्यायन हस्तांतरित किया है जिसने भारतीय वीजा तथा होन्डुरस के साथ भारत के संबंधों में सुधार को सुलभ बनाया है। होन्डुरस भारत में अपना दूतावास खोलने की कार्रवाई भी कर रहा है। अक्तूबर, 2014 में छठे भारत–एलएसी निवेश कन्क्लेव में होन्डुरस के आर्थिक विकास मंत्री की भागीदारी द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक बढ़ाने में सहायक होगी।

निकारागुआ

मंत्रालय ने हाल ही में पनामा में हमारे दूतावास के लिए निकारागुआ के संगत प्रत्यायन हस्तांतरित किया है जिसने भारतीय वीजा तथा निकारागुआ के साथ भारत के संबंधों में सुधार को सुलभ बनाया है। 17 नवंबर, 2014 को मैनागुआ में भारतीय पक्ष से श्री आर. स्वामीनाथन, विशेष सचिव (एएमएस एंड सीपीवी) तथा निकारागुआ पक्ष से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए उप–मंत्री श्री वाल्ड्रेक जेंटचके की अध्यक्षता में प्रथम भारत–निकारागुआ विदेश कार्यालय परामर्शों के आयोजन के साथ भारत–निकारागुआ के बीच द्विपक्षीय संबंध और अधिक सुदृढ़ हुए। श्री आर. स्वामीनाथन ने विदेश मंत्री श्री सेमुअल सेंटोस लोपेज के साथ भी भेंट की। इस बैठक ने राजनैतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और कोंसुली क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने के लिए परस्पर वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की संभावना प्रदान की। भारत द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रिक सब–स्टेशनों की स्थापना के लिए तीन एलओसी प्रदान करने भी विचार–विमर्श किया गया। इस बात पर सहमति हुई की प्रमुख क्षेत्र जैसे कि औषधि, ऑटोमोटिव, आईटी, कृषि, ऊर्जा मानव संसाधन विकास में अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। भारत ने कृषि क्षेत्र में निकारा गुआ की सहायता करने के लिए एक वर्ष के लिए निकारागुआ को आईटीईसी के एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया।

श्री एल. वारो बालटोडानो, निवेश संवर्धन तथा विदेश व्यापार हेतु राष्ट्रपति के सलाहकार की अध्यक्षता में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 16–17 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित भारत–एलएएसी निवेश कन्क्लेव में भाग लिया।

भारत सरकार ने 2014 में सिद्धांततः 2 एलओसी अनुमोदित किए –(i) निकारागुआ में ला एसपेरांजा–गाटेअडा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए 31.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर और (ii) कार्लोस फोनसेका सब–स्टेशन/ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए 26.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

भारत ने अप्रैल, 2014 में डेंगू महामारी के लिए निकारागुआ को दवाइयां दान दी।

पनामा

राष्ट्रपति श्री जुआन कार्लोस बरेला, सेंटर–राइट पनामा पार्टी के अध्यक्ष ने 1 जुलाई, 2014 को पनामा के 37वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यग्रहण किया। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की अपनी तीव्र इच्छा जाहिर की है।

छियासठ भारतीय कंपनियों ने एक्सपोकॉमर–2014 जो कि पनामा शहर में 26–29 मार्च, 2014 को पनामा वाणिज्य, उद्योग और कृषि चैम्बर द्वारा आयोजित केंद्रीय अमेरिका में सबसे बड़े वार्षिक वाणिज्यिक प्रदर्शनियों में से एक है में भाग लिया। 35 विदेश कंपनियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया।

दो परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की प्रगति चल रही है – (i) टेलीमेट्री ट्रेकिंग और कमांडिंग (टीटीसी) भू–स्टेशन की पनामा में

इसरो द्वारा सेटेलाइट ऑपरेशन के लिए टेलीमेट्री ट्रेकिंग स्थापना तथा (ii) पनामा में जैव–विविधता तथा ड्रग खोज केंद्र की स्थापना के लिए पनामा को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर एलओसी प्रदान करना।

कैरीबियन देश

क्यूबा

क्यूबा के प्रथम विदेश व्यापार एवं निवेश उप–मंत्री श्री एनटोनियो लुईस कारीकार्टे कोरोना जिन्होंने 16–17 अक्तूबर, 2014 को भारत–एलएसी निवेश कन्क्लेव में भाग लिया, की यात्रा के साथ वर्ष 2014 में क्यूबा के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए। उन्होंने नए विदेश निवेश कानूनों का सिंहावलोकन तथा नव गठित मेराई मुक्त जोन में उपलब्ध सुविधाओं पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया और ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बॉयो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत से निवेश आमंत्रित किए। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के साथ भी भेंट की।

इंजेक्टबेल उत्पाद संयंत्र के नवीकरण तथा भारत सरकार की 7.7512 अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन के तहत बल्क ब्लेडिंग फर्टीलाइजर प्लांट की स्थापना के लिए भारतीय एग्जिम बैंक तथा क्यूबन बानको डी एस्टीरियर के बीच दो करारों पर हस्ताक्षर किए।

शैक्षिक सहयोग के लिए जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय तथा यूनीवर्सिटी ऑफ हवाना के बीच सितंबर, 2014 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

डोमीनिकल गणराज्य

विदेश कार्य राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 15–17 फरवरी, 2015 तक डोमीनिकल गणराज्य की अधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान राज्यमंत्री (वी.के.एस.) ने राष्ट्रपति श्री डानीलो मेडिना तथा विदेश मंत्री श्री एन्ड्रेस नवारो के साथ विचार–विमर्श किए।

हेती

सुश्री कार्मेला जीन मेरी, आर्थिक एवं वित्त मंत्री ने अक्तूबर, 2014 में भारत–एलएसी निवेश कन्क्लेव के लिए पांच सदस्यी हेती प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्रालय में सचिव (ईए) के साथ भी विचार–विमर्श किए।

हेती के राष्ट्रपति श्री निकेल जोसेफ मारटले टीईआरआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले दिल्ली सतत विकास सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6–7 फरवरी, 2015 को भारत की निजी यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान हेती के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के साथ भेंट करेंगे और प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री के साथ विचार–विमर्श करेंगे।

भारत सरकार की 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता अनुदान के साथ जनवरी, 2010 के तबाही वाले भूकंप में हेती के विस्थापित नागरिकों के लिए गांधी गांव (राजधानी शहर पोर्ट–अयू–प्रिंस के बाहरी ओर) में 241 ड्बेलिंग ईकाइयों की स्थापना की गई है।

जमैका

भारत तथा जमैका के बीच इतिहास, संसदीय प्रजातंत्र, राष्ट्रमंडल की सदस्यता अंग्रेजी साहित्य तथा क्रिकेट के प्रेम के समान संबंधों पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मित्रवत संबंध है जो 70 हजार से अधिक मजबूत भारतीय लोगों द्वारा पुनः लागू होते हैं जो कि अब जमैका की कुल जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत है जिन्होंने स्वयं को जमैका की मुख्य धारा में समाहित कर लिया है।

भारत सरकार ने जमैका की सरकार को किंगस्टन, जमैका में प्रसिद्ध सबीना पार्क क्रिकेट मैदान जो कि कैरीबियन में फ्लड लाइट के बगैर अकेला स्टेडियम था, में फ्लड लाइट की स्थापना के लिए 0.002 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया। इन फ्लड लाइटों का 3 अगस्त, 2014 को एक सार्वजनिक समारोह में जमैका की सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया।

जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) विदेश राज्य मंत्री का 18–19 फरवरी, 2015 को जमैका की यात्रा का कार्यक्रम है। उनके जमैका के प्राधिकारियों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर एक करार करने की भी संभावना है।

सूरीनाम

सूरीनाम के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध 1873 में भारत से अनुबंध श्रमिकों के पहले समूह के आगमन के साथ एक शताब्दी से भी अधिक पुराने हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम की जनसंख्या का 27.4 प्रतिशत हैं। भारत और सूरीनाम के जोशीले और मित्रवत द्विपक्षीय संबंध है। राष्ट्रपति श्री देसी डेलानो बोटर्से ने 16 जुलाई, 2014 को ब्राजीलिया में ब्रिक्स सम्मेलन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक बैठक की जिसके दौरान द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और दोनों नेता दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमत हुए।

जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) विदेश राज्य मंत्री तथा सूरीनाम गणराज्य के विदेश मंत्री श्री विंसटन जी. लेकिन की सह–अध्यक्षता में 13 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में सूरीनाम तथा भारत के बीच 5वें संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) का आयोजन किया गया। सूरीनाम के विदेशी मंत्री के साथ शिक्षा एवं समुदाय विकास मंत्री श्री अश्विन अधिन तथा एक बड़ा बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल साथ था। राजनैतिक, आर्थिक और व्यापार, पारंपरिक दवा, तकनीकी सहयोग, शिक्षा, कोंसुलर तथा सांस्कृतिक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे क्षेत्रों पर दोनों मंत्रियों द्वारा विचार–विमर्श किया गया। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया।

ब्राजील की राष्ट्रपति सुश्री दिलेमा राउसेफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए किएरा इवेन्ट्स सेंटर में प्रधान मंत्री के आगमन पर स्वागत करते हुए।

गुयाना के राष्ट्रपति की 07–12 जनवरी, 2015 के दौरान भारत यात्रा।

विदेश मंत्री और संयुक्त मैक्सिको राज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री जोस एंटोनियो मियाडे कुरी ब्रेना 22 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में एक हस्ताक्षर समारोह में।

विदेश राज्य मंत्री 13 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में सूरीनाम गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री विंस्टन जी. लाकीन से मुलाकात करते हुए।

भारत ने सूरीनाम को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की नई क्रेडिट लाइन प्रस्ताव किया जिसके लिए सूरीनाम द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव भेजे जाएंगे। एस' लैंड्स अस्पताल, पैरामारिबो में शहगृह के उन्नयन तथा सूरीनाम में एनएटीआईएन संस्थान को कंप्यूटर तथा अन्य उपकरण की आपूर्ति के लिए दो अनुदान सहायता परियोजनाओं की घोषणा की गई।

मार्च, 2003 में हस्ताक्षरित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में 28 जुलाई, 2014 को आयोजित की गई जिसके दौरान 2014–19 के लिए एक कार्य योजना तथा 2014–15 के लिए एक वरीयता कार्य योजना पर विचार–विमर्श किया गया।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा भारत से एलओसी के अंतर्गत 0.005 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए 2014 में तीन चैतक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की गई है। सूरीनाम के 6 पायलट एमओडी सूरीनाम तथा एचएएलके के बीच करार की शर्तों के तहत एचएएल रोटरी विंग अकादमी, बंगलुरू में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त कर रह हैं। इन पायलटों का प्रशिक्षण पूरा होने पर एचएएल द्वारा तीन हेलीकॉप्टरों की असेम्बल तथा संचालनरत किया जाएगा।

पैरा अश्विन अधिन, सूरीनाम गणराज्य के शिक्षा एवं समुदाय विकास मंत्री ने 13–25 नवंबर, 2014 को भारत की व्यक्तिगत यात्रा की। यात्रा के दौरान 24 नवंबर, 2014 को उन्होंने राज्य मंत्री (वी.के. एस.) के साथ एक सिस्टाचार भेंट की और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान किया।

आईसीसीआर के तत्वाधान में दो संगीत एवं नृत्य दलों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूरीनाम की यात्रा की। पहला सुश्री कल्पना पटवारी की अध्यक्षता 5 सदस्यीय भोजपुरी संगीत दल था जिसने 21–23 मई, 2014 के दौरान 2 सार्वजनिक प्रस्तुतियां दी। दूसरा सुश्री इन्दिरा नायिक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समर्पित/लाइट शास्त्रीय दल था जिसने सूरीनाम में 15–19 अक्तूबर, 2014 और बारबाडोस था सेंटबिनसेंट और ग्रेनाडिन्स में 22–27 अक्तूबर, 2014 को प्रस्तुति की।

सेंट किट्स एंड नेविस

दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और मित्रवत बने रहे। भारत तथा सेंट किट्स एंड नेविस के बीच करों से संबंधित सूचना के आदान–प्रदान (टीआईईए) के लिए न्यूयॉर्क में 11 नवंबर, 2014 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

त्रिनिदाद और टबैगो (टीएंडटी)

भारत के त्रिनिदाद और टबैगो (टीएंडटी) के साथ घनिष्ठ और मित्रवत संबंध हैं जो 1845 से बने हुए हैं जबकि 225 भारतीय श्रमिकों के साथ पहला जहाज त्रिनिदाद के किनारे पहुंचा। देश की कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत आज भारतीय वंशजों की है जिनकी गतिशील भारतीय संस्कृति है। मौजूदा सरकार 1962 में देश की स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय व्यक्तियों की अध्यक्षता में दूसरी सरकार है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा त्रिनिदाद के ऊर्जा मंत्री श्री केविन रामनारिने ने भारत तथा टीएंडटी के बीच ऊर्जा क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार–विमर्श करने के लिए 21वें विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस के दौरान मास्को में मुलाकात की।

मिशन ने परस्पर हित के मुद्दों पर भारतीय पक्ष के साथ संपर्क को सुकर बनाने के लिए प्रबुद्ध व्यक्तियों और संगठनों को शामिल करते हुए प्रवासी परिषद् की स्थापना करने की कदम उठाया। भारत जाने कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत को 17 युवा प्रवासियों को भेजा गया ताकि वे अपने पूर्वजों के देश का प्रथम ज्ञान प्राप्त कर सके।

आयुष के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पारंपरिक दवाओं और चिकित्सीयय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार–विमर्श करने के लिए टीएंडटी की यात्रा की जिसके दौरान चिकित्सीय पौधों के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। टीएंडटी का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2014 में नई दिल्ली में आयोजित छठे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में भाग लिया।

आईसीसीआर के तत्वाधान में सुश्री कल्पना पटवारी की अध्यक्षता में छः सदस्यीय भोजपुरी संगती दल और सुश्री इन्दिरा नाइक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय शास्त्रीय दल ने मई और अक्तूबर, 2014 में टीएंडटी की यात्रा की जो क्रमशः भारतीय आगमन दिवस तथा दीवाली उत्सव के साथ था। इन समूहों ने देश भर में कई प्रस्तुतियां दी।

भारतीय मिशन ने त्रिनिदाद और टबैगो के अंतर धार्मिक संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ''आधुनिक समय की समस्याओं को हल करने के लिए प्राचीन बुद्धि और आत्मिक उत्तर'' पर घनिष्ठता से सहयोग किया। सुश्री इला गांधी, महात्मा गांधी की पोती इस आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि थी जिसमें कई देशों के प्रबुद्ध विद्वानों ने भाग लिया।

आईटीईसी कार्यक्रम टीएंडटी में मानव संसाधन के विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम बना रहा। वर्ष 2013–14 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत भारत को 25 विद्वान भेजे गए। हाल ही में त्रिनिदाद और टबैगो में खाद्य मंत्री को चावल की खेती में एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया है ताकि त्रिनिदाद के प्राधिकारियों को चावल की खेती में संशोधन करने में सहायता दी जा सके।

■■

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

9

संयुक्त राष्ट्र में भारत

संयुक्त राष्ट्र महा सभा का 69वां सत्र

संयुक्त राष्ट्र महा सभा के 69वें सत्र का नियमित सत्र न्यूयॉर्क में सितंबर, 2014 में आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24–30 सितंबर, 2014 को सामान्य वाद–विवाद के लिए अधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की। यह प्रधानमंत्री द्वारा मई, 2014 में कार्यग्रहण करने के पश्चात् पहली यात्रा थी। 27 सितंबर, 2014 को सामान्य वाद–विवाद के दौरान अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने वर्तमान राजनीतिक वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार और पुनर्गठन की कड़ी वकालत की। उन्होंने 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ तक सुधार पूरे किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने इसके विकास के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण के लिए भारत की इच्छा व्यक्त की उन्हें कहा कि ''किसी राष्ट्र का भविष्य उसके पड़ोसी से जुड़ा होता है। इसलिए मेरी सरकार ने हमारे पड़ोसियों के साथ मित्रता और सहयोग को आगे बढ़ाने पर उच्चतम वरीयता प्रदान की है।''

प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समुचित शांति, अधिक स्थिर और समावेशी वैश्विक विकास तथा विकास के लिए इकट्ठे काम करने और एक अधिक रहने लायक तथा सतत विश्व का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया। 2015 पश्चात् विकास एजेंडा पर उन्होंने कहा कि ''गरीबी उन्मूलन 2015 पश्चात् विकास एजेंडा का प्रमुख हिस्सा बना रहना चाहिए और इस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए।''

इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आतंकवाद नए आकार और नाम ले रहा है तथा कोई भी देश इस खतरे से परे नहीं है, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने के लिए केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया। इस प्रयास के प्रतीक के रूप में उन्होंने विश्व समुदाय को इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में व्यापक समझौता किया जाए। उन्होंने अपने क्षेत्र में आतंकवादी पनाहों की अनुमति देने वाले अथवा आतंकवाद को उनकी नीति के हथियार के रूप में उपयोग करने वाले राष्ट्रों की भर्त्सना की।

यूएनजीए में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले उन्होंने श्री बान की – मून, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक की जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार, मौसम परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा सहित कई मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 23 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2014 तक यूएनजीए सत्र के लिए न्यूयॉर्क यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने जी4, ब्रिक्स, आईबीएसए, सार्क, जीसीसी त्रोइका, भारत–सीईएलएसी क्वार्टेड तथा एनएएम फिलिस्तीन समिति की बैठकों में भाग लिया। उन्होंने 53 सदस्य राष्ट्रमंडल के नेताओं के साथ भी वार्ता की और राष्ट्रमंडल मंत्रालयी कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। उन्होंने यूके, चीन, सुडान, मालदीव, किरिगिज गणराज्य, नाइजीरिया, नार्वे, ग्रीस और इजरायल के अपने समकक्षों के साथ बैठकें की। इन बैठकों के दौरान हुए विचार–विमर्शों में भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्र तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक महत्व के मुद्दे शामिल थे।

विदेश मंत्री 2 अक्तूबर, 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए संयुक्त राष्ट्र मेमोरियल में संयुक्त राष्ट्र के बहादुर शांति सैनिकों की याद में पुष्पांजलि देने वाली पहली विशिष्ट व्यक्ति बनी। यह मेमोरियल 1988 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात् स्थापित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री बान की मून का भारत दौरा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यू एन एस जी) श्री बान की मून ने 9 से 13 जनवरी, 2015 के दौरान भारत का आधिकारिक दौरा किया। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल था। यू एन एस जी ने अपना दौरा गुजरात से शुरू कियाए जहां वह विशिष्ट मेहमान थे और 11 जनवरी 2015 के वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने प्रधान मंत्री के साथ सम्मेलन के अवसर पर भी स्वतंत्र विचारों का आदान–प्रदान किया था। चर्चा में 2015 पश्चात विकास कार्य–सूचीए जलवायु–परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित मुद्दे भी कवर किए गए थे। उन्होंने वदोदरा का दौरा भी कियाए जहां उन्होंने 10 मेगावाट के नहर के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र का

प्रधानमंत्री यूएनजीए में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री बान की–मून से मुलाकात करते हुए।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 25 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर ग्रुप–4 बैठक के दौरान ब्राजील, जर्मनी और जापान के अपने ब्राजीलियाई समकक्षों के साथ।

उद्घाटन भी किया। अपने दिल्ली दौरे के दौरान यू एन एस जी ने भारत के राष्ट्रपति और लोक सभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से भी द्विपक्षीय बातचीत की। यू एन एस जी ने इंडिया एण्डदि यूना इटेड नेशन्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड‰ विषयपर विदेशी मामलों की भारतीय परिषद (इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स) में 13वां सप्रु हाउस लेक्चर भी दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को यू एन जी ए के 69वें सत्र के उच्च स्तरीय खण्ड में अपने अभिभाषण में वैश्विक शासन के संस्थानों के सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और कहा, ''हमें देशों के बीच ईमानदारी से बातचीत और वचनबद्धता की आवश्यकता है। मैं यह उस दार्शनिक परम्परा की विचारधारा से कह सकता हूं, जहां से मैं आया हूं। हमारे प्रयास यहां संयुक्त राष्ट्र में से आरंभ होने चाहिए। हमें सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र का सुधार करना चाहिए और इसे अधिक लोकतांत्रिक तथा भागीदारी वाला बनाना चाहिए। वे संस्थान जो 20वीं सदी की अत्यावश्यकताओं को दर्शाते हैं वे 21वीं सदी में प्रभावी नहीं होंगे। इसके असंगत होने का जोखिम और उसका समाधान करने की क्षमता किसी में भी न होने का जोखिम उठाना होगा।''

उन्होंने आगे यह कहकर अपनी बात खत्म की कि ''हम ऐतिहासिक क्षण में जी रहे हैं। हर युग को उसकी विशेषता से परिभाषित किया जाता है और हर पीढ़ी को इस बात से याद किया जाता है कि उसने अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ मिलकर कैसे मुकाबला किया। हमारे ऊपर अब अपनी चुनौतियों का सामना करने की जिम्मेदारी है। इस महा सभा के अलावा कहीं भी यह घोषणा नहीं की गई है। अगले वर्ष हम सत्तर हो जाएंगे। हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हमें 80 अथवा 100 वर्ष के होने तक इंतजार करना चाहिए। आइए, हम 2015 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सुधारने का अपना वायदा पूरा करें। आइए 2015 पश्चात विकास कार्यसूची संबंधी अपनी शपथ पूरी करें ताकि यहां संपूर्ण विश्व में हममें नई आशा और विश्वास हो। आइए 2015 को चिरस्थायी विश्व के लिए नया आमूल परिवर्तन काल बनाएं। आइए इसे एक साथ नए सफर का आरंभ बनाएं।''

प्रधान मंत्री के अभिभाषण से पहले, भारत, ब्राजील, जर्मनी, और जापान से जी–4 विदेश मंत्री 69वें यू एन जी ए के अवसर पर 25 सितंबर, 2014 को न्यूयार्क में मिले, जहां सुरक्षा परिषद सुधार हेतु स्वतंत्र विचारों का आदान–प्रदान किया गया था। बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में मंत्रियों ने 21वीं सदी की भूराजनीतिक वास्तविकताओं के आलोक में सुरक्षा परिषद की अपनी सतत वचनबद्धता पर बल दिया। वे इस बात पर सहमत हुए कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का प्रभावी सामना करने के लिए सुरक्षा परिषद की कठिनाइयां सुरक्षा परिषद सुधार संबंधी तत्काल आवश्यकता की दमदार चेतावनी है, जो इसे अधिक व्यापक प्रतिनिधिक, कुशल और पारदर्शी बनाती है और इस प्रकार से उसकी प्रभाविकता और न्याय संगतता तथा उसके निर्णयों के कार्यान्वयन को और बढ़ाती है।

मंत्रियों ने अपनी चिंता व्यक्त की कि संयुक्त राष्ट्र की नींव रखने के 70 वर्ष पश्चात सुरक्षा परिषद के पहले और एकमात्र बार सुधार के 50 वर्ष पश्चात सहस्त्राब्दी सम्मेलन के 15 वर्ष पश्चात और 2005 विश्व सम्मेलन के 10 वर्ष पश्चात जब हमारे नेताओं ने एकमत से सुरक्षा परिषद के जल्द सुधार के लिए कहा था– अभी भी चर्चाओं में बाधाएं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की प्रक्रिया को अन्तहीन कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अतः जी–4 मंत्रियों ने अपने सभी साथियों के संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ का अंततः एक ऐसी प्रक्रिया का ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आमंत्रित किया, जो 20 वर्ष तक खींच गई और सितंबर 2015 तक हमारे राज्याध्यक्षों और सरकार द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास करने के लिए कहा।

उन्होंने व्यापक सुरक्षा परिषद की स्थायी और गैर–स्थायी दोनों श्रेणियों में प्रतिनिधित्व करने वाले अफ्रीका सहित विकासशील देशों की महत्ता पर अपने मतों की पुष्टि भी की।

उन्होंने सुरक्षा परिषद के सुधार के बारे में चर्चा पर सिविल सोसाइटी, मीडिया और शैक्षणिक समुदाय की अधिक भागीदारी संबंधी आवश्यकता को भी स्वीकारा और ब्राजील, भारत और जापान द्वारा निकाय के सुधार की तात्कालिकता व संबंधी चर्चा को व्यापक बनाने के लिए आयोजित सेमिनारों को याद किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः प्रधान मंत्री की पहल

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यू एन जी ए के 69वें सत्र के उच्च स्तरीय खण्ड में अपने अभिभाषण के दौरान प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषणा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से समर्थन की मांग की।

उन्होंने कहा, ''योग हमारी प्राचीन परम्परा का सबसे बहुमूल्य उपहार है। योग दिमाग और शरीर की एकता, विचार और कार्यवाही, संयम और सिद्धि, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य और सेहत के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है। यह केवल व्यायाम ही नहीं है बल्कि यह स्वयं विश्व और प्रकृति के साथ एकात्मकता की भावना को खोच निकालता है। अपनी जीवनचर्चा में परिवर्तन और चेतना का सृजन करके, यह जलवायु परिवर्तन का सामना करने में हमारी मदद कर सकता है। आइए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने के लिए कार्य करें।

आह्वान के अनुरूप, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की कार्यसूची मद 124 प्रतिशत 'ग्लोबल हेल्थ एण्ड फॉरेन पॉलिसी' के तहत संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के लिए प्रारूप महासभा संकल्प पेश किया। 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए प्रारूप संकल्प के सह–प्रायोजक के रूप में 167 सदस्य राज्यों (27 नवंबर, 2014 की तिथि तक) ने रिकॉर्ड संख्या में हस्ताक्षर किए।

8वां अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के न्यासी परिषद स्थित भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित विशेष समारोह में 2 अक्तूबर, 2014 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें बांग्लादेश के दौरे पर आए वित्त मंत्री के साथ ही 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम कुटेसा और संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव श्री जेन इलिआसन ने भाग लिया। समारोह के दौरान, विदेश मंत्री ने अध्यक्ष, महासभा को महात्मा गांधी का चरखा चलाते हुए एक आदमकद चित्र प्रस्तुत किया। इस समारोह में 80 से भी अधिक स्थायी प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के बड़ी संख्या में छोटे बच्चों के साथ ही विभिन्न स्थायी मिशनों से शिष्टमंडलों ने भाग लिया। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों के बोल के साथ ही श्री कारमन मूरे के समूह द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

शांति स्थापना

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना संबंधी मुद्दों पर अपनी सक्रिय भागीदारी, समग्र वक्तव्य देकर और शांति स्थापना संबंधी विशेष समिति के भीतर वाद–विवाद में भाग लेकर जारी रखी है। एक वर्ष के व्यवधान के पश्चात शांति स्थापना संबंधी विशेष समिति के प्रतिवेदन को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिए जाने के लिए हमारी ओर से किए गए प्रयासों का भी आंशिक योगदान रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तीन शांति स्थापना वाद–विवाद में भाग लिया और 69वें यू एन जी ए की चौथी समिति में शांति स्थापना वाद–विवाद में भी भाग लिया। भारत ने लंबे समय से लंबित पड़े सेना प्रतिपूर्ति दरों की समीक्षा को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे 2014 में औपचारिक रूप दिया गया था। शांति स्थापना कार्यों संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्य दल के साथ भागीदारी के साथ ही शांति स्थापना के क्षेत्र में अन्य बहुपक्षीय पहलों में भागीदारी शांति स्थापना के क्षेत्र में किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप थे। शांति स्थापना अधिदेश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में देशों की सहायता करने में सेना पुलिस की अधिक भागीदारी और जब कभी आवश्यक हो आधारभूत वास्तविकताओं के माध्यम से उनकी समीक्षा की मांग को संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों के साथ लगातार उठाया गया था।

कुल मिलाकर, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश रहा है और उसके अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिदेशित 69 शांति स्थापना मिशनों में से 48 में 1,80,000 सैनिकों से ज्यादा को भेजा है। हाल ही में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए सैन्य दल भेजने वाला तीसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राष्ट्र रहा है, जिसके दस संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में 7,884 सेना और पुलिस कर्मी नियोजित हैं। मुख्य शांति स्थापना कार्यों में भारत की उपस्थिति में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (4035), दक्षिणी सूडान (2073), लेबनान (885), हेती (429), लाइबेरिया (250) और सीरिया इसराइल सीमा पर गोलन हाइट्स (190) शामिल हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों और पुलिसकर्मियों द्वारा उच्च स्तरीय निष्पादन ने उन्हें विश्व भर में ख्याति प्रदान की।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्य विभाग के अवर महासचिव श्री हर्व लैडसोस के नेतृत्व में 4 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 25 जुलाई 2014 को भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल रक्षा सचिव, विशेष सचिव (आई ओ एण्ड पीओएल), विदेश मंत्रालय, थल सेना के चीफ, थल सेना के वाइस चीफ और थल सेना के डिप्टी चीफ (आई एस एण्ड टी) से मिला।

जल दस्युता

सोमालिया के तट पर जल दस्युता संबंधी संपर्क समूह (सी जी पी सी एस) की 16वीं समग्र बैठक न्यूयार्क में 14 मई 2014 को हुई थी। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर–मंत्रालयी शिष्टमंडल ने उच्च जोखिम क्षेत्र और पानी के जहाजों पर निजी रूप से संविदा पर रखे गए सैन्य सुरक्षा कार्मिकों सहित अपनी चिंताओं को उठाया।

सी जी पी सी एस की 17वीं समग्र बैठक 28 अक्तूबर 2014 को दुबई में हुई। श्री विनोद कुमार, अपर सचिव (अंतर्राष्ट्रीय संगठन) विदेश मंत्रालय ने समग्र बैठक हेतु भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

अक्तूबर, 2014 के अंत में जल–दस्युओंकी कैद से 7 भारतीय नाविकों को छुड़वाया। आज की तिथि में कोई भी भारतीय बंधक नहीं है, किंतु फिर भी हम एच आर ए के संबंध में चिंतित हैं।

राष्ट्रमंडल

भारत राष्ट्रमंडल का सबसे अधिक सदस्य वाला राज्य है, जहां संघ की कुल जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत है। भारत ने संघ के कार्यकलापों में अपनी भागीदारी जारी रखी। भारत राष्ट्रमंडल बजट में अंशदान करने वाला चौथा सबसे बड़ा अंशदाता है और तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि में योगदान देने वाला पांचवां सबसे बड़ा अंशदाता है।

विदेश मंत्री राष्ट्रमंडल बैठक में।

संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टीशिप काडांसेल में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर विशेष स्मारक समारोह की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री (2 अक्टूबर 2014 न्यूयार्क)

भारत 2013–15 की अवधि के लिए पुनः संरूपित राष्ट्रमंडल मंत्रालयी कार्य समूह (सी एम ए जी) का सदस्य है। ऑकलैण्ड में सरकारी बैठक के राष्ट्रमंडल अध्यक्षों (सी एच ओ सी एम) में स्थापित सी एम ए जी राष्ट्रमंडल के मूलभूत राजनैतिक मूल्यों के गंभीर अथवा निरंतर उल्लंघन को देखता है। इसमें नौ सदस्य राज्यों से विदेश मंत्री शामिल होते हैं। फिजी में एक निर्वाचित सरकार बनाने के बाद, आज सी एम ए जी की औपचारिक कार्यसूची में कोई भी देश नहीं है।

राष्ट्रमंडल महासचिव श्री कमलेश शर्मा ने राष्ट्रमंडल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हेतु 1–2 सितंबर, 2014 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रमंडल महासचिव ने प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की।

राष्ट्रमंडल मंत्रीमण्डलीय कार्य समूह (सी एम ए जी) की बैठक 12–13 मार्च, 2015 को लंदन में होगी, जिसमें विदेश मंत्री भाग लेंगी। चर्चा का केन्द्र राष्ट्राध्यक्ष के मुख्य राजनैतिक मूल्य और सभी राष्ट्रमंडल राज्यों द्वारा उनका निष्ठा से पालन किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता होता है।

आतंकवाद

भारत सभी प्रयासों का पुरजोर समर्थन करता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्राधिकार के भीतर उन सभी प्रयासों का जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाते हैं। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा सहमत वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति (ग्लोबल काउंटर टेरेरिज्म स्ट्रेटजी) आतंकवाद का विरोध करने के लिए सार्वभौमिक रूप से सहमत रणनीतिक ढांचा है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी समीक्षा रणनीति (जी सी टी एस) की चौथी द्वैवार्षिक समीक्षा 12–13 जून 2014 को आयोजित हुई थी। भारत ने जी सी टी एस के विचार–विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया और जी सी टी एस संबंधी सकल्पों को अंतिम रूप देने में योगदान दिया।

24 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विदेशी आतंकवादी लड़ाकुओं के बढ़ते खतरे पर संकल्प 2178 (2014) स्वीकार किया, जिसने विश्व में लगभग प्रत्येक देश को प्रभावित किया है। हालांकि भारत वर्तमान में यू एन एस सी का सदस्य नहीं है, भारत समान सोच रखने वाले देशों के साथ इस संकल्प की बातचीत के दौरान पूर्णतः शामिल था।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबंध शासन पद्धति के सदस्य राज्यों द्वारा कठोर अनुपालन किया जाता है और उल्लंघन के मामले में प्रतिबंध शासन पद्धति का उल्लंघन करने वाले सदस्य देशों के विरूद्ध यू एन एस सी प्रतिबंध समिति द्वारा ठोस कार्यवाहीकी जाती है, 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति जैसे यू एन एस सी की प्रतिबंध समितियों के साथ भागीदार बने रहे। इसके अतिरिक्त, हमने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद–विरोधी निकायों जैसे आतंकवाद विरोध कार्यकारी निदेशालय, जिसकी कार्यशाला में हमने नियमित रूप से भाग लिया और सुरक्षा परिषद की अलकायदा और तालिबान निगरानी टीम के साथ संगठित रूप से कार्य भी किया।

धर्म निरपेक्ष आंदोलन

संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने धर्म–निरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है, क्योंकि इसने विकासशील देशों को सामूहिक रूप से राजनैतिक और आर्थिक मुद्दों के क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है। शीत युद्ध के बाद के युग में, एन ए एम में निःसंदेह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिर भी आंदोलन अत्यधिक संगत बना रहा, विशेष रूप से उन मुद्दों के संबंध में जहां दक्षिण के देशों के मध्य विचारों की समानता संभव होती है। भारत ने अलजीयर्स (अलजीरिया) में 26–29 मई, 2014 को आयोजित मध्याविधि एन ए एम मंत्रीमण्डलीय सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अगला एन ए एम सम्मेलन 2015 में वेनेजुएला में होना निश्चित हुआ है।

लोकतांत्रिक पहल

i. **लोकतांत्रिक समुदाय (सीओडी):** लोकतांत्रिक समुदाय पूरे विश्व में लोकतांत्रिक नियमों का समर्थन करने और लोकतांत्रिक व्यवहारों और संस्थाओं को सुदृढ़ करने के एक समान लक्ष्य की तलाश में सरकारों सिविल समाज और निजी क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रों का एक वैश्विक अंतर–सरकारी गठबंधन है। भारत लोकतांत्रिक समुदाय का एक सक्रिय सदस्य रहा है और यह इसके शासकीय परिषद का एक सदस्य भी है। शासकीय परिषद की बैठकें तिमाही आधार पर की जाती हैं। 24 सितंबर, 2014 को न्यूयार्क में भारत ने यूएनजीए के अनुदेशों के अनुरूप सी ओ डी की शासकीय परिषद की उच्च स्तरीय वैश्विक संस्थाओं में लोकतंत्र अभाव से संबंधित मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।

ii. **बाली लोकतंत्र फोरमः** 7वीं बाली लोकतंत्र फोरम (बीडीएफ सात) की बैठक विकसति हो रही क्षेत्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाः 21वीं सदी में राजनैतिक विकास, सार्वजनिक भागीदारी और सामाजिक–आर्थिक प्रगति की चुनौतियां विषय पर 10–11 अक्तूबर, 2014 को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा के और अधिक रचनात्मक भूमिका निभाने और संयुक्त राष्ट्र के नीति

नियंता निकाय के रूप में काम करने की आवश्यकता का उल्लेख किया।

iii. **संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि (यू एन डी ई एफ):** भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच भागीदारी के परिणामस्वरूप 2005 में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि (यू एन डी ई एफ) की शुरूआत की गई थी। वर्तमान में भारत यू एन डी ई एफ का दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता है जिसने नवंबर 2014 तक 31.56 मिलियन अमरीकी डॉलर की संचयी राशि का अंशदान दिया है। भारत इस राशि को लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं के संवर्धन के लिए एक प्रभावी तंत्र मानता है ओर सर्वोच्च शासकीय निकाय सलाकहार बोर्ड के सदस्य के रूप में यू एन डी ई एफ में एक अहम भूमिका निभाता है।

चुनाव

भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। भारत को वर्ष 2015–2017 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार आयोग (एच आर सी) के लिए पुनः चुन लिया गया। न्यू यार्क स्थित यू एन जेनरल एसेम्बली में 21 अक्तूबर, 2014 को मानवाधिकार परिषद के चुनाव में एशिया–प्रशांत समूह में भारत को सबसे अधिक वोट (162) मिले।

भारत को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में भी वर्ष 2015 से 2017 के कार्यकाल के लिए भी पुनः चुन लिया गया जिसका आयोजन 29 अक्तूबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया गया था जिसमें एशिया प्रशांत समूह से भारत को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे। अप्रैल 2014 में आयोजित आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के अनुसांगिक निकायों के चुनाव में भारत को 2015 से 2017 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड में ध्वनि मत से चुन लिया गया, और गैर सरकारी संगठनों की समिति में वर्ष 2015 से 2018 के कार्यकाल के लिए पुनः चुन लिया गया और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास आयोग में 2015 से 2018 के कार्यकाल के लिए चुना गया। श्री चंद्र शेखर दास गुप्ता को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति में वर्ष 2015 से 2017 के कार्यकाल के लिए पुनः चुन लिया गया। भारत द्वारा मनोनीत सुश्री जगजीत पवाड़िया, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड में वर्ष 2015 से 2020 के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। भारत द्वारा मनोनीत डा. रसिक रविन्द्र केन्द्रीय अंटार्कटिक तथा समुद्र अनुसंधान केन्द्र के पूर्व निदेशक को न्यू यार्क में जून 2014 में समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकार राष्ट्रों की 24वीं बैठक के दौरान कमिशन आन लिमिट्स आफ कांटिनेंटल शेल्फ में चुन लिया गया।

आर्थिक तथा विकास संबंधी मुद्दें

समूह–77 और चीन की 50वीं वर्षगांठ संबंधी शिखर सम्मेलन

समूह–77 जो संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा समूह है, की 50वीं वर्षगांठ संबंधी शिखर सम्मेलन की मेजबानी सांताक्रूज शहर में क्लूरीनेशनल स्टेट आफ बोलीविया द्वारा 14 से 15 जून, 2014 तक की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पेरू में तैनात भारतीय राजदूत श्री मनप्रीत बोहरा द्वारा किया गया जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य भी दिया।यह शिखर सम्मलेन 'सांताक्रूज उद्घोषणा' को स्वीकार करके संपन्न होगा जिसमें विकासशील देशों के विकासमूलक तथा अन्य प्राथमिकताओं और साथ ही वर्ष 2015 के उपरांत विकास एजेंडा पर आगामी चर्चा में उनके सरोकारों का भी उल्लेख है।

जमीन से घिरे विकासशील देशों पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

जमीन से घिरे विकासशील देशों पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आस्ट्रिया के विएना शहर में 3 से 5 नवंबर 2015 तक आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डा.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जमीन से घिरे विकासशील देशों के लिए विएना कार्ययोजना 2014–2015 को स्वीकार किया गया जिसके तहत जमीन से घिरे विकासशील देशों के विशिष्ट सरोकारों तथा उनके समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है।

जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र

वर्ष 2014 के बाद जनसंख्या तथा विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्ययोजना से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई पर आम सभा का एक विशेष सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में 22 सितंबर, 2014 को आयोजित किया गया। वर्ष 2014 आई सी पी डी की 20वीं वर्षगांठ है जिसका आयोजन सितंबर 1994 में काहिरा में किया गया था, जिसके दौरान और अधिक समान एवं चिरस्थायी विश्व के निर्माण के लिए एक स्मरणीय 20 वर्षी कार्य योजना को 179 सरकारों द्वारा स्वीकार किए गए। यह कार्ययोजना जो औपचारिक तौर पर वर्ष 2014 में समाप्त होने वाली थी, को 65वें सत्र में आम सभा में संकल्प पारित करके बढ़ाया गया। जनसंख्या तथा विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए भारत ने आई सी पी डी कार्ययोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का उच्चस्तरीय घटक

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का उच्चस्तरीय घटक 2014 का आयोजन न्यूयार्क में 7–9 जुलाई, 2014 तक किया गया है। राजदूत श्री अशोक कुमार मुखर्जी, न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इस सत्र के उच्चस्तरीय घटक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और उन्होंने "वर्ष 2015 में सहत्राबदि विकास लक्ष्यों को पूरा करने और भविष्य में चिरस्थायी विकास लाभ के लिए चालू तथा उदीयमान चुनौतियों को पूरा करना" विषय पर वार्षिक मंत्रालयी समीक्षा प्रस्तुत की।

उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के तत्वाधान में उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच की प्रथम बैठक 30 जून से 9 जुलाई 2014 तक आयोजित की गई। उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच में परिचर्चा के दौरान चिरस्थायी विकास के सभी तीन आयामों में प्रगति पर बल दिया गया।

विकास सहयोग मंच (डी सी एफ)

विकास सहयोग मंच की चौथी द्विवार्षिकी बैठक न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 10 से 11 जुलाई, 2014 तक आयोजित की गई। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के उच्चस्तरीय घटक के एक भाग के रूप में आयोजित की गई। वर्ष 2014 विकास सहयोग मंच के तहत वर्ष 2015 के उपरांत विकास एजेंडे के संदर्भ में "विकास सहयोग का भविष्य" विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्री कुमार तुहीन, संयुक्त सचिव (डी पी ए–II), विदेश मंत्रालय ने विकास सहयोग मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यू एन ई एस सी ए पी)

भारत ने एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग के 70वें वार्षिक सत्र में भाग लिया। यह सत्र थाईलैंड में राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण 23 मई, 2014 को और मुख्य द्वितीय सत्र 4–8 अगस्त, 2014 तक आयोजित किया गया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री हर्षवर्धन श्रृंग्ला, थाईलैंड में भारत के राजदूत और एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 'साझा प्रगति हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिवीटी' विषय पर मंत्रालयी घटक में राष्ट्र की ओर से वक्तव्य दिया।

श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बैंकाक में 19 तथा 20 नवंबर, 2014 को "महिला पुरूष समानता तथा महिला सशक्तिकरणः बीजिंग+20 समीक्षा" विषय पर एशिया तथा प्रशांत सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। श्रीमती मेनका गांधी ने पुलिस जेनरल अब्दुल सेंगसिगकाउ, थाईलैंड के सामाजिक विकास तथा मानव सुरक्षा मंत्री से मुलाकात की और सुश्री मेंग जियाउसी, राष्ट्रीय बाल एवं महिला कार्यकारी समिति की उपाध्यक्ष, स्टेट काउंसिल आफ चाइना और श्रीमती मेहर आफ्रोज, बांग्लादेश के महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ इस सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात की।

श्री किरण रीजीजू गृह राज्यमंत्री ने बैंकाक में 27 तथा 28 नवंबर 2014 को एशिया तथा प्रशांत में सिविल रजिस्ट्रेशन और व्हाइटल स्टेटिस्टिक्स विषय पर प्रथम मंत्रालयी सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय वक्तव्य देने के अलावा श्री रीजीजू ने "सिविल रजिस्ट्रेशन तथा स्मार्ट निवेश के रूप में पहचान प्रणाली" विषय पर मंत्रालयी पैनल में हिस्सा लिया।

भारत ने 19–21 मई, 2014 के दौरान पट्टाया में संपन्न एशिया–प्रशांत सतत विकास मंच के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। भारत ने 18–20 अगस्त, 2014 के दौरान बैंकॉक में यूएनईएससीएपी सामाजिक विकास समिति के तीसरे सत्र में भाग लिया। भारत ने 14–17 अक्टूबर, 2014 के दौरान बैंकॉक में संपन्न सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी समिति और परिवहन समिति दोनों के चौथे सत्रों में भाग लिया। दूतावास ने यूएनईएससीएपी के सहयोग से बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र में 2 अक्टूबर, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया।

26 दिसम्बर, 2014 को हिंद महासागर सुनामी की 10वीं वर्षगांठ पर स्मृति समारोह के अवसर पर भारत सरकार ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का दृढ़ता से सामना करने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए सुनामी, आपदा और जलवायु संबंधी तैयारियों के लिए ईएससीएपी न्यास कोष में एक मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान देने की घोषणा की।

डॉ. शमसाद अख्तर, अवर महासचिव, संयुक्त राष्ट्र और ईएससीएपी के कार्यकारी सचिव ने 2–6 फरवरी, 2015 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और वाणिज्य मंत्रालय में बैठकें की।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ)

श्रीमती शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव (डीआईपीपी), वाणिज्य विभाग ने ''समग्र तथा सतत् औद्योगिक विकास रणनीति और साधन को बढ़ावा'' विषयक पहले मंच और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास

संगठन (यूएनआईडीओ) की कार्यक्रम तथा बजट समिति (पीबीसी) के 30वें सत्र में 23–26 जून, 2014 के दौरान भाग लिया। श्रीमती शुभ्रा सिंह ने महानिदेशक, यूएनआईडीओ से भी मुलाकात की और वे यूएनआईडीओ में अन्य पदाधिकारियों से मिलीं।

सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य विभाग के निमंत्रण पर यूएनआईडीओ के उप महानिदेशक, श्री टी. निशिकावा ने 25 सितम्बर, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा प्रवर्तित ''मेक इन इण्डिया'' अभियान में महानिदेशक की ओर से भाग लिया।

मिशन ने ''समग्र तथा सतत् औद्योगिक विकास के लिए निवेश बढ़ाने हेतु भागीदारी'' नामक दूसरे यूएनआईडीओ समग्र तथा सतत् औद्योगिक विकास (आईएसआईडी) मंच में भाग लिया, जो 4–5 नवम्बर, 2014 के दौरान वियना में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री वान की मून ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

मिशन ने 25–26 नवम्बर, 2014 के दौरान वियना में यूएनआईडीओ के औद्योगिक विकास बोर्ड (आईडीबी) की बैठक के 42वें सत्र में भाग लिया।

यूएन–आवास

यूएन–आवास द्वारा आयोजित 7वें विश्व शहरी मंच (डब्ल्यूयूएफ–7) का आयोजन ''विकास में शहरी समानता–शहर जीवन के लिए'' विषय पर 7–11 अप्रैल, 2014 के दौरान मेडिलीन, कोलंबिया में किया गया था। इस बैठक में 140 से अधिक देशों की सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों, शहरी व्यावसायिकों, स्थानीय प्राधिकारियों और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग 22,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 7वें विश्व शहरी मंच (डब्ल्यूयूएफ–7) के दौरान जारी की गई मेडिलीन घोषणा से वर्ष 2015 के बाद विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी और वर्ष 2016 में आवास और सतत् शहरी विकास (आवास–III) पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन में भी सहायता मिलेगी। भारत की ओर से आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के दो अधिकारियों और हुडको तथा बीएमटीपीसी से एक–एक अधिकारी सहित 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

डॉ. जोन क्लॉस, कार्यकारी निदेशक, संयुक्त राष्ट्र आवास ने 12–15 नवम्बर, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन एवं शहरी विकास मंत्रीय सचिव, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालयय सचिव, शहरी विकास और सचिव, (ईआर) और इसी मंत्रालय के अपर सचिव (आईओ) से मुलाकात की।

पर्यावरण संबंधी मुद्दे

जलवायु परिवर्तन विषयक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रकाश जावेड़कर ने 1–13 दिसम्बर, 2014 के दौरान लीमा, पेरू में संपन्न जलवायु परिवर्तन विषयक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों (सीओपी–20) के 20वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल (सीएमपी–10) के पक्षकारों के सम्मेलन की 10वीं बैठक भी शामिल थी। डरबन मंच पर अधिक कार्रवाई के लिए 'कार्रवाई के लिए लीमा आह्वान' नामक गठित तदर्थ कार्य समूह का परिणाम दस्तावेज़ दिसम्बर, 2015 में पेरिस में आयोजित किए जाने वाले सीओपी–21 में 2020 की अवधि के बाद के लिए एक व्यापक, संतुलित और न्यायोचित परिणाम को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लीमा सम्मेलन से पूर्व वर्ष भर अनेक बैठकें और तैयारी हेतु सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसमें मार्च, जून और अक्टूबर में बॉन, जर्मनी में अंतरसत्रीय बैठकें शामिल थीं। भारत ने इन बैठकों में सक्रियता से भाग लिया और अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चर्चाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेसिक समूह के भाग के रूप में भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ समन्वय लीमा सम्मेलन से पूर्व भी जारी रहा, जिसमें नई दिल्ली (अगस्त) और सनसिटी, दक्षिण अफ्रीका (अक्टूबर) में बैठकें शामिल थीं। भारत ने समान मानसिकता वाले विकासशील देशों (एल एम डी सी) के समूह के साथ भी घनिष्ठता से काम किया जिसने लीमा सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

जलवायु शिखर सम्मेलन–2014

संयुक्त राष्ट्र महासचिव वान की मून ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 23 सितम्बर, 2014 को जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य जारी किया और परिवहन पर कार्यसत्र में भी भागीदारी की। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु भारत द्वारा की गई पहलों को रेखांकित किया।

सतत् विकास लक्ष्य और 2015 के बाद का विकास कार्यक्रम

एसडीजी के एक सैट हेतु बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के खुले कार्यसमूह की स्थापना करने पर मिला अधिदेश

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सम्मेलन (रियो+20) का महत्वपूर्ण निर्णय था, जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए रियो–डि–जेनेरियो में जून, 2012 में हुआ था। सतत् विकास लक्ष्यों (एस डी जी) पर खुला कार्यसमूह ने 14–18 जुलाई, 2014 को न्यूयॉर्क में संपन्न अपनी 13वीं बैठक में अपना कार्य समाप्त किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा को एसडीजी के लिए एक प्रस्ताव सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 169 लक्ष्यों को शामिल करते हुए OWG के इस प्रस्ताव में 17 लक्ष्यों का समूह है। वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त करने के मुख्य लक्ष्य के साथ ओडब्ल्यूजी द्वारा संस्तुत लक्ष्यों के समूह को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के सतत् विकास के तीन आयामों में समान रूप से बाँटा और संतुलित किया गया है। ओडब्ल्यूजी के प्रस्ताव में विकासशील देशों को वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और प्रणालीगत सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक भागीदारी पर समर्पित लक्ष्य शामिल हैं, जबकि 'कार्यान्वयन के साधन' के रूप में पृथक लक्ष्यों को भी प्रत्येक लक्ष्य के तहत शामिल किया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ओडब्ल्यूजी के तहत चर्चाओं और बातचीत में सक्रियता से भागीदारी की और इक प्रक्रिया के विकासाभिमुख परिणाम प्राप्त करने में अर्थपूर्ण योगदान दिया।

2015 के प्रश्चात् विकास कार्यक्रम– चरण निर्धारण

महासभा के 68वें सत्र के दौरान, महासभा के अध्यक्ष द्वारा 2015 के पश्चात् विकास मसौदा के लिए मंच की स्थापना करने हेतु जनवरी 2015 से अंतर–सरकारी विचार–विमर्श सहित कई उच्च स्तरीय आयोजन तथा विषयक (Thematic) वाद–विवाद का आयोजन किया गया था, जिसे सितंबर 2015 में अपनाए जाने का अनुमान है। इन घटनाक्रमों में महिलाओं का योगदान, 2015 के पश्चात् विकास मसौदे के लिए युवा एवं सभ्य समाज (Civil Society); 2015 के पश्चात् विकास मसौदा में मानवाधिकार तथा कानूनी नियम; उत्तर–दक्षिण का योगदान, दक्षिण–दक्षिण, त्रिकोणीय सहयोग तथा 2015 के पश्चात् विकास मसौदा में विकास हेतु ICT (भागीदारी की भूमिका) स्थिर तथा शांतिपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना तथा जल, स्वच्छता एवं 2015 के पश्चात् विकास मसौदा में धारणीय ऊर्जा सहित विविध प्रकार के शीर्षकों को शामिल किया गया है। भारत ने इन आयोजनों में बढ–चढकर हिस्सा लिया था तथा महत्वकांक्षी, व्यापक एवं न्यायोचित 2015 के पश्चात् विकास मसौदे के साथ गरीबी उन्मूलन को अपने मुख्य एवं सर्वसमावेशी उद्देश्य तथा धारणीय विकास के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण स्तंभों पर संतुलित बल देने को विस्तार देने पर अपने विचारों को साझा किया था।

धारणीय विकास वित्त पोषण (ICESDF) पर विशेषज्ञों की अंतर–सरकारी समिति

वर्ष 2012 में रियो में आयोजित धारणीय विकास (रियो+20) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसरण में, रियो+20 शिखर सम्मेलन द्वारा अधिदेशाधीन धारणीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संसाधनों को गतिशील बनाने तथा उनके प्रभावी उपयोग की सुविधा प्रदान करने की प्रभावी धारणीय विकास वित्त पोषण रणनीति पर विकल्पों का प्रस्ताव रखते हुए रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन, प्रभावोत्पादकता पर विचार, मौजूदा उपकरणों तथा अवसंरचनाओं का सामंजस्य तथा सहक्रिया तथा अतिरिक्त पहलों के मूल्यांकन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वाधान में धारणीय विकास वित्त–पोषण पर 30 विशेषज्ञों की अंतर–सरकारी समिति गठित की गई थी। समिति ने अगस्त 2013 के बाद से पांच सत्रों का आयोजन किया तथा 8 अगस्त 2014 को अपना कार्य समाप्त कर लिया था। समिति ने 2015 के पश्चात् लक्ष्यों को प्राप्त करने में संसाधनों को गतिशील तथा उनके प्रभावी उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभावी वित्तीय रणनीति तैयार करने के लिए पर्याप्त संख्या में नीतिगत विकल्पों पर शामिल की सिफारिशों की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय में अपर आर्थिक सलाहकार सुश्री राजश्री रे इस समिति के लिए भारतीय विशेषज्ञ के रूप में नामित थीं।

मर्करी पर मीनामाता कन्वेंशन

मर्करी पर मीनामाता कन्वेंशन को 10 अक्टूबर 2013 को कुमामोतो, जापान में आयोजित पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र राजदूत श्री अशोक कुमार मुखर्जी, भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 30 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की ओर से मर्करी पर मीनामाता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

UNEP के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा (UNEA) का उद्घाटन सत्र 23–27 जून 2014 तक नैरोबी में आयोजित किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य हेतु राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च स्तर खंड पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। उच्च स्तरीय खंड का विषय "ए लाईफ ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल" था, इसमें दो मुद्दों– (i) धारणीय उपभोग तथा उत्पादन सहित धारणीय विकास लक्ष्यों तथा (ii) वन्य जीवों का अवैध व्यापार, को संबोधित किया गया था। UNEA में पर्यावरण मंत्रियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों, सरकारी प्रतिनिधियों, सभ्य समाज तथा बिजनेस लीडरों सहित लगभग 1200 सहभागियों ने

भाग लिया था। प्रेसीडेंट श्री केन्याटा, UNSG श्री बान की मून तथा 68वें UNGA के प्रेसीडेंट श्री जॉन आशे ने भी महासभा को संबोधित किया था। महासभा द्वारा मंत्रालयी आउटकम दस्तावेज तथा 18 संकल्पों एवं विभिन्न पर्यावरण मुद्दों पर संकल्पों को स्वीकार किया गया था।

अदिस अबाबा में 13–16 जुलाई, 2015 को आयोजित किए जाने वाले विकास के लिए वित्त पोषण (FID) पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आउटकम दस्तावेजों के लिए जनवरी 2015 में अंतर–सरकारी वार्ताएं शुरू की गई।

रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के सरकारी पक्षकार के तौर पर भारत ने रामसार कन्वेंशन स्थायी समिति की 48वीं बैठक में भाग लिया था। यह बैठक रामसार सचिवालय मुख्यालय, ग्लैंड, स्वीटजरलैंड में 26 से 30 जनवरी 2015 तक आयोजित की गई थी।

सामाजिक तथा मानवीय मुद्दे

यू–एन मानवाधिकार परिषद (HRC)

भारत को एशिया प्रशांत दल में मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 2015–17 की अवधि के लिए पुनः चुना गया था। मानवाधिकार परिषद (HRC) के सदस्य के तौर पर भारत ने 2014 में आयोजित तीन नियमित सत्रों तथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ईराक तथा फिलीस्तीन पर तीन विशेष सत्रों की कार्यवाहियों में भाग लिया था। मानवाधिकार परिषद के ब्यूरो में एशिया प्रशांत दल के उपाध्यक्ष के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हुए भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वर्ष के दौरान भारत ने भी मानवाधिकार परिषद द्वारा अपनाए गए कुछ संकल्पों को तैयार करने में रचनात्मक तौर पर भाग लिया था। मानवाधिकार परिषद के विभिन्न विषयपरक मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा सीरिया, कोरिया जनवादी गणराज्य (डी पी आर के), म्यांमा, ईरान तथा श्रीलंका एवं फिलीस्तीन पर देश के जुड़े संकल्पों को अपनाकर उन देशों से जुड़ी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया है। मानवाधिकार परिषद ने भारत द्वारा पहल की गई 'समुद्री प्रवासियों के मानवाधिकारों' पर प्रेसीडेंशियल कथन को अपनाया है। यूनीवर्सल आवधिक समीक्षा (यू पी आर) प्रक्रिया में दिए गए कुल 42 देशों के रिपोर्ट जिसमें से 22 राष्ट्रीय रिपोर्टों पर विचार किया गया उसमें वक्तव्य देते हुए भारत ने भी रचनात्मक रूप से हिस्सा लिया। भारत ने कतर के यू पी आर के लिए त्रोईका के सदस्य के तौर पर भी सेवाएं प्रदान की।

महत्वपूर्ण संधि निकायों तथा मानवाधिकार तंत्रों में चार लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों ने विशिष्टता के साथ अपनी सेवाएं देना जारी रखा जिनमें राजदूत दिलीप लाहिड़ी (उपाध्यक्ष नस्ल भेद समापन समिति), राजदूत चंद्रशेखर दास गुप्ता (उपाध्यक्ष आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति), श्री आनंद ग्रोवर (उच्च मानक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिकार विषय पर विशेष रिवोर्ताज), श्री किशोंर सिंह (शिक्षा का अधिकार संबंधी विशेष रिपोर्तज) शामिल हैं।

बाल अधिकार (सी आर सी) और महिलाओं के प्रति पक्षपात समाप्त करने से संबंधित समितियों को प्रस्तुत भारत की रिपोर्टें (सीईडीएडब्ल्यू)

सचिव महिला एवं बाल विकास, श्री शंकर अग्रवाल ने बाल अधिकार कन्वेंशन से संबंधित संयुक्त तीसरी एवं चौथी सामाजिक रिपोर्ट और सी आर सी पर दो वैकल्पिक प्रोतोकाल से संबंधित प्रारंभिक रिपोर्टें दिनांक 2–3 जून, 2014 को प्रस्तुत की। सचिव (महिला एवं बाल विकास) श्री शंकर अग्रवाल ने 2 जुलाई, 2014 को महिलाओं के प्रति पक्षपात समाप्त करने से संबंधित समिति को भारत की संयुक्त चौथी तथा पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय शिष्टमण्डल का भी नेतृत्व किया। भारतीय शिष्टमण्डल की इन दो संधि निकायों के साथ वार्ता में विभिन्न विधायी दस्तावेज व्यापक रूप से प्रस्तुत किए गए, कार्यक्रम तथा नीतियां तय की गईं ताकि प्रत्येक बच्चे के लिए उसके जीने, सर्वांगीण विकास, संरक्षा तथा भागीदारी और साथ ही महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के पक्षपात को समाप्त करने संबंधी अधिकारों को पूर्णतः परिणामोन्मुख बनाने के लिए एक सक्षम माहौल सृजित किया जा सके।

दोनों संधि निकायों अर्थात् सीआरसी तथा सीईडीएडब्ल्यू ने संगत अभिसमयों के कार्यान्वयन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इसके व्यापक आकार तथा कई कानूनों तथा पहलकदमियों को शामिल करने के बावजूद क्रमशः बच्चों के अधिकार प्राप्त करने तथा साथ ही महिलाओं के विरुद्ध भेद–भाव खत्म करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की अनुशंसा की है। समितियों ने कन्वेन्शनों के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने की भी अनुशंसाएं कीं।

भारत और यूएन महिलाएं

यूएन महिला अवर महासचिव और कार्यकारी निदेशक श्रीमती फुम्ज़िले मलाम्बो ज्कुका ने यूएनजीए के लिए लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण से संबंधित मामलों, 2015 के बाद के विकास एजेंडा का मसौदा तैयार करने तथा संबंधित मामलों पर चर्चा हेतु विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से उनकी न्यूयॉर्क (अक्टूबर–2014) यात्रा के दौरान मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, विदेश मंत्री ने यूएन महिलाओं तथा उसके मामलों पर भारत की वचनबद्धता और सहयोग के अनुरूप यूएन महिलाओं के लिए भारत के योगदान की 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की पांचवी किस्त सौंपी।

यूएन महिला कार्यकारी निदेशक ने 7–11 नवम्बर, 2014 को भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष, विदेश मंत्री तथा यूपीए अध्यक्षा से मुलाकात की। वह मेन इन्गेज (पूरे विश्व में 400 एनजीओ की एक सहयोगी) द्वारा आयोजित नजदीक हो रही दुनिया में पुरुष तथा पुरूषत्व सहित विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर दूसरी वैश्विक संगोष्ठी की मुख्य वक्ता थी।

भारत ने 9–10 फरवरी, 2014 को होने वाले यूए महिला कार्यकारी बोर्ड के पहले नियमित सत्र में भाग लिया। भारत वर्ष 2013–16 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए इस बोर्ड का सदस्य है।

भारत 2014–18 की अवधि के लिए कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन का एक चयनित सदस्य है। कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन का 59 वां सत्र 9–20 मार्च, 2015 को हुआ। सीएसडब्ल्यू के 59वें सत्र का मुख्य केंद्र बीजिंग की घोषणा के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा और कार्रवाई के लिए मंच था।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)

भारत को 4 जून, 2014 के पेरिस में यूनेस्को में 2014–2018 तक चार–वर्षीय अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा हेतु अंतर–सरकारी समिति के लिए दस देशों के बीच हुए चुनाव में सबसे अधिक वोटों (135/142) से चुना गया था। वर्ष 2014–15 के लिए भारत को समिति के वाइस चेयर के रूप में चुना गया था। जून–2014 में, भारत सर्वसम्मति से यूनेस्को राष्ट्रमंडल समूह के चेयर पर्सन के रूप में भी चुना गया था।

वर्तमान में, भारत यूनेस्को की निम्नलिखित 9 समिति /निकायों में हैः कार्यपालक बोर्ड; विश्व धरोहर समिति अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईबीसी); अंतर सरकारी बायोइथिक समिति (आईजीबीसी); अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी); यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद (आईबीई) जिनेवा, स्विटज़रलैंडय ईएफए स्टीयरिंग समितिय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति तथा यूनेस्को राष्ट्रमंडल समूह का चेयर पर्सन है।

यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री इरिना बोवोका ने 23–26 नवम्बर, 2014 तक भारत में, यूनेस्को द्वारा भारत सरकार सहित अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहभागियों के सहयोग से आयोजित ''उपवर्जन से सशक्तिकरण तकः विकलांग व्यक्तियों के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की भूमिका'' पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरकारी दौरा किया।

भारत ने नवम्बर, 2014 में 10वीं मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक में ई–9 चेयर पाकिस्तान को सौंपी। ई–9 पहल, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे नौ अत्यधिक प्रदूषित विकासशील देशों के लिए वर्ष 1993 में नई दिल्ली में ईएफए शिखर सम्मेलन में स्थापित एक मंच है।

यूनेस्को के अधिदेश जैसे शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार एवं सूचना के क्षेत्र में 2015 पूर्व विकास एजेंडा को बनाने हेतु यूनेस्को में चल रहे विचार–विमर्श में भारत शामिल है।

विश्व धरोहर समिति के सदस्य के रूप में भारत ने 15–25 जून, 2014 को दोहा में हुए विश्व धरोहर समिति के 38वें सत्र में भाग लिया। बैठक के दौरान भारत के दो स्थल 'रानी–की–वाब' और 'द ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क कंसर्वेशन एरिया' विश्व धरोहर सूची में अभिलेखित किए गए। इस अभिलेखन के साथ, भारत के विश्व धरोहर सूची में कुल 32 स्थान हैं तथा अभिलेखित स्थानों की संख्या के अनुसार कुल मिलाकर पांचवे स्थान पर है। विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान दूसरी मुख्य उपलब्धि भारत की वर्ष 2014–15 के लिए वाइस–चेयर के रूप में नियुक्ति रही है। भारत ने दोहा में विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान अपनी महत्वकांक्षी परियोजना 'मौसमः समुद्र मार्ग और सांस्कृतिक परिदृश्य' को भी आरंभ किया।

भारत ने 24–28 नवम्बर, 2014 तक पेरिस में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा हेतु अंतर–सरकार समिति के 9वें सत्र में भाग लिया। जंदिआल गुरू, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच परंपरागत पीतल और तांबे शिल्प के बर्तन बनाना, पर भारत के नामांकन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अभिलेखित किया गया। अब भारत के इस सूची में 11 तत्व हैं और भारत का सूची में लिखे गए तत्वों की संख्या के अनुसार कुल मिलाकर आठवां स्थान है।

भारत ने 18–20 जून, 2014 तक पेरिस में यूनेस्को, मुख्यालय में हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईएचपी) की अंतर–सरकारी परिषद के 21वें सत्र में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया। इस सत्र के दौरान भारत ने विश्व की बड़ी नदी पहल के प्रारंभ के लिए संशोधित प्रस्ताव का समर्थन किया।

भारत ने 01–04 जुलाई, 2014 तक यूनेस्को, पेरिस में हुए अंतर–सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के 47वें कार्यपालक परिषद में भी भाग लिया। भारत ने कार्यपालक सचिव की नियुक्त के लिए आवेदकों की चयनित सूची तैयार करने के लिए विचार–विमर्श प्रक्रिया तथा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र अभियान 50वीं वर्षगांठ पहल (आईआईओई–2) में आईओसी की सहभागिता पर हुई चर्चा में भाग लिया।

शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (यूएनएचसीआर)

भारत ने 29–30 सितम्बर, 2014 को जिनेवा में हुए शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (यूएनएचसीआर) के कार्यकारिणी के 65वें

सत्र में भाग लिया। इस वर्ष के दौरान भारत यूएनएचसीआर के विचार–विमर्श में शामिल हुआ और इसके आधारभूत अधिदेश पर कायम रहते हुए, शरणार्थी समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त कार्यों का समर्थन किया तथा शरणार्थी समस्या के उपयुक्त समाधानों के लिए कार्य किया। भारत ने मेज़बान देशों में प्रतिक्रिया और प्रबंधन के क्षमता निर्माण में यूएनएचपीआर के प्रयासों का समर्थन किया, जिसमें शरणार्थी द्वारा अपनी जीविका निर्वहन हेतु क्षमता विकास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग ने शरणार्थियों के लिए भारत की नीति और दृष्टिकोण की सराहना की।

प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम)

भारत ने 25–28 नवंबर, 2014 तक जिनेवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) परिषद के 105वें सत्र के विचार–विमर्श के दौरान और कार्यक्रम तथा वित्त (एससीएपी) संबंधी स्थायी समिति की बैठक में रचनात्मक भूमिका निभाई। भारत ने आईओएम से आग्रह किया कि वह बड़े लक्षित देशों से समुद्र में प्रवासियों की सुरक्षा सहित मानवीय सीमा प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने और सभी साझेदारों के लिए लाभप्रद स्थिति पैदा करने के लिए कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और सभी साझेदारों के लिए लाभप्रद स्थिति पैदा करने के लिए कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रवासियों के बीच जागरूकता पैदा करें और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए मानवीय तथा व्यवस्थित प्रणाली स्थापित करें।

भारत ने प्रवासियों और उनके परिवारों सहित सभी साझेदारों के बीच विचारों और दृष्टिकोणों के आदान–प्रदान के लिए अर्थपूर्ण मंच तैयार करने के लिए नवीन, प्रभावशाली और वहनीय लागत वाले तरीके पर सामाजिक मीडिया के उपयोग की वकालत की।

भारत ने समुद्रपारीय विकास सहायता (ओडीए) के साथ धनप्रेषण को जोड़ने के लिए राज्य/गैर राज्य एक्टर्स के कार्यकलापों का विरोध करना जारी रखा। भारत ने धनप्रेषण को किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अर्जन मानने की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर दिया और इसे अपने विवेक के अनुसार उपयोग में लाने के उनके एकाधिकार पर भी पूरा जोर दिया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति (यूएनआईएसडीआर)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक (यूएनआईएसडीआर) ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) हेतु 2015 के बाद के फ्रेमवर्क के निगोशिएट जीरो प्रारूप के लिए आपदा न्यूनीकरण पर तीसरे विश्व सम्मेलन के प्रेपकॉम–1 को 14–15 जुलाई और प्रेपकॉम–2 को 17–18 नवंबर, 2014 तक आयोजित किया। भारत विकासशील देशों विशेषकर कम विकसित देशों की चिंताओं की वकालत करने के लिए बैठक में रचनात्मक रूप से सक्रिय रहा और शीघ्र चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समर्थन करने के लिए आपदा तैयारी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संभावित तथा पर्याप्त संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने आपदाओं के अनुवीक्षण के लिए गैर–आदेशात्मक अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के समर्थन में तर्क दिया और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने और आपदाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय सरकारों के लिए नीतिगत उपाय की वकालत की। यूएनआईएसडीआर ने इस वर्ष आपदाओं के प्रबंधन में भारत के प्रयासों, विशेषकर सटीक भविष्यवाणी, प्रभावी शीघ्र चेतावनी, समय से लोगों को बाहर निकालने और सुसमन्वित आपदा पश्चात उपायों के माध्यम से मानवीय मौतों पर हुदहुद और फाइलीन तूफानों के प्रभाव को न्यूनतम करने में भारत के प्रयासों की सराहना की।

गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजु ने 22–26 जून, 2014 के दौरान बैंकाक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर छठें एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। श्री किरण रिजिजु ने सम्मेलन में उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की सह–अध्यक्षता की। देश का वक्तव्य देते समय श्री रिजिजु ने अक्तूबर, 2013 में भारत के पूर्वी तट से टकराने वाले तूफान 'फाइलीन' से पहले एक मिलियन से अधिक लोगों को बाहर निकालने में भारत सरकार द्वारा किए गए समय से पूर्व उपायों के महत्व को बताया।

प्रवास तथा विकास पर वैश्विक मंच

भारत ने प्रवास तथा विकास पर वैश्विक मंच (जीएफएमडी) के लिए वैश्विक मंच की सातवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया, जो 14–16 मई, 2014 के दौरान स्टॉक में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और विकास पर मूल, प्रवास तथा निर्दिष्ट स्थान के देशों के बीच वार्ता को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि द्वारा किया गया और इसमें प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय से भी एक प्रतिनिधि शामिल थे। प्रवासियों के लिए मूल और निर्दिष्ट स्थान के प्रमुख देश के रूप में भारत ने भी जीएफएमडी के संचालन समूह, मंच के भविष्य पर मूल्यांकन दल और जेनेवा में संपन्न मंच की बैठक के साथी राष्ट्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने लागत प्रभावी प्रयासों के साथ प्रवास की व्यवस्थित, मानवीय, पारदर्शी और वहनीय लागत संबंधी बातचीत को बढ़ावा दिया और इसका समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास आयोग (यूएन–सीएसटीडी)

भारत वर्ष 2015 से प्रारंभ होने वाली चार वर्षीय अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास आयोग (सीएसटीडी) का सदस्य पुनः निर्वाचित हुआ है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 12–16 मई, 2014 तक जेनेवा में संपन्न इसके सत्रहवें सत्र में भाग लिया। भारत ने 30 अप्रैल, 2014 तक यूएन सीएसटीडी कार्य समूह पर उन्नत सहयोग (डब्ल्यूजीईसी) की चौथी और अंतिम बैठक में एक सदस्य के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। डब्ल्यूजीईसी के सदस्यों के बीच विचारों के सतत विचलन के कारण, यह सीएसटीडी के 17वें सत्र के लिए कोई संस्तुति नहीं कर सका, जब इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2005 में सूचना सोसाइटी पर विश्व शिखर सम्मेलन द्वारा अंगीकार किए गए ट्यूनिश एजेंडे में यथानिहित उन्नत सहयोग के कार्यान्वयन पर संस्तुतियां करने के लिए अधिदेश दिया गया था।

भारत ने जिनेवा में 26–28 नवंबर, 2014 तक संपन्न सीएसटीडी के अंतर–सत्रीय पैनल के दौरान ठोस योगदान किया। इस सत्र में, डब्ल्यूएसआईएस परिणामों के कार्यान्वयन की सीएसटीडी के दस वर्ष की समीक्षा के प्रारूप रिपोर्ट पर और सीएसटीडी सचिवालय द्वारा तैयार किए गए 'अंतर्राष्ट्रीय इटरनेट सार्वजनिक नीति के चित्रण कार्य' पर रिपोर्ट पर चर्चा हुई, जिस पर मई, 2015 में सीएसटीडी के 18वें वार्षिक सत्र में आगे चर्चा की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र औषध और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी)

यूएनओडीसी के कार्यकारी महानिदेशक श्री यूरी फेडोतोव ने राजस्व सचिव के आमंत्रण पर 2–4 दिसंबर, 2014 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान वे यूएनओडीसी की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए और भारत के साथ इस क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए संगत प्राधिकारियों से वार्ता में संलग्न रहे। उन्होंने मादक द्रव्य नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से मुकाबला करने में और बड़ी नेतृत्व भूमिका निभाने पर विचार करने के लिए भारत सरकार को निमंत्रित किया। इन्होंने वित्त मंत्री, राजस्व सचिव, विशेषगृह सचिव और विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (अंतर्राष्ट्रीय संगठन) से मुलाकात की।

स्वापक औषध आयोग (सीएनडी का संयुक्त राष्ट्र महासभा विशेष सत्र (यूएनजीएएसएस) तैयारी खंड 3 दिसंबर, 2014 को वियना में हुआ था। 57वीं सीएनडी और 23वें सीसीपीसी का संयुक्त पुनः बुलाया गया सत्र 4–5 दिसंबर, 2014 को हुआ।

सीएनडी का 58वां सत्र 9–17 मार्च, 2015 तक वियना में होना तय किया गया है।

वर्ष के दौरान संगत मंत्रालयों के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराध नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर यूएनओडीसी की अनेक बैठकों में भाग लिया।

विश्व स्थास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

भारत ने 19–24 मई, 2014 तक जिनेवा में संपन्न 67वें विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) में भाग लिया। पोलियो के उन्मूलन में भारत के प्रयासों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सराहना की गयी। भारत ने वहनीय, स्तरीय, सुरक्षित दवाओं, वैक्सिनों की न्ययोचित उपलब्धता के लिए उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय नीति स्पेस की आवश्यकताओं और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया और उल्लेख किया कि 30 अगस्त, 2003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन निर्णय और ट्रिप्स घोषणा के दोहा सहित डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स करार के तहत उपलब्ध लचीलेपन के पूर्ण उपयोग का उल्लेख किया। इससे विकासशील देशों को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायता मिलेगी।

जलवायु तथा स्वास्थ्य के बीच संबंध विश्व स्वास्थ्य असेम्बली की वार्ताओं के दौरान भारत ने जलवायु परिवर्तन के समाधान के महत्व पर चर्चा की। असेम्बली में हुई विभिन्न वार्ताओं में भारत ने सहभागिता की जिसमें गैर–राज्य कर्ताओं के साथ ढांचागत जुड़ाव सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के विनियोजन प्रतिजीवाणु रोधी सहित जीवाणु रोधी उपशमन पर विचार–विमर्श हुआ।

भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यसूची संचालन समूह की 24 जनवरी, 2015 को आयोजित पहली बैठक में हिस्सा लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 136वें सत्र (24 जनवरी से 03 फरवरी, 2015) में अन्य बातों के साथ–साथ जीव प्रतिरोधी कार्य योजना (एएमआर), वायु प्रदूषण और स्वास्थ्यए डब्ल्यू एच ओ में गैर राज्य कर्ताओं की भूमिका, घटिया, नकली, गलत लेबलयुक्त, जाली, कृत्रिम (SSFFC) चिकित्सा उत्पादों तथा डब्ल्यू एच ओ से संबंधित वित्त पोषण मामलों पर एक वैश्विक कार्य योजनापर विश्व स्वास्थ्य असेम्बली के एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। भारत ने 25 जनवरी, 2015 को इबोला विषाणु रोग पर आयोजित विशेष सत्र में भी भाग लिया जिसमें इबोला के फैलने पर विचार किया गया।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.)

भारत ने जेनेवा में 28 मई से 12 जून 2014 तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 103रे सत्र में भाग लिया। आई.एल.सी. के दौरान भारत की गरीबों तथा उपेक्षित श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक उन्नयनोमुखी स्कीमों की सराहना की गई। इस संबंध में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)

आदि को आई.एल.ओ. घटकों के दायरे में श्रमिकों हेतु महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय माना गया। भारत शासी निकाय तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन सहित आई.एल.ओ. में चल रही सुधार प्रक्रिया में संलग्न रहा।

आई. एल. सी. के दौरान, बंधुआ मजदूरी को प्रभावी तरीके से समाप्त करने में बाधाएं संरक्षण और क्षतिपूर्ति उपायों को लागू करने में होने वाली कमियों को दूर करने के लिए बंधुआ श्रमिक अभिसमयए 1930 (संख्या 29) को समर्थन देने के लिए एक नयाचार तथा संस्तुति को स्वीकार करने हेतु भारत ने अपना समर्थन दिया। भारत ने दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई। भारत ने अनुरोध किया कि 2015 के बाद की विकास कार्यसूची में श्रमिक गतिशीलता को दीर्घकालिक विकास के एक मुद्दे के रूप में मान्यता दी जाए।

सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 3–13 नवंबर, 2014 के दौरान जेनेवा में आयोजित आई. एल. ओ. शासी निकाय के 322वें सत्र में भाग लिया। भारत ने उल्लेख किया कि मानकों को लागू करने संबंधी समिति के मुद्दों के समाधान के लिए आई. एल. सी. के मंच पर त्रिपक्षीय विचार–विमर्श करना सर्वोत्तम उपाय होगा। भारत ने उल्लेख किया कि सामाजिक न्याय के साथ समावेशी वैश्वीकरण के अंतिम लक्ष्य को केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा जबकि इन आई. एल. ओ. सामाजिक न्याय घोषणा, 2008 के अनुरूप अपनी विकास अनुसूची में बढ़िया कार्य को बढ़ावा दें।

भारत ने समुद्री यात्रियों की पहचान संबंधी दस्तावेजों के संबंध में आई. एल. ओ. के अभिसमय संख्या 185 पर विचार–विमर्श के लिए 04–06 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित विशेषज्ञों की बैठक मेंए जेनेवा में आई. एल. ओ. मुख्यालय में 16–19 फरवरी को आयोजित रोजगार के गैर मानक फार्मों पर श्रमिक विशेषज्ञों की समिति की बैठक में तथा सरकारी समूह, नियोक्ता समूह एवं श्रमिक समूह की 23–25 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित बैठक में भाग लिया।

एच. आई. वी./एड्स (यूनेड्स) पर साझा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमः

यूनेड्स के 34वें कार्यक्रम समन्वयन बोर्ड (बी. सी. सी.) की बैठक 1–3 जुलाई, 2014 के दौरान जेनेवा में आयोजित की गई। कार्यसूची की अनेक मदों पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें 2015 से बाद की अवधि के लिए एड्स प्रतिक्रिया की अद्यतन स्थिति विषय वस्तु खण्ड एच. आई. वी.ए किशोर एवं युवा, पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। पूरे विश्व में एच. आई. वी. के साथ जी रहे लाखों लोगों के जीवन वर्धन की उम्मीद बढ़ाने वाली कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत की अनवरत चल रही अग्रणी भूमिका की पी. सी. बी. में सराहना की गई।

यूएनआईएडीएस की 35 वी कार्यक्रम समन्वयक बोर्ड (पीसीबी) बैठक 9–11 दिसम्बर, 2014 तक आयोजित हुई थी। बैठक के दौरान, एचआईवी/एड्स के विरुद्ध लड़ाई में भारत की एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में भूमिका के साथ–साथ कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाली दवाईयों कि पहुंच को प्रसारित करने के लिए, जो कि जीवन प्रदान कर रही हैं और पूरे विश्व में एचआईवी के साथ रह रहे लोगों के लिए आशा है, के लिए सराहना की गई। पीसीबी बैठक ने कार्यसूची मदों, के साथ–साथ एड्स पर 2015 उत्तरार्द्ध घटनाक्रम कार्यसूची पर प्रतिक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी और एचआईवी के रोकथाम/ईलाज के लिए एंटी–रेटरोवायरल दवाईयों के सामरिक प्रयोग पर चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)

भारत बूसान में दक्षिण कोरिया में 20 अक्तूबर से 07 नवम्बर, 2014 तक आयोजित आईटीयू पूर्णाधिकारी सम्मेलन (पीपी–14) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के लिए पुनः निर्वाचित हुआ। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ–साथ, सचिव (दूरसंचार) ने सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पीपी–14 के दौरान सक्रिय रूप से विभिन्न पैनल चर्चाओं और समिति पदों में भाग लिया। पीपी–14 के दौरान, आईटीयू के शीर्ष प्रबंधन पदों के साथ–साथ महासचिव और आईटीयू परिषद के चुनाव हुए।

भारत आईटीयू द्वारा 10–13 जून, 2014 तक जेनेवा में आयोजित डब्ल्यूएसआईएस +10 उच्चस्तर कार्यक्रम के प्रारंभिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। डब्ल्यूएसआईएस +10 उच्चस्तर कार्यक्रम में भाग लेने वाली यूएन एजेंसियों के अधिदेश के तहत डब्ल्यूएसआईएस के परिणामों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और विगत 10 वर्षों की उपलब्धियों का जायजा लिया। भारत ने सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) के दोनों चरणों के परिणामों पर अनुवर्ती कार्रवाई और पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन किया और डब्ल्यूएसआईएस के 2003 में जेनेवा सम्मेलन में सहमत हुए विभिन्न कार्रवाई श्रृंखलाओं पर विगत 10 वर्षों में भारत द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों और भविष्य के लिए इसके लक्ष्यों को रेखांकित किया।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान संगठन (आईएनटीओएसएआई)

भारत की उपलेखानियंत्रक व लेखा परीक्षक श्रीमती सुमन सक्सेना और सीएजी कार्यालय के निदेशक श्री राजदीप सिंह ने सामाजिक योजना पर वियाना में 5–7 नवम्बर, 2014 तक आयोजित आईएनटीओएसएआई कार्यदल की प्रथम वैयक्तिक बैठक और आईएनटीओएसएआई शाषी बोर्ड की 66वीं बैठक मे भाग लिया।

अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू)

लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भारतीय संसदीय प्रतिनिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें राज्य सभा के माननीय उपसभापति, प्रो. पी.जे. कुरियन, पांच सांसद, और लोक सभा तथा राज्य सभा के महासचिव शामिल थे, जिन्होंने जेनेवा में 10–16 अक्टूबर, 2014 तक अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) के 131वें आईपीयू सभा में भाग लिया। भारतीय संसदीय प्रतिनिमंडल ने आईपीयू सभा के चारों खंडों, पैनल चर्चा, विभिन्न मुद्दों पर आईपीयू समिति के सत्रों, आपातकालीन सत्रों और पूर्व तथा पश्च–सभा सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

लोक सभा अध्यक्ष ने आईपीयू द्वारा 04–05 सितम्बर, 2014 तक जेनेवा में आयोजित संसद के महिला अध्यक्षों के 9वें वार्षिक बैठक में भी भाग लिया। अध्यक्ष ने दो दिवसीय बैठक के सत्रों में भाग लिया और मुख्य वक्तव्य भी दिया।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसरण में, स्विटज़रलैंड द्वारा जेनेवा अभिसमयों के न्यासी की हैसियत से 17 दिसम्बर, 2014 को चौथे जेनेवा अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत ने जेनेवा अभिसमयों के एक उच्च संविदाकारी पक्षकार के रूप में सम्मेलन भाग लिया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक घोषणा को अपनाया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों के पूर्ण रूप से सम्मान की आवश्यकता को दोहराया।

मोन्ट्रक्स दस्तावेज मंच की संवैधानिक बैठक

भारत ने 16 दिसम्बर, 2014 को जेनेवा में आयोजित मोन्ट्रक्स दस्तावेज के ''संवैधानिक बैठक'' के प्रारंभिक सत्र में भाग लिया। स्विटज़रलैंड ने मौजूदा स्थापित सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के व्यावहारिकात को दोहराते हुए निजी सैन्य और सुरक्षा कंपनियों के संचालन को विनियमित करने के लिए 'मोन्ट्रक्स दस्तावेज' की शुरुआत की और देशों द्वारा पीएमएससी रखने की बाध्यता निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई विधिक खामी नहीं है।

भारत ने भी मोन्ट्रक्स +05 सम्मेलन में भाग लिया और निजी सुरक्षा कंपनियों के संचालन को विनियमित करने में दस्तावेज में मौजूद न्यायिक खामियों के मुद्दे पर चर्चा में योगदान दिया।

इबोला के प्रभाव को कम करने में भारत का सहयोग

भारत ने इबोला वायरस बीमारी के प्रभाव से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में व्यापक योगदान दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहलों और इबोला आपातकालीन सहयोग के लिए यूएन मिशन की स्थापना को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। भारत ने इबोला के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहु–भागीदार न्याय निधि में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंशदान दिया। महासचिव द्वारा सितम्बर, 2014 में सभी संबंधित संयुक्त राष्ट्र के तत्वों के प्रयासों को संयुक्त करने और इबोला प्रभाव के वैश्विक नियंत्रण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए इबोला प्रभाव से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रतिक्रिया प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त, भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इबोला के फैलाव को रोकने संबंधित इसके प्रयासों में सहयोग के लिए 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंशदान दिया। द्विपक्षीय आधार पर भारत ने अगस्त–2014 में तीन प्रभावित देशों सियारा लियोन, लाइबेरिया और गिन्नी गणराज्य के लिए चिकित्सा आपूर्तियों के खरीद के लिए तत्काल 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया।

भारत ने 05 दिसम्बर, 2014 को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 'इबोला–नियत विकास के लिए खतरा' पर विशेष बैठक में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के आग्रह पर दिवाली तथा गुरुपर्व के महत्व को मानते हुए अन्य अपनाए जाने वाले संकल्पों के बीच 29 दिसम्बर, 2014 को एक संकल्प अपनाया। इसके अतिरिक्त, संकल्प को मुख्यालय के संयुक्त राष्ट्र निकायों और अन्य केंद्रों में भी परिभाषित किया गया, जहाँ प्रत्येक वर्ष इन दिवसों को मनाने हेतु आधिकारिक बैठकों के आयोजन को रोकने के लिए कहा गया।

वैधानिक और संधि प्रभाग

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून

आतंकवादः

आतंकवाद और उससे संबंधित मुद्दे मई–जून 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद–निरोधक रणनीति की चौथी समीक्षा और अक्तूबर, 2014 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को मिटाने के उपायों की कार्यसूची के अंतर्गत छठी समिति में आतंकवाद और उससे संबंधित मुद्दे चर्चा के विषय थे। रणनीति की समीक्षा के फलस्वरूप 13 जून, 2014 को संकल्पना 68/276 के रूप में संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा एक परिणाम दस्तावेज स्वीकार किया गया। छठी समिति ने दिसंबर, 2014 में स्वीकार कने के लिए आम सभा द्वारा विचार–विमर्श करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद निरोधक उपायों पर जारी की गई संकल्पना को स्वीकार किया। भारत ने रणनीति की समीक्षा एवं छठी समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया।

दोनों मंचों पर आतंकवाद की जोरदार भर्त्सना की गई और यह इंगित किया गया कि जहां कहीं भी, किसी के द्वारा या किसी के विरूद्ध किसी भी उद्देश्य, कारण अथवा विचारों के लिए की गई

आतंकवादी घटना को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। परिणाम दस्तावेज में आतंकवादियों को सुरक्षित रास्ता देने को नकारा गया है और आतंकवादियों के प्रत्यर्पण अथवा सजा देने का प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान उन लोगों के लिए भी है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराते हैंए योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं अथवा ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

दो मंचों के परिणाम दस्तावेजों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विदेशी आतंकवादी लड़ाके, व्यक्ति जो अपराध करने, उसकी योजना बनाने अथवा तैयारी करने, अथवा आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपने देश के अलावा दूसरे देशों की यात्रा करने वालों से होने वाले बड़े खतरों पर गहरी चिंता प्रकट की।

व्यावहारिक उपायों के अलावा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों से निपटने के लिए विधिक शासन पद्धति को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता स्वीकार की गई है। अतंर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रों से हर संभव प्रयास करने हेतु आगे आने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में, छठी समिति ने अपने कार्यकारी समूह की सिफारिशों पर विचार किया और आम सभा से सिफारिश की थी कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक मसौदा व्यापक समझौते के शेष मुद्दों पर स्थायी प्रगति के लिए और समय देने की आवश्यकता थी, इसलिए प्रारूप समझौते की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आम सभा के सत्तरवें सत्र में छठी समिति के कार्यकारी समूह की स्थापना की जाए। छठी समिति ने भी सभी सदस्य राष्ट्रों को अंतर सत्र अवधि के दौरान अपने प्रयासों को दो गुना करने को प्रोत्साहित किया।

महासागर और सामुद्रिक कानून

सामुद्रिक नियम, 1982 संबंधी संयुक्त राष्ट्र समझौता में स्टेट पार्टियों की बैठक में, अनौपचारिक सलाहकार प्रक्रिया, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र परिधि के बाहर सामुद्रिक जैव विविधता का संरक्षण और धारणीय उपयोग संबंधी कार्यकारी समूह सामुद्रिक पर्यावरण मूल्यांकन नियमित प्रक्रिया, कंटिनेंटल शेल्फ सीमा आयोग, और अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण की बैठक सहित विभिन्न मंचों पर महासागर और सामुद्रिक नियम संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जाता है।

स्टेट पार्टी की 24वीं बैठक (9–13 जून, 2014) के दौरान भारत के पूर्व सदस्य डॉ. राजन के इस्तीफे के कारण उनके शेष कार्यकाल जून 2017 को पूरा करने के लिए हुई रिक्ति को भरने के लिए कंटीनेंटल शेल्फ सीमा आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय उम्मीदवार डॉ. रसिक रवीन्द्र का चयन किया गया।

अनौपचारिक सलाहकार प्रक्रिया ने 27–30 मई 2014 को अपनी 15वीं बैठक आयोजित की और आम सभा की संकल्पना 68/70 के अनुसरण में वैश्विक खाद्य सुरक्षा में समुद्री खाद्य पदार्थों की भूमिका शीर्षक पर मुख्य रूप से विचार–विमर्श किया। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की परिधि से बाहर सामुद्रिक जैव विविधता के संरक्षण एवं धारणीय प्रयोग संबंधी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एड–होक ओपन इंडेड अनौपचारिक कार्यकारी समूह ने 1–4 अप्रैल और 16–19 जून, 2014 को बैठकें आयोजित कीं। इस प्रभाग ने बैठकों के दौरान सामने आए विभिन्न विधिक पक्षों पर सक्रिय भागीदारी की और अपना योगदान दिया।

जुलाई 2014 में किंग्सटन, जमैका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण के 20वें वार्षिक सत्र में मध्य हिंद महासागर में पॉलिमेटेलिक सल्फाइड्स का पता लगाने के लिए भारत की कार्य योजना को अनुमोदित किया। इसमें जर्मनी के साथ व्यस्ततापूर्ण वार्तालाप भी शामिल था, जिसकी कार्य योजना भारत द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित थी। अंततः भारत के विधिक तर्कों से सहमत होने पर जर्मनी को अपनी कार्य योजना में संशोधन करना पड़ा और विवाद के मुद्दों को हटाना पड़ा।

एशियाई–अफ्रीका विधिक सलाहकार संगठन (ए ए एल सी ओ)

एशियाई–अफ्रीकी विधिक सलाहकार संगठन ने 15–18 सितंबर, 2014 को ईरान के तेहरान में अपना 53वां वार्षिक सत्र आयोजित किया। भारत का प्रतिनिधित्व डॉ. नीरू चड्ढा, अपर सचिव (विधि व संधि)–नेता, और डॉ. वी. डी. शर्मा, निदेशक (विधि व संधि)–सदस्य की संरचना वाले प्रतिनिधिमंडल ने किया।

53वें सत्र के लिए श्री दानेश याज़्दी, ईरान के उप विदेश मंत्री और सुश्री अगिम्बा क्रिस्टीने अनयांगो, केन्या की उप सॉलिसिटर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने सेवामुक्त होने वाले अध्यक्ष डॉ. नीरू चड्ढा के आमंत्रण पर अपना पदभार ग्रहण किया।

सत्र के दौरान सामुद्रिक कानून, शरणार्थियों की स्थिति और उनके प्रति व्यवहार, फलिस्तीन शासित क्षेत्रों में यहूदियों को बसाने सहित फलिस्तीनियों और इजराइल की अन्य प्रथाओं का निर्वासन, राष्ट्रीय विधान के लिए क्षेत्र बाह्य आवेदन जिसमें कि एकतरफा संस्वीकृतियों को लागू करना शामिल है, विषयों पर सत्र के दौरान चर्चा की गई।

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की कार्यसूची के कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें विदेशी आपराधिक क्षेत्राधिकार से राजनयिकों को प्रतिरक्षा, आपदा की दशा में लोगों की सुरक्षा और वातावरण संरक्षण और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून की पहचान शामिल है।

भारतीय कथनों/हस्तक्षेपों ने इन विषयों से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत रेंज को कवर किया। इसके अतिरिक्त ए ए एल सी ओ के संगठनात्मक मामलों को संगठन में विधि अधिकारियों की घटती संख्या का विशेषज्ञ संदर्भ लेते हुए चिन्हांकित किया गया है।

चीन ने एक नए मद साइबरस्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कानून को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है। भारतीय प्रतिनिधि ने साइबरस्पेस के उपयोग और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विनियमों में अंतर को देखते हुए उसका समर्थन किया है तथा सचिवालय को इस विषय पर अध्ययन करने को कहा है जिसके आधार पर नए ए ए एल सी ओ सत्र में चर्चा आरंभ की जा सके। ईरान ने इस सुझाव के साथ कि ए ए एल सी ओ हिंसात्मक उग्रवाद और आंतकवाद से लड़ने के लिए सिद्धांतों को प्रतिपादित करे जिसके परिणामस्वरूप इस विषय पर ए ए एल सी ओ संधि हो सके, एक नए विषय हिंसात्मक उग्रवाद और आतंकवाद पर चर्चा हेतु अनुरोध किया। तथापि, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह इंगित किया कि आतंकवाद और उससे जुड़े मुद्दे अत्यंत संवेदनशील और जटिल हैं, विशेषकर इस बात के मद्देनजर कि इन मुद्दों पर विभिन्न सदस्य देशों की राय भिन्न–भिन्न है। आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के व्यापक सम्मेलन का प्रारूप विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में ए ए एल सी ओ सदस्य देशोंके लिए आसानी से एक आम सहमति बनाना और ए ए एल सी ओ के भीतर आतंकवाद पर एक बाध्यकारी समझौते के निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा।

इसलिए यह सुझाव दिया गया कि सचिवालय से अनुरोध किया जाए कि वह हिंसात्मक उग्रवाद और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए अंतर सत्रीय बैठकों और सेमिनारों को आयोजित करे जिससे कि भविष्य में इस विषय पर कुछ ए एएल सी ओ दिशा–निर्देशों के निर्धारण तक पहुंचा जा सके। ए ए एल सी ओ के 53वें सत्र में पांच देश नामतः कोमोरास माली रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान और वियतनाम तथा चार अंतर्राष्ट्रीय संगठन नामतः यू एन, यू एन एन ओ डी सी, यू एन एच सी आर और आई सी आर सी को ए ए एल सी ओ के पर्यवेक्षक के तौर पर चुना गया।

यू एन चार्टर पर विशेष समिति

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की विशेष समिति हर वर्ष न्यूयार्क में बैठक करती है। इसके प्रतिवेदनों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में विचार किया जाता है। विशेष समिति की आखिरी बैठक फरवरी 2014 में आयोजित की गई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रश्न, चार्टर के अध्याय सात के अंतर्गत स्वीकृतियों की अनुपयुक्ति से तीसरी दुनिया के देशों को सहायता पहुंचाने के संबंध में चार्टर के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रश्न और संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बीच संबंधों संबंधी मुद्दों से संबंधित मुख्य प्रस्तावों पर विचार किया गया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने निश्चयपूर्वक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और सुरक्षा को बनाए रखना सर्वोपरि है। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कर्तव्य सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की ओर से अपने कर्तव्य निर्वहन के तौर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में स्वीकृतियां केवल एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं जब वे चार्टर के प्रावधानों के अनुसरण में एक अंतिम उपाय के तौर पर अन्य सभी उपायों के खत्म होने के बाद जारी और अनुपयुक्त की गई हों। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अंगों, विशेषकर महासभा और सुरक्षा परिषद के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने और जांच करने के लिए किए गए प्रयासों हेतु समर्थन व्यक्त किया गया। इस संबंध में 24 सितंबर 2012 को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तरों पर रूल ऑफ लॉ पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महासभा द्वारा स्वीकार की गई घोषणा की ओर ध्यान दिलाया जो कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन करने के लगातार प्रयासों की महत्ता पर जोर देती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के मुख्य भाग के दौरान, विधि एवं संधि प्रभाग ने छठी समिति चर्चाओं में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के उपयोग हेतु विशेष समिति के विचाराधीन मुद्दों पर संक्षिप्त विवरण तैयार किए। छठी समिति ने महासभा से सिफारिश की कि विशेष समिति उसकी अगली बैठक में उन्हीं विषयों/मुद्दों पर विचार करना जारी रखेगी जो कि 17–25 फरवरी 2015 को आयोजित होगी।

यूनाईटेड नेशन्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ (यू एन सी आई टी आर ए एल)

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूनाईटेड नेशन्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ (यू एन सी आई टी आर ए एल) और इसके संबद्ध कार्यशील समूहों जोकि क्रमशः मध्यस्थता और समझौता सुरक्षा हितों और ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन को देख रहे हैं, की बैठकों में भाग लिया। 47वां वार्षिक सत्र न्यूयार्क में 7–18 जुलाई 2014 को आयोजित किया गया था। इस सत्र के दौरान कमीशन को अंतिम रूप दिया गया और यू एन जी ए को संधि आधारित निवेशक देश मध्यस्थता में पारदर्शिता पर प्रारूप कन्वेंशन को संयुक्त किया गया। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन संबंधी कार्यकारी समूह का 30वां सत्र 20–24 अक्तूबर 2014 से वियना में आयोजित किया गया। कार्यकारी समूह ने रिजोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट के लिए प्रारूप नियमों के ट्रैक.९ पर विचार किया और साथ ही विभिन्न परिणामों और प्रवर्तन तंत्रों की महत्ता विशेषकर मध्यस्थता सहित विकासशील देशों ओर उन देशों के लिए जो संघर्षोत्तर स्थितियों का सामना कर रहे हैं और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुद्दों को भी विचार हेतु लिया। सत्र के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर इस ट्रैक ऑफ द रूल्स के प्रारूप टेक्स्ट पर प्रगति हुई। चल संपत्ति पर सुरक्षा हितों (ऋण भार) के पंजीकरण के लिए एक रजिस्ट्री की स्थापना करने के लिए देशों को मार्गदर्शन हेतु सिद्धांतों/नियमों को अंतिम रूप दिए जाने का प्रयास कर रहा था। इससे संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति पर

अधिकतम संभव ऋण जुटा सकने में समर्थ होंगे तथा ऋणदाता को सुरक्षा और प्राथमिकता दी जा सकेगी।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ (यू एन आई डी आर ओ आई टी)

इस प्रभाग ने 11–12 सितंबर 2014 को तैयारी समिति बैठक के तीसरे सत्र में भाग लिया। इसका उद्देश्य यह था कि रोम में यू एन आई डी आर ओ आई टी की सीट के लिए जो अंतरिक्ष परिसंपत्तियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की जाए। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रेंस के संकल्प एक के अनुसार थी। इसमें अंतरिक्ष परिसंपत्तियों हेतु पदार्थ विशेष के संबंध में मोबाइल उपकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित कन्वेंशन प्रोटोकॉल अपनाया गया। बैठक के दौरान अंतरिक्ष परिसंपत्तियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री की संस्थापना के लिए प्रारूप विनियमन के साथ–साथ रजिस्ट्रार के चयन हेतु प्रस्तावों के लिए अनुरोध संबंधी मुद्दों पर विचार किया गया।

प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से संबंधित हेग कान्फ्रेंस (एच सी सी एच)

8–10 अप्रैल, 2014 की अवधि में हेग में आयोजित सम्मेलन के सामान्य मामले और नीति संबंधी परिषद में इस प्रभाग ने भाग लिया। परिषद ने अन्य बातों के साथ कार्य समूह द्वारा पूरे किए गए कार्य का स्वागत किया। इसके अलावा हेग सिद्धांतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संविदाओं में चयन कानून संबंधी प्रारूप प्रख्यापन को अंतिम रूप देने और उस पर सदस्यों की अनुमति वाले पाठ का भी स्वागत किया। परिषद ने बच्चों की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर स्थाई ब्यूरो के कार्य की सराहना की। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय सरोगेसी प्रबंधनों से उठने वाले मुद्दों की भी सराहना की और इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि इस क्षेत्र में बहु–पक्षीय दस्तावेजों को तैयार करने की संभावना पर कार्य जारी रखा जाए।

माल्टा प्रक्रिया

माल्टा प्रक्रिया के संबंध में मध्यस्थता ढांचा की स्थापना के लिए मध्यस्थता संबंधी वर्किंग पार्टी ने सिद्धांतों का विकास किया है ओर उसने प्रत्येक राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक मध्यस्थता हेतु केंद्रीय संपर्क केंद्र की स्थापना का आह्वान किया है। परिषद ने इस क्षेत्र में कन्वेंशन के विकास की दिशा में आगे कदम उठाए जाने की योजना वाले सुझाव सहित 'जजमेंट्स प्रोजेक्ट' की महत्ता की सराहना की है।

दिनांक 30–31 अक्तूबर, 2014 को इस प्रभाग ने परमानेन्ट ब्यूरो, हेग में आयोजित तकनीकी सहायता कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। हेग अभिसमय के सदस्य देशों और इसमें भाग लेने वाले देशों (या जो इसके सदस्य बनने पर विचार कर रहे हैं और/या हेम अभिसमय का अनुसमर्थन या उसे स्वीकार करने पर भी विचार कर रहे हैं) उनके सरकारी अधिकारियों, न्याय पालिका और प्रोपटेशनरों के लाभ के लिए अभिसमयोत्तर सहायता हेतु कार्यनीतिक रूपरेखा के प्रारूप संबंधी अपने कार्य को अंतिम रूप देने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। कार्यनीतिक रूपरेखा को संशोधित प्रारूपपर कार्यसमूह की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद परमानेन्ट ब्यूरो वर्ष 2015 में इसे काउंसिल ऑफ जनरल अफेयर्स एंड पालिसी के प्रारूप को अंतिम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

मध्यस्थता सम्बन्धी स्थायी न्यायालय (पी सी ए)

इस प्रभाग ने 9 अक्तूबरए 2014 को पीस पैलेस में आयोजित वित्तीय समिति निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी स्वतंत्र कार्यसमूह की बैठक में भाग लिया। कार्य समूह का कार्य वित्तीय समिति में समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय समूहों के लिए चक्रीय प्रणाली को वास्तव में कैसे लागू किया जाए इस संबंध में दो दौर की चर्चा हुई लेकिन इस चर्चा में किसी स्वीकार्य परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सका। चूंकि वित्तीय समिति के सदस्यों का चुनाव हाल ही में हुआ है और अगला चुनाव 2016 में होगा अतः बैठक जनवरी 2015 तक स्थगित की गई।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की बजट समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है और हाल ही में 5 नवंबर, 2014 को इसका आयोजन हुआ था तथा इस प्रभाग ने इसमें भाग लिया था। बजट समिति के अध्यक्ष ने वर्ष 2014 की पहली और दूसरी तिमाही की बजट कार्य संपादन रिपोर्ट पेश की। इसमें इस बात को रेखांकित किया गया था कि पहली तिमाही के आखिर में आय और व्यय दोनों बजट से कम रहे (व्यय आय से कम रहा और इस आधार पर वर्ष 2015 के बजट का प्रस्ताव किया गया ताकि पी सी ए सेवाओं में प्रत्याशित वृद्धि की मांग से निपटने के साथ–साथ ब्यूरो को वर्ष के दौरान संशोधित/अनुपूरक बजट को अनुमोदनार्थ अतिरिक्त बैठक के लिए प्रशासनिक परिषद के पास न जाना पड़े। आरक्षित कोष शैक्षिक सहायता कोष, सम्मेलन निधि और मुद्रण तथा अनुवाद कोष में रजिस्ट्री सेवाओं से होने वाली विभिन्न आय से योगदान दिए जाने का प्रस्ताव है और इसका सदस्य देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अंटार्कटिका

इस प्रभाग ने 28 अप्रैल से 7 मई, 2014 को ब्राजीलिया (ब्राजील) में आयोजित अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री समिति (ए टी सी एम) की सैतीसवीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक में भारत एवं 12 अन्य गैर–परामर्शदात्री सदस्य देशों तथा अन्य पर्यवेक्षी संगठनों सहित 30 परामर्शदात्री देशों ने भाग लिया। ए टी सी एम के कार्य विभिन्न समूहों नामतः (क) अंटार्कटिका पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति (सीईपी) (ख) विधिक और संस्थागत मामलों संबंधी कार्य समूह (ग) पर्यटन और गैर–सरकारी कार्य संबंधी कार्यसमूह (घ) परिचालनात्मक मामले संबंधी कार्य समूहों द्वारा किए गए थे। विधिक और संस्थागत कार्यसमूह ने सी ई पी और अन्य कार्य समूहों

द्वारा परिणामी संकल्पों को ए टी सी एम के पूर्ण अधिवेशन में इन्हें अंगीकार किए जाने से पूर्व इनका पुनरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त विधिक और संस्थागत कार्य समूह द्वारा तीन मुख्य बिन्दुओं नामतः (क) अंटार्कटिका प्रणाली का ऑपरेशन (ख) दायित्व ए टी सी एम निर्णय (2010) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय समूद्री संगठनोंके पोलर कोड का कार्यान्वयन पर चर्चा की।

समुद्री परिसीमन के संबंध में बांग्लादेश के साथ विवाद

बांग्लादेश ने समुद्री विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुलग्नक VII के अनुच्छेद 287 और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ समुद्री सीमा के परिसीमन संबंधी मध्यस्थता शुरू की है। फरवरी 2010 में यू एन सी एल ओ एस के अनुलग्नक VII के अनुच्छेद 3 के अनुसार एक पांच सदस्यीय पैनल गठित किया गया। यह प्रभाग बांग्लादेश मेमोरियल के संबंध में भारत की प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए वकीलों और अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठक करने में सक्रिय रहा था। यहां यह स्मरणीय है कि 31 जनवरी, 2013 को बांग्लादेश ने भारत के काउंटर मेमोरियल के संबंध में जवाब दिया। भारत ने 31 जुलाई 2013 को अपना प्रत्युत्तर पेश किया।

अधिकरण ने बांग्लादेश के अनुरोध पर दोनों देशों के संगत तटों एवं बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित ठोस बिंदु को देखने के लिए नदमुख क्षेत्र का दौरा करने का कार्यक्रम बनाया। 23–25 अक्तूबर, 2013 तक अधिकरण ने स्थलीय दौरा किया। तत्पश्चात 9 से 18 दिसंबर, 2013 तक हेग के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में इस मामले में मौखिक अभिवचन शुरू हुआ। लिखित अभिवचन के दौरान दोनों देशों ने वही दृष्टिकोण अपनाया जो उन्होंने मौखिक अभिवचन ने अपनाया था। दोनों पक्षकार इस तथ्य के प्रति सतर्क थे कि अधिकरण का अवार्ड उनके दावों से अलग हो सकता है।

मध्यस्थ अधिकरण ने हेग में 7 जुलाई, 2014 को अपना निर्णय दिया। इस निर्णय के माध्यम से प्रादेशिक समुद् अनन्य आर्थिक क्षेत्र, कांटिनेन्टल शेल्फ और 200 नॉटिकल मील से दूर कांटिनेन्टल शेल्फ के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा निर्धारित की गई। मध्यस्थ संबंधी निर्णय अंतिम और दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है।

मुक्त व्यापार समझौते

विदेश मंत्रालय प्रभाग ने यूरोप मुक्त व्यापार संघ तथा कनाडा के साथ बातचीत की।

द्विपक्षीय निवेश समझौते

इस प्रभाग ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौतों संबंधी द्विपक्षीय बातचीत शुरू की।

प्रत्यर्पण और अन्य अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहायता

इस प्रभाग ने प्रत्यर्पणसंधियों, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता, सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता और अन्य देशों से दोषी व्यक्तियों के अंतरण संबंधित विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं में भाग लिया। प्रभाग ने लेबनान और मलावी के साथ की जा रही प्रत्यर्पण संधियों के प्रति प्रारूप की जांच भी की। प्रभाग ने प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोधों के साथ–साथ घरेलू तथा अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने संबंधी अनुरोधों की भी जांच की और इस संबंध में विधिक सलाह भी दी। इस प्रभाग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोषी लोगों के अंतरण संबंधी समझौते पर बातचीत में भाग लिया। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण जोकि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है के समक्ष अंतरदेशीय दत्तकग्रहण से संबंधित लंबित मामलों को हमारी विधिक सूचना के आधार पर निर्णीत किया गया।

जर्मनी, आइसलैंड, चिली, स्विटजरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और स्लोवाकिया के साथ राजनयिक मिशनों और कांसुलर पदों के लाभप्रद व्यवसाय/रोजगार संबंधी व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा

इस प्रभाग ने स्पेन सामाजिक सुरक्षा समझौते की जांच की तथा जापान के साथ इस समझौते को अंतिम रूप दिया।

पुनरीक्षण

इस प्रभाग ने अनेक सुरक्षा सहयोग समझौते और स्वास्थ्य, जैव तकनीकी, वाह्य अंतरिक्ष मुद्दों, विज्ञान और तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, बहुराष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक द्रव्य व्यापार/स्वापक पर भी समझौते, गोपनीयता पर समझौते, जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों का बंटवारा, गैस और ऊर्जा, सांस्कृतिक सहयोग, दृश्य श्रृव्य, सड़क परिवहन, रेलवे, व्यापार परियोजनाओं, डी टी ए शिक्षा, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर द्विपक्षीय समझौते, लाभदायक रोजगार, जल विज्ञान और कस्टम सहयोग आदि की जांच की।

भारत ने वर्ष के दौरान विदेशों के साथ कई बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधि/समझौतों पर हस्ताक्षर/अनुसमर्थन किया है। (**परिशिष्ट –I** में) विस्तृत सूची लगा दी गई है। 2014 के दौरान जारी पूर्ण शक्तियों के साधनों की सूची **परिशिष्ट –II** में है और 2014 के दौरान अनुसमर्थन किए गग साधनों की सूची **परिशिष्ट –III** में है।

निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले

10

भारत ने वर्ष के दौरान सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण सहित वैश्विक और गैर–विभेदकारी परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों संबंधी विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। निरस्त्रीकरण मुद्दों संबंधी भारत का मत भारत के आंतरिक सुरक्षा हितों और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सहकारिता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ निकट संबंध की इसकी परंपरा द्वारा निदेशित है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रथम समिति, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग, निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन, जैविक और जीव–विष हथियार सभा (बी टी डब्ल्यू सी) रासायनिक हथियार सभा (सी डब्ल्यू सी), कतिपय पारंपरिक हथियारों संबंधी सभा (सी सी डब्ल्यू) छोटे अस्त्रों और हल्के हथियारों पर कार्यवाही का यू एन कार्यक्रम में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

भारत ने 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक गैर–विभेदकारी और पुष्टियोज्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए अपनी प्रतिएद्धता को इंगित किया।

गुट–निरपेक्ष आंदोलन सदस्य के रूप में भारत ने समूह के संकल्प परमाणु निरस्त्रीरण संबंधी महासभा की उच्च स्तरीय बैठक का 2013 तक अनुसरण का 2014 की पहली बैठक में समर्थन किया। संकल्प में अन्य बातों के साथ–साथ परमाणु हथियार सभा संबंधी निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत के तत्काल प्रारंभ करने, परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में 26 सितंबर को प्रारंभ और बढ़ावा देने का स्वागत किया और अपने इस निर्णय को दोहराया कि 2018 से पूर्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण संबंधी उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया जाए।

2014 की प्रथम बैठक में परमाणु हथियारों पर सामान्य वाद–विवाद और विषयागत वाद–विवाद के दौरान निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को इंगित किया और इस प्रयोजन हेतु भारत द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उपायों को दोहराया। परमाणु निरस्त्रीकरण की महत्ता को कम आंकते हुए भारत ने बहुपक्षीय, गैर–विभेदकारी निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में बातचीत और परमाणु हथियारों एवं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पूरा करने वाले अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों हेतु विखण्डय पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुष्टियोज्य संधि हेतु अपने समर्थन को दोहराया।

भारत के संकल्प व्यापक विनाश के हथियारों के अधिग्रहण से आतंकियों को रोकने के उपाय जिसे पहले 2002 में लाया गया था, को पुनः सहमति से स्वीकार किया गया। संकल्प को 90 देशों द्वारा सह–प्रायोजित किया गया जोकि 2013 से तेरह अधिक था। संकल्प ने यूएन सदस्य राष्ट्रों से आह्वान किया कि व्यापक विनाश के हथियारों के अधिग्रहण से आतंकियों को रोकने के लिए लक्षित उपाय करें और इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करें। संकल्प हेतु सशक्त समर्थन ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में निरंतर एकता को इंगित किया। परमाणु हथियारों के प्रयोग के निषेध सभा संबंधी भारत के संकल्प ने किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत परमाणु हथियारों के प्रयोग या प्रयोग के संकट पर प्रतिबंध हेतु अंतरराष्ट्रीय सभा पर चर्चा प्रारंभ करने के लिए निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन की मांग को दोहराया। यह संकल्प परमाणु हथियारों के मानवीय प्रभाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में वर्तमान चर्चाओं के संदर्भ में और अधिक संगतहो गया है। संकल्प ने इस विश्वास को भी दोहराया कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाले बहुपक्षीय, वैश्विक और विधिक दृष्टि से बाध्यकारी उपाय, निरस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु हथियारों के निषेध पर समझौते संबंधी बातचीत हेतु अनुकूल परिवेश निर्मित करेंगे। संकल्प को प्रथम समिति द्वारा बहुमत से स्वीकार किया गया और 2013 में 34 की तुलना में 40 देशों द्वारा सह–प्रायोजित किया गया। भारत के तीसरे संकल्प परमाणु खतरे को कम करना ने परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा और परमाणु हथियारों की विसचेतक या विलक्ष्य सहित इनके स्वयं या दुर्घटनावश प्रयोग के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संकल्प को भी बहुमत से स्वीकार किया गया और इसमें 2013 में 27 सह–प्रयोजकों की तुलना में 33 तक वृद्धि दर्ज की गई।

प्रथम समिति ने भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रोद्योगिकी की भूमिका पर भारत द्वारा प्रस्तावित प्रारूप निर्णय को अपनाया।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यू एन डी सी)

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग ने 7–25 अप्रैल, 2014 से 2014 हेतु अपने स्वायत्त सत्र का आयोजन किया। अपने 2012–14 चक्र हेतु आयोग द्वारा अपनाई गई कार्य–सूची के अनुसार आयोग ने परमाणु निरस्त्रीकरण और पारंपरिक हथियारों के क्षेत्र में सी सी एम से संबंधित दो कार्यसूची मदों पर चर्चा की। भारत ने आयोग की चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया ताकि 2014 में सिफारिशों पर सहमति प्राप्त की जा सके। भारत ने बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण कार्यसूची, विशेषकर यू एन डी सी की वैश्विक प्रकृति को महत्ता देते हुए उसे आगे बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मशीनरी के विशेषीकृत विमर्शी अंग के रूप में यू एन डी सी के कार्य से संबंधित उच्च महत्ता पर बल दिया।

निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सी डी)

वर्ष के दौरान सम्मेलन में हुई विभिन्न चर्चाओं में भारत ने कार्य के कार्यक्रम को अपनाकर सी डी में स्वायत्त कार्य को प्रारंभ करने की आवश्यकता पर बल देना जारी रखा। भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण, विखण्ड; पदार्थ कट–ऑफ संधि (एफ एम सी टी), बाह्य अंतरिक्ष में अस्त्र दौड़ को रोकना (पी ए आर ओ एस) और नकारात्मक सुरक्षा आश्वासनों (एन एस ए) के चार मुद्दों सहित सी डी की कार्यसूची संबंधी सभी मुद्दों पर अपने संदर्भ को बांटा। भारत ने सी डी की कार्यसूची मदों में अनौपचारिक वाद–विवाद में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने सम्मेलन को विश्व समुदाय के एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण बातचीत मंच के रूप में इसकी महत्ता को दोहराया। इसने दोहराया कि परमाणु निरस्त्रीकरण अभी भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय हेतु शीर्ष वरीयता है। भारत ने गैर–विभेदकारी सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय रूप में पुष्टियोज्य विखण्डय पदार्थ कट–ऑफ संधि (एफ एम सी टी) में चर्चाओं हेतु अपने समर्थन को सूचित किया, जोकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुसार है। भारत ने एफ एम सी टी बातचीत हेतु सहमत अधिदेश को इंगित किया और कहा कि भारत इस अधिदेश को दोबारा खोलने को समर्थन नहीं करता है, भारत ने अपनी धारणा को भी व्यक्त किया सम्मेलन में अपने अधिदेश को करने के लिए सदस्यता, साख और प्रक्रिया नियम हैं।

कतिपय पारंपरिक हथियारों संबंधी सम्मेलन (सी सी डब्ल्यू)

सी सी डब्ल्यू के लिए उच्च संविदा दलों की वार्षिक बैठक 13–14 नवंबर, 2014 को जिनेवा में आयोजित की गई, भारत ने संयुक्त राष्ट्र ढांचों के भीतर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में सी सी डब्ल्यू के लिए अपने समर्थन को इंगित किया। भारत ने 2013 में उच्च संविदा दलों की बैठक में सहमत अधिदेश के आधार पर 2015 में सी सी डब्ल्यू में जहरीले स्वायत्त हथियार प्रणालियों से संबंधित मुद्दों पर सतत चर्चा करने का समर्थन किया। 12 नंवबर, 2014 को संशोधित प्रोटोकॉल–II (ए पी–II) के 16वें वार्षिक सम्मेलन में भारत ने ए पी–II में वर्णित दृष्टिकोण अपने समर्थन को प्रदर्शित किया और कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंगों को अंततः समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। भारत ने ए पी–II के अंतर्गत संवर्धित विस्फोटक उपकरणों (आई ई डी) पर सतत कार्य का भी समर्थन किया। 10–11 नवंबर, 2014 को हुई प्रोटोकॉल V के 8वें वार्षिक सम्मेलन में, भारत ने जेनरिक बचावात्मक उपायों, युद्ध के विस्फोटक अवशेषों, सहयोग और सहायता तथा पीड़ित सहायता संबंधी सूचना को रिकॉर्ड और पारेषण करने सहित सभी मुद्दों पर चर्चा मे योगदान दिया। भारत ने अप्रैल 2014 में हुई दोनों प्रोटोकॉल V और ए पी–II के विशेषज्ञों की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने 23–27 जून, 2014 को मपूतो में हुए कार्मिकरोधी बारूदी सुरंग (ओटावा सम्मेलन) के राष्ट्र दलों के समीक्षा सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

जैविक जीव–विष हथियार सम्मेलन (बी टी डब्ल्यू सी)

भारत ने 4–8 अगस्त 2014 को हुए विशेषज्ञों की बी टी डब्ल्यू सी की वार्षिक बैठक और 1–5 दिसंबर, 2014 को हुई राष्ट्र दलों की बैठक में पर्याप्त योगदान किया। भारत ने 2014 में विशेषज्ञों की बैठक में व्यापक विनाश के हथियारों की समग्र श्रेणी को निषेध करने के लिए बी टी डब्ल्यू सी की पहली बहुपक्षी, गैर–विभेदकारी संधि के रूप में उच्च महत्ता को दोहराया।

भारत ने सभा की प्रभावकारिता, इसके कार्यान्वयन के सुदृढीकरण और इसके सार्वभौमीकरण के प्रयासों में सुधार के लिए सहयोग बढ़ाया। दिसंबर, 2014 में राष्ट्रीय दलों की बैठक में भारत ने सभा के अनुच्छेद–दस के कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बी टी डब्ल्यू सी बैठकों में कार्यसूची की तीन मदों (सहयोग और सहायता, एस ई टी विकास की समीक्षा तथा राष्ट्रीय कार्यान्वयन) और द्विवार्षिक कार्यसूची मदों (अनुच्छेद सात के अंतर्गत सहायता और सहयोग) पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया जैसाकि 7वें समीक्षा सम्मेलन मे निर्णय लिया गया था।

रासायनिक हथियार सम्मेलन (सी डब्ल्यू सी)

भारत को 2015–17 की अवधि के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन की कार्यकारी परिषद का सदस्य पुनः चुन लिया गया। एशियन ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाली कार्यकारी परिषद ब्यूरो के

वाइस चेयरमैन का कार्यकाल मई 2014 में समाप्त हो गया। जैसकि पिछले वर्षों में हुआ था भारत ने राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर कार्यकारी परिषद के नियमित सत्रों (08–11 जुलाई, 2014) और (7–10 अक्तूबर, 2014) की कार्यकारी परिषद की अनेक विशेष बैठकों और राष्ट्रीय दलों के सम्मेलनों (सी एस जी) में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने, उद्योगों के निरीक्षण, राष्ट्रीय कार्यान्वयन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहायता में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा।

रासायनिक हथियार सम्मेलन के संदर्भ में एशियन ग्रुप और एन ए एम ग्रुप को एकाकार करने में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई और संगठन के अनेक अनुसंगी निकायों जैसे वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड (एस ए बी) तथा प्रशासनिक और वित्तीय मामलों संबंधी परामर्शदात्री निकाय (ए सी ए एफ) में अपना योगदान बढ़ाया। भारत ने ओ पी सी डब्ल्यू की गतिविधियों से अपने आप को जोड़े रखा और जुलाई, 2014 में नेशनल अथारिटीज़ इन एशिया की बारहवीं क्षेत्रीय बैठक और अगस्त 2014में 'रीजनल बेसिक कोर्स ऑन एसिसटेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल वीपन्स' नई दिल्ली में आयोजित की।

छोटे शस्त्र और हल्के हथियार

छोटे शस्त्रों और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार के सभी पहलुओं को रोकने, विरोध करने और उन्मूलन करने के संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम यू एन पी ओ ए को जुलाई 2001 में स्वीकार किया गया जिसमें यह उपबंध है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक उपायों का एक व्यापक सेट तैयार किया जाए। भारत ने 16–20 जून, 2014 में न्यूयार्क में आयोजित राष्ट्रों की द्वैवार्षिक बैठक (बी एम एस) में भाग लिया जिसमें यू एन पी ओ ए और इंटरनेशनल ट्रेंसिंग इन्स्ट्रूमेंट के कार्यान्वयन के लिए एक व्यावहारिक दस्तावेज स्वीकार किए गए।

अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

भारत ने सिविलियन न्यूक्लियर सुविधाओं की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ आई ए ई ए और भारत सरकार के बीच समझौते के अतिरिक्त प्रोटोकाल का अनुसमर्थन किया। यह प्रोटोकाल 25 जुलाई, 2014 से लागू हुआ। भारत के सुरक्षा मानकों के समझौते के अनुसार नरोरा के दो रिएक्टरों एन ए पी 1 व 2 को दिसंबर, 2014 में स्वेच्छा से आई ए ई ए के सुरक्षा उपायों के अधीन कर दिए गए।

सिविल परमाणु सहयोग

भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच 05 सितंबर, 2014 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के क्षेत्र में अन्य बातों के साथ–साथ गैर ऊर्जा क्षेत्रों यथा कृषि, औषधि, न्यूक्लियर सुरक्षा और सहयोग के अन्य क्षेत्रों जैसा कि पारस्परिक सहमति से निर्णय हो, हेतु यूरेनियम की आपूर्ति, उत्पादन और रेडियो आइसोटोप्स की प्रयोज्यता को कवर किया गया है।

भारत–कनाडा न्यूक्लियर कोआपरेशन एग्रीमेंट संबंधी संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 25 नवंबर, 2014 को ओटावा में आयोजित की गई। बैठक में अन्य चीजों के साथ–साथ न्यूक्लियर कोआपरेशन एग्रीमेंट और द्विपक्षीय आर एंड टी तथा औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की गई। 30 दिसंबर, 2014 को प्रधानमंत्री के वाशिंगटन दौरे के दौरान अमेरिका के साथ परमाणु सहयोग के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए एक संपर्क समूह गठित किया गया।

परमाणु सुरक्षा

भारत ने वर्ष 2016 में आयोजित होने वाले परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए 27–28 अक्तूबर, 2014 को वाशिंगटन डी सी में आयोजित शेरपाओं की पहली बैठक में भाग लिया। बैठक में भारत ने तैयारी प्रक्रिया से एक सारगर्भित और प्रभावी दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो एन एस एस प्रक्रिया की उपलब्धियों का बखान करते हुए नेताओं द्वारा स्वीकार्य हो और जो न्यूक्लियर सुरक्षा के क्षेत्र में संपादित किए जाने वाले कार्यों की ओर उन्मुख हो।

न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए अंतराष्ट्रीय कानूनों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता हेतु भारत–कनाडा संयुक्त कार्यशाला 16–17 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यशाला में आई ए ई ए, भारत, कनाडा और एशिया/सेंट्रल एशिया के 15 देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

एशिया में आपसी विमर्श और विश्वास प्राप्त करने के उपायों पर सम्मेलन (सी आई सी ए)

एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने के लिए एक 26 सदस्यीय क्षेत्रीय मंच सी आई सी ए बनाया गया है। वर्ष के दौरान भारत ने 04–06 नवंबर, 2014 में यांगजू, चीन में आयोजित विशेष कार्यकारी दल (एस डब्ल्यू सी) और वरिष्ठ अधिकारी समिति (एस ओ एस) में भाग लिया। भारत ने एशियाई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वस्वीकृत और एक–एक कदम बढ़ाकर वर्तमान सहमति वाले देशों में आपसी विश्वास बढ़ाने के उपायों को और सुदृढ़ करने और इसके कार्यान्वयन हेतु अपना समर्थन देने को रेखांकित किया।

आसियान रीजनल फोरम (एआरएफ) और संबंधित मंच

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में राजनैतिक सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र हमारी बढ़ती संलिप्तता ए आर एम में हमारी भागेदारी दर्शाती है। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 10 अगस्त, 2014 को ने पाई ता में 21वें ए आर एफ बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। विभिन्न आसियान के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र के बीच सहयोग और सहभागिता समेत विश्वास बढ़ाने के उपायों से लेकर सुरक्षात्मक कूटनीति तक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सर्वसम्मति दिखी। एशिया के प्रशांत सुरक्षा तंत्र जिसे विभिन्न राजनैतिक और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रीय मंचों पर लगातार महत्व दिया जा रहा है, के मुद्दे पर हमने एक वार्तालाप केंद्रित ढांचा बनाने को अपना समर्थन दिया, जो खुला, पारदर्शी, समावेशी और विकासात्मक प्रक्रिया पर आधारित हो। भारत ने ए आर एफ की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक सी बी एम और उपचारात्मक कूटनीति संबंधी दो अंतर–सत्रीय ग्रुप बैठकें, आपदा राहत की अंतरराष्ट्रीय बैठकों, समुद्री सुरक्षा आतंकरोधी अंतरराष्ट्रीय अपराधों, नान–प्रालिफरेशन और निरस्त्रीकरण, रक्षा विश्व विद्यालयों कालेजों/ संस्थानों के प्रमुखों की बैठक और ए आर एफ डिफेंस आफिसियल्स डायलाग और विभिन्न सहयोगी गतिविधियों और सेमीनारों में भाग लिया। भारत ने आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस (ए डी एम एम प्लस), एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स (ई डब्ल्यू जी) ऑन एच ए डी आर, मिलिटरी मेडिसिन, समुद्री सुरक्षा, शांति बहाली प्रक्रियाओं, आतंकरोधी बैठकों में भाग लिया और वह 2014–17 के वर्तमान सत्र में ई डब्ल्यू सी ऑन ह्यूमनेटेरिजम माइन एक्शन की सह अध्यक्षता कर रहा है।

जकार्ता में अक्तूबर, 2014 में आयोजित ईस्ट एशिया समिट (ई ए एस) में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र संबंधी एक कान्सेप्ट पेपर भी प्रस्तुत किया गया।

निर्यात नियंत्रण

भारत अपनी सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर्स सप्लायर्स ग्रुप (एन एस जी) और तीन अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण क्षेत्रों नामतः मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम (एम टी सी आर), ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (ए जी) और वासेनार अरेंजमेंट (डब्ल्यू ए) और इन चारों क्षेत्रों के व्यक्तिगत सदस्यों से भी संपर्क में है। क्षेत्रीय सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात अन्य बातों के साथ–साथ भारत की पहुंच दोहरे उपयोग तथा उच्च प्रोद्योगिक मदों तक हो जाएगी और इससे वैश्विक अप्रसार प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री के अमरीका दौरे के दौरान 30 सितंबर, 2014 को जारी संयुक्त बयान में अमेरिका ने इस तथ्य की अभिपुष्टि की कि भारत एन एस जी की सदस्यता के लिए तैयार है और यह एम टी सी आर की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसी वर्ष के दौरान भारत ने अप्रैल 2014 में वियना में आयोजित एन एस जी आउटरीच कार्यशाला मई 2014 में पेरिस में आयोजित एम टी सी आर आउटरीच वर्कशाप और जून 2014 में वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया। नवंबर, 2014 में वियना में एन एस जी ट्रोयका के साथ आयोजित होने वाली आउटरीच मीटिंग के शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव ने किया।

■■

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

11

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका)

छठा ब्रिक्स सम्मेलन

फोर्टलिजा और ब्राजीलिया, ब्राजील में 15–16 जुलाई, 2014 को आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का अति महत्वपूर्ण विषय था– समावेशी विकासः स्थायी समाधान। नेताओं ने वैश्विक शासन के सुधारों से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की जिनमें राजनीतिक और आर्थिक, व्यापार संबंधी, वित्तीय, क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों के साथ–साथ ऐसे वैश्विक मुद्दे जिनमें विश्व–व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ), आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रीय सुनियोजित अपराध, जलवायु परिवर्तन, 2015 के पश्चात् विकास कार्यसूची आदि के साथ–साथ अंतः ब्रिक्स सहयोग आदि मुद्दे शामिल थे। छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी फोर्टलिजा घोषणापत्र पर चर्चा तथा उसके परिणाम ब्रिक्स देशों में चर्चा का विषय रहे।

छठे ब्रिक्स सम्मेलन के मुख्य परिणामों में शामिल हैं नए विकास बैंक (न्यू डेवेलपमेंट बैंक) की स्थापना के लिए समझौता करना– जिसका मुख्यालय शंघाई में होगा, प्रथम अध्यक्ष भारत से होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष रूस से होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला अध्यक्ष ब्राजील से होगा और प्रथम क्षेत्रीय केन्द्र अपने मुख्यालय के साथ अफ्रीका में स्थापित किया जाएगा तथा आकस्मिकता आरक्षण व्यवस्था (कंटिन्जेंट रिजर्व अरेंजमेंट) की स्थापना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने जिसका कुल प्रारंभिक आकार 100 बिलियन यू.एस डॉलर होगा तथा चीन की निजी प्रतिबद्धता 41 बिलियन यू.एस. डॉलर, ब्राजील, रूस और भारत की 18 यू.एस. डॉलर प्रति देश तथा दक्षिण अफ्रीका की 5 बिलियन यू. एस. डॉलर होगी जो ब्रिक्स देशों के बीच बहुपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी।

ब्रिक्स देशों में व्यापार अवसरों को बढ़ाने का वातावरण तैयार करने के लक्ष्य हेतु ब्रिक्स देशों की निर्यात ऋण गारंटी एजेंसियों में तकनीकी सहयोग के एक ज्ञापन पर तथा आपसी हित की नवोन्मेशी परियोजनाओं के वित्तपोषण की सहायतार्थ नवप्रवर्तन के संबंध में अतः बैंक सहयोग समझौते पर भी इस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए।

सम्मेलन से पूर्व 14 जुलाई, 2014 को फोर्टलिजा में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों तथा व्यापार मंत्रियों की बैठक भी हुई। दोनों मंत्रीय स्तरीय बैठकों में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिक्स के व्यापार मंत्रियों ने बैठक के उपरांत एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की। 16 जुलाई, 2014 को ब्राजीलिया में ब्रिक्स नेताओं ने ब्राजील द्वारा आमंत्रित 11 दक्षिण अमरीकी देशों के राज्य/शासन अध्यक्षों से भी भेंट की। इस बैठक के उपरांत कोई भी वक्तव्य/घोषणा नहीं की गई।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अंत में न्यूयार्क में रूस के विदेश मंत्री की मेजबानी में 25 सितम्बर, 2014 को हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री ने भाग लिया। मंत्रियों ने क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर यू एन एस सी सुधार, आर्थिक सहयोग तथा अन्य आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के उपरांत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। मंत्री स्तरीय बैठक से पूर्व ब्राजील की मेजबानी में ब्रिक्स के शेरपाओं की बैठक हुई।

आई.बी.एस.ए डायलॉग फोरम

आई बी एस ए के विदेश मंत्रियों की बैठक

विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अंत में 24 सितंबर, 2014 को आई बी एस ए के विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। मंत्रियों ने आई बी एस ए वार्ता मंच के और सुदृढ़ीकरण और सशक्तिकरण हेतु अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। यात्रियों ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन. डब्ल्यू आई पी ओ. जी–20, जी–24, ब्रिक्स आदि सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर आई बी एस ए देशों के बीच सघन समन्वय और सहयोग के महत्व पर बल दिया। बैठक के उपरांत एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई।

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी–20)

ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में 15–16 नवम्बर, 2014 को हुए 9वें जी–20 सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने किया। भारत के लिए जी–20 सम्मेलन की कार्यसूची में महत्वपूर्ण विषयों मेः प्रेषण लागत को कम करना, 2013 के दौरान जी–20 जी डी पी में 2018 तक 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की प्रतिबद्धता, 2025 तक कार्यशक्ति में महिलाओं की भागीदारी में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करना, ऊर्जा सामर्थ्य बनाने में योगदान, तथा हानिकारक टैक्स प्रथाओं वाले टैक्स प्रदाता विशिष्ट नियमों में पारदर्शिता सहित क्षार क्लब तथा लाभ परिवर्तन संबंधी कार्य को 2015 तक अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा से संबंधित सार्वजनिक स्टाकहोल्डिंग पर भारत के सैद्धांतिक मत की भी सराहना की गई तथा बाली में दिसम्बर 2013 को 9वें डब्ल्यू टी ओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सभी निर्णय कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता को भी नेताओं की विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया।

जी–20 सम्मेलन के अंत में प्रधानमंत्री ने भी ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लिया। नेताओं ने विश्व की अर्थव्यवस्था, आई एम एफ सुधार तथा जी–20 कार्यसूची के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने यूफा, रूस में जुलाई 2015 को अगले ब्रिक्स सम्मेलन से पूर्व न्यू डेवेलपमेंट बैंक के अध्यक्ष (भारत द्वारा) और उपाध्यक्ष नामांकित करने की भी सहमति प्रकट की।

ग्रुप ऑफ फिफ्टीन (जी–15)

69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन से हट कर, श्रीलंका, जी–15 के वर्तमान अध्यक्ष ने 26 सितम्बर, 2014 को न्यूयार्क में विदेश मंत्रियों की 37वीं बैठक का आयोजन किया। सचिव, (ई आर एण्ड डी पी ए) ने बैठक में विदेश मंत्री का प्रतिनिधित्व किया तथा देश का वक्तव्य दिया।

हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)

सी एस ओ बैठक

हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की चौथी द्वि–वार्षिक बैठक फुकेट, थाईलैंड में 19–20 जून, 2014 को हुई। भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व श्रीमती सुजाता मेहता, सचिव (ई आर डी पी ए) द्वारा किया गया। बैठक में अन्य बातों के अलावा आई ओ आर ए की मंत्री परिषद की 14वीं बैठक की कार्यसूची और कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई जो तदनन्तर 9 अक्तूबर, 2014 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता में हुई।

मंत्री परिषद की 14वीं बैठक (सी ओ एम)

भारतीय महासागर कोर के मंत्रियों की परिषद की 14वीं बैठक 9 अक्तूबर, 2014 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। श्रीमती सुजाता मेहता, सचिव (ई आर तथा डी पी ए) ने बैठक के लिए शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। बैठक की कार्यसूची संबंधी मुद्दों मेः जल अर्थव्यवस्था विकसित करना, महिला सशक्तिकरण समुद्रीय सहयोग, मानव संसाधन विकास और क्षमता विकास पर्यटन को बढ़ावा देना, वार्ता साझेदारों के साथ भागीदारी को बढ़ाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में आई ओ आर ए सहयोग शामिल थे। प्रबंधन संबंधी आई ओ आर ए कार्यशाला, आई ओ आर ए कविता उत्सव, सांस्कृतिक संवर्धन संबंधी कोर ग्रुप की दूसरी बैठक, भारतीय महासागर संवाद सहित 1 नवम्बर, 2013 को पर्थ में गत मंत्रिमण्डलीय बैठक से भारत की पहले और महिला सशक्तिकरण और गरीबी उपशमन संबंधी आई ओ आर ए कार्यशाला का बहुत स्वागत किया गया और सभी आई ओ आर ए सदस्यों द्वारा इसकी व्यापक सराहना की गई। भारत ने आई ओ आर ए की विशेष निधि के लिए 1,00,000 अमरीकी डॉलर के अंशदान की घोषणा की। भारत ने आई ओ आर ए सचिवालय के लिए अनुसंधान विश्लेषक को नियुक्त करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया।

सोमालिया के आई ओ आर ए स्तर की सदस्यता मांगने के अनुरोध को मंत्रियों की परिषद ने एकमत से स्वीकार कर लिया। बैठक ने 2015–17 के दौरान दक्षिण अफ्रीका का अगले उपाध्यक्ष (वाइस चेयर) के रूप में स्वागत किया जो इण्डोनेशिया–ऑस्ट्रेलिया से अध्यक्षता ग्रहण करेगा। बैठक ने संयुक्त अरब अमीरात का भी 2017–19 के दौरान उपाध्यक्ष बनने के प्रस्ताव का स्वागत किया।

■■

प्रधानमंत्री 15 नवंबर, 2014 को ब्रिस्बेन, आस्ट्रेलिया में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ।

प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में 9वें जी–20 शिखर सम्मेलन में अन्य नेताओं के साथ एक सामूहिक फोटो में।

विदेश मंत्री आई बी एस ए बैठक में।

प्रधानमंत्री ब्रिसवेन आस्ट्रेलिया में जी 20 समिट के प्रथम आरंभिक सत्र में (नवंबर 15, 2014)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

12

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काठमांडू में (26–27 नवंबर, 2014) 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सार्क प्रक्रिया के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई और सार्क देशों को समर्पित उपग्रह, 3–5 वर्षों के लिए बिजनेस वीजा तथा सार्क व्यावसायियों के लिए बिजनेस ट्रेवलर कार्ड, पोलियो मुक्त क्षेत्र की मॉनीटरिंग/निगरानी, सार्क देशों के नागरिकों के लिए पोलियो और पंच संयोजन टीकों तथा तत्काल चिकित्सा वीजा के प्रावधान सहित कई एकपक्षीय पहलकदमियों की घोषणा की। इन पहलकदमियों का अन्य सार्क सदस्य देशों ने स्वागत किया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह ने 23–25 नवंबर, 2014 को क्रमशः मंत्रिपरिषद के 36वें सत्र और स्थायी समिति के 41वें सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्री ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा (विद्युत) में सहयोग पर सार्क करार की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया।

भारत आर्थिक समाकलन, संपर्क एवं ऊर्जा पर केन्द्रित कई क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय परियोजनाओं का समर्थन करता रहा है। भारत का सक्रिय व्यवस्थित तथा पारस्परिक दृष्टिकोण सार्क की प्रभावकारिता बढ़ाने में परिवर्तनकारी कारक रहा है। अप्रैल–नवंबर 2014 के दौरान सार्क प्रभाग ने निम्नलिखित सार्क कार्यकलापों को सुविधाजनक बनायाः–

- नई दिल्ली में 7–11 जुलाई, 2014 के दौरान सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र (एस डी एम सी) द्वारा "डैमेज, लॉस एण्ड रिकवरी नीड्स एण्ड ऑन रेसीलेंट रिकवरी डेवलपिंग साउथ एशिया फ्रेमवर्क" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नई दिल्ली में 04 अगस्त–05 सितंबर, 2014 के दौरान सार्क डाक्यूमेंटेशन सेन्टर (एस डी सी) द्वारा कार्यालय संचलन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नई दिल्ली में 25 से 29 अगस्त, 2014 को एस डी सी द्वारा "बिबलियोमीट्रिक टूल्स एण्ड टेक्नीक्स" पर पाठ्यक्रम।
- राजस्थान में 7–8 सितंबर, 2014 को "सार्क मोटर वाहन करार के मसौदे" पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ समूह की तीसरी बैठक।
- नई दिल्ली में 30 सितंबर 2014को सार्क मोटर वाहन करार के मसौदे और सार्क रेल करार के मसौदे के पाठ को अंतिम रूप देने के लिए परिवहन संबंधी सार्क अंतर–सरकारी समूह की 5वीं बैठक।
- नई दिल्ली में 24–25 सितंबर, 2014 को सार्क के संस्कृति मंत्रियों की तीसरी बैठक। इस बैठक में बामियान (अफगानिस्तान) को वर्ष 2015 के लिए सार्क सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। इस बैठक में सार्क विरासत सूची तैयार करने पर सहमति बनी तथा वर्ष 2015–17 के लिए संशोधित सार्क एजेंडे पर भी सहमति हुई।
- नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा खाद्य एवं कृषि संबंधी क्षेत्रीय तकनीकी समिति की चौथी बैठक (21–22 सितंबर, 2014), रसायन एवं रासायनिक उत्पादों पर क्षेत्रीय तकनीकी समिति की प्रथम बैठक (23–24 सितंबर, 2014) और विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार संबंधी क्षेत्रीय तकनीकी समिति की प्रथम बैठक (25–28 सितंबर, 2014) आयोजित की गई।
- ऊर्जा क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 16–17 अक्तूबर, 2014 को सार्क ऊर्जा मंत्रियों की 5वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ऊर्जा सहयोग (विद्युत हेतु) सार्क ढांचागत करार को भी अंतिम रूप दिया गया जिस पर काठमांडू में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए।
- माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में सहयोग पर चर्चा करने के लिए 30–31 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में सार्क के शिक्षा/उच्चतर शिक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा हेतु समान एवं विशेष सुविधा हेतु "दिल्ली घोषणा पत्र" को अंगीकार किया गया।
- 10–11 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में सार्क फूड बैंक की शासी बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई जिसमें सार्क फूड बैंक के लिए कार्यकारी दिशा–निर्देशों पर विचार किया गया।

27 नवंबर, 2014 को 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में सार्क देशों के नेता।

- 26–27 नवंबर,2014 को काठमांडू (नेपाल) में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और इससे पूर्व मंत्रिपरिषद और स्थायी समिति की बैठकों का क्रमशः विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने प्रतिनिधित्व किया। इस शिखर सम्मेलन में सार्क ऊर्जा सहयोग (विद्युत) हेतु करार की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए। दक्षिण एशिया में लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से "काठमांडू घोषणा पत्र" में एक प्रभावी वाहन के रूप में क्षेत्रीय सहयोग की शक्ति संवर्धन एवं सार्क को करने का आह्वान किया गया।
- उपरोक्त के अतिरिक्त सार्क प्रभाग ने निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान कीः–
  - i. बुक रिव्यू लिटरेरी ट्रस्ट द्वारा दक्षिण एशियाई विश्व विद्यालय का 2 विशेषांक का प्रकाशन।
  - ii. राष्ट्रपति भवन और पुराना किला (आई सी सी आर के सहयोग से) नवंबर, 2014में 8वां दक्षिण एशियाई बैण्ड महोत्सव।
  - iii. नई दिल्ली में नवंबर, 2014 में 7वां दक्षिण एशियाई आर्थिक शिखर सम्मेलन और भारतीय उप महाद्वीप और उससे बाहर क्षेत्रीय सहयोग पर एक अध्ययन (आर आई एस द्वारा)।

मार्च 2015 में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैंः–

मार्च 2015 में दूरसंचार और आई सी टी संबंधी कार्यकारी समूह की चौथी बैठक। पी टी बी की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से मार्च 2015 में नई दिल्ली में एसईजीए–III की सार्क पी टी बी समीक्षा बैठक।

मार्च 2015 के अंत में नई दिल्ली में सार्क के परिवहन मंत्रियों की बैठक।

13

विकास सहयोग

विकास साझेदारी प्रशासन

विदेश मंत्रालय में विकास साझेदारी प्रशासन (डी पी ए) की स्थापना जनवरी 2012 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमों की पहुंच और कार्यक्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। डी पी ए को अवधारणा, आरंभ, कार्य निष्पादन और पूर्ण करने के स्तरों के माध्यम से भारतीय विकास परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक संभालने हेतु कार्यविधि स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। इसका उद्देश्य भारत की विकास सहायता के मुख्य पहलुओं (Facts) को पूरा करने में शामिल प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना तथा उनका संवर्धन करना है उदाहरण के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहायता तथा अन्य योजनाओं के तहत क्षमता विकास कार्यक्रम, ऋण और अनुदान सहायता परियोजनाएं। डी पी ए मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों के साथ निकट सहयोग से कार्य करता है, जो भारत की विकास सहायता पहलों के तहत कवर किए जाने हेतु परियोजनाओं को वरीयता प्रदान करने तथा उनके चयन के लिए साझेदार देशों के साथ मुख्य संपर्क संस्थान रहा है।

डी पी ए परियोजना आंकलन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के चरणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में परियोजनाओं को संभालने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित कर रहा है। आरंभिक वर्षों में, डी पी ए ने विभिन्न विकासशील देशों के ऋण के तहत मुख्य परियोजनाओं को कवर करने और अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बंगलादेश तथा अफ्रीकी देशों में विकास परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया। तकनीकी सहायता और क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु मांग, जिसमें आम नागरिक और सेना कर्मी शामिल हैं, मैं साझेदार देशों से गत कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है।

ऋण श्रृंखला (एल ओ सी)

रियायती दरों पर ऋण हाल ही के वर्षों में कम विकसित और विकासशील देशों को भारत की विकास सहायता का एक मुख्य उपाय के रूप में उभरा है। ऋण अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमरीका में भारत की विकास सहायता नीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। द्विपक्षीय सहायता को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से एल ओ सी ने उधार लेने वाले देशों को भारत से माल और सेवाएं आयात करने तथा अपनी विकासात्मक वरीयताओं के अनुसार अवसंरचना विकास और क्षमता विकास के लिए परियोजनाएं लेने के योग्य बनाया है।

पिछले दशक के दौरान 214 एल ओ सी में कुल 13280.12 मिलीयन अमरीकी डॉलर आबंटित किए गए हैं, जिसमें से 7538.39 मिलीयन अमरीकी डॉलर अफ्रीकी देशों के लिए आबंटित किए गए थे और 5741.73 मिलीयन अमरीकी डॉलर गैर–अफ्रीकी देशों को स्वीकृत किए गए थे। 1 अप्रैल से 31 जनवरी, 2015 की अवधि के दौरान 2272.61 मिलीयन अमरीकी डॉलर की राशि के 14 एल ओ सी स्वीकृत किए गए हैं। इस अवधि के दौरान अफ्रीका को 881.17 मिलीयन अमरीकी डॉलर आबंटित किए गए हैं, जिसमें 200 मिलीयन अमरीकी डॉलर मॉरीशस के लाइट रेपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए बुरकीना फासो में पनबिजली परियोजना के लिए 184 अमरीकी डालर, 150 अमरीकी डालर घाना में कृषि प्रणाली सुदृदीकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन में इक्विटी भागीदारी के लिए, 65.68 मिलीयन अमरीकी डॉलर मॉरीटेनिआ को सोलर डीजल हाइब्रिड रूरल इलेक्ट्रीसिटी प्रोजेक्ट के लिए, 62.95 मिलीयन अमरीकी डॉलर सेनेगल को राइस सेल्फ–सफीशिएन्सी प्रोग्राम और 45 मिलीयन अमरीकी डॉलर गाम्बिआ को इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपेंशन एण्ड रिपलेसमेंट ऑफ एस्बेस्टस वाटर पाइप ऑफ परियोजना के लिए, 1000 मिलीयन अमरीकी डॉलर नेपाल को जलविद्युत, सिंचाई और विभिन्न अन्य अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए, 100 मिलीयन अमरीकी डॉलर विएतनाम को भारत से विशेषीकृत उपकरणों की खरीद के लिए, 140 मिलीयन अमरीकी डॉलर म्यांमार को दो सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए, 70 मिलीयन अमरीकी डॉलर फिजी को सह–उत्पादन विद्युत संयंत्र तथा 50 मिलियन गुआना में रोड परियोजना के लिए 26.24 मिलीयन अमरीकी डॉलर निकारागुआ को विद्युत पारेषण लाइन और उप–स्टेशन परियोजना के लिए आबंटन शामिल है।

2010 में, भारत ने बंगलादेश को 1 बिलीयन अमरीकी डॉलर के ऋण की घोषणा की थी। इसमें से 200 मिलीयन अमरीकी डॉलर को 2012 में बंगलादेश सरकार द्वारा वरीयता दी गई परियोजनाओं में उपयोग हेतु अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया था। ऋण के तहत उपलब्ध शेष 800 मिलीयन अमरीकी डॉलर को कुल 751.95 मिलीयन अमरीकी डॉलर की 15 परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें आपूर्तियों के साथ ही अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। आपूर्तियों की खरीद पूरी हो गई है।

रेल पुल, रेल लाइनें आदि के निर्माण सहित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। एल ओ सी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी बंगलादेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षों के साथ आवधिक सभी बैठकों के माध्यम से की जाती है।

नेपाल को वर्ष 2007 और 2010 में क्रमशः 100 मिलीयन अमरीकी डॉलर और 250 मिलीयन अमरीकी डॉलर की दो एल ओ सी के अलावा जलविद्युत, सिंचाई और अन्य विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए 1000 मिलीयन अमरीकी डॉलर की एल ओ सी दी गई है। सड़क परियोजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं विद्युत ट्रांसमिशन और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 100 मिलीयन अमरीकी डॉलर की एल ओ सी का पूर्णतः उपयोग किया गया है। विद्युत ट्रांसमिशन और सड़क परियोजनाओं के लिए दी गई 250 मिलीयन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला पर कार्य तेजी से चल रहा है और सड़क परियोजना अच्छी चल रही है। 69.37 मिलीयन अमरीकी डालर, कुल मिला कर इस एल ओ.सी के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी के भाग के रूप में, समीक्षा मिशनों के अधिकारियों ने नेपाल, बंगलादेश और म्यांमार का दौरा किया। भारतीय दूतावासों और आयात–निर्यात बैंक, भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए उधार देने वाले के एजेंट से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

पड़ोसी देशों में अनुदान सहायता प्राप्त विकास परियोजनाएं

अफगानिस्तान सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिक क्षेत्रों के अनुसार अफगानिस्तान में अवसंरचनात्मक विकास, जलविद्युत परियोजनाओं, विद्युत उप–केन्द्रों, कृषि से जुड़ी परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हेरात प्रोविन्स में सलमा डैम (42 मेगावाट) का पुनर्निर्माण कार्य अगले वित्त वर्ष में पूरा होने की संभावना है। दोषी और चारीकर स्थित दो उप केन्द्रों का कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरा होने की संभावना है।

अफगान की संसद का निर्माण कार्य प्रगति पर है हालांकि लागू करने वाली एजेंसियों की पहचान करने में आ रही दिक्कतों के कारण यह कार्य धीमी गति से हो रहा है। अफगानिस्तान को 2.5 मिलीयन टन गेहूं की आपूर्ति और इसकी ढुलाई का कार्य अप्रै, 2014 में पूरा हो गया और काबूल स्थित इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय बालक अस्पताल (इन्दिरा गांधी इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स हॉस्पीटल) में चिकित्सीय उपस्कर की आपूर्ति और इसे चालू किए जाने का कार्य आरंभ हो गया है। स्टोर पैलेस के पुनरुद्धार का कार्य बहुत बारीकी से किया जा रहा है ताकि इस महल को अपने वास्तविक भव्य स्वरूप में लाया जा सके। कांधार की अफगानिस्तान नेशनल एग्रीकल्चरल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (ए एन ए एस टी यू) के विधार्थियों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई), नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया। ग्रंथालयों के लिए पुस्तकों और प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करों की आपूर्ति के माध्यम से अफगानिस्तान नेशनल एग्रीकल्चरल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इन्डियन स्कूल ऑफ माइन्स में अफगान के अधिकारियों/कर्मचारियों को खनन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है। एक खनन संस्थान की स्थापना किए जाने, बसों की आपूर्ति और संबद्ध डिपो की पूर्ति संबंधी प्रस्ताव भी विचार/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। अफगानिस्तान के साथ भारत के विकास की भागीदारी में शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में किए जाने वाले सहयोग में भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद (आई सी सी आर) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के 674 छात्रवृत्तियों से अफगान राष्ट्रिकों के लिए प्रतिवर्ष 1000 विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति दिया जाना शामिल है। महत्वपूर्ण प्रगति का दूसरा क्षेत्र कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण जिनका सामुदायिक जीवन पर प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, के क्षेत्र में स्थानीय स्वामित्व और प्रबंध पद ध्यान केन्द्रित करते हुए सुमेद सीमा क्षेत्रों में समुदाय–परक परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दो चरणों में लघु विकास परियोजनाओं को लागू किया जाना है। लघु विकास परियोजनाओं (नवम्बर 2012 में शुरू की गई) के तीसरे चरण में 100 मिलीयन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त परियोजनाएं शामिल होंगी और इसमें देश के सभी प्रान्त शामिल होंगे।

आर्थिक विकास में वृद्धि करने और विकास को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सम्पर्क साधन में अभिवृद्धि करने के लिए सीमा पार की बहुत सी परियोजनाएं योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें कलादां मल्टी ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (जिससे भारत के पूर्वी सामुद्रिक और म्यांमार के सित्वे पोर्ट के बीच और तत्पश्चात मिजोरम में भारत–म्यांमार सीमा तक सम्पर्क मार्ग होगा) ये भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग जिसमें भारत तमूकलेवा–कलेम्यो खंड में पुलों का निर्माण होगा और कलेवा–यग्यी खंड में 120 किलोमीटर सड़क का कोटि उन्नयन किया जाएगा। लागू की जाने वाली अन्य सड़क परियोजनाओं में रिट–टिड्डिम मार्ग शामिल है। कृषि उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से ने पाइ नौ में एडवान्स्ड सेन्टर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड एजुकेशन और एक राइस बायो–पार्क की स्थापना की जा रही है। मंत्रालय में एक वैश्विक दर्जे का म्यांमार इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फौर्मेशन टेक्नोलॉजी (एम आई आई टी) स्थापित किए जाने के विषय पर भी विचार किए जाने का कार्य अग्रिम चरण में है। यंगून चिल्ड्रेन हॉस्पीटल एण्ड सित्वे जनरल हॉस्पीटल को अत्याधुनिक चिकित्सीय उपस्कर की आपूर्ति और इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है।

भू–अभिलेख विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय को डेस्कटॉप कम्प्यूटरों की आपूर्ति का कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरी होने की प्रत्याशा है। यंगून और ने पाई ताओ में भाषा प्रयोगशाला और ई–रिसोर्स सेंटर की स्थापना का कार्य अप्रैल, 2014 में पूरा हुआ था।

भारत और नेपाल के बीच सम्पर्क सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सीमा पार परियोजनाओं में भारत–नेपाल सीमा और क्रॉस–बोर्डर रेल संपर्क पर एकीकृत चेकपोस्ट का निर्माण किया जाना शामिल है। दक्षेस शिखर वार्ता के लिए अपनी नेपाल यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने काठमांडु में एक 200 बिस्तर वाले आपातकालीन और संधान केन्द्र (इमरजेंसी एण्ड ट्रौमा सेन्टर) का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रिक क्रॉस–बोर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण, रितौदा में पोलीटेक्निक की स्थापना, नेपाल की नगरपालिकाओं को अग्निशमन इंजन की आपूर्ति, पशुपति नाथ मंदिर के परिसर के समीप धर्मशाला का निर्माण, दक्षिणकाली–कुलेखाती रोड का कोटिउन्नयन आदि विचार/कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।

श्रीलंका के साथ भारत के विकास की हिस्सेदारी परामर्शदात्री दृष्टिकोण पर आधारित है जो सरकार की प्राथमिकताओं में दृष्टिगोचर होता है। बहु–क्षेत्रीय हिस्सेदारी में जाफना सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण और निरूकथेश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार शामिल है। डिकोया में 150 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण कार्य वर्ष में पूरा हो गया था।

भारत एक बड़ी आवासीय परियोजना जिसमें 50,000 भवनों का निर्माण किया जाना शामिल है, के माध्यम से श्रीलंका में इंटर्नली डिसप्लेस्ट पर्सन्स (आई डी पी) के पुनर्थक स्थापना में सहयोग कर रहा है। 17 जनवरी, 2012 को भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था जिसमें परियोजना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अभिपुष्ट की गई है। 1000 भवनों के निर्माण की प्रायोगिक परियोजना वर्ष 2012 में पूरी हुई थी। उत्तरी पूर्वी प्रान्तों में स्वामित्व–प्रेरित प्रक्रिया के अन्तर्गत 45,000 भवनों के निर्माण और मरम्मत के दूसरे चरण का कार्य इस समय जारी है। वर्ष 2013 के अन्त तक 10,250 भवनों का निर्माण कार्य हुआ, अन्य 16,000 भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 2014 के अन्त तक पूरा होने की प्रत्याशा है और शेष कार्य वर्ष 2015–16 तक पूरा होने की प्रत्याशा है। स्वामी चालित निर्देश में उनके भवनों के निर्माण में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से संलग्न किया जाता है, निधियां निर्माण के चार परिभाषित चरणों में समापन से संबद्ध चार किस्तों में उनके बैंक खाते में भेजी जाती हैं। इस परियोजना का कार्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। पौधारोपण क्षेत्र में नियोजित भारतीय मूल के तामिलों के लिए मध्य/यूवा प्रान्तों में एजेंसी चालित मॉडल के अन्तर्गत परियोजना का तीसरा चरण अर्थात 4000 भवनों का निर्माण कार्य भी श्रीलंका की सरकार द्वारा भूमि की पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात शुरू हो चुका है। इस परियोजना हेतु नियुक्त परामर्शदाता ने परियोजना के लिए प्रारंभिक अभिकल्प और विकास का कार्य आरंभ कर दिया है।

वर्ष के दौरान पूरी की गई द्विपक्षीय परियोजनाओं में माले, मालदीव में भारत सरकार की सहायता से निर्मित भारत–मालदीव फ्रेंडशिप फैकल्टी एण्ड टूरिज्म स्टडीज और उलानबातर, मंगोलिया में राजीव गांधी स्कूल ऑफ प्रोडक्शन एण्ड आर्ट का फेज–1 शामिल है।

अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में विकास परियोजना

अफ्रीका के साथ भारत की हिस्सेदारी सहयोग के परामर्शदात्री मॉडल, विकास के अनुभव को बांटे जाने पर आधारित है और यह अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों के निवारण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकासात्मक हिस्सेदारी के माध्यम से क्षमता निर्माण में अफ्रीकी देशों के साथ संपर्क और आर्थिक विकास में योगदान में पिछले दशक में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दो भारत–अफ्रीकी मंच की शिखर वार्ता (क्रमशः 2008 और 2011 में आयोजित) में इस महाद्वीप के साथ विकास की साझेदारी को और अधिक बल मिला है। अनुदान सहायता के अंतर्गत अफ्रीकी देशों को दिए गए उल्लेखनीय सहयोग में लाइबेरिया को 15 बसों की आपूर्ति और घाना में टमाटर उत्पादन और प्रसंस्करण संबंधी प्रायोगिक शोध परियोजना के लिए 2.088 मिलीयन अमरीकी डॉलर दिया जाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त सहायता राशि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरणों अस्पताल उपस्करों, दवाइयों, एम्बुलेंसों, वाहनों, ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों तथा अफ्रीका के कई अन्य देशों में अन्य वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रदान की गई थी।

आपदा राहत के लिए मानवीय सहायता

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को भारत द्वारा मानवीय आधार पर सहायता प्रदान की गई थी। यह सहायता सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोवीना, फिलीपीन्स, क्रोशिया, सीरिया, नेपाल, सोलोमन द्वीप और बुरून्डी के लिए दी गई थी। इसके अतिरिक्त निकारागुआ को दवाइयों की, अल्जीरिया को और सुरक्षा रोग से संबंधित बैक्सीन तथा नेपाल को एरियल रोडवे की आपूर्ति की गई थी।

तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी, एससीएएपी तथा कोलम्बो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना) के माध्यम से क्षमता निर्माण

पूर्व के वर्षों की भांति वर्ष 2014–15 में भारत का विकास सहभागिता कार्यक्रम हमारी क्षमता निर्माण का एक पूर्ण पहलू बना रहा है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी)कार्यक्रम, अफ्रीका कार्यक्रम हेतु विशेष राष्ट्रमंडलीय सहायता (एस सी ए ए पी) तथा कोलम्बो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना (टी सी ओ) निरंतर सुदृढ़ होती रही है तथा नए–नए क्षेत्रों में नई सहयोगी संस्थाओं और कार्यप्रणालियों को शामिल करने से उनका कार्यक्षेत्र और पहुंच बढ़ी है।

15 सितंबर, 1964 में आरंभ हुए आई टीई सी कार्यक्रम के 2014 में 50 वर्ष पूरे हो गए। इसका स्वर्ण जयंती समारोह 21 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली स्थित मौर्या शेरेटन होटल में हुआ। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री द्वारा किया गया। इस समारोह में विदेश राज्य मंत्री राजदूतों, आई टी ई सी के सहयोगी देशों के उच्चायुक्त आई टी ई सी की सहयोगी संस्थाओं के प्रमुखों/प्रतिनिधियों तथा

वर्तमान में भारत में इसके पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे सैकड़ों आई टी ई सी सहभागियों ने भाग लिया। स्वर्ण जयंती समारोह में विदेश मंत्री ने एक नए आई टी ई सी वेब पोर्टल की प्रिलांचिंग की। इससे आई टी ई सी आवेदनों की प्रोसेसिंग काफी सरल हो जाएगी और यह आई टी ई सी के पूर्व छात्रों के आपसी संवाद और जानकारी प्रदान करने वाले एक मंच के रूप में कार्य करेगा। विदेश मंत्री ने वर्ष 2014–15 के लिए एक आई टी ई सी विवरण पुस्तिका (आई टी ई सी द्वारा कराए जाने वाले सिविलियन पाठ्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी देने वाली पुस्तिका) भी जारी की। इसके अतिरिक्त लेसन्स इन फ्रेन्डशिप के नामवाली एक फिल्म भी दिखाई गई जिसमें विगत 50 वर्षों के दौरान आई टी ई सी की यात्रा और आपसी मित्रता पर प्रकाश डाला गया है। यह वृत्त चित्र विदेश मंत्रालय के एक्स पी डिवीजन के सहयोग से डी पी ए द्वारा तैयार किया गया था। इस महत्वपूर्ण लक्ष्त तक आई टी ई सी की पहुंच को यादगार बनाने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों और भारत में आई टी ई सी की सहयोगी संस्थाओं द्वारा अपने यहां पूरे साल समारोह आयोजित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान देश भर में फैली संस्थाओं में विभिन्न लघु अवधि और मध्यावधि पाठ्यक्रमों हेतु 161 सहयोगी देशों (सहयोगी देशों की सूची परिशिष्ट चार में दी है) के लिए आई टी ई सी/एस सी ए ए पी कार्यक्रम के तहत 8300 नागरिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। सहभागियों ने अपने प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय स्मारकों/विरासत स्थलों का अध्ययन दौरा भी किया। आई टी ई सी के तहत सिविलियन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो पूरी तरह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है में विभिन्न कार्यरत पेशेवरों के लिए लगभग 280 विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये विषय हैं–आई टी लोक प्रशासन, चुनाव प्रबंधन, एस एम ई, उद्यमशीलता, ग्रामीण विकास, संसदीय मामले तथा 47 प्रशिक्षण संस्थाओं में पुनप्रयोज्य ऊर्जा (आई टी ई सी/एस सी ए ए पी कार्यक्रम के तहत सिविलियन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं की सूची परिशिष्ट पांच में दी है।

एशिया और प्रशांत महासागर में सहकारी और आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना के अंतर्गत 500 अन्य छात्रवृत्तियां भी प्रदान की गई थीं। इसके तहत प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित शामिल थे–मानव संसाधन विकास लेखापरीक्षा और लेखे, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाइल, वित्तीय प्रबंधन, बीमा इत्यादि। भारत की प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं अर्थात एनएडीटी नागपुर, एल बी एस एन ए ए–मसूरी, आई जी एन एफ ए–देहरादून, एन ए ए ए–शिमला और एन ए सी ई एन, फरीदाबाद में इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष भूटान के दस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत–भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति पर भेजता रहा है तथा मनीला स्थित कोलम्बो प्लान सटॉफ कॉलेज रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी पी एस सी) में सेकेन्डमेंट हेतु भारतीय शिक्षक प्रदान करता रहा है।

रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

2014–15 के दौरान, सहभागी देशों को 1600 रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किए गए थे। ये पाठ्यक्रम सामान्य एवं विशिष्ट दोनों स्वरूप के थे जिनमें सुरक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, समुद्री जलविज्ञान, काउंटर इन्सर्जेंसी और जंगल संघर्ष तथा साथ ही तीनों सेवाओ में युवा अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम भी शामिल थे। नेशनल डिफेंस कॉलेज, (एन डी सी) नई दिल्ली तथा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, (डी एस एस सी) वेलिंगटन जैसे अग्रणी संस्थानों में चलाए गए पाठ्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए और इसमें स्तवित्तपोषण आधार पर विकासशील देशों के अधिकारियों को आकर्षित किया।

विशेष पाठ्यक्रम

सामान्य आई टी ई सी/स्केप/टी सी एस– कोलंबो योजना पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त सहभागी देशों की मांग के अनुकूल नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न विषयों में विशेष पाठ्यक्रम चलाए गए:–

- 25–29 अगस्त, 2014 से संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा फीजी में हंसार्ड रिपोर्टस हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।
- 1 मई– 30 जुलाई, 2014 को फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर (एफ एफ डी सी), कनौज में रवांडा के युवा प्रशिक्षुओं के लिए इसेंशियल ऑयल फ्रैगरेंस एंड फ्लेवर पर विशेष पाठ्यक्रम चलाया गया।
- 9–23 अप्रैल, 2014 के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा चुनाव प्रबंधन सिद्धांत एवं क्रिया विधि पर तीसरा विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।
- 17–28 नवंबर, 2014 के दौरान विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आर आई एस) द्वारा दक्षिण–दक्षिण विकास सहभागित पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।
- 15 सितंबर–3 अक्तूबर, 2014 के दौरान ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा 'सतत विकास हेतु सामाजिक उद्यम' पर विशेष कार्यक्रम चलाया गया।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति विकासशील देशों के साथ भारतीय सुविज्ञता के आदान–प्रदान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय साबित हुई है। 2014–15 के दौरान फोरेंसिक साईंस आयुर्वेद, चावल उत्पादन के क्षेत्र में तथा सरकारों के सलाहकारों तथा राज्य के परामर्शकों के रूप में सहभागी देशों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उप विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। रक्षा प्रशिक्षण दलों को सहभागी देशों में प्रतिनियुक्त किया गया था। ■■

निवेश तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन

14

निवेश तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी) प्रभाग मंत्रालय के आर्थिक राजनयिक प्रयासों को निश्चित निर्देश और जोर देती है यह क्षेत्रीय प्रभागों, मिशनों और पोस्टों, भारत सरकार के मंत्रालयों और सर्वोच्च उद्योग संघों के समन्वय से निवेश एवं व्यापार संवर्धन गतिविधियों के लिए कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित व्यापार एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है। यह वित्त, वाणिज्यक, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अन्यों के साथ–साथ शिक्षा का कार्य देखने वाले मंत्रालयों को नीतिगत मुद्दों के संबंध में इनपुट प्रदान करता है तथा इन मंत्रालयों द्वारा गठित समितियों में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी करता है।

मंत्रालय के बजट की बाजार विस्तार गतिविधियां के अंतर्गत आईटीपी प्रभाग निर्यात और निवेश में वृद्धि करने के लिए मिशनों/पोस्टों के प्रयासों के संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करता है। 2014–15 में बजटीय शीर्ष के अंतर्गत मिशनों और पोस्टों को पांच करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। वाणिज्य विभाग की बाजार पहुंच उपाय (एमएआई) योजना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के रूप में यह विभाग वर्ष के दौरान होने वाली निर्यात संवर्धन गतिविधियों तथा व्यापार मेलों के संबंध में इनपुट प्रदान करता है। यह योजना विशिष्ट संवर्धन गतिविधियों और व्यापार मेलों में निर्यात संवर्धन परिषदों की भागीदारी का वित्त पोषण करती है।

आईटीपी प्रभाग ने स्वचालित मार्ग द्वारा शामिल नहीं किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कार्य देखने वाले आर्थिक मामलों के विभाग के विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड में तथा भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं तथा विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं को खोलने के संबंध में वित्तीय सेवा विभाग की अंतर विभागीय समिति ने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना जारी रखा। आईटीपी और कानूनी तथा संधि प्रभागों ने द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण करार के प्ररूप उद्धरण के संशोधन के लिए गठित समिति ने विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

आईटीपी प्रभाग विदेशों/एयरलाइनों के साथ वायुसेवा करारों से संबंधित सभी मामलों के लिए विदेश मंत्रालय में नोडल प्रभाग है और यह इन मामलों पर सिविल विमानन मंत्रालय के साथ घनिष्ठता से कार्य करता है। 2014 में प्रभाग ने मिस्र, सेसेल्स, कोरिया गणराज्य तथा न्यूजीलैंड के साथ आयोजित द्विपक्षीय वायु सेवा वार्ता में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। आईटीपी प्रभाग ने नवंबर, 2014 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन वार्ता (आईसीएएम) सम्मेलन में भी भाग लिया।

विभाग ने मंत्रिमंडल सचिवालय के तत्वाधान में गठित परियोजना निगरानी समिति तथा पत्तन परियोजनाओं के संबंध में जहाजरानी मंत्रालय की समिति ने विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त, आईटीपी प्रभाग ने परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद् तथा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् की कार्य समितियों के साथ कार्य किया। सचिव (आर्थिक संबंध) ने एक्जिम बैंक के बोर्ड में कार्य करना तथा संयुक्त सचिव (आईटीपी) ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), निवेश भारत और वैश्विक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी संबंध (जीआईटीए) में सरकारी नामितियों के रूप में कार्य करना जारी रखा।

आईटीपी प्रभाग ने नई दिल्ली में 26–27 नवंबर, 2014 को चौथे भारत–अरब भागीदारी सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर संघ (फिक्की) को बजटीय सहायता प्रदान की। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आईटीपी प्रभाग के सहयोग से 4–5 दिसंबर, 2014 को ''अफ्रीका के संबंध में सम्मेलन–संभावनाओं की भूमि'' की मेजवानी की।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 25 सितंबर, 2014 को ''मेक इन इंडिया'' अभियान आरंभ किया गया। विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों ने इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए कई इवेंट आयोजित किए। उन्हें इस इवेंट में एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय तथा विदेशी उद्योगपतियों, एनआरआई, उद्योग संघों के सदस्यों को शामिल करने के लिए कहा गया था। आईटीपी प्रभाग ने इवेंट के आयोजन के लिए सूचना, डाटा इत्यादि प्रदान करने हेतु डीआईपीपी के साथ समन्वय करते हुए मिशनों/पोस्टों को सहायता प्रदान की।

विदेश मंत्रालय की ओर से आईटीपी प्रभाग नोडल विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ चीन–प्रस्तावित आसियान अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की स्थापना के लिए वार्ताओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

आईटीपी प्रभाग ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए हैमबर्ग और पेरिस में आयोजित पुनः–निवेश रोड शो में भाग लिया। आईटीपी प्रभाग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन तथा निर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में परस्पर सहयोग के संवर्धन के लिए द्विपक्षीय बैठकों और रोड शो के आयोजन के लिए जर्मनी को जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के प्रतिनिधिमंडल का भी भाग था।

भारत में आईटीपी प्रभाग की बिजनेस वेबसाइट (www.indiabusiness.nic.in) ने भारतीय अर्थव्यवस्था, नई नीतिगत कदमों, भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों इत्यादि की वर्तमान स्थिति के संबंध में सूचना प्रदान करना जारी रखा। सभी मिशनों/पोस्टों को सप्ताहिक तथा मासिक समाचार–पत्र भेजे गए थे जिसने उन्हें आर्थिक एवं वाणिज्यिक मुद्दों पर समयबद्ध अद्यतन जानकारी प्रदान की।

आईटीपी प्रभाग के बिजनेस में भारत के वार्षिक प्रकाशन को विदेशों में मिशनों/पोस्टों को वितरित किया गया। ये प्रकाशन निवेश संभावनाओं, विनियामक ढांचे के विभिन्न पहलुओं तथा भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर सूचना प्रदान करते है।

ऊर्जा सुरक्षा

15

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग की स्थापना विदेश मंत्रालय में वर्ष 2009 में की गई थी और यह भारत की ऊर्जा कूटनीति का समन्वय करता है तथा विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों में सरकार की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संबंधी कार्यों के लिए नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करता है। यह राजनयिक कदमों के माध्यम से सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पॉवर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, की अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों का समर्थन करता है। यह ऊर्जा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए), ऊर्जा सक्षमता और सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (आईपीईईसी), अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ), अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम) इत्यादि तथा जी–20, पूर्वी एशिया समिट, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, आईबीएसए इत्यादि में ऊर्जा से संबंधित मामलों पर भारत के संपर्क का कार्य करता है। यह परिकल्पना की जाती है कि यह कृषि एवं उर्वरक जैसे मंत्रालयों के समन्वय से खाद्य सुरक्षा के मामलों का संचालन करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों के साथ बैठकों में भागीदारी

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने निम्नलिखित बैठकों में सक्रिय भागीदारी द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों के साथ कार्य किया:

- 12–13 मई, 2014 के दौरान सिओल, दक्षिण कोरिया में आयोजित 5वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयी बैठक;
- पेरिस में 2–3 जून, 2014 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के स्थायी समूह की दीर्घावधि सहयोग (एसएलटी)/ऊर्जा शोध तथा प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (सीईआरटी) की बैठकें;
- 2–3 जून, 2014 तथा 3–4 नवंबर, 2014 को अबूधाबी (यूएई) में आयोजित आईआरईएनए –आईआरईएनए परिषद् की क्रमशः 7वीं और 8वीं बैठक;
- ऊर्जा सक्षमता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (आईपीईईसी) –नीति समिति (पीओसीओ) की 9वीं तथा 10वीं बैठक क्रमशः मेक्सिको में 16–17 जून, 2014 को आयोजित की गई और शंघाई, चीन में 24–25 नवंबर, 2014 को आयोजित की गई। इसने 10–11 सितंबर, 2014 के दौरान पेरिस में आयोजित कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ) की बैठक में भी भाग लिया;
- जी–20 ऊर्जा सततता कार्य समूह–मेलबर्न, अस्ट्रेलिया में 10–13 फरवरी, 2014 को आयोजित जी–20 ईएसडब्ल्यूजी की पहली बैठक के संदर्भ में दूसरी बैठक 28–30 मई, 2014 के दौरान सिडनी में और तीसरी बैठक 25–27 अगस्त, 2014 को ब्रिसबेन, अस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। ईएसडब्ल्यूजी में विश्व ऊर्जा वास्तु, गैस बाजार के सुदृढ़ीकरण, बाजार पारदर्शिता और निवेश, ऊर्जा सक्षमता तथा असक्षम फोसिल ईंधन इमदाद को हटाने पर विचार व्यक्त किए;
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)–प्रथम उच्च स्तरीय समूह, ऊर्जा क्लब की अस्ताना, कजाकिस्तान में 5 जून, 2014 को बैठक हुई और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा तथा उनके संबद्ध देशों में ऊर्जा सक्षम क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर विचार–विमर्श किया गया;
- आसियान एवं प्रशांत ऊर्जा मंच (एपीईएफ) –ऊर्जा डाटा तथा नीति सूचना पोर्टल तैयार करने के संबंध में विशेषज्ञ समूह की बैठक (ईजीएम) 26–27 अगस्त, 2014 तथा 2014 नीति वार्ता बैंकॉक, थाइलैंड में 26–28 नवंबर, 2014 को आयोजित की गई। ऊर्जा संबंधित डाटा और सदस्य देशों की नीति के संबंध में पोर्टल तैयार किया जा रहा है;
- ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग के 17–22 जनवरी, 2015 के दौरान अबूधाबी (यूएई) में आयोजित होने वाले आईआरईएनए ऊर्जा असेंबली के 5वें सत्र और 8वें विश्व भविष्य ऊर्जा समिट में भाग लेने का प्रस्ताव है।

द्विपक्षीय ऊर्जा बैठकें/अन्य बैठकें

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने 24–25 अप्रैल, 2014 को अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित 11वें भारत–कजाकिस्तान अंतर–सरकारी आयोग (आईजीसी) तथा तेल एवं गैस क्षेत्र में परस्पर सहयोग के मामलों पर रियाद में 28 अक्तूबर, 2014 को दूसरे भारत–सऊदी ऊर्जा परामर्शों में भाग लिया।

कजाकिस्तान एक्सपो–2017 का आयोजन कर रहा है जिसका शीर्षक भविष्य की ऊर्जा है। एक्सपो–2017 की तैयारी बैठक के रूप में 22–24 अक्तूबर, 2014 के दौरान अस्ताना में भविष्य ऊर्जा मंच तथा अंतर्राष्ट्रीय आयोजना की बैठक आयोजित की गई। ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने भविष्य ऊर्जा मंच की बैठक में भाग लिया।

जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) तथा एशिया प्रशांत ऊर्जा शोध केंद्र (एपीईआरसी) द्वारा आयोजित तीसरे एलएनजी उत्पादक–उपभोक्ता सम्मेलन का 6 नवंबर, 2014 को टोकियो में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य एलएनजी बाजार के संबंध में वैश्विक परिदृश्य को साझा करना तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुकर बनाना था।

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग 14 जनवरी, 2015 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ संयुक्त अनौपचारिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन कर रहा है।

टीएपीआई पाइप लाइन परियोजना से संबंधित तकनीकी कार्य समूह और अनुवीक्षण समिति की अगली बैठक फरवरी, 2015 में आयोजित की जानी संभावित है।

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग 9 जनवरी, 2015 को भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित किए जा रहे ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन से जुड़ा है।

टीएपीआई पाइपलाइन परियोजना

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा गेल के साथ टीएपीआई पाइपलाइन परियोजना पर घनिष्ठता से समन्वय किया। 6–8 जुलाई, 2014 के दौरान अशगाबट, तुर्कमिनिस्तान में 26वें तकनीकी कार्य समूह तथा तत्पश्चात् 18वीं अनुवीक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। अशगाबाट, तुर्कमिनिस्तान में 18–20 नवंबर, 2014 के दौरान तकनीकी कार्य समूह की 27वीं बैठक तत्पश्चात् टीएपीआई पाइपलाइन परियोजना संबंधी अनुवीक्षण समिति की 19वीं बैठक आयोजित की गई। टीएपीआई लिमिटेड को 11 नवंबर, 2014 को शामिल किया गया था। टीएपीआई गैस पाइपलाइन परियोजना पर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है और इसके लिए वार्ता अग्रिम चरण में है।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार के हाल ही के थ्रस्ट के साथ फरवरी, 2015 में पहली नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक निवेशक बैठक और एक्सपो (पुनः निवेश) का आयोजन किया जा रहा है। तैयारी संबंधी कार्यवाही के रूप में ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ घनिष्ठता से समन्वय कर रहा है और उसने संभावित वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नवंबर, 2014 के दौरान हैमबर्ग तथा पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो में भाग लिया है तथा एम्स्टर्डम, लंदन तथा संघीई में रोड शो का समन्वय किया है।

आंतकवाद का सामना और नीति आयोजना

16

आतंकवाद का सामना (सीटी)

भारत ने आतंकवाद की सभी कार्रवाइयों की निंदा की है और वह विश्व में आतंकवाद तथा इसकी हर प्रकार की अभिव्यक्ति की समस्या को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति वचनबद्ध है।

भारत ने वर्ष के दौरान आतंकवाद का सामना (सीटी) के संबंध में भागीदार देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) के माध्यम से अपनी ढांचागत वार्ता जारी रखी। भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ सीटी पर जेडब्ल्यूजी आयोजित की (अवधि अप्रैल–नवंबर, 2014 के दौरान):

क्र. सं.	देश/संगठन का नाम	तारीख	स्थान
1.	जर्मनी	15–16 मई, 2014	नई दिल्ली
2.	आस्ट्रेलिया	4 अगस्त, 2014	कैनबरा

भारत 15–16 जनवरी, 2015 को लंदन में यूके के साथ सीटी के संबंध में एक जेडब्ल्यूजी का आयोजन करेगा। इससे भारत तथा यूके के बीच सीटी सहयोग में और वृद्धि होने की संभावना है। तुर्की, इंडोनेशिया और ईयू के साथ फरवरी–मार्च, 2015 के दौरान जेडब्ल्यूजी आयोजित करने का प्रस्ताव है। भारत विश्व आतंकवाद रोधी मंच (जीसीटीएफ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। जीसीटीएफ में सिविलियन क्षमता निर्माण के लिए विशेषज्ञ और संसाधनों को जुटाने तथा अपराधिक न्याय प्रणाली तथा हिंसा उग्रवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों में मानदंड तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

भारत ने हाल ही में यूएन, जीसीटीफए, एससीओ, एआरएफ इत्यादि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भागीदारी की है।

वैश्विक साइबर मुद्दा प्रकोष्ठ

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बढ़ते हुए उपयोग ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत सरकार के हितों को रखने तथा उनकी सुरक्षा में विदेश मंत्रालय की भागीदारी आरंभ की है। सीटी–जीसीआई, पीपीएंडआर प्रभाग, विदेश मंत्रालय में वैश्विक साइबर मुद्दा प्रकोष्ठ वैश्विक साइबर मुद्दों से संबंधित सभी मामलों का कार्य देखता है।

विदेश मंत्रालय ने 23–24 अप्रैल, 2014 में साओपालो, ब्राजील में इंटरनेट अभिशासन के भविष्य (एनईटी मुंडेल के रूप में भी ज्ञात) के संबंध में वैश्विक बहु–पणधारी बैठक के लिए एक अंतर–मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल भेजा। विभिन्न बहुराष्ट्रीय मंचों में विदेश मंत्रालय ने पारदर्शी, गणतांत्रिक और प्रतिनिधित्व इंटरनेट अभिशासन के लिए सहमति और समर्थन बनाना तथा प्रमुख देशों और संगठनों जैसे कि ईयू के साथ वैश्विक साइबर मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा।

आने वाले आयोजनः जनवरी, 2015 में कोरिया गणराज्य (आरओके) के साथ तथा फरवरी, 2015 में यूके और फ्रांस के साथ वैश्विक साइबर मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ताएं।

नीति आयोजना और शोध

नीति आयोजना और शोध के क्षेत्र में इस प्रभाग ने विदेश नीति पर शोध तथा लेखों में रत शिक्षा जगत, विचारकों, शोध संगठनों और भारत के विदेश नीति संस्थानों को अपना समर्थन देना और उन्हें भारत के बाह्य संबंधों के विभिन्न आयामों पर विचार–विमर्श करने के लिए सेमीनार, सम्मेलन और अध्ययन आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा।

इस प्रभाग की ऐसी आउटरीच गतिविधियों के जरिए मंत्रालय ने विदेश नीति तथा वैश्विक मामलों के विभिन्न क्षेत्रों पर नए परिदृश्य और विशेषज्ञों के सूचित मत प्राप्त किए। देश में विभिन्न संस्थानों में आयोजित प्रभाग द्वारा आंशिक/पूर्णतः वित्त–पोषित सेमीनारों, सम्मेलनों, बैठकों और अध्ययनों की एक सूची **परिशिष्ट–VI** में दी गई है।

प्रभाग ने विदेश मंत्री और विदेश सचिव के लिए मसौदा भाषण तैयार किए। इसमें मंत्रिमंडल के लिए विदेश मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का मासिक सार तथा एक समयबद्ध तरीके से

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का समेकन, मुद्रण और वितरण करना जारी रखा। प्रभाग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन के 2014 अंक के अध्याय ''भारत तथा विदेश'' के लिए सामग्री इकट्ठी और समेकित की। इसने उन मुद्दों पर 13 मार्च, 2014 को विदेश सचिव के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की एक बैठक आयोजित की जिन पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय के साथ वार्ता करने की आवश्यकता थी। इस प्रभाग ने फरवरी, 2014 में अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के समय संसद सदस्यों में परिचालन हेतु ''विदेश मंत्रालय की गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण'' संबंधी एक पुस्तिका प्रकाशित की।

परिस्थिति कक्ष

परिस्थिति कक्ष मंत्रालय का एक बहु–आयमी, बहु–सुविधा आधुनिक कला परिसर है। 2007 में स्थापित इस कक्ष में किसी आपदा परिस्थिति के प्रबंधन के लिए आवश्यक अपेक्षित संचार कनेक्टिविटी और डिस्प्ले पैनल है। मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका के अतिरिक्त इस परिसर का सभी प्रभागों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि टेलीफोन/वीडियो क्रॉन्फ्रेंस इत्यादि सहित प्रस्तुतियों और सम्मेलनों के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता रहा है। अब वीडियों क्रॉन्फ्रेंसिंग सुविधा 17 मिशनों में स्थापित कर दी गई है। जेएनबी में नया परिस्थिति कक्ष पूरा हो गया और सभी उपकरणों के विस्तृत परीक्षण करने के पश्चात् ठेकेदार से इसे ले लिया गया है।

सीमा प्रकोष्ठ

सीमा प्रकोष्ठ भारत की बाह्य सीमाओं के सभी पहलुओं और भारतीय सर्वेक्षण के समन्वय से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को शामिल करते हुए मानचित्रों की प्रकाशन हेतु की जांच करती है। यह विदेश मंत्रालय में अन्य प्रभागों को सीमा से संबंधित मामलों पर भूगोलीय सलाह और तकनीकी प्रदान करती है। यह उपलब्ध भूगोलीय स्ट्रिप/आधार मानचित्रों के समेकन और डिजिटीकरण में सहायता करती है। यह प्रकोष्ठ सीमा खंभों के रखरखाव/मरम्मत सहित संयुक्त सीमा सर्वेक्षण कार्य तथा भारतीय क्षेत्र में किसी घुसपैठ की रिपोर्ट (डाटाबेस इत्यादि रखना) के संबंध में भारतीय सर्वेक्षण/राज्य सरकारों के साथ भी तालमेल रखती है। यह समुंद्री सीमा, अनन्य आर्थिक जोन (ईईजेड) तथा महाद्वीपीय जल सीमा के वर्णन से संबंधित सूचना के समेकन और डिजिटीकरण में भी सहायता प्रदान करती है। यह रक्षा मंत्रालय के समन्वय से प्रतिबंधित मानचित्रों की जांच करती है और नौसेनिक हाइड्रोग्राफिक कार्यालय तथा भूविज्ञान मंत्रालय के साथ तालमेल करती है। सीमा प्रकोष्ठ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित सभी मानचित्रों/दस्तावेजों/सूचना का संग्रह। सीमा प्रकोष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय भूमि और भारत की समुंद्री सीमा के संबंध में विभिन्न आंतरिक/अंतर–मंत्रालयी बैठकों में भाग लिया है।

■■

प्रोटोकॉल

17

विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल प्रभाग ने अप्रैल–नवंबर, 2014 के दौरान राष्ट्र प्रमुख, उपराष्ट्रपति, सरकार प्रमुख तथा विदेश मंत्री के स्तर पर 30 आने वाले और 14 जाने वाले दौरों का समन्वय किया। इस अवधि के दौरान दौरों के कैलेंडर की सूची नीचे दी गई है।

संदर्भाधीन अवधि के दौरान होन्डुरस और चार्ड ने नई दिल्ली में अपने दूतावास खोले; कोरिया गणराज्य ने बंगलौर में अपना व्यापार कार्यालय खोला; बांग्लादेश ने अगरतला में अपना सहायक उच्चायोग, यूके ने अहमदाबाद में अपना उप उच्चायोग खोला। चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता, तिरूवनंतपुरम और गोवा शहरों में 27 मानद कोंसुल खोले गए। 29 मिशन प्रमुखों ने राष्ट्रपति को अपने क्रेडेंशियल्स प्रस्तुत किए। नई दिल्ली में राजनयिक मिशनों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में 59 नए पद सृजित किए गए।

2014 के लिए यात्राओं का कैलेंडर

राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख/उप–राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर द्वारा राष्ट्र यात्राएं

क्र.सं.	मेहमान	दिनांक
1.	आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री	3–5 सितंबर, 2014
2.	चीन के राष्ट्रपति	17–19 सितंबर, 2014
3.	वियतनाम के प्रधानमंत्री	27–28 अक्तूबर, 2014

राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख/उप–राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर द्वारा अधिकारिक/कार्य संबंधी यात्राएं

क्र.सं.	मेहमान	दिनांक
1.	अफगानिस्तान के राष्ट्रपति	26 और 27 मई, 2014
2.	मालदीव के राष्ट्रपति	26 और 27 मई, 2014
3.	श्रीलंका के राष्ट्रपति	26 और 27 मई, 2014
4.	भूटान के प्रधानमंत्री	25–28 मई, 2014
5.	मॉरीशस के प्रधानमंत्री	26 और 27 मई, 2014
6.	नेपाल के प्रधानमंत्री	25–28 मई, 2014
7.	पाकिस्तान के प्रधानमंत्री	26 और 27 मई, 2014
8.	बांग्लादेश के स्पीकर	25–28 मई, 2014

राष्ट्र प्रमुख/सरकार/उप–राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला और समकक्ष स्तर की निजी/ट्रांजिट यात्रा

क्र.सं.	मेहमान	दिनांक
9.	घाना के उप–राष्ट्रपति	3–7 नवंबर, 2014
10.	रवांडा के राष्ट्रपति	3–7 नवंबर, 2014

11.	कोटे डी'ल्वोइरे के प्रधानमंत्री	3–7 नवंबर, 2014
12.	नेपाल के उप–राष्ट्रपति	8–11 नवंबर, 2014

विदेश मंत्री और समकक्ष स्तर द्वारा अधिकारिक यात्रा

क्र.सं.	मेहमान	दिनांक
1.	ओमान के विदेश मंत्री	3 और 4 जून, 2014
2.	चीन के विदेश मंत्री	8–10 जून, 2014
3.	रूसी संघ के उप–प्रधानमंत्री	18 और 19 जून, 2014
4.	फ्रांस के विदेश मंत्री	9 जून–2 जुलाई, 2014
5.	सिंगापुर के विदेश मंत्री	30 जून–5 जुलाई, 2014
6.	यूके के विदेश मंत्री	7–9 जुलाई, 2014
7.	युगांडा के विदेश मंत्री	27–31 जुलाई, 2014
8.	राष्ट्र सचिव, यूएसए	30 जुलाई –1 अगस्त, 2014
9.	जर्मनी के विदेश मंत्री	8 सितंबर, 2014
10.	बांग्लादेश के विदेश मंत्री	18–21 सितंबर, 2014
11.	कनाडा के विदेश मंत्री	12–14 अक्तूबर, 2014
12.	गुवाटेमाला के विदेश मंत्री	14–16 अक्तूबर, 2014
13.	मेक्सिको के विदेश मंत्री	19–22 अक्तूबर, 2014
14.	नेपाल के विदेश मंत्री	19–21 अक्तूबर, 20134
15.	मोजाम्बिको के विदेश मंत्री	23–30 नवंबर, 2014

भारत के राष्ट्रपति/उप–राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री की बाहर जाने वाली यात्रा

क्र.सं.	मेहमान	दिनांक
1.	भूटान को प्रधानमंत्री	15 और 16 जून, 2014
2	चीन को उप–राष्ट्रपति	26–30 जून, 2014
3.	ब्राजील को प्रधानमंत्री (ब्रिक सम्मेलन)	13–18 जुलाई, 2014
4.	नेपाल को प्रधानमंत्री	3 और 4 अगस्त, 2014
5.	जापान को प्रधानमंत्री	31 अगस्त –3 सितंबर, 2014
6.	वियतनाम को राष्ट्रपति	15–18 सितंबर, 2014
7.	यूएसए को प्रधानमंत्री (द्विपक्षीय यात्रा केसाथ समेकित यूएनजीए)	25–30 सितंबर, 2014
8.	अफगानिस्तान को उप–राष्ट्रपति	29 सितंबर, 2014
9.	नार्वे और फिनलैंड को राष्ट्रपति	12–17 अक्तूबर, 2014
10.	भूटान को राष्ट्रपति	7 और 8 नवंबर, 2014
11.	म्यांमार को प्रधानमंत्री (पूर्वी एशिया समिट/आसियान–भारत समिट)	11–13 नवंबर, 2014

12.	आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री (द्विपक्षीय यात्रा केसाथ समेकित जी–20 समिट)	14–18 नवंबर, 2014
13.	फिजी को प्रधानमंत्री	19 और 20 नवंबर, 2014
14.	नेपाल को प्रधानमंत्री (सार्क सम्मेलन)	25–27 नवंबर, 2014

अप्रैल–नवंबर, 2014 के दौरान विदेश मंत्री की बाहर जाने वाली यात्राएं

क्र.सं.	देश जिसकी यात्रा की	दिनांक
1.	भूटान	15 और 16 जून, 2014
2.	बांग्लादेश	25–27 जून, 2014
3.	नेपाल	25–27 जुलाई, 2014
4.	म्यांमार	8–11 अगस्त, 2014
5.	सिंगापुर	15 और 16 अगस्त, 2014
6.	हनोई	25 और 26 अगस्त, 2014
7.	बहरीन	6 और 7 सितंबर, 2014
8.	काबुल और दुशांडबे	10–12 सितंबर, 2014
9.	यूएसए	24 सितंबर–2 अक्तूबर, 2014
10.	लंदन	16 और 17 अक्तूबर, 2014
11.	मॉरीशस	1–3 नवंबर, 2014
12.	यूएई	11 और 12 नवंबर, 2014
13.	नेपाल	24 और 27 नवंबर, 2014

कोंसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा सेवाएं

18

मंत्रालय का कोंसलर, पासपोर्ट एंव वीजा प्रभाग (सीपीवी) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और पासपोर्ट कार्यालयों के इसके नेटवर्क एंव पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है; और विदेश स्थित भारतीय मिशनों एंव केन्द्रों के माध्यम से आप्रवासी भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को कोंसुलर, वीजा एवं पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है ।

पासपोर्ट सेवाएं

हाल के वर्षों में पासपोर्ट जारी किया जाना विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सुस्पष्ट और साविधिक एवं नागरी सेवा के रूप में उभरा है । हाल के वर्षों में मंत्रालय ने देश में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने में कई गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार किए हैं । भारतीय पासपोर्ट (तिब्बती शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र, भारत वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र भारत वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र जम्मू और कश्मीर में पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र और नियंत्रण रेखा यात्रा अनुमति जैसे अन्य यात्रा दस्तावेजों सहित) विदेश मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन और 37 पासपोर्ट कार्यालयों के इसके अखिल भारतीय नेटवर्क, सीपीवी प्रभाग (केवल राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं । इस नेटवर्क में काफी विस्तार किया गया है अर्थात पीपीपी मोड में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र जुड़े हैं और पासपोर्ट कार्यालयों के विस्तारित क्षेत्र के अंग के रूप में कार्यात्मक/प्रभावी अतिरिक्त 18 पासपोर्ट सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं । विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए कोंसुली दस्तावेजों के सत्यापान के अतिरिक्त पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड पीआईओ कार्ड, इसी एवं अन्य विविध कोंसली सेवाएं 118 भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती है ।

पासपोर्ट सेवाओं में उच्च वृद्धि

पिछले दशक में, पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के कार्यक्षेत्र और इसकी मात्रा दोनों में पर्याप्त विस्तार हुआ है । जनवरी–दिसंबर, 2014 के दौर मंत्रालय ने 2013 में 86.88 लाख की तुलना में लगभग 1.01 करोड़ पासपोर्ट तथा संबंधित सेवा आवेदनों की चौका देने वाली संख्या पर कार्यवाई की है जिसके चलते लगभग 16 प्रतिशत (भारत में पासपोर्ट कार्यालयों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को शामिल करते हुए की वृद्धि दर्ज की है । 37 पासपोर्ट कार्यालयों मुख्यालयों और अंडवान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के कार्यालय को 87.37 लाख पासपोर्ट सेवा से संबंधित दस्ताविज जारी किए गए थे (26.48 राजनयिक पासपोर्ट, 17560 सरकारी पासपोर्ट, 2595 अभ्यर्पण प्रमाणपत्र (एससी) 7641 पहचान प्रमाणपत्र (आईसी)और 4278 नियंत्रण रेखा(एलओसी) आवेदनों सहित)। विदेश स्थित 183 भारतीय मिशनों/केंद्रों ने 13.73 लाख पासपोर्ट जारी किए जिसमें ई सी एवं अन्य पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाएं शामिल हैं। इस प्रकार भारत सरकार ने कुल मिलाकर 98.80 लाख पासपोर्ट जारी किए और पूरे वर्ष में पासपोर्ट से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान कीं। यह अपने आप में सर्वाधिक है और 2008 से यह तीन गुना वृद्धि है। 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार 5, 70, 35, 943 नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट थे। भारत आज वैश्विक पासपोर्ट जारी करने के मामले में चीन और अमरीका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है।

पासपोर्ट शुल्क के संबंध में सरकार का राजस्व में 2010–11 से दुगुनी वृद्धि हो गई है। सभी पासपोर्ट सेवाओं से 2014–15 के दौरान कुल 2100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष, 2014–15 के दौरान केंद्रीय पासपोर्ट संगठन को 560.33 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी।

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन

केंद्रीय पासपोर्ट कार्यालय का गठन मंत्रालय के एक अधिनस्थ कार्यालय के रूप में 1959 में किया गया था जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी होते हैं जो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत अपीलीय प्राधिकारी तथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति नियमावली, 1978 के तहत विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पासपोर्ट संगठन की कुल स्वीकृत संख्या 2697 थी। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा परियोजना की प्रबंधन इकाई (पी एम यू) को संचालित करने की दृष्टि से वर्ष 2007 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 15 तकनीकी और 6 सहायक स्टाफ सहित 21 पद सृजित किए गए थे।

मंत्रालय ने सी पी ओ संवर्ग का पुनर्गठन एवं विस्तार करते हुए सी पी ओ कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भर्ती नियम में संशोधन/पदों की डाउग्रेडिंग/पात्रता सेवा में छूट की अनिवार्यता के साथ तीव्र पदोन्नति की मंशा से उनके पास उपलब्ध रिक्त पद भर दिए गए हैं। मंत्रालय ने पूर्व निरधारित एवं परस्पर सहमत मानकों पर आधारित व्यक्तिगत निष्पाद को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करने के लिए पिछले प्रभाव से 21 मार्च, 2013 को एक संशोधित उत्पादक्तायुक्त प्रोत्साहन योजना (पी एल आई एस) अधिसूचित किया है। यह भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनोखी योजना है। सी पी ओ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई योग्य सेवाओं की पहचान करने तथा इस प्रकार देश में शासन में सुधार के प्रति योगदान करने की दृष्टि से पासपोर्ट सेवा पुरस्कार शुरू किए गए हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस अर्थात् 24 जून को चयनित कर्मचारियों और पासपोर्ट कार्यालयों को दिए जाते हैं।

वर्ष 2014 में कुल 5 डी पी सी पदोन्नतियों के लिए पूरे किए गए (कुल 287 कार्मिकों): 9 मई, 2014 को 17 ए पी ओ को डी पी ओ में पदोन्नति देने के लिए डी पी सी, 30 मई, 2014 को 108 कार्मिकों के स्थायीकरण के लिए डी पी सी (अवर श्रेणी लिपिक तथा कार्यालय सहायक), 25 अगस्त, 2014 को सहायकों को सुप्रीटेंडेंट में पदोन्नत किए जाने के लिए डी पी सी (पी जी ओ का डाउग्रेडेड पद), 49 कार्मिकों के लिए एम ए सी पी, 3 सितंबर, 2014 को 26 कार्मिकों के लिए एम ए सी पी (आशुलिपिक, अवर श्रेणी लिपिक तथा कार्यालय सहायक), तथा 10 सितंबर, 2014 को पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी से सहायक पासपोर्ट अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने के लिए 87 कार्मिकों के लिए डी पी सी आयोजित की गई।

वास्तविक अवसंरचना

37 पासपोर्ट कार्यालयों में से 18 स्वयं के भवनों से प्रचालनरत है, 04 भारत सरकार के भवनों से कार्य कर रहे हैं और शेष 15 किराए के भवनों से कार्य कर रहे हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों को अपने भवनों में स्थानांतरित करने से संबंधित मंत्रालय की नीति के अनुरुप आधुनिक भवनों का निर्माण किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने अब तक आठ जगहों अर्थात श्रीनगर, अमृतसर, देहरादून, मुंबई, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी एवं जालंधर में भू–खण्ड अधिग्रहित किए हैं। मुंबई स्थित नवनिर्मित पासपोर्ट कार्यालय भवन के लिए अधिग्रहण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है। पासपोर्ट सेवा केन्द्र (PSK) खोलने पर बल दिया जा रहा है। शिलांग और करीमनगरमें पी एस के खोले गए हैं। त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर में पी एस के खोलनेका कार्य अंतिम चरण पर है। ईटानगर, दिमापुर, सिलिगुड़ी और इंदौर में पी एस के खोलने के लिए स्थान निर्धारित कर लिया गया है।

पासपोर्ट सेवा परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वय

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम, एक महत्वाकांक्षी मिशन मोड परियोजना, राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के भाग के रूप में टाटा कंसलटेंसी सर्विस (TCS) के साथ मिलकर सेवा प्रदाता के रूप में सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड में सफलतापूर्वक चल रहा है।

वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्र भर में सफलतापूर्वक करने के बाद यह योजना 14 जून, 2012 से वर्तमान में प्रचालन और रख–रखाव चरण पर है तथा इसने अपने सफलतापूर्वक प्रचालन के ढाई साल पूरे कर लिए हैं।

पूरे देश में 37 पासपोर्ट कार्यालयों के विस्तृत भाग के रूप में सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं सहित 77 पासपोर्ट सेवा आवेदकों को व्यापक पहुंच प्रदान की जा रही हैं, जिससे पासपोर्ट आवेदकों को व्यापक पहुंच प्रदान की कजा सके। टोल फ्री नंबर (1800–258–1800) का इस्तेमाल करते हुए एक 24ग7 राष्ट्रीय कॉल सेंटर खोला गया है जो 17 भाषाओं में समयोजित स्थिति और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। कॉल सेंटर में प्रतिदिन 22,000 से अधिक कॉल आती हैं। http://passportindia.gov.in पोर्टलपर भी समायोजित अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है। यह परियोजना, आवेदक की निजी जानकारी के सत्यापन के लिए राज्य/यू टी पुलिस प्रणाली, पोस्टल डिलीवरी के लिए भारतीय पोस्ट और पासपोर्ट बुकलेट की आपूर्ति व्यवस्था के लिए आई एस पी नासिक के साथ एकीकृत है। जैसे ही पासपोर्ट प्रेषित किया जाता है, आवेदक को एक एस एम एस/ई–मेल एलर्ट भेज दिया जाता है। यह परियोजना 183 मिशनों और केन्द्रों के साथ–साथ आप्रवास प्राधिकरणों को भी समुचित अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।

31 दिसंबर, 2014 तक नई प्रणाली के माध्यम से 2.24 करोड़ से अधिक पासपोर्ट सेवा संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई की गई है और 2.09 करोड़ से अधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं। 77 पी एस के में हर रोज लगभग 50,000 नागरिक आते हैं।

अधिक आउटरीच को सुरक्षित करने तथा आवेदकों को और बेहतर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 77 कार्यरत पी एस के के अतिरिक्त, मंत्रालय उत्तर पूर्वीय देशों सहित पूरे देश में 18 और पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित करने जा रहा है। पासपोर्ट एप्लिकेशन कलेक्शन सेंटर मोड के रूप में आइजॉल, गुलबर्ग, करीमनगर और पुडुचेरी में पहले से ही एक–एक पी एस के कार्य कर रहे हैं। शिलांग में 14 नवंबर, 2014 से पी एस के पूर्ण रूप से कार्यरत हैं।

पासपोर्ट भारत पोर्टल

पासपोर्ट सेवाओं पर विस्तृत और नई जानकारी प्रदान करने, मिलने का समय निश्यित करने की प्रक्रिया, दस्तावेजों, स्थिति की

जानकारी तथा अन्य संबंधित मामलों की पासपोर्ट सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल passportindia.gov.in बनाया गया है जिसे किसी भी समय और कहीं भी देखा जा सकता है। इस पोर्टल को अधिक सरल और प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए निरंतर मॉनीटर और अद्यतन किया जाता है। यह पोर्टल द्विभाषी है जिसमें हिंदी में भी जानकारी प्रधान रूप से दिखाई जाती है। यह समय–समय पर हुए पासपोर्ट सेवा संबंधी सार्वजनिक सूचनाएं, सलाह तथा प्रेस विज्ञप्ति से अद्यतित रहता है।

सेवाएं प्रदान करने में किए गए उल्लेखनीय सुधार

पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, देश भर में पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। जनवरी–दिसंबर, 2014 के दौरान देश भर में 21 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट 03 दिनों के अंदर; 47 प्रतिशत 07 दिनों में; 64 प्रतिशत 14 दिनों में; 75 प्रतिशत 21 दिनों में और 77 प्रतिशत 30 दिनों में जारी किए गए (पुलिस सत्यापन के लिए समय के अलावा)। तत्काल पासपोर्टके मामलों में 28 प्रतिशत उसी दिन; 60 प्रतिशत 01 दिन के अंदर, 84 प्रतिशत 03 दिनों के अंदर और 98 प्रतिशत 07 दिनों के अंदर जारी किए गए।

आवेदनों की संख्या

पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करने की संख्या के आधार पर सर्वोच्च 05 राज्य केरल, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश थे जहां कुल आवेदनों के 51 प्रतिशत से भी अधिक था।

प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर सर्वोच्च 05 पासपोर्ट कार्यायल थेः हैदराबाद, लखनऊ, बैंगलोर, दिल्ली और कोलकाता।

प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर शीर्ष 5 जिले (दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलुरू और चैन्नई महानगरों को छोड़कर); मल्लापुरम, पुणे, थाने, अहमदाबाद तथा कोजीकोड। नई प्रणाली में पब्लिक डिलिंग काउंटरों की संख्या मौजूदा 350 से बढ़ाकर 1610 कर दी गई है और पब्लिक डिलिंग का समय 4 घंटों से बढ़कर 7 घंटे प्रतिदिन हो गया है।

पुलिस सत्यापन

पासपोर्टों को समय पर जारी करने में पुलिस सत्यापन की अहम भूमिका होती है। पुलिस सत्यापन में तेजी लाने के लिए मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों के साथ निकट संपर्क में है। पुलिस सत्यापन को पूरा करने में लगने वाले दिनों का अखिल भारतीय औसत 42 है और लगभग 47 प्रतिशत पुलिस सत्यापन अपेक्षित 21 दिनों की समय सीमा में पूरा हो जाता है। कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेसों ने लगातार पुलिस सत्यापन कार्रवाई का समय कम रखना कायम रखा है। उदाहरण के रूप में, नई प्रणाली के तहत, आंध्रप्रदेश(15 दिन, गोवा 16 दिन और चंडीगड 17 दिन में) पूरा किया। मंत्रालय द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के फलस्वरूप ज्यादा से ज्यादा जिले वांछित जिला पुलिस मुख्यालय सत्यापन मॉडल को अपना रहे हैं। अभी तक 726 पुलिस जिलों में से 528 ने नई प्रणाली को अपनाया है और जिला मॉडल पर कार्य कर रहे हैं।

प्रकियाओं का कार्यात्मक वृद्धिकरण/सरलीकरण

- 31 दिसंबर, 2014 के अनुसार, प्रतिदिन दिए जा रहे अपॉइमेंट स्लाटों की संख्या 50,000 से अधिक है। गत वर्ष की तुलना में यह 30 प्रतिशत कि वृद्धि है।
- अप्वाइंटमेंट प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को समाप्त करने के लिए, मंत्रालय ने जुलाई 2013 में ऑनलाईन भुगतान प्रणाली को लागू किया तब से, अप्वाइंटमेंटों कि उपलब्धता में स्पष्ट सुधार हुआ है। कुछ आवेदकों कि श्रेणियां और सेवाएं ऐसी हैं जिसके लिए श्वाक इनश सुविधा उपलब्ध है।
- दूरस्थ क्षेत्रों जहां आवेदनों की संख्या कम है, में पासपोर्ट सेवाओं की पहुंच को विस्तार देने के लिए अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पी एस के) को स्थापित किया जा रहा है। 18 पी एस के स्थापित करने की योजना है–आइजोलए शिलांग तथा कारमीनगर के पीएसके 2014 में शुरू कर दिए गए थे।
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के ई–माइग्रेट प्रणाली को पी एस पी प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। यह विदेश में रोजगार प्राप्त करने वाले भावी श्रमिकों द्वारा जमा कराए गए पासपोर्टों को पासपोर्ट डाटाबेस से ऑनलाइन वैधता प्रदान कर देता है। इससे सुरक्षा बढ़ी है और पासपोर्ट के दुरुपयोग/पहचान की चोरी के जोखिम कम हुए हैं।
- एम–पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप जो कि मार्च 2013 में एण्ड्रायड प्लैटफार्म पर शुरू हुआ था, को विण्डोज और एप्पल आई ओ एस प्लैटफार्म पर उपलब्ध कराया गया। यह ऐप पासपोर्ट संबंधित सूचना के साथ–साथ पी एस के को पता करना, लागू शुल्क, स्मार्ट फोन पर पासपोर्ट आवेदन को जमा करने और पता करने के मोड की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- पासपोर्ट आवेदन को जमा करने संबंधित प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि पंजीकृत किराया करार आवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- 01 अगस्त, 2014 से पासपोर्टों पर स्याही हस्ताक्षर न करने और समय तथा श्रमशक्ति के बचत के लिए इन्हें मोहर हस्तक्षेपों से बदलने के लिए भी मंत्रालय ने निर्णय लिया।

- मंत्रालय ने दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापन की आवश्यकता को बदलते हुए स्वयं द्वारा सत्यापण प्रणाली को भी शुरू किया है।

पासपोर्ट मेला

पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2014 की अवधि में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा समय–समय पर सप्ताह के अंत/अवकाश के दिनों में 384 पासपोर्ट मेलाओं का आयोजन किया गया। इन मेलों के दौरान 1.99 लाख पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुई।

पासपोर्ट सेवा शिविर

पासपोर्टों की बढ़ती मांग को पूरा करने और पी एस के से दूर रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से कई स्थानों पर पासपोर्ट सेवा शिविरों को आयोजित किया गया। सबसे पहला पासपोर्ट सेवा शिविर फतेहगढ़ (यू पी) के 14 दिसंबर, 2013 को शुरू किया गया। तदुपरांत, नागरिकों के हित के लिए दूरस्थ स्थानों पर आयोजित किए गए 61 पासपोर्ट सेवा शिविरों के माध्यम से 16,000 आवेदन प्राप्त हुए। ये आगरा, अगरतला, इलाहाबाद, अमेठी, बेलगाम, बरहामपुर, भावनगर, बीकानेर, भीमावरम, भूज, कूडालोर, दमन, धनबाद, गंगटोक, ग्वालियर, गया, गुंटुर, इम्फाल, ईंटानगर, इंदौर, जमशेदपुर, काकीनाडा, करवार, करीमनगर, खड़गपुर, कोल्हापुर, कोटा, कोहिमा, लक्षदीप, मुरादाबाद, महबूबनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, मैसूर, नैनीताल, नेलोर, पथानमथीता, पुडुचेरी, राउरकेला, सोलापुर, सिलिगुड़ी, सीवान, शिलांग, श्रीनगर, श्रीकाकुलम, उदयपुर, विरार तथा वारंगल में आयोजित हुए।

साझे सेवा केंद्र

डिजीटल डिवाइट विशेषतः दूरस्थ ग्रामीणों इलाकों में, की चुनौती का समाधान करने की दृष्टि से मंत्रालय ने डेट वाई द्वारा प्रोत्साहित मैसर्स सी एस सी से 19 मार्च, 2014 को सिटीजेन सेन्ट्रिक सेवाएं घर तक सुलभ कराने के उद्देश्य से एक लाख से अधिक साझे सेवा केन्द्रों (सी एस सी एस) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश और झारखंड में 15 चुनिंदा सी एस सी स्थानों पर पायलट मोड में पासपोर्ट से संबंधित सेवा आवेदन ऑन लाइन भरने की शुरूआत की। पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को उनके सेवा समुच्च के भाग के रुप में जोड़ा गया है। सी एस सी एस के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन फार्म को भरने एवं अपलोड करने तथा प्रयोज्य शुल्क का भुगतान (डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यमस से अथवा एस बी आई इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से सामान्य प्रभार जो 100 रुपए से अधिक न हो) पी एस के का विजीट करने के लिए मुलाकात का समय लेने को सुविधाजनक बनाते हैं। एप्वाइंटमेंट सिड्यूल के अनुसार आवेदक आवेदन जमा करने की प्रक्रिया (फोटोग्राफ/बायोमेट्रिक का संकलन सहायक दस्तावेजों का सत्यापन एवं अनुमोदन सहित) को पूरा करने के लिए पी एस के का विजीट करते हैं। पूरे सप्ताह तथा सप्ताहंत के दौरान सी एस सी के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हैं। 37,000 से अधिक आवेदकों ने वर्ष के दौरान इन सेवाओं का इस्तेमाल किया है।

विदेशों में पासपोर्ट सेवाएं

2014 के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने 13.73 लाख पासपोर्ट एवं अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान की हैं। दोनों देशों जैसे यू ए ई और सऊदी अरब ने विदेशों में कुल 33.60 प्रतिशत सेवाओं का योगदान दिया है (स्थानवार, दुबई, आबुधाबी, रियाद, जेद्दा, कुवैत, मस्कट, दोहा 48.33 प्रतिशत सेवाएं) पासपोर्ट सेवा के दृष्टिकोण से शीर्ष 10 देश थे। यू ए ई, सऊदी अरब, अमरीका, कुवैत, दोहा, मस्कट, सिंगापुर, बहरीन, यू.के. और कनाडा उन्होंने संयुक्त रूप से विदेशों में कुल 65 प्रतिशत पासपोर्ट सेवाओं का योगदान दिया।

विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों को पासपोर्ट सेवा के साथ संयोजित करने में आने वाली तकनीकी और संभार तंत्र संबंधी चुनौतियों का अध्ययन करने हेतु मंत्रालय, एन आई सी और मैसर्स टी सी एस के प्रतिनिधियों ने पैरिसए ताशकंद और दुबई में मिशनों का दौरा किया। यह संयोजन 2015–16 में पूरा हो जाने की संभावना है।

पुरस्कार तथा मान्यता

इस परियोजना को सरकार में उच्चतम स्तर पर मान्यता मिली है। यह मामले के रूप में अध्ययन का विषय है और इसे अनेक पुरस्कार मिले हैं:

- स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया (मार्च, 2014)
- एन ई जी पी परियोजनाओं के अंतर्गत मिशन मोड परियोजनाओ पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मान्यता का प्रमाण पत्र– मैसर्स इलेटस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा (मार्च, 2014)
- केस स्टडी, टी सी एस, भारतीय पासपोर्ट कार्यालय प्रकिया पुनःइंजीनियरी एवं डिजीटीजेशन के माध्यम से सरकारी क्षेत्र की सेवाओं का कायाकल्प – मामले पर
- जनवरी 2014 में 'उच्च निष्पादन–ई–गवर्नेंस वेबसाइट्स–कार्यकुशल सरकारी सेवा प्रदान करने में गेम चेंजर शीर्षक के अनुसंधान पेपर को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित ई–गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 'एम–पासपोर्ट' मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एम बिलियन विशेष उल्लेख पुरस्कार जुलाई 2014 में दिया गया।

- प्रगति और विकास के 10 वर्ष (2004–2014) नामक संकल्प जिसे यू पी ए सरकार की मुख्य उपलब्धियों में माना गया (जनवरी 2014)

पासपोर्ट सेवा दिवस और पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने दूसरे पासपोर्ट सेवा दिवस तथा पासपोर्ट अधिकारियों के तीन दिवसीय सम्मेलन (23–25 जून) 2014 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। 24 जून वह दिन है जबकि 1967 में पासपोर्ट अधिनियम अधिनियमित हुआ था जिससे स्वातंत्रयोत्तर भारत में पासपोर्ट तथा अन्य यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए एक ठोस विधिक ढांचे की नींव रखी गई थी। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मंत्री महोदया ने पासपोर्ट अधिकारियों को नसीहत दी कि वे नागरिकों से संबंधित अपनी भूमिका को महज कार्य नहीं बल्कि सेवा मानकर पूरा करें। इस सम्मेलन की कार्यसूची यह थी कि पिछले वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान किए जाने के सम्मान स्वरूप, मंत्री महोदया ने चुनिंदा कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों तथा पासपोर्ट कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

पासपोर्ट सेवा परियोजना (PSP) के तहत मंत्रालय ने एक मजबूत लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित की है जिसमें टॉल फ्री नंबर (1800–258–1800) है, जो 17 भाषाओं में 24×7 के आधार पर प्रचालित है यह विभिन्न सेवाओं, शिकायतों का निपटान तथा नागरिक फीडबैक के विषय में सूचना प्रसार का कार्य देखता है तथा यह फिलहाल केंद्रीय प्रणाली प्लैटफार्म पर कार्य करता है। एक ई–मेल आधारित सहायता पटल की भी स्थापना की गई हैए नागरिक उसे passportindia.gov.in पोर्टल के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं तथा वे अपनी शिकायतें एवं सुझाव भी भेज सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जांच भी कर सकते हैं। वर्तमान में यह प्रतिदिन 22,000 कॉल का निपटान करता है (इसमें से 48 प्रतिशत हिंदी में तथा 23 प्रतिशत अंग्रेजी में)।

संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा परियोजना) तथा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सी पी वी प्रभाग ने एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इन्हें मंत्रालय के लिए लोक शिकायत निदेशक के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। यह दूरभाष, ई–मेल तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों का निपटान करता है और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से प्राप्त संदर्भों का भी निपटान करता है। इसके अलावा, सभी पासपोर्ट कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट के केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली (CPGRAM) के माध्यम से लोक शिकायतों का निवारण करते हैं, यहां 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान 8370 शिकायतें प्राप्त हुई थीं (2013 की 1045 लंबित शिकायतों सहित), जिसमें से 7934 मामलों का पूर्णतया निपटान कर दिया गया है। 01/01/2014 से 31/12/2014 की अवधि के दौरान 34,402 लोक शिकायत पेटिशन (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शिकायतों/पूछताछ तथा CPGRAMS से संबंधित 23,423 ई–मेल सहित) प्राप्त हुए थे, जिसमें से 33,521 मामलों का निपटान कर दिया गया है। उनके आवेदनों पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशों सहित उनकी अद्यतन स्थिति दर्शाते हुए वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया है, जिसे लोगों द्वारा उनके हित के लिए आसानी से देखे जा सकते हैं। पिछले 03 वर्षों के दौरान शिकायतों की संख्या में तेजी से कमी आई है।

सभी पासपोर्ट कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के वेबसाइट के केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली के माध्यम से लोक शिकायतों का निपटान करते हैं। आवेदकों की सहायता के लिए तथा उनकी शिकायतों का तीव्रता से निवारण करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में सूचना तथा सुविधा पटल, लोक शिकायत प्रकोष्ठ तथा हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पासपोर्ट कार्यालयों तथा पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर शिकायत/सुझाव पेटियां संस्थापित की गई हैं। लोक शिकायत अधिकारी का नाम, पता तथा फोन नं0 भी पासपोर्ट कार्यालयों में दर्शाया गया है। समय–सीमा के अंतर्गत नागरिकों से किसी शिकायत के विषय में पूछताछ करने के लिए तथा उसके निवारण के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र है।

पासपोर्ट अदालत एवं मेला

पासपोर्ट आवेदकों के शिकायतों के निवारण के लिए पासपोर्ट कार्यालय नियमित रूप से पासपोर्ट अदालतों का आयोजन करते हैं। ये अदालतें, कुछ 7,000 पुराने तथा जटिल मामलों को सुलझाने में काफी सहायक रही हैं।

नागरिकों द्वारा मुलाकात का समय लेने में होने वाली समस्याओं का निपटाने के उद्देश्य से पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा समय–समय पर सप्ताहांत पासपोर्ट मेलों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2014 में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा सप्ताहांत/अवकाश के दौरान समय–समय पर 384 पासपोर्ट मेलों (2013 में 2013 मेलों की तुलना में) का आयोजन किया गया था, जिसमें 1.99 लाख पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई थी।

हज यात्रीः विशेष अभियान

भारतीय हज समिति द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार (संसद के अधिनियम सं. 2002 के 35 के तहत गठित) केवल वैध पासपोर्ट

धारक ही हज के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह मामला संतुष्टि का है कि, वर्ष 2014 में भावी हज यात्रियों को पासपोर्ट जारी करना सुचारू ढंग से पूरा किया गया था। 1,25,000 आबंटित हज कोटा कि तुलना में नियत समय–सीमा तक हज समिति ने लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त किए थे। सभी पासपोर्ट कार्यालयों को यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि भावी हज आवेदकों के पासपोर्ट आवेदनों को उच्च प्राथमिकता दी जाए तथा नोडल अधिकारी की नियुक्ति करके; सहायता पटल शुरू करके, ऐसे आवेदकों के लिए मुलाकात के समय का स्लॉट आरक्षित करके तथा ऐसे नागरिकों से प्राप्त अनुरोधों/शिकायत पेटिशनों की सुनवाई तत्काल किए जाने के द्वारा उन्हें शीघ्रता से पासपोर्ट जारी करके अपेक्षित सहायता प्रदान की जाए।

पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

विभिन्न राज्यों के पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, इन कार्यालयों का सतर्कता निरीक्षण भी नियमित आधार पर किया जाता है। इन निरीक्षणों के दौरान, प्रक्रियात्मक दक्षता में सुधार लाने के लिए विचारों का आदान–प्रदान भी किया जाता है। सतर्कता निरीक्षणों के ध्यान का केंद्र पासपोर्ट कार्यालयों में भ्रष्टाचार तथा कदाचार के मामलों पर था। इन निरीक्षणों के पश्चात, लोक पासपोर्ट सेवा केंद्रों को बेहतर सेवा प्रदान करने में लंबित मामलों को निपटाकर तथा अन्य रुकावटों को हटाकर दक्षता में सुधार करके बेहतर प्रचालन कौशल के लिए उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों को सलाह दी गई थी, तथा गैर–तकनीकी सेवा स्तर के करारों (SLA) के तहत भी नियमित आधार पर निरीक्षण किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)

RTI के तहत आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी(CPIO) तथा एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी(APIO) को नियुक्त किया जाता है। CPV पर भाग में भी एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त सचिव(PSP) तथा CPO सभी पासपोर्ट कार्यालयों तथा CPV पर भाग केसंदर्भ में प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं। 1 जुलाई, 2013 से, पासपोर्ट कार्यालयों तथा CPV प्रभाग से संबंधित ऑनलाईन प्राप्त आर टी आई आवेदनों के लिए आर टी आई पोर्टल, भारत सरकार में CPV पर भाग एक अलग अनुभाग का प्रचालन कर रहा है। 17 जून, 2014 से, सभी पासपोर्ट कार्यालयों में ऑनलाईन CPIO पोर्टल बनाया गया है। 2 जुलाई, 2014 के आगे से, CPV पर भाग नेडाक द्वारा प्राप्त आर टी आई आवेदनों को ऑनलाईन अपलोड करना शुरू कर दिया है। इस प्रभाग द्वारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान कुल 4948 ऑनलाईन तथा डाक से प्राप्त आर टी आई आवेदनों का निपटान किया था। (इसमें से 3816 आवेदनों को उनकी ओर से कार्रवाई के लिए RPO को भेजे गए तथा CPV प्रभाग से 984 आवेदनों का उत्तर दिया गया था। इसी अवधि के दौरान, 891 डाक तथा ऑनलाईन प्रथम अपील प्राप्त किए गए थे। तथा उनका निपटान भी कर दिया गया था।

अपील (पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत)

पी आई ए के निर्णयों के विरूद्ध अपील प्रभावित व्यक्तियों को पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदत्त सांविधिक अधिकार है। वर्ष 2014 में, फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर महीनों में 7 अपील सत्र आयोजित हुए, जिसमें 143 अपीलकर्ताओं ने इन कार्यवाहियों में हिस्सा लिया था। सुनवाई के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण में 164 सकारण आदेश (एक पक्षीय निर्णय सहित) जारी किए गए ।

यात्रा दस्तावेज तैयार करना तथा इसे वैयक्तिक बनानाः

सभी भारतीय यात्रा दस्तावेज इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारतीय पासपोर्टों की समग्र गुणवत्ता, कार्यात्मकता तथा सुरक्षा में सुधार करने की दृष्टि से कई उपाय किए गए हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों, मुख्यालय तथा विदेश स्थित चुनिंदा मिशनों/कैंन्द्रों में मशीन आधारित पठनीय पासपोर्ट प्रिंटर्स प्रदान किए गए हैं । सभी पासपोर्ट कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मशीन–रीडेबल पासपोर्ट जारी करते हैं ।

विदेशों में स्थित 160 मिशनों/केन्द्रों और सहायक सचिव (पासपोर्ट) का कार्यालय, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह पोर्ट ब्लेयर के लिए मशीन पठनीय पासपोर्ट (एमआरपी) जिसमें अस्पष्ट छवि सुरक्षा फीचर शामिल हो, सीपीवी प्रभाग के केन्द्रीय भारतीय पासपोर्ट मुद्रण प्रणाली (सीआईपीपीएस) में मुद्रित करवाए जाते हैं। सी आई पी पी एस ने 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान 1,62,828 पासपोर्ट मुद्रित करवाए (इनमें अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए 3529 पासपोर्ट शामिल है) ।

ई–पासपोर्ट

मशीन रीडबल ट्रेवल डाक्यूमेंट में बायोमेट्रिक डेटा शामिल करने के लिए आईसीएओ सिफारिशों के अनुरूप भारत में अपने मौजूदा पासपोर्ट को ई–पासपोर्ट की इलेक्ट्रोंनिक श्रेणी में अद्यतन करने का भी निर्णय लिया है । ई–पासपोर्ट के माध्यम से फर्जी विधि तथ दस्तावेज में छेड़छाड़ के विरूद्ध अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है । इन ई–पासपोर्टों से किसी एक एकल व्यक्ति को बहुविध पासपोर्ट

जारी करने से भी बचा जाता है, इस प्रकार पासपोर्ट जारी करने में काफी हद तक सुरक्षा सुनिश्चित हिती है । इंडियन सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी) नासिक ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्टलेस इनलेज के प्रापण हेतु एक वैश्विक पी क्यू बी की शुरूआत की है ।

अंतर्राष्ट्रीय नागर वमानन संगठन (आईसीएओ)

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के मशीन रीडेबल ट्रेवल डॉक्यूमेंट (एमआरटीडी) संबंधी तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) के सदस्य के रूप में कार्य किया है और एमआरटीडी पर आईसीएओ दिशानिर्देशों को क्रियान्वित करता रहा है। आईसीएओ ने केन्द्रीय संदर्भ के रूप में डॉक्यूमेंट 9303 के संबंध में नागर विमान सुरक्षा में सुधार लाने के लिए आईसीएओ के रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा दस्तावेजों हेतु, वैश्विक रूप से इन्टरआपरेबल ई–पासपोर्ट वैलीडेशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए लागत साझदारी आधार पर आईसीएओ पब्लिक की डायरेक्टी (पीकेडी) स्थापित की है । पीकेडी बोर्ड सदस्यों को पीकेडी सहभागी देशों द्वारा नामित किया जाता है और आईसीएओ परिषद् द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। भारत को 04 फरवरी 2009 में आईसीएओ पीकेडी में प्रवेश मिला।

संयुक्त सचिव (पीएसवी) एवं सीपीओ ने 31 मार्च– 1 अप्रैल, 2014 को पेरिस में आयोजित पीकेडी बोर्ड की 19वीं बैठक में भाग लिया और मशीन रीडेबल ट्रेवल डॉक्यूमेंटस (एमआरटीडी) पर क्षेत्रीय सेमिनार तथा ताशकंद में 8–10 अप्रैल, 2014 के यात्री पहचान बैठक में भी भाग लिया । उन्होंने मॉन्ट्रियल में 21–23 मई, 2014 को 22 वीं यात्रा सलाहकार समूह (टीएजी–एमआरटीडी) बैठक तथा 28–30 अक्तूबर, 2014 को ओसलो में आयोजित 20 वीं पीकेबी बोर्ड बैठक तथा दूसरे बॉर्डर्स डे में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया । 7–9 अक्तूबर, 2014 को मॉन्ट्रियल में एमआरटीडीएस, बायोमेट्रिक्स तथा सुरक्षा मानकों पर 10 वीं संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में मंत्रालय के पदाधिकारियों द्वारा भी भारत का प्रतिनिधित्व हुआ ।

जनता को सूचित करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने सभी नॉन मशीन रीडेबल पासपोर्ट (एमआरपीएस) को वैश्वक रूप से चरणबद्ध करने के लिए 24 नवंबर, 2015 की समय–सीमा निर्धारित की है । 25 नवंबर, 2015 और उससे आगे विदेशी सरकारें गैर–एमआरपी पासपोर्ट के साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के वीजा अथवा प्रवेश से इनकार कर सकती हैं । भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए चिपकाए गए फोटो सहित सभी हस्तलिखित पासपोर्टों को गैर–एमआरपी पासपोर्ट माना जाता है । 20 वर्ष की वैधता वाले सभी पासपोर्ट भी इसी श्रेणी में आऐंगे । भारतीय सरकार ने 2001 से एमआरपी पासपोर्ट जारी करना प्रारंभ कर दिया था । सभी नए भारतीय पासपोर्ट आईसीएओ अनुपालनकारी एमआपी पासपोर्ट है । आईसीएओ द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी पासपोर्ट मशीन–रीडेबल पासपोर्ट जारी करते हैं ।

डिजिटल करने की परियोजना

भारतीय मिशनों/केन्द्रों में पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई और पीआईओ एप्लिकेशनों के लिए ''इमेज पुनःप्राप्त करने वाले डेवबेस का सृजन'' की परियोजना जून, 2012 में 3 विक्रेताओं के एक पैनल को दी गई थी । प्रथम चरण में कांसुलर दस्तावेजों को डिजिटल करने का कार्य 5 और द्वितीय चरण में अन्य 34 मिशनों/केन्द्रों में शुरू किया गया जिनमें से 31 मिशनों/केन्द्रों का कार्य पूर्ण हो गया है या कार्याधीन है । 31 दिसंबर, 2014 तक, लगभग 15 करोड़ कांसुलर दस्तावेजों को डिजिटल किया गया है । एक बार कार्यान्वत होने पर परियोजना, डेटा का केन्द्रीय संग्रहण, फाइलों की आसान पुनः प्राप्ति तथा सभी विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों में एकरूपता के रूप में होगा ।

आरपीओ/पीएसके में संसदीय समिति का दौरा

पासपोर्ट सेवाओं के संबंध में संसद का नजदीकी हित की काफी संख्या में पीक्यू द्वारा पुष्टि की गई थी और कई संसदीय समितियों द्वारा जांच एवं निरीक्षण/अध्ययन यात्राएं की गई थीं ।

(क) राजभाषा संसदीय समिति की पहली उप–समिति ने विदेश मंत्रालय और उसके कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन पर समीक्षा के लिए 16 जनवरी, 2014 को पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर का दौरा किया । जनवरी–फरवरी, 2015 में समिति द्वारा पासपोर्ट कार्यालय गोवा, रायपुर और देहरादून की यात्रा प्रस्तावित है ।

(ख) विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की 2014 की प्रथम बैठक ''पासपोर्ट सेवाए'' कार्यसूची पर 05 दिसंबर, 2014 को हुई ।

सार्वजनिक आउटरीच

अपनी आउटरीच को विस्तार प्रदान करने के भाग के रूप में, सीपीवी प्रभाग सर्विस प्रोवाईडर के सहयोग से एक अर्ध–वार्षिक सरकारी समाचार 'पासपोर्ट पत्रिका' निकल रहा है जिसमें विभिन्न पासपोर्ट संबंधी मुद्दों पर जानकारी होगी । कई पासपोर्ट कार्यालय में मीडिया रोड शो भी आयोजित किए गए जिसमें मीडिया को दी जा रही पासपोर्ट सेवाओं में सुधार के बारे में सूचित किया गया । प्रशासनिक सुधार तथा पीजी विभाग ने भारत सरकार के संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए अपने प्रधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीएसपी को केस स्टडी के रूप में शामिल किया है ।

वीजा

विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों द्वारा वीजा जारी करना

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने 2014 में 4.37 मिलियन वीजा जारी किए हैं । मिशनों/केन्द्रों द्वारा वीजा जारी करने की प्रक्रिया को और सरल किया गया है, जिसमें जारी करने की प्रणाली को कम्प्यूकरीकृत करना और वीजा सेवाओं को आउटसोर्स करना जो 2006 में शुरू हुआ, शामिल है । वर्तमान में 64 मिशनों/केन्द्रों में वीजा कार्य आउटसोर्स किया गया है ।

वीजा जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा माहौल को बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2012 में भारत की यात्रा करने के लिए वीजा चाहने वाले विदेशियों के लिए बायोमेट्रिक नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो कि IVFRT (आप्रवासन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण एवं ट्रैकिंग) परियोजना का एक हिस्सा है। यह गृह मंत्रालय, एन आई सी तथा विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना है जिसमें गृह मंत्रालय नोडल प्राधिकारी है और विदेश मंत्रालय विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में क्रियान्वयन प्राधिकारी है। बायोमैट्रिक नामांकन प्रक्रिया में 10 उंगलियों के निशान तथा चेहरे की बायोमैट्रिक शामिल है। सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों में इस सम्पूर्ण योजना को वर्ष 2015 तक लागू कर दिए जाने की उम्मीद है। इस समय (31 दिसंबर, 2014 तक) IVFRT योजना (बायोमैट्रिक्स के बिना) विदेश स्थित 155 भारतीय मिशनों/केन्द्रों में शुरू की गई हैं (इनमें से 61 बिना बायोमैट्रिक्स के हैं)। बायोमैट्रिक्स प्रक्रिया की शुरुआत विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों में IVFRT प्रणाली को लागू करने से संबंधित है। बायोमैट्रिक नामांकन प्रक्रिया के साथ IVFRT योजना के क्रियान्वयन से भारत आने वाले वास्तविक विदेशी सैलानियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा वीजा जारी तंत्र के सुरक्षा पहलुओं से जुड़े माहौल में सुधार होगा।

सी पी वी प्रभाग द्वारा वीजा जारी किया जाना

सी पी वी प्रभाग ने (31 दिसंबर, 2014 तक) विदेशी राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को 7823 वीजा जारी किए। सी पी वी प्रभाग ने स्थानांतरण तथा सरकारी कार्य से भारतीय मिशनों/केन्द्रों में कार्यभार ग्रहण करने जाने वाले भारतीय सरकारी अधिकारियों को (31 दिसंबर, 2014 तक) 7725 वीजा नोट भी जारी किए।

भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा वीजा/कोंसुली/पासपोर्ट कार्यों को आउटसोर्स किया जाना

मंत्रालय ने वर्ष 2006–07 के दौरान विदेश स्थित मिशनों तथा केन्द्रों में वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग शुरू की। तदुपरांत पासपोर्ट तथा कोंसुली सेवाओं का भी आउटसोर्स किया गया। अभी तक 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति अनुसार विदेश स्थित 64 भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने पासपोर्ट/वीजा/कोंसुली सेवाओं तथा संग्रहण कार्य की आउटसोर्सिंग की है। आउटसोर्स करने का उद्देश्य आम जनता को वीजाए पासपोर्ट तथा कोंसुली सेवाएं तत्काल एवं कारगर ढंग से उपलब्ध कराना है।

वीजा में छूट संबंधी करार

भारत ने 60 देशों के साथ वीजा में छूट संबंधी करार संपन्न किए हैं जिसके तहत राजनयिक/सरकारी पासपोर्टधारकों को वीजा की अपेक्षाओं से छूट दी जाती है। वर्ष 2014 में नार्वे के साथ इस प्रकार के वीजा में छूट संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

साक्ष्यांकन और अपोस्टिल कन्वेंशन परियोजना

इस मंत्रालय के सी पी वी प्रभाग में साक्ष्यांकन प्रकोष्ठ बाहर के देशों में व्यक्तिगत तथा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए लोगों के शैक्षिक, वाणिज्यिक तथा व्यक्तिगत दस्तावेजों के अभिप्रमाणन के लिए साक्ष्यांकन सेवाएं प्रदान करता रहा है। इसके अलावा भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी विदेशों में निर्यात और साथ ही अन्य कारोबारी गतिविधियों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा साक्ष्यांकित वाणिज्यिक दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। अभिप्रमाणन दो प्रकार का होता है; सामान्य साक्ष्यांकन तथा अपोस्टिल प्रमाणन। अपोस्टिल प्रमाणन उन देशों में प्रयोग किए जाने वाले दस्तावेजों का किया जाता है जो हेग अपोस्टिल कन्वेंशन के सदस्य हैं। यद्यपि सामान्य साक्ष्यांकन निःशुल्क है, अपोस्टिल स्टिकर लगाने के लिए पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से 50 रुपए प्रति दस्तावेज/ प्रति पृष्ठ, जैसा भी मामला हो, पर पृष्ठ का शुल्क लिया जाता है।

विदेश मंत्रालय द्वारा साक्ष्यांकन/अपोस्टिल प्रमाणन के लिए दस्तावेजों के संग्रहण तथा आपूर्ति का कार्य जुलाई 2012 से दो वर्ष की अवधि के लिए 05 कंपनियों को आउटसोर्स किया गया है और इसे 31/03/2015 तक बढ़ाया गया है। ये कंपनियां प्रति दस्तावेज 22 रुपए (व्यक्तिगत), 18 रूपए (शैक्षिक) और 16 रुपए (वाणिज्य) का सेवा शुल्क लेती है। जनवरी से दिसंबर 2014 की अवधि के लिए सी पी वी प्रभाग ने साक्ष्यांकन प्रकोष्ठ ने अपोस्टिल सदस्य देशों में प्रयोग करने के लिए 383651 व्यक्तिगत दस्तावेजों और 169534 वाणिज्यिक दस्तावेजों का साक्ष्यांकन किया और 357864 दस्तावेजों का अपोस्टिल प्रमाणन किया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता तथा गुवाहाटी में चार विदेश मंत्रालय शाखा सचिवालय ने 34305 दस्तावेजों का साक्ष्यांकन/अपोस्टल प्रमाणन किया गया। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कोंसुली दस्तावेजों का साक्ष्यांकन भारतीय मिशन/केन्द्र द्वारा भी किया जाता है।

कोंसुली मामले

प्रत्यर्पण तथा विधिक सहायता

विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध जिनमें वित्तीय धोखाधड़ी तथा मादक द्रव्यों की तस्करी भी शामिल है, से निपटने के लिए एक कानूनी तथा संस्थागत कार्यढ़ाचा की व्यवस्था करने हेतु द्विपक्षीय कोंसुली करारों पर बातचीत करने के लिए विभिन्न देशों के साथ सक्रियता से वार्ता करता रहा है। इन करारों में प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधिए असैनिक तथा वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि और सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी करार शामिल हैं।

जनवरी तथा दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान छह प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध–संयुक्त राज्य अमरीका, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान तथा कीनिया से एक–एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, स्थानीय अभियोजन के लिए भारत को 32 अनुरोध (संयुक्त अरब अमीरात से 30 और सऊदी अरब से 02 अनुरोध) प्राप्त हुए। भारत ने प्रत्यर्पण के लिए चार अनुरोध–संयुक्त अधिराज्य (यू के) को एक, सऊदी अरब को दो तथा थाइलैण्ड को दो अनुरोध भेजे हैं। इसके अलावाए भारत ने अमरीका में एक व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया और संयुक्त अरब अमीरात में भारत में एक व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया।

कोंसुली मुद्दे

विश्व भर में 183 देशों में लगभग 28 मिलियन प्रवासी भारतीय रहते हैं। इनमें से विदेशों में रहने वाले लोगों में से लगभग 10 मिलियन लोग भारतीय हैं। इन भारतीय नागरिकों में से अधिकांश अस्थायी प्रवासी है जिनमें महिला कामगार भी शामिल हैं और इनमें से 90 प्रतिशत कामगार खाड़ी क्षेत्रों में काम में लगे हैं। ये भारतीय कामगार अपने तथा भारत में अपने परिजनों के बेहतर जीवनयापन के लिए विदेश जाते हैं। हालांकि, एक बार विदेश पहुंचने पर उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं क्योंकि विदेश में काम करने तथा वहां की रहन–सहन की स्थिति उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं भी हो सकती है।

सी पी वी प्रभाग में कोंसुली अनुभाग की मुख्य सरोकार विदेशों में रहकर काम करने वाले भारतीय नागरिकों की देखभाल से संबंधित है। उपर्युक्त के अलावा कोंसुली प्रभाग भारत में गिरफ्तार किए गए विदेशियों तथा विदेशी मूल के लोगों की मौत के मामलों को देखता है जिनमें भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों को कोंसुली सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान शामिल हैं। कोंसुली अनुभाग आम जनता को लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने तथा उनके कल्याण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। कोंसुली अनुभाग द्वारा भारतीय मूल के लोगों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने, मृत भारतीय कामगारों के परिजनों को बकाया वेतनों तथा मृत्यु क्षतिपूर्ति के भुगतान, पी आई ओ/ओ सी आई कार्ड जारी करने, भारतीय कर्मी दलों के सदस्यों की गिरफ्तारी तथा भारतीय जहाजों को कब्जे में लिए जाने के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय के साथ संपर्क करनेए विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत भारतीय नागरिकों के विवाह तथा तलाक संबंधी मामले, विदेशों में भारतीय नागरिकों के जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण संबंधी मुद्दे निपटाए जाते हैं।

विदेशों में भारतीय मिशन/केन्द्र विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों को विदेशों में समग्र रूप से उस समुदाय के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों में निष्पक्ष तरीके से सलाह देते हैं तथा उनका मार्गदर्शन करते हैं। विदेशों में भारतीय नागरिकों के हित तथा कल्याण के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने कई सदस्य देशों जिनमें ईरान, अमरीका, चीन, रूसी परिसंघ, संयुक्त अरब अमीरात आदि देश शामिल हैं, के साथ कोंसुली मामलों पर विभिन्न द्विपक्षीय कार्यसमूहों का गठन किया है। इसके अलावा, भारतीय मिशन/केन्द्र कोंसुली सेवाएं जैसे–विभिन्न दस्तावेजों का साक्ष्यांकन, भारतीय नागरिकों के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण, भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को भारत वापस भेजने की व्यवस्था करने, भारतीय नागरिकों के विवाह सम्पन्न कराने/पंजीकरण कराने, विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों को कोंसुली सेवाएं सुलभ करवाने, भारतीय नागरिकों को भारतीय न्यायालय से शमन भेजने आदि जैसे कार्य करते हैं।

द्विपक्षीय कोंसुली बैठकें

इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय कोंसुली मुद्दे पर संयुक्त कार्यसमूह की बैठकें 18–19 मई, 2014 तक ईरान के साथ तेहरान में, 25–29 अगस्त, 2014 तक ऑस्ट्रेलिया के साथ कैनबरा में और 16 जुलाई, 2014 को ब्राजील के साथ प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान आयोजित की गई और 10 सितंबर, 2014 को अमरीका के साथ नई दिल्ली में, 28 अक्तूबर, 2014 को रूसी परिसंघ के साथ, 17 नवंबर, 2014 को स्विट्जरलैण्ड के साथ और इण्डोनेशिया के साथ 15–16 दिसंबर, 2014 को आयोजित की गई। इन बैठकों के दौरान कोंसुली, वीजा तथा पासपोर्ट संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

प्रशासन तथा स्थापना

19

प्रशासनिक प्रभाग के पास मंत्रालय के मुख्यालय तथा 182 भारतीय मिशनों/ विदेश स्थित केंद्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनशक्ति संसाधन के बेहतर उपयोग की जिम्मेदारी है। इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह प्रभाग काडर प्रबंधन की गतिविधियों का निरीक्षण करता है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती/ स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति तथा दूसरों में आपसी कैरियर विकास शामिल है। इसके साथ, यह प्रभाग कर्मचारी संबंधी सभी उपयुक्त नियमों और अधिनियमों के निरूपण, संशोधन और सुधार का कार्य भी देखता है। यह प्रभाग नए मिशनों/ विदेश स्थित केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमोदन भी प्राप्त करता है।

दुनिया के साथ भारत के संबंध मजबूत बनाने के उद्देश्य से तथा बढ़ती जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए, 2008 में एक व्यापक विदेश मंत्रालय विस्तार योजना आरंभ की गई थी जो 2018 तक चलेगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अलग–अलग स्तरों पर लगभग 50 पदों को जोड़ा जायेगा। मंत्रालय में जनसंसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु वर्ष 2011–12 में भारतीय विदेश सेवा 'ख' संवर्ग पुनःपरीक्षण प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया था, जो वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है। यह काडर पुनःपरीक्षण न केवल अधिकारियों के कैरियर संभावनाओं में विस्तार करेगा, बल्कि सेवाओं में भी कुशलता लायेगा। इन प्रयासों की देख–रेख के साथ, डीओपीडी तथा यूपीएससी की सलाह के साथ मंत्रालय में भर्ती नियमों के पुनःपरीक्षण का व्यापक कार्यक्रम भी जारी है और अगले कुछ महीनों के दौरान पूरा होने की संभावना है।

वर्तमान में मंत्रालय की स्वीकृति संख्या 4024 है (जानकारी संलग्नक IX में)। इन पदों के विरुद्ध तैनात कर्मचारी भारत तथा 182 मिशन/ विदेश स्थित केंद्रों में प्रतिनियुक्त हैं। इसमें भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय विदेश सेवा 'ख' (आईएफएस 'बी'), द्विभाषिया संवर्ग, विधिक एवं संधि संवर्ग, पुस्तकालय संवर्ग शामिल हैं, परंतु ग्रुप 'डी' तथा एक्स–काडर पद नहीं। मंत्रालय के विभिन्न समूहों पर भर्ती 01 अप्रैल से 30 नवम्बर, 2014 तक सीधे भर्ती (डीआई), विभागीय पदोन्नति (डीपी) तथा सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) के माध्यम से की गई (जानकारी संलग्नक X में)।

इसकी कार्य करने की प्रवृत्ति को देखते हुए, विदेश मंत्रालय ने हमेशा भाषाई क्षमता की उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास पर विशेष बल दिया है। इतने वर्षों में, इसका परिणाम सेवा में विदेशी भाषा क्षमता सहित काफी विशाल और विविध समूह का निर्माण रहा है, जो अधिकारियों को अपनी राजनयिक जिम्मेदारी अधिक प्रभावी रूप से करने में सहयोगी है (जानकारी संलग्नक XI में)।

मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार नियमों के समान कर्मचारियों के बीच विकलांग व्यक्तियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व होने की अपनी नीति पर जारी है। इस लक्ष्य की ओर, मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा सहित विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त पदों का निर्धारण किया है।

समीक्षाधीन वर्ष जकार्ता में आशियान का नया मिशन खोलने के उद्देश्य से भारत सरकार के साथ भारत के वैश्विक राजनयिक मौजूदगी में ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने का साक्षी रहा।

मंत्रालय का अपने मिशनों/ केंद्रों की सहभागिता सहित विदेशों में हिंदी के प्रसार और प्रसार के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत, हिंदी पाठ्य पुस्तकें, साहित्य तथा बाल पुस्तकें, हिंदी पत्रिकाएं, हिंदी सीखने के लिए सीडी, कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्यक्रम के लिए सॉफ्टवेयर, शब्दकोष आदि सहित हिंदी शिक्षण सामग्री शैक्षिक संस्थानों तथा अन्य एनजीओ को भेजी जाती है। भारतीय मिशनों/ केंद्रों के माध्यम से, मंत्रालय विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों को हिंदी संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करता है।

मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन नीति को बहुत अधिक प्राथमिकता प्रदान की जाती है। मंत्रालय में सितम्बर, 2014 में हिंदी दिवस के उपलक्ष पर हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने हिंदी प्रतियोगित के विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को सभी विदेश स्थित मिशनों/ केंद्रों के साथ–साथ मुख्यालय में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में हिंदी शिक्षण हेतु विदेशी छात्रों को 10 छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य में सहयोग करता है।

सतर्कता यूनिट

27 अक्टूबर, 2014 से 01 नवम्बर, 2014 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। सभी भारतीय मिशन/ विदेश स्थित केंद्रों तथा विदेश मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित शपथ ली। इस सप्ताह के दौरान, मंत्रालय ने अपने पोर्टल पर सतर्कता मामलों को ऑनलाइन दायर करने की सुविधा जारी की। इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मंत्रालय, राजनयिक मिशन/ विदेश स्थित मिशन, भारत में पासपोर्ट कार्यालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, अनुसंधान और सूचना तंत्र, विदेशी मामलों पर भारतीय परिषद से संबंधित सतर्कता शिकायतें दायर की जा सकेंगी।

01 जनवरी, 2013 से विदेश मंत्रालय ने रुपये 50 करोड़ तथा उससे अधिक कीमत के सभी अधिप्राप्तियों/ परियोजनाओं के लिए मंत्रालय और संभावित बिडकर्ता/ विक्रेता के बीच संविदा–पूर्व इंटीग्रिटी समझौता हस्तांतरित किया गया। यह विदेश सेवा संस्थान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा विदेशी मामलों पर भारतीय परिषद सहित मंत्रालय के सभी संलग्न/ अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त निकाय के लिए लागू होगा।

यह इंटीग्रिटी समझौता दो स्वतंत्र बाहरी अनुविक्षकों (आईईएम) के एक पैनल के माध्यम से कार्यान्वित होगा, जो मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श सहित नियुक्त किए जाएंगे। उच्च सत्यनिष्ठा और ख्याती वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति मंत्रालय द्वारा आईईएम के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

वर्ष 2014–15 के लिए मंत्रालय में सीएनवी प्रभाग के सतर्कता यूनिट द्वारा देखे गए मामलों की जानकारी निम्नलिखित है:–

- 31 मार्च, 2014 को लंबित मामलों की संख्या – 75
- 01 अप्रैल, 2014 से 30 दिसम्बर, 2014 की अवधि के दौरान जांचने हेतु प्राप्त मामलों की संख्या – 39
- 30 नवम्बर, 2014 को मामलों की कुल संख्या – 114
- औपचारिक जुर्माने के लगने के बाद बंद किए गये मामलों की संख्या – 06
- 01 अप्रैल, 2014 से 30 नवम्बर, 2014 की अवधि के दौरान मृत्यु, वीआरएस आदि के कारण, बिना जुर्माने के बंद हुए मामलों की संख्या –37
- 01 अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर के दौरान बंद किए गए मामलों की कुल संख्या – 43
- 30 नवम्बर, 2014 को लंबित मामलों की संख्या – 71

कल्याण

कल्याण प्रभाग विदेश मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के सामान्य कल्याण को देखता है। इस वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय ने अपने 08 कर्मचारियों को खोया है, जिनके लिए देह–संस्कार और अनुग्राही भुगतान से संबंधित सभी सहायता प्रभाग द्वारा कर्मचारी लाभ निधि से दी गई। एक्सटर्नल अफेयर स्पाउस एसोसिएशन (ईएएसए) कल्याण अनुभाग विदेश मंत्रालय कर्मचारी लाभ निधि के माध्यम से बच्चों को 8 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के 03 वार्ड को एमबीबीएस कोर्स में तथा 76 वार्ड इंजीनियरिंग कोर्स में भर्ती दी गई, जिसके लिए सारी औपचारिकता इस प्रभाग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर पूरी की।

केंद्रीय विद्यालय की 52 सीटों पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला मिला। इस वर्ष के दौरान, इस प्रभाग द्वारा किये गए कल्याण कार्यों में सामुदायिक सामंजस्य और सशस्त्र सेनाओं के लिए झण्डा दिवस हेतु निजी संग्रह का प्रबंध करना शामिल है।

कल्याण प्रभाग भारतीय मिशनों/ विदेश स्थित केंद्रों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु मनोरंजनात्मक क्लब खोलने में सहयोग देता है। जब और जैसे अधिकारी और कार्मिक सदस्य मिशन से मुख्यालय लौटते हैं, उन्हें कई सार्वजनिक/ निजी विद्यालयों में भर्ती के लिए, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड और टेलीफोन कनेक्शन आदि में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

स्थापना

स्थापना प्रभाग मंत्रालय के कार्यालय और आवासीय कॉम्पलेक्स को संभालने तथा रख–रखाव का कार्य आवास और कार्यालय के लिए स्थान का आवंटन मंत्रालय के कार्यालयों के लिए कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर की खरीद और आपूर्ति को देखता है। यह मिशनों और विदेश स्थित केंद्रों पर तैनात अधिकारियों को भत्तों और विशेष अनुदान से संबंधित मामलों; कार्यालय वाहन और विशेष अधिप्राप्ति वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति साथ ही साथ मिशनों और विदेश स्थित केंद्रों के लिए आवासीय व्यवस्था और चांसरी के किराए की व्यवस्था को भी देखता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मंत्रालय के दिल्ली के कार्यालयों तथा मिशनों और केंद्रों में आपूर्ति हेतु कलात्मक वस्तु के चयन और खरीद का कार्य साथ ही साथ तोषाखाना से संबंधित मामलों का ध्यान रखता है।

सभी यूज़र की पहुँच को आसान बनाने तथा ओडीए वस्तुओं का सुचारू रूप से ट्रैक करने हेतु एक आनलाईन ओडीए पोर्टल बनाया गया। तोषखाना में प्राप्त उपहारों की जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर त्रिमासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।

कार्मिकों का सफाई की ओर रुझान करने की जरूरत तथा अपने आस–पास की सफाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने

के लिए मंत्रालय के साथ–साथ हमारे मिशनों/विदेश स्थित केंद्रों में 'स्वच्छ भारत अभियान' के दौरान कई गतिविधियाँ की गई।

इसमें अप्रचलित फाइलों/कागजों/फर्नीचर आदि की छटाई तथा कार्य स्थान और शौचालय को साफ सुथरा रखना शामिल हैं। 02 अक्टुबर, 2014 को मंत्रालय के कार्यालयों में 'स्वच्छ भारत' शपथ दिलाई गई जिसके बाद श्रमदान किया गया। 06 दिसम्बर, 2014 को मंत्रालय के कार्यालय में दोबारा श्रमदान किया गया।

हमारे मिशनों/विदेश स्थित केंद्रों के सादश्यमूलक प्रवृत्ति को देखते हुए सभी भारतीय मिशनों/विदेश स्थित केंद्रों में अपने परिसर में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए समान उपाय किए गए।

परियोजनाः–

यह प्रभाग विभिन्न निर्माण/नवीकरण परियोजनाओं के समय पर प्रारंभ/पूर्ण होना सुनिश्चत करने के उद्देश्य से उनका निकटता से अनुर्विक्षण करता है। अबुजा में निर्माण परियोजना पूरी कर ली गई तथा दर–ए–सलाम में उच्चायोग के आवास तथा चांसरी के निर्माण कार्य को पुरस्कृत किया गया।

मुख्य नवीकरण परियोजनाओं का कार्य क्वालालंपुर, डब्लिन, कोलंबो, सिडनी, पेरिस में सांस्कृतिक केंद्र और भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन में सांसकृतिक विंग में परामर्शदाता की नियुक्ति और वास्तुकला संबंधी ड्राइंग की तैयारी से लेकर वास्तविक जारी नवीकरण के विभिन्न स्तरों पर है।

कैरो में चांसरी का नवीकरण अनुमोदनार्थ है तथा कुवैत में चांसरी, इंडिया हाउस और कर्मचारी आवास का कार्य जारी है। निकोसिया, पोर्ट ऑफ स्पेन तथा पोर्ट लुइस (चांसरी और डब्ल्यू एच एस), ताशकंत और वेलिंगटन सहित कई परियोजनाएं वर्तमान में डिज़ाईन और निविदा स्तर पर हैं तथा वर्तमान वित्त वर्ष में निर्माण स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

परियोजना प्रभाग क्वालालंपुर (मलेशिया) में तोरना गेट के निर्माण संबंधी परियोजना भी देख रहा है। इस अवदि के दौरान हेलसिंकी, बैंकॉक, काबुल और ज़गरेब में प्लॉट/बिल्ड–अप संपत्ति का अभिग्रहण उल्लेखनीय है। इसके अलावा, ग्वांग्जू (चांसरी और आवास के लिए भूमि), सूवा (चांसरी और आईसीसी के लिए भूमि का टुकड़ा) तथा तेल अवीव में चांसरी के लिए बनी हुई संपत्ति का अभिग्रहण संभावित है।

वित्त वर्ष 2014–15 के लिए मंत्रालय के पूंजी परिव्यय बजट के अंतर्गत रु. 300 करोड़ आवंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए रु. 437 करोड़ तक की पर्याप्त बढ़ौत्तरी की गई है जिससे चालू परियोजनाओं के अभिग्रहण/निर्माण पर लक्षित व्यय तय वित्त वर्ष 2015–16 में संभावित परियोजनाएं शामिल हैं।

ए एंड आर एम प्रभाग के सक्रिय सहयोग के साथ पीडी प्रभाग द्वारा 16 सेवानिवृत्त राजदूतों का एक पैनल तैयार किया गया। वह वर्गीकृत फाईलों को पढ़कर 'अवर्गीकृत' की जाने वाली फाईलों का सुझाव देते हैं।

वह अभी तक 6488 फाइलें अवर्गीकृत करा चुके हैं, जिनमें से 2797 फाइलें संबंधित विभागाध्यक्ष से अनुमोदन लेने के बाद भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार में मूल्यनिरूपण के लिए दे दी गई है। इसके अलावा 2122 सामान्य फाईलें नष्ट कर दी गई हैं।

सूचना का अधिकार तथा मुख्य जन सूचना कार्यालय

20

मंत्रालय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की ओर पूर्ण प्रयास करता रहा है। मंत्रालय में प्राप्त आवेदनों को इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देखा जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सर्वप्रेषण प्रकटिकरण पर निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आरटीआई आवेदन/ अपील/जवाबों को सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है।

मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में डीओपीटी द्वारा बताए गए आरडीआई आवेदन को ऑनलाइन स्वीकर करने की प्रणाली को चालू कर दिया है। भारत सरकार के मंत्रालय/ विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई शुल्क के भुगतान हेतु पोस्टल ऑर्डर के इलेकट्रॉनिक खरीद के लिए डीओपीटी द्वारा प्रस्तावित ई–आईपीओ (इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर) योजना सभी 183 मिशनों/ विदेश स्थित केंद्रों में लागू कर दी गई है।

01 अप्रैल, 2014 से 30 नवम्बर, 2014 के दौरान मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगते हुए कुल 1206 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनको सफलतापूर्वक निपटाया गया। आवेदन सामान्य रूप से विदेशी संबंध, प्रशासनिक मामले, हज यात्रा, द्विपक्षीय यात्राएं और उन पर हुए व्यय जैसे मामलों पर थी। सीपीवी प्रभाग, मिशन और विदेश स्थित केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा विदेशी मामलों पर भारतीय परिषद इस अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र जन प्राधिकरण के रूप में अपना रिकॉर्ड बनाए हुए है।

सभी सीआईसी सुनवाइयों आरटीआई सेल से एक प्रतिनिधित्व और संबंधित मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) उपस्थित होता है।

21 ई–गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी

ई–गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग (ईजी एंड आईटी) मंत्रालय को सभी प्रकार का आईटी समर्थन तथा विदेश स्थित मिशनों/ केंद्रों और मंत्रालय में चल रहे विभिन्न ई–शासन एप्लिकेशनों को समर्थन देता रहा है।

कार्यकुशलता लाने और कागजों की संख्या कम करने के उद्देश्य से दिनांक 03 जुलाई, 2014 को मंत्रालय में ई–ऑफिस प्रारंभ किया गया। ईजी एंड आईटी प्रभाग डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंश के रूप में 'ई–गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेकनोलॉजी' लागू करने के कदम उठा रहा है। विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में एकीकृत मिशन अकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर (आईमास) कार्यान्वित किया गया है। इन मिशनों/केंद्रों की लेखांकन पद्धति में एकरूपता आई है। मंत्रालय आई–मास का अगला वर्जन बनाने की प्रक्रिया में है, जो वेब–आधारित होगा। जिसमें मंत्रालय में वित्तीय योजना और व्यय प्रबंधन को बेहतर बनाएगा। मंत्रालय के पुस्तकालय में एक वेब–आधारित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया जो यूज़र को ब्राउज़र आधारित पहुंच देगा।

पासपोर्ट और ऑनलाइन वीज़ा जैसी मंत्रालय की ई–सेवाओं को ई–ताल (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड एग्रीगेशन लेयर) के साथ एकीकृत किया गया है, जो राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड योजना है। इस मंत्रालय ने कॉम्प डीडीओ सॉफ्टवेयर और ई–प्रणाली मिशन मोड परियोजना भी लागू की है। आईवीएफआरटी (उन्प्रवासन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग) का ऑनलाइन वीजा संघटक गृह मंत्रालय के नेतृत्व में 155 भारतीय मिशनों/ केंद्रों में संचालित किया गया है जबकि बायोमेट्रिक नामांकन 59 मिशनों/केंद्रों में कार्यान्वित किया गया।

साईबर सुरक्षा खतरे के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए, ईजीएंडआईटी प्रभाग मुख्यालय में अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा विदेशी तैनाती पर जा रहे अधिकारियों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देने पर विशेष बल देता रहा है।

■■

समन्वय प्रभाग

22

समन्वय प्रभाग राज्यों के राज्यपालों, लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उप सभापति केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों, न्यायपालिका के सदस्यों, सरकारी पदाधिकारी आदि की विदेश यात्राओं के लिए सभी प्रस्तावों पर राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति प्रदान करने की कार्रवाई करता है। विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक अनापत्ति समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, दौरे के राजनीतिक तथा कार्यात्मक औचित्य आयोजित की गई बैठकें और संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर दी जाती है।

अप्रैल 2014 से नवम्बर, 2014 के दौरान ऐसी यात्राओं के लिए 2268 राजनीतिक अनापत्तियां जारी की गई।

यह प्रभाग विदेशी गैर–अनुसूचित उड़ानों, राजनयिक उड़ानों और विदेशी नौसैनिक जहाजों की यात्राओं के लिए राजनयिक अनापत्तियां प्रदान करने से संबंधित कार्य भी देखता है। अप्रैल 2014 से नवम्बर, 2014 के दौरान इस प्रभाग ने 490 विदेशी गैर–अनुसूचित सैनिक उड़ानों को अनापत्ति तथा 47 नौसेना जलयानों की यात्राओं को अनापत्ति जारी की।

समन्वय अनुभाग विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोहों में भारतीय खिलाड़ियों और खेल–कूद टीमों की भागीदारी के लिए और विदेशी खिलाड़ियों की टीमों की भारतीय यात्रा के लिए अनुमोदन प्रदान करने की कार्रवाई करता है। अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2014 के दौरान 203 ऐसे मामलों पर अनापत्ति प्रदान की गई थी। यह प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियों, कार्यशालाएं आयोजित करने, भारतीय टैलीग्राफ अधिनियम (1885) के तहत एमेच्योर डब्ल्यू/टी लाइसेंस प्रदान करने, विदेश स्थित भारत विदेश सांस्कृतिक मैत्री और सांस्कृतिक सोसाइटियों के लिए सहायता अनुदान के लिए अनापत्ति देने के अनुरोधों की भी जांच करता है। अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2014 के दौरान इस प्रभाग ने भारत में 1408 सम्मेलन/संगौष्ठी आदि के लिए अनापत्ति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त आगामी प्रशिक्षण/ शोध के लिए विदेशी विद्वानोंकी यात्रा की 143 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई।

विद्यार्थी वीज़ा को शोध वीज़ा में परिवर्तित करने के लिए गृह मंत्रालय से प्राप्त 45 संदर्भित मामलों को जांचा गया तथा गृह मंत्रालय को अनापत्ति भेजी गई। वित्त मंत्रालय से प्राप्त भारत में विदेशियों द्वारा अभिग्रहीत स्थाई संपत्ति और एनजीओ/ट्रस्ट द्वारा आयकर के 11(1)(सी) के अंतर्गत आयकर में छूट से संबंधित मामले भी जांचे गए तथा वित्त मंत्रालय को जवाब भेजा गया।

समन्वय अनुभाग विदेशी राष्ट्रिकों को पद्म अवार्ड प्रदान करने से संबंधित कार्य भी करता है। समन्वय अनुभाग द्वारा विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों से नामांकन प्राप्त किया जाता है और मंत्रालय को अवगत कराया जाता है।

समन्वय प्रभाग द्वारा मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई), सदभावना दिवस (20 अगस्त), राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) और कौमी एकता सप्ताह (31 अक्टूबर) भी समन्वित किया जाता है।

सचिवों की समिति की बैठक के दौरान और प्रधान मंत्री को दी गई प्रस्तुतिरण के दौरान लिए गए निर्णय की अनुपर्ती कार्रवाई पर कैबिनेट सचिवालय की ई–समीक्षा वेबसाइट का अनुवीक्ष्ण और अद्यतन का कार्य भी प्रभाग ने किया।

वीआईपी सेल ने मंत्रियों, संसद सदस्यों और अन्य उच्च पदाधिकारियों से प्राप्त संदर्भों पर कार्रवाई की।

शिक्षा सेल इस मंत्रालय को क्रमशः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आबंटित सीटों पर स्व–वित्तपोषित विदेशी–छात्र योजना के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस/बीई/बी फार्मेसी और भारत के विभिन्न संसथाओं से डिपलोमा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 65 मित्र पड़ौसी एवं विकासशील देशों से विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश के संबंध में कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अग्रेशित विदेशी छात्रों संबंधित अल्प–अवधि इलेक्टिव प्रशिक्षण के लिए अनापत्ति के मामलों को भी देखता है।

शैक्षिक वर्ष 2014–15 के दौरान नामांकित सीटों पर चयन के लिए विदेशी छात्रों से संबंधित प्राप्त/कार्रवाई किए गए आवेदनों की जानकारी निम्नलिखित है:–

- मिशनों/केंद्रों से प्राप्त 49 आवेदनों में से 23 एमबीबीएस की सीटों पर तथा 2 बीडीएस की सीटों पर अभ्यर्थी चयनित किए गए। वास्तविक भर्ती उच्चतम न्यायालय के लंबित फैसले के कारण रुकी हुई है।
- मिशनों/केंद्रों से प्राप्त 60 आवेदनों में से 41 बी. इंजीनियरिंग सीटों पर और 08 बी. फार्मेसी सीटों पर अभ्यर्थियों को चयनित किया गया।
- मिशनों/केंद्रों से प्राप्त 21 आवेदनों में से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में पीजी मेडिकल कोर्स के लिए 05 सीटों पर अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। वास्तविक भर्ती उच्चतम न्यायालय में लंबित फैसले के कारण रुकी हुई है।

अप्रैल–नवम्बर, 2014 की अवधि के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संदर्भित सरकारी मेडिकल कॉलेज में विदेशी छात्रों के चयन और विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा प्राप्त एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ तथा जेआइपीएमईआर, पुडुचेरि द्वारा संचालित पीजी मेडिकल भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए अनापत्ति के 764 मामले निपटाए गए।

■■

विदेश प्रचार तथा लोक राजनय प्रभाग

23

21वीं शताब्दी में चुनौतियों का बेहतर सामना करके प्रभावी परिणाम तक पहुंचने के उद्देश्य से जनवरी, 2014 में मंत्रालय ने एक्सपी और पीडी प्रभागों को मिलाते हुए एक प्रभाग–(एक्स पीडी) बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2014 में, विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार तथा लोक राजनय प्रभाग ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विभिन्न विदेश नीति के मामलों पर भारत सरकार के पक्ष को प्रभावी रूप से बताने, साथ ही साथ अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय जनता को भारत, उसकी विदेश नीति तथा विश्व के साथ भारत के संबंधों के विभिन्न आयामों को बताने का अधिदेशित कार्य जारी रखा है। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्टॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ एक सक्रिय कार्य व्यवस्था के साथ–साथ मंत्रालय ने अपने लोक राजनयिक पहलों को और बढ़ाया है। विशेष रूप से डिजिटल प्रकार से, जिसके परिणाम जनता की राय को बनाने में और व्यापक श्रोता तक पहुचते हुए प्रभावी रूप में हुआ है।

प्रेस कवरेज़

मई, 2014 में नई सरकार के शपथ–ग्रहण समारोह जिसमें सार्क देशों के नेता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उच्च पदाधिकारीगण मुख्य अतिथि थे, से शुरूआत करते हुए एक्सपीडी प्रभाग सभी नई पहलों के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय प्रेस का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करते हुए सबसे आगे रहा है। विशेष रूप से विदेश नीति और राजनयिक पहुंच में/ प्रधान मंत्री के विज़न को ध्यान में रखते हुए एक्सपीडी प्रभाग ने सुनिश्चित किया कि कैच–फेजिज जैसे 'पड़ौसी पहले' (Neighbourhood First) तथा 'पूर्व की ओर कार्यान्वित' (Act East) विदेश नीति का प्रिंट, इलेक्टॉनिक साथ ही साथ सामाजिक मीडिया मंचों पर व्यापक रूप से प्रसार है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल हमीद और रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री ब्लादिमिर पुतिन ने दिसंबर, 2014 में भारत का दौरा किया। राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने की संभावना है।

वीवीआईपी यात्राएं:– पूर्ण रूप से सुचारू मीडिया केंद्रों की स्थापना और संचालन, मीडिया ब्रीफिंग का प्रबंध तथा राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री की विदेश यात्रा में साथ मीडिया का फेसिलिटेशन साथ ही साथ यात्रा का मीडिया कवरेज सुनिश्चित करना सभी लॉजिस्टिक प्रबंध एक्सपीडी प्रभाग करता है।

क) इस वर्ष के दौरान, इस प्रभाग ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की वियतनाम, नॉर्वे, फिनलैंड तथा भूटान यात्रा, उप–राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी की चीन यात्रा और प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भूटान, ब्राज़ील, नेपाल, जापान, यूएसए, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी यात्रा में साथ गए मीडिया प्रतिनिधिमंडल को सहायता प्रदान की।

ख) विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा इस वर्ष के दौरान विभिन्न राजनयिक अवसरों विशेष रूप से उनकी बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम, बहरीन, ताज़किस्तान, अपगानिस्तान, यूएसए, यूके. मालद्वीप, मॉरीशस. यूएई और आरओके की यात्रा के दौरान दिए गए भाषणों और वक्तव्यों का प्रकाशन

ग) एक्सपीडी प्रभाग ने विभिन्न विश्व नेताओं की आगामी यात्राओं की जानकारी का प्रचार–प्रसार करने में एक अहम किरदार निभआया है जिसमें राज्यों के प्रमुख/चीन और ऑस्ट्रेलिया सरकार शामिल हैं। एक्सपीडी प्रभाग ने यात्रा कर रहे गणमान्य व्यक्तियों (जैसे यूएस राज्य सचिव की यात्रा के लिए) के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इन यात्राओं के उपयुक्त कवरेज हेतु भारत में आधारित विदेशी मीडिया कार्मिकों और आने वाले मीडिया के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की।

नई सरकार की पहल का प्रचार:–

क) 02 अक्टूबर, 2014 को, स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने पर एक्सपीडी प्रभाग ने विदेश मंत्रालय, दिल्ली तथा विदेश स्थित मिशनों में सभी संबंधित आयोजनों के प्रेस कवरेज को सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई।

ख) 25 दिसम्बर, 2014 को जब प्रधान मंत्री ने 'मेक इन इंडिया' अभियान का औपचारिक उद्घाटन किया, एक्सपीडी प्रभाग ने औद्योगिक नीति और प्रचार विभाग के साथ निकटता के साथ कार्य किया। यह सुनिश्चित करते हुए कि इस अभियान को वैश्विक छाप मिले।

प्रेस ब्रीफिंगः–

पिछले कई सालों से, एक्सपीडी प्रभाग संयुक्त सचिव (एक्सपी) और सरकारी प्रवक्ता द्वारा निरंतर रूप से प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करता रहा है जो सप्ताह में कम से कम एक बार की जाती है।

i. जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम या महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौतियां होती हैं, जैसे इराक बन्धक संकट या महत्वपूर्ण यात्राओं के दौरान, प्रेस ब्रीफिंग बहुत ही व्यापक रूप से हुई है।

ii. जानकारी के तुरंत और समय पर प्रसारण को देखते हुए, 'एसएसएस एलर्ट', 'यू ट्यूब पर सीधा प्रसारण' और वास्तविक समय आधार पर विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पूरी अनुलेखन को डालने जैसी नए फीचर्स चलाए हैं।

iii. क्षेत्रीय भाषा मीडिया तक पहुंचनाः इस अवधि के दौरान प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया को दिए गए सरकारी प्रवक्ता के जवाब को हिंदी, उर्दू, अरबी, तमिल, बंगाली, असमिया, मलयालम में अनुवाद किया गया तथा तेलुगु को भी शामिल करने के क्षेत्र में विस्तार हुआ है।

प्रेस कवरेज और ब्रीफिंग के अलावा, एक्सपीडी मंत्रालय के सामाजिक, मीडिया और डिजिटल मीडिया को दूर तक पहुंचाने के प्रयासों के नोडल प्रभाग उत्तरदायी होने के साथ–साथ भारत के राजनयिक प्रयत्नों में सहयोग देने वाले नए प्रकाशनों और डॉक्यूमेंटरी को निकालता है। इन क्षेत्रों में कुछ प्रमुख नए फीचर्स/नीतियां/कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं–

नए डिजिटल आउटरीचः–

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट का अरबी और स्पेनिश रूपांतर की शुरूआतः जब मंत्रालय की वेबसाइट के हिंदी रूप को जनता की प्रशंसा प्राप्त हो रही थी, एक्स पी डी ने अरबी और स्पेनिश का नया रूप भी शुरू कर दिया।

i. नई आशियान–भारत वेबसाइटः– अपनी 'पूर्व की ओर कार्यान्वित' (Act East) विदेश नीति को देखते हुए, नई आशियान–भारत वेबसाइट (http://www.mea.gov.in/aseanindia/index/htm) भी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में जोड़ी गई।

ii. विदेश मंत्रालय ऑनलाइन; विदेश मंत्रालय के सामुदायिक मंच का प्रतिरूप; इस चर्चा मंच का उद्देश्य एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना जहां अधिकारी, सभी के सामान्य संदर्भ के व्यापक रेंज के मामलों पर बातचीत, शेयर और विचार–विमर्श कर सकते हैं।

iii. रेडियो पर इंडिया ग्लोबः प्रसिद्ध कार्यक्रम 'इंडिया ग्लोब' के सभी एपिसोड विदेश स्थित भारतीय मिशन की सलाह से तैयार किए जाते हैं और वह अब एआईआर एफएण चैनल पर प्रसारण के लिए उपलब्ध है, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के समर्पित चैनल (http://mea.gov.in/mea-campaigns.htm) तथा विदेश मंत्रालय के साउंडक्लाउड पेज (http://soundcloud.com/meaindia) तथा यू–ट्यूब चैनल (http://www.youtube.com/user/meaindia) पर भई प्रसारित है। यूजर इंडिया ग्लोब के नवीनतम एपिसोड को एमईए इंडिया मोबाईल एप पर भी सुन सकते हैं।

iv. पारस्परिक विश्व मैप विदेश मंत्रालय वेबसाइट (http://www.mea.gov.in/indian-missions-abroad.htm) यूज़र विदेश स्थित भारतीय मिशनों के सभी एकीकृत वेब पेज को एक एकल अंतरापृष्ठ, भारतीय संधि डाटाबेस (httphttp://www.mea.gov.in/treaty.htmhtm) के माध्यम से देख सकते हैं। इस डाटाबेस का उद्देश्य भारत के विदेशी देशों के साथ हुई संधि/करार/समझौता ज्ञापनों के सुलभ और खोजने लायक लिंक या लिंक की श्रेणी प्रदान करना है। सतर्कता संबंधी शिकायतों के लिए भी (http://www.mea.gov.in/lodge-complaint.htm) विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एक मॉड्यूल जोड़ा गया है।

सामाजिक मीडिया मंचः–

इस वर्ष के दौरान सभी मुख्य सामाजिक मीडिया मंचों पर विदेश मंत्रालय की मौजूदगी व्यापक और प्रभावशाली गतिविधि के रूप में दर्ज हुई (पिछले वर्ष से लगभग दुगुना)।

i. भारतीय राजनय फेसबुक पेज (www.facebook.com/indiadiplomacy) तथा विदेश मंत्रालय, भारत के फेसबुक पेज (www.facebook.com/MEAIndia) के विश्व के अलग–अलग देशों से क्रमशः 225000 तथा 600000 से ज्यादा अनुगामी है।

ii. एमईए इंडिया जी+ पेज को अपने इनर सर्कल में जोड़ने वाले लोगों की संख्या 100000 पर करते हुए तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार भारतीय राजनय ट्विटर खाते (@indiandiplomacy) तथा सरकारी वक्ता का ट्विटर खाते की मिलाकर 400000 अनुगामी है। यह मंच भारत तथा इसकी विदेशी नीति संबंधी ट्वीट करने के काम आता है।

iii. प्रेस ब्रीफिंग और अन्य मीडिया आयोजनों की वीडियो निरंतर रूप से एमईए इंडिया यू–ट्यूब चैनल (www.youtube.com/user/meaindia) पर अपलोड की जाती है।

iv. इस प्रभाग द्वारा प्रमाणित बड़ी डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में भारतीय राजनय यू–ट्यूब चैनल (www.youtube.com/user/indiandiplomacy) के माध्यम से एक विशेष ऑनलाइन उपस्थिति प्राप्त की है, जिसके 10000 से अधिक ग्राहक हैं और 1 मिलियन से अधिक श्रोता हैं।

v. मंत्रालय के सभी प्रमुख आयोजनों की फोटोग्राफ के लिए फ्लिकर अकाउंट (http://www.flickr.com/photos/

meaindia) एक उपयोगी और प्रसिद्ध ऑनलाइन संग्रह के रूप में कार्य कर रहा है।

vi. एमईए इंडिया मोबाईल एपः 'एमईए इंडिया' भारत सरकार के किसी संगठन द्वारा आरंभ किया गया पहला मोबाईल एप है। 'एमईए इंडिया' का 2.2 वर्जन की आरंभ किया गया है, जिसमें टेलीफोन डायेक्टरी और ''वॉट्स न्यू फ्रॉम इंडिया फ्रॉम इंडियन मिशन'' ऑन माइ स्क्रीन परिचित किया गया है।

दृश्य आउटरीच–फिल्में और डॉक्यूमेंट्री

इस वर्ष, एक्स पी डी प्रभाग ने अपने गैर–सरकारी पार्टनर के साथ मिलकर कई डॉक्यूमेंट्री का कार्म सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है जो विश्व भर में प्राप्त हो चुका है।

i. विशिष्ट डॉक्यूमेंट्री में शामिल है–''ब्रिज़िग वर्ल्ड, अ मीटिंग ऑफ माइंडः द स्टोरी ऑफ इंडियन्स इन दी युनाइटिड किंगडम'', ब्रिज़िग वर्ल्ड्स, अ प्लेस इन दी सन, द स्टोरी ऑफ इंडियन इन युनाइटिड स्टेट'', ''हिंदु नेक्टरः स्पीरिचुवर वॉन्डरिंग इन इंडिया'', ''हैंडमेड इन इंडिया'', ''लेसन्स इन फ्रेंडशिप'', ''किस्सा–ए–पारसी'', ''सुलह–ए–कुल''. लोक सेवा प्रसारण न्यास और लोक राजनय प्रभाग द्वारा निर्मित 'द क्वांटम इंडियन्स' को 2013 की सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।

ii. यह प्रभाग डॉक्यूमेंट्री के विशेष स्क्रीनिंग का भी प्रबंध करता हैः फायर इन द ब्लड, नत्यानुभव, किस्सा–ए–पारसी तथा हिंदी नेक्टर–स्पिरिचुअल वेन्डरिंग इन इंडिया को बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया।

पुस्तकें, पत्रिकाएं, व्याख्यान और भाषणः–

इस वर्ष, एक्स पी डी प्रभाग ने भारत–चीन सांस्कृतिक संबंध पर एक विश्व कोष प्रकाशित किया, जो भारतीय और चीनी विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है।

i. सितम्बर, 2014 में विदेश मंत्री की पहली प्रेस वार्ता के दौरान एक्सपीडी प्रभाग ने 'फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की (मुद्रित तथा डिजिटल रूप में); जिसमें नई सरकार की विदेश नीति की उपलब्धियों को दर्शाया है और वह बहुत अच्छे से स्वीकार की गई।

ii. भारत के युवा को देश की राजनयिक चुनौतियों से और अधिक अवगत कराने तथा छात्रों को विदेश नीति की निर्णय–प्रक्रिया के और निकट लाने हेतु एक्सपीडी प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के 'विशिष्ट वक्तव्य की श्रृंखला' को देश के हर कोने में पहुँचाने का कार्य किया। विशिष्ठ वक्तव्य श्रृंखला के अंतर्गत 32 वक्तव्य दिये जा चुके हैं।

iii. इस प्रभाग की प्रमुख पत्रिका, इंडियन पर्सपेक्टिव्स अब मोबाईल प्लेटफॉर्म पर 14 भाषाओं में उपलब्ध है– हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इंडोनेशियन, इटैलियन, पास्तु, पर्शियन, पुर्तगाली, रूसी, सिंहालीस, स्पैनिश, तमिल। इसके अतिरिक्त, यह पत्रिका उच्च रिजोल्यूशन वाले मोबाइल फोन जैसे छोटे से यंत्र पर देखी जा सकती है।

iv. इस प्रभाग ने पूरे भारत से, ऊर्जा और जिंदगी से भरी युवा बालिकाओं की तस्वीरों को संग्रहीत करते हुए 'गर्ल चीलड' जैसी विषय–वस्तु पर वर्ष 2015 का कैलेंडर प्रकाशित किया है जो की लड़कियों के लिए महफूज़, सुरक्षित और समान वातावरण प्रदान करने के हमारे लक्ष्य का एक प्रतिबिंब है।

v. एक्स पी डी प्रभाग ने कोंसुलर और पासपोर्ट प्रभागों की नई पहल को सुनिश्चित किया जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट दिवस के समारोह को राष्ट्रीय रूप से कवर करना शामिल है।

vi. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद इस पहल का दिसंबर 2014 के महीने में विज्ञापन अभियान के माध्यम से व्यापक प्रसार किया गया।

परिचय यात्राएँ

अपने मित्र देशों के बीच भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने और दोस्ताना राजनयिक आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एक्स पी डी प्रभाग ने म्यांमार, थायलैंड, छोटे द्वीपसमूह, विकासशील देशों, अफ्रीकी देशों, लेटिन अमरीकी देशों तथा रूसी संघ के विदेशी पत्रकारों द्वारा एक परिचय यात्रा आयोजित की। समसामाजिक भारत की जागरूकता और समझ बढ़ाने तथा भारतीय साहित्य की विरासत को जानने के आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, एक्सपीडी प्रभाग ने 26 दिसम्बर, 2014 से 06 जनवरी, 2015 तस ऑस्ट्रेलिया, कोस्टारिका, ईरान और कनाडा से 5 प्रतिष्ठित चित्रकारों और साहित्यकारों को बुलाया। वरिष्ठ जर्मन पत्रकारों के दो प्रतिनिधिमंडल की शीघ्र ही भारत यात्रा करने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर, भारत के पत्रकारों की एशियाई देशों में परिचय यात्रा भी आयोजित की गई।

द्विपक्षीय मीडिया मंच

मीडिया संवाद और आदान–प्रदान बढ़ाने के उद्देश्य से सितम्बर, 2013 में भारत–चीन मीडिया मंच के उद्घाटन के बाद, अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में 14 अरबी संघ सदस्यों की उपस्थिति सहित पहला ऐसा भारत–अरब संघ मीडिया मंच आयोजित किया गया। अंग्रेजी, अरबी, हिंदी और उर्दू प्रेस के वरिष्ठ पत्रकारों की सहभागिता सहित यह प्रतिष्ठित आयोजन का 21 अगस्त, 2014 को स्वयं विदेश मंत्री ने उद्घाटन किया।

■■

24

विदेश सेवा संस्थान

अधिकारी प्रशिक्षाणार्थी

विदेश सेवा संस्थान ने भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 2012 बैच के 36 आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षणार्थी ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और 18 जून, 2014 को एफएसआई में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह इस आयोजन की मुख्य अतिथि थीं। 2012 बेच के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के लिए विदेश मंत्री के स्वर्ग पदक से सुश्री प्रियंका सोहोनी को पुसस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ सोध निबंध के लिए राजदूत बिमल सान्याल स्मृति मेंडल से सुश्री गीतांजली ब्रेडन को नवाजा गया। सर्वोत्तम खिलाड़ी ट्राफी से श्री रिचपाल सिह और सुश्री निधि चौधरी को पुरस्कृत किया गया।

2013 बैच के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों ने सिंतबर, 2013 में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक राष्ट्रीय अकादमी में फाउंडेशन कोर्स पर जाने से पूर्व अगस्त 2013 में एफएसआई में एक सप्ताह का निर्देशन कोर्स किया। बैच नौ–महीने के दीर्घ प्रशिक्षण के लिए दिसंबर 2013 में एफ एस आई लौटडा। उनके प्रशिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक राजनय, हाइड्रो डिप्लोमेसी, मीडिया संबंध सांस्कृतिक राजनय, सूचना का अधिकार सामाजिक विकास, अल्पसंख्यक और जन अधिकार मामले आदि जैसे विषय शामिल है। इस कार्यक्रम में प्रशासन, स्थापना, लेखा , प्रोतोकॉल, कॉन्सुलर मामले, प्रतिवेदन कौशल, राजभाषा नीति, विदेश प्रचार लोक राजनय, प्रतिनिधित्व कौशल तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत पर मॉड्यूल भी शामिल है।

प्रशिक्षण, अंतः क्रिया सूत्रें, सामूहिक चर्चा, केस अध्ययन, भूमिका निर्वहन तथा अनुकरण और सर्जनात्मक सोच को विकसित करने के लिए विषयात्मक मामलों पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिया जाता है। प्रभावी संवाद कौशल विकसित करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्सुलर कार्य पर विशेष मॉड्यूल भी इसमें शामिल है। प्रबंधन और आर्थिक मामलों पर प्रवीणता विकसित करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से पांच सप्ताह का एक कोर्स आयोजित किया गया। अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्य से परिचित कराने हेतु उन्हें चार अलग–अलग समूहों में पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के भारतीय मिशनों में भेजा गया।

अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना तथा विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के साथ भेजा गया। उन्होंने मुंबई में माजागोमा डॉकयार्ड लिमिटेड, बी ए आर के का भी दौरा किया और प्रमुख। वित्तीय संस्थानों और औद्योगिक स्थापनाओं के साथ इंटरेक्टिव सत्र किया। अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को देश के सम्पन्न सांस्कृतिक विविधता, विरासत तथा आर्थिक और पर्यटन संभाव्य से बेहतर परिचित कराने हेतु उनके लिए तीन सप्ताह का भारत दर्शन आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों में एक महीने का डिस्ट्रिक्ट अटेचमेंट शामिल है जहां अधिकारी प्रशिक्षणार्थी को प्रशासन के बारे में साधारण जन स्तर पर जानकारी तथा राज्यों की कार्य प्रणाली और जिला प्रशासन के बारे में सीखने का अवसर मिला। उनकी जिला यात्रा के बाद अधिकारी प्रशिक्षणार्थी ने एफ एस आई शिक्षकों और राज्य स्थानीय आयुक्त की मौजूदगी में एक विस्तृत प्रस्तुति बनाई। एफ एस आई में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 2013 बैच को अक्तूबर 2014 में मंत्रालय में डेस्क अटेचमेंट पर भेज दिया गया।

वर्ष 2014 बैच के आई एफ एस अधिकारी प्रशिक्षार्थियों ने एल बी एस एन ए ए मसूरी में फाउंडेशन कोर्स में जाने से पूर्व अगस्त 2014 को एफ एस आई में एक सप्ताह का निर्देशन कोर्स किया। 2015 बैच के 32 अधिकारी प्रशिक्षणार्थी तथा 2013 बैच का एक ओ टी 15 दिसंबर 2014 से एफ एस आई में अपना प्रशिक्षण आरंभ करेंगे।

मिड–कैरियर प्रशिक्षण

एफ एस आई ने 1997 और 1998 बैच के ग्रेड–IV अधिकारी (निदेशक–स्तर) के लिए एफ एस आई, फ्लेचर्स स्कूल आफ ला एंड डिप्लोमेसी, मस्स चुसेट् और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में 22 जून से 11 जुलाई, 2014 तक तीन सप्ताह का एक एम सी टी पी फेज–II आयोजित किया।

एम सी टी पी–I (कैरियर के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम फैज–I) का एक लचिला कार्यक्रम उन अधिकारियों के लिए जो कि अपनी पहली बाल की विदेशी तैनाती पूरी करके मुख्यालय वापस आते हैं।

जिनकी 5 से 8 वर्षों की सेवा का अनुभव रखते हैं के लिए वहां रखा गया जहां वही अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनी गति और सुविधा के अनुसार पूरा कर सकें।

गैर–अनिवार्य प्रशिक्षण की भी प्रणाली रखी गई ताकि रूचि रखने वाले अधिकारी प्रतिष्ठित भा रतीय तथा अंतर्राष्ट्री विश्वविद्यालयों तथा उत्कृठ केन्द्रों से अपनी विशेषज्ञता/रूचि वाले विशिष्ट विषय में प्रगामी प्रशिक्षण की सुविधा उठा सकें।

अन्य प्रशिक्षण माड्यूलः आई एफ एस अधिकारी प्रशिक्षणार्थी तथा प्रतिनियुक्तियों/अवर सचिव/उप सचिव स्तर और अन्य अधिकारियों के व्यापक प्रदर्शन तथा विचारों के आदान–प्रदान के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें व्यापार और आर्थिक राजनय, मीडिया प्रबंधन, हाइड्रो डिप्लोमेसी आदि विषय शामिल हैं।

अंतर सेवा प्रशिक्षण

भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों के लिए 19 से 23 मई, 2014 को पहली बार आर्थिक और वाणिज्य प्रशिक्षण का निर्देशन कैप्सूल आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

भारतीय विदेश सेवा के शाखा 'ख' के लिए प्रशिक्षण

अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों, सहायकों/व्यक्तिक सहायकों तथा कलर्क के लिए प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया गया। भारत सरकार नियमों तथा कार्यालय प्रक्रिया तथा विदेश मंत्रालय की विशिष्ट विषय जैसे आई एफ एस (पी एल सी ए) नियम, आई एम ए एस (एकीकृत मिशन लेखा प्रणाली), प्रोतोकाल, आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्य, कोन्सुल, पासपोर्ट तथा वीजा कार्य आदि के मौजूदा प्रशिक्षण कोर्स के अलावा व्यक्तित्व विकास और मूल कंप्यूटर और आई टी कौशल, वेबसाइट प्रबंधन, वित्त एवं बजट कार्य, विदेश मंत्रालय ओवरव्यू, विदेश नीति व्यापार पदोन्नति, सांस्कृति राजनय, मीडिय हैंडलिंग, वी वी आई पी यात्राएं आदि के क्षेत्रों में नया प्रशिक्षण कैप्सूल प्रारंभ किया गया। विदेश मंत्रालय के एम टी एस स्टाफ और ड्राइवरों के लिए पहली बार दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विदेश स्थित प्रतिरोध विदेशी राजदूतावास/राजनयिक संस्थानों के साथ संयोजन

डीन, एफ एस आई 23–28 सितंबर, 2014 को प्रीटोरिया में हुई राजनयिक अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान की डीन और निदेशकों की 41वीं बैठक में उपस्थित हुए। 21 अक्तूबर, 2014 को श्री के.ई. महोई, उप महानिदेशक, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के नेतृत्व में 4 सदस्यों के प्रतिनिधमंडल ने एफ एस आई का दौरा किया। इस वर्ष के दौरान नई दिल्ली में कई दूतावासों (अफगानिस्तान, अजरबैजान, कोस्टारीका, लीबिया, सर्बिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम) एफ एस आई के साथ संपर्क किया। सितंबर और नवंबर 2014 में एफ एस आई में कार्यक्रम के अंतर्गत आसियान छात्रों के लिए भारत की विदेश नीति पर एक वक्तव्य आयोजित कराया।

एफ एस आई ने 19 नवंबर, 2014 को फिजी गणराज्य की सरकार के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

स्वच्छ भारत अभियानः

एफ एस आई ने प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए स्वच्छ भारत अभियान में सहभागिता दी। अपने परिसर को साफ करने और इस संदेश/सीख को अपने प्रशिक्षण विषय में शामिल करने के अलावा एफ एस आई ने इस अभियान को अपने आस–पास भी फैलाया, जैसे बेर सराय के इलाके में। इन्होंने सभी शेयर होल्डरों जैसे बेर सराय व्यापारी संघ, आवासीय कल्याण संघ, सी पी डब्ल्यू डी, एम सी डी, उस क्षेत्र के अन्य संस्थान– आई एस टी एम, विशेषज्ञ/एन जी ओ– सुलभ शौचालय की एक बैठक आयोजित कराई। कार्रवाई की योजना पर चर्चा के लिए एक बैर सराय स्वच्छ भारत समिति का निर्माण किया गया जिसमें मासिक स्वच्छता तथा जागरुकता अभियान आयोजित करना शामिल है।

■■

25

राजभाषा कार्यान्वयन नीति और विदेशों में हिंदी का प्रचार–प्रसार

मंत्रालय का मिशनों/केंद्रों की सहभागिता सहित विदेशों में हिंदी के प्रचार–प्रसार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत हिंदी पाठ्यपुस्तकें, साहित्य और बाल पुस्तकें, हिंदी पत्रिकाएं, हिंदी शिक्षण सी डी, कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर, शब्दकोष आदि सहित हिंदी शिक्षण सामग्री शिक्षण संस्थानों और अन्य एन जी ओ को भेजी जाती है। मिशनों/केंद्रों के माध्यम से मंत्रालय हिंदी संबंधी गतिविधियों के लिए विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों को सहयोग प्रदान करता है।

मंत्रालय द्वारा विभिन्न देशों में क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करना, विदेशों में हिंदी के प्रचार–प्रसार की एक पहल है। ये क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन हमारे विदेश स्थित मिशनों के साथ विदेशों में भारतीय संस्कृति और हिंदी के प्रचार से जुड़े स्थानीय आयोजकों के सहयोग से किए जाते हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन न्यूयार्क, मास्को और मॉरिशस में किए गए। इसके अतिरिक्त हर तीन वर्षों में एक विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2012 में जोहन्सबर्ग में आयोजित किया गया था। अगला विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में सितंबर 2015 में आयोजित होने जा रहा है।

हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए भारत और मॉरिशस के बीच एक द्विपक्षीय करार के तहत मॉरिशस में एक विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। सचिवालय का कार्य विदेश मंत्रालय तथा मॉरिशस सरकार में उनके मॉरिशस समकक्षी के सहयोग से किया जाता है।

मंत्रालय विदेशी विद्यार्थियों को केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में हिंदी अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य में भी सहयोग प्रदान करता है। प्रति वर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को विदेश मंत्रालय लगातार उच्च प्राथमिकता देता रहा है। मंत्रालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर इस वर्ष भी 'हिंदी पखवाड़े' का आयोजन किया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।

हिंदी दिवस 2014 के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और साथ ही विदेश स्थित मिशनों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों के लिए विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया था।

प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मुख्यालय के साथ–साथ हमारे विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जिन मिशनों ने विश्व हिंदी दिवस मनाने हेतु अनुदान का अनुरोध किया था उन सभी को वह प्रदान किया गया। मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं।

मंत्रालय में विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक हिंदी सलाहकार समिति कार्य कर रही है।

संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के आधार पर, विदेश स्थित भारतीय मिशनों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में, मंत्रालय सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु राजभाषा विभाग के सहयोग से विदेश स्थित भारतीय मिशनों और भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

26

सांस्कृतिक संबंधों हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) की स्थापना 09 अप्रैल, 1950 को भारत बाह्य सांस्कृतिक संबंधों को सूत्रबद्ध करने तथा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने और भारत तथा अन्य देशों के बीच पारस्परिक समझ विकसित करनेए संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने और विकसित करने तथा इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संसाधनों/उपायों को करने के लिए की गई थी।

आई सी सी आर के कार्यकलापों को मुख्यतः इस प्रकार विभाजित किया जा सकता हैः शैक्षिक तथा बौद्धिकः कला तथा संस्कृति एवं अन्य कार्यकलाप।

शैक्षिक तथा बौद्धिक

आई सी सी आर कला और संस्कृतिए मानविकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी छात्रों द्वारा स्नातक पूर्व स्नातकोत्तर तथा डाक्टरी कार्यक्रमों में पढ़ाई तथा साथ ही इंजीनियरी, फॉर्मेसी, अकाउन्टेंसी, व्यापार प्रशासन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। शैक्षिक वर्ष 2014–15 के लिए 6200 से अधिक आई सी सी आर छात्रवृत्तिधारक भारत के 20 से अधिक राज्यों में 120 से अधिक विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के कार्यकलापों का सुचारु रूप से प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र परामर्शदाताओं की वार्षिक बैठक आई सी सी आर मुख्यालयए नई दिल्ली में 22 अप्रैलए 2014 को हुई थी ताकि रुपात्मकता का पता लगाकर मुद्दों का समाधान किया जा सके ताकि विदेशी छात्रवृत्तिधारकों का भारत में रहना आरामदायक और उपयोगी बनाया जा सके।

आई सी सी आर विभिन्न कल्याण उपायों, विशिष्ट भारतीय विद्वानों द्वारा व्याख्यानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन कैम्पों का आयोजन करती है ताकि विदेशी छात्रवृत्तिधारकों को भारत को जानने तथा इसकी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत तथा इस देश की औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमताओं को जानने का अवसर मिल सके। इन कार्यकलापों के एक भाग के रूप में चौथा अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तिधारक सम्मेलन 07–09 मार्चए 2014 के दौरान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानए राउरकेला में आयोजित किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में छात्रवृत्तिधारकों ने भाग लिया। आई सी सी आर द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 नवंबर, 2014 को पुणे में भी किया गया। चेन्नई आई आई टी में 08–14 जून को आयोजित स्पिक मैकेज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर स्टूडेन्ट्स को भी इसने सहयोग दिया।

मौलाना आजाद की जन्म शती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा विदेश मंत्री के लिए एक आमंत्रण का आयोजन 10 नवंबर, 2014 को किया गया। अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने–अपने राज्यों के राज्यपालों/मुख्यमंत्रियों के साथ छात्रों की बातचीत का आयोजन किया।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को आई सी सी आर इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि वे आई सी सी आर पूर्व छात्र समूह स्थापित करे और इस प्रकार के अनेक समूह पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। माननीय विदेश मंत्री ने 02 नवंबरए 2014 को अपने मॉरीशस दौरे में आई सी सी आर पूर्व छात्र समूह लांच किया।

आई सी सी आर ने विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के परामर्श से अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययनों के पीठ स्थापित किए हैं। इन पीठों का उद्देश्य यह है कि विदेशी छात्रों को भारत के बारे में शिक्षित करने के अलावा वे एक धुरी का काम करें जिसके इर्द–गिर्द विदेशों में स्थित शिक्षा संस्थानों में भारतीय अध्ययनों का विकास होगा।

30 नवंबर, 2014 तक इस प्रकार की पीठों की संख्या 77 थी जिसमें स्कूल स्तरीय हिंदी अध्यापकों के 11 पद शामिल हैं। कुल 77 पीठों में से 29, भारतीय भाषाओं के अध्यापन के लिए (22 हिंदी पीठ जिनमें 11 प्रोफसर स्तरीय तथा 11 अध्यापक सतरीय) 04 संस्कृत पीठ, 02 तमिल पीठें और 01 बंगाली पीठ हैं जबकि शेष पीठें भारत से संबद्ध विषयों से संबंधित हैं।

अप्रैल, 2014 से नवंबर, 2014 की अवधि के दौरान भारतीय अध्ययनों की नई पीठें स्थापित करने के लिए साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा और दारुसलाम विश्वविद्यालय और तंजानिया के साथ भारतीय अध्ययनों की नई पीठें स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। महात्मा गांधी संस्थानए मोकाए मॉरीशसय रियूकोकू विश्वविद्यालय, क्योटो, जापान; लागोस बिजनेस स्कूल, लागोस, नाइजीरिया; आरबस विश्वविद्यालय, आरबस डेनमार्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा, वारसा, पोलैण्ड में भी आई सी सी आर की पीठें जारी रखने के लिए पांच और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसी अवधि में एक और महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि लागोस बिजनेस स्कूल, लागोस, नाइजीरिया में एक अल्पावधिक पीठ को साझा रूप से संचालित करने के लिए आई सी सी आर और भारत के निर्यात–आयात बैंक (ऐक्जिम बैंक) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेशों में पीठों के अलावा, आई सी सी आर भारत में भी, अर्थात् सार्क पीठ और नेल्सन मंडेला पीठ चलाती है जिसके लिए स्कालर्स को विदेशों से भारत में आमंत्रित किया जाता है। जबकि अफ्रीकी

स्कालरों को नेल्सन मंडेला पीठ के लिए आमंत्रित किया जाता है जो स्थायी रूप से जे एन यू में स्थापित है, वहीं सार्क देशों के स्कालर्स सार्क पीठ के लिए आमंत्रित किए जाते हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में बारी–बारी से स्थापित की जाती है।

आई सी सी आर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्कालर्स को वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप प्रदान करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर संस्कृति और सामाजिक विज्ञानों में विशेषज्ञ हासिल करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आई सी सी आर को एक कनिष्ठ फैलोशिप जून 2014 में क्रोएशिया से तथा एक वरिष्ठ फैलोशिप स्पेन से मिली जिन्होंने 2012–13 में फैलोशिप ग्रहण की और वे अपनी फैलोशिप के दूसरे चरण में भी बने हुए हैं, जो पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से जुलाई 2014 में आरंभ हुई।

अपने बाहरी दौरों पर भेजे जाने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत आई सी सी आर ने ब्राजील, कोलम्बिया, क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मॉरीशस, रूस, टर्की, यू के और यू एस ए सहित विश्व के अनेक भागों में 17 उत्कृष्ट स्कालर्स को प्रायोजित किया।

शैक्षिक विजिटर्स कार्यक्रम के अंतर्गत आई सी सी आर ने 04 उत्कृष्ट शिक्षाविदों/स्कालरों को कजाकिस्तान, जर्मनी और ट्यूनीशिया से आमंत्रित किया।

कला और संस्कृति

इस समय आई सी सी आर के विदेशों स्थित सभी महाद्वीपों में फैले 34 पूर्ण तथा 01 उप केन्द्र है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और 'साफ्टपावर' को न केवल नृत्य, संगीत, योगा और हिंदी की कक्षाओं के माध्यम से बल्कि कला और मूर्तिकला की प्रदर्शनियों, दर्शनशास्त्र, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, आर्थिक रुझानों, भारत में सिनेमा आदि से संबंधित स्थानीय और भारत से आए आगंतुकों के द्वारा भी प्रचार–प्रसार करने के केन्द्र बनाना है। सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए सरकारी निजी भागीदारी मॉडलों के संवर्धन हेतु 03 जुलाई, 2014 को आई सी सी आर तथा कासा डी ला इंडिया को 75,000 यूरो की वित्तीय सहायता प्रदान करने या व्यय का 25 प्रतिशत देने, जो भी कम हो, के लिए 05 वर्ष की अवधि हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य रूप से स्थानीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित एक सांस्कृतिक केन्द्र का उद्घाटन बुसान, कोरिया गणराज्य में किया गया। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए लगातार बातचीत और मार्गदर्शन के माध्यम से आई सी सी आर अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या के साथ–साथ उनके आकार तथा विविधता को बढ़ाने में भी सफल रही है।

आई सी सी आर ने 55 भारतीय सांस्कृतिक समूहों/कलाकारों को अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अनेक देशों में दौरे के लिए प्रायोजित किया/यात्रा अनुदान दिया जिनमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समारोह भी शामिल थे। परिषद ने मॉरीशस में ''भारत के अनुबंधित श्रमिकों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ के समारोहों'' में भारत की सहभागिता का 31 अक्तूबर से 09 नवंबर, 2014 तक तथा अल्जीरिया में ''दूसरे भारत–अरब सांस्कृतिक समारोह'' का 20–27 नवंबर, 2014 को भी आयोजित किया।

आई सी सी आर ने 07 अप्रैल, 2014 को सिएमरीप, कम्बोडिया में भारत–एम जी सी संग्रहालय के उद्घाटन का भी समन्वय किया, जहां ''वस्त्रम–भारतीय वस्त्रों का भव्य संसार'' नामक प्रदर्शनी की जा रही है। इसने 29–30 सितंबर, 2014 को संग्रहालय शासी बोर्ड की बैठक की संयुक्त अध्यक्षता तथा समन्वयन भी किया।

आई सी सी आर ने अपनी ओर से विभिन्न देशों में 24 प्रदर्शनियां भी भेजी जिनमें फोटोग्राफी, चित्रकला और वस्त्रों का विस्तृत प्रतिबिम्ब था। इसने विदेशों में भारतीय समसामयिक कला और फोटो प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 05–09 नवंबर, 2014 के दौरान जयपुर में 'मैत्री' नामक भारत–चीन माहिला कलाकारों की रेजीडेन्सी का भी आयोजन किया। इन पेंटिंग का उद्घाटन 09 नवंबर, 2014 को जयपुर में किया गया। इसे भारत और चीन में अनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

क्षितिज श्रृंखला के अंतर्गत आई सी सी आर ने अपनी आजाद भवन कला दीर्घा में चित्रकला और मूर्तिकला पर 27 प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

सांस्कृतिक सहयोग संवर्धन पर भारतीय प्रशांत रिम एसोसिएशन (आई ओ आर ए) के कोर ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में आई सी सी आर ने 29–30 अगस्त, 2014 को कोची में बैठक की मेजबानी की। इस ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों पर पर्थ में आयोजित आई ओ आर ए की मंत्रिस्तरीय बैठक में विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्कों को बढ़ावा देने के लिए आई सी सी आर ने विदेशी सहभागिता के साथ भारत में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें महत्वपूर्ण है 10–12 अक्तूबर, 2014 के दौरान दिल्ली में आयोजित बेगम अख्तर शताब्दी समारोह जिसमें एक पाकिस्तानी समूह, 02 बांग्लादेशी समूहों तथा 03 भारतीय समूहों ने प्रतिभागिता की; दिल्ली में 13–15 अक्तूबर, 2014 के दौरान आयोजित ''अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य संगीत समारोह'' जिसमें हंगरी, इजराइल, पोलैण्ड, रूस, यू के तथा भारत के समूहों ने सहभागिता की; 28–30 अक्तूबर, 2014के दौरान दिल्ली में आयोजित ''अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य एवं संगीत समारोह'' जिसमें हंगरी, इजराइल, पोलैण्ड, रूस, यू के तथा भारत के समूहों ने सहभागिता की, 28–30 अक्तूबर, 2014 के दौरान दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत समारोह जिसमें इजराइल, कजाकिस्तान, मलेशिया, रूस, स्पेन और भारत से समूहों ने सहभागिता की और विदेश मंत्रालय के सार्क प्रभाग की ओर से 07–09 नवंबर, 2014 के दोरान पुराना किला, नई दिल्ली में आयोजित ''आठवां दक्षिण एशिया बैण्ड समारोह, 2014'' जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, फ्रांस, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बैण्ड समूहों ने सहभागिता की। अपने स्वयं के कार्यक्रमों के अलावा आई सी सी आर ने 21–23 नवंबर, 2014 के दौरान नेहरू पार्क, दिल्ली में कृष्णा प्रेरणा चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ''पांचवां विश्व बांसुरी वादन समारोह, 2014'' को भी सहयोग प्रदान किया जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बेल्जियम और दक्षिण कोरिया से पांच विदेशी समूहों ने सहभागिता की। आई सी सी आर, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह तथा कृष्णा प्रेरणा चेरीटेबल ट्रस्ट ने 21–23 नवंबर, 2014 के दौरान नेहरू पार्क, दिल्ली में ''दूसरा विश्व थपक समारोह'' आयोजित किया जिसमें अल सल्वाडोर, हंगरी, इजराइल, जॉर्डन, कोरिया, नीदरलैण्ड्स, स्पेन और भारत से समूहों ने सहभागिता की। नई दिल्ली में 28 अक्तूबर से 11 नवंबर, 2014 के दौरान ''आठवें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय

कला समारोह, 2014'' के आयोजन के लिए आई सी सी आर ने 'फोरम ऑफ आर्ट बियोण्ड बार्डर्स'' (एफ ए बी बी) तथा 'प्रसिद्ध फाउंडेशन' दिल्ली के साथ ही सहयोग किया जिसमें ऑस्ट्रिया,यू एस ए, चेक गणराज्य से 02 समूहों, हंगरी, इजराइल और पाकिस्तान के समूहों ने सहभागिता की।

उपर्युक्त समारोहों के अलावा, आई सी सी आर ने अफगानिस्तान, अल सल्वाडोर, मॉरीशस और रूस के विदेशी सांस्कृतिक समूहों के कार्यक्रमों की मेजबानी की। इन सबके अलावा आई सी सी आर ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय कृवि भागटीमिगुली पिगुली के काव्य पर आधारित एक कार्यक्रम की दिल्ली में मेजबानी करके तुर्कमेनिस्तान के दूतावास को सहायता प्रदान की तथा उन्हीं पर नई दिल्ली में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन करके भी सहायता प्रदान की। तुर्कमेनिस्तान से एक 30 सदस्यीय लोक नर्तक समूह के कार्यक्रम को 16 अक्तूबर, 2014 को आयोजित करके भी आई सी सी आर ने तुर्कमेनिस्तान दूतावास को सहयोग दिया। आई सी सी आर ने नई दिल्ली में 27 नवंबर,2014 को 'ताजिक पर्शियन कवि अब्दुर्रहमान जमीं की 600वीं जन्मशती' को मनाने के लिए नई दिल्ली में एक संगोष्ठी के आयोजन में तजाकिस्तान दूतावास को सहयोग प्रदान किया।

आई सी सी आर ने इण्डोनेशिया के सुप्रसिद्ध कठपुतली मास्टर दालोंग सुकीवो तेजो के 'कुम्भकरण का पतन' शीर्षक के तैयार रामायण कठपुतली कार्यक्रम का आई सी सी आर के आजाद भवन सभागार में 29 जनवरी, 2014 को आयोजन करने में नई दिल्ली में इण्डोनेशियाई राजदूतावास को सहायता प्रदान की।

नई दिल्ली के आजाद भवन सभागार में भारतीय कलाकारों/समूहों द्वारा प्रस्तुत 'क्षितिज श्रृंखला' के अंतर्गत आई सी सी आर द्वारा अठारह सांस्कृतिक संध्यायों का आयोजन किया। ''क्षितिज श्रृंखला'' कार्यक्रमों का आयोजन परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी किया जाता है।

अन्य गतिविधियां

आई सी सी आर ने ''विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम'' के अंतर्गत कोस्टारिका और जर्मनी से प्रख्यात हस्तियों के दौरों की मेजबानी की।

आई सी सी आर द्वारा 26–30 मई, 2014 के दौरान भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों (2013 बैच) के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानों, कार्यक्रमों तथा प्रस्तुतियों के माध्यम से अधिकारियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई गई।

आई सी सी आर पांच भिन्न भाषाओं में पत्रिकाएं, यथा– ''इंडियन होरिजोन'' (अंग्रेजी–त्रैमासिक), ''गगनांचल'' (हिंदी–द्विमासिक), ''पेपलेसदी ला इंडिया'' (स्पेनिश–छमाही), ''राकोन्द्रे एवकलिन्डे'' (फ्रेंच–छमाही), तथा ''थकाफट–उल–हिंदी'' (अरबी–तिमाही) का भारत तथा विदेशों में वितरण के लिए प्रकाशन करती है।

हिंदी को बढ़ावा देने तथा इसका प्रचार–प्रसार करने के लिए परिषद भारत तथा विदेशों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जैसे सम्मेलन और पुस्तकों का लोकार्पण/हिंदी भाषा के प्रचार के लिए परिषद विदेश स्थित अपने सांस्कृतिक केन्द्रों, मिशनों और विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापक/प्रोफेसर नियुक्त करती है। यह विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा सांस्कृतिक केन्द्रों को हिंदी पुस्तकें, शब्दकोश तथा अपनी पत्रिका ''गगनांचल'' की प्रतियां भेजती हैं। अप्रैल से नवंबर 2014 के बीच परिषद ने ''गगनांचल'' खंड 37 के अंक 01,02 व 03 प्रकाशित किए। परिषद ने श्रीमती रुपरानी को शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनीवर्सिटी, चीन में सुश्री शीरीं कुरैशी को श्रीलंका, कोलम्बो स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में तथा श्रीमती कविता सिंह को येरेवेन स्टेट लिंग्विस्टिक यूनीवर्सिटीए आर्मेनिया में हिंदी अध्यापक के रूप में प्रायोजित किया। आई सी सी आर से दो हिंदी अध्यापकों ने प्रसार भारती द्वारा मई 2014 में आयोजित एक दिवसीय हिंदी प्रशिक्षण कैम्प में भाग लिया। परिषद ने श्शसर्वप्रथम संस्कृत समन्वय समितिश्श के सहयोग से 19 जूनए 2014 को अपने सभागार में काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया तथा सितंबरए 2014 में ''हिंदी पखवाड़ा'' का भी आयोजन किया। परिषद बैंकाक और तुर्कमेन नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज अश्गाबाद में हिंदी सीख रहे छात्रों को पुस्तकें भी प्रदान करती है।

परिषद के संस्थापक अध्यक्षए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा सौंपा गया वैयक्तिक पुस्तक भंडार तथा पाण्डुलिपियां भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पुस्तकालय का सत्व हैं। मौलाना आजाद की वैयक्तिक पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों की सूची पुस्तक रूप में तीन भाषाओं दृ अरबीए उर्दू तथा फारसी में मुद्रित है। पिछले दशकों के पुस्तकालय कई बढ़ा है और वर्तमान ने इसके 50,000 से अधिक पुस्तकें हैं। परिषद ने ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालयों का प्रशासन देखने तथा भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के क्रियाकलापों का समन्वय जारी रखा।

भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आजाद की मधुर स्मृति में परिषद ने 1958 में मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यान आरंभ किए। इन व्याख्यानों का उद्देश्य विश्व के विभिन्न लोगों के बीच बेहतर सूझ–बूझ बढ़ाना है तथा महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रतिवर्ष भारत तथा विदेशों से प्रख्यात वक्ता आमंत्रित किए जाते हैं जो मानव मात्र को और विशेष रूप से भारत के लोगों को सम्बोधित करते हैं। इस वर्ष का व्याख्यान 11 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली के तीन मूर्ति हाउस के नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी द्वारा ''पश्चिम एशिया में अशांति की एक सदीः राष्ट्रीयता के कुछ फंदेश्श विषय पर दिया गया था।

इस अवधि के दौरान परिषद ने बुडापेस्ट में यूनिवर्सिटी आफ पेक्स, यूनीवर्सिटी आफ दारेस्लाम तथा सेंट्रल पार्क ऑफ हरारे में क्रमशः स्थापना के लिए महात्मा गांधी की तीन प्रतिमाएंः हंगरी, तंजानिया और जिम्बाब्वे में भिजवाई थीं।

दिसंबर 2014 से मार्च 2015 के बीच संभावना है कि 08 नई पीठों का (ऑस्ट्रेलिया) में 03 मेकवोर यूनीवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न); कनाडा (मैकगिल यूनिवर्सिटी); जमैका (यूनिवर्सिटी आफ वेस्टइंडीज); आइसलैण्ड (चुलालोंगका; यूनिवर्सिटी), यूक्रेन (तारास शेवचेनको नेशनल यूनिवर्सिटी आफ कीव); और यू एस ए (रुटगर्स स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजर्सी) को प्रचालनात्मक बनाया जाएगा जिनके लिए समझौता ज्ञापनों पर पिछले वर्षों में पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

27

विदेशी मामलों की भारतीय परिषद (आई सी डब्ल्यू ए)

विदेशी मामलों की भारतीय परिषद (आई सी डब्ल्यू ए) ने विश्व का भारत से और भारत का विश्व से संपर्क स्थापित कराने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। नई सरकार के आने के साथ, यह लक्ष्य और भी महत्वपूर्ण बन गया है तथा पूर्ण जोश के साथ पूरा किया जा रहा है। नीचे दर्शाए गए आईसीडब्ल्यूए,, के संदृश्य उसके कार्य को इंगित करते रहे हैः

(i) नीति और नीति विकल्पों पर सविज्ञ मत की संस्था के रूप में विकसित होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका अध्ययन और शोध में सहयोग प्रदान करना।

(ii) अन्य देशों के साथ आपसी लाभप्रद तरीके से शोध, सहयोग, संस्थागत संवाद तथा ज्ञान के आदान–प्रदान के माध्यम से भारत के संबंधों को बढ़ाना।

(iii) वैश्विक मामलों से संबंधित जानकारी और ज्ञान के समाशोधनगृह के रूप में कार्य करना।

अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते समय, आईसीड्बल्यू, अपने शासी निकाय और शासी परिषद द्वारा अनुमोदित 4 बिंदु की विदेश रणनीति का अनुकरण कर रहा हैः

(i) सार्क देश और म्यांमार,

(ii) दस प्राथमिक देश जैसे चीन, रूस, यूएस, इरान, आस्ट्रेलिय, इंडोनेशिया, जापान, तुर्क, जर्मनी, और ब्राजील,

(iii) पश्चिम एशिया, केंद्रीय एशिया, पूर्व एशिया, यूरोपियन संघ, अफ्रीका और लातिन अमरीका की ओर क्षेत्रीय पहुंच,

(iv) विषयक मामले (उदाहरणः ऊर्जा सुरक्षा) तथा उपयुक्त क्षेत्रीय समूह (उदाहरण ब्रिक्स और आईबीएसए)

अनुसंधान और प्रकाशन

इस संस्थान का प्रमुख भाग इसकी निदेशक (अनुसंधान), 16 अनुसंधान सहकर्मी (सभी पी एच डी धारक) और अनुसंधान प्रशिक्षणार्थी की एक छोटी परंतु प्रतिभावान अनुसंधान संकाय है। इस अनुसंधान संकाय का निरीक्षण उप महानिदेशक, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के कार्यरत अधिकारी तथा महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

अनुसंधान संकाय संस्थान के आउटरीच गतिविदियों में सहायता प्रदान करने के अलावा विभिन्न शिक्षण और अनुसंधान परियोजनाएं भी कराता है। अनुसंधान और प्रकाशन में इस अवधि के दौरान इनकी निम्नलिखित उपलब्धि हैः

(i) व्यू पाइंट –24(12 हिंदी अनुवाद सहित)

(ii) मामलों का संक्षिप्त –07(02 हिंदी अनुवाद सहित)

(iii) नीतियों का संक्षिप्त – 10(08 हिंदी अनवाद सहित)

(iv) सपः हाउस कागजात – 03

(v) किताबें और अन्य प्रकाशन– 07

अनुसंधान संकाय के सदस्यों ने राष्ट्रीय पत्रिका में 09 लेख तथा विदेशी पत्रिका में 9 लेख प्रकाशित किए। इस अवधि के दौरान संकाय के सदस्यों ने 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।

कोर समूह

अनुसंधान संकाय के अतिरिक्त ICWA के विद्वानों को प्रमुख समूह द्वितीय चैनल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके माध्यम से अनुसंधान और प्रकाशन गतिविधियां चलाई जाती हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान चीन और म्यांमार की कोर समूह ने अपनी बैठकें रखी, जिसमें अपने विशेषज्ञों के बीच अध्ययनशील आदान–प्रदान किया गया। इस प्रक्रिया में, उन्होंने अपने लक्ष्य देशों में उन्नतियों का निरंतर सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया तथा अपने आकलन को संबंधित प्राधिकारी के साथ बांटा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपने चयनित विषय पर पुस्तक प्रकाशन की प्रक्रिया में भी सहयोग दिया।

बाहरी विद्वानों द्वारा अनुसंधान परियोजना का पैकेज हमारी अनुसंधान और प्रकाशन गतिविधियों के तीसरे चैनल का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसंधान समिति बाहरी विद्वानों से प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। इसके अनुमोदन के बाद विद्वानों को अपनी परियोजना चलाने के लिए किताब और यात्रा अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में कुल 15 परियोजनाएं कार्यान्वत की जा रही हैं।

आउटरीच

संगोष्टी, व्याख्यान, सम्मेलन, गोलमेज आदि की श्रेणी का आयोजन एक प्रमुख गतिविधि रही है। यह विद्वानों, राजनयिकों, मीडिया प्रतिनिधियों और रणनीतिक संप्रदाय और सभ्य समाज के सदस्यों को इस आयोजन में आकर्षित करता है। कथित अवधि के दौरान, कुल 51 कार्यक्रम आयोजित किए गए। (सूची पैरा–20 में उल्लिखित) यह कार्यक्रम सामान्य तौर पर न केवल श्रोताओं के लिए बल्कि हमारी अनुसंधान संकाय के सदस्यों के लिए भी अनेक प्रकार से लाभप्रद होती है। विशेष महत्व के निम्नलिखित कार्यक्रम कथित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सफलतापूर्वक आयोजित किए गए:–

(i) 18 सितंबर, 2014 को चीन जन गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम जी जिंपिग का संबोधन।

(ii) "इंडिया इन दी इमर्जिंग ग्लोब ऑर्डरः पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स" पर आई सी डब्ल्यू ए, एस आई एस, जे एन यू संवाद 2014।

(iii) 27 जून, 2014 को भारतीय मूल के युवाओं के लिए 28वां भारत जानो कार्यक्रम।

(iv) सपः हाउस व्याख्यान श्रेणी के अंतर्गत मोजाम्बिक के विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा संबोधन।

(v) 03 नवंबर 2014 को "दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीका मुद्दाः अफ्रीका के विकास के बदलते आयाम" पर पैनल चर्चा में दक्षिण अफ्रीका 2012 के जन व्यवस्था मंत्री का व्याख्यान

(vi) 02 दिसंबर, 2014 को द ट्रिब्यून नेशनल सिक्योरिटी फोरम के सहयोग के साथ "राष्ट्रीय सुरक्षाः भारत के लिए आगे की मुख्य चुनौती" गोलमेज, जिसमें मुख्य भाषण रेलमंत्री और विशेष भाषण जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा दिया गया।

आईसीडब्ल्यूए में मुख्य प्रवक्ताओं और पेनल दल के रूप में वरिष्ठ विदेशी राजनयिकों की गोलमेज जैसे नए कार्यक्रम की शुरूआत की गई। 10 जून, 2015 को 15 अफ्रीकी राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भारत–अफ्रीका संबंधों पर एक अहम चर्चा में भाग लिया जिसमें कुछ सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी विशेषज्ञों भी उपस्थित थे। 24 जून 2014 को, आईसीडब्ल्यूए द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक पर हुई चर्चा ने विद्यानों के बीच एक रोचक पारस्परिक वार्ता का रूप ले लिया जिसमें पोलेंड के राजदूत एक महत्वपूर्ण बक्ता रहे। इसके बाद 27 जून, 2014 को "कैनेडा का विश्वालोकन –तथा भारत के साथ संबंध" पर एक गोलमेज बैठक हुई जिसमें कैनेडा के उच्चायुक्त प्रमुख वक्ता थे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का चुनाव पर भी एक गोलमेज आयोजित की गई। यह गोलमेज चर्चाएं हमारे आईसीडब्ल्यू, के समर्थकों और अन्य मित्रों तथा अनुसंधान संकाय के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई।

बाह्य संवाद

आईसीडब्ल्यूए अपने मिशन द्वारा ट्रेक–।। राजनय के संचालन को बड़ी गंभीरता से लेता है। वर्तमान में विदेशी देशों में प्रबुद्ध मंडल के साथ 37 समझौता ज्ञापन है तता भारत के विश्विद्यालयों के साथ 06 समझौता ज्ञापन है। जैसा कि हमारा आउटरीच कार्यों का टेबल बताता है, भारत और विदेश दोनों ही जगह बाह्य साझेदारों के साथ संवाद आयोजित किए गए। 07 देशों से हमारे यहां प्रतिनिधिमंडल आए और हमने हमारे विद्वानों के प्रतिनिधिमंडल को 09 देशों मे भेजा। हमारे प्रतिनिधिमंडलों की इन यात्राओं ने लक्ष्य देशों के स्टेक–होलडर्स से जोड़ने, हमारे परिप्रेक्ष्य को बताने, तथा अनेक नजरिए को समझने में सहयोग दिया है। रिपोर्ट नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों से बांटी जाती है।

विदेशी नीति पर राष्ट्रीय चर्चा

विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मामलों में अंग्रेजी की श्रेष्ठता भी इस अवधारण को दूर करने के लिए आईसीडब्ल्यूए स्रकिया रूप से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय चर्चा और विदेश नीति मामलों में स्थानीय भाषाएं और राष्ट्रभाषा इस्तेमाल की जा रही है। आईसीडब्ल्यूए अपने अनुसंधान विशेषज्ञों को लेखन और प्रकाशन हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हाल ही में प्रकाशित मामलों के संक्षिप्त, विचार तथा नीति संक्षिप्त का आईसीडब्ल्यूए ने हिंदी में अनुवाद कराया और वेबसाइट पर प्रकाशित किया। आईसीडब्ल्यूए की कार्यों में विदेशी नीति और वैश्विक मामलों पर युवा वर्ग की रूचि जागृत करना शामिल है। आईसीडब्ल्यूए भारत के अन्य हिस्सों में इन मामलों पर जागरुकता पैदा करने की भूमिका है। इस भूमिका को निभाने के लिए, आईसीडब्ल्यूए ने गया, लखनऊ और मुरादाबाद के केंद्रीय और राज्य विश्विविद्यालयों में निबंध–लेखन, आलेख–पठन, वाद–विवाद और पेनल चर्चा का आयोजन किया और इस अवधि के दौरान वाराणसी, रांची और कुरूक्षेत्र में भी समान आयोजन कराने की योजना है। आईसीडब्ल्यूए इन गतिविधियों और अनुसंधान कार्यक्रमों में हिंदी में अकादमिकों, पत्रकारों और शोधकर्ताओं को शामिल करने का प्रयास है। आईसीडब्ल्यूए ने भारत के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में विवरण हेतु उनके द्वारा प्रकाशित किताबों को हिंदी अनुवाद के लिए चयनित किया है। आसीडब्ल्यूए आयोजनों में युवा श्रोताओं की रुचि बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आईसीडब्ल्यूए हिंदी में छेटे निबंदों से किताबों की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय चर्चा और विदेश नीति मामलों के लेखन से बढ़त के साथ प्रक्रिया की शुरूआत है।

शासी परिषद (जीसी) शासी निकाय (जीबी) और समिति बैठकें

रिपोर्ट अवधि के दौरान, निम्नलिकित जीबी, जीसी और समिति बैठकें हुईः

(i) 17 अप्रैल, 2014 को कार्यक्रम समिति

(ii) 24 अप्रेल, 2014 को अनुसंधान समिति

(iii) 29 मई, 2014 को वित्त समिति

(iv) 19 अगस्त 2014 को शासी परिषद

(v) 19 अगस्त, 2014 को शासी निकाय

(vi) 21 नवंबर, 2014 को वित्त समिति

संवाद

आईसीडब्ल्यू इस दढ़ विश्वास के साथ मार्गदर्शित किया जाता है कि जितना भी संभव हो इसके अनुसंधान परिणाम सार्वजनिक डोमेन पर डाले जाएं और इसके आउटरीच गितविधियों का भी अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। अपने अनुसंधान परिणाम (किताबों के अलावा) को आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर प्रकाशित करके, नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्तियां जारी करके, और अपनी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर सुवीधाओं को सुचारू रूप से प्रकाशित करके इसको सुरक्षित रखा जाता है।

हाल ही में आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट को पूरी तरह से पुननिर्मित किया गया है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जा रही है। इस वेबसाइट को प्रत्येक माह आधा मिलियन से ज्यादा लोग देखते है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, आईसीडब्ल्यूए के दिल्ली संवाद वेबसाइट और विडियो गैलरी को क्रमशः 385954 और 282509 हिट्स प्राप्त हुए हैं। अंततः वर्तमान में हमारे फेसबुक को 23 देशों से 825 लाइक प्राप्त हैं और ट्विटर खाते में 1108 फालोअर्स हैं।

"आईसीडब्ल्यू गेस्ट कालम" हमारी वेबसाइट की एक नई विशेषता है। इसे 02 जून, 2014 को प्रारंभ किया गया जिसमें मिस्सरोली, निदेशक तता डॉ इवा ग्रॉस, यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज (EUISS) की वरिष्ठ विश्लेषक द्वारा "यूरोपियन संघ–भारत संबंधों के सामर्थ्य को बढ़ाना" पर ऑप–एड लेख नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं।

इंडिया क्वार्टर्ली

इंडिया क्वार्टर्ली विदेश मामलों पर आईसीडब्ल्यूए द्वारा प्रकाशित की जा रही प्रतिष्ठित पत्रिका है। इसका 69 वर्षों के अविछिन्न प्रकाशन का रिकार्ड रहा है। यह एसएजीई के सहयोग से प्रकाशित की जाती है जसने यह सूचित किया कि पत्रिका मार्केट में प्रचलित है जिसके फलस्वरूप, यह स्व–वहनीय प्रकाशन बन जाता है।

पुस्तकालयः

पस्तकालय इस संस्थान की प्रमुख संपत्ति है। वर्तमान में इसमें कुल 1,41,343 पुस्तके हैं, जिनमें कई दुर्लभ और बहुत पुरानी किताबें हैं। 01 अप्रैल 2014 से पुस्तकालय में लगभग 350 नई किताबें शामिल हुई हैं।

■■

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

28

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त विचार केंद्र है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रोद्योगिक संबंधी मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त है। संस्थान की अभिकल्पना विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर प्रभावी नीतिगत वार्ताओं और क्षमता निर्माण को संपोषित करने वाले मंच के रूप में की गई है। आर.आई.एस के अनुसंधान कार्यक्रम में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना तथा विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्तों में विकासशील देसों की सहायता करना मुख्यतः शामिल है। आरआईएस विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहलों की अंतर–सरकारी प्रक्रिया शामिल रहता है। अपने व्यपाक विशषज्ञा के समूह के माध्यम से, आरआईएस अंतर्राष्ट्रीय अर्थिक मामलों पर नीतिगत सामंजय को सुदृढ़ करता है और साझेदारी विकसित करता है।

अप्रैल 2014 से नवंबर, 2014 के दौरान आरआईएस द्वारा किए गए मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार है।

नीति संवाद, सम्मेलन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

सातवां दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के लोक राजनय प्रभाग के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 05–07 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में सातवां दक्षिण एशिया आर्थिक (एसएईएस) शिखर सम्मेलन आयोजित किया। एसएईएस के सह–आयोजनों मे नीति संवाद केंद्र (सीपीडी), बांग्लादेशय साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, इन्वायरमेंट एण्ड इकानॉमिक्स (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपालय साउथ एशिया नीति अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस), नेपालय संधारणीय विकास नीति संस्थान (एसडीपीआई) और श्रीलंका का निती अध्यय संस्थान (आईपीएस) शामिल है। भारतीय औद्योगिक संगठन (सीआईआई), द वर्ल्ड बैंक और यूएनईएससीएपी इस शिखर सम्मलेन में सहयोगी थे। भारत के उप–राष्ट्रपति श्री मुहम्मद हामिद अंसारी ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका विषय दक्षिण एशिया आर्थिक संघ की ओर ती। उद्घाटन सत्र में आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी मे स्वागत भाषण दिया; आरआईएस के अध्यक्ष, राजूदत श्याम सुंदर ने उद्घोषणा भाषण दिया; नीति संवाद केंद्र, ढाका के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रबिर डे ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। तीन दिन के इस शिखर सम्मेलन में प्रसिद्ध अककादमिकों और नीतिज्ञों द्वारा पैनल चर्चा और पस्तुतीकरण, पुस्तक विमोचन हुआ।

आईआईएस और एनएसएबी के अध्यक्ष राजूदत श्री श्याम सरन ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय एकीकरणः पूर्व, वर्तमान और भविष्य पर पूर्व अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें श्री मुहम्मद मुस्तफ मस्तूर, अफगानिस्तान के उप वित्तमंत्री श्री गौहर रिज्वी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय मामलों के सलाहकारय श्री लिनपो नमगे दूर्जी, भूटान के वित्तमंत्री, श्री राम शरण महत, नेपाल के वित्तमंत्री तथा श्री सारथ अमुनुगमा, श्रीलंका के आर्थिक सहयोग मंत्री ने भाग लिया। मीडिया संवाद के अलावा सातवें एसएईएस के कार्यसूची में दक्षिण आर्थिक संघ की गहन चर्चा, चुनौतिया और आगे के कार्य, दक्षिण एशिया संपर्क, मानक एवं विनिमय, वृहत आर्थिक प्रदर्शन, संभावना तथा नीति सहयोग, वित्तीय और आर्थिक सहयोग, व्यापार सुविधा जैसे सीमाशुल्क सहयोग, सेवा व्यापार, आपसी पहचान और व्यपार सुधार सहित दक्षिण एशिया निवेश ब्लॉक पर सहयोग और गैर–प्रशुल्क उपायों पर समांतर सत्र शामिल थे।

ब्रिस्बेन जी–20 शिखर सम्मेलन के समक्ष मुद्दों पर संगोष्ठी

आरआईएस ने 30 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में ब्रिस्बेन जी–20 सिखर सम्मलेन के समक्ष मुद्दों पर एक संगोष्ठी आयोजित की। डॉ. सुरेश प्रभु, जी–20 शेरपा ने बीज भाषण दिया। सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (ईआर और डीपीए), विदेश मंत्रालय ने इस संगो,ठी की अध्यक्षता की। प्रोफेसर मुकुंद दुबे, प्रधान सीएसडी ने वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली, ऊर्जा और विकार मामलों पर हुए प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र के पैनल में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानदेशक आरआईएस, प्रोफेसर एस.के. मोहन्ती, आरआईएस, प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, सहायक सदस्य, आरआईएस तथा डॉ. लीना श्रीवास्तव, उप–कुलपति टीईआरआई विश्वविद्यालय शामिल थे। डॉ. राम उपेन्द्र दास, प्रोफेसर

आरआईएस वैश्विक विकार के लिए वित्तीय कार्य तथा अवसंरचना वित्तीकरण पर हुए दूसरे सत्र के अध्यक्ष ते। इस सत्र के पैनल में प्रो. सचिन राय, निदेशक और मुख्य कार्यपालक, एनआईपीएफपी तथा डॉ आर कविता राय, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी शामिल थे। इस सत्र के बाद एक खुली चर्चा हुई।

आसियान–भारत विचारों पर तीसरी गोलमेज (एआईएनटीटी)

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय, आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र, आसियान सचिवालय, वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी और वियतनाम भारतीय और दक्षिण पश्चिम एसियाई अध्ययन संस्थान (वीआईआईएएस) के साथ संयुक्त रूप से 25–26 अगस्त, 2014 को आसियान–भारत हनोई, वियतनाम में एकीकरण और विकास विषय पर आसियान–भारत विचारों पर तृतीय गोलमेज (एआईएनटीटी) का आयोजन किया। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री महामहिम श्री फाम बिन्ह मिन्ह ने मुख्य भाषण दिया। भारत के विदेश मंत्री श्री शुषमा स्वराज ने उद्गोषणा भाषण दिया। आरआईएस के उपाध्यक्ष श्री वीएस सेसादरी और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव (पूर्व) श्री अनिव वाधवा ने भी विशेष भाषण दिया।

आसियान–भारत प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यान

आसियान–भारत प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यान श्रेणी भाग के रूप में, दो व्याख्यान आयोजित किए गए। पहला व्याख्यान आरआईएस द्वारा विदेश मंत्रालय, आरआईएस के आशियान–भारत केंद्र और आशियान सचिवालय के साथ संयुक्त रूप से 12 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी (वीएएसएस) के प्रधान प्रो. डॉ गुयेन ज्वान यांग ने व्याख्यान दिया। एआईसी और आरआइएस के अध्यक्ष श्री श्याम शरण ने स्वागत उल्लेख दिया। दूसरा व्याख्यान आरआईएस द्वारा सीआईआई, आईसीसीआर और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान के साथ संयुक्त रूप से 13 अगस्त, 2014 को कोलकाता में आयोजित किया गया। भारत के पूर्व विदेश सचिव श्री कृष्णन श्रीनिवासन ने उद्घोषणा भाषण दिया तथा आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र के संयोजक प्रो. प्रबीर डे ने स्वागत भाषण दिया। सीआईआई, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के पूर्व अध्यक्ष श्री आलोक मुखर्जी ने भी संबोधन दिया।

भारत और म्यांमार के बीच संपर्क गलियारों को विकास गलियारों में परिवर्तित करना

श्री वी.एस. शेशाद्री, उपाध्यक्ष, आरआईएस द्वारा भारत और म्यांमार के बीच संपर्क गलियारों को विकास गलियारों में परिवर्तन पर आरआईएस रिपोर्ट 14 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में प्रारंभ की गई। सुजाता मेहता, सचिव (ईआर एण्ड डीपीए) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने रिपोर्ट को जारी किया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। प्रो. राम उपेन्द्र दास, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

सीमापार संपर्क पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से 12 मई, 2014 को नई दिल्ली में सीमापार संपर्क पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने की, श्री अनिल वाधवा, सचिव(पूर्व), विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे वर्ल्ड बैंक से प्रतिष्ठित नीतज्ञों, अकादमिकों और प्रतिनिधित्वों ने इस विचार–विमर्श में हिस्सा लिया। सम्मेलन में महत्वपूर्ण वक्त भी थे जैसे 8 हेनरी स्टिंगस, यूएस व्यापार और विकार संस्था (वाशिंग्टन डीसी) के दक्षिण और दक्षिण पूर्वीय एशिया के क्षेत्रीय निदेशक, सुश्री फातिमा सुमर, राज्य उप–सहायक सचिव, दक्षिण और केंद्रीय एशियाई मामलों का ब्योरा, यूएस राज्य विभाग, वाशिंग्टन डीसी, श्री कत्सुओ मत्सुमोतो, उप महानिदेशक और भारत व भूटान के निदेशक, दक्षिण एशिया विभाग, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान (जेआईसीए), टोकियो तथा अन्य।

आशियान–भारत पारगमन परिवहन करार पर गोलमेज

आरआईएस के आशियान–भारत और विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने 16 अप्रैल 2014 को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में आशियान–भारत पारगमन परिवहन करार (एआईटीटीए) पर एक गोलमेज आयोजित की। राजदूत श्री वी.एस. शेशाद्री, उपध्यक्षा, आरआईएस ने उद्घोषणा भाषण दिया, तथा श्री अनिव वाधवा, सचिव(पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। प्रो. प्रबीर डे, संयोजक आरआईएस का आशियान–भारत केंद्र ने प्रमुक प्रस्तुतीकरण दिया। विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्वीय परिषद, नागर विमानन मंत्रालय, नौपरिवहन मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, योजना आयोग से वरिष्ठ नीतिज्ञों ने परामर्शी में भाग लिया। आसाम, केरला, महाराष्ट्रा, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधियों ने भी गोलमेज में भाग लिया।

भारत में पुनरुत्पादक दवाइयों और मरीजों की मांगों के संचालन पर गोलमेज

आरआईएस, सस्सेक्स विश्वविद्यालय, पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग ने संयुक्त रूप से भारत में पुनरुत्पादक दवाइयों और मरीजों की मांगों के संचालन पर 02 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली में गोलमेज का आयोजन किया। प्रो. श्रीमती चक्रवर्ती, पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली अध्यक्ष रहीं और प्रो. सचिव चतुर्वेदी, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. प्रसन्ना के. पात्रा, सस्सेक्स विश्वविद्यालय, यूके ने सत्र के विषय को प्रस्तुत किया। डॉ. वासन्था मुथुस्वामी, पूर्व वरिष्ठ उप–महानिदेशक, आईसीएआर, डॉ. नंदिनी गोकुलचंद्रन, उप निदेशक, न्यूरोजेन, मुंबई, प्रो. पीबी सेशागिरि, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर और अन्य इस चर्चा में शामिल हुए। डॉ. रवि श्रीनिवास, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

भारत–चीन आर्थिक संबंधों पर विचारमंथन सत्र

आरआईएस ने 27 सिंतबर, 2014 को श्भारतचीन आर्थिक संबंधों पर एक विचारमंथन सत्र आयोजित किया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की। इसमें श्भारतचीन द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर आरआईएस के अध्ययन पर चर्चा हुई। पैनल में प्रो. एस.के. मोहन्ती, आरआईएस, प्रो. सुनंदा सेन, जेएनयू, और प्रो. मनमोहन अग्रवाल, आरआईएस शामिल थे।

एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश और कार्यप्रणाली के विकास पर परामर्शादात्री बैठक

आरआईएस और पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश और कार्यप्रणाली के विकास 15 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली में परामर्शदात्री बैठक आयोजित की। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, आरआईएस ने संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। डॉ. पीजी चेगप्पा, आईसीएआर, आईएसईए, बंगलोर के राष्ट्रीय प्रो. संजय कुमार श्रीवास्तव, महानिदेशक, एसएसएआई, प्रो. प्रणव एन देसाई, सीएसएसपी, जेएनयू, डॉ. निधि चान्ना, टीईआरआई, श्री अनिकेत आगा, येले विश्वविद्यालय, डॉ. के रवि श्रीनिवास, और अन्य ने चर्चा में भाग लिया।

मौसम परिवर्तन और नए समाज के लिए परिसर पर संगोष्ठी

आरआईएस ने मौसम परिवर्तन और नए समाज के लिए परिसर पर दिनांक 15 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रो. अजीत सिंह, क्रैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित प्रो. मुख्य प्रवक्ता थे। सुश्री लीडिया पोवेल, प्रमुख, अनुसंधान प्रबंधन केंद्र, डॉक्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, चर्चा में शामिल हुईं। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया और प्रो. एस के मोहन्ती, आरआईएस ने अध्यक्षता की

जी पार्थसारथी और आरआईएस पर विशेष व्याख्यान

आरआईएस ने जीपार्थासारथी और आरआईएसष पर उनके जन्म शताब्दी वर्ष में 16 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। प्रो. वी आर पंचमुखी, पूर्व महानिदेशक, आर आर एस और पूर्व अध्यक्ष आईसीएसएसआर ने यादगार भाषण दिया। राजदूत श्याम शरण अध्यक्ष, आरआईएस ने विशेष भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, प्रो. अशोक पार्थासारथी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पूर्व एस व टी सलाहकार तथा विभिन्न प्रमुख एस एण्ड डी विभागों के सचिव, प्रो. राम उपेन्द्र दास, आरआईएस ने भी श्रोताओं को संबोधित किया।

भारत–आसियान संपर्क पर गोलमेज

आर आई एस में भारत–आसियान केंद्र ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा उत्तर–पूर्वीय परिषद ने संयुक्त रूप से ''भारत–आसियान संपर्कः उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर 29–30 सितंबर, 2014 को शिलॉग में दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। प्रो. प्रबीर डे, संयोजक, त्पै में भारत–आसियान केंद्र ने स्वागत भाषण दिया। श्री अनिल वाधवा, सचिव(पूर्व), विदेश मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया। श्री रिजलि विल्मर इंद्राकेशुमा, भारत में इंडोनेशियन राजदूत ने विशेष भाषण दिया। उत्तर–पूर्व के मिशनों, राजनयकों, वरिष्ठ अधिकारी आशियान प्रमुखों, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विद्वानों ने सम्मेलन में भाग लिया।

आशियान की अगुवाई में एकीकरण प्रक्रिया, आर सी ई पी, टी पी पी तथा एफ टी ए ए पी की संभावना पर पैनल चर्चा

आर आ एस ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में 'आशियान– एकीकरण प्रक्रिया, आर सी ई पी, टी पी पी तथा एफ टी ए ए पी की संभावना' पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। श्री वी. एस. शेशाद्री, उपाध्यक्ष, आर आई एस ने चर्चा की अध्यक्षता की। डॉ. संचिता बासु दास, संयोजक, ए पी ई सी अध्ययन केंद्र, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान(आई एस ई ए एस), सिंगापुर और प्रो.

राय उपेन्द्र दास, आई आई एस पैनल के सदस्य थे। श्री टी सी जेम्स, परामर्शदाता, आर आई एस चर्चा में शामिल थे।

एफ आई डी सी संगोष्ठी श्रृंखला

एफ आई एस में पूर्व की भांति भारतीय विकास सहयोग नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और सुविज्ञ वाद–विवाद के लिए भारत विकास सहयोग चर्चा मंच(एफ आई डी सी) प्रारंभ किया। एफ आई डी सी के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मासिक संगोष्ठी श्रृंखला का प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत 17 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग पूर्व से चिंतन' पर संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आर आई एस ने स्वागत भाषण दिया। श्री डॉमनिक बार्टस्च, मिशन के प्रमुख, शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, नई दिल्ली ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। डॉ. बी आर पंचमुखी, पूर्व महानिदेशक, आर आई एस ने व्याख्यान दिया। डॉ. मिलिन्दो चक्रोबर्ती, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय अकादमी सरलीकरण तथा प्रोफेसर विधि विद्यालय और व्यावसायिक अध्ययन विद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, चर्चा में शामिल हुए। श्री प्रत्युश, आर आई एस के अनुसंधान सहायक ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। 03 सितंबर, 2014 के नई दिल्ली में 'नए विकास बैंक और दक्षिण–दक्षिण सहयोग' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। राजदूत श्याम शरण, अध्यक्षता आर आई एस ने अध्यक्षता की। प्रतिष्ठित पैनलकर्ता में डॉ. रथिन रॉय, निदेशक ए आ फी एफ सी; श्री चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव(विदेश मंत्रालय); सुश्री पूजा पार्वति, ऑक्सफेम इंडिया शामिल थे। श्री अमिताभ बेहार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय संस्थान ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। एफ आई डी सी संगोष्ठी श्रेणी के अंतर्गत '2015 उपरांत विकार मुद्देः भारतीय परिप्रेक्ष्य' पर ''अप्रेल 2014 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रो. बिस्वजीत धर, महा निदेशक, आई आई एस ने अध्यक्षता की। पैनल प्रमुखों में श्री तनमय लाल, संयुक्त सचिव(यू एन ई एस), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री तुहिन कुमार, संयुक्त सचिव (डी पी ए–II) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार शामिल थे।

आर आई एस ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रृंखला

आर आई एस ने एक ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रेणी की शुरूआत की। इस श्रेणी के हिस्से के रूप में, अब तक निम्नलिखित संगोष्ठियां आयोजित की गईः (क) ''आई बी एस ए में सामाजिक क्षेत्रों का स्तरः एक दशक का मूल्यांकन'' 09 अक्तूबर, 2014 को डॉ. बीना पांडे, अनुसंधान सहयोगी, आई आई एस द्वारा। डॉ. एश नारायण राय, निदेशक, सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सत्र की अध्यक्षता की तथा श्री विजय नरेश मेहता, सलाहकार(एम ई) विदेश मंत्रालय चर्चा में शामिल थे। (ख) ''एशिया में रिजर्व प्रबंधनः बदलती रूपरेखा तथा चुनौतियां'' डॉ. प्रियदर्शी दास, अनुसंधान सहयोगी, आर आई एस द्वारा 11 नवंबर, 2014 को। प्रो. बी बी भट्टाचार्य, आर आई एस के शासी निकाय तथा शासी परिषद के सदस्य तथा डॉ. सष्यसांची साहा, सहायक प्रोफेसर, आर आई एस चर्चा में शामिल थे। (ग) 'औद्योगिक इंटरफेस तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरणः एक भारतीय संदर्भ' डॉ. अश्विन गुप्ता, सलाहकार/वैज्ञानिक जी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अध्यक्षता की तथा डॉ. नित्या नंदा, सहयोगी, टी ई आर आई चर्चा में शामिल थे।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

''दक्षिण–दक्षिण सहयोग ज्ञान (एल एस सी) साझेदारी विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

आर आई एस ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आई टी ई सी/एस सी ए ए पी कार्यक्रम के अंतर्गत 17–28 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में साझेदारी विकास पर दो सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

म्यांमार में व्यापार और निवेश क्षमता को बढ़ाना

आर आई एस और सी ई ई एस, म्यांमार ने संयुक्त रूप से ड्रेड शिफ्ट, यू एन ई एस सी ए पी, आर्टनेट, आर आई एस में आशियान–भारत केंद्र, यू एम एफ सी सी आई, कोलकाता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और सस्सेक्स विश्वविद्यालय के सहयोग से 26–30 मई, 2014 को यू एम एफ सी सी आई बिल्डिंग, यंगून में व्यापार नीति और विश्लेषण पर एक सप्ताह का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम; तथा 16–20 सितंबर, 2014 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में पांच दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया।

विचारकों के नेटवर्क की स्थापना

आर आई एस निम्नलिखित विचारकों के नेटवर्क की स्थापना में भी अग्रसर रहा जैसे, आशियान–भारत के विचारकों के नेटवर्क की स्थापना(ए आई एन टी टी); सार्क आर्थिक शिखर सम्मेलनों के सार्क नेटवर्क; दक्षिणी विचारकों का नेटवर्क(एन इ एस टी) तथा एशियाई जैव प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तन विकास पहल(ए बी आई डी आई)।

आर आई एस प्रकाशन

आर आई एस प्रकाशनों की सूची परिशिष्ट ग्प् में दी गई है।

बजट

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2014–15 के लिए आर आई एस को 5.35 करोड़ के बजट सहयोग की स्वीकृति प्रदान की।

पुस्तकालय

29

विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय मुख्यालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केंद्रों में कार्यरत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए पुस्तकालय के साथ–साथ संसाधन और सूचना केंद्र के रूप में सामान्य तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पुस्तकालय में एक सौ हजार पुस्तकें, मूल्यवान संसाधन सामग्री और मानचित्र, माइक्रो फिल्मों एवं सरकारी दस्तावेजों का संग्रह मौजूद है। यह विदेश मंत्रालय में नीति आयोजना तथा अनुसंधान को समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय लगभग 300 पत्रिकाएं/दैनिक तथा समाचार पत्र शीर्षक (ऑन–लाइन जर्नल्स और डेटाबेस सहित) मंगवाता/प्राप्त करता है और उसका रखरखाव करता है।

पुस्तकालय समिति पुस्तकालय के क्रियाकलापों का प्रबंधन करती है जिसमें पुस्तकों की खरीद और दैनिकी/पत्रिकाएं और डेटाबेस मंगवाना शामिल है। विदेश सचिव पुस्तकालय समिति का गठन/पुनर्गठन करते हैं। वर्तमान पुस्तकालय समिति में संयुक्त सचिव(सीटी, जी सी आई और पी पी एण्ड आर) बहैसियत अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं। टेरिटोरियल प्रभाग के तीन निदेशक/उप सचिव इसके सदस्य तथा निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) सदस्य–सचिव हैं। अनुमोदन के आधार पर वेंडरों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों की पुस्तकालय समिति की बैठकों में प्रस्तुत करने से पहले पुस्तकालय के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। इस पुस्तकालय की पुस्तकों का चयन करने के लिए प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय समिति की 2 बैठकें आयोजित की जाती हैं। रोज की जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता आधार पर अनुरोधित/अनुशंसित पुस्तकें खरीदी जाती हैं। अंतर–पुस्तकालय के माध्यम से भी पुस्तकें खरीदी जाती हैं।

पुस्तकालय में मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारीयों के लिए व्यवस्था है परंतु, हम नियमित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय (पी एम ओ), उप राष्ट्रपति कार्यालय, वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद (आई सी डब्लूय ए), एन एस सी एस, राष्ट्रीय विकास परिषद(एन डी सी) और विभिन्न अन्य कार्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं इससे जुड़े विषयों पर मूल्यवान एवं विशिष्ट संग्रह के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शोधकर्ताओं को भी पुस्तकालय की सेवाएं प्रदान करते हैं।

एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर "लिबसिस" का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रलेखन/ग्रंथ–संदर्भी सेवाएं तथा अन्य पुस्तकालय प्रचालन एवं सेवाएं कंप्यूटरीकृत कर दी गई हैं। ऑन लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओ पी ए सी) के माध्यम से सभी पुस्तकों एवं प्रलेखों तथा पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं/दैनिकियों से प्राप्त चुनिंदा लेखों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। हमने हाल ही में पटियाला हाउस और जवाहल लाल नेहरू भवन के पुस्तकालय में उपयोग हेतु "वेब सेंट्रिक लिबसिस" से जोड़ते हुए पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर को उन्नत बनाया है। विदेश मंत्रालय की वेबसाईटः http://mealib.nic.in पर इंटरनेट के माध्यम से भी पुस्तकालय संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विदेश मामलों संबंधी डाटाबेस में पुस्तकालय में प्राप्त सभी नए प्रलेखों जैसे पुस्तकों, मानचित्रों, माइक्रोफिल्मों, पत्रिकाओं तथा दैनिकियों से प्राप्त चुनिंदा लेखों को नियमित आधार पर फीड किया जा रहा है। पुस्तकालय अपने उपभोक्ताओं को ऑन लाईन/वेब आधारित सेवाएं, ऑन लाइन जर्नल्स/पेरियोडिकल्स तथा डेटाबेस सेवाएं, ई–मेल सेवाएं, बुक एलर्ट एण्ड आर्टिकल एलर्ट सेवाएं तथा साथ ही सभी प्रकार की सर्वाधिक आधुनिक कंप्यूटरीकृत सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन ऑन लाइन डेटाबेसों और दैनिकियों/पत्रिकाओं के बारे में यूजरनेट और पासवर्ड के जरिए इंटरनेट पर जानकारी हासिल की जा सकती है। ऐसे शीर्षकों की सूची मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों और केंद्रों में भी चालित की जाती है और यह विदेश मंत्रालय की वेबसाइटः http://mealib.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अपने उपभोक्ताओं को डाकुमेंटेशन, बिबिलियोग्राफिक, करेंट अवेयरनेस/एसडीआई और संदर्भ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पुस्तकालय नियमित आधार पर विभिन्न बुलेटिनें जैसे रीसेंट एडिशन्स, फॉरेन अफेयर्स डकुमेंटेशन बुलेटिन एवं क्रोनिकल ऑफ इवेन्ट जारी करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय ने विभिन्न ऑनलाइन डेटाबेसेस/ आनलाइन सेवाओं जैसे ईआईयू ऑनलाइन सर्विसेस (एनर्जी ब्रीफिंग एवं फोरकास्ट सहित), बिजनेस मानीटर इंटरनेशनल, मार्केट लाइन एडवांटेज, न्यूजपेपर डाइरेक्ट, जेएसटीओआर आर्काइवल कंपलीट, प्रोक्वेस्ट एबीआई इंफोर्मा कंपलीट, जेन ऑनलाइन सर्विसेस, केसिंग्स वर्ल्ड न्यूज आर्काइव्स, आदि के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है।

पुस्तकालय ने एनआईसी के सहयोग से विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1948 से 1998–99) तथा फोरेन अफेयर्स रिकार्ड (1955 से 1999) का फुल टेक्स्ट सीडी–आरओएम निकाला है।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह है। पूर्व विदेश सचिव के निर्देश के अनुसार कुछ चुनिंदा दुर्लभ पुस्तकों की सूची पहले ही तैयार और मुद्रित करा ली गई है। इन पुस्तकों को जेएनबी स्थित एक पृथक दुर्लभ पुस्तक लाइब्रेरी में रखा गया है।

हमने हाल ही में 1947 से 2014 तक 'भारत की द्विपक्षीय संधियों एवं करारों तथा साथ ही संयुक्त घोषणापत्रों और विज्ञप्तियों' को प्रकाशित/पुनः मुद्रित करने के लिए एक परियोजना पूरी की है और इस प्रकाशन को शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

पुस्तकालय दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों को समय–समय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (आईएलए), इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फार्मेशन सेंटर (आईएएसएलआईसी), इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन्स एण्ड इंस्टीट्यूशन्स (आईएफएलए) और स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन (एसएलए) तथा अन्य अधिकारियों ने समय–समय पर आई एल ए, आई ए एस एल आई सी, आई एफ एल ए, एस एल ए, आदि के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया।

■■

वित्त एवं बजट

30

वर्ष 2014–15 के लिए विदेश मंत्रालय के लिए कुल बजट परिव्यय (बजट अनुमान स्तर पर) 14730.39 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2013–14 के लिए आबंटित बजट (11719 करोड़ रुपये) से 25.70 प्रतिशत अधिक था। इस बजट का बड़ा भाग योजना और गैर–योजना निधि दोनों के माध्यम से अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए है।

योजना

विदेश मंत्रालय के बजट का योजना घटक अवसंरचना, जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट्स, कृषि, उद्योग आदि के क्षेत्रों में कई बड़ी विकास परियोजानाओं की जरूरतों को पूरा करता है जिन्हें भारत के पड़ोसी देसों जैसे भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार में चलाई जाती है।

भूटान योजना बजट शीर्ष से हमारा एक प्रधान लाभग्राही है। कई महत्वपूर्ण जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट्स जैसे पुनातसांग्धू जल विद्युत परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

अफगानिस्तान भी योजना घटक से निधि का दूसरा महत्वपूर्ण गंतव्यस्थान है। अफगानिस्तान में काबुल से पुले–ए–खुमारी तक डबल सर्किट पारेषण लाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना के अतिरिक्त घटक के रूप में दोशी और चारीकर में दो उप–केंद्रों का अब निर्माण किया जा रहा है।

म्यांमार में कालादन मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना पर भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

गैर–योजना

वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के प्रधान लाभग्राही भूटान (₹1350 करोड़), बांग्लादेश (₹ 350 करोड़), अफगानिस्तान (550 करोड़ रू.) श्रीलंका (500 करोड़ रु.), नेपाल (450 करोड़ रु.) म्यांमार (180 करोड़ रू.) तथा अफ्रीकी देश (300 करोड़ रु.) थे। कुछ अन्य लाभग्राहियों में मालदीव, मंगोलिया, लातिन अमेरीकी, यूरेशिया और अन्य क्षेत्रों के देश शामिल है।

मंत्रालय को 31 अक्टूबर 2014 तक पासपोर्ट जारी करने, वीजा शुल्क और अन्य प्राप्तियों से ₹2391.06 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रहीः

लघु शीर्ष	**राजस्व प्राप्ति (करोड़ में)**
पासपोर्ट	1182.90
वीजा शुल्क	975.86
अन्य प्राप्तियां	232.30
सरकारी होस्टलों, गेस्ट हाउसों आदि से प्राप्तियां	–
आरटीआई	–
कुल	**2391.06**

वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान के अनुसार बजट आवंटन का क्षेत्रवार विश्लेषण दर्शाता है कि कुल 14730.39 करोड़ रुपये के आबंटन में से बजट का 64.05 प्रतिशत (9434.82 करोड़ रु.) तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (6268.81 करोड़ रु.) के अंतर्गत परियोजनाओं पर और विदेशी सरकारों को ऋण एवं अग्रिम (3166.01 करोड़ रु.) के रूप में आबंटित किया गया था। मिशनों और केंद्रों को बजट का 12.44 प्रतिशत (1832.31 करोड़ रु.) आबंटित किया गया था। शेष आबंटन विशेष राजनयिक व्यय (10.83 प्रतिशत), पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन (3.69 प्रतिशत), अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों को अनुदान (4.18 प्रतिशत), पूंजीगत परिव्यय (2.03 प्रतिशत), विदेश मंत्रालय सचिवालय (1.92 प्रतिशत) तथा अन्यों (0.86 प्रतिशत) पर किया गया।

■■

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

01 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान अन्य देशों के साथ भारत द्वारा संपन्न अथवा नवीकृत संधियां/अभिसमय/करार

क. बहुपक्षीय

क्रम सं०	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति/स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
1.	ब्रिक्स नव विकास बैंक पर करार	15 जुलाई, 2014		
2.	अन्तर–अमरीकी विदेशों में सजायाफ्ता अपराधियों को सौंपने पर अन्तर–अमरीकी अभिसमय	9 जून, 1993	14 मार्च, 2014	–
3.	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नागरिक परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा के अनुप्रयोग हेतु भारत सरकार और अंतर्राष्टीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच करार के अतिरिक्त प्रोतोकाल	15 मई, 2009	25 जुलाई, 2014	25 जुलाई, 2014
4.	काला–जार दक्षिण–पूर्व क्षेत्र से काला–आजार की समाप्ति पर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाइलैंड के बीच समझौता	09 सितंबर, 2014	–	09 सितंबर, 2014
5.	कस अंधे, आँखों से कमजोर अथवा न पढ़ सकने वाले व्यक्तियों के लिए प्रकाशित सामग्री तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के वास्ते मर्राकेश संधि	27 जून, 2013	23 मई, 2014	–
6.	नागोया प्रोतेकाल जैव–सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोतोकाल की जिम्मेदारी और सुधार संबंधी नागोया– कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोतोकाल	11 अक्तूबर, 2011	28 नवंबर, 2014	–
7.	नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर भारत गणराज्य और कोरिया समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	16 जनवरी, 2014	–	16 जनवरी, 2014
8.	नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर भारत गणराज्य और बांग्लादेश लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	20 सितंबर, 2014	–	20 सितंबर, 2014
9.	नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर भारत गणराज्य और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	28 अक्तूबर, 2014	–	28 अक्तूबर, 2014
10.	नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर भारत गणराज्य और बांग्लादेश लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	07 नवंबर, 2014	–	07 नवंबर, 2014
11.	चाय उत्पादक मंच अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच का गठन	21 जनवरी, 2013		25 मार्च, 2014

परिशिष्ट–I

ख. त्रिपक्षीय

क्रम सं०	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति/स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
1.	शून्य	–	–	–

ग. द्विपक्षीय

क्रम सं०	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति/स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
1.	आस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर आस्ट्रेलिया सरकार और भारत सरकार के बीच करार	5 सितंबर, 2014	–	–
2.	आस्ट्रेलिया भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेलकूद के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	5 सितंबर, 2014		
3.	आस्ट्रेलिया भारत और आस्ट्रेलिया के बीच जलसंसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	5 सितंबर, 2014		
4.	आस्ट्रेलिया भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) पर सहयोग	5 सितंबर, 2014		
5.	आस्ट्रेलिया भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सामाजिक सुरक्षा पर करार	18 नवंबर, 2014		
6.	आस्ट्रेलिया भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित करार	18 नवंबर, 2014		
7.	आस्ट्रेलिया भारत और आस्ट्रेलिया के बीच स्वापक पदार्थों की अवैध तस्करी और पुलिस सहयोग पर समझौता ज्ञापन	18 नवंबर, 2014		
8.	आस्ट्रेलिया भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कला और संस्कृति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	18 नवंबर, 2014		
9.	आस्ट्रेलिया भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	18 नवंबर, 2014		
10.	अजरबैजान भारत गणराज्य और अगरबेजान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	04 अप्रैल, 2013	18 अप्रैल 2013	20 जून, 2014

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
11.	अजरबैजान भारत गणराज्य और अगरबेजान गणराज्य के बीच अपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर संधि	44 अप्रैल, 2013	03 मई, 2013	20 जून, 2014
12.	अजरबैजान भारत गणराज्य और अगरबेजान गणराज्य के बीच नागरिक और वाण्ज्यिक मामलों में विधिक और न्यायिक सहयोग पर संधि	04 अप्रैल, 2013	12 अगस्त, 2014	
13.	बहरीन विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय और बहरीन राजनयिक संस्थान, विदेश मंत्रालय, बहरीन अधिराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	19 फरवरी, 2014		19 फरवरी, 2014
14.	भूटान सीएजी और आडिटर जनरल ऑफ भूटान के बीच समझौता ज्ञापन			2014 में नवीकृत
15.	ब्राजील आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन से परिहार हेतु भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय में संशोधन करने वाला प्रोतोकाल	15 अक्तूबर, 2013	23 जनवरी, 2014	
16.	ब्राजील सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच करार	15 अक्तूबर, 2013	01 जनवरी, 2014	
17.	ब्राजील भारतीय दूर संवेदी (आईआरएस) उपग्रहों से डाटा प्राप्त करने और उसे प्रक्रियाबद्ध करने के लिए ब्राजील के अर्थ स्टेशन का संवर्धन करने में सहयोग स्थापित करने संबंधी समझौते को लागू करना	16 जुलाई, 2014		
18.	ब्राजील कोंसली और गतिशीलता मामलों पर परामर्शी तंत्र की स्थापना पर ब्राजील संघीय गणराज्य के विदेश संबंध मंत्रालय और भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	16 जुलाई, 2014		
19.	ब्राजील पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	16 जुलाई, 2014		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
20.	बेल्जियम किंबर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट आधारित आंकड़ों के आदान–प्रदान हेतु प्रायोगिक परियोजना पर भारत गणराज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और बेल्जियम के फेडरल पब्लिक सर्विस इकोनोमी के बीच समझौता ज्ञापन	25 नवंबर, 2013		25 नवंबर, 2013
21.	कनाडा भारत गणराज्य की सरकार और कनाडा सरकार के बीच दृश्य–श्रृव्य सहयोग करार	24 फरवरी, 2014	25 मार्च, 2014	
22.	चीन सांस्कृतिक संस्थानों के बीच आदान–प्रदान और सहयोग को सुदृढ़ करने पर भारत के गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और चीनी जनवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	18 सितंबर, 2014		
23.	चीन भारत गणराज्य की सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और चीनी जनवादी गणराज्य की सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के बीच पंचवर्षीय व्यापार एवं आर्थिक विकास योजना	18 सितंबर, 2014		
24.	चीन भारत–चीन संयुक्त आर्थिक समूह के दसवें सत्र का सहमत कार्यवृत्त	18 सितंबर, 2014		
25.	चीन रेलवे क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने पर भारत गणराज्य की सरकार के रेल मंत्रालय और चीनी जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	18 सितंबर, 2014		
26.	चीन चीन के जनवादी गणराज्य के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारतीय तीर्थ यात्रियों (कैलाश मानसरोवर यात्रा) के लिए नया मार्ग खोलने के संबंध में भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और चीनी जनवादी गणराज्य के विदेश मामले मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	18 सितंबर, 2014		
27.	चीन भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याम मंत्रालय और चीनी जनवादी गणराज्य के चीनी खाद्य एवं मादक पदार्थ प्रशासन के बीच मादक पदार्थ प्रशासन और सहयोग पर कार्य योजना	18 सितंबर, 2014		
28.	चीन भारत गणराज्य के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा चीनी जनवादी गणराज्य के प्रेस, पब्लिकेशन, रेडियो, फिल्म एवं दूरदर्शन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच दृश्य–श्रव्य सह–प्रस्तुति पर करार	18 सितंबर, 2014		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
29.	चीन सीमा शुल्क मामलों मे परस्पर प्रशासनिक सहायता और सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और चीनी जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार	18 सितंबर, 2014	28 नवंबर, 2014	
30.	क्रोएशिया आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार को एशिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	12 फरवरी, 2014	12 अगस्त, 2014	
31.	चेक गणराज्य भारत गणराज्य और चेक गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा पर करार	08 जून, 2010	22 जुलाई, 2014	01 सितंबर, 2014
32.	चेक गणराज्य रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और चेक गणराज्य के चेक रेलवे (सेस्केद्राही) और एसोसिएशन ऑफ चेक रेलवे इंडस्ट्री (एसीआरवाई) के बीच समझौता ज्ञापन	08 जून, 2010	22 जुलाई, 2014	01 सितंबर, 2014
33.	फीजी आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान एवं वित्तीय अपवंचन के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फीजी गणराज्य सरकार के बीच करार	13 जनवरी, 2014	26 फरवरी, 2014	
34.	फीजी भारत और फीजी के बीच राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना और विषय वस्तु संबंधी सूचना के आदान–प्रदान पर भारत के विदेश सेवा संस्थान और फीजी के विदेश मामले मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	19 नवंबर, 2014		
35.	फीजी भारत और फीजी के बीच संबंधित राजधानियों में राजनयिक मिशनों के लिए भूमि–निर्धारण के संबंध में समझौता ज्ञापन	19 नवंबर, 2014		
36.	फीजी फीजी में सह–उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु ऋण श्रृंखला प्रदान करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फीजी गणराज्य की सरकार की बीच समझौता ज्ञापन	19 नवंबर, 2014		19 नवंबर, 2014
37.	फिनलैंड भारत के परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड और फिनलैंड के विकिरण एवं परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण के बीच सहयोग हेतु करार	16 अक्तूबर, 2014		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
38.	फिनलैंड भारत गणराज्य और फिनलैंड गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा पर करार	12 जून, 2012	25 जून, 2012	01 अगस्त, 2014
39.	फिनलैंड भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और फिनलैंड गणराज्य की सरकार के रोजगार एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन	16 अक्तूबर, 2014		
40.	फिनलैंड भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल, इंडिया (एचएसईआर भोपाल) और तुर्कु विश्वविद्यालय, फिनलैंड के बीच वैज्ञानिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर करार	16 अक्तूबर, 2014		
41.	इजराइल भारत गणराज्य की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल के बीच वर्गीकृत सामग्री की सुरक्षा एवं सूचना पर करार	27 फरवरी, 2014		27 फरवरी, 2014
42.	इजराइल अपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल के बीच करार	27 फरवरी, 2014	25 अप्रैल, 2014	
43.	इजराइल होमलैंड और लोक सुरक्षा मुद्दों में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल के बीच करार	27 फरवरी, 2014		
44.	इजराइल होमलैंड और लोक सुरक्षा मुद्दों में सहयोग पर इजराइल और भारत के बीच करार	27 अगस्त, 2014		27 अगस्त, 2014
45.	जमैका सबीना पार्क में फ्लडलाइट लागने के लिए 2.1 मिलियन अमरीकी डालर की भारतीय अनुदान सहयाता प्रदान करने के लिए भारत सरकार और जमैका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	मार्च, 2014		
46.	जापान पर्यटन के क्षेत्र में जापान टूरिज्म एजेंसी, भूमि, अवसंरचना, परिवहन एवं पर्यटन, जापान सरकार और पर्यटन मंत्रालय, भारत गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	25 जून, 2014		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
47.	जापान जापान के शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच करार को लागू करना	25 जनवरी, 2014		
48.	जापान भारतीय मानक ब्यूरो और जापानी औद्योगिक मानक समिति के बीच सहयोग ज्ञापन	25 जनवरी		
49.	जापान भारत में दूरसंचार टावर में ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक माडेल प्रोजेक्ट पर नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) जापान और आर्थिक कार्य विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	25 जनवरी, 2014		
50.	जापान स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जापान के स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	01 सितंबर, 2014		
51.	कोरिया वर्गीकृत सैन्य सूचना की सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	16 जनवरी, 2014	18 सितंबर, 2014	29 अक्तूबर, 2014
52.	कोरिया बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और कोरिया एयरोस्पेस रिसर्च इन्स्टीट्यूट के बीच करार को क्रियान्वित करना	16 जनवरी, 2014	16 जनवरी, 2014	16 जनवरी, 2014
53.	कोरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम पर कोरिया गणराज्य के विज्ञान, आईसीटी एवं भावी योजना मंत्रालय और भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	16 जनवरी, 2014	16 जनवरी, 2014	16 जनवरी, 2014
54.	कोरिया वर्ष 2014–17 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	16 जनवरी, 2014	16 जनवरी, 2014	16 जनवरी, 2014
55.	कोरिया दूरदर्शन और कोरिया इंटरनेशनल ब्रोडकास्टिंग फाउंडेशन (एकिरंग टीवी) के बीच सहयोग पर करार	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
56.	कोरिया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कोरिया गणराज्य के विज्ञान आईसीटी और भावी योजना मंत्रालय के बीच संयुक्त आशय घोषणा पत्र	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014
57.	कोरिया प्रमाणीकरण प्राधिकरणों की परस्पर मान्यता के लिए सहयोग और सूचना के आदान–प्रदान पर भारत गणराज्य के प्रमाणीकरण नियंत्रण प्राधिकारियों, संचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा कोरिया गणराज्य के कोरिया इंटरनेट एवं सुरक्षा एजेंसी (केआईएसए) के बीच समझौता ज्ञापन	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014
58.	कोरिया साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (एर्ट–इन) और कोरिया इंटरनेट एण्ड सेक्युरिकी एजेंसी (किसा) के कोरिया कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम कोआर्डिनेशन सेंटर (कसर्ट / सीसी) के बीच समझौता ज्ञापन	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014
59.	कोरिया भारत गणराज्य की सरकार के रेल मंत्रालय और कोरिया गणराज्य की सरकार के भूमि, अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के बीच रेल के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014	17 जनवरी, 2014
60.	कुवैत सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और कुवैत राज्य की सरकार के बीच करार	08 नवंबर, 2013	07 जनवरी, 2014	
61.	लिचटेन्स्टेन कर मामलों पर सूचना के आदान–प्रदान पर भारत गणराज्य की सरकार और लिचटेन्स्टेन राज्य की सरकार के बीच	08 मार्च, 2013		18 जनवरी, 2014
62.	मालदीव करार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और मालदीव गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	15 सितंबर, 2014		
63.	मैक्सिको शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अंतरिक्ष सहयोग के संबंध में दूसरों और मैक्सिको अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन	16 जुलाई, 2014		
64.	म्यांमार म्यांमार में लैंग्युवेज लेबोरेटरीज एण्ड ई–रिसार्स सेंटर पर भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	08 मई, 2014		08 मई, 2014

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
65.	म्यांमार सीमा सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	08 मई, 2014		08 मई, 2014
66.	मेसेडोनिया आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और वित्तीय अपवंचन के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मेसेडोनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	17 दिसंबर, 2013	05 फरवरी, 2014	
67.	मोरक्को भारत गणराज्य सरकार और मोरक्को अधिराज्य की सरकार के बीच पर्यावरण सहयोग पर करार	01 फरवरी, 2014		01 फरवरी, 2014
68.	मोजाम्बिक ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार पर भारत गणराज्य की सरकार और मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	23 अप्रैल, 2014		
69.	मोरक्को मेरी फिसरीज में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और मोरक्को अधिराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	01 फरवरी, 2014		01 फरवरी, 2014
70.	नेपाल दूरदर्शन और नेपाल टेलिविजन के बीच में करार	03 अगस्त, 2014		03 अगस्त, 2014
71.	नेपाल प्रेस काउंसिल ऑफ नेपाल और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन	22 सितंबर, 2014		
72.	नेपाल इलेक्ट्रिक पावर व्यापार, क्रॉस–बोर्ड ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन एवं ग्रिड कन्नक्टिविटी एवं ग्रिड कन्नक्टिविटी पर नेपाल सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार	21 अक्तूबर, 2014		
73.	नेपाल भारत और नेपाल के बीच मोटर वाहन करार पर समझौता ज्ञापन	26 नवंबर, 2014		
74.	नेपाल भारत और नेपाल के बीच नेपाल पुलिस एकेडमी (एनपीए) पर समझौता ज्ञापन	26 नवंबर, 2014		
75.	नेपाल नेपाल को 1 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला देने पर भारत और नेपाल के बीच करार	26 नवंबर, 2014		
76.	नेपाल भारत और नेपाल के बीच अरुण–III के लिए पीडीए पर समझौता ज्ञापन	26 नवंबर, 2014		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति/स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
77.	नेपाल भारत और नेपाल के बीच परंपरागत दवाइयों पर समझौता ज्ञापन	26 नवंबर, 2014		
78.	नेपाल भारत और नेपाल के बीच युवा आदान–प्रदान पर समझौता ज्ञापन	26 नवंबर, 2014		
79.	नेपाल भारत और नेपाल के बीच पर्यटन पर समझौता ज्ञापन	26 नवंबर, 2014		
80.	नीदरलैंड स्वास्थ्य देखरेख और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नीदरलैंड अधिराज्य के स्वास्थ्य, कल्याण और खेलकूद मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	30 जनवरी, 2014		
81.	ओमान भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार के बीच अपराधिक मामलों पर विधिक एवं न्यायिक सहयोग पर करार	29 अक्तूबर, 2014	28 नवंबर, 2014	
82.	पेरू भारत गणराज्य की सरकार और पेरू गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा सहयोग पर करार	28 अक्तूबर, 2013	28 नवंबर, 2014	
83.	पेरू शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और पेरू गणराज्य की सरकार के बीच आदान–प्रदान कार्यक्रम	28 अक्तूबर, 2013		
84.	संग्रहालय विकास, चल सांस्कृतिक संपत्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार–प्रसार और प्रोत्साहन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार के संस्कृति मंत्रालय और पेरु गणराज्य की सरकार के संस्कृति मंत्रालय के बीच आशय पत्र	28 अक्तूबर, 2013		
85.	क्यूबेक भारत गणराज्य और क्यूबेक के बीच सामाजिक सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन	26 नवंबर, 2013	01 जनवरी, 2014	
86.	रूस सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच संधि	21 अक्तूबर, 2013	01 जनवरी, 2014	
87.	रूस वर्ष 2015–16 की अवधि के लिए विदेश मंत्रालय और रूस के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकाल	11 दिसंबर, 2014		

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति/स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
88.	रूस रूसी परिसंघ के रक्षा मंत्रालय के सैन्य शैक्षणिक स्थापनाओं में भारतीय सशस्त्र सेना के प्रशिक्षण के लिए करार	11 दिसंबर, 2014		
89.	रूस भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग मजबूत करने के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण	11 दिसंबर, 2014		
90.	रूस परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग की रूपरेखा में तकनीकी डाटा और सूचना न प्रकट करने का प्रावधान	11 दिसंबर, 2014		
91.	रूस 2015–16 में तेल एवं गैस में सहयोग बढ़ाने हेतु अंतर–सरकारी करार की रूपरेखा के अंतर्गत सहयोग कार्यक्रम (पीओसी)	11 दिसंबर, 2014		
92.	रूस प्रत्यापन संबंधी तकनीकी सहयोग पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई)और रूसी परिसंघ की फेडरल एकरेडिटेशन सर्विस के बीच समझौता ज्ञापन	11 दिसंबर, 2014		
93.	रूस स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और रसियन फाउंडेशन फॉर बेसिक रिसर्च (आरबीएफआर) के बीच समझौता ज्ञापन	11 दिसंबर, 2014		
94.	रूस रूस के पोटाश खदान में स्टेक प्राप्त करने के लिए हुए समझौते को लागू करने हेतु रूस के एक्रॉन और भारत के एनएमडीसी (कन्सोर्टियम लीडर) के बीच समझौता ज्ञापन	11 दिसंबर, 2014		
95.	सैन मैरिनो कर के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सैन मैरिनो गणराज्य की सरकार के बीच करार	19 दिसंबर, 2013	22 जुलाई, 2014	
96.	सऊदी अरब भारत गणराज्य के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और सऊदी अरब अधिराज्य के श्रम मंत्रालय के बीच घरेलू सेवा कामगार भर्ती हेतु श्रम सहयोग पर करार	02 जनवरी, 2014	23 जनवरी, 2014	
97.	स्पेन दृश्य–श्रव्य सह–प्रस्तुति के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य और स्पेन अधिराज्य की सरकार के बीच करार	26 अक्तूबर, 2012	28 मार्च, 2014	

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति/स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
98.	स्पेन औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ सांइस, वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय, त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो के बीच समझौता ज्ञापन	मई, 2014		
99.	सैंट किट्स एण्ड नेविस कर के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सैंट किट्स एण्ड नेविस की सरकार के बीच करार	11 नवंबर, 2014		
100.	स्वीडेन भारत गणराज्य और स्वीडेन अधिराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा पर करार	26 नवंबर, 2014	26 नवंबर, 2014	01 अगस्त, 2014
101.	संयुक्त अरब अमीरात निवेश के प्रोत्साहन और सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच करार	12 दिसंबर, 2013	26 फरवरी, 2014	21 अगस्त, 2014
102.	संयुक्त राज्य अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा अनुवृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	29 जनवरी, 2014		29 जनवरी, 2014
103.	संयुक्त राज्य अमेरिका चिकित्सा उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग पर एफडीए ऑफ यूएसए तथा भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच आशय वक्तव्य	10 फरवरी, 2014		10 फरवरी, 2014
104.	वियतनाम सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच करार	01 नवंबर, 2013	01 जनवरी, 2014	
105.	वियतनाम सीमाशुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच करार	15 सितंबर, 2014	19 दिसंबर, 2014	
106.	वियतनाम भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच समुद्री नौवहन करार	24 मई, 2014	01 जनवरी, 2014	
107.	वियतनाम वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच वायु सेवा करार	20 नवंबर, 2013		02 जून, 2014

परिशिष्ट–I

क्रम सं०	अभिसमय / संधि / करार का शीर्षक	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थ सहमति / स्वीकृति देने की तारीख	लागू होने की तारीख
108.	वियतनाम दूरसंचार विश्वविद्यालय, रक्षा मंत्रालय, वियतनाम में अंग्रेजी भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	28 अक्तूबर, 2014		28 अक्तूबर, 2014
109.	वियतनाम वर्ल्ड हेरीटेज साइट ऑफ माईसन, क्वांग नाम प्रोविन्स, वियतनाम के संरक्षण और पुनरुद्धार हेतु भारत गणराज्य और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	28 अक्तूबर, 2014		
110.	वियतनाम वर्ष 2015–17 के लिए भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	28 अक्तूबर, 2014		28 अक्तूबर, 2014
111.	वियतनाम दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम के आदान–प्रदान के लिए प्रसार भारती, नई दिल्ली, भारत और व्यास ऑफ वियतनाम (वीओवी), हनोई, वियतनाम के बीच कोआपरेशन ब्रोडकास्टिंग हेतु समझौता ज्ञापन	28 अक्तूबर, 2014		28 अक्तूबर, 2014
112.	वियतनाम भारत गणराज्य के युवा मामलों में सहयोग पर कौशल विकास, उद्यमशीलता, युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के हो चिन मिन्ह कम्युनिस्ट यूथ यूनियम के सेंटरल कमेटी के बीच समझौता ज्ञापन	15 सितंबर, 2014		15 सितंबर, 2014

परिशिष्ट–II

01 जनवरी–31 दिसंबर, 2014 के दौरान जारी किए गए पूर्ण क्षमता वाले दस्तावेज

क्र.सं.	अभिसमय/संधि	पूर्ण क्षमता वाले दस्तावेज जारी होने की तारीख
1.	फीजी आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान परिहार एवं वित्तीय अपंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फीजी गणराज्य की सरकार के बीच करार	23 जनवरी, 2014
2.	मराक्केस संधि आँख से अंधे, दृष्टि से कमजोर अथवा नहीं पढ़ सकने वाले व्यक्तियों के लिए प्रकाशित सामग्री तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए मराक्केस संधि	7 फरवरी, 2014
3.	वियतनाम सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार	25 मार्च 2014
4.	आसियान भारत गणराज्य और एसोसिएशन ऑफ साउथ–ईस्ट एशियन नेशन्स के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर करार की रूपरेखा के तहत सेवाओं में व्यापार पर करार	12 अगस्त, 2014
5.	आसियान भारत गणराज्य और एसोसिएशन ऑफ साउथ–ईस्ट एशियन नेशन्स के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर करार की रूपरेखा के तहत निवेश पर करार	12 अगस्त, 2014
6.	नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	21 मई, 2014
7.	मिनामता अभिसमय बुद्ध पर मिनामता अभिसमय	19 अगस्त, 2014
8.	हांगकांग सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और चीन के जनवादी गणराज्य के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार के बीच करार	18 सितंबर, 2014
9.	ओमान अपराधिक मामलों में विधिक एवं न्यायिक सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत के बीच करार	29 अक्तूबर, 2014

परिशिष्ट–III

01 जनवरी, 2014–31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन दस्तावेजों एवं उन पर हुई सहमति की तारीख

क्र.स.	अनुसमर्थन दस्तावेज / सहमति	अनुसमर्थन जारी होने की तारीख
1.	सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य और ब्राजील संघीय गणराज्य के बीच करार	01 जनवरी, 2014
2.	भारत गणराज्य और क्यूबेक के बीच सामाजिक सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन	01 जनवरी, 2014
3.	सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच संधि	01 जनवरी, 2014
4.	सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच करार	01 जनवरी, 2014
5.	भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच समुद्री नौवहन करार	जनवरी, 2014
6.	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम हेतु भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोतोकाल	23 जनवरी, 2014
7.	भारत गणराज्य के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और सऊदी अरब अधिराज्य के श्रम मंत्रालय के बीच घरेलू कामगारों की भर्ती हेतु श्रम सहयोग पर करार	23 जनवरी, 2014
8.	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम हेतु भारत गणराज्य की सरकार और मेसेडोनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	05 फरवरी, 2014
9.	सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और कुवैत राज्य की सरकार के बीच करार	07 जनवरी, 2014
10.	आयपर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम हेतु भारत गणराज्य की सरकार और फीजी गणराज्य की सरकार के बीच करार	26 फरवरी, 2014
11.	निवेश के संवर्धन और सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच करार	26 फरवरी, 2014
12.	विदेशों में सजायाफ्ता अपराधियों को सौंपने अंतर–अमेरिकी अभिसमय	14 मार्च, 2014
13.	अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच का गठन	25 मार्च, 2014

परिशिष्ट–III

क्र.स.	अनुसमर्थन दस्तावेज / सहमति	अनुसमर्थन जारी होने की तारीख
14.	भारत गणराज्य की सरकार और कनाडा सरकार के बीच दृश्य–श्रव्य सह–निर्माण करार	25 मार्च, 2014
15.	भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	18 अप्रैल, 2014
16.	अपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य के बीच संधि	03 मई, 2014
17.	अपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और इजराइल राज्य की सरकार के बीच संधि	25 अप्रैल, 2014
18.	दृश्य–श्रव्य सह निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य और स्पेन अधिराज्य की सरकार के बीच करार	28 मार्च, 2014
19.	आँखों से अंधे, दृष्टि से कमजोर अथवा न पढ़ सकने वाले व्यक्तियों के लिए प्रकाशित सामग्री तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए सराकेश संधि	23 मई, 2014
20.	असैनिक परमाणु सुविधाओं की सरक्षा के अनुप्रयोग के लिए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच करार के अतिरिक्त प्रोतोकाल	12 मई, 2014
21.	भारत गणराज्य की सरकार और पेरू गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा सहयोग पर करार	06 जून, 2014
22.	भारत गणराज्य और चेक गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा पर करार	22 जुलाई, 2014
23.	करों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान हेतु भारत गणराज्य की सरकार और सेन मैरिनो गणराज्य की सरकार के बीच करार	22 जुलाई, 2014
24.	सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विधिक एवं न्यायिक सहयोग पर भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य के बीच संधि	12 अगस्त, 2014
25.	आय पर करों के संबंध में कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और क्रोएशिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	12 अगस्त, 2014
26.	वर्गीकृत सैन्य सूचना की सुरक्षा पर भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	18 सितंबर, 2014
27.	जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोतोकाल की जिम्मेदारी और सुधार पर नागोया–कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोतोकाल	28 नवंबर, 2014
28.	भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार के बीच अपराधिक मामलों में विधिक और न्यायिक सहयोग पर करार	28 नवंबर, 2014

परिशिष्ट–III

क्र.स.	अनुसमर्थन दस्तावेज / सहमति	अनुसमर्थन जारी होने की तारीख
29.	सीमाशुल्क मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता एवं सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और चीनी जनवादी गणराज्य के बीच करार	28 नवंबर, 2014
30.	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग एवं परस्पर सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच कराक	19 दिसंबर, 2014

परिशिष्ट–IV

आईटीईसी तथा एससीएएपी देशों की सूची
आईटीईसी देश

क्रम सं.	देश	क्रम सं.	देश
1.	अफगानिस्तान	31.	कोलंबिया
2.	अलबेनिया	32.	कामनवेल्थ ऑफ डोमिनिका
3.	अल्जीरिया	33.	कोमोरोस
4.	अंगोला	34.	कांगो
5.	अंग्यूला	35.	कुक्स द्वीप
6.	एंटिगुआ और बारबुडा	36.	कोस्टा रिका
7.	अर्जेंटीना	37.	कोट डी आइवरी
8.	अरमेनिया	38.	चेक गणराज्य
9.	अजरबैगान	39.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
10.	बहामास	40.	जिबूती
11.	बहरीन	41.	डोमिनिकन रिपब्लिक
12.	बांग्लादेश	42.	इक्वाडोर
13.	बरबडोस	43.	मिस्र
14.	बेलारूस	44.	एल–सलवाडोर
15.	बेलिज	45.	इक्वेटोरियल गिनी
16.	बनिन	46.	इरिट्रिया
17.	भूटान	47.	इस्टोनिया
18.	बोलीविया	48.	इथोपिया
19.	बोसनिया–हर्जेगोविना	49.	फीजी
20.	ब्राजील	50.	गेबन
21.	ब्रुनेई दारूस्सलाम	51.	जॉर्जिया
22.	बुल्गारिया	52.	ग्रेनेडा
23.	बुर्किना फासो	53.	ग्वेटमाला
24.	ब्रुंडी	54.	गिनी
25.	कंबोडिया	55.	गिनी बिसाऊ
26.	कैप वर्डे द्वीप	56.	गुयाना
27.	केमैन द्वीप	57.	हैती
28.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	58.	होंडुरस
29.	चाड	59.	हंगरी
30.	चिली	60.	इण्डोनेशिया

परिशिष्ट–IV

क्रम सं.	देश	क्रम सं.	देश
61.	ईरान	92.	निकारागुआ
62.	इराक	93.	नाइजेर
63.	जमैका	94.	ओमान
64.	जॉर्डन	95.	पलाऊ
65.	कजखस्तान	96.	फिलीस्तीन
66.	किरिबाती	97.	पनामा
67.	कोरिया (डीपीआरके)	98.	पपुआ न्यू गिनी
68.	किर्गिस्तान	99.	परागुवे
69.	लाओस	100.	पेरू
70.	लातिविया	101.	फिलीपींस
71.	लेबनान	102.	पोलैण्ड
72.	लाइबेरिया	103.	कतर
73.	लीबिया	104.	साओ तोम गणराज्य
74.	लिथुआनिया	105.	रोमानिया
75.	मेसेडोनिया	106.	रूस
76.	मेडागास्कर	107.	रवांडा
77.	मलेशिया	108.	समोआ
78.	मालदीव	109.	सेनेगल
79.	माली	110.	सर्बिया
80.	मार्शल द्वीप	111.	सिंगापुर
81.	मौरिटोनिया	112.	स्लोवाक गणराज्य
82.	मैक्सिको	113.	सोलोमन द्वीपसमूह
83.	माइक्रोनेशिया	114.	सोमालिया
84.	मोलदोवा	115.	श्रीलंका
85.	मंगोलिया	116.	सैंट किट्स एण्ड नेविस
86.	मोंटेनिग्रो	117.	सैंट लूसिया
87.	मोंटसेरट	118.	सैंट विसेंट तथा ग्रेनेडाइन्स
88.	मोरक्को	119.	सूडान
89.	म्यांमार	120.	दक्षिण सूडान
90.	नौवरू	121.	सूरीनाम
91.	नेपाल	122.	सीरिया

परिशिष्ट–IV

क्रम सं.	देश	क्रम सं.	देश
123.	ताजिकिस्तान	138.	वेनेजुएला
124.	थाईलैंड	139.	वियतनाम
125.	तिमोर लेस्ते	140.	यमन
126.	टोगो	**स्कैप देश**	
127.	टोंगा	141.	कैमरून
128.	त्रिनदाद एवं तोबैगो	142.	कैमरून
129.	ट्यूनिशिया	143.	गाम्बिया
130.	तुर्की	144.	घाना
131.	तुर्कमेनिस्तान	145.	कीनिया
132.	टर्क्स एण्ड कैकोस द्वीप	146.	लिसोथो
133.	तुवालु	147.	मलावी
134.	यूक्रेन	148.	मॉरीशस
135.	ऊरुग्वे	149.	मोजाम्बिक
136.	उज्बेकिस्तान	150.	नामीबिया
137.	वनुआतु	151.	नाइजीरिया

परिशिष्ट–V

आईटीईसी /एससीएएपी के सूचीबद्ध संस्थानों की सूची

क्र.स.	संस्थान का नाम	शहर
लेखा, लेखापरीक्षा, बैंकिंग और वित्त पाठ्यक्रम		
1.	सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान	नई दिल्ली
2.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रणाली लेखा परीक्षा केंद्र	नोएडा
3.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान –	पुणे
आईटी, दूरसंचार और अंग्रेजी पाठ्यक्रम		
4.	एप्टेक लिमिटेड	नई दिल्ली
5.	उन्नत संगणना विकास केंद्र	मोहाली
6.	उन्नत संगणना विकास केंद्र	नोएडा
7.	दूरसंचार प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में उत्कृष्टता केंद्र	मुंबई
8.	सीएमसी लि.	नई दिल्ली
9.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	हैदराबाद
10.	एनआईआईटी लि.	नई दिल्ली
11.	यूटीआई टेक्नॉलाजी लि.	बंगलोर
प्रबंधन पाठ्यक्रम		
12.	भारत का प्रशासनिक स्टाफ कालेज	हैदराबाद
13.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकॉनामिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट	दिल्ली
14.	अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
15.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	अहमदाबाद
एसएमई/ ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
16.	इंटरेप्रेन्यूरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया	अहमदाबाद
17.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरेप्रेन्यूरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट	नोएडा
18.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रोस्माल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज	हैदराबाद
19.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद
विशेष पाठ्यक्रम		
20.	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	नई दिल्ली
21.	ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट	नई दिल्ली
22.	इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ मास सम्युनिकेशन	नई दिल्ली
23.	अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र	कोलकाता
24.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	नई दिल्ली
25.	राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण संस्थान (भारतीय मानक ब्यूरो)	नोएडा

परिशिष्ट–V

क्र.स.	संस्थान का नाम	शहर
26.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	चेन्नई
27.	राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
28.	रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकादमी	गाजियाबाद
29.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	नई दिल्ली
30.	वी.वी. नेशनल लेबर इस्टीट्यूट	नोएडा
तकनीकी पाठ्यक्रम		
31.	सेन्ट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एण्ड ट्रेनिंग इस्टीट्यूट	फरीदाबाद
32.	सेन्ट्रल इस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन	हैदराबाद
33.	सेन्ट्रल इस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन	हैदराबाद
34.	सेन्ट्रल साइंटिफिक इस्ट्रमेंट्स अर्गेनाइजेशन	नई दिल्ली
35.	फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इस्टीट्यूट	केरल
36.	जीओलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रशिक्षण संस्थान	हैदराबाद
37.	भारतीय उत्पादन प्रबंधन संस्थान दृ कंसबइल,	उड़ीसा
38.	भारतीय दूरसंवेदी संस्थान	देहरादून
39.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रूड़की, जल विज्ञान विभाग
40.	भारतीय प्रौद्योगिकी	रूड़की, जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग
41.	राष्ट्रीय फर्मास्युटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	एसएएस नगर, पंजाब
42.	दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन	कोयम्बटूर
पर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा पाठ्यक्रम		
43.	एल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर, इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी,	रुड़की
44.	बेयफूट कालेज दृ तिलोनिया,	राजस्थान
45.	सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी	चेन्नई
46.	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	गुड़गांव
47.	टेरी (ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान)	नई दिल्ली

परिशिष्ट–VI

वर्ष 2014–15 के दौरान नीति, आयोजना और अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूरी तरह वित्त पोषित विश्वविद्यालय/संस्थाओं द्वारा आयोजित/प्रारंभ किए गए सम्मेलन/सेमिनार/अध्ययन परियोजनाएं

क्र.स.	कार्यक्रम	संस्थान/लाभग्राही
1	'द अरब स्प्रिंगः वर्तमान परिदृश्य एवं आईसीसी में भारत के लिए नीति विकल्प' पर सेमिनार आयोजित किया गया	वाना
2	निम्नलिखित पर चार सेमिनारः (i) भारत की अर्थव्यवस्थाः आर्थिक सुधार एवं आर्थिक नीति जिसमें विदेश नीति पहलू शामिल है (14 जून 2014) (ii) कोल्डवार रिडक्सः भारत–रूस संबंध एवं भारत की नीति संबंधी चुनौतियां (09 अगस्त 2014) (iii) रक्षा तैयारी एवं भारत में उच्च रक्षा संगठन (15 नवंबर, 2014) और (iv) आंतरिक सुरक्षा एवं भारत में विद्रोहः बाह्य आयाम (24 जनवरी, 2015)	एशिया सेंटर, बंगलौर
3.	26–28 फरवरी, 2015 के दौरान 21वीं सदी के माध्यम से भारत की विदेश नीति संबंधी रणनीति पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार	केरल विश्वविद्यालय
4.	मार्च 2015 में आयोजित होने वाले प्रो. विजय लक्ष्मी द्वारा 'भारत–अमरीकी संबंध में सहक्रिया निर्माणः आगामी दशक में चुनौतियों' पर सेमिनार	जेएनयू में कनाडाई, अमरीकी और लातिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र

परिशिष्ट–VII

प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों और जारी किए गए पासपोर्टों, प्राप्त कुल विविध आवेदनों और प्रदान की गई सेवाओं की कुल संख्या, जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या और तत्काल स्कीम के तहत राजस्व, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पासपोर्ट कार्यालयों का कुल राजस्व और व्यय दर्शाने वाला विवरण

आरपीओ	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की कुल सं. (सामान्य + तत्काल)	जारी किए गए सामान्य पासपोर्ट की संख्या	जारी किए गए तत्काल पोसपोर्ट की संख्या	जारी किए गए पोसपोर्टों की कुल संख्या (सामान्य + तत्काल)	प्राप्त विविध आवेदनों की संख्या	प्रदान की गई विविध सेवाओं की संख्या	पासपोर्ट और प्रदान की गई विविध सेवाओं की संख्या
अहमदाबाद	4,05,717	3,96,359	4,938	4,01,297	14,217	13,572	4,14,869
अमृतसर	1,00,743	97,106	3,908	1,01,014	4,793	4,645	1,05,659
बंगलौर	5,07,350	4,53,747	58,477	5,12,224	13,055	12,393	5,24,617
बरेली	1,11,351	89,505	3,459	92,964	2,887	2,846	95,810
भोपाल	1,33,025	1,30,249	11,534	1,41,783	1,555	1,520	1,43,303
भुवनेश्वर	89,730	87,743	3,049	90,792	3,776	3,680	94,472
चंडीगढ़	3,67,126	3,60,680	13,696	3,74,376	15,093	14,414	3,88,790
चेन्नई	3,77,260	3,51,963	19,352	3,71,315	17,387	16,987	3,88,302
कोचीन	3,04,759	2,43,163	60,822	3,03,985	24,529	24,425	3,28,410
कोयंबटूर	1,13,268	1,11,809	2,287	1,14,096	1,936	1,914	1,16,010
देहरादून	70,172	65,030	5,264	70,294	1,939	1,918	72,212
दिल्ली	4,46,961	3,64,661	64,536	4,29,197	8,846	8,625	4,37,822
गाजियाबाद	1,61,666	1,30,887	15,648	1,46,535	2,535	2,308	1,48,843
गोवा	42,944	41,807	345	42,152	5,039	5,028	47,180
गोवाहाटी	62,488	55,496	7,124	62,620	1,690	1,572	64,192
हैदराबाद	6,73,886	6,16,314	30,254	6,46,568	43,883	40,986	6,87,554
जयपुर	2,46,584	2,33,211	5,739	2,38,950	11,889	11,785	2,50,735
जालंधर	2,15,929	2,11,644	877	2,12,521	18,366	18,070	2,30,591
जम्मू	28,559	28,357	25	28,382	3,813	1,303	29,685
कोलकाता	4,31,629	3,68,665	25,665	3,94,330	14,233	13,722	4,08,052
कोझीकोड	2,77,609	2,42,372	35,481	2,77,853	9,834	9,792	2,87,645
लखनऊ	6,00,127	5,52,457	22,980	5,75,437	27,026	26,487	6,01,924
मदुरई	2,23,626	2,29,421	156	2,29,577	10,355	10,175	2,39,752
मालापुरम	2,42,712	2,00,349	40,088	2,40,437	5,498	5,443	2,45,880
मुंबई	3,75,444	3,36,315	37,849	3,74,164	10,338	9,921	3,84,085
नागपुर	97,757	85,910	5,598	91,508	1,480	1,456	92,964
पटना	2,89,941	2,41,453	2,924	2,44,377	12,422	12,111	2,56,488
पुणे	2,20,887	1,89,475	20,947	2,10,422	4,440	4,089	2,14,511

परिशिष्ट–VII

प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों और जारी किए गए पासपोर्टों, प्राप्तकुल विविध आवेदनों और प्रदान की गई सेवाओं की कुल संख्या, जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या और तत्काल स्कीम के तहत राजस्व, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पासपोर्ट कार्यालयों का कुल राजस्व और व्यय दर्शाने वाला विवरण

आरपीओ	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की कुल सं. (सामान्य + तत्काल)	जारी किए गए सामान्य पासपोर्ट की संख्या	जारी किए गए तत्काल पोसपोर्ट की संख्या	जारी किए गए पोसपोर्टों की कुल संख्या (सामान्य + तत्काल)	प्राप्त विविध आवेदनों की संख्या	प्रदान की गई विविध सेवाओं की संख्या	पासपोर्ट और प्रदान की गई विविध सेवाओं की संख्या
रायपुर	33,943	33,304	938	34,242	297	293	34,535
रांची	66,608	62,094	2,234	64,328	2,495	2,398	66,726
शिमला	31,670	27,904	3,231	31,135	1,600	1,562	32,697
श्रीनगर	55,217	55,938	205	56,143	2,081	270	56,413
सूरत	1,30,160	1,23,725	4,669	1,28,394	8,548	8,533	1,36,927
थाने	2,38,342	2,10,508	18,031	2,28,539	6,234	5,892	2,34,431
त्रिची	1,93,907	1,97,295	1,375	1,98,670	11,954	11,915	2,10,585
त्रिवेंद्ररम	1,89,017	1,60,580	27,223	1,87,803	13,704	13,636	2,01,439
विशाखापट्नम	1,87,082	1,72,898	7,919	1,80,817	14,727	14,060	1,94,877
कुल	**83,45,196**	**75,60,394**	**5,68,847**	**81,29,241**	**3,54,494**	**3,39,746**	**84,68,987**
क	37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (पासपोर्ट+विविध सेवाएं) =81,29,241+3,39,746						84,68,987
ख	विदेश मंत्रालय, पीवी-II अनुभाग (सरकारी एवं राजनयिक पासपोर्ट)=17560+2648						20,208
ग	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह						3,529
घ	क्षे.पा.का. दिल्ली जारी (आईसी)						7,641
ङ	सरेंड्डर सर्टिफिकेट एवं एलओसी जारी किए गए = 2595+4278						6,873
	पीपीटी+ईसीएस+भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा विविध सेवाएं						
	कुल योग						

परिशिष्ट–VIII

31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पासपोर्ट संगठन की कैडर सं.

I. ग्रुप एवं पद का नाम	कुल स्वीकृत संख्या
समूह 'क'	
पासपोर्ट अधिकारी	17
उप पासपोर्ट अधिकारी	71
सहायक पासपोर्ट अधिकारी	135
कुल	223
समूह 'ख' (राजपत्रित)	
पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी	320
अधिक्षक	245
कुल	565
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	
सहायक	428
हिंदी अनुवादक	23
आशुलिपिक ग्रेड I	17
कुल	468
समूह 'ग' (अराजपत्रित)	
अपर श्रेणी लिपिक	628
अपर श्रेणी लिपिक (हिंदी)	04
अवर श्रेणी लिपिक	648
ड्राइवर	00
आशुलिपिक ग्रेड II	13
कार्यालय सहायक	148
कुल	**1441**
II. पासपोर्ट सेवा परियोजना की परियोजना प्रबंधन इकाई (पी एम यू) को जनशक्ति प्रदान करने के 2007 के केंद्रीय मंत्रि परिषद के निर्णय के द्वारा सृजित किए गए पद	
तकनीकी	15
प्रशासनिक	06
कुल	21
कुल योग (I+II)	**2718**

परिशिष्ट–IX

31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों / केंद्रों में काडर सं. (वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संगणित पदों एवं काडर आदि से परे पदों सहित)

क्र.सं.	पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
1	काडर I	5	31	36
2	काडर II	6	41	47
3	काडर III	38	126	164
4	काडर IV	54	148	202
5	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ वेतनमान	98	232	330
6	(i) कनिष्ठ वेतनमान	10	25	35
	(ii) परिवीक्षा आरक्षित	62		62
	(iii) छुट्टी आरक्षित	15		15
	(iv) प्रतिनियक्ति आरक्षित	19		19
	(v) प्रशिक्षण आरक्षित	7		7
	उप जोड़	**314**	**603**	**917**
	भारतीय विदेश सेवा (ख)			0
7	(i) ग्रेड I	126	120	246
	(ii) प्रतिनियक्ति आरक्षित	6		6
8	(iii) एकीकृत ग्रेड II एवं III	351	225	576
	(iv) छुट्टी आरक्षित	30		30
	(v) प्रतिनियक्ति आरक्षित	16		16
	(vi) प्रशिक्षण आरक्षित	25		25
9	(i) ग्रेड IV	267	333	600
	(ii) छुट्टी आरक्षित	60		60
	(iii) प्रतिनियक्ति आरक्षित	55		55
10	(i) ग्रेड V/VI	157	88	245
	(ii) छुट्टी आरक्षित	60		60
	(iii) प्रतिनियक्ति आरक्षित	14		14
11	(i) Grade II of Cypher Cadre	61	77	138
	(ii) छुट्टी आरक्षित	24		24
12	(i) आशुलिपिक काडर	377	509	886
	(ii) छुट्टी आरक्षित	47		47
	(iii) प्रशिक्षण आरक्षित (हिंदी)	10		10
	(iv) प्रतिनियक्ति आरक्षित	12		12
13	दुभाषिया काडर	7	26	33
14	एल एवं टी काडर	23	1	24
	उप जोड़	1728	1379	3107
	कुल जोड़	**2042**	**1982**	**4024**

परिशिष्ट–X

01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति तथा मंत्रालय में कराई गई सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती संबंधी आकड़े

क्र.स.	समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	अ.जा.	अन.ज. जा.	ओ.बी.सी.
1.	ग्रुप ए	119	10	11	9
2.	ग्रुप बी	295	45	37	16
3.	ग्रुप सी	241	05	21	76
	कुल	655	60	69	101

परिशिष्ट–XI

विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भा.वि.से. के अधिकारियों की संख्या

क्र.सं.	भाषा	अधिकारियों की संख्या
1.	अरबी	95
2.	भाषा इंडोनेशिया	10
3.	भाषा माले	1
4.	भाषा थाई	1
5.	बर्मी	7
6.	चीनी	72
7.	फ्रांसीसी	79
8.	जर्मन	29
9.	हीब्रू	6
10.	जापानी	25
11.	कजख	1
12.	किसवाहिली	2
13.	कोरेन	5
14.	फारसी	21
15.	पुर्तगाल	22
16.	पुश्तु	2
17.	रूसी	87
18.	सर्बी–क्रोएशिया	1
19.	सिनहली	4
20.	स्पैनिश	73
21.	तुर्की	7
22.	यूक्रेनियम	1
23.	वियतनामी	4
	कुल	**555**

परिशिष्ट–XII

आरआईएस प्रकाशनों की सूची

पुस्तकें

- मेकांग क्षेत्र में आसियान–भारत द्वारा गहराती आर्थिक सहभागिता प्रबीर डे
- विकास नीतियां और व्यापारः बढ़ते वैश्विक एवं क्षेत्रीय मूल्यः रूल्स ऑफ आरिजिन थ्रू चेन्स– राम उपेन्द्रदास एवं राजन सुदेश रत्न

रिपोर्टें

- दक्षिण एशिया विकास एवं सहयोग रिपोर्ट 2014
- भारत और म्यांमार के बीच संपर्क गलियारों को विकास गलियारे में परिवर्तन –राजदूत वी.एस. सेश्रादरी
- एशिया प्रशांत में जैव प्रौद्योगिकी क्षमता पर सर्वे रिपोर्टः राष्ट्रीय पहलुओं और क्षेत्रीय सहयोग के अवसर
- पूर्व एशियाई आर्थिक समाकलन प्रक्रिया के लिए भारतीय आर्थिक गतिकता का अर्थ– राम उपेन्द्र दास
- भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच बढ़ते क्रॉस बोर्डर प्रोडक्शन नेटवर्कः एक प्रारंभिक मूल्यांकन दृ प्रबीर डे एवं मानव मंजुमदार
- आशियान –भारत समुद्री संपर्क रिपोर्ट
- आशियान –भारत रणनीतिक सहभागिता का डाइनेमिक्सः प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेकण्ड राउण्ड टेबल ऑफ आसियान –इंडिया नेटवर्क आफ थिंक टैंक

परिचर्चा पत्र

192 द ग्रोथ– इम्प्लायमेंट रिलेशनशिप सिन्स 2000 –शिपरा निगम

191 द यूरोपियन यूनियन प्रोपोज्ड इक्वालाइजेशन सिस्टमः भारत के निर्यात के लिए कुछ निहितार्थ –विश्वजीत घर

पोलिसी ब्रीफ

65 जैव विविधता अधिनियम के तहत सुविधा एवं लाभ की हिस्सेदारीः एक अधिक प्रभावी व्यवस्था की ओर

64 इट इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनामिक्स ग्रोथ इन चाइनाः फाइनैंस मैटर

एफआईडीसी पालिसी ब्रीफ

3 पोस्ट 2015 विकास एजेंडाः एक भारतीय परिदृश्य

जर्नल्स

साउथ एशिया इकोनामिक्स जर्नल

1. खण्ड 15, अंक 2, सितंबर 2014

एशियाई जैव प्रौद्योगिकी विकास समीक्षा

2. खण्ड 16, संख्या 2, जुलाई 2014

परिशिष्ट–XIII

2014–15 में विदेश मंत्रालय का वित्तीय व्यय

2014–15 के लिए बजट आबंटन (बअ) 14730.39 करोड़ रुपये है जो कि 2013–14 के बजट अनुमान से 25.7 प्रतिशत अधिक है।

विदेश मंत्रालय का वास्तविक व्यय 2008–09 से 2013–14 (राजस्व और पूंजी)

वर्ष	वास्तविक (रुपए करोड़ में)	प्रतिशत विगत वर्ष से प्रतिशतता में अंतर
2008-09	6630.73	45.02
2009-10	6290.77	-5.13
2010-11	7153.27	13.71
2011-12	7872.76	10.06
2012-13	10120.88	28.55
2013-14	11807.36	16.66
2014-15(BE)	14730.39	24.75

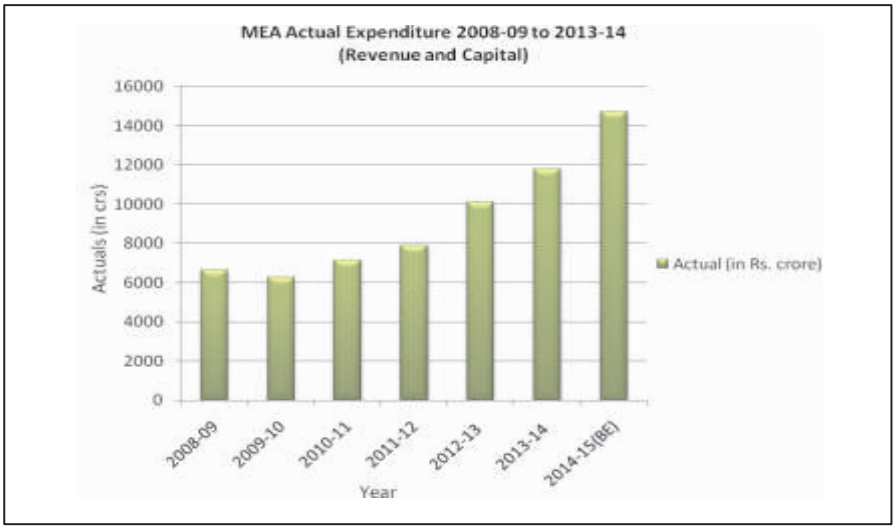

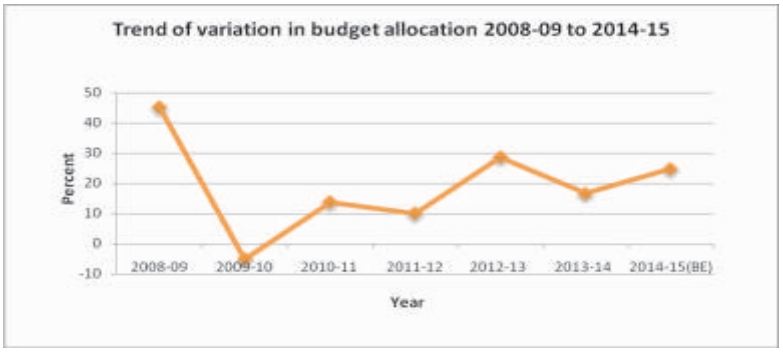

परिशिष्ट–XIV

2014–15 में मुख्य क्षेत्रवार आबंटन (बजट अनुमान)

क्षेत्र	आबंटन (रुपए करोड़ में)
तकनीकी एवं आर्थक सहयोग	6268.81
दूतावास एवं मिशन	1832.31
विदेशी सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	3166.01
विशेष राजनयिक व्यय	1596.01
पासपोर्ट एवं उत्प्रवास	542.83
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	417.59
विदेश मंत्रालय का सचिवालय	282.76
पूंजीगत परिव्यय	300
संस्थानों को अनुदान	198.3
अन्य	125.77
कुल	14730.39

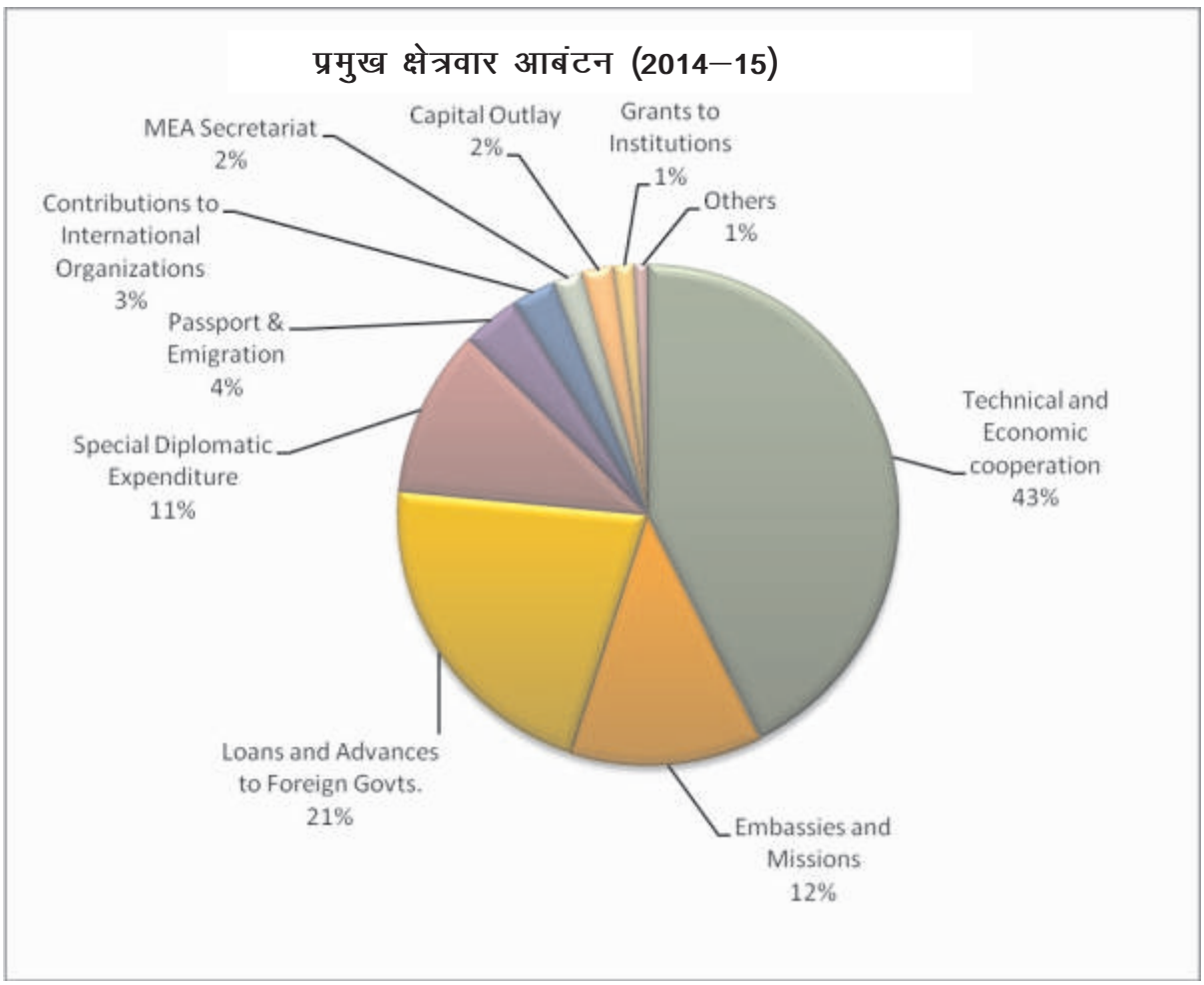

परिशिष्ट–XV

भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

चालू वित्त वर्ष 2014–15 में भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के प्रधान लाभग्राही इस प्रकार थे (ये आंकड़े बजट अनुमान 2014–15 से संबंधित हैं):'

क्र.स.	तकनीकी सहयोग बजट	(रुपए करोड़ में)	भारत के कुल सहायता एवं ऋण बजट का प्रतिशत
1.	भूटान	3065.99	48.91%
2.	बांग्लादेश	350.00	5.58%
3.	अफगानिस्तान	676.00	10.78%
4.	श्रीलंका	500.00	7.98%
5.	नेपाल	450.00	7.18%
6.	म्यांमार	330.00	5.26%
7.	अफ्रीकन देश	350.00	5.58%
8.	यूरेशियन देश	40.00	0.64%
9.	मालदीव	25.00	0.40%
10.	लातिन अमरीका देश	30.00	0.48%
11.	मंगोलिया	2.50	0.04%
12.	अन्य	449.32	7.17%
	कुल	6268.81	100.00%

परिशिष्ट–XVI

लम्बित सीएजी लेखापरीक्षा पैराओं की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	जिन पैराओं/पीए रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी लेखा परीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तु की गई है, उनकी संख्या	जिन पैराओं/पीए रिपोर्ट के संबंध में एटीएन लंबित है उनका ब्यौरा		
			ऐसे एटीएन की संख्या जो पहली बार भी मंत्रालय द्वारा नहीं भेजी गई है।	ऐसे एटीएन की संख्या जो भेजी गई परन्तु टिप्पणी सहित वापस कर दी गई और मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।	ऐसे एटीएन की संख्या जिन्हें लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षित किया गया है परन्तु उन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1	2010-11	-	-	1	-
2	2011-12	-	-	-	-
3	2012-13	-	-	1	-
4	2013	-	-	1	-
5	2014	-	6	2	-
Total		-	6	5	-

जनवरी, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष की नवीनतम लेखा परीक्षा रिपोर्टों में प्रदर्शित होने वाली महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार

1.	वैश्विक संपदा प्रबंध की निष्पादन लेखा–परीक्षा	**कार्यक्षेत्र (डामेन) सूचना की कमी और कार्य योजना तैयार न होना।** ऐसा देखा गया है कि वांछित कार्यक्षेत्र (डोमेन) सूचना अर्थात् स्वामित्व वाले, किराए और लीज़ पर लिए गए चांसरी भवनों/दूतावास आवासों/ स्टाफ आवासों इत्यादि की संख्या की जानकारी में पहले से विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं होती है। सूचना की अनुप्लब्धता से पी.ए.सी. को दिए गए आश्वासन के अनुरूप किराए के दायित्व को घटाने के प्रति प्रणालीगत दृष्टकोण की कमी का पता चलता है। पी.ए.सी. को दिए गए आश्वासन के बावजूद विदेश मंत्रालय को संपदा प्रबंध की कार्य योजना बनाना बाकी है। **संपत्ति अधिग्रहण के विलम्ब** मंत्रालय ने पी.ए.सी. दो पर आश्वासन दिया था कि संपत्ति के अधिग्रहण एवं निर्माण से संबंधित आंतरिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने एवं उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। तथापि लेखा परीक्षा द्वारा 7 मामलों (जनेवा, बर्न, हैमबर्ग, मुयुनिश, विश्केक, स्टॉकहोम और मिलान) को नोट किया गया था। फिर भी निर्णय लेने में कमियां रह गई और विलंब हुआ। भूमि की खरीद/संपत्ति अधिग्रहण में विफलता के चलते 2011/12 के दौरान 7.83 करोड़ रुपए की राशि का किराया आउटगो हुआ।

		निर्माण गतिविधि में विलंब लेखा परिक्षा द्वारा 10 मामलों (शंघाई, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट लउस, दार एस सलाम, काठमांडू, ताशकंद, कीव, ब्रासीलिया, दोहा और निकोसिया में संपत्तियों में निर्माण की शुरूआत में विलंब को नोट किया। ये विलंब ड्राइंग प्रस्तुत करने में विलंब अपेक्षित परिसंपत्तियों के प्रकार में पुष्टि करने में विफलता, परियोजना डिजाइनों को अंतिम रूप दिए जाने, स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब, परियोजना अपेक्षाओं में बार–बार परिवर्तन होने तथा अन्य क्रियाविधि संबंधी विलंब के कारण हुए। इस प्रकार के अधिकांश विलंब मंत्रालय को आंतरिक व्यवस्थाओं के चलते हुए। पी.ए.सी. ने संपत्ति प्रबंधन की विगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जाँच करने के दौरान विदेश मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया था कि निर्माण पूर्व गतिविधियों में विलंब से बचने के लिए विशेष समय–सीमा निर्धारित की जाए तथा अनुविक्षण तंत्र स्थापित किया जाए। 2011–12 में इन मामलों में वार्षिक रेंटल आउटगो 16.36 करोड़ रुपए था। **नवीकरण/पुनर्विकास गतिविधियों में विलंब** मंत्रालय द्वारा विभिन्न केंद्रों पर स्वामित्व वाले भवनों का नवीकरण/पुनर्विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है। मंत्रालय/संबंधित मिशनों में रख–रखाव किए गए अभिलेखों की लेखा परीक्षा से पता चलता है कि चार केंद्रों सिडनी, हांगकांग, क्वालालंपुर और जकार्ता में 2011–12 के दौरान 7.44 करोड़ रुपए के परिहार्य किराया व्यय में अनियमिताएँ तथा व्याप्ति विलंब हुए थे। **भारत में निर्माण गतिविधियों में विलंब** घरेलू निर्माण परियोजनाओं में भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण की कमी देखी गई थी। 5 परियोजनाओं (आर.पी.ओ. जयपुर, आर.पी.ओ. अमृतसर, आर.पी.ओ. मुम्बई, आर.पी.ओ. श्रीनगर और एफ.एस. आई. दिल्ली) के रिकार्ड की लेखापरीक्षा से पता चला कि 22 वर्षों तक (आर.पी. जयपुर) परियोजनाओं को प्रारंभ करने में पर्याप्त विलंब हुआ। आर.पी.ओ. श्रीनगर में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। हालांकि, भूमि 2006 में ही खरीद ली गई थी। अकेले 2011–12 के दौरान 3 आर.पी.ओ. (आर.पी.ओ. अमृतसर, आर.पी.ओ. मुम्बई, आर.पी.ओ. श्रीनगर) के संबंध में परिहार्य रैंटल आउटगो 3.98 करोड़ रूपए था।
2.	सरकार के खाते से बाहर के बैंक खाते का रखरखाव	भारतीय दूतावास ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, ने सरकार के बहीखाते में प्रविष्ट किए बिना बैंक खातों को प्रचालित किया तथा 41,17,118 अर्जेंटाइन पैसों (5.18 कोरड़ रुपए) का लेन–देन किया। **(पैराग्राफ 5.1)**
3.	वस्तुओं की खरीद में नियमों का उल्लंघन	भारत का महाकौसलावास अंटलाना ने नियमों का उल्लंघन करते हुए तथा उचित, पारदर्शी तथा सही प्रक्रिया का अनुपालन किए बगैर तीन अलग–अलग खरीदों में अर्थात् कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर/फिटिंग्स हेतु 1.61 करोड़ रुपए की खरीद की। **(पैराग्राफ 5.2)**
4.	मासिक लेखे खाते में फर्जी भुगतान वाउचर तथा रसीद चालान	भारत का महाकौशलवास, होस्टन, यू.एस.ए. ने 3,72,632 अमरीकी डॉलर का फर्जी भुगतान वाउचर और 3,62,172 अमरीकी डॉलर का रसीद चालान तैयार किया और इसे अपने मासिक खाते में डालकर मंत्रालय को प्रस्तुत किया रोकड़ बही में दर्शाये बिना 69,356 अमरीकी डॉलर की निकासी की गई और 35,266 अमरीकी डॉलर जमा किया गया। कौसलावास का खाता गंभीर अशुद्धियों से प्रभावित हुआ जो प्राप्तियों के कम लेखांकन और अलेखांकित आहरण से जोखिम भरा था। **(पैराग्राफ 5.3)**

5.	परियोजना प्रबंधन दलों को विदेश भत्ते का अधिक भुगतान	मास्को और पैरिस स्थित मिशनों ने मास्को और पैरिस में परियोजना प्रबंधन दलों में तैनात भारतीय वायुसेना के 6 आधिकारियों को विदेश प्रतिपूरक भत्ते के स्थान पर विदेशी भत्ते का भुगतान किया। **(पैराग्राफ 5.4)**
6.	पासपोर्ट विविध सेवाओं हेतु शुल्क की कम उगाही	पासपोर्ट विविध सेवा शुल्क में संशोधन न किए जाने के कारण 1.52 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। **(पैराग्राफ 5.5)**
7.	सेवा प्रदाताओं को आबंधित वित्तीय लाभ	पासपोर्ट सेवाओं को अभ्यर्पित करने हेतु सेवा प्रभारों में अनियमित रूप से वृद्धि और ऐसी सेवाओं पर अननुमेय प्रशासनिक शुल्क की उगाही की वजह से सितंबर 2010 से मार्च 2013 के दौरान सेवा प्रदाता को 67.36 लाख रुपए आवंछित वित्तीय लाभ पहुँचा। **(पैराग्राफ 5.6)**

संक्षिप्तियां

आल्को	एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन
एआरएफ	आसियान क्षेत्रीय संघ
आसियान	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन
एएसईएम	एशिया यूरोप बैठक
एसोचैम	एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
एयू	अफ्रीकी संघ
एडब्ल्यूजी–एल सी	दीर्घावधिक सहयोगात्मक कार्रवाई पर एडी–एचओसी कार्य समूह
आयुष	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्साए यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक
बार्क	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
बिमस्टेक	बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाडी पहल
बिप्पा	द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा सुरक्षा करार विज्ञान संस्थान
ब्रिक	ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन
सीबीएम	विश्वास उत्पादक उपाय
सीबीआरएन	रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल तथा परमाणु
सीका	व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सीलैक	लातिन अमरीकी तथा कैरीबियाई देशों का समुदाय
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी करार
चोगम	राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीएलएमवी	कंडोबिया, लाओ पीडीआर, बर्मा एवं वियतनाम
सीपीआईओ	मुख्य जन सूचना अधिकारी
सीपीवी	कोंसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा
डीटीएए	दोहरा कर परिवर्जन करार
ईएएम	विदेश मंत्री
ईएएसए	विदेश मंत्रालय स्पाउजेज संघ
इकोसोक	आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
ईईपीसी	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद
ईयू	यूरपोपीय संघ
ऐक्जिम	भारतीय निर्यात–आयात बैंक
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
एफआईडीसी	भारतीय विकास सहयोग संघ
एफएमसीटी	फिसाइल सामग्री कट ऑफ संधि
एफटीए	मुक्त व्यापार करार
जी–20	समूह 20
जीसीटीएफ	वैश्विक आतंकवाद निरोध मंच
जीएफएमडी	वैश्विक देशांतर तथा विकास मंच
जीओआई	भारत सरकार
एचईपी	जल विद्युत परियोजना
एचआरसी	मानवाधिकार परिषद
आईएएफएस	भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन
आईएएनएस	भारत एशिया समाचार सेवा
इब्सा	भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच
आई/सी	स्वतंत्र प्रभार
आईसीएओ	अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईसीडब्ल्यूए	भारतीय मामलों की विश्व परिषद
आईडीपी	आंतरिक विस्थापित व्यक्ति
आईडीएफआर	राजनय तथा विदेश संबंध संस्थान
आईडीएसए	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
आईईए	अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आईआईएफटी	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएमसी	भारतीय जनसंचार संस्थान
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईओएम	अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन संगठन
आईओएनएस	बौद्धिक विज्ञान संस्थान
आईओआर –एआरसी	क्षेत्रीय सहयोग पर हिंद महासागर परिधि संघ
आईटीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
आईपीयू	अंतर संसदीय संघ
आईआरटीएनए	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटेक	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग
आईटीएमए	अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र विनिर्माता संघ

आईवीएफआरटी	उत्प्रवासन, वीजा तथा विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग
जेसीवीसी	व्यापार सहयोग संयुक्त समिति
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्यकारी दल
एलसीएस	थल सीमा शुल्क केन्द्र
एलडीसी	अल्पतम विकसित देश
एलओसी	ऋण श्रृंखला
एमईपी	यूरोपीय संसद सदस्य
मर्कोसुर	दक्षिणी शंकु देश बाजार
एमजीसी	मेकांग गंगा सहयोग
एमओईएफ	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपी	सांसद
एमटीसीआर	मिसाइल तकनीक नियंत्रण प्रणाली
नाम	गुटनिरपेक्ष आंदोलन
नासा	राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अंतरिक्ष प्रसाशन
एनडीसी	राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
निफ्ट	राष्ट्रीय फैशन तथा तकनीकी संस्थान
एनपीटी	अप्रसार संधि
एनएससीएस	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
ओसीआई	भारतीय समुद्रपारीय नागरिकता
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओपीसीडब्ल्यू	रासायनिक हथियार निषेध संगठन
ओटीएस	प्रशिक्षु अधिकारी
फारमैक्सिल	भारत भेषज निर्यात संवर्धन परिषद
पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीएम	प्रधान मंत्री
पीटीए	अधिमानिक व्यापार करार
पीटीआई	भारतीय प्रेस ट्रस्ट
पीएसपी	पासपोर्ट सेवा परियोजना
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरजीओबी	भूटान सरकार
आरटीआई	सूचना का अधिकार
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
साफ्टा	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र
साऊ	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
स्काप	अफ्रीकी कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमण्डल सहायता
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
एसडीपी	लघु विकास परियोजना
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसईडी	सामरिक आर्थिक वार्ता
सिका	मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली
एसएमई	लघु एवं मझोले उद्यम
एसआर	विशेष प्रतिनिधिमंडल
टेरी	टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
उनासुर	दक्षिण अमरीकी राष्ट्र संघ
अनसिट्रल	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग
यूएनसीओपीयूओए	बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनसीएसटीडी	विज्ञान तथा तकनीक विकास पर संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूनीस्काप	एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूनीफिल	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूएनओडीसी	स्वापक तथा अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय
यूपीए	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक अधिकार संगठन
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
एक्सपीडी	विदेश प्रसार तथा तथा लोक राजनय प्रभाग

विदेश मंत्रालय
भारत सरकार

यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। : **www.mea.gov.in**